



पृष्ठ : २१

अंक : १-

- युवकों का भी सरकारीकरण ?
- शिक्षा जगत के समक्ष इस युग की चुनौती
- अहिंसक शक्ति प्रकट करने का एक शैक्षिक प्रयोग
- शिक्षा में क्रान्ति का अर्थ
- जीवन की बुनियादें

अगस्त, १९७२

युवकों का भी सरकारीकरण ?

सरकार की ओर से घोषणा हुई है कि उसकी ओर से देश भर में एक मौ नेहरू युवक केन्द्र खुलेंगे। इन केन्द्रों में क्या होगा ? खेल के मदान होंगे खेल के सामान होंगे। इसके अगला ओर क्या क्या होगा ? और ये युवक कौन होंगे ? कहा गया है कि इन केन्द्रों में खेल के साथ साथ कुछ युवकनेता भी प्रशिक्षित किये जायेंगे। इन 'नेताओं' को क्या प्रशिक्षण मिलेगा और ये नेता प्रशिक्षित होकर क्या करेंगे ?

युवकों को कमाने, खाने रोना, और सीखने की जितनी सुविधाएँ मिल सकें मिलनी चाहिए। लेकिन युवक स्वतंत्र निर्भय नागरिक बनें यह चिन्ता सबसे पहिले होनी चाहिए। क्या नेहरू युवक केन्द्र की इस योजना से यह उद्देश्य पूरा होगा ?

वर्ष : २१

अंक : १

हमें ऐसा लगता है कि जब सरकार युवकों को भी सरकारीकरण की अपनी दूरगामी योजना में सम्मिलित करने जा रही है। अगर हमारे युवक भी सरकार के हो जायेंगे तो क्या बचेगा जो समाज का होगा ?

लोकतंत्र स्वतंत्र रहे, इसके लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं एक राजनीति में सभी दलों को बराबर स्वतंत्रता हो, और दो शिक्षा स्वतंत्र हो। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों धृष्टियों से हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। सरकार अधिक-से-अधिक अधिकार अपने हाथ में करती जा रही है। विरोधी दल की स्थिति दिनोदिन बिगड़ रही है। जो विरोधी दल ऊपर से भरे पूरे दिग्दर्श देते हैं वे भी अन्दर-अन्दर घासले होते जा रहे हैं। अनेक विरोधी सदस्य कमाई और सुविधाओं तथा भाई भतीनों के लिए

समाज कैसे चलेगा ? पर विज्ञान ने शस्त्र का स्वरूप बदल दिया है । आज दुनिया के सामने मवाल है कि इन शस्त्रों से कैसे मुक्त हो ? महावीर, बुद्ध और ईसा जो नहीं कह सके, वह बात आज निःशस्त्रीकरण की माँग द्वारा रखी जा रही है । निःशस्त्रीकरण आज दुनिया की अनिवार्य आवश्यकता बन गयी है । निःशस्त्रीकरण में सिपाही की भूमिका समाप्त होती है । तब यह सवाल उठता है कि दण्ड शक्ति के स्थान पर अब कौन सी शक्ति समाज की रक्षा करेगी ? आज शस्त्र रखें तो सर्वनाश, (विकल्प के अभाव में) न रखें तो सर्वनाश । परिणामस्वरूप दुनिया की आकांक्षा निःशस्त्रीकरण की है और आयोजन शस्त्रीकरण का हो रहा है, क्यों कि आज कोई विकल्प नहीं है ।

गांधीजी ने ध्यान दिलाया कि यह वाछनीय हो नहीं आवश्यक भी है कि सम्मति से समाज चले, क्योंकि लोकतन्त्र की असली शक्ति सम्मति की शक्ति है । उसका साधन शिक्षा है । आज जो स्थान सैनिक का है, भविष्य में शिक्षक का बने ।

समाज को दण्ड शक्ति से चलाने की एक पद्धति है । यदि सम्मति शक्ति से चलाना हो तो पद्धति बदलनी होगी । कोयले के इंजिन को जीजल से चलाना हो तो इंजिन की डिजाइन बदलनी होगी । इसके लिए आज परिस्थिति और मनःस्थिति दोनों अनुकूल हैं । विज्ञान में प्रकाश और चेतना दोनों का विकास हुआ है । प्रकृति का नियम है कि अणुकार में आदमी को भय होता है । प्रकाश से हिम्मत बढ़ती है । इसलिए आज भय कम हुआ है और स्वाभिमान बढ़ा है । आज मालिक मजदूर को, सरकार जनता को, शिक्षक छात्र को भय से नहीं चला सकते । पहले के जमाने का ५० वर्ष की उम्र का बेटा बाप के सामने धर-धर काँपता था, पर आज का ३ साल का पुत्र भी कीन नहीं पकड़ने देता । पहले शिक्षक कक्षा में डण्डा लेकर पढ़ाते जाता था, और आज लेकर जाये तो वह डण्डा उसी की पीठ पर पड़ सकता है । इसलिए आज के शिक्षण की आयोजना में सोचना होगा कि सहकार का संस्कार कैसे विकसित हो ? परस्पर सहकार से समाज कैसे चले ? यह सोच करनी होगी, अन्यथा यह पीढ़ी खो जायगी । इसका अर्थ यह हुआ कि पूरी शिक्षा का दृष्टिकोण ही बदलना होगा ।

लोकतन्त्र की पहली शर्त मतदान है । मतदाता को इतनी न्यूनतम शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए कि जिससे चुनाव-घोषणा-पत्र समझ कर मत दे सके । आज के स्तर के अनुसार हायर मेकण्डरी तक की शिक्षा की न्यूनतम माँग है । कृपि प्रधान देश भारत में प्रौद्योगिकी, स्त्रियो एवं बच्चों के काम के दायरे बड़े हुए हैं ।

जो बच्चे किसान के घर में काम करते हैं उन्हें शिक्षित करना हो तो उनके कामों को शिक्षा का माध्यम बनाना होगा ।

सोकनत्र में शिक्षा का स्वरूप बुनियादी शिक्षा का होगा । सामाजिक और प्राकृतिक परिस्थिति के अनुबन्ध द्वारा शिक्षा देनी होगी ।

आज लोकतन्त्र में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया है । क्योंकि या तो नया जन-प्रतिनिधि बन गया है या जन प्रतिनिधि को लोग गलती से नेता समझने लगे हैं । प्रतिनिधि सदा जनमत के पीछे चलनेवाला होता है । आज जनता का मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है । यदि भविष्य में जनता को आगे बढ़ाना है तो नेतृत्व का नया स्वरूप विकसित करना होगा । उसकी जिम्मेदारी शिक्षक पर है । शिक्षक को समाज का नेतृत्व अपने हाथ में लेना होगा । यह तभी सम्भव है जबकि शिक्षक की भूमिका ऊँची हो । उसे जन प्रतिनिधि से उदासीन रहना होगा । उदासीन अर्थात् उत्-आसीन ऊपर आसन जमाया हुआ—उदासीन नहीं । मायापीश की स्थिति आज जन-प्रतिनिधि के नीचे नहीं है । वही स्थिति शिक्षक की होनी चाहिए ।

आज शिक्षकों के अखिल भारतीय संगठन है, लेकिन वे अत्यन्त सीमित दायरे में सोचते हैं । वे अपने घेरे बढाने की माँग हेतु हड़ताल करने हैं । यदि हड़ताल करना ही हो तो वह शिक्षा के विषय को न्याय के समान स्वतन्त्र करने जैसे विषय पर होनी चाहिए ।

यह कैसे होगा ? निम्न शिक्षकों में इस विचार के प्रति तत्पन हो, वे इस काम को उठा लें । आचार्य विनोबा ने इसके लिए आचार्यकुल के रूप में रास्ता खोला है ।

प्रश्न विश्वविद्यालय स्वायत्त हो है, फिर भी समस्या प्यो-की प्यो है । आपका अभिप्राय किस प्रकार की स्वायत्ता से है ?

उत्तर विश्वविद्यालय का कुलपति, उपकुलपति सरकार के हाथ का विलीन हो होता है । सरकार उनके आदेशों को सुपरसोड कर सकती है, न्याय विभाग के समान शिक्षा जगत को शिक्षा के मसलों पर निपेधाज्ञा के अधिकार नहीं हैं ।



समाज वैसे चलेगा ? पर विज्ञान ने शस्त्र का स्वरूप बदल दिया है । आज दुनिया के सामने सवाल है कि इन शस्त्रों से वैसे मुक्त हो ? महावीर, बुद्ध और ईसा जो नहीं कह सके वह बात आज निःशस्त्रीकरण की माँग द्वारा रखी जा रही है । निःशस्त्रीकरण आज दुनिया की अनिवार्य आवश्यकता बन गयी है । निःशस्त्रीकरण में सिपाही का भूमिका समाप्त होती है । तब यह सवाल उठता है कि दण्ड शक्ति के स्थान पर अब कौन सी शक्ति समाज की रक्षा करेगी ? आज शस्त्र रखें तो सर्वनाश (विकल्प के अन्धकार में) न रखें तो सर्वनाश । परिणामस्वरूप दुनिया की आकांक्षा निःशस्त्रीकरण की है और आयोजन निःशस्त्रीकरण का हो रहा है क्यों कि आज कोई विकल्प नहीं है ।

गांधीजी ने ध्यान दिलाया कि यह वांछनीय ही नहीं आवश्यक भी है कि सम्मति से समाज चले, क्योंकि लोकतंत्र की असली शक्ति सम्मति की शक्ति है । उसका साधन शिक्षा है । आज जो स्थान सैनिक का है, भविष्य में शिक्षक का बने ।

समाज को दण्ड शक्ति से चलाने की एक पद्धति है । यदि सम्मति शक्ति से चलाना हो तो पद्धति बदलनी होगी । कोयले के इंजिन को डीजल से चलाना हो तो इंजिन की डिजाइन बदलनी होगी । इसके लिए आज परिस्थिति और मन स्थिति दोनों अनुकूल हैं । विज्ञान में प्रकाश और चेतना दोनों का विकास हुआ है । प्रकृति का नियम है कि अंधकार में आदमी को भय होता है । प्रकाश से हिम्मत बढ़ती है । इसलिए आज भय कम हुआ है और स्वाभिमान बढ़ा है । आज मालिक मजदूर को, सरकार जनता को, शिक्षक छात्र को भय से नहीं चला सकते । पहले के जमाने का ५० वर्ष की उम्र का बेटा दाप के सामने घर-घर काँपता था, पर आज का ३ साल का पुत्र भी कीन नहीं पकड़ने देता । पहले शिक्षक कक्षा में डण्डा लेकर पढ़ाने जाता था, और आज लेकर जाय तो वह डण्डा उसी की पीठ पर पड़ सकता है । इसलिए आज के शिक्षण की आयोजना में सोचना होगा कि सहकार का सहकार कैसे विकसित हो ? परस्पर सहकार से समाज कैसे चले ? यह सोच जरूरी होगी, अन्यथा यह पीढ़ी खो जायगी । इसका अर्थ यह हुआ कि पूरी शिक्षा का दृष्टिकोण ही बदलना होगा ।

लोकतंत्र की पहली शर्त मतदान है । मतदाता को इतनी न्यूनतम शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए कि जिससे चुनाव घाघणा पत्र समझ कर मत दे सके । आज के स्तर के अनुसार ह्वापर सेकण्डरी तक की शिक्षा की न्यूनतम मांग है । कृषि प्रधान देश भारत में ग्रीडो, स्त्रियो एव बच्चो के काम के दायर बट हुए हैं ।

नयी छात्रीय त्वरित प्रगति नहीं करती है। उसका असली कारण यह है कि नयी छात्रीय के प्रेरक विचार को सारी जनता न तो पूरा-पूरा समझती है और न उसे स्वीकारती ही है। कुछ लोग गांधीजी के कार्यक्रम के अनुसार हिन्द-स्वराज्य नहीं चाहते, क्योंकि वे मानव प्रकृति और मानव कल्याण की बुनियादों के रूप में गांधीजी की विचार सरणी को नहीं मानते। इस सही दृष्टि-भेद को स्वीकार कर समस्या सुलझाना चाहिए। मानसिक आत्मन्य का भी एक बोझा है। आदतों की पुरानी लीक पर चलना हमेशा आसान है और बहुत से लोगों को अपनी असमर्थता के कारण इस पुराने ढर में ही रहने में सन्तोष मिलता है। शहरी में शिक्षितवर्ग वर्तमान पद्धति में बुनियादी परिवर्तन या मामूली हर फेर भी नहीं चाहता, क्योंकि वर्तमान पद्धति को चान्द्र रखने में उसको लाभ है।

यथास्थितिवादियों की ये विरोधी बातें

ये विरोधी लोग जिस पद्धति का समर्थन करते हैं उसकी कमजोरियों का उनको पूरा भान है। वे जानते हैं कि वर्तमान शिक्षा की योजना सारे राष्ट्र के लाभ के लिए कभी नहीं की गयी थी। असल में वह मध्यम वर्ग के लिए थी, जो बीबरसाही के दलाल हैं उनका राज्यसत्ता में प्रवेश करने के लिए प्रमाण पत्र पाने का रुद्ध है। उसका उद्देश्य ही सीमित और सकीर्ण है। इसलिए वह जीवन के बुनियादी तत्वों की शिक्षा नहीं दे सकती। केवल ऊपर ऊपर की बातों की शिक्षा हो देगी। सम्पूर्ण और स्वस्थ मानव बनानेवाले विचार जैसे स्वातन्त्र्य जीवन की आशा, नैतिक साहस और प्रेम की शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में नहीं मिलती।

आज थोड़े गुरुकुल ऐसे हैं जहाँ विचार करना, सेवा करना सिखाया जाता है। परन्तु अब तक ये लोग पुरानी धिंकी-धींकी शिक्षा-परम्परा में जकड़े हुए हैं, वे मुक्त नहीं हो सकते। बिनोबा कहते हैं कि भारत में स्वातन्त्र्य प्राप्त किया तो पुराने राज्य का षण्डा जिस तरह एक दिन के लिए भी नहीं सहा गया, उसी तरह पुरानी शिक्षा भी फौरन बदल देनी चाहिए। पुराना शिक्षाक्रम नहीं निभाना चाहिए। भारत अभी तक शिक्षा में गुलामी निभा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिनकी आवाज 'अनमत' समझी जाती है वे पुरानी राज्य व्यवस्था की पैदाइश हैं। पुरानी पद्धति चालू रखने में उनका स्वार्थ है। इस शिक्षा ने हमें सुविधा प्रेमी बनाया है, हमको आजीवन बैठन की नोकरी दी है और हमें आशा है कि यही हमारे बालकों की भी मिलेगी। आरामपरस्ती हमको यथा-स्थितिवादी बनाती है। इस जीर्ण मनोवृत्ति को घनाप रखने में हमारा डरपोकनन

और हमारी अपराधी वृत्ति दोनों ससक्त हैं। सरकार के पास बैठे वहाँ से भाते हैं, उसका शान्त चित्त से विचार करेंगे तो हमें मालूम होगा कि जिनके बच्चों को भर पेट भोजन और शिक्षा नहीं मिलती, जो अपनी मेहनत की कमाई स्वयं नहीं खा पाते, वे लोग जो गाँवों में रहते हैं, हमारी शिक्षा और सुख-सुविधा का स्वयं दे रहे हैं, रेतिहर और मजदूर हमें खिलाते हैं—हमें बपड़े देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हम जो कहेंगे वे हैं, दुनिया में जो कुछ चीजें बन रही हैं उनके उत्पादन नहीं हैं। साफ कहें तो हम दूसरों का खून चूसनेवाले हैं। इसलिए हम परिवर्तन से डरते हैं। हम डरते हैं कि कहीं बुनियादी और राष्ट्रीय विचारों को गम्भीरतापूर्वक स्वीकार करने से हमारे अपने जीवन में क्रांति आ जायेगी। जाने-अनजाने हम ये विचार तोड़ते हैं। हम जानते हैं कि हमने अपना घर रेत पर बनाया है परन्तु हम आशा रखते हैं कि मरने के पहले आन्धी तथा तूफान हमें वही घसीट न ले जाय।

सृजनात्मक जीवन की तालीम

यदि हम उस आरामतलब शिक्षा का त्याग करते हैं और अपने प्रमाण पत्र फेंक देते हैं और एक सही इनसान बनानेवाली कोई तालीम शुरू करने का निश्चय करते हैं, तो उसके लिए सोचना होगा कि तालीम कौन-सा रास्ता बताती है? बुनियादी शिक्षा के क्या आधार हैं?

प्रत्येक मनुष्य को उत्पादन काम, प्रेम और ज्ञान की आवश्यकता है, इस बुनियाद पर नयी तालीम आधारित है।

आदमी उत्पादन करना चाहता है। उसके भीतर सृजन करने की प्रेरणा रहनी है। वह अपने हाथ से वनी अच्छी वस्तु देखता है, तब उसकी सृजन करने की प्रेरणा सन्तुष्ट होती है। खेत और बगीचा बनाता है, बराम से पूनी बनाता है, लकड़ी और धातु की उपयोगी और कलापूर्ण चीजें बनाता है, संगीत सीखता है और विभिन्न चित्रकलाओं में रुचि लेकर वह अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सारे ससार में भगवान के चित्र बनानेवाले धर्मों में देवों की जातियों में से कुछ देवों को सर्वोत्तम कारीगर और सर्वोत्तम कलाकार बताया गया है। काम केवल भौतिक आवश्यकता नहीं है, वह जीवन के अर्थ और प्रकार का हिस्सा है। कोई भी काम यदि शान्तचित्त से और तबीयत से किया जाय तो उससे कार्यक्षमता और कला, दोनों पर समान अधिकार हो जाता है।

मनुष्य की दूसरी आवश्यकता प्रेम करना और प्रेम पाना है। अपनी मानवीय प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्ति के लिए वह दूसरों का साथ चाहता है। इस

प्रतिक्रिया में उसकी आकांक्षाएँ, योजनाएँ और उपक्रम होते हैं तथा व्यक्तिगत दुःख भी शामिल होने हैं। परिवार, दल या जाति में वह अपना समावेश चाहता है जिससे वह अपनी कमजोरी के समय में मदद पा सके और जिसको अपना धल व बुद्धि अर्पण कर सके, ऐसे किसी समाज का वह सदस्य बनना चाहता है। अपने मानव बन्धुओं की सेवा में अपनी ज़ाबदारी अदा करना चाहता है। मनुष्य की सामाजिक आदतें उसकी अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में अवश्य मदद पहुँचाती हैं। उसको ये आदतें केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वभाविक उपक्रम ही नहीं होती, बल्कि उनसे जीवन की ऊँचाइयों को छूने का प्रयत्न भी होता है।

व्यापक और गहरी जिज्ञासा

मनुष्य की तीसरी आवश्यकता ज्ञान-प्राप्ति की है। व्यक्ति में शोध करने की और समझने की इच्छा रहती है। इस नये ज्ञान का किसी व्यावहारिक उपयोग से सम्बन्ध नहीं रहता। सभी बड़े-छोटे लोगों में निरपेक्ष, शुद्ध, निःस्वार्थ, जिज्ञासा भाव स्वभावतः रहता है। अपने आस-पास वह जो कुछ देखता है उससे स्वभाव और अर्थ का पता लगाना चाहता है। उसकी तात्कालिक भौतिक आवश्यकता से सम्बन्ध न रखनेवाली सब प्रकार की चीजों के सम्बन्ध में उसके मन में जिज्ञासा रहती है और उन पर उसका प्रयोग चलता रहता है। विज्ञान का इतिहास बताता है कि इस शुद्ध जिज्ञासा की उपयोग रहित ज्ञान की तृप्ति के लिए मनुष्य ने जो कोशिशें की हैं उनमें से अग्रत्यक्त रूप से बहुत उपयोगी और व्यावहारिक खोज हुई हैं। परन्तु बिना प्रेरणा से केवल ज्ञान और समझ की खोज होनी है वह प्रेरणा भौतिक आवश्यकताओं और सुविधाओं की पूर्ति के लिए हो रहे अच्छे और आसान तरीकों की मानव-जाति की खोज के मुनाबले बहुत व्यापक और गहरी खोज है।

यदि मनुष्य की मुख्य आवश्यकताएँ ये हैं तो इनकी तुलना में समाज की प्रगति को मापना चाहिए। जिस समाज के लिए मनुष्य की सहनशक्ति, उसको 'सुन्दरम्' बनाने में खर्च होती है, वह समाज का पूर्णतया मानवीय अंग है। सर्वोदय का फेंच विद्यार्थी कहता है कि शान्ति, स्वातंत्र्य और सन्तोष के सिवाय सच्ची प्रगति नहीं है। उसी आवश्यक सत्य को दूसरे शब्दों में इस तरह रखा जा सकता है कि सच्चे सामाजिक जीवन के फलस्वरूप शान्ति मिलती है, मन की आजादी बुनियादी आजादी है। इन दिनों जनसाधारण जिसको प्रगति कहते हैं, उसका बहुत-सा अंश लेशमात्र भी प्रगति नहीं है। वह भौतिक सुविधाओं का डेर मात्र है।

पास या अमेरिका के पास प्रचुर मात्रा में जितनी मोटर, रेडियो, विद्युत साधन हैं, इस तुलना में भारत के पास साधन न होने से यह पिछड़ा हुआ माना गया है। जो यह कहते हैं वे भौतिकतावादी हैं, और उन्हें प्रगति का सही अर्थ मालूम नहीं है। परन्तु मनुष्य के जीवन की प्रगति केवल उसकी मालिशों की चीजों की सख्या पर आधारित नहीं है। जिस मनुष्य को परिपूर्ण आत्म-सतोपदायक काम मिलता है, बड़ा मित्रवर्ग और पारिवारिक प्रेम मिलता है, प्रतिष्ठा और सन्नति के अवसर छुले मिलते हैं वह मनुष्य साधन सम्पन्न है। जिन देशों को सम्पन्न कहा जाता है, उन्होंने उपरोक्त साधन सम्पन्नता पायी है या नहीं यह बहुत शकस्पद है।

शैक्षिक प्रगति के पैमाने

शिक्षा के क्षेत्र में हम अपनी प्रगति उपरोक्त मूल्यों से नापनी चाहिए। अच्छी शिक्षा से द्वारा सृजनशील प्रवृत्ति का विकास हो तथा सहकारी जीवन, बौद्धिक राज की अभिवृद्धि आनन्द और उत्साह से साथ-साथ मानवीय क्षमताओं का विकास हो यह उद्देश्य शिक्षा प्रणाली का होना चाहिए। विकासशील मानव की आवश्यकताएँ बहुत सारी लेकिन गहरी होती हैं। बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के साथ ही वह अपने आसपास की दुनिया और मनुष्यों से विषय में जानना चाहता है और उसमें भावना के साथ डूबना चाहता है। आनन्द चीजों को बटोरने में नहीं है बल्कि के सम्पूर्ण विकास में निहित है।

तालीम जो मानव को पूर्ण बनाये

व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए नयी तालीम सबसे बढ़िया और सरल साधन है। लोगों को तालीम आसानी से मुलभ हो इस सिद्धांत पर नयी तालीम आधारित है। अपनी शारीरिक आवश्यकताएँ, शारीरिक थम द्वारा प्राप्त करनी पड़ती हैं। इसलिए अच्छे जीवन के नवश का आवश्यक अंश शरीर थम है। अपना थम जो आप कर सकते हैं दूसरों पर थोपना अन्याय, शोषण और कामरता है। क्योंकि जीवन और विकास की चाबी परिश्रम है, प्राथमिक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादक हस्तोद्योग से करना नयी तालीम का मूल मंत्र है। उत्पादन काय प्रतिदिन के जीवन में सत्य अहिंसा क सत्य का व्यावहारिक प्रदर्शन है।

अपने लिए स्वयं अन्न पैदा करने में, घर बनाने और सजान में और अपने ओजारों को आकार देने में मनुष्य का शरीर स्वस्थ और पुष्ट होता है, उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का विकास होता है। अच्छी तरह काम करने से कारीगर को आनन्द होता है। वह अनुभव करता है कि उसकी बुद्धि का व्यापक

हो रहा है, वह स्वयं की तालीम दे रहा है। माता-पिता, पत्नी और बच्चों की भलाई के लिए काम करने का सत्तोष उसे प्राप्त है। वह प्रकृति और मानव-सृष्टि में शांतिपूर्वक रहने के जीवन सम्बन्धी कानून को समझने के साथ उसके पालन में सहयोग देना सीखता है। प्रौढ़ और बच्चे के शरीर, मन और आत्मा के उत्तम अंश को बाहर लाने की शक्ति इस प्रकार के उपयोगी बुद्धिपूर्ण काम में है। और उसमें बुद्धि और आत्मा का उच्चतम विकास सम्भव है। वह केवल शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी नहीं करता, परन्तु मानव प्रकृति की सब अभौतिक (यानी बुद्धि, आत्मा, वाणी आदि की) आवश्यकताएँ पूरी करता है। इसलिए बुनियादी पाठशाला के उद्योग के कार्यक्रम का तात्कालिक ध्येय भौतिक और वास्तविक है—जैसा कि कपड़े बनाना, चाव-भाजी, अनाज बोना, कम्पोस्ट खाद तैयार करना, मकान साफ करना, मरम्मत करना, रसोई पकाना, आदि में सब बातें बच्चा समझ सकता है। उसके हृदय की गहराई में समाज का क्रियाशील और उपयोगी सदस्य बनने की कामना रहती है इसलिए उसे ये बातें अच्छी लगनी हैं। वह अपने शिक्षक और सहपाठियों के साथ योजना बनाता है। उसे अमल में लाता है। उसके परिणामों को जाँच करता है—मूल्यांकन करता है। उसके अने हाथ से पैदा किया गया उपयोगी काड़ा, अनाज, खाद आदि का प्रमाण और मूल्य, शिष्टाचारों के काम को सफलता और समीक्षा की सच्ची पक्षीटी है।

नयी तालीम का मूल्यांकन भौतिक परिणामों से किया जाता है। उसकी मनुष्यवृत्ता में पेरिवरणीय या उपयोगी प्रकार का शिक्षण कहा जाता है ऐसा नहीं है। नयी तालीम का ध्येय पूर्ण मानव बनाने की तालीम देना है, खेति-हर या कारखानों का श्रमिक बनाने का ध्येय नहीं है। उसके कार्यक्रमों या तात्कालिक ध्येय जीवनोपयोगी वस्तुओं का कुशल उत्पादन है, परन्तु इन कार्यक्रमों का अन्तिम लक्ष्य बालक की शारीरिक शक्ति परिष्कार बनाने के साथ कुशलता, परिपूर्णता, धैर्य, सात्विक विवाद, मित्रभाव, निस्वार्थ सेवा आदि गुणों द्वारा मन में स्फूर्ति लाने का है। 'प्रसन्नता से आना का विकास होता है और अच्छे काम करने से कठिनाइयों को दूर करने में और सौंदर्य की प्राप्ति में वास्तविक प्रयत्नता मिलती है। अन्तिम लक्ष्य को सफलता के लिए तात्कालिक उत्पादन में सफलता आवश्यक है, परन्तु पाठशाला का कार्यक्रम अन्तिम ध्येय के अनुसार होता है। बुनियादी तालीम केवल उद्योग-व्यापार की तालीम नहीं है, क्योंकि उसका ध्येय मनुष्य की मानवत्व, उदार और वास्तविक बनाना है। उत्पादन कार्यप्रणाली के तात्कालिक

सदय और स्थिर, मुक्त बलशाली पुरुषार्थ के अन्तिम लक्ष्य के लिए भी बुनियादी पाठशाला को मानव आत्मा की सिद्धियों का परिपूर्ण उपयोग करना ही चाहिए। वैज्ञानिक, जीवनोपयोगी विविध कलाओं का अध्ययन करते हुए उसे प्रयोगात्मक रूप देना उसके लिए अनिवार्य है। हमारी दृष्टि से नयी तालीम में सकुचितता नहीं होनी चाहिए ऐसा विनोबाजी ने लिखा है। हमारा ध्येय महान् भारत बनाने का है। इसलिए हमारी बौद्धिक तालीम विशाल और बुनियादी होनी चाहिए। हम अपना जीवन गाँव में बितायें, परन्तु दुनिया की सांस्कृतिक धारा से उसको पोषण देते रहें। अहिंसा और विज्ञान की मैत्री का नाम नयी तालीम है। इस मैत्री में से हम पृथ्वी पर स्वर्ग ला सकते हैं।

दो स्तरीकरण

बुनियादी तालीम, यानिक व्यवस्था के खिलाफ है। हाथ से चलाने के यंत्र की शिक्षा का मूलाधार बनाने से हम पीछे हटते हैं और बीसवीं सदी की सिद्धियों की दृष्टि से ओझल करने हैं। इस आलोचना का विचार यहाँ करना चाहिए। गाँवों के लिए बुनियादी तालीम अच्छी हो सकती है परन्तु जहाँ यंत्र तंत्र ज्यादा प्रगति में हैं, ऐसे महरो के लिए वह प्रतिकूल है।

हम सम्भव में दो भागें ध्यान देने योग्य हैं

(१) जब लोग विज्ञान की बातें करते हैं तब प्रायः उनके बहने का अर्थ यंत्र-विद्या होता है, इसलिए उनके विचार और दलीलों में गड़बड़ होती है। वस्तुतः 'विज्ञान' मानसिक सत्य है, यह दुनिया की जानकारी प्राप्त करने का तरीका, या साधन है। यह शक्ति मानव के ज्ञानासु स्वभाव की एक सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। अनुशक्ति के परीक्षण द्वारा वस्तुओं का पृथक्करण कर वातावरण को समझने के प्रयत्नों के परिणामों को विज्ञान कहते हैं। उसका प्रामाणिक लक्ष्य बवल व्यावहारिक उपयोग नहीं है अपितु बुद्धिपूर्वक समझने का है। नयी तालीम में मन की, प्रश्न करने की वृत्ति का विकास पर बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। आवश्यक प्रक्रियाओं को सही ढंग से समझने के लिए उन्हें अत्यंत सादे तरीके से करना चाहिए। जो बालक हुए या नदी से पानी निकलता है और श्रुतु के अनुसार पानी की सतह का उतार-चढ़ाव देखता है उसे स्नान-घर में टकी से पानी लेनेवाले बालक की अपेक्षा पाँच के सोती का ज्यादा सही और वैज्ञानिक ज्ञान होता है।

जो बालक सबली पर भजमूल, समान और प्रमाण प्रसार बटवाला सूत पातला है वह बराम की परत और बजाई की प्रक्रियाओं में निष्णात होता है। यह योग्यता उसे हैंडल घुमाने से, बिजली का बटन दबाने और यंत्र को काम

करते देखते रहने से कभी नहीं मिल सकती। जिसमें कुशलता का उपयोग नहीं किया जाता, ऐसे यंत्र की अपेक्षा हाथ के औजार और उनके उपयोग से बच्चे माल की पक्का बनाने का पूर्ण अनुभव, अपने वातावरण की विशेषता की वैज्ञानिक समझ के लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है।

यांत्रिक परावलम्बन वैज्ञानिक खोज की जिज्ञासा को समाप्त करता है। बिजली का बटन दबानेवाले लोगों में ही क्या एक भी यह जानता है कि उसके अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है ?

यंत्र और मानव

यांत्रिक प्रगति का महत्व समाज या शिक्षा में तभी है जब वह मानव जाति की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। जैसा हमने देखा, इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ मनुष्य अपनी खुद की सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। यंत्रों की मदद स्वतंत्र रूप से अच्छी या खराब नहीं है। यदि यह मनुष्य को मनुष्य बनाने में मददगार होती है तो अच्छी है, वकाबट डालती है तो बुरी है। गत शताब्दी के भारी तकनीकी विकासों से भौतिक चीजों का उत्पादन बहुत अधिक हुआ है। परन्तु उससे लोगों का हाथ से काम करने का आनंद समाप्त हुआ है। कामगार उत्पादन की प्रक्रिया नहीं समझ सकता और वह समूह वे रूप में उसका हिस्सेदार भी नहीं बन सकता। अब मनुष्य अपने औजारों का स्वयं मालिक नहीं रहा। वह यंत्र का नौकर है। काम के अर्थ वे साथ साथ जीवन का अर्थ भी नीचे गिर गया है। क्योंकि हमने अपनी यह धारणा बना ली है कि अपनी चीजों की मालिकी हमारे सारे सुख का आधार है। यंत्रवाद केवल उत्पादन बढ़ाने का औजार है। जीवन के बुनियादी रूप्य की दृष्टि से उसका उपयोग गौण होना चाहिए। मनुष्य यदि सारी दुनिया का भौतिक सुख भी प्राप्त कर ले, लेकिन उससे अपनी आत्मा का हनन होना दे, तो उससे क्या लाभ होगा ? नयी तालीम यंत्रों के विरुद्ध नहीं है। परन्तु उसका आग्रह है कि यंत्र को उसके उचित स्थान पर रखना चाहिए। यंत्र औजार है— उसे हम पर हावी नहीं होना चाहिए।

अहिंसा की शक्ति प्रकट करने का एक शैक्षिक प्रयोग

[श्री चार चौधरी उन गिने-चुने गांधी विचार-प्रेरित रचनात्मक कार्यकर्ताओं में से हैं, जिन्होंने भारत-विभाजन के बाद तब के पूर्वी पाकिस्तान और दब के बांग्ला देश में निरन्तर अहिंसक लोकशक्ति जागृत करने के प्रयोग करते रहे हैं। यह हमारे सौभाग्य की बात है कि बांग्ला देश के स्वातंत्र्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी दमन चक्र से ईश्वर ने उन्हें बचा लिया। बयॉबुद्ध आदरणीय श्री चारदा गत मई '७२ के सर्वोदय सम्मेलन में पधारे थे, और उन्होंने अपने अनुभवपूर्ण भाषण में अहिंसक शक्ति के प्रयोग की जो कहानी सुनायी थी, उसमें से नौआपाली के आश्रम-विद्यालय का प्रेरक अनुभव हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।—सं०]

हमारे नौआपाली गांधी आश्रम में एक पुराना मकान है, उसके एक तले के एक छोटे-से कमरे में बैठकर मैं अपना लिखा-पढ़ी का काम करता था। वहाँ से गाँव के घेन-बगीचे आदि दिखाई देते थे। हर रोज मैं यह देखता था कि छ गान माल से लेकर बारह बौद्ध साठ तक के कुछ बच्चे हाथ में एक टोकरी, एक बटारी और कभी-कभी घले में रखी डालकर एक गाय को साप लिये दूर-दूर झाड़ने याग में जा रहे हैं, खेत में गाय को बांधकर दूर-दूर झाड़ते हुए बगीचे में पड़ा हुआ एकाध नारियल, कुछ सुगारियाँ चुपके से उठा लेते हैं, और उन्हें टोकरी के भीतर डालकर ऊपर से घास फूस रखकर, उसे दब देते हैं। कभी बगीचे की बाड़ में से कुछ लकड़ियाँ भी तोड़कर रख लेते हैं, कभी गाय की निरी के खेत में घुसाकर कुछ फसल भी चरा देते हैं। इस तरह के उन सबकी वे समय का उपयोग होता था। साफ है कि वे स्वाभाविक रूप से चोरी की शक्ती से होते थे। उनसे बाप या अभिभावक यहाँ वहाँ काम करके कभी कुछ कमा लेते थे और कभी रात को चोरी-डकैती के लिए निकल पड़ते थे। इस तरह यहाँ चोरी एक स्वाभाविक पेशे में परिणत होता जा रहा था। यह दूर-दूर भरे मन में चिंतन चलने लगा।

कुछ दिनों के बाद मैंने उन लड़कों के अभिभावकों को बुला भेजा। वे आये और हम एक साथ बैठे। छोटी-सी भूमिका के बाद मैंने उनसे पूछा, “तुम्हारे

लडके इधर-उधर घूमकर जो कुछ इकट्ठा करते हैं उससे कितनी आमदनी होती है ?” वे मेरे इस प्रश्न से असमंजस में पड़ गये । मैंने उन्हें समझाकर कहा, ‘लडको को अगर एक नारियल मिल गया और कुछ दूसरी चीजें मिल गयी तो भी कुल मिलाकर चार-पाँच आन की चीजें हो जाती हैं, एक आदमी के लिए पेट भरने लायक हो जाता है, लेकिन इससे लडके भी चोर बनने की टालीम पा रहे हैं, उसका क्या होगा ?’ यह सुनकर वे लोग दुःख के साथ कहने लगे, ‘हम गरीब आदमी हैं, खाने की दे नहीं सकते हैं, स्कूल में भी भेज नहीं सकते ।’ तब मैंने कहा, ‘इन लडको को मुझे दे दो, मैं इनको रोज तीन आन दूँगा । सबेरे का नाश्ता दूँगा, दोपहर और रात का खाना वे घर जाकर खावें । आगे चल कर रात को उन्हें अपने पास रखने की व्यवस्था जब कर सकूँगा, तब रात को भी मेरे पास रहेंगे ।’

वे इस पर राजी हुए । इस तरह से मेरा एक नया प्रयोग शुरू हो गया । वे सब किसान मजदूर के लडके थे हाथ के काम में अभ्यस्त थे । हमारे आम के खेतों में घान, पाट जालू, नाना प्रकार की सब्जियों की फसल होती थी । इस काम के लिए सामान्य लिपे-पडे मजदूर आभग में रहते थे । उनके हर एक के साथ तीन-तीन आर-आर लडके दे दिये । उनको इतना कह दिया था कि बच्चे कितनी भी घरारत क्यों न करें, वे उन्हें मारेंगे नहीं धमकी भी नहीं देंगे । कोई लडका कोई बड़ा कमूर बरे, तो उसे मेरे पास ले आवें । इस तरह से मेरा एक अभिनव स्कूल शुरू हुआ । प्रचलित पद्धति से अक्षर सिखाने या पढ़ाने की ड्रेजरी (गाथी मजदूरी) मुझे बहुत पीडा देती थी । इसीलिए मैंने दूसरे रास्ते से उनको सिखाना शुरू किया । वे जब रुई धुतते थे, सूख कासते थे, तब मैं बोर्ड पर बड़ अक्षरों में लिख देता था—‘चरखा’ रुई और उन गझरो को पढ़ाकर बोलता था यह ‘च’ यह ‘र’ और यह ‘खा’ है । तीसो अक्षर मिलकर हुआ ‘चरखा’ । इस तरह अक्षर परिचय की शिक्षा होती रही । इस पद्धति से मैंने देखा कि उनकी अक्षर-ज्ञान बहुत जल्दी हो गया था । मैं उनको लेकर बैठता था । यान करने के ठग ॥ नमी-नमी कहानियाँ कहता था । फिर उन लडको से वह कहानियाँ कहने के लिए कहता था । यह देखकर दूसरे लडके भी कहानो कहने के लिए उत्सुक हो जाते थे । इस तरह से उनकी पढ़ाई बड़े आनन्द के साथ चलती थी । कुछ लडको को तो पढ़ने की धुन ही लग गयी थी । हमारे स्कूल में सब तरह की आजादी थी । अपनी ‘मृ खला’ लडके खुद ही बनाये रखते थे । काम भी वे अपनी ही प्रेरणा से करने लगे थे । काम के साथ-साथ हर तरह की शिक्षा चलती थी । कुछ दिनों के बाद उनके काते हुए सूत से उनके लिए सफेद स्पाउट पोशाक—हाफ शर्ट, हाफ ब्रास्ट, ‘०२]

पेण्ट और टोपी—बना दी गयी। उनकी पैदा की हुई सज्जी बेचने के लिए उहीं को बाजार में भेजा जाता था। सब चीजों पर एक चिप्पी (स्लिप) लगाकर उनका मूल्य लिख दिया करता था। उसी दाम पर चीजें बेची जायगी, उससे कम में नहीं या ज्यादा में भी नहीं। उनसे रखाई बनाने की और बपड़े धोने के लिए साबुन बनाने की सिखा दी गयी थी। वे साबुन बनाकर खुद ही बाजार में बेचने जाने लगे। उनका चाल चलन बदलने लगा। वे दिनभर इतने कामों में व्यस्त रहते थे कि किसी के साथ झगडा करने या माली-मालीज करने का मौका ही नहीं मिलता था। स्कूल उनके लिए दिनभर सोकने का, काम करने का, पढ़ने का बगीचा बना। स्कूल में प्रांतयोगिता और सहयोगिता साध-नाम चलती थी। बाद में गीत और मजन सिखान का काम बड़ी सुंदरता से चलने लगा। मैं यह अनुभव करता था कि व समयते व कि मेरी तरह उनको दूसरा कोई प्यार नहीं करता था। उनके छोटे-छात्र उद्गारों से उनके व्यवहार से मुझे यह प्रतीत होता था। मेरा यह अनुभव पक्का है कि प्यार से ही ऐसे लड़कों को ठीक राह पर लाया जा सकता है। छुट्टी होने से वे दुखी होते थे। बड़ बड़ सिंघाबिद आकर यह विद्यालय देख जाते थे और प्रशंसा करते थे। मैं उनसे कहता था कि यहाँ लड़के सीखते भी हैं, और कमाते भी हैं। उनके लिए मेरा कुछ भी खर्च नहीं होता।

वागगा देग में सब जगह ऐसा स्कूल चलाया जा सकता है और एक ही साल के अन्दर निरक्षरता दूर की जा सकती है। इसमें खर्च भी नहीं के बराबर है, लेकिन मैं यह स्कूल रख न सका। लड़कों के अन्दर जो परिवर्तन दीख पड़ता था वह उस समय का बट्टर पाकिस्तानी मुसलमान समाज सहन नहीं कर सका। वे लोग मुझे तरह-तरह के मुकदमों में फँसाकर स्कूल से दूर रखने लगे। गाँव के साधारण लोग मुखिया लोगों के डर से स्कूल से अपने लड़के हटा लेने लगे। इस तरह स्कूल अपने आप बन्द हो गया। इस स्कूल के अनुभव से ही मेरे मन में यह विचार आया कि इस पद्धति से इसे एक 'रूरल युनिवर्सिटी' में परिणत किया जा सकता है। उसकी परिकल्पना भी बनायी गयी थी। खादीप्रामोद्योग, कृषि, गोपालन, मधु मक्खी पालन आदि कामों के माध्यम से शिक्षा लेकर लड़के प्रेजुएट (स्नातक) बनेंगे और हल भी चलायेंगे।

मेरी राम में यह था एक सच्चे ढंग का अहिंसात्मक प्रयोग। मेरे पास ज्ञान या शक्ति की कमी थी। मैं थोड़ा-बहुत काम कर सका। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली मनुष्य ज्यादा काम कर सकता है।



शिक्षा : आज का स्वरूप एवं कल की कल्पना

बस्ता के कमरों में भारत के भविष्य का निर्माण हो रहा है। शिक्षक रूपी शिल्पी समाज एवं मानवता के लिए उपयुक्त, थोप्ल, आदर्श नागरिकों के निर्माण में व्यस्त हैं। शिक्षा ही जीवन है। क्या क्या अपेक्षाएँ हैं शिक्षा, शिक्षार्थी एवं शिक्षक से, शिक्षालयों से? पर वास्तव में क्या ये अपेक्षाएँ पूरी हो रही हैं? क्या हमारा यह विश्वास सुदृढ़ आधार पर आधारित है? क्या आज की शिक्षा कल के तकनीकी उपकरणों से समाज के लिए योग्य नागरिक पैदा कर सकेगी जो समय के साथ कदम बढ़ा सके, परिस्थितियों में अपन आपको व्यवस्थापित कर सके और देश की अपेक्षाओं को साकार कर सके? एक बड़ा भारी प्रश्नवाचक चिह्न है। तो आइये, वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करें और कल की कल्पना कर आवश्यक तैयारी करें।

शिक्षा का वर्तमान स्वरूप

किसी भी विद्या-संस्थान में प्रवेश करने पर आप पायेंगे कि भिन्न भिन्न वर्गों, धनी-मानी परिवारों, मध्यवर्गीय कर्मचारियों या मजदूर घरानों से, विभिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमियों, एक व दो नम्बर के छात्रे रखकर सरकारी कर की बोरी करनेवालों, कालाधन रखनेवालों, पड़े-लिखे आदर्श परिवारों, अनपढ़ एवं सिपा में अक्षर रखनेवालों, अपराधी माता पिताओं, टूटे परिवारों से आये विभिन्न आयु के, अध्ययन एवं शिक्षा की तरफ रुचि रखाने वाले या शिक्षा से घृणा करनेवाले निर्बुद्धि छात्र छात्राएँ विद्यालय परिवार के अंग हैं, और ३० से ५० से समूहों में बस्ता के कमरों में अध्ययन कर रहे हैं।

अब आप कल्पना कर सकते हैं विभिन्नजातों की, विकटता की, जो इन विद्यार्थी समूहों में विद्यमान हैं।

प्रत्येक कक्षा के लिए व्यक्तिगत घुसक के रूप में पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, भिन्न-भिन्न विषयों के विशेषज्ञ द्वारा। इस तथ्य को भाँवा हैं ओसल रखकर

कि कितने बालक इस खुराक को पचा सकेंगे, किन-किन बालकों को इस खुराक से शक्ति मिलेगी तथा कौन-कौन इस खुराक को पचाने में असमर्थ रहेंगे और उनकी बीमारी बढ़ जायेगी। इस प्रकार सभी बालकों को समान रूप से शक्तिशाली एवं समान गति से आगे बढ़ानेवाले मानकर पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया जाता है, जिनको बिना प्रश्न किये प्रत्येक विद्यार्थी को एक वर्ष पूरा करना है। सत्र के अन्त में इस खुराक का प्रभाव परीक्षा द्वारा मापा जाता है।

यह पाठ्यक्रम जब शिक्षक के पास ला जाता है तो शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि यह पाठ्यक्रम प्रत्येक विद्यार्थी के गले में दवा की खुराक के रूप में डाल दे। शिक्षक के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। वह सभी विद्यार्थियों को एक ही छड़ी से हौकना शुरू कर देता है। विद्यार्थी यह प्रयत्न करते हैं कि वे किसी प्रकार निर्धारित पाठ्यक्रम को गले उतार लें तथा परीक्षा के समय उगत दें, और इस प्रकार प्रमाणित कर दें कि वे अगली वक्षा अथवा अधिक शक्तिशाली आगामी वार्षिक खुराक लेने के लिए तैयार हैं।

सत्र के अन्त में परीक्षा ली जाती है कि पाठ्यक्रम रूपी खुराक का विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव हुआ, वे कितना हज़म करने में सफल हुए। परीक्षा होती है, ग्रेड दिये जाते हैं, अंक दिये जाते हैं और फिर शिक्षक अंक अथवा ग्रेड के क्रम में विद्यार्थियों की सूची तैयार करता है। अर्थात् उच्चतम अंको से शुरूकर निम्नतम अंकवाले विद्यार्थी तक की सूची तैयार करता है। उच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी—जो बुद्धिमान हैं, आमतौर पर शिक्षा में रुचि रखनेवाले पारिवारिक पृष्ठभूमि से आये होते हैं—की प्रशंसा करता है, तथा उसके अच्छे अंक प्राप्त करने का कारण अपने द्वारा आदर्श शिक्षण, आदर्श कक्षा-संगठन, आदि आदि बताता है। कम अंक प्राप्त विद्यार्थियों के लिए उनकी निम्न बुद्धि, खराब अथवा दूषित वंश-परम्परा, घटिया पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि का नहीं होना, आदि कारण बताता है। इस प्रकार जिन विद्यार्थियों को किसी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है, उच्च ग्रेड प्रदान कर प्रोत्साहन दिया जाता है। जिन पिछड़े एवं कमजोर तथा दूषित वातावरण के शिकार विद्यार्थियों को वास्तव में प्रोत्साहन की आवश्यकता है, व्यक्तिगत सहायता की जरूरत है, उन्हें हताशा का शिकार बनना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत विशिष्टता की पूर्ण विकसित होने का अवसर प्राप्त नहीं होता, जो कि शिक्षा का उद्देश्य एवं लक्ष्य है, और जिसमें देश, समाज एवं मानवता की भलाई निहित है।

अब जब ये विद्यार्थी कार्यभेत्र में प्रविष्ट होने हैं तो फिर इन्हें अनेको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । क्योंकि जो खुराक कक्षा के कमरे में दी गयी, वह तो नियमतः वार्षिक खुराक एवं सत्र के अन्न में होनेवाली परोक्षा को ध्यान में रखकर दी गयी थी । उसका वास्तविक परिस्थितियों, सामाजिक जीवन, समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं से सम्बन्ध स्थापित नहीं किया गया था । विज्ञान-अध्यापक ने प्रयोग करने के लिए निर्देश दिया था कि पुस्तक के १५वें पेज पर निर्देश एवं प्रयोग का वर्णन है, उसके अनुसार प्रयोग करो । गणित-अध्यापक ने बताया कि प्रश्नावली के सवाल १ से १४ तक पुस्तक के २५ वें पेज पर दिये जवाहरण के समान हैं । सामाजिक ज्ञान में प्रश्नों के उत्तर के लिए सम्बंधित पेज अथवा अनुच्छेदों पर निशान लगवा दिये गये थे, जिनको कठम्य करना था अर्थात् इस पूरी प्रक्रिया में विद्वानों के व्यावहारिक पक्ष को समझने का मौका नहीं मिला था ।

यह है आज की शिक्षा की स्थिति । अब आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि आज के शिक्षक-शिलो आज के विद्याभित्तों में जिस विद्यार्थी का निर्माण कर रहे हैं, वह विद्यार्थी क्या कल की चुनौतों का हथौड़ा कर सकेगा ? क्या वह कल की जिम्मेदारियों को सम्भाल सकेगा ?

तब कल के समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु शिक्षण का रूप वैसा हो लम्बक के मुयाव निम्न प्रकार है

(१) शिक्षक का प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व के विकास एवं पोषण के लिए बालक की अपनी क्षक्तियों का प्रयोग करना चाहिए ।

(२) बौद्धिक दृष्टि से कमजोर बालक पर शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए ।

(३) हमें अपनी शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रमों को बदलना चाहिए तथा इस बात पर जोर देना चाहिए कि बालक में निहित क्षक्तियों को बाहर निकालने एवं विकसित करने पर अधिक ध्यान दिया जाय, बजाय इसके कि शिक्षक बालक के मस्तिष्क में अधिक-से-अधिक सूचनाएँ उगलने का प्रयत्न करे ।

(४) शिक्षण में उस ज्ञान का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए जो बालक की रुचि द्वारा विकसित हुआ है । ताकि बालक की रुचि निरंतर बनी रहे ।

(५) प्रतियोगिता को कम से कम प्रोत्साहित किया जाय । प्रतियोगिता का प्रयोग सिर्फ उसी समय करना चाहिए जबकि बालक स्वयं इसकी आवश्यकता महसूस करे ।

(६) बालक द्वारा अभिक्रम, कल्पना एवं आगुति को अधिक-से-अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

(७) किसी कौशल में प्रशिक्षण देने के साथ साथ उस बौशल के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रयोग करने का अनुभव बालक को मिलना चाहिए ।

(८) बालक में सृजनात्मक व्यक्तित्व का विकास शिक्षण का मुख्य बिंदु हो ।

इस प्रकार परिस्थिति का रूढ़ बदल जाता है । जहाँ पहले कमजोर विद्यार्थी असफल होता था, वहाँ अब उपर्युक्त सुझावों के अनुसार कमजोर विद्यार्थी शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यान का केन्द्र होगा, तथा बालक एम शिस्त का विकास अनुभव पर आधारित होगा ।

कमी कहाँ है ? क्यों है ?

कमजोरी दो स्थानों पर हो सम्भव हो सकती है—शिक्षक में, अथवा 'प्राध्यापक' में । शिक्षक तथा म बालक को नेतृत्व देता है तथा शिक्षक का नेतृत्व शालीय प्राध्यापक, नेता प्रधानाध्यापक से मिल रहे नेतृत्व से प्रभावित होता है । राज्य का संप्रदाय का वातावरण, जिम बालक का विकास हो रहा है शालीय

फिर हम राजस्थान का ही उदाहरण लेते हैं। यहाँ शिक्षकों में से वरिष्ठता के आधार पर शास्त्रीय प्रधानों की नियुक्तियाँ होती हैं। पहली रात में शिक्षक के रूप में सोनेवाले व्यक्ति दूसरे दिन सठ्ठे हो वरिष्ठता देवी की कृपा से वह शाला-प्रधान के रूप में, शालीय नेता के रूप में प्रकट हो जाता है तथा बिना किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किये शाला-प्रधान बन बैठता है।

अतः इस व्यक्ति से शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक नेतृत्व की अपेक्षा करना दुराशा मात्र ही होगी। यह व्यक्ति शालीय संगठनात्मक वातावरण की शिक्षा के लिए सपुष्पक नहीं बना सकेगा। तो इन भयावही परिस्थितियों से छुटकारा पाने के उपाय क्या हो सकते हैं ?

सुधार के लिए सुझाव

(१) शिक्षक-प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों में आमूल-मूल परिवर्तन किया जाय।

(२) शिक्षण की विधियों में नवीनतम तकनीकी साधनों के उपयोग एवं शोध पर आधारित परिणामों के उपयोग के लिए शिक्षक को सक्षम बनाया जाय और प्रशिक्षित किया जाय।

(३) शालीय प्रशासकों के लिए शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाय। इस प्रशिक्षण की अवधि १ से २ वर्ष की हो सकती है। यहाँ हमें व्यावसायिक प्रबन्ध की विधियों का भी उपयोग करना चाहिए।

(४) शिक्षक-प्रशिक्षण में भर्ती के तरीके दोषपूर्ण हैं, अतः शिक्षक-प्रशिक्षण में भर्ती के समय उम्मीदवारों का चयन मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं के आधार पर किया जाना चाहिए।

(५) शिक्षक-प्रशिक्षण कालेजों के व्याख्याताओं की भर्ती के तरीके दोषपूर्ण हैं, अतः इनको बदला जाना चाहिए तथा व्याख्याता पदों पर सीधे भर्ती की प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन व्याख्याताओं को प्रति दो वर्ष के बाद सेवा-कालीन प्रशिक्षण के लिए आवश्यक रूप से भेजा जाना चाहिए, ताकि ये शिक्षा में हो रहे नवीनतम प्रयोगों एवं विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

सेण्टर ऑन एडवांस स्टडी इन एजुवेशन, बड़ौदा

अनुशासनहीनता का उपचार : एक योजना

आधे दिन हमें समाचार-पत्रों, आकाशवाणी-केन्द्रों एवं प्रचार-प्रसारण के अन्य साधनों के द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं समाज के लोगों से यह ज्ञात होता है कि उनके बाल में अनुशासनहीनता कम थी और अब विद्यार्थी-अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। प्रायः सत्र के प्रारम्भ में और परीक्षा के दिनों में वही हड़ताल, कहीं घेराव, कहीं छेड़-छाड़, कहीं नकल, कहीं चोरी, कहीं गुण्डागिरी, कहीं जुआ तथा शराबखोरी और न जाने किन-किन अपराधों में विद्यार्थियों को पकड़े जाने एवं सजाये जाने के समाचार मिलते रहते हैं। दिन-प्रतिदिन इन घटनाओं की वृद्धि भी बतायी जाती है। ऐसा लगता है कि इन हरकतों से सारा समाज पीड़ित रहना है। मैं व्यक्तिगत अनुभव से एवं लम्बे समय तक विद्यार्थियों के बीच में रहने के माते, यह मानना हूँ कि विद्यार्थियों को मूल रूप में दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

दोषी कौन ?

दोष तो इनको दो गयी शिक्षा-व्यवस्था में है जो इन्हें कर्महीन, कर्तव्यहीन, और निराशावादी बनाती है। दोष मैं भागीदार इनके निर्माता शिक्षक और माता-पिता भी हैं। सबसे बड़े दोषी, इनका मोहरा बनकर कर्णव्यभ्रष्ट एवं निहित स्वार्थों की प्राप्ति हेतु काम में लेनेवाले, ये राजनेता एवं राजनैतिक दल हैं, जिन्होंने राष्ट्र की इस महान शक्ति की गरिमा बढ़ाने के स्थान पर उसे पयभ्रष्ट कर अपने भंगुल में फँसा रखा है। बड़े-बड़े राजनैतिक दलों की घुसपैठ शिक्षण-संस्थाओं में होनेवाले चुनावों के समय स्पष्ट रूप से देखी और अनुभव की जा सकती है। अतः खोर को नहीं, खोर की माँ—इन दलों को—मारना उचित होगा। जिसने लाखों अनुशासनहीन कर्मियों को प्रोत्साहित किया है।

फिर भी यदि मान लिया जाय कि हमारे ये कर्णधार एवं अविध्य के आधार विद्यार्थी अनुशासनहीनता और निविध्य प्रकार के दोषों में फँसे हैं तो मैं दुःख-

पूर्वव यह मानता है कि इस प्रकार के कार्यों को कम एवं नियमित करने में व्यवस्था उन कार्यों को रोकने में एक परामर्श समिति या सलाहकार मण्डल का गठन ही सच्चा उपचार होगा, जिसने कार्यों में सन्वामार्ग प्रदान कर इन विद्यार्थियों को उन्नत और राष्ट्रहित में मोचने की ओर प्रवृत्त किया जा सकेगा।

समाधान के नपाय

प्रत्येक शिक्षण-संस्था में, चाहे वह स्कूल, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय हो, एक सलाहकार मण्डल भी उसी कार्य प्रणाली का मुख्य अंग होना चाहिए। इस सलाहकार मण्डल को प्रथम आवश्यकता के रूप में स्वीकारना होगा। इसके गठन में अधिक कार्यकर्ताओं का योगदान होना जरूरी है। प्रधानाध्यापक, आचार्य अथवा विद्वद्विद्यालय के अधिकारियों को निम्न भाव से अधिक-से-अधिक सुयोग्य एवं शिक्षा के मतलब की समझनेवाले लोगों को नामजद करना होगा। अधिकतर सदस्य स्थानीय हों, ताकि वे सम्मानित हों और उनके आने-जाने पर यात्रा व्यय एवं दैनिक भत्ते पर कुछ खर्च न हो। जब भी चाहें उन्हें बुलाया जा सके अथवा उनसे परामर्श किया जा सके। स्थानीय होने से वे अधिक जिम्मेदार, निष्ठावान एवं कर्तव्य पालन होंगे। वे सभी स्थानीय बातों की एवं स्थितियों और आवश्यकताओं को जाननेवाले भी होंगे। इन नामजद सदस्यों में व्यापक जानकारी एवं व्यवसायों के लोग लिये जायें जिनमें अधिकतर अनुभवी, प्रगतिशील और अवकाश प्राप्त हों ताकि वे इसकी सदस्यता का सम्मानरूप में स्वीकार करेंगे। इस प्रकार के लोग, शिक्षक, अभिभावक, जज, वकील, डाक्टर, समाज-सेवक, प्रशासक और स्थानीय सम्मान की दृष्टानेवाले लोग होंगे। विद्यार्थी-संगठनों के प्रतिनिधि और संस्थाओं के अधिकारियों के प्रतिनिधि एवं संस्थाओं के अधिकारियों को भी मनोनीत किया जाना चाहिए। शहर के राजनेताओं एवं दलों के लोगों की कम-से-कम प्रतिनिधित्व दिया जाय। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाय। अर्थात् सलाहकार मण्डल जितना सर्वांग हो, उतना ही अच्छा होगा। यदि आवश्यक हो तो जनता के अन्य जरूरी प्रतिनिधियों को भी बैठकों में आमंत्रित किया जाय।

मण्डल का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से विद्यार्थी समस्याओं का समाधान करना होगा। कार्यक्रम, शिक्षण-विधियों एवं अन्य प्रकार के शैक्षिक कार्यों में इसका हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। इस मण्डल का पदेन सचिव संस्था का मुख्य अधिकारी प्रधानाध्यापक या आचार्य ही होना चाहिए। संस्था के वरिष्ठ अनुभवों शिक्षकों को भी यह दायित्व दिया जा सकता है। सचिव संस्था के सभी अनुशासनहीन

मामलों को इस मण्डल की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। मण्डल के सदस्य उन मामलों को गहराई से अध्ययन करने के बाद अपना निष्पक्ष निर्णय बैठक में बहुमत से देंगे। यह निर्णय सचिव के द्वारा सम्बन्धित विद्यार्थियों को बुलाकर बताया जाता चाहिए। बैठक में सम्बन्धित विद्यार्थियों को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। इसके बाद सम्पूर्ण संस्था के विद्यार्थियों को सामूहिक बैठक अथवा सभा में दण्ड की बात विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए ताकि संस्थागत रूप में दिये मण्डल के निर्णय अविरोध लागू हो सकें। इस सभा में मुक्त वातावरण में अन्य विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का भी पता लग सकेगा।

इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो निर्णय दिये गये हैं वे निष्पक्ष, समाजहित एवं विद्यार्थीहित से प्रेरित हैं।

इस प्रकार की योजना में जहाँ एक ओर विद्यार्थी-समाज आरवस्त होगा, वहीं दूसरी ओर इस कार्य-प्रणाली से बोधो विद्यार्थी के प्रति समाज के अन्य लोगों की ओर छात्र-समाज की सहानुभूति भी बढेगी और सारी संस्था के माध्यमों एवं विद्यार्थी नेतृत्वों को नगर की जनता, सम्मानित नागरिकों एवं अपने हितचिन्तकों का दृष्टिकोण भी जानने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार के निर्णयों के औचित्य को टाला नहीं जा सकेगा। आज इन बातों के अभाव में जहाँ ५-१० विद्यार्थी आधे दिन हड़तालों का आयोजन करवाकर वातावरण खराब कर सकते हैं, वह नहीं हो पायेगा।

विश्वास एवं अनुभव के आधार पर यह योजना आज के बिगड़े माहौल में चापद अधिक कारगर सिद्ध हो सकेगी और शिक्षण-मस्याओं में आधे दिन होने-वाली विवृत घटनाएँ बन्द हो सकेंगी। यह योजना समाजवादी युग की निर्मात्री भी होगी, क्योंकि इसमें स्थानीय समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है।

अनुभव एवं प्रयोगार्थ इस योजना को किसी समस्याग्रस्त संस्था में कुछ वर्षों तक परीक्षण लागू किया जाय, ताकि योजना के महत्त्व और सफलताओं का लेखा-जोखा मिल सके। इस सम्बन्ध में उठनेवाली अन्य बातों का भी धरावर अध्ययन किया जाय तो कुछ समय बाद इसका सारापन सामने आयेगा। सच्ची निष्ठा से योजना को कार्यरूप देने से चापद समाधान, उपचार या मार्ग मिल जाय।

प्राध्यापक भूगोल, उदयपुर विश्वविद्यालय,
उदयपुर (राजस्थान)

शिक्षा की क्रान्ति का अर्थ

आजकल दायद ही कोई दिन बीतता ही जब देश के किसी-न-किसी कर्णधार के मुँह से शिक्षा-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की बात सुनने को न मिले। विस्मय तब होता है जब स्वयं शिक्षामंत्री हम तरह की बात कहते सुने जाते हैं। परिवर्तन की आवश्यकता जब इतनी गहराई से अनुभव की जाती है तो वह लाया क्यों नहीं जाता, उसके रास्ते में बाधा बन कर कीन खाड़ा है, इस तरह की जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

परिवर्तन क्यों नहीं होता, हम सवाल का उत्तर प्रायः सापेक्ष दृष्टिकोण से दिया जाता है। अभिभावक, विद्यार्थी, अध्यापक, शासन सभी को एक साँस में समानता दीपी ठहरा कर देश का जिम्मेदार चिन्तक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि शिक्षाधी परिवर्तन की बात समूचे समाज के सुन्दर से काट कर नहीं सोची जा सकती। शिक्षाधिकारियों को यह उत्तर रटा हुआ है कि बच्चों पर सबसे ज्यादा असर अभिभावकों का पड़ता है, अतः उनके सक्रिय सहयोग के बिना शिक्षा-क्षेत्र में आये हुए ठहराव को हिलाना बहुत कठिन है। सुनने में यह बात जितनी तर्कसंगत लगती है, भीतर से उतनी ही गैरव्यवनी लगती है। जिस देश की अधिसंख्य जनता स्वयं अनपढ़ और रुढ़िग्रस्त है, वहाँ बच्चों की तालीम के लिए सरकार को उनके मौ-बाप से क्या मदद मिल सकती है ?

ठीक ऐसा ही भोलापन उम वर्क में निहित है जिसके अनुसार शिक्षापी क्रांति का प्रश्न सर्वजनोपजागरूकता और सहयोग से जुड़ा हुआ है। सम्भव है कि सरकारी तक का यह भोलापन एक स्वार्थपरक नीति हो जिसका लक्ष्य परिवर्तन की परिधि बढ़ाकर उस की सक्ति घटा देना हो। आजगल जिस तरह शिक्षापी परिवर्तन और सामाजिक जागृति के दो सवाल को जोड़ा जाता है, वह घोड़े के आगे गाड़ी लगाने की तरह है। यदि तालीमी फेरबदल जनसामान्य के सजग हो जाने के बाद ही सम्भव होंगे तो प्रश्न उठता है कि तब उस की आवश्यकता क्या रहेगी? यह एक प्रचलित सत्य है कि शिक्षा के माध्यम से ही किसी देश की जनता अपने भौमिक दायित्वों तथा उद्देश्यों के प्रति चेतन होती है। शिक्षा उस चेतना को प्राथमिक सत है, उमका परिणाम नहीं—यह सीधी-सारी बात आजकल लगभग मुला दी गयी है। आशय यह है कि शिक्षापी परिवर्तन की समस्या को किसी अन्य सन्दर्भ से जोड़ना और जोड़कर उसका घेरा बढ़ाने की कोशिश करना न केवल अपने आप में एक असफल कोशिश है, बल्कि एक दुर्भाग्यपूर्ण नीति भी है।

इस नीति के जनक राजनेताओं और मौकरशाहों की तो यह नियति ही रही है कि वे परिवर्तन को तब तक रोके रहें जब कोई राजनीतिज्ञ या अफसर शिक्षा-पद्धति में पूर्ण परिवर्तन की बात करता है तो समझना यह चाहिए कि वह पूर्णता की आड़ में अपना सेवाकाल ठीक-ठीक गुजार लेना चाहता है। भारतीय शिक्षानेत्र में पूर्ण परिवर्तन का इस समय केवल एक अर्थ है और वह यह है कि शिक्षा-जगत की समस्त गतिविधियों का केन्द्र शिक्षक बने। मौकरशाहों के सिर पर विभाग का कागजी भार ही हो और वे शिक्षक समुदाय के वरिष्ठ व्यक्तियों को एकत्र करने का माध्यम मात्र बनें। पाठ्यक्रम निर्माण, पुस्तक चयन व लेखन, परीक्षा, नयी विधुक्तियाँ आदि सभी जिम्मेदारियाँ शिक्षक के भरोसे छोड़ दी जायें तथा उनमें राजनेताओं व मौकरशाहों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, किसी किस्म का प्रभाव न हो।

यहाँ यह भी स्पष्ट करना होगा कि इस नयी व्यवस्था में ऊँची कक्षाएँ पढ़ाने-वाले शिक्षक 'ऊँचे' नहीं समझे जायेंगे। रुस जैसे कुछ सामाजवादी देशों को छोड़ कर अभी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में प्राथमिक शिक्षण से टक्कर लेना माध्यमिक काम समझा जाता है। इस गहरी भ्रांति ने आरम्भिक कक्षाओं के शिक्षक को पतली आय व भारी काम का चिकार बनाये रखा है। बच्चों का साहचर्य एक ताजगी देनेवाला नहीं, चकानेवाला अनुभव होता है और उसकी अधिक

मात्रा किसी दयस्व की मानसिक क्रियाशीलता को कुंठित कर सकती है, यह मनोवैज्ञानिक सत्य शिक्षा के जमींदार अनदेखा करते आये हैं। यदि भारतीय शिक्षा की नयी व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया जाये तो उसमें ऐसी मिलीजुली संस्थाएँ खोलने पर विचार किया जाना चाहिए, जिनमें बच्चों, किशोरों व युवकों, के शिक्षक एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होंगे तथा समय समय पर एक दूसरे का अनुभव ग्रहण करेंगे। ऐसी स्थिति में विभिन्न पदों की अर्हताओं के हमारे वर्तमान मानदण्ड को पलटना अनिवार्य होगा। शान्तिनिकेतन का ख्याल कुछ ऐसा ही था और यही नियोजना पांडिचेरी के अंतरराष्ट्रीय शिक्षा-संस्थान की है।

सोचने की बात है कि ऐसे किसी परिवर्तन को कोई राजनेता या नीकरमाह भला क्यों सम्भव होने देगा जिसमें उसकी अपनी ही कुर्सी के पाये टूट जायें? यह बात सोची सायद इसलिए नहीं जाती क्योंकि देश के तमाम स्वतन्त्राभ्यास शिक्षाविद् आये दिन ऐसे यथस्य जारी करते रहते हैं जिनसे लगे कि वे सालीम में सुधार लाने की छतिर अपने महत्त्व का बलिदान करने से शिष्टकैंरी नहीं। अमूल परिवर्तन की बात कह कर वे प्रगतिशीलता और निःस्वार्थता का पौराणिक मन्त्र ओढ़ लेते हैं व उस ओढ़कर स्वयं परिवर्तन के रास्ते में खड़े हो जाते हैं।

उन की यह भूमिका काटी जा सकती है या नहीं और यदि काटी जा सकती है तो कैसे, इन सवालों पर विचार करने से पूर्व यह तय करना आवश्यक है कि क्या भारतवर्ष का शिक्षा-समुदाय किसी नयी व्यवस्था की चुनौती को स्वीकार करेगा? क्या वह अपने बड़े हुए काम व जिम्मेदारों के बोझ को एक क्रियाशील जीवन जीने के स्वप्न के सहारे बहन कर सकेगा? इन तरह के सवाल उठाना इसलिए संगत है कि इहे आजकल सरकार व उनके अधिकारी अक्सर उठाते हैं और इनका उत्तर न' में दे कर अपनी भूमिका की सार्वजना प्रमाणित करते हैं। शिक्षा-समुदाय से ये प्रश्न अभी नहीं पूछे जाते।

ये प्रश्न उभरते इसलिए हैं कि आज के भारत का स्कूली मुदरित प्रायः एक मरीब, परेधान, निजिज्य तथा सन्नोपी जीव माना जाता है। इन विशेषणों को अन्पया ॥ लिदा जाये, इस उद्देश्य से यहाँ इनकी उत्पत्ति में क्रियाशील कारणों को स्पष्ट करना जरूरी है। वैसा इसलिए भी जरूरी है कि शिक्षा-अगत में आमूल परिवर्तन का तर्क जितने स्पूल रूप में सरकार तथा नीकरमाहों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, स्कूली मास्टर उसे उतनी ही उदासीनता से अनदेखा कर देता है। प्रायः तो वह अपने विभाग के बारे में बात ही नहीं करता—इस डर से कि कहीं कोई ऐसी वैरी बात मुँह से न निकल जाये। करता भी है तो अपनी संस्था में

टाट गट्टी या डेस्क कम होने की, पक्की इमारत या खेल का मैदान न हान की, और यदि बहुत हुआ तो बनने अन्याय जन की । उसकी दृष्टि कभी स्थायी मामलों से परे नहीं जाती । कदाचित् वह समझता है कि पूर्ण परिवर्तन के कोई अर्थ नहीं होते, क्योंकि परिवर्तन जैसा चाहे हो उसकी सस्था को प्राथमिक आवश्यकताएँ यही बनी रहेंगी ।

शिक्षक की आर्थिक स्थिति

स्कूल अध्यापक की यह द्वितीय वि-ना जिन कारणों से उपकी है, उनमें उसकी अधित स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है । यह मश-रा ऐसा है जिस पर कुछ भी कहना आजकल हास्यास्पद बन गया है । तनह्राहें जिस ढंग से राई-रती का मोल करके पिछले बरसों में बढे हैं, वह उन्हें बढाने और बढवान का कोई बहुत उम्दा तथा कारगर तरीका नहा था । चाहिये यह था कि अलग अलग उद्यमों के सम्बन्ध में अपेक्षित योग्यता व परिश्रम के बारे में हम अनन परन्तु दिनों के मूल्य छोड़ने तथा एक स्थायीन जमान का नवी अपेक्षाएँ निश्चित करते । ऐसी किसी कोशिश में स्कूल के अध्यापक को ए-र अनपठ देश में क्या स्थान मिलता, यह आसानी से सोचा जा सकता है । पर इसकी विन्ता न सकलाफ पाने वालों ने की, न हलाक करनेवालों ने । परिणाम सामने है कि जहाँ जिले भर पर रोव रखने की कीमत दुनिया भर की सुख सुविधाओं के गणित से आँकी जाती है, वहाँ देश की भावी पीढ़ी का अनुशासनपूर्वक जीना सिखानेवाला देश के कई हिस्सा में जन्मे रुपये तनह्राह पर टाई रुपये की सालाना वृद्धि पाता है । अध्यापक की तनह्राह के बारे में आज कोई नयी बात कहने की जरूरत नहीं है । सारा धर्चा का मर्म यही है कि देश का भावी जनमानस तैयार करनेवाला व्यक्ति स्वयं जागरूक तथा क्रियाशील होने के लिए स्वतंत्र व सक्षम हो । अब सवाल यह है कि उसे यह सब कैसे नसीब हो ? सरकार सोचती है कि जागरूकता का सनै सनै सवार किया जा सकता है और इसी लक्ष्य से उसने दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद तथा प्रादेशिक राजधानियों में विश्वार सभा स्थापन सोच दिये हैं । कुछ चुने हुए स्कूलों में अधिक सामग्री तथा सुविधाएँ देकर या पुनस्को के प्रकाशन भेजवा कर देश के शिक्षक समाज में चेड़ना लाने का सपना भी कुछ इसी तरह का है । इन कार्यक्रमों की अभिपूति के निमित्त सरकार अपने अधिकारियों को हजार तरह के फण्ड देती है और लगभग हर मौसम में राजधानी की मुश और का मौसा भी । यह सब कितना बेमानी है इसे स्पष्ट करने के लिए देश के परन्तु दिनों में आज से कोई साठ वर्ष पूर्व का

एक लेख अवतरणीय है। (यह लेख युवा प्रेमचन्द्र ने स्कूलों के सब डिप्टो इस्पेक्टर के रूप में अपनी नियुक्ति के कुछ ही दिन बाद प्रकाशित किया था ।)

"कुछ तो रुपयों की कमी है और कुछ बेजा खर्च । कमी-कमी सरकार ने दो-चार लाख ज्यादा दिया भी तो वह इस्पेक्टर और डाइरेक्टरों और मैं तथा तू के बांट-बसरे में पड़ जाता है और मुर्दरिस ज्यों-का-त्यों मूला रह जाता है । दुर्भाग्य से सरकार का स्थाल है कि मुआयना ज्यादा होना चाहिए, चाहे तालीम हो या न हो । मुआयने पर खया खर्च किया जाता है, मगर तालीम की खबर नहीं ली जाती....गवर्नमेण्ट कब यह समझेगी कि मुआयना कभी तालीम को जगह नहीं ले सकता ।"

इन वाक्यों में कोई रम्बे-बोडे, अकिडेयुक्त सुझाव देने की हवस नहीं है; स्कूल के अध्यापक के प्रति मानवीय सहानुभूति प्रकट करने की इच्छा भर है । नौकरशाही और अध्यापक की कथमकथ का यह चित्र आज अंदामान भी अप्रासंगिक नहीं बना है । देश स्वाधीन हो चुका है, पर हमारे मुर्दरिस को आज भी राष्ट्रपति की सहानुभूति की जरूरत है । जिसे वे अपने सचित्र पोस्टरों के माध्यम से भूतपूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन् की वर्ष गाँठ पर अत्यन्त स्नेह व धडा-पूर्वक अभिव्यक्त करते हैं । इसी दिन देश भर के मास्टर अपने बाल्याण फण्ड के लिए धन्दा उगाहने घर-घर जाते हैं । शिक्षातंत्र के सूत्रधार आज तक स्कूल के मास्टर की दशा में मुँह चुग कर आँखों की आँड में दारण लेते हैं, या फिर शीठियों में बकसक करके अवसद्ध विकास की मूल वजह आधुनिक तकनीकी उपकरणों तथा उनके वितरण के लिए आवश्यक शोध का अभाव है ।

अभाव अगर सचमुच किसी बात का है तो वह इस समझ का कि वैचारिक सम्पन्नता का जीवन आदसों और प्रोत्साहन के सहारे नहीं, पर्याप्त आय के सहारे जिया जाता है और उसी पर किसी व्यक्ति की स्वच्छन्द क्रियाशीलता निर्भर रहती है ।

इनमें से पहली बात सरकारी खजाने के बँटवारे से जुड़ी है और दूसरी मुर्दरिस के काम को बलकों से भिन्न समझने से । सरकारी दिमाग को ये दोनों ही बातें रास नहीं आती । छात्र-संख्या का बोझ और अध्यापन के घण्टे कम किये जाने की बात तो अभी स्वयं अध्यापकों द्वारा भी नहीं उठायी जाती । वर्तमान में वे ४०:१ के अनुपात और प्रति सप्ताह ३०-२५ घंटाएँ पढ़ाने के दायित्व से सन्तुष्ट नजर आते हैं । वस्तुतः छात्र-संख्या और शिक्षक का अनुपात कहीं वहाँ उपर्युक्त न्यूनतम संख्या से बहुत अधिक है और यही स्थिति काम के घण्टों और

अकार की भी है। जरूरत पड़ने पर मास्टर से ७०-८० बच्चों की कमायद भी करवायी जा सकती है और आदमियों अथवा पशुओं की गणना भी। चुनावों में मतगणना के काम में शिक्षक ही सबसे आगे रहते हैं और इसी समय परीक्षाओं की संधारी के लिए बच्चों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस अनादरर पूर्ण स्थिति से बेखबर स्कूली अध्यापकों की तकलीफ अभी बेवकल वेतन बढ़ाने की माँग को ले कर प्रकट हुई है और इस सम्बन्ध में प्रत्येक अवसर पर सरकार का उत्तर मानो टेंप किया हुआ रहता रहता है। बजट में पैसा नहीं है। जब कभी किसी प्रदेश में ज्यादा दबाव पड़ने पर तनकाह में पाँच-दस रुपये की वृद्धि की जाती है तो सरकारी रेडियो यह कहने से नहीं चूकता कि इस वृद्धि से सरकार को इतने लाख रुपये का घाटा सहना पड़ेगा।

यदि सरकार के पास सचमुच पैसा नहीं है तो वह प्रदेश के मंत्री और मास्टर के बीच में मौक़रगाही की सड़ों पर गद्दे बिछाने का इतज़ाम कैसे कर लेती है? एक बचकानी सी बात समझने के लिए वह प्रान्त भर के अफ़मरों की पहले दर्जे का यात्रा-भत्ता दे कर राजधानी बुलाने से नहीं हिचकती। यही नहीं, वह ऐसे सस्थानों पर लाखों रुपये प्रतिदिन का व्यय भी महन कर लेती है जिनका काम सिवाय अँगूठे इकट्ठे करने के और कुछ नहीं है। एक ऐसे देश में जहाँ साक्षरता का प्रतिशत विश्व के अन्य देशों की तुलना में अपमानजनक रूप से नीचा है और जहाँ की सरकार के पास प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने के लिए हमेशा बटुआ लग रहता है, वहीं पर जवाहरलाल नेहरू के नाम पर सिर्फ उच्चस्तरीय शोध के लिए एक आलीशान विश्वविद्यालय कैसे चल रहा है?

इस तरह यह सिद्ध हो जाता है कि शिक्षानीति में आमूल परिवर्तन की सारी सरकारी बातें मर्म विमुख हैं। उनकी प्रवचक प्रवृत्ति समझकर आमूल परिवर्तन की आवश्यकता की सही सन्दर्भ में परखने की अनिच्छा स्कूल के अध्यापक में महज इसलिए है क्योंकि उसकी स्वतंत्र चिन्तना की मौक़रगाही व राजनीति ने अभी अभ्यास का अवसर नहीं दिया। उसकी द्विचकिचाहट का सकल मनोविज्ञान से सम्बद्ध है, न कि कार्यकारी अक्षमता से। जैसाकि प्रायः सोचा जाता है। अपने हर कदम के लिए राजधानी के आदेश पर आश्रित रहनेवाला यह निरोह, सम्मानहीन प्राणी बाणों के छद्म स्वानय का जीवित अवतार है। वह अपनी सस्या में छात्रों की सस्या और अध्यापकों के चयन से लेकर पाठ्य-सामग्री के आकलन व स्कूल के दैनिक कार्यक्रम की नियोजना तक किसी भी मसले पर एक रस्ती भर स्वतंत्रता नहीं बरत सकता। उसके अस्तित्व की

यह सब क्यों पढ़ाते हैं। सही प्रश्न यह है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाये, यह चुनाव करने की आजादी क्या हमने अपने शिक्षकों को दी है ?

भाषा : इस सन्दर्भ में चर्चा का सबसे प्रचलित विषय भाषा रही है। देश के तय्यकथित 'पब्लिक' स्कूलों में—जिनसे नौकरशाही का एक बड़ा अंश अब भी तैयार होकर निकलता है—आरम्भ से ही शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी रहती है। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी को यह महत्त्व प्राप्त नहीं है। किन्तु वहाँ लगातार उपर्युक्त पाठ्यसामग्रियों की दरिद्रता की बात अत्यंत हीन स्वर में की जाती रही है। हिन्दी व अन्य प्रान्तीय भाषाओं में यदि अच्छी पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता सरकार समझती है तो उसकी राष्ट्रीय शिक्षण-सोष परिषद् अंग्रेजी में पुस्तकें तैयार करने में इतना धन व शक्ति क्यों व्यय करती है ? भूगोल, इतिहास, समाज विज्ञान जैसे विषयों पर परिषद् की अधिसूच्य पुस्तकें अंग्रेजी में ही तैयार हुई हैं और उसकी शिक्षण निर्देशिकाओं ने भी राष्ट्रभाषा को हेय समझा है। जहाँ तक अनुवाद का प्रश्न है, अब यह कहना आवश्यक हो गया है कि इस कला के वर्तमान रूप के सहारे कोई आशा लगाना व्यर्थ है। देश के डेरो भाषाविद् तथा विद्वद्जन आजकल अनुवाद की नोकरी पर ज़िन्दा हैं और उनके काम के लिए सरकार ने छूबमूरत इमारतें बनवा दी हैं। इनमें किये जा रहे अनुवाद स्वयं घातानुकूलित होते हैं। उनका भाषा की जीवत भाषा में कोई सम्बन्ध नहीं होता और उन्हें पढ़ने व समझने के लिए छात्र को लगभग उतनी ही भाषापट्टी करनी पड़ती है जितनी उसे अंग्रेजी में लिखी पुस्तकें पढ़ने के लिए करनी पड़ती—कभी कभी उससे भी अधिक। 'जनरल इन्फार्मेशन' की 'साधारण अर्थशास्त्र' लिखने वाले ये फुर्तले अनुवादक जितने वर्षों में भारतीय छात्र को विद्वत् के समकालीन ज्ञान-कोष तक घबेल पावेंगे, यह अज्ञात शायद उन्होंने स्वयं लगाया होगा। वरना इसकी और इनकी सहकर्मियों सम्भावनी निर्माताओं की प्राथमिक विन्यास अपने सेवाकाल की लम्बा करने की होती है।

असंलियत यह है कि ऐसे सारे महानुभाव, जो कक्षा से दूर अपने शीतल कमरों में हिन्दी को सम्पन्न बनाने में लगे हैं, सरकार के दलाल मात्र हैं। इनकी दलाली की वजह से 'अंग्रेजी हटाओ' आन्दोलन को एक फसली शक्ति मिली। जिस के सहारे सरकार ने अपनी अंग्रेजीपरस्त नीति और पुष्टा कर ली। अपेक्षा यह थी कि अंग्रेजी पहले प्रशासन से हटे, फिर शिक्षा से। शिक्षा में भी अंग्रेजी की दुहरी अहमियत समझने लायक थी—एक तो माध्यम के रूप में, दूसरे विषय के रूप में। निरसन्देह 'अंग्रेजी हटाओ' आन्दोलन की प्राथमिक मति यही थी कि

अंग्रेजी प्रशासन से हटे—केंद्र और प्रदेश दोनों में। प्रशासन से अंग्रेजी शायद हटी, किंतु मात्र औपचारिक रूप से, जबकि शिक्षा के क्षेत्र से कई प्रदेशों ने उसे व्यावहारिक रूप से हटा दिया। यह सब सब स्तुत्य होता जब यह एक राष्ट्रीय नीति के रूप में होता। इसके स्थान पर सरकारें यह कहती रही कि अंग्रेजी धीरे धीरे हट रही है जबकि धीरे-धीरे हटने का कोई अर्थ नहीं होता। नीति निर्णय की सफलता व अपनी भसमतसाहत का प्रदर्शन करने की नीयत से सरकार ने शिक्षा को बलि का बकरा बनाया और भूखतापूर्वक अंग्रेजी का नाम लेकर शिक्षा के मानदण्ड ही उखाड़ फेंके। जिन प्रदेशों में ऐसा हुआ वहाँ के बच्चे आज अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं जबकि उनके मावी जीवन में अंग्रेजी की जरूरत बरकरार है। मंत्रियों व अफसरों की औलाद 'पब्लिक' स्कूलों में अंग्रेजी जानकर अगली मौक़र-प्राप्ति का प्रमुख चटक यन्त्र की संपादना कर रही है जबकि मामूली आदमी की औलाद अंग्रेजी के अज्ञान को मुद्दा बनाकर उस मौक़र-प्राप्ति से लोहा लेने में धाये आदस पर पल रही है।

लिए प्रायः अनुसूचित समाज गया। बात वही वापस आ जाती है। स्कूलों अध्यापक आज भी सत्ता के भेद सिखाकर हिन्दीभाषी छात्र को अंग्रेजी के व्याकरण को पंगु कर देता है वरना दस वर्ष की अवधि आसानी से तीन वर्ष में बदल सकती है।

मतलब यह है कि अंग्रेजी की मानसिकता से मुक्त हुए बिना यदि कोई सरकार समाज के साधनहीन वर्ग के बच्चों को अंग्रेजी अव्ययन से मुक्त करती है, तो यह उसकी एक गैर-समाजवादी दुर्नीति भर है जिससे सभी को बाकिफ होना चाहिए। उसकी यह नीति बस्तुतः उस उपनिवेशी मानसिकता का अंग है जिससे वर्तमान भारतीय शिक्षा के जनक लार्ड मैकाले ने सन् १८३५ में त्रिनागरी सत्र में अपने भाषण के द्वारा भारतीय चिन्तन पर एक लम्बे समय के लिए छाप दिया था। मैकाले बस्तुतः भारतीय शिक्षा पर सागोपाग विचार करनेवाले प्रथम और अन्तिम आधुनिक विचारक थे और यह हमारा तत्कालीन शिक्षाविदों की कहिणी का सचूत है कि वे आज तक मैकाले की गालियाँ देने के सिवाय कुछ न कर पाये। मैकाले के बाद देश में या तो टैंगोर जैसे ममूनावादी हुए हैं जो दान्तिनिवेतन खोलकर बिनारे हो गये या फिर जवाहर जैसे पट्टनवादी नौकरशाह शिक्षाशास्त्री। इनमें से किसी में इतनी साबित नहीं थी कि मैकाले की लगायी हुई गाँठ खोल सकें। मैकाले ने कहा था कि हिन्दुस्तानी लोग अंग्रेजी के माध्यम से जब तक यूरोपीय ज्ञान का आश्रय नहीं करेंगे तब तक वे अपने पुराणपथी देश के भगवत पिंडप्रेम के सिवार बन रहेंगे। मैकाले के इन शब्दों के 'स्वदेशीय' जोश से टक्कर लेने लायक उत्साह हम शताब्दी में या तो गायी ने दिखाया या फिर लोहिया ने। पर इन शायों के समान गर्मदिल आश्रयों के बावजूद भारतीय शिक्षा की खानी सिविल लाइस के बासियों के हाथ से नहीं निकली तो नहीं निकली। क्या आश्चर्य है कि हमारी शालोम का उच्चतम लक्ष्य आज तक साहब की पदवी प्राप्त करना है और अच्छी नौकरी का मतलब खोबदाश की हैसियत समझा जाता है। जिन व्यूहों पर हमने मौलिक विचार व सुझाव देने का भार छोड़ा है, वे क्षणप्रतिक्षित नौकरशाही संगठन हैं, इनके प्रत्येक सदस्य ने अध्यापकी छोड़कर साहबी पद को, यह उनके प्रतिवेदनों के पहले पन्ने पर छपी नाम पद तालिम ॥ कोई भी देख सकता है।

देश के शिक्षापीढ़ी के इस संकटापन्न स्थिति का कोई उपचार निकट भविष्य में सरकार करेगी, इस आशा के लिए कोई सम्बल हमारे पास नहीं है।

पचतन की एक कहानी जो हम अपने बच्चों को पठाते हैं, वह है जिसमें सीधी-सादी मछली जाल में फँस जाती है जबकि तालाब छोड़ देनेवाली तथा मरने का स्वाग रचनेवाली मछलियाँ बच जाती हैं। शिक्षाजगत् का जागरूक सदस्य आज किसी मछली का आदर्श ग्रहण करेगा या फिर चौधो राह निकालेगा ? इस चौधो राह के निश्चय के लिए यह बहस उठायी गयी है। भाग लेनेवालों की सुविधा के लिए ऐस के आधारभूत तर्क पुनः प्रस्तुत हैं

(क) शिक्षायो क्रांति पर सार्थक चिन्तन का पहला चरण यह होना चाहिए कि भारतीय शिक्षा की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या कॉलेज या विद्वविद्यालय न होकर स्कूल हो।

(ख) देश के राजनीतिज्ञों तथा शिक्षा विभाग की नौकरशाही से किसी आमूल परिवर्तन की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन के मूल में उही की नियति निहित है।

(ग) बच्चों के शिक्षक की आर्थिक स्थिति से विमुक्त शिक्षायो क्रांति की कोई चर्चा सार्थक नहीं हो सकती।

(दिनमान, २० अगस्त, ७२ से साभार)



सूचना

पाठकों को सूचित किया जाता है कि सफ़द बाग़ की महेंगई एवं छपाई आदि की दरी में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण वर्ष २१ अक्त १ माह अगस्त '७२ से नयी तालीम मासिक का वार्षिक चढ़ा ६ रुपये के स्थान पर ८ रु० और एक प्रति का मूल्य ५० पैसे के स्थान पर अब ७० पैसे हो गया है कि हमें आशा है पाठकगण हमारी विवशताओं को ध्यान में रखते हुए अपना अधिकाधिक सहयोग पूर्ववत् प्रदान करते रहेंगे।

—सम्पादक

दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव

[गत जून, ७२ में गुजरात के चारदाग्राम नामक नयी तालीम केन्द्र में भविल भारत नयी तालीम समिति की बैठक के साथ साथ गुजरात राज्य का नयी तालीम सम्मेलन भी आयोजित किया था। उक्त सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। उनमें से दो प्रस्ताव भविल भारतीय महत्त्व के हैं, जिन्हें हम नयी तालीम के पाठकों की जानकारी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।—स०]

उच्च शिक्षा में परिवर्तन

प्रस्ताव नं० ४ . हमारी उच्च शिक्षा की सस्थाएँ विद्यार्थियों को स्वायत्त परिश्रमी, आत्मविश्वासयुक्त और अपनी समस्याओं को अपनी धूम्रदूम से हल कर सकें, ऐसा नहीं बना पायी हैं। फलस्वरूप शिक्षित युवक भापूनी नौकरी खोजते, हुआग का अनुभव करते और बेरोजगारी के कारण कमी-कमी असामाजिक प्रवृत्तियों की ओर मुड़ जाते हैं। उच्च शिक्षा को, ध्येयवशी बनाने तथा राष्ट्रपयोगी तालीम-बद्ध युवक तैयार करने वाली प्रवृत्ति के रूप में बनवाने का निश्चय हो सके, तो शिक्षा के लिए खर्च होनेवाली शक्ति, समय और धन का अधिक लाभकारी उपयोग हो सकेगा।

पू० बापूजी ने नयी तालीम की ओ शिक्षा सूचित्र की थी, उसने इतने सालों के यत्नवित् प्रयोगों ॥ यह सिद्ध कर दिखाया, कि शिक्षा की यह पद्धति सर्वांगी विकासोन्मुख मानव बनाने में काफी सफलता प्राप्त करती है। इस तालीम के तरीके को उच्च शिक्षा में व्यापक बना सकें, तो हमारी औद्योगिक समस्या को हल करने में काफी मदद मिल सकती है। इस दृष्टि से उच्च शिक्षा का औद्योगिक समाज से अनुबन्ध आवश्यक है।

(१) समानोपयोगी अनुकूल उद्योग और परिश्रम के लिए हर रोज कम से कम २ घण्टे देने से धुसजाव की जाय।

(२) उच्च शिक्षा की नयी सस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जायें।

(३) इन समस्याओं में शिक्षक-विद्यार्थी सम्पर्क सजीव रह पाये इतनी समस्या की मर्यादा रखी जाय ।

(४) उच्च शिक्षा आर्थिक दृष्टि से अधिक भाररूप न हो जाय, इसका ध्यान रखकर, कार्यक्षमता बनी रहे, इतना कार्यभार व्यापकों को उठाना चाहिए ।

(५) धैर्य श्रेष्ठ समाज की आर्थिक स्थिति की मर्यादा को ध्यान में रखकर निश्चित हो ।

(६) राज्य उठा सके, इतना विशेष बोझ वह उच्च शिक्षण में भी उठाने और इस तरह समस्याओं का बोझ घटाकर उनको व्यापारी बनने से रोकने में सहकार दे ।

माध्यमिक शिक्षा दूरी करने के बाद सभी विद्यार्थियों को विद्यापीठ में जाकर केवल साहित्यिक और तार्किक शिक्षा प्राप्तकर सिर्फ मामूली क्लर्क की नौकरी के लिए मारे-मारे फिरने से बचना चाहिए ।

समाज के लिए आवश्यक उद्योगों की निम्न-मिश्र कक्षाओं की तालीम के लिए थोड़े पैमाने पर व्यवस्था करके विद्यार्थियों को उस ओर आकर्षित किया जाय, और इस तरह की तालीम देकर समाज के लिए अनेक दृष्टियों से उपयोगी नागरिक तैयार करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

नयी तालीम की स्थापना गांधीजी के बताये हुए मार्ग पर इस प्रकार की उच्च शिक्षण की स्थापना करने और उन्हें व्यापक करने में पहल करे, और उच्च शिक्षण की समस्याएँ, समाज तथा राज्य इस दिशा में कदम उठायेँ, ऐसी अपेक्षा यह सम्मेलन रखता है ।

नयी तालीम के प्रादेशिक संघ

प्रस्ताव न० ५—गुजरात में नयी तालीम सघ यद्यपि विविध क्षेत्रों में काम कर रहा है तथापि उसे बहुत-सी दिशाओं में विकास जारी रखना है, यह सम्मेलन ऐसी अपेक्षा रखता है ।

भारत के सभी प्रदेशों में सभी अपने-अपने प्रादेशिक नयी तालीम सघ अस्तित्व में नही आये हैं, इसलिए वहाँ इस प्रकार का विकास-कार्य दिखायी नहीं पड़ता । यह सम्मेलन मानता है कि भारत के सभी प्रदेशों में नयी तालीम में बढ़ा चलनेवाले व्यक्ति और मण्डल मिलकर अपने प्रदेशों में नयी तालीम सघों की स्थापना करें ।

अखिल भारतीय क्षेत्र में सर्वप्रथम 'हिंदुस्तानी तालीम सघ' अस्तित्व में था, अब नयी तालीम को चारों ओर से प्रोत्साहन मिलता था। बाद में सर्व सेवा सघ को अखिल भारत नयी तालीम समिति यह कार्य कर रही है। इस समिति को सभी प्रदेशों से प्रतिनिधित्व युक्त सघ में परिवर्तित किया जाय तो देश में नयी तालीम का आन्दोलन अधिक गतिमान होगा, ऐसा यह सम्मेलन मानता है, और नयी तालीम समिति के समस्त अपना अभिप्राय आदरपूर्वक विचारार्थ पेश करता है। सभी प्रदेशों में प्रादेशिक सघों की स्थापना करने का प्रयत्न करना उपरोक्त अखिल भारतीय नयी तालीम समिति का स्वाभाविक कार्य है, ऐसा यह सम्मेलन मानता है। उक्त समिति इस प्रकार के प्रादेशिक सघों का सघ बनवा फडरेसन का स्वरूप ले, ऐसा उसे सम्मेलन का सविनय सूचन है।

सेवाग्राम में अखिल भारत राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन

नयी तालीम समिति (सर्व सेवा सघ) और शिक्षा मण्डल वर्धा के समुक्त तत्वावधान में अखिल भारत राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन सेवाग्राम में दिनांक १४, १५ और १६ अक्टूबर १९७२ को सम्पन्न होगा। सम्मेलन में उन महत्वपूर्ण शैक्षणिक समस्याओं की ओर, जो आज राष्ट्र के सम्मुख हैं, ध्यान खींचा जायगा। बुनियादी शिक्षा के शिक्षक, सर्वोदय विचार के उक्त, शिक्षण के काम में लग हुए रचनात्मक कार्यकर्ता और गांधीजी द्वारा बतायी गया शिक्षण पद्धति में जो लोग रुचि रखते हैं, उन सबको सम्मेलन में भाग लेना आमंत्रित किया जाता है।

केन्द्र व राज्यों के शिक्षामंत्री, विश्वविद्यालयों के व कुछ अन्य सुप्रसिद्ध शिक्षा दार्शनिकों को भी अर्चवियों में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायगा। इस सम्मेलन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया जा रहा है। श्री श्रीमन्नारायण, राज्यपाल, गुजरात, सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।

अन्य जानकारी के लिए कृपया निम्न पते पर पत्र-व्यवहार करें,

के एस आचार्य
मंत्री, नयी तालीम समिति सेवाग्राम,
वर्धा, महाराष्ट्र

फिलिपीन्स में स्वावलम्बी शिक्षा के स्कूल

[पेट्रो टी० ओराटा फिलिपीन्स में बैरियो (ग्राम) शिक्षा बान्दोलन के संस्थापक हैं, जिसका उन्होंने इस लेख में वर्णन किया है । इस साल उन्हें २१ वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में नये तत्त्वों द्वारा सार्वजनिक सेवा करने के उपलक्ष्य में मैक्मेने पुरस्कार दिया गया है । (रेमान मैक्मेने फाऊन्टेन, फिलिपीन्स का भौर से दिये जाने वाले ये पुरस्कार, जिन्हें अक्सर एशिया का नॉबेल पुरस्कार कहा जाता है, सार्वजनिक सेवा के लिए एशियाई नेताओं को दिया जाता है ।) डा० ओराटा सन् १९५० से १९६० तक यूनेस्को के शिक्षा-विभाग के सदस्य थे और अब फिलिपीन्स के शिक्षा सचिव के अवैतनिक विशिष्ट सहायक हैं । उन्होंने विकासशील देशों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर विस्तारपूर्वक लिखा है ।]

स्वावलम्बी शिक्षा के इन अभिनव प्रतिष्ठानों में एक ओर ग्राम माध्यमिक स्कूल, पढ़ाई शुरू करने से पहले के स्कूल, साम्प्रदायिक वाचैज और अनेक कक्षाओंवाले स्कूल हैं, तो दूसरी ओर अधिक उन्नत जीवन के लिए विज्ञान और समाजशास्त्रों का अध्ययन कराना, विद्यार्थियों को चिन्तन मनन की प्रिया, मूल्यों की परख करना, अपनी फीस और स्कूल के अन्य खर्च पूरे करने के लिए काम करके धन कमाना, आदि सिखाना और व्यवहार्य अनुमगान कार्य के लिए शैक्षिक नेताओं को प्रशिक्षित करना है ।

दूसरे महायुद्ध के दौरान घादों पर परियोजनाएँ सन् १९४५ में शुरू की गयी थी । प्रान्तीय राजधानियों से बाहर पनसीवान के उरदनता स्थान पर, एक छत-विहीन गिरजाघर में पहला हाईस्कूल खोला गया । न किताबें थी, न कागज-पेंसिल और न अध्यापकों को वेतन देने के लिए कोई रकम ही ।

उद्देश्य यह था कि हर लड़के और लड़की को स्कूल में शिक्षा पाने का अवसर देने के लिए स्कूल को उनके घरों के इतने नजदीक ले जाया जाय, जहाँ वे आसानी से चलकर आ सकें, और नयी योग्यताओं के विकास से अपने कामों या क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ाने में, (अपनी दैनंदिन शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में) उनके पालकों की मदद कर सकें ताकि वे अपने स्कूलों का स्वर्थ उठाने में समर्थ हो सकें ।

लोग जिस अवस्था में थे, उनके पास जो भी था, स्कूल खोलने के लिए जो भी साधन-सुविधाएँ भूगृह थीं, शिक्षकों और प्रबन्धकों के रूप में जो लोग उपलब्ध थे, जो भी छात्रों सामान मिल सकता था, हमने उसको ही जुटाकर एक वक्त में केवल एक या आधा कदम ही आगे बढ़ना शुरू किया । इस काम में लोगों ने जुद्ध योग्यताएँ बनाने, फैसले करने और उनको कार्यान्वित करने में मदद की ।

अगर हम इस बात का इतजार करते कि पहले सब चीजें उपलब्ध कर दी जायें—इमारतें, पाठ्य-पुस्तकें, वैज्ञानिक उपकरण, योग्य-अध्यापक, आदि—तो आज उन १५०० हाईस्कूलों, ४५ सामुदायिक कालेजों और ५०० पूर्ण स्कूलों में जो २५,००० बच्चे और युवा पढ़ रहे हैं, वे स्कूल में दाखिल होने का मौका पाने के लिए अब तक इतजार में ही बैठे होते ।

हमने अतिरिक्त अनुदान, उपकरण और प्रबन्धकों की माँग से दुःखीत नहीं की, बल्कि जो भी उपलब्ध सुविधाएँ थीं, उनका हमने भरसक और भी अच्छा उपयोग किया । कुछ मामलों में तो हमारे पास काम शुरू करने के लिए कुछ भी

नहीं था, लेकिन जो हम सोचते थे कि किया जाना चाहिए, उसको करने का मन में सक्षम था, इसलिए हम जो कर सके, किया।

इस सकारात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य यह था कि फिलिपीन्स और शायद अन्यत्र भी प्रचलित उस सामान्य प्रथा के चक्र में फँसने से बच सकें, जिनके अनुसार कोई नया काम करने की शुद्धात समस्याओं और कठिनाइयों को एक लम्बी सूची पेश करने से की जाती है, जिसके बाद हर व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है, और किसी को काम शुरू करने की हिम्मत नहीं पड़ती। हमने ओ किया, उसका मतलब यह था कि यह सुनने के बाद कि लोगों ने अनेक उपयोगी और अच्छे काम पहले से ही कर रखे थे, उनमें अगले कदम उठाने का उत्साह पैदा हो जाता था। इस दृष्टिकोण की सीमाएँ हो सकती हैं, लेकिन कई फायदे भी हैं। लोगों में आगे बढ़ने का उत्साह पैदा होता है, कुठार और निराशा-ग्रस्त मन से काम शुरू करने की अपेक्षा उत्साह भरे मन से काम कर पाने में उन्हें ज्यादा अच्छा महसूस होता है।

हमने हर परिस्थिति का यह जानने की दृष्टि से जायजा लिया कि कितना ज्ञान (स्थानीय और विदेशी), सुविधाएँ और साधन उपलब्ध थे ताकि उनका उपलब्ध साधनों के रूप में पूरी तरह या अंशतः अतिरिक्त कक्षाएँ खोलने, प्रयोग करने, काम-चलाऊ तौर पर आवश्यक उपकरण तैयार करने, सेमिनार और वर्कशॉप चलाने आदि के लिए इस्तेमाल कर सकें।

जहाँ कुछ समय उपयोग के बाद कमरे खाली रहते थे वहाँ स्कूल लगाये गये। घरों की किफायती शोपट्रियो, दूकान और बगीचे के भीजार और उपकरणों यहाँ तक कि स्कूल के बगीचे का भी उस समय इस्तेमाल किया जा सकता था, जबकि नियमित कक्षाओं के लिए उनकी जरूरत नहीं रहती थी और जो रोज़मर्रा के स्कूल-समय का थोड़ा बचत हो लेने थे।

फिलिपीन्स में ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की काफी बड़ी संख्या है, जो बेकार हैं। अतिरिक्त कक्षाओं को पढ़ाने के लिए हमने उनका इस्तेमाल किया। वहाँ ऐसे अध्यापकों की संख्या भी काफी है, जो या तो प्रशिक्षण प्राप्त हैं या थोड़े से अतिरिक्त प्रशिक्षण के बाद योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। वे इन कक्षाओं को पढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें मामूली सा पारिवर्तिक दिया जाता है ताकि वे अपने अपर्याप्त नियमित वेतन में कुछ जोड़ सकें।

पढ़ने से मीज़ूद प्राथमिक या हाईस्कूल लाइब्रेरियों का ही हमने प्रयोग किया, केवल उनमें आवश्यक नयी पुस्तकें भी जुटा दी।

स्कूलों, अस्पतालों, दवाई को दूधानो और विद्यार्थियों के घरों में ऐसी असह्य चीजें होती हैं जिन्हें रहो समझ कर फेंक दिया जाता है, जैसे विजली के जले बल्ब, खाली डिब्बे और बोतल, घिसे फटे टायर और ट्यूब, टूटे शीशे, मकई का छालन, बाँस और लकड़ियाँ आदि। इन सब चीजों का इस्तेमाल हाईस्कूल और कालेजों के लिए कामचलाऊ ढंग के वैज्ञानिक उपकरण तैयार करने और पूर्वस्कूल के बच्चों के खेल का सामान तैयार करने के लिए किया गया।

आमतौर पर स्कूल का प्रिंसिपल या जिले का सुपरवाइजर, सांकेतिक बेलन लेकर ही हाईस्कूल, यूथस्कूल या कालेज के सहायक प्रिंसिपल या अध्यापक के रूप में अतिरिक्त कक्षाओं का प्रबन्ध चलाते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि (अतिरिक्त खर्च के बिना ही) प्राथमिक, यहाँ तक कि हाईस्कूल और कालेज तक के बीच एक अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करनेवाली प्रक्रिया चल पड़ी, जो फिलिपीन्स में तथा अन्य देशों में भी स्कूल-प्रशासन का सबसे जरूरी लक्ष्य है।

उतना ही महत्वपूर्ण कार्य अन्य देशों के अनुभव का इस्तेमाल करना था, जिन्हें समान परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। स्विटजरलैंड, इजरायल और सिंगापुर में शिक्षाविदों ने भाषा-समस्या का हल निकालने के लिए क्या किया था? बर्मा, थाईलैंड, फिजी भारत, आस्ट्रेलिया में शिक्षा की विषय-वस्तु को लोगो की, विशेषकर गाँवों में, समस्याओं और जरूरतों से जोड़ने के लिए क्या किया गया है और क्या किया जा रहा है?

विदेशों अनुभव की नकल नहीं की गयी, बल्कि जैसे जैसे समस्याएँ उठती गयी, उनको उनके अनुरूप ढाला गया। अगर ऐसा न किया जाय, तो सम्भवतः यह हाजा—और कुछ स्थानों पर इस समय हो रहा है—कि एक दिन उन गलतियों को भी दुहराया जाता है जो कहीं और हुई थीं, बजाय इसके कि उन गलतियों से सीखें।

अध्यापकों के वेतन, पाठ्यपुस्तकों, लाइब्रेरी की किताबों और दूसरी जरूरी चीजों का कैसे प्रबंध किया गया, इन स्थितियों में हमें फिर धारों ओर नज़र उठाकर देखना चाहिए कि आखिर कुछ न कुछ साधनों से शुरु करके भी प्राइवेट स्कूल और कालेज स्थापित किये जाते रहे हैं, चलते हैं और अपने खर्च निकाल कर काफी मुनाफा भी कमा लेते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल कालेज ऐसा कर सकते हैं तो पहले से प्राप्त अनेक सुविधाओं के बावजूद बिना लाभ के आधार पर नये बसास क्यों नहीं चलाये जा सकते?

विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को अपने सेत या फार्म में अधिक से-अधिक

पैदा करके अपनी आमदनी बढ़ाने में, या कोई नया व्यापार या काम शुरू करके कुछ अतिरिक्त पैसा बचाने में मदद की जाती है। यह सब पाठ्यक्रम से बाहर का काम नहीं है बल्कि विद्यार्थियों को जिन्दगी के लिए और खुद अपना काम शुरू करने के लिए तैयार करने और उनके अभिभावकों की उपयोगी शिक्षा जारी रखने के लिए, जिन्हें अपने अंदर नयी समझों का विकास करने के उपलब्ध में योग्यता प्रमाण पत्र दिया जा सकता है स्कूल के पाठ्यक्रम का ही अंग बना दिया गया है। अपने आपको तथा अन्य लोगों को मदद के लिए ये काम करने पर विद्यार्थियों को हाईस्कूल या कॉलेज की शिक्षा का श्रेय दिया जाता है।

वनस्पति उद्योग और पशु उद्योग के व्यूरो, पी० ए० सी० डी० और एन० सी० आई० डी० ए० तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के प्रसार कमचारियों से परामर्श किया जाता है और उनकी सहायता मांगी जाती है, ताकि विद्यार्थी और उनके पालक नये कीमती और दृष्टिबोधनीय चीजें सकें जिनकी उन्हें जरूरत है। अनिवार्य यह सहायता पुस्तक में सहर्ष प्रदान की जाती है।

उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी को अगर सूअर का नन्हा-सा बच्चा दिया जाता है और कहा जाता है कि वह उसे पाल पोस कर बड़ा करके के बाद बचकर मुनाफा कमा सकता है और अपनी पीस और अन्य ज़रूरतों के पैसे निकाल सकता है तो साथ ही इस काम में उसका आग्रह भी किया जाता है, जो उसकी पहचान का अंग होता है। उसे दिखाया जाता है कि सूअर के बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए उसका भोजन कैसे पैदा करना चाहिए, बीमार पड़ने पर क्या करना चाहिए बीमार पड़ने से रोकने के लिए उसे किस तरह टीके लगाने चाहिए और कहा जाता है कि सूअर को बेचने के बाद उसे सूअर के बच्चे की मूल कीमत ६ प्रतिशत का मुद्रा जोड़कर, आवर्ती फंड को या उस व्यक्ति को लौटा देनी चाहिए, जिसने उसकी खरीद में मदद की थी।

यह हमारा सीमांत था कि आरम्भ से ही, और फिर लगातार, हमें बाहर से थोड़ी थोड़ी मदद मिलती रही है। इनमें विदेशी एजेंसियाँ भी शामिल हैं—ब्रिटिश (ग्राम) बुक फाउण्डेशन, एशिया फाउण्डेशन, यूनीसेफ यूनिस्को (कूपन स्कीम), पी० ए० सी० डी० तथा अन्य जिन्होंने पाठ्यपुस्तकों खरीदने के लिए छोटी-छोटी रकम अनुदान के रूप में दी, ताकि वह सस्ते दामों पर ग्राम हाईस्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों को बच सकें, विज्ञान और खेल कूद के सामान्य सामान तैयार कर सकें और शिक्षा का निर्देशन करने का प्रबंध कर सकें।

इस प्रकार पिछले सात वर्षों में, सरकार पर खर्च का भार ढाले बिना ही,

या नाम मान मार डाल कर ही, हम ढाई लाख से अधिक बच्चों को ग्राम-स्कूलों, सामुदायिक कालेजों और पूर्व स्कूलों में दाखिल कर सके हैं। ये परियोजनाएँ क्रमशः सन् १९६४, १९६६ और १९६९ में शुरू की गयी थी।

इस सच हम लोग फिलिमोन्स के सबसे दूर बसे गाँवों के लिए कई दर्जों वाले स्कूल (अर्थात् ऐसे स्कूल, जिनमें एक ही अध्यापक के अन्तर्गत पहले से लेकर छठे दर्जे तक की पढ़ाई होनी है) खोलेंगे। अगर इस परियोजना को पूरी तरह चालू कर सके तो इससे करीब दस लाख से ज्यादा ऐसे बच्चों को लाभ होगा।

इसका यह अर्थ नहीं कि घन जितना भी अधिक प्राप्त हो सके, आवश्यक नहीं है। निश्चय ही उसकी जरूरत है और जितना ही ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। लेकिन घन ही सब कुछ नहीं है। कल्पना प्रवण, निस्वार्थ और निष्ठावान नेतृत्व की जरूरत है, जो उससे बेहतर काम करके दिखा सके, जो वर्तमान साधनों, सुविधाओं, साजो-सामान और शिक्षकों, प्रबन्धकों के द्वारा किया जा रहा है।

इसके अलावा, जरूरत भर की अनिश्चित रकम खुद आम लोगों से ही प्राप्त हो सकती है, जो जीवन पर्वत चलने वाली अपनी शिक्षा की खातिर दे सकते हैं और अगर, संयोगवश, सरकार के पास भी देने के लिए कुछ राशि हो, तो उनका इस्तेमाल आवर्ती-फंड कायम करने के लिए किया जा सकता है, ताकि उससे विद्यार्थियों और उनके पालकों के लिए काम की नयी परियोजनाएँ शुरू की जा सकें।

स्थापित नये परिवर्तन अकसर अत्यन्त महँगे पड़ते हैं। इतना ही नहीं, नयी मशीनें लगा लेने के बाद वे अकसर बेकार पड़ो रहती हैं, क्योंकि किसी को इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि उनकी किस तरह चलाना चाहिए और एक बार अगर खराब हो जायें तो उनकी मरम्मत कैसे करनी चाहिए। शिक्षा के जरिये, हर मुमकिन काशिश करनी चाहिए कि ऐसे नये साधनों के विकास को ही प्रोत्साहन दिया जाय जो कोमती न हों, और देश जिनका खर्च उठा सके। यह ज्यादा अच्छा है कि जरूरत की कुछ-कुछ मशीनें और साजो-सामान खुद तैयार किया हुआ कामचलाऊ ढंग का हो। हमने ऐसा ही किया, पहले विज्ञान की शिक्षा में, फिर समाज-विज्ञानों की पढ़ाई में, पूर्व स्कूल में, व्यावहारिक कलाओं में और परेलू अर्थशास्त्र आदि में।

इस तरह का कामबलाक साजो-सामान बनाने में बच्चे अकसर कुछ काम घर पर भी ले जाते थे, जहाँ अनिवार्यतः उनके माँ बाप और दूसरे बच्चे भी उनकी मदद करते थे, जिससे उन्हें भी लाभ होता था। इसके अलावा कुछ चीजें जैसे, लेम्प और तोन्ने की तराजू आदि का घरों में भी उपयोग होता है। अकसर गृहस्थों को बाजार में ठम लिया जाता है, जहाँ तौलने की मन्दीनो और नापने के गजों में कुछ-न-कुछ गड़बड़ कर दी जाती है।

हमने उन कामों से ही आरम्भ किया जिनका करना प्राप्त सुविधाओं और करनेवालों के देखते हुए सम्भव था। इसके बाद उन कामों को हाथ में लेने के लिए काफी धन मिल गया, जिनके लिए अधिक पैसों, समय और परिश्रम की जरूरत थी। हमने महसूस किया कि शुरू में हल्के और आसान काम, जिनके लिए अतिरिक्त पैसों या बाहरी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती, सफलतापूर्वक कर लेना कठिन और बड़े काम शुरू करने के लिए अच्छी तैयारी साबित होते हैं।

शिक्षा की प्रासंगिकता और गुणात्मकता बढ़ाने के बारे में क्या किया जा रहा है? इन दिशाओं में हम अभी तक ज्यादा आगे नहीं जा सके, लेकिन हमने कुछ अगले कदम जरूर उठाए हैं।

हमने विज्ञान की पड़ाई वैज्ञानिक तथ्यों को रटकर याद करने और वैज्ञानिक सिद्धान्तों को स्थापकृत 'प्रक्रिया' या अन्वेषी दृष्टिकोण' द्वारा खोजने की सीमा से आगे बढ़ाया है। हमने पूछा "एक वैज्ञानिक विद्वान खोज लेने के बाद, फिर क्या?" हम दो कदम आगे बढ़े—पहला कदम, हमने विद्यार्थियों को इस ओर उन्मुख किया कि वे उस सिद्धान्त का अत्यन्त सरल और व्यावहारिक टगो से प्रयोग करें-बोने के लिए धीज धुन या एक बामगर कुएं से बाँसों की नाली द्वारा सिफार्द की व्यवस्था करने जैसे कामों में; और दूसरा कदम, हमने उन्हें निर्देशन दिया कि अपनी जानकारी और वैज्ञानिक सिद्धान्तों को लागू करने से प्राप्त लाभ में वे अपने सहपाठियों और पड़ोसियों को भी साक्षीदार बनायें।

हमने विज्ञान के विद्यार्थियों की कामबलाक वैज्ञानिक साजो-सामान बनाने के काम का निर्देशन दिया, ताकि पैसा बना सकें, जो जैसे भी उपलब्ध नहीं था, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, ताकि विज्ञान की शिक्षा उनके लिए अधिक अर्थपूर्ण, दृष्टिकर और साथ ही उपयोगी बन सके। मिसाल के लिए, स्विट्जरलैंड में पढ़े बनानेवाले विद्यार्थी अपने चार साला बोर्स का पहला साल सिर्फ, उन औशरों के बनाने में लगाते हैं, जिनसे घटिया बनायी जाती है, और यह 'काम करते हुए' प्रशिक्षण पाने का तरीका है।

सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम इसलिए बनाया गया ताकि विद्यार्थी उन तरीकों और साधनों की खोज कर सकें, जिनसे वे अपने आपको अपराधी बनने या अपराधियों के शिकार बनने से बचा सकें। उन्होंने सिर्फ, यही नहीं सीखा कि अच्छा आचरण क्या होता है बल्कि उन्होंने अच्छा आचरण करने का अभ्यास भी किया। इसके अलावा, उन्होंने अपनी जानकारी में सहपाठियों और पड़ोसियों को भी साक्षीदार बनाया।

हमने पहली जमात से ही, बल्कि पूर्व स्कूल के समय से ही, बच्चों को सिखाया कि वे सोच विचार करके और मूल्यों को परख करके कार्य करें। हमने नशा और समुदाय में, बस, सड़क की पटरी आदि में वास्तविक जीवन स्थितियों का इस्तेमाल किया, और हमने पाठ्यपुस्तकों में वर्णित परिघटितियों को उनके अंदर सोपने और सोचकर अमल करके की रक्षा देने के लिए इस्तेमाल किया।

हमें अभी बहुत आगे तक जाना है। लेकिन हम यंत्रसूत्र करते हैं कि एक निस्वार्थ, निष्ठावान और कल्पनाशील नेतृत्व की उतनी ही जरूरत है, जितनी धन की और कुछ मामलों में तो धन से भी ज्यादा। अगर धन उपलब्ध हो तो अच्छा, लेकिन हम धन के लिए रुके नहीं रहे। अगर रुक जाते तो अब तक इन्तजार ही करते रहते। आश्चर्य की बात है कि सरकार ने जब हमारे काम के इतने अच्छे परिणाम देखे, तो उसने रकम देने का प्रस्ताव किया और अब विदग्धता यह है कि हाईस्कूल तक मुक्त पढ़ाई का प्रबन्ध करने की कोशिश की जा रही है। यह गलत बात होगी।

यूनेस्को कूरियर : से साभार पुनर्मुद्रित



सम्पादक मण्डल :

श्री घोरेंद्र मजूमदार प्रधान सम्पादक

वर्ष : २९

श्री वंशोधर श्रीवास्तव

अंक : १

आचार्य राममूर्ति

मूल्य : ७० पैसे

अनुक्रम

युवको का भी सरकारीकरण	१ सम्पादकीय
शिक्षा जगत में समस्त इस युग की चुनौती	३ श्री घोरेंद्र मजूमदार
जीवन की बुनियादें	६ मार्जरी साहस
अहिंसा की शक्ति प्रकट करने का	
एक दार्शनिक प्रयोग	१४ श्री चारु चौधरी
शिक्षा : आज का स्वरूप एवं	
कल की कल्पना	१७ श्री मोती लाल शर्मा
अनुशासनहीनता का उपचार : एक योजना	२३ श्री दिनेशचन्द्र भारद्वाज
शिक्षा की अन्तिम का अर्थ	२६ श्री कृष्ण कुमार
दो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव	३७
फिलिपीन्स में स्वावलम्बी शिक्षा के स्कूल	४० श्री पेद्रो टो० ओराटा

अगस्त, १९२



- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्द्रा आठ रुपये है और एक अंक के ७० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट, द्वारा सर्व स्रेष्ठ संघ के लिए प्रकाशित;
अनुपम प्रेस, के. २९/३० दुर्गाघाट, वाराणसी में मुद्रित

सर्वोदय विचार के प्रसारण में श्री गांधी आश्रम का स्तुत्य कार्य

आषाढे कृपालानी के संचालन में श्री गांधी आश्रम लगभग १४ वर्ष से खादी के माध्यम से जनता की जा सेवा कर रहा है, वह किंगो से छिगा नहीं है। आश्रम श्री गांधी आश्रम का प्रधान कार्यालय सज्जन में है। मेरठ, सहारनपुर, आगरा, मुरादाबाद, अमृतसर, अकबरपुर, केरना, मगहर और प्रयाग, इस प्रकार ६ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, कश्मीर और असम राज्यों में भी आश्रम का काम चलता है। १९७१-७२ को कुल उत्पत्ति करीब ५ करोड़ रुपये की है और बिक्री ११ करोड़ रुपये की। आश्रम का काम २० हजार गांधी में चलता है। ७२४ उत्पत्ति-केन्द्र एवं ४०३ बिक्री-भण्डार हैं। कस्तिन १ लाख २३ हजार, बुनकर ८ हजार, अन्य कारीगर ५ हजार व कार्यकर्ता ३१००, कुल १ लाख ४० हजार लोगों को आर्थिक व पुरी राजी मिलती है।

यभी श्री गांधी आश्रम की वार्षिक सभा गत २२ से २४ अगस्त को मुजफ्फरनगर में आश्रम के प्रधानमंत्री श्री विजय नारायण शर्मा की अध्यक्षता में हुई। उसने सर्वोदय-साहित्य-विप्री में पुरी ताकत लगाने का संकल्प किया गया और आश्रम-कार्यकर्ताओं ने अपील की गयी कि ये स्वयं गो सर्वोदय-साहित्य का अध्ययन करें ही, प्राहकों का भी अधिक-से-अधिक माहित्य है। श्री गांधी आश्रम ने साहित्य-प्रचार के लिए खास रियायती का ऐलान किया है :

(१) हर खादी के खरीददार को, जितने की खादी खरीदेगा, उतना मान्य साहित्य भाषी कीमत पर दिया जायगा।

(२) सर्वोदय-साहित्य-मेट, जिसमें ११ रु० का साहित्य है, वह ४ रुपये में हर खादक को दिया जायगा। इसके लिए खादी-खरीद का बन्धन वार्षिक-स्वर्ण-जयंती तक नहीं रहेगा।

सर्वोदय-साहित्य-मेट में वे पुस्तकें रहती हैं — (१) आत्मकथा . गांधीजी, (२) बापू कथा, (३) तीसरी जंकि - विनोबा, (४) गीता प्रवचन, और (५) मेरे सपनों का भारत या अन्य साहित्य २ रुपये मूल्य का। इस प्रकार ११ रुपये की ११०० पृष्ठों की ये ५ किताबें केवल चार रुपयों में दी जायेंगी। साहित्य पर दी जानेवाली रियायत का पूरा शार श्री गांधी आश्रम का प्रधान कार्यालय उठायेगा।

श्री गांधी आश्रम के इस स्तुत्य निर्णय के लिए हम उसे बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि उनके विभिन्न केन्द्रों के व्यवस्थापक साहित्य प्रचार के कार्य में दिनचर्या लेकर इसे आगे बढायेंगे।

—राधाकृष्ण बजाज
अध्यक्ष

सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

आवरण मुद्रक : सण्डेलवाल प्रेस, मानमन्दिर, वाराणसी-१

नयी तालीम

सर्व-संघ की भासिनी

वर्ष • २१

अंक २

सितम्बर, १९७२



नित्य नयी तालीम के अद्वितीय साधक : विनोबा

दिये गये थे उनमें सबसे महत्त्व का काम यही था। परन्तु स्थानीय निकाय इस अधिकार का सदुपयोग नहीं कर पाये और बहुत शीघ्र इन प्रारम्भिक स्कूलों के शिक्षक स्थानीय निकायों की राजनीति में फँस गये। ये अध्यापक ही देहातों के बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि थे। अतः इन निकायों से सम्बन्धित जो चुनाव होने लगे उन चुनावों में इनका रोल महत्त्व का होने लगा। स्थानीय निकायों के चुनावों के "एजेण्डा" बनकर ये अध्यापक अध्ययन-अध्यापन के अपने स्वधर्म से द्युत हो गये। अध्यापक समय से स्कूल नहीं जाते, घर पर रहते, रोती कराते या दूसरे धन्वे करते। शिक्षा विभाग की ओर से नियुक्त निरीक्षक अगर अध्यापकों को उनकी कर्तव्य-विमुखता के लिए दण्ड भी देना चाहते तो स्थानीय निकायों के सदस्य उनको ऐसा करने से रोकते। स्वतंत्रता के बाद स्थानीय निकायों के अध्यक्ष आदि के चुनावों का महत्त्व जय बढ़ गया तो निरीक्षकों की परवशता भी बढ़ गयी, और प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासन और भी कमजोर और निकम्मा हो गया। फलतः स्थानीय निकायों के निष्क्रमे प्रशासन को समाप्त करने की माँग बढ़ी।

२. थोड़े ही दिनों में निकाय के सदस्यों के छोटे-मोटे स्वार्थ प्रधान हो गये और निकाय अपने कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं करने लगे। अध्यापकों को वेतन देने के लिए सरकार से जो धन मिलता था स्थानीय निकाय उनका भी दुरुपयोग करने लगे। अध्यापकों को समय से वेतन नहीं मिलने लगा और धीरे-धीरे निकायों की दुर्ब्यवस्था और भ्रष्टाचार के प्रति शोभ बढ़ने लगा। और ज्यों-ज्यों देश में स्वतंत्रता की चेतना जागृत होती गयी, इन निकायों से शिक्षा को निकाल लेने की माँग बढ़ती गयी। पहले प्रछन्न रूप से पीछे खुलकर शिक्षक-सघों ने भी स्थानीय निकायों के भ्रष्टाचार की निन्दा की और माँग की कि चूँकि सरकार निकायों को शिक्षा का लगभग पूरा अनुदान देती है अतः वह शिक्षा को अपने हाथ में ले ले।

३. शिक्षा के लिए प्राप्त अनुदान को दूसरे कामों में खर्च करने अथवा अन्य दुरुपयोगों का परिणाम यह हुआ कि निकायों के स्कूल अत्यन्त विपन्न अवस्था में पहुँच गये। अधिकांश स्कूलों के भवन टूटे-फूटे और अरक्षित रहने लगे। विद्यार्थियों के लिए बैठने के लिए टाट-पट्टी तक का अभाव हो गया। स्कूल पेड़ों के नीचे लगने लगे। पढ़ाने

के साधन का अभाव हुआ—श्यामपट नहीं, नक्शे नहीं, शिल्प आदि विज्ञान-शिक्षण की सामग्री नहीं, फिर भी स्कूळ चलते रहते ।

जब प्रदेश में वेसिक शिक्षा आरम्भ हुई तो ये दोष और भी निरपेक्ष रूप से सामने आये, क्योंकि वेसिक शिक्षा पद्धति में शिल्प-शिक्षण के लिए ड्राफ्ट और कच्चा माट्ट अनिवार्य है । कुछ रुई, कुछ कांडे-चांडे, कुछ रंग आदि चाहिए हो । उत्तर प्रदेश सरकार ने शिल्प सामग्री के लिए पहले ३२ रुपये और पीछे १०० रुपये प्रति वेसिक स्कूळ दिये । इस सामग्री के खरीद-फरोख्त में तो निकायाँ ने गड़बड़ की हो, परन्तु जो भली-बुरी सामग्री स्कूळों को दी गयी उसको रखने तक के पर्याप्त स्थान के अभाव में शिल्प-शिक्षण विहम्बना बन गया । साधनहीन वेसिक स्कूळ क्षति (वेस्टेज) के बहुत बड़े स्रोत बन गये । इन पाध-लियों से ऊबरकर जनता ने वेसिक शिक्षा के सरकारीकरण की माँग की ।

इस माँग के बावजूद प्रारम्भिक शिक्षा का सरकारीकरण न होता अगर प्रारम्भिक शिक्षा का खर्च स्थानीय निकाय स्थानीय स्रोतों से निकाल पाते । जब स्थानीय निकायाँ का शिक्षा के प्रबन्ध का अधिकार दिया गया था तो उससे यही आशा की गयी थी । परन्तु स्थानीय निकाय ऐसा नहीं कर पाये और शिक्षा का लगभग पूरा खर्च सरकारी अनुदान से चलने लगा । और जब पूरा खर्च सरकार ही देती है तो शिक्षा का प्रशासन भी सरकार अपने हाथ में ले ले, इस दलील को सदा के लिए दावा नहीं जा सका और फलस्वरूप आज प्रारम्भिक शिक्षा का सरकारीकरण हो गया है ।

तो हम आशा करें कि प्रारम्भिक शिक्षा के सरकारीकरण से ये सीनें बुराइयाँ दूर होंगी, अर्थात्

१—अध्यापकों को समय से वेतन मिलेगा ।

२—समय से वेतन पानेवाले सन्तुष्ट अध्यापक स्थानीय निकायों की राजनीति से मुक्त होकर अध्ययन-अध्यापन के काम में लगेंगे ।

३—स्कूलों को पर्याप्त साधन मिलेंगे जिससे प्रारम्भिक शिक्षा अधिक पूर्ण और पर्याप्त बन सकेगी ।

परन्तु अध्यादेश के अध्ययन करने से लगता है कि ये बुराइयाँ दूर भी होंगी तो आशिक रूप में और सम्भव है कि बुराइयाँ भी पैदा हो जायें ।

१ अध्यादेश में बेसिक शिक्षा की परिभाषा देते हुए लिखा गया है कि बेसिक शिक्षा का तात्पर्य हाई स्कूलों या इण्टरमीडियेट कालेजों से भिन्न स्कूलों में आठवीं कक्षा तक दी जानेवाली शिक्षा से है और "बेसिक स्कूल का तदनुसार अर्थ लगाया जाय" (अध्यादेश २-ख)। इसका मतलब यह हुआ कि आज तक हाई स्कूलों अथवा इण्टरमीडियेट कालेजों (जिनमें से अधिकांश शहरों और कस्बों में हैं) और इनसे भिन्न स्कूलों में (जिनमें से अधिकांश देहातों में हैं) चलनेवाली प्रारम्भिक (बेसिक) शिक्षा में जो एकरूपता थी वह समाप्त हो जायगी। एक दिन प्रदेश के वर्नाक्यूलर और एंग्लोवर्नाक्यूलर स्कूलों के पाठ्यक्रम में जो भेद था उसे जूनियर हाई स्कूल (सिनीयर बेसिक स्कूल) तक के स्तर की शिक्षा को सर्वत्र समान करके मिटा दिया गया था। और दोनों ही प्रकार के स्कूलों में कक्षा ८ तक समान पाठ्यक्रम चलने लगा था। अब यह निश्चय है कि इस परिभाषा के अनुसार प्रदेश की प्रारम्भिक शिक्षा में वर्नाक्यूलर और एंग्लोवर्नाक्यूलर तथा देहातों और शहरों का पुराना भेद पुनः आ जायेगा। मानलोजिए आज एक ही पाठ्यक्रम चलाने की बात स्वीकार भी कर ली जाय, परन्तु अगर कल बेसिक शिक्षा परिषद् ने पाठ्यक्रम में, शिक्षण-विधि में अथवा मूल्यांकन पद्धति में कोई सुधार किया और हाईस्कूलों और इण्टरमीडियेट कालेजों ने अपनी कक्षाओं (६, ७ और ८) में उन्हें लागू नहीं किया तो विषमता तो बढेगी ही। बेसिक शिक्षा परिषद् पर इन संस्थाओं से सलग्न सीनियर बेसिक स्तर की शिक्षा पर नियंत्रण न होने से इस विषमता को क्या दूर किया जा सकेगा? हमारा अभिमत है कि अगर इस विषमता को दूर नहीं किया गया तो प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा की यह विषमता प्रदेश की पूरी शिक्षण प्रणाली को ही विषाक्त कर देगी। अभी तक तो हम पब्लिक स्कूल और गैर-पब्लिक स्कूल में चलनेवाली दो शिक्षण-पद्धतियों से ही परेशान हैं और जिसको दूर करके "लोक-शिक्षा की एक समान प्रणाली" लागू करने की सिफारिश कोठारी कमिशन ने की है। परन्तु इस भेद के बाद तो देहात और शहर, अमीर और गरीब की खाई इतनी अधिक चौड़ी और गहरी हो जायगी कि उसमें समाजवादी समाज बनाने की कल्पना सदा-सदा के लिए दूब जायगी।

२. अध्यादेश की दूसरी कमजोरी जो बेसिक शिक्षापरिषद के सारे प्रयत्नों को "नियुक्ति और स्थानान्तरण" के छिटपुट प्रयासों तक ही सीमित कर देती है। भूमि-भवन और शिक्षण के साधनों तथा उपकरणों को स्थानीय निकायों के ही अधिकार में छोड़ देना है। बेसिक शिक्षा परिषद को सबसे पहले इन्हें ही अपने नियंत्रण में लेना चाहिए था; क्योंकि प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार का यही पहला कदम है। अध्यादेश के अनुच्छेद ११-२ (क) में कहा गया है "गाँवशिक्षा समिति" बेसिक स्कूलों के भवनों और उनके उपकरणों में सुधार करने के लिए यथास्थित जिला परिषद अथवा अन्तरिम जिला परिषद को सुझाव देगी और फिर अनुच्छेद १२-५ के अन्तर्गत निदेशक को अधिकार दिया गया है कि अगर उसे समाधान हो जाय कि समिति की सिफारिश के बावजूद "स्थानीय निकाय ने जिसका स्कूल हो उसके सम्बन्ध में अपने कर्तव्यों का पालन करने में जानबूझकर अथवा निरन्तर चूक की है, तो परिषद आदेश द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, पाँच वर्ष से ऐसी अधिक अवधि के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, स्थानीय निकाय को अपवर्जित करने, स्कूल का प्रबन्ध जिसके अन्तर्गत स्कूल की भूमि भवन, निधियाँ तथा अन्य परिसम्पत्तियाँ भी हैं, अपने हाथ में लेने का निर्देश दे सकती है।"

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि चाहे राजनैतिक दबाव के कारण हो चाहे किसी दूसरी नीति के कारण, शिक्षा के भौतिक साधनों को स्थानीय निकायों के हाथ में छोड़ दिया गया है, परन्तु कैसे यह आशा की जाय कि स्थानीय निकाय, ईमानदारी के साथ प्रमादरहित होकर शिक्षा के भौतिक साधन अर्थात् पर्याप्त भूमि, अच्छे भवन और पर्याप्त उपकरण आदि बेसिक शिक्षा परिषद की समितियों के सिफारिश से बेसिक स्कूलों को उपलब्ध कर देंगे। सौ वर्ष जिन निकायों ने किसी की बात नहीं सुनी, सुनकर भी अनसुनी की, वे अचानक सुधरेंगे नहीं, यह बात निश्चित है, और एक बार फिर भौतिक साधनों के अभाव में (जिन्हें स्थानीय निकायों के हाथ में छोड़ दिया गया है) बेसिक शिक्षापरिषद के गुणात्मक सुधार के सारे प्रयास व्यर्थ बना दिये जायेंगे।

अतः अध्यादेश को पढ़कर यह बात साफ़ हो जाती है कि बेसिक

शिक्षा परिषद् की स्थापना एवान्त प्रशासनिक व्यवस्था है और परिषद् को लाचार होकर अपने काम को बेतन वितरण, नियुक्ति और स्थानान्तरण के प्रयास तक ही सीमित करना होगा।

३ बेसिक शिक्षा परिषद् और उसकी सहायता के लिए निर्मित समितियों के संगठन को देखने से एक और बात साफ होती है कि परिषद् और समितियाँ सरकारी नौकरों अथवा सरफार द्वारा मनोनीत सदस्यों से ही निर्मित हुई है। इस प्रकार के संगठन से शिक्षा की स्वायत्तता को बहुत घड़ा रतारा है। इतना ही नहीं, इससे लोकतंत्र को भी बहुत घड़ा रतारा है, क्योंकि इससे सत्ता का केन्द्रीकरण तो होता ही है, वैश्विक प्रशासन का भी केन्द्रीकरण होता है। इस अभ्यादेश से सारकारीकरण और केन्द्रीकरण को घल गिलेगा, जिससे शिक्षा की स्वायत्तता समाप्त हो जायगी। अतः तत्काल आवश्यकता इस बात की है कि राज्य स्तर पर एक ऐसी शिक्षासमिति की स्थापना की जाय जिसमें वे शिक्षाविद् शामिल हों, जिन्होंने शिक्षा की समस्याओं पर, विशेषतः बेसिक शिक्षा की समस्याओं पर चिन्तन किया और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। यह समिति गैर सरकारी, असाभ्रदायिक और पक्षमुक्त होगी तो अधिक प्रभावपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से काम कर सकेगी। इस समिति का संगठन ऐसा होना चाहिए कि उसमें सरकारी सदस्यों का बाहुल्य न हो। इस समिति का काम होगा (१) प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले सभी विषयों पर बेसिक शिक्षा परिषद् को सलाह देना, (२) जनता और परिषद् के बीच सम्पर्क का काम करना, और (३) जिन नीतियों के सम्बन्ध में परिषद् और समिति में मतभेद हो, उसके कार्यान्वयन में सहायता देना।

हमारा दूसरा सुझाव यह है कि अभ्यादेश के अन्तर्गत जो गाँव समितियाँ घनी हैं वे मात्र सलाहकार समितियाँ न हों—वे प्रशासनिक इकाइयाँ भी हों। वे स्वतंत्र निर्णय लें और उन्हें कार्यान्वित करने में सक्षम हों। परन्तु यह करने के पहले निश्चय कर लिया जाय कि उनके संगठन में गैर सरकारी प्रतिनिधित्व का बाहुल्य होगा और विद्यालयों के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक स्वातंत्र्य में सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा।

४ एक अन्तिम बात यह कहनी है कि अगर उत्तर प्रदेश की

प्रारम्भिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा कहना ही है, जो बाछनीय है, तो राज्य के प्रत्येक प्राइमरी स्कूल के प्रत्येक क्रिया कलापों में बेसिक शिक्षा की आत्मा प्रकट होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा परिषद् प्रयास करे कि बेसिक शिक्षा के तत्व प्रदेश के बेसिक स्कूलों में दाखिल हों। कोठारी कमीशन, जो बेसिक शिक्षा का हिमायती नहीं है, के अनुसार ये तत्व हैं— (१) शिक्षा में उत्पादक क्रियाकलाप, (२) पाठ्यक्रम का उत्पादक काम, एवं बालक के भौतिक और सामाजिक वातावरण से अनुबन्ध, और (३) स्थानीय समुदाय और स्कूल का निकट का सम्पर्क। दूसरे शब्दों में, बेसिक स्कूल के लड़के अनिवार्य रूप से कोई समाजोपयोगी उत्पादक धन्धा करे—अपनी क्षमता के अनुसार उतनी देर करे जितनी देर में उन्हें उस धन्धे को वैज्ञानिक ढंग से करना आवे, और उनको जो भी पढ़ाया लिखाया जाय उसका सम्यन्ध उनके काम से, और उनके भौतिक तथा सामाजिक वातावरण से हो एवं समाज-सेवा के कार्यों द्वारा वे अपने समुदाय के सतत सम्पर्क में रहें।

अगर ऐसा नहीं होता है तो बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की कोई उपयोगिता नहीं है।

—वशीधर श्रीवास्तव



उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम १९७२

[चूँकि प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए संविधान के अनुच्छेद ५५ के अन्तर्गत राज्य सरकार पर विशेष दायित्व रखा गया है और चूँकि उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की वर्तमान संस्थाएँ व्यवस्था पर्याप्त तथा सुदृढ़ नहीं थी और पुनः संघटित करना तथा बेसिक स्कूलों, नामल स्कूलों तथा अन्य बेसिक प्रशिक्षण इकाइयों के क्षेत्र में सुदृढ़ प्रशासन के अभिकरणों के रूप में राज्य बेसिक शिक्षा परिषद् तथा उसकी सहायता के लिए स्थानीय परामर्शदात्री इकाइयों को स्थापित करना आवश्यक समझा गया ।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और राज्यपाल को यह समाधान हो गया था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें दूरतः कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ।

अतः संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल ने एक अध्यादेश प्रख्यापित किया । इस अध्यादेश के कुछ अंश पाठकों की जानकारी के लिए नीचे दिये जाते हैं ।—सं०]

परिभाषाएँ

१—जब तक कि प्रश्न से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अध्यादेश में :

(क) “नियत दिनांक” का तात्पर्य उस दिनांक से है जब परिषद् स्थापित की जाय ।

(ख) “बेसिक शिक्षा” का तात्पर्य हाईस्कूल या इंटरमीडिएट कालेजों से भिन्न स्कूलों में आठवीं कक्षा तक दी जानेवाली शिक्षा से है और यह “बेसिक स्कूल” का तदनुसार अर्थ लगाया जायगा ।

(ग) "परिषद" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन संघटित उत्तर-वैसिक शिक्षा परिषद से है।

(घ) "निदेशक" तथा "जिला वैसिक शिक्षा अधिकारियों" का तात्पर्य क्रमशः वैसिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, और जिला वैसिक शिक्षा अधिकारियों के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों से है।

(ङ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य जिला परिषद, अन्तरिम जिला परिषद, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमिटी या मोटोफाइड एरिया कमिटी, जैसी भी दशा हो, से है—

परिषद का संघटन (१) इस अध्यादेश के अधीन उत्तर प्रदेश वैसिक शिक्षा परिषद के नाम से एक परिषद स्थापित की गयी।

(२) परिषद शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रावाली एक निगमित निकाय है, तथा इस अध्यादेश के उद्देश्यों के अधीन रहते हुए, उसे सम्पत्ति का अर्जन और धारण करने की शक्ति होगी और अपने नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा—

(३) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(क) निदेशक, जो पदेन अध्यक्ष होगा।

(ख) दो व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम १९५१ की धारा १७ के अधीन स्थापित जिला परिषदों के अध्यक्षों में से, यदि कोई हो, नाम निर्दिष्ट (नॉमिनेट) किये जायेंगे।

(ग) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ९ के अधीन संघटित महापालिकाओं के नगरप्रमुखों में से, यदि कोई हो, नाम निर्दिष्ट किया जायगा।

(घ) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, १९१६ के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों के प्रेसिडेण्टों में से, यदि कोई हो, नाम निर्दिष्ट किया जायगा।

(ङ) सचिव, राज्य सरकार, वित्त विभाग, पदेन (यदि मनोनीत अधिकारी बैठक में स्वयं उपस्थित न हो सकें तो अपने विभाग के किसी अधिकारी को जिसका पद राज्य सरकार के उपसचिव II कम न हो, बैठक में उपस्थित होने के लिए भेज सकते हैं।)

(च) प्रिंसिपल, राज्य शिक्षा-संस्थान, पदेन।

(छ) दो शिक्षाविद, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(ज) एक अधिकारी, जिसका पद शिक्षा उपनिदेशक, के पद से कम न हो, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा, जो सदस्य-सचिव होगा।

परिपद के कृत्य

(१) इस अध्यादेश के अधीन परिपद का कृत्य राज्य में बेसिक शिक्षा तथा उनके लिए अध्यापक-प्रशिक्षण दिये जाने को सुगठित करना, समन्वय करना, उसपर नियंत्रण करना, उसके स्तर को ऊँचा उठाना तथा उसे राज्य की सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली से परस्पर सम्बद्ध करना होगा।

(२) परिपद की विशेषतया निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :

(क) बेसिक शिक्षा और उस हेतु अध्यापक-प्रशिक्षण के लिए शिक्षाक्रम तथा पुस्तकें विहित करना।

(ख) जूनियर हाईस्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, परीक्षा तथा ऐसी अन्य परीक्षाओं का संचालन करना जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर उसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अध्यापित करे और ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना।

(ग) शिक्षण देने तथा परिपद द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए परीक्षार्थियों को तैयार कराने के प्रयोजन से, संस्थाओं की ऐसी शर्तों के अधीन जो वह लगाना उचित समझे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना या निलम्बित करना और ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा उन पर नियंत्रण रखना।

(घ) बेसिक स्कूलों, नार्मल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र हकाइयों, राज्य शिक्षा-संस्थान का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण रखना।

(ङ) किसी जिले में या राज्य में अथवा उसके किसी भाग में बेसिक शिक्षा के विकास-प्रसार तथा सुधार एवं उसमें अनुसंधान हेतु योजनाएँ तैयार करना।

(च) किसी जमीन या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन करना, धारण करना। या निस्तारण करना और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपकरण का दान शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना।

(छ) राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता और ऋण प्राप्त करना।

(ज) ऐसे सभी कार्य करना जो इस अध्यादेश द्वारा प्रदत्त या आरोपित

किसी शक्ति या प्रयोग या किसी कृत्य वा सम्पादन अथवा कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक अथवा अनुसंगिक हो ।

कर्मचारियों का स्थानान्तरण

(१) बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में किसी स्थानीय निकायों के अधीन उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व कार्यरत प्रमुख अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी (जिसके अन्तर्गत कोई पर्यवेक्षी या निरीक्षण कर्मचारी वर्ग भी है ।) परिपद को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे और वे परिपद के अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जायेंगे और वे उसी अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं अन्य निबन्धनों एवं शर्तों पर पद धारण करेंगे जिन पर वे धारण करते यदि परिपद संचालित न की गयी होती और वे तब तक इस प्रकार बने रहेंगे जब तक कि परिपद द्वारा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निबन्धनों एवं शर्तों में पर्यावृत्ति परिवर्तन न कर दिया जाय ।

(२) किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक को किसी अन्य स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल में स्थानान्तरण, सिवाय उसकी सहमति के नहीं किया जायगा ।

बेसिक शिक्षा समितियाँ

(१) प्रत्येक जिले के लिए एक समिति स्थापित की जायगी, जो जिला बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे

(क) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो अध्यक्ष होगा ।

(ख) तीन व्यक्ति जो जिला परिपद या अन्तर्निहित जिला परिपद के यदि कोई हों, सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(ग) तीन व्यक्ति जो जिले में स्थित नगर महापालिकाओं, नगरपालिका बोर्ड, मेट्रोकाउन्सिल एरिया कमिटियों तथा टाउन एरिया कमिटियों के सदस्यों से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(घ) एक व्यक्ति जो निदेशक द्वारा जिले में, निम्नांकित में प्रत्येक से, अर्पित

(१) लड़कों के इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रिंसिपल्स में से,

(२) लड़कियों के इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रिंसिपल्स में से,

(३) लड़कों के राजकीय मानक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों में से, और

(४) लड़कियों के राजकीय मानक स्कूलों को, प्रधान अध्यापिकाओं में से, नामनिर्दिष्ट किया जायगा ।

(ड) तीन से अधिक अन्य शिक्षाविद, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(च) विद्यालय उप निरीक्षक, जो समिति का सदस्य सचिव होगा ।

(२) पदेन सदस्यों से निम्न समिति के सदस्यगण ऐसे निबंधनों और शर्तों पर पद धारण करेंगे जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे ।

(३) परिषद समिति से ऐसे विषयों पर परामर्श करेगी जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे और उससे किसी अन्य विषय पर भी परामर्श कर सकती है ।

गाँव शिक्षा समितियाँ

(१) प्रत्येक गाँव या गाँवसमूह के निमित्त जिसके लिए यू० पी० पंचायत राज्य एक्ट १९४७ के अधीन गाँवसभा स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायगी, जो 'गाँवशिक्षा समिति' कहलायगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे

(क) गाँवसभा का प्रधान जो अध्यक्ष होगा ।

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन सरदाक (जिनमें से एक सरदाक महिला होगी) जो अब विद्यालय उप निरीक्षक (सब डिप्टी इन्स्पेक्टर) द्वारा नामनिर्दिष्ट किय जायेंगे ।

(ग) उस गाँव या गाँवसमूह में बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक, और यदि एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्ठतम, जो उसका सदस्य-सचिव होगा ।

(२) इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समिति—

(क) बेसिक स्कूलों के भवनों और उनके उपकरणों में सुधार करने के लिए धनसंस्थिति मिला परिषद अथवा अन्तरिम मिला परिषद को सुझाव देगी, और

(ख) ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करेगी और अध्यापकों द्वारा समय-मालन किये जाने तथा उनकी उपस्थिति के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देगी ।

बेसिक स्कूलों पर नियंत्रण

(१) निदेशक किसी बेसिक स्कूल (चाहे वह किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति अथवा निकाय का हो) और व्यक्ति शिक्षा के सम्य व में स्थानीय निकाय के कर्तव्यों का सम्पादन करनवाली अथवा उससे सम्बद्ध स्थानीय निकाय के

अभिलेखों और उसकी कार्यवाहियों का भी समय-समय पर निरीक्षण कर सकता है अथवा करा सकता है।

(२) निदेशक

(क) किसी बेसिक स्कूल के प्रबन्धाधिकरण को (जिसके अंतर्गत कोई स्थानीय निकाय भी है) निरीक्षण करने पर अथवा अन्य प्रकार से पाये गये किसी दोष या कमी को दूर करने का, या

(ख) किसी स्थानीय निकाय का बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित अपने कृत्यों का सम्पादन करने के सम्बन्ध में निरीक्षण करने पर अथवा अन्य प्रकार से पाये गये किसी दोष या कमी को दूर करने का निर्देश दे सकता है।

(३) यदि किसी बेसिक स्कूल का प्रबन्धाधिकरण उपधारा (२) खण्ड (क) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक प्रबन्धाधिकरण द्वारा किये गये स्पष्टीकरण या अन्तर्वेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्—

(क) किसी ऐसे बेसिक स्कूल की दशा में जो स्थानीय निकाय का न हो, ऐसे स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिए मामला परिषद को अभिविष्ट कर सकता है, या

(ख) किसी ऐसे बेसिक स्कूल की दशा में, जो स्थानीय निकाय का हो, परिषद की उपधारा (५) के अधीन कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकता है।

(४) किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में उपधारा (३) के खण्ड (क) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद उस स्कूल की मान्यता वापस ले सकती है,

(५) यदि किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में उपधारा (३) के खण्ड (ख) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद का यह समाधान हो जाय कि स्कूल के कार्यकलापों का ठीक प्रबन्ध नहीं हो रहा है, अथवा उस स्थानीय निकाय ने जिसका स्कूल हो उसके सम्बन्ध में अपने कर्तव्यों का पालन करने में जानबूझकर अथवा निरन्तर धूर्त भी है, तो परिषद आदेश द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की, पाँच वर्षों से ऐसी अनधिक अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, स्थानीय निकाय को अपवर्जित करने, स्कूल की भूमि, भवन, निधियाँ तथा अन्य परिसम्पत्तियाँ भी हैं, अपने हाथ में लेने का निर्देश दे सकती है, और तदुपरान्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, केवल ऐसे निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो परिषद द्वारा आरोपित किये जायें, स्कूल के प्रबन्ध में ऐसी सभी रक्तियाँ तथा प्राधिकार उपलब्ध होंगे जो स्थानीय निकाय को उपलब्ध होते, यदि इन उपधारा के अधीन कोई आदेश न दिया गया होता।

(६) यदि स्थानीय निकाय, उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अयावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् मामला परिपद को उपधारा (७) के अधीन कार्यवाही करने के लिए अभिदिष्ट कर सकता है,

(७) यदि उपधारा (६) में अधीन कोई सिफारिश प्राप्त होने पर परिपद को यह समाधान हो जाय कि स्थानीय निकाय ने बेसिक शिक्षा के सम्बन्धों में अपने कर्तव्यों का पालन करने में जानबूझकर अवज्ञा निरत रह चुका है अथवा बेसिक शिक्षा के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार से प्राप्त किसी अनुदान का दुरुपयोग किया है अथवा उसे व्यावहृतिक किया हो, तो परिपद मामला राज्य सरकार की उपधारा (८) के अधीन कार्यवाही के लिए अभिदिष्ट कर सकता है।

(८) राज्य सरकार उपधारा (७) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि पाँच वर्षों से अधिक ऐसी अवधि के लिए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाय, बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय की शक्ति तथा कृत्य, ऐसे दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय परिपद को अन्तर्लिखित हो जायेंगे।

राज्य सरकार द्वारा निघटन

(१) परिपद ऐसे निदेशों को कार्यन्वित करेगी जो उसे इस अध्यादेश के कुछल प्रसाशन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें।

(२) यदि इस अध्यादेश के अधीन परिपद द्वारा अपनी किन्हीं शक्तियों के प्रयोग में या प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में और अपने किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में अथवा सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में परिपद और राज्य सरकार के बीच, अथवा परिपद और किसी स्थानीय निकाय के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निष्पक्ष अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

इस अध्यादेश द्वारा अथवा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके परिपद अथवा किसी समिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय पर न्यायालय में कोई अपील नहीं की जायगी। ●

वनारसो दास चतुर्वेदी

गांधी और विनोबा

महात्मा गांधीजी के विषय में बहुत-सी किताबें निकली हैं और भविष्य में भी निकलती रहेंगी, लेकिन आचार्य विनोबाजी की पुस्तक 'गांधी' जैसा देखा समझ' अपना अलग ही महत्त्व रखती है। इस पुस्तक का संकलन और सम्पादन गुजराती में श्री कान्ति भाई साहू ने किया है। यह पुस्तक सरसरी निगाह से पढ़ने की नहीं है, बल्कि स्वाध्याय के तौर पर अध्ययन करने की है। एक बात ध्यान देने योग्य है, वह यह, कि विनोबाजी किसी के भी अन्ध भक्त नहीं हैं। वे स्वतंत्र चिन्तन करते हैं और अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखते हैं। एकाध जगह उन्होंने महात्माजी की स्पष्ट आलोचना भी की है। उदाहरण के लिए, उन्होंने यह बात लिखी है कि अग्रे ग्यारह वर्षों के साथ बापू ने 'स्वाध्याय' पर जोर नहीं दिया। उनके कार्यक्रम की यह न्यूनता विनोबाजी की तीव्र दृष्टि से बच नहीं सकी। विनोबाजी यह नहीं चाहते कि हम लोग बिना सोचे-समझे गांधीजी का अनुकरण करते रहें। जमाना बदल रहा है, और तेजी से बदलता जा रहा है। ऐसा स्थिति में गांधीजी के सिद्धान्तों की खूँटी से बंधे रहना ठीक नहीं। विनोबाजी ने एक और बात भी स्पष्ट कर दी है कि गांधीजी निरन्तर प्रगतिशील थे और जो लोग यह कहते हैं कि 'यदि आज गांधीजी जीवित रहते तो यह करते, वह करते' वे भयंकर भूल करते हैं। विनोबाजी लिखते हैं "यह भ्रान्तिभाति समझ लेना की बात है कि गांधीजी पल-पल विकसित होते रहे। अगर हमें हम नहीं समझेंगे तो गांधीजी को जरा भी नहीं समझ सकेंगे। वे तो रोज रोज बदलते, पल-पल विनियमित होते रहे हैं। वह आदमी ऐसा नहीं था कि पुरानी किताब के संस्करण ही निकालता रहे। कोई नहीं कह सकता कि आज वे हाते तो वैसा मोठ छेते। उन्होंने अमुक समय अमुक बात कही थी, इसलिए आज भी वैसे काम की आशीर्वाद ही देने, ऐसा अनुमान लगाना अपने मतलब की

घात होगी।" मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा अनुमान लगाने का किसी को हक नहीं। 'लोकोत्तराणां चेदासि को हि विज्ञातुमर्हति'—लोकोत्तर पुरुष के वित्त की चाह कोन पा सकता है ? इसलिए गांधीजी आज होते तो क्या करते और क्या न करते, इस तरह नहीं सोचना चाहिए।

विनोबाजी बापू के वित्तने ऋणी थे। यह बात हम ग्रन्थ में भली प्रकार स्पष्ट कर दी गयी है। यह मतलबने की आवश्यकता नहीं कि विनोबाजी ने उस ऋण को चक्रवर्द्धि ब्याज सहित चुका दिया। यदि आज भारतवर्ष में बापू के 'सच्चा नाम-लेबा' हैं तो विनोबाजी, काका कालेलकर और जयप्रकाशजी जैसे अल्पसंख्यक व्यक्ति ही हैं। विनोबाजी ने इस बात पर जोर दिया है कि बापू में वास्तव्य भाव की प्रधानता थी। पार्यक्ताओं के वे पिता ही नहीं, माता भी थे।

इस ग्रन्थ में अनेक प्रेरणादायक वाक्य यत्र-तत्र छिटे पड़े हैं। विनोबाजी ने जो कुछ पडा है उसे उन्होंने भलीभाँति हृदयंगम भी कर लिया है, और वे अपने स्वाध्याय से निकाले हुए रत्नों को दूसरों को भी दिखलाते हैं। एक जगह पर उन्होंने लिखा है—'छकराचार्य का वाक्य मुझे हमेशा याद आता है कि मनुष्य के परम भाग्य तीन होते हैं। १—मानव-देह की प्राप्ति, २—मुमुक्षुत्व-मुक्ति की छटपटाहट, और ३—किसी महापुरुष के आश्रय का लाभ, 'मनुष्यत्वंमुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः।'

'छकराचार्य के इस वाक्य पर विचार करता हूँ तो मेरा हृदय आनन्द से उछलने लगता है। मैं परम धन्य हूँ कि मानव-देह मिली, मुक्ति की धुन लगी और महापुरुष का संश्रय मिला। सन्त-महात्माओं की बाणी पुस्तकों में पढ़ना एक बात है और उसका प्रत्यक्ष सत्संग करना, उनके मार्गदर्शन में काम करना, प्रत्यक्ष उनका जीवन देखना, अलग बात है। मुझे यह भाग्य प्राप्त हुआ, इससे मैं धन्य हो गया।'।

कई जगह विनोबाजी ने बड़े मौलिक विचार प्रस्तुत किये हैं। संस्यारों किस प्रकार निष्प्राण और निस्तेज बनती जाती हैं, इसपर उनके विचार बड़े उत्तेजक हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कबीन्द्र के शान्ति-निकेतन, मालवीयजी के हिन्दू विश्वविद्यालय और रामकृष्ण परमहंस के आश्रम तथा गुरुकुलों का जिक्र किया है, और महात्माजी की शस्याओं का मूल रस कैसे सूख रहा है इसका भी उल्लेख किया है। उन्होंने एक जगह लिखा है—"अब मेरे सामने सवाल उठता है कि क्या स्फूर्तिशाय कालानुक्रम से होता रहता है ? इसमें कोई शक नहीं कि वेगक्षय-

फारी सामर्थ्य काल में होती है, इसलिए बार-बार गति देनी पड़ती है। चैतन्य का स्पर्श बार-बार होना चाहिए सभी गति मिश्रती है। घड़ी को बार-बार चामी देनी पड़ती है। इससे यह समझ सकते हैं कि कालानुक्रमेण स्फूर्ति का क्षय होगा लेकिन वह इतना जल्दी अपेक्षित नहीं था। यह तो २०-२५ वर्षों के अन्दर ही पहले की स्फूर्ति एकदम लुप्त हो रही है।

इसके कारणों पर विचार करने पर दो-तीन बातें ध्यान में आती हैं। हमारी सस्याजों का देखते-देखते जीवन रस सूखता जा रहा है, इसका कारण है स्वाध्याय का अभाव। हम कर्मयोग में पड़े हैं। कर्मयोग में उसके लाभ के साथ-साथ हानि भी होती है। शंकराचार्य, रामानुज, बुद्ध, महावीर आदि के अनुयायियों के जो कुछ दोष थे, वे हमने सुधारें, यह बात सही है। हमने कर्मयोग पर अधिक भार दिया। यह सुधार जरूरी था। लेकिन ये लोग आत्मज्ञान में जितने गहरे उतरते थे, उतने गहरे हम नहीं उतरते। इससे कार्य के विकास के साथ-साथ हमारी विचारनिष्ठा पड़ती जाती है। हमारे कामों की गठरी भारी बनती जाती है, लेकिन उसका तख उड़ रहा है। मनुष्य चला जाता है, सस्या रह जाती है। फिर वह निस्तेज, फीकी पड़ती जाती है, दृष्टि छिछली बनती जाती है।

इस पुस्तक का 'गांधी-विश्वास या आत्म विश्वास' नामक अध्याय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विनोबाजी परमुखापेक्षी नहीं हैं। वे स्वतंत्र विचार तथा आत्म-विश्वास, स्वाध्याय और चिन्तन को बहुत महत्त्व देते हैं। वे यह नहीं चाहते कि हम लोक को पीटते रहें। आजकल सर्वोदय विचारधारा में शिथिलता आ गयी है। उसके कारण भी उन्होंने बतलाये हैं। इसकी मुख्य वजह उन्होंने यह बतलायी है कि हम लोगों में स्वाध्याय का अभाव है और हम प्रश्नों की गहराई में नहीं उतर सकते। मिल-जुलकर सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति हम लोगों में प्राप्त नहीं हुई। विनोबाजी ने लिखा है—'यदि बुद्ध भगवान ने जीते ही यह कह दिया होता कि अब आप लोग एक समुदाय बनाओ और विचार करो। जिस विषय में सब एक मत हो, वह करो। मैं केवल सांघीरूप रहूँगा। कभी मेरी सलाह सूछी जायगी तो आऊँगा अवश्य, लेकिन वह धन्यनकारक न होगा। आप सबको ही मिल-जुलकर करना है।' उन्होंने ऐसा किया होता तो उनके बाद चार शिष्य बुद्ध के नाम पर ही जिस तरह एकदम भिन्न भिन्न चार सम्प्रदायों में बँट गये, उस तरह वे कदाचिन् न बँट होते।

बुद्ध ने ऐसा नहीं किया, इससे उनके निर्वाण के बाद उनके शिष्यों के बीच

सीधे मतभेद पैदा हो गये—चार पन्थ खड़े हो गये । चारों कहते कि 'गुरु भगवान् बुद्ध ने ऐसा सिखाया है ।' एव ने कहा, 'दुनिया पूर्ण उत्पन्न है ।' दूसरे ने कहा, 'नहीं दुग्ध है ।' तीसरे ने कहा, 'विनाश है ।' दसरे का सारा समेल बुद्ध के नाम पर ब्रह्मा । हजार वर्ष तक उनमें खोप लागते रहे । इसलिए निर्बलता आयी थीर पाद में शकराचार्य के प्रहार से तो एगदम सारा टूट ही गया ।

विनोबाजी ने यह पुस्तक अत्यन्त धटापूर्वक लिखी है । उनका एक वाक्य पढ़ लीजिए—'कुछ निमित्तों से मैं उनसे बात बटुल गया । उन्होंने मुझ जैसे असम्यक् मनुष्य को सम्यक् तो नहीं, लेकिन सैबक प्ररुत बना दिया । मेरे भीतर के क्रोध के स्वाधामुखी का और दूसरों अनेक बातनामों की बहनामि का दमन कर देनेवाला तो बापू ही थे । आज मैं जो कुछ हूँ, यह सब बापू के आशीर्वाद का फलफार है । बहुत-बहुत बातें मैंने बापू के चरणों में रहकर सीसी ।'

जिसी विचारशील पाठक के लिए इस ग्रन्थ से अनेक प्रेरणाएँ मिल सकती हैं । सन् १९३८ में विनोबाजी का शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया और वजन सिर्फ ८८ पौण्ड रह गया था । उस समय बापू ने उनकी मुला भेजा और बहुत सी बातचीत करने के पश्चात् कहा—'तुम्हें सारा चिन्तन बन्द करना पड़ेगा । शरीर विचार छोड़ देने पड़ेंगे । आग्रह, काम अपवा किरी भी विषय का विचार नहीं करना पड़ेगा ।' विनोबाजी ने उनकी आज्ञा का अग्रह पालन किया और पौष्टिक आहार लिया तथा सारा समय ध्यान्त एव प्रसन्नचित्त से बिताया । मरीजा यह हुआ कि दस महीने में उनका वजन ८८ पौण्ड से बढ़कर १२८ पौण्ड हो गया ।

यह ग्रन्थ विनोबाजी ने सैकड़ों लेखों तथा प्रवचनों से लेकर बनाया गया है । पहले गुजराती में छपा था और अब हिन्दी में आ गया है । ग्रन्थ की हिन्दी भाषा में प्रवाह है । यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि आचार्य विनोबाजी ने इसे देखकर भाव्यता प्रदान कर दी है । गांधी और विनोबा दोनों के विचारों की समन्वये में यह पुस्तक अत्यन्त सहायक है । इसका संदेश निराशा का नहीं, आशा का है । अन्त में विनोबाजी का एक वाक्य उद्धृत किया जाता है—'विचारों की हमेशा छानबीन होती रहनी चाहिए । सभी प्रेरक विचारों का अध्ययन हो । उनमें जविचार, दुर्विचार के जो लक्ष हो, उनका निवारण किया जाय । इस तरह विचारों का अनुशीलन होता रहेगा, तो जो स्फूर्तिदायक मालूम पट रहा है, वह मालूम नहीं पटगा ।' हमारी समझ में यही इस पुस्तक का महत्वपूर्ण सार है । ●

जीवन की बुनियादें

[मार्जरी साइक्स द्वारा लिखित 'जीवन की बुनियादें' नामक पिछले अकों से चली आ रही खेलमाला का समापन इस अंक में हो रहा है। नयी तालीम की विचार स्थापना में, महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्रियों में मार्जरी साइक्स का अपना एक स्थान है।]

यह सम्झा लेज, यद्यपि आज से २५ वर्ष पहले लिखा गया था, पर आज यह इस चीज को उद्घाटित करता है कि नयी तालीम का महत्त्व उस समय मान की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से समझा जाता था, जबकि उस समय इस प्रकार के स्कूल भी थोड़े थे लेकिन वे सुयोग्य शिक्षकों द्वारा संचालित होते थे जो नयी तालीम के सिद्धान्त और प्रयोग पर पूर्ण भावस्था रखते थे।—स०]

नयी तालीम क्या है ?

नयी तालीम के सिद्धान्तों को प्रयोग में लाने के प्रयत्न के लिए उन्हें पाँच मुद्दों में बताया जा सकता है :

१. बुनियादी तालीम का केन्द्र : बालक जिन बुनिया में रहते हैं उसे समझना चाहते हैं, उसमें अपना स्थान खोजना चाहते हैं, यह उनकी स्वाभाविक दिग्दर्शनी दिशाई देती है। हमने शुरू में देखा कि बच्चों की सीखने, बनाने और पारिवारिक कामों में सहयोग देने की आन्तरिक भावना उनकी मनपसन्द आदतों में शामिल है। पाँच-छ साल का बालक जिन्हे पौधो, प्राणियों और खुद काम में ला सके, ऐसी सब प्रकार की निर्जीव वस्तुओं में रस लेता है। वह पिता-माता, भाई-बहन, हमउम्रवालों और अन्य लोगों से रस लेता है। कोई चीज उसे बनती है उसको समझने, सफाई करने, रसोई बनाने, धर्तन मोजने, हल चकाने, मछली पकड़ने, कपड़े बुनने, कुम्हार का चाक घुमाने, आदि कामों में सितम्बर, '०२]

बच्चों की गहरी रुचि होती है। छोटे बच्चे बड़े लोगों की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों का अनुकरण अपने खेल में करते हैं। चीजें बनाने और उत्पादन करने की उनकी चाह, सामाजिक काम में शामिल होने की लालसा तथा चीजों को उपयोग में लाने के तरीके सीखने के लिए वे सदा उत्सुक रहते हैं और उन्हें खुशी होती है। बालकों की शिक्षा और उनकी विविध शक्तियों के विकास में उनका स्वाभाविक रुच हो और वह उनकी प्रवृत्तियों का आधार रूप हो सके इसके लिए बुनियादी तालीम की विविध श्रेणियों में साधारण ज्ञान की सूचना होती है। उन्हें गिनती करना, हिसाब करना आदि गणित की प्रक्रिया सिखायी जाती है। पढ़ने-लिखने का व्यावहारिक उपयोग है, यह बच्चों के मन में स्पष्ट होता है। कपास, अनाज, शाक-भाजी आदि का वजन करना पड़ता है। उनका प्रमाण देखना पड़ता है। दाम निर्दिष्ट करने होते हैं। लाभ-हानि का हिसाब रखना पड़ता है, तस्ते के कद (आकार) के अनुसार उसे खोरना पड़ता है। मकान की योजना बनानी पड़ती है। जब बागवानी और खेती गम्भीरता से करने लगते हैं तब जमीन और उसके प्रकार, पौधों की सब अवस्था, किसान के धनु-मित्र, पक्षी और कीड़े, सरसामान की सम्भाल और प्रतुओं व महीनों की विशेषता सम्बन्धी कुछ सीखने का काम अत्यावश्यक व्यावहारिक महत्व का होता है। फसल की खाद देना, घर की योजना बनाना, आदि वैज्ञानिक भावना से किये जायें तो ज्ञानदार आनन्द का बहुत विशाल क्षेत्र खुल सकता है। उसका अर्थ यह नहीं कि बाहर के वैज्ञानिक शब्दों का बहुत प्रवेश हो, पर इसका अर्थ यह है कि बालकों के विषय में रुचि बढ़ाने के लिए प्रयोग करने, उस विषय पर विचार करने, कारण और उसके असर को बुद्धि से समझने के लिए सरसाहित किये जाने चाहिए।

२. बुनियादी तालीम जीवन-प्रेरक है : शिक्षण-सिद्धान्त और उसकी पद्धति की परिभाषा हर किताब में मिलती है कि वास्तविक शिक्षा यानी बालकों में छपी अनिकसित शक्तियों को बाहर लाना ही पढ़ाई का उद्देश्य होता चाहिए। हमें यह नहीं सोचना है कि विद्यार्थी का दिमाग केवल सन्दूक है, उसमें जानकारी की दृष्टि से अच्छी तरह लिखी पुस्तक व्यवस्थित रूप में भरना है। फिर भी हमारी अमिळतम पाठशालाएँ अपने विद्यार्थियों में इस प्रकार की दार्शनिक जानकारी भर देती हैं और उस जानकारी की परीक्षा में दोहराने की विद्यार्थी की गति के अनुसार अपनी सफलता मानती हैं। हम सोचते नहीं कि क्या विद्यार्थी अपने मन में भी कोई काम कर सकता है? कुछ सोच सकता है? या वे केवल प्रश्न के एक पहेलू की ही पकड़कर चलते हैं? सीखे हुए सिद्धान्तों का उपयोग

नयी परिस्थिति में वे कर सकते हैं क्या ? बुनियादी पाठशालाएँ इस स्थिति में परिवर्तन की कोशिश करती हैं। ये बालक विकासमान प्राणी हैं, उनको बढने के लिए स्वस्थ, सम्पन्न और पोषक वातावरण की आवश्यकता है। साल भर में उसने जो जानकारी प्राप्त की उसे प्रत्येक श्रेणी के अंतिम समय में छात्र जैसी की वैसी बता दें, इस पर बुनियादी शालीम के पाठ्यक्रम में उतना महत्त्व नहीं दिया जाता। पाठशाला के वातावरण तथा सामाजिक व्यवहार में, शिक्षकों के मानस में, पुस्तकालय में, नारीगरी में, संगीत तथा समाज के सयाने बुझुगों से विद्यार्थी को सतत प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए, और उसका प्रभाव पाठ्यक्रम में भी हो जिसे वे स्वयं उपयोग कर सकें, हज़म कर सकें। ज़मीन में अलग-अलग प्रकार के पौधे अलग अलग तरह से उगते हैं। बच्चा भी उसी तरह बढते हैं। उनको स्वतन्त्रता देने पर सब एक प्रकार के प्रश्न नहीं पूछते। एक प्रकार की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे। विद्यार्थी सुनी हुई या पढ़ी हुई जानकारी शब्दशः नहीं बता सकता हो तो उसका अर्थ उसे मान्य हो। यह नहीं कि उन्होंने उस जानकारी को आत्मसात् नहीं किया है। स्वस्थ जीवन अपनी आवश्यकतानुसार समन ग्रहण करता है और उसे आत्मसात् करता है। पौधों का विकास मापने का जो तरीका आजमाते हैं वही बालकों का विकास मापने का एक मात्र तरीका है। स्वावलम्बन, फूल फल के गुण पर से माप सकते हैं। बंध बंधाये पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति को जीवन प्रेरक शिक्षा द्वारा बदलना चाहिए। सबसे पहले उसे शिक्षकों को बदलना चाहिए। हमारे अधिकतर शिक्षकों की धारणा है कि अब उनके आगे शालीम की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने य विचार बदलने चाहिए। उनके मानस की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर बदलनी चाहिए। काम को नवीन दृष्टि से समनाने और सिखाने का प्रयोग ही जीवन है, ऐसा शिक्षकों को समनना चाहिए। मानस परिवर्तन के सिवाय नयी टेक्नीक की शालीम एक रास्ते में डली हुई पद्धति को नयी पद्धति में परिणत करेगी।

३. नयी शालीम सहकार मूलक है - अनुष्य अकेला नहीं रह सकता। वह परिवार और समाज में रहता है। अपने विकास को आदिम अवस्था में भी उसका जीवन बुनियादी तौर पर सहकार पर ही निर्भर करता था। शिक्षा का अर्थ है कि उसे सही काम पर लगाना, उसकी सुव्यवस्थात्मक दृष्टि को दिशा देना, उसमें सहयोग से काम करने की प्रेरणा भरना। इस प्रकार की सहकार-योजना बनाने की व्यवस्था में काम के प्रत्येक अंग का उपयोग होना चाहिए। 'बुनियादी शालीम' में जो साधन अपनाये गये हैं उन सब पर उस सहयोग का

असर प्रभावपूर्ण हो और उत्पादन की हुई चीजों का उपयोग किस भाँति करना है, इसका निर्णय सहकार से होना चाहिए ।

आजकल अधिकतर पाठशालाओं में प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत ज्यादा प्रचलित है; क्योंकि शिक्षक वर्ग और माता-पिता दोनों ने स्पर्धा-पद्धति से शिक्षा पायी है । इसलिए दूसरी कोई पद्धति उनकी समझ में नहीं आती है । बार-बार कहा जाता है कि बालक इनाम के लिए या परीक्षा में प्रथम आने के लिए या प्रमाण-पत्र हासिल करने के लिए काम करेंगे । लालच के सिवाय बालक जरा भी काम नहीं करेंगे । हमारे शिक्षण-पद्धति के स्वार्थी स्वयं का लज्जास्पद परिणाम स्पर्धा-पद्धति है । बाहरी लामो के लिए चलायी गयी इस स्पर्धा के भयंकर परिणाम बहुत दर्दनाक हैं, यह स्पष्ट है । परीक्षा के लिए घनी शिक्षा-प्रणाली जीवनहीन और बेकार है । वे सत्य, अहिंसा के तालीम-पर नहीं हैं ।

परन्तु सर्वसामान्य के लिए सबके द्वारा मिल जुल के काम करने से ही भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक एवं मानसिक उन्नति हो सकती है । यही सही जीवन की शिक्षा है । इसलिए बुनियादी तालीम में एक बालक को दूसरे बालक की स्पर्धा में नहीं रखते हैं । प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति की नींव ध्मानपूर्वक रखी जाती है । परन्तु प्राप्य लक्ष्य सामूहिक होता है और यह प्राप्य लक्ष्य बालकों को एक साथ काम करके अपनी टुकड़ी में लिए प्राप्त करना है ।

दृष्टान्त के रूप में पचाई-खोज की व्यवस्था देखें । बाहर से व्यक्ति को अलग दिखानेवाले काम में स्पर्धा का तत्त्व दाखिल करना बहुत आसान होगा । पुराना शिक्षक बच्चे को बहेगा—कौन सबसे ज्यादा बातता है, देखें ! और सबसे ज्यादा बातनेवाले को शायामी देगा या खुशी की तालियाँ बजावेगा, यह गलत तरीका है । परन्तु बुनियादी पाठशाला में स्वयं शिक्षक भी असम्भावित ढँपा आदर्श रखने से रोक्ता है । सब बालक मिलाकर यह निर्णय करते हैं कि सप्ताह में कितना सूत बातने का लक्ष्य रखना है । प्रति दिन सबने मिलकर बितना बात, यह देखने के लिए सबने तारो या जोड़ करते हैं और लक्ष्य के हिसाब से कितना बात उसका प्रमाण देखते हैं । अगर लक्ष्य से कम हुआ तो प्रत्येक को दूसरे दिन कुछ अधिक बातने का प्रयत्न करना चाहिए । इस पद्धति से छात्र काम सम्पूर्ण सहकारी बुनियाद पर चलता है यह केवल एक दृष्टान्त है । पाठशाला में दिन भर इस सहयोग का अधिक असर रहा करता है । यह अमिट

प्रभाव बालकों को सिखाता है कि सहयोग से काम करने का ठोका काम की व्यवस्था की दृष्टि से स्वाभाविक, सही और यथार्थ है ।

फिर भी पहले कहा गया उदनुसार समूह में व्यक्ति को भुलाया नहीं जाता । शिक्षक पाठशाळा के जीवन के अनेक पहलुओं में प्रत्येक बालक की श्रम का नोट ध्यानपूर्वक रखता है । खुद के दिन भर के काम की, खुद की योजना, शक्ति, क्षमता और समूह के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए विद्यार्थी को कहा जाता है । विद्यार्थी का लिखने का अभ्यास पक्का हो जाता है उसके बाद तुरंत अत्यन्त शासन तरीके से वह लिखने को शुरुआत करता है । विद्यार्थी अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करता है । इस बीच वर्ग में विचार विनिमय होता है, उससे और पाठशाला में सिखाये गये विषयों पर ग्रहणशक्ति ने अनुसार रोजनिशि में विचार प्रदर्शित करने की शक्ति सामान्य शालाओं की अपेक्षा बुनियादी शाला में बहुत उच्च होती है ।

इस तरह सहकारी समाज की व्यवस्था में जवाबदारी और व्यक्तिगत बुद्धि का विकास होता है और इन सादे ठोस उपायों द्वारा बुनियादी पाठशाला के विद्यार्थी लोकतन्त्र की स्वतंत्रता के आवश्यक लाभों का अनुभव करते हैं । लोकतन्त्र के स्वातन्त्र्य का अर्थ है सबकी भलाई के लिए स्वीकार किये गये कानूनों की मर्यादावाला स्वातन्त्र्य ।

४. बुनियादी शिक्षा अहिंसक है यह शिक्षा बालकों के लिए ही है इसलिए उनमें बच्चों की स्वाभाविक प्रेरणाओं की उपेक्षा नहीं होती, वह जीवन में प्रेरक तत्व की तरह है । वह मानव की अपार विविधता का आदर करती है । वह सहकारी है इसलिए बालकों को आपस में एक-दूसरों का आदर करने की तालीम देती है । परस्पर एक दूसरे का स्वेच्छापूर्वक आदर करना, अहिंसक समाज का आवश्यक कानून है । परन्तु यह अहिंसा हिंसा का इनकार मात्र नहीं है ।

गांधीजी के शब्दों के अनुसार, 'अहिंसा सच्चा स्वातन्त्र्य देनेवाली है।' 'स्वातन्त्र्य' शरीर, मन, आत्मा के तन्दुरुस्त विकसितवाली स्थिति है । किन्तु किन्तु चीजों की सच्ची आवश्यकता है इसका ज्ञान स्वातन्त्र्य की बुनियाद है । खादा, स्वात्मभ्रम भोजन, साफ कपड़े, अच्छा मकान, अच्छा आरोग्य, समीप और ताल्लुबद हलचल एवं अपने हाथों में सुन्दर निर्माण की सुखी, कार्य और खेल में मित्र व साथी का आनन्द, इन चीजों की आवश्यकता है । ये सब चीजें अच्छी बुनियादी पाठशाला का वातावरण गुंथी बनाती हैं । सच्ची सम्पत्ति का यह स्तर है कि कृत्रिम मेहुमानपिरो, सोना पीदो और चमकीले कपड़ों की लूणा से मुक्त होना ।

सच्ची सम्पत्ति क्या है इसे अहिंसक समाज समझता है और उससे वह सन्तुष्ट रहता है। इसलिए उसे अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं रहती। सन्तोष, आत्मसंयम, इच्छा तथा स्वामित्व की स्वेच्छापूर्वक भर्थादा नयी तालीम के आचारशास्त्र के अंग हैं।

अहिंसक आचार का मूल्यांकन तब तक पूर्ण और निविध्य नहीं होता जब तक कि गहराई से समाज-व्यवस्था के द्वारा उसकी बुनियाद सत्य पर नहीं रहती। हमारा अन्तिम लक्ष्य राष्ट्र या मानवमान को भलाई है। परन्तु हमेशा समूह के काल्पनिक कल्याण के लिए चारित्र्य और सदबुद्धि व्यक्त के लाभों का बलिदान होने का डर रहेगा, यानी एक या दूसरे रूप में सदैव सरमुह्यारी का डर बना रहेगा। समाज या व्यक्ति का कायमो भला सभी सम्भव है जब वह प्रकृति के नियम या धर्म की भाषा में ईश्वरेच्छा के अनुकूल हो। गांधीजी की तरह सत्य और प्रामाणिकता के लिए सामाजिक दबाव से न झुकनेवाले व्यक्तियों को नयी तालीम पैदा नहीं करती है, तो वह असली महर्ष के प्रदत्त में मानव-जाति के प्रति बेवफा होगी। इसलिए बुनियादी शिक्षा में से सत्य का सर्वोपरि स्थान है। शिक्षा में सबसे कोमल और महत्वपूर्ण काम भावी प्रजा को सत्य और भलाई के लिए आवश्यक पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करने में सहायक होना है। प्रायः बालक को यह सीखना है कि अपनी स्वार्थपूर्ण और आक्रामक प्रेरणाओं को विरुद्ध बनाकर सर्वोदय की ओर से जाना है, क्योंकि इससे स्वयं उसका जीवन अपने साधियों के समाज में पूर्णरूप से फल फूल सजता है। परन्तु अकेला यह बस नहीं है। उसे समझना चाहिए कि समग्र मानव-जाति जिस विश्व की अंग है उसके शाश्वत कानूनों को मान्य करने से और उन कानूनों का अमल करने से ही वह (समग्र मानव-जाति) अपनी पूर्ण शक्ति सौन्दर्य में विवसित कर सकती है। जिस तरह स्वार्थी बालक अपने परिवार को दुःखी करता है उसी तरह मानव-जाति अन्य जीवों के और दुनियारूपों अपने घर के अन्य साधनों की स्वार्थी असावधानता और अक्रमक शोषण से दुनिया के जीवन को दुःखी बनाती है। इसका अर्थ यह है कि स्थायी स्वातंत्र्य के लिए बुनियादी गुण चतुराई और उदारता है। सयानावन सादी भाषा में कहें तो न्यायवत् पूर्ण सत्य पर पक्की भट्टा जो समग्र समाज के जीवन के सुखशान्ति का चित्र देखता है और अपने जीवन को उस विश्व के अनुसार बनाता है। वह सयाना उदारता यानी सबके भले में ही अपनी भलाई के सिद्धान्त पर पक्की थप्पा, सच्चा, प्रेमल, सदार आत्मा मिलता है। उस सबमें भलाई प्रतिविम्बित देखना है। उनके इन विविध व्यक्तियों का अर्थ अहिंसा के

प्रति गहरा आदर होता है। वह किसी मानव को दुखी नहीं करता।

मानव-जाति के दूसरे गुण इन दो के अंग हैं। प्रामाणिकता, वफादारी, हिम्मत, साफ और तेज बुद्धि, निरपेक्ष कुशल हाथ और दृष्टि से सब अच्छे गुण हैं। हमने देखा कि नयी तालीम का लक्ष्य इन गुणों का विकास करना है। परन्तु स्वतंत्र रूप से वे द्वितीय कोट के हैं। अगर उनके मूल में सत्य-अहिंसा नहीं हो तो आसानी से उनका उपयोग चोड़े लोभों के स्वार्थों के लिए या भौतिक विचार-सरणी के लिए किया जा सकता है। हिटलर के जर्मनों और दूसर बहुत से सर-मुस्त्यारी व अग्यायी राज्यों में यही घटित हुआ। प्रामाणिक मानवों ने अपनी कुशलता, बुद्धि प्रामाणिकता और बहादुरी का उपयोग हिंसक और असत्य के बुनियाद-वाली जीवन-प्रणाली के लिए किया है। सज्जनता और भलमनसाईंमूलक शिक्षा ही सत्य-अहिंसा मूलक होने की अधिकारिणी है। परमेश्वर के नाम का उपयोग करें या न करें तो भी यदि नयी तालीम सज्जनता और भलमनसाईं का प्रचार करती है तो वह आध्यात्मिक शिक्षा है।

अगर भारत गांधीजी का चरता पसंद करता है तो वह सज्जनों का आदर करनेवाला और दूर दूर के गाँव के परीब से गरीब सबके सुन्तोय, स्वातन्त्र्य तथा शान्ति से प्रपति मापनेवाला और उनका मूल्य समझनेवाला समाज विकसित करने में काम में लगेगा। इस विकास में शिक्षक और शाला का केन्द्रीय स्थान है।

भारत के छोटे-छोटे गाँव के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकतर खुद करते थे। अपने समाज के व्यवहारों की व्यवस्था भी वे स्वयं करते थे। इन्हीं गाँवों की जमीन ने भारत के बड़े से-बड़े विचारक, कवि और सन्तों को पोषण दिया है। यही ग्रामीण समाज अहिंसक आदर्श के नजदीक आवे। वह आदर्श अभी भी भारत के हृदय में है। नयी तालीम इस अहिंसक आदर्श का निश्चयपूर्वक स्थिर भारतीय समाज की बुनियाद डालने का ध्येय रखती है। भूतकाल की सुन्दर सस्कृति टिकी हुई है, क्योंकि वह सत्य की पहाड़ी चट्टान पर खड़ी है तथा दूसरे देशों के सम्बन्धों से और बड़े हुए ज्ञान से ज्ञाया अलग प्रकार की समृद्ध सामग्री से नयी सस्कृति बनायी जा सकती है। परन्तु मानव के सच्चे स्वभाव से उन्ही सही मूल्यों द्वारा उसी पहाड़ी चट्टान पर नयी सस्कृति चित्रित करनी चाहिए।

स्कूल में सफलता के मार्ग में दस बाधाएँ

स्कूल में बालक की सफलता की सम्भावनाएँ—सफलता जो इस बात से नापी जाती है कि वह विभिन्न परीक्षामो में कितने अच्छे पर्वें करता है। कानून के अनुसार जिस आयु तक स्कूल में पढ़ना जरूरी है, वया उसके बाद भी वह उच्च शिक्षा या ट्रेनिंग के लिए पढ़ाई जारी रखता है—धीरे तौर पर उसको सामाजिक पृष्ठभूमि से हटलुक रखती है। अधिकतर राष्ट्रो में यह ताल्लुक इतना सीधा है कि स्कूलों में यह आरोप लगाया जाता है कि स्कूल छीट-छीटकर बियायीं दाखिल करके यथापूर्व स्थिति को कायम रखने में मदद करते हैं, न कि व्यक्तिगत क्षमतामो और अभिरुचियो के विकास में।

लगभग पिछले पचीस वर्षों में शिक्षा का उल्लेखनीय रूप से जनतंत्रीकरण हुआ है। इस प्रवृत्ति का पता इस बात से लगता है कि स्कूलों में भरती होने-वाले बियायियो और विभिन्न प्रकार के पैक्षिक प्रोग्रामो की सस्था में और स्कूलों पर लर्न की जानेवाली घनराशि में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है।

फिर भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का लक्ष्य आज भी इतना दूर है कि वहाँ तक विश्व के अधिकांश देशो को पहुँचना बाकी है। इसके बावजूद कि अधिकांश सरकारें आज सामाजिक शिक्षा लागू करने के लिए सार्वजनिक रूप में बचतबद्ध हैं, लेकिन सब सो यह है कि शिक्षा की जो सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं, उनमें पूरा लाभ उठाने में बच्चो की एक बहुत बड़ी तादाद असमर्थ रहती है, बहुत से ही विभिन्न पैक्षिक कार्यक्रमो में दाखिला तक पाने में बन्धित रह जाते हैं और बहुत से स्कूल ऐसे कार्यक्रम-सिंयार करने या किसी सेवाएँ प्रदान

करने में असमर्थ होखते हैं जो उन बच्चों और युवाओं की जरूरतें पूरी कर सकें, जिनके लिए वे छोले जाते हैं।

कुछ समूह सजातिक नहीं हैं—अर्थात् इन समूहों के सभी सदस्य एक जैसे नहीं हैं—न उनके बच्चे ही इस कारण स्कूल में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वे किसी ऐसे वर्ग में नहीं आते।

फिर भी, कुछ ऐसे कारण हैं जो कक्षा में दाखिल होने के बाद ही बच्चों की पढ़ाई में रुकावट या बाधा डाल सकते हैं।

१

एक बालक स्कूल में पिछड़ सकता है, अगर वह एक ऐसे परिवार से आता है जो गरीब है।

गरीबी बच्चों को स्कूल में संकलित पाने के अवसरों पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। एक बच्चा जो लगातार भूखा रहता है, उसे स्कूल के सबब पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी ही। एक बच्चा जिसके माँ बाप उसे जहरत के कपड़े नहीं बनवा सकते, शारीरिक असुविधा महसूस कर सकता है या अपने से बेहतर कपड़ोंवाले सहपाठियों के सामन लज्जित महसूस कर सकता है।

एक बच्चा जो बड़ी भीड़ भाड़वाले घर से आता है, जहाँ भोजन हमेशा कम पड़ जाता है या ठीक से संतुलित किस्म का नहीं होता, जहाँ सफाई की व्यवस्था इतनी खराब है कि उसे तरह-तरह की बीमारियाँ लग सकती हैं, वह स्कूल का काम पूरा कर सकेगा, इसकी सम्भावना कम है। एक बच्चा अगर यह देखता है कि उसके पास-पड़ोस के बयस्क लोग या तो बेकार मारे मारे फिरते हैं या फिर बहुत मामूली नौकरियाँ करते हैं, तो वह अपने भविष्य की सम्भावनाओं के बारे में सीमित उम्मीदों का विकास कर सकता है।

२

एक बालक स्कूल में पिछड़ सकता है, अगर उसे अपनी मानसिक क्षमताओं और भाषा का विकास करने के लिए केवल सीमित अवसर ही प्राप्त होते हैं।

मध्य वर्ग के बच्चों के मुकाबले में एक गरीब बच्चे को अपनी मानसिक क्षमताओं और भाषा का विकास करने में अत्यन्त सीमित अवसर प्राप्त होते हैं। निम्न और मध्य वर्ग के बच्चों के छात्रों की शैलियों के भेद अक्सर इस बात का गतीजा होत हैं कि उनके माँ बाप विशेषकर उनकी भाषाएँ उनके साथ किस ढंग

से धोती है और परिवार में एक-दूसरे के प्रति किस प्रकार का व्यवहार चलता है ।

बच्चा कक्षा में अपने साथ भवसे महत्वपूर्ण जो चीज लेकर जाता है, वह होती है उसकी प्रभावी याया । निम्न वर्ग के घर बच्चों को अनेक प्रकार के उद्दीपन प्रदान करते हैं । और उनके अन्दर अनेक योग्यताएँ और क्षमताएँ विकास करने में मदद करते हैं, लेकिन वे अक्सर उन्हें उस कोटि का अनुभव प्रदान करने में असफल रहते हैं, जो एक बच्चे को स्कूल में अध्यापक की माँगों की पूर्ति करने में मददगार साबित हो सकें ।

गरीब परिवारों के बच्चों को अक्सर वास्तु प्रतीकों में भेद करने या फर्क देखने में, मूर्त कार्यों के विपरीत सामान्य प्रत्ययों का प्रयोग करने में, और स्कूल सम्बन्धी कार्य में सफलता के लिए जरूरी अन्य योग्यताएँ प्राप्त करने में अपेक्षा-भूत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है । इस प्रकार, स्कूल ऐसे बच्चे से उन बातों की अपेक्षा करता है, जिनके लिए शैक्षणिक और आरम्भिक बचपन के अनुभवों ने तैयार नहीं किया है । जिससे वह अक्सर शुरू से ही अनुत्तीर्ण होने लगता है ।

३

एक बालक स्कूल में पिछड़ सकता है, अगर उसके घर और पड़ोस के जीवन मूल्यों और कक्षा के मूल्यों में तीव्र अन्तर्विरोध होता है ।

मूल्य, दृष्टिकोण, आत्म सम्बन्धी धारणाएँ, और सफलता पाने की प्रवृत्ति सामाजिक वर्गों से सम्बन्धित हैं । वे मूल्य और आदर्श जो एक बच्चे और उसके परिवार के लिए महत्वपूर्ण और अर्थवान् हैं, सम्भव है कि उनसे सर्वथा भिन्न हों, जो अध्यापकों और स्कूल के दूसरे कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हैं ।

आचरण व्यवहार के वे तरीके, जो परिवार और पड़ोस में पसन्द किये जाते हैं और जिनके लिए बालक को शाबासी मिलती है, सम्भव है कि उन्हें स्कूल के अधिपति घृणा करता है और उनके लिए बालक को दण्ड भी दें ।

विधिवत् शिक्षा प्राप्त करने और स्कूल में सफलता पाने की बात की विभिन्न सांस्कृतिक और जातीय समूह एक जैसा मूल्य नहीं देते । नतीजा यह है कि स्कूल के रूढ़ियों को घर में समर्थन मिल सकता है और नहीं भी । यह देखकर कि घर और पड़ोस में जिस आचरण को अनुमोदित और उचित समझा जाता है, और स्कूल में उससे विपरीत आचरण को पसन्द किया जाता है, एक बालक गहरी उत्पन्न में पड़ जाता है ।

बच्चा जैसे-जैसे बड़ा और परिपक्व होता जाता है, उसके लिए अभिजात वर्ग के मूल्य और आचरण के मानदण्ड अधिक महत्वपूर्ण होते जाते हैं। दरअसल, अभिजातवर्गीय संस्कृति युवाओं के आचरण पर इतनी हावी हो सकती है कि एक विद्यार्थी उन मूल्यों का तिरस्कार या उनकी अवहेलना कर सकता है, जिन्हें उसका परिवार या स्कूल सिखाने की कोशिश करते हैं, अगर वे मूल्य उनसे विपरीत हैं, जो अभिजातवर्ग को महत्वपूर्ण लगते हैं। मूल्य, दृष्टिकोण और भावनाएँ, ये सब स्कूल के वातावरण में अपना योग देने हैं और विद्यार्थी क्या सोचता है और किन बातों को महत्वपूर्ण मानता है, इस पर इस वातावरण का गहरा असर पड़ता है।

४

एक बालक स्कूल में पिछड़ सकता है, अगर वह किसी अल्पसंख्यक कौम या नीच जात का सदस्य हो।

विशेष रूप से अगर वे नजर आते हों या पहचाने जाते हों तो उन बच्चों को, जो अल्पसंख्यक कौमो या नीची जातों के सदस्य हैं और जिनके प्रति समाज में व्यापक रूप से भेदभाव बरता जाता है, स्कूल में पिछड़ सकते हैं। एक बच्चे को अगर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, या अगर वह सोचता है कि उसके साथ भेदभाव बरता जाता है तो इसका अपने और अपनी हीनियत के बारे में उसकी भावनाओं, अपनी कौम के बारे में उसके सहज अभिमान और अपनी सफलता की सम्भावनाओं पर गहरा असर पड़ता है।

निम्न वर्ग के बच्चों या निम्न संस्कृति में पले बच्चों के बारे में अध्यापक तथा स्कूल के अन्य कर्मचारियों की जो निम्नकोटि की आशाएँ होती हैं, अक्सर उन बच्चों के अन्दर अपनी सफलता के बारे में पहले से मौजूद निम्न धारणाओं को और भी पक्का कर देती हैं। चूँकि यह उम्मीद की जाती है कि ऐसे बच्चे सफल नहीं होंगे, अध्यापक उन्हें ध्यान देकर नहीं पढ़ाते और अब वे फेल हो जाते हैं, तो मानो स्कूल की यह भविष्यवाणी, कि ऐसे लड़के तो फेल होंगे ही, पूरी हो जाती है।

निम्न कौमो और निम्न भाषा-भाषी बच्चों को स्कूलों में निम्न कोटि की छालीम दी जाती है। स्कूल के कर्मचारियों में उनके प्रति पूर्वाग्रह और विद्वेष होने के कारण न बच्चों के साथ भेदभाव बरता जाता है, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर भी नहीं दिया जाता। कुछ मिसालें ऐसी भी मिलती हैं कि कुछ समूह अपनी संस्कृति की रक्षा और समृद्धि के लिए कोशिश करते हैं और स्कूल की

ओर से किये गये प्रयत्नों को उन्हें मिटाने की कोशिश के रूप में देखते हैं।
 मेदभाव के कारण कुछ विद्यार्थी सफलता पाने में असमर्थ रहते हैं।

५

एक बालक स्कूल में पिछड़ सकता है अगर वह प्रवासी है।

सैत-मजदूरों के बच्चों को, जो फसल के मौसमों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहते हैं, छानाबंदीश कबीलों, जिप्सियों और घूम-घूमकर काम करनेवाले धर्मिकों के बच्चों को लगातार स्थानान्तरण करना पड़ सकता है। ऐसे भ्रमणशील बच्चे, चाहे जितने भी विविध अनुभव प्राप्त कर लिये हों और विभिन्न किस्म के काम सीख लिये हों, लेकिन स्कूल में या तो इन योग्यताओं की कोई माप्यता नहीं दी जाती या उन्हें महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता।

अक्सर भ्रमणशील बालक को स्कूल या अन्य सार्वजनिक एजेन्सियों द्वारा बोझ ही माना जाता है। चूँकि स्कूल में उनकी हाजिरी अनियमित होती है, इसलिए अध्यापकों की समझ में नहीं आता कि वे ऐसे भ्रमणशील बच्चों के साथ क्या करें, और वे इस इन्तजार में रहते हैं कि वे फिर कभी बले जायें। भ्रमणशील बालक इसलिए पढ़ाई में पिछड़ जाता है, क्योंकि स्कूल या तो ऐसे कार्यक्रम तैयार करने में असमर्थ होता है या तैयार करना ही नहीं चाहता, जिनमें उनके निरन्तर भ्रमणशील जीवन और सांस्कृतिक पद्धति का पूरा विचार रखा जाता हो।

६

एक बालक स्कूल में पिछड़ सकता है, अगर शिक्षा का माध्यम उसकी अपनी मातृभाषा या बोली न हो।

अपने बचपन काल में एक बच्चा जो भाषा सीखता है या अपने घर में जिस भाषा की बोलता है अर्थात् जो उसकी 'मातृभाषा' है—वह अक्सर उससे भिन्न होती है, जिसका प्रयोग स्कूल में उनके अध्यापक करते हैं या जिसका प्रयोग उन पुस्तकों और अन्य पाठ्यसामग्रियों में किया जाता है, जिसका वह इस्तेमाल करता है। इस प्रकार अलग योग्यताओं और क्षमताओं के जवाब, स्कूल में सफलता पाने के लिए जिनका विकास करने की अपेक्षा उससे की जाती है, उनमें ही एक नयी भाषा का सीखना भी हो सकता है।

उसकी मातृभाषा या उसके बोलने का पैटर्न यदि अभी तक परिनिष्ठित नहीं है तो बच्चा पिछड़ सकता है। अध्यापकों द्वारा प्रयुक्त भाषा अगर बालक के घर में बोली जानेवाली भाषा से भिन्न है तो उसे स्कूल में सफल होने के लिए एक

अपरिचित भाषा सबक को समझने और उसका प्रयोग करने की क्षमता प्राप्त करनी होगी। स्कूल अगर उसकी अपनी मातृभाषा या बोली का विस्तार या उसकी अवहेलना करता है, अगर अध्यापक उन बच्चों को दण्ड देते हैं, जो अपरिचित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इससे स्वयं अपने और अपने परिवार के बारे में बालक की भावनाओं पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

७

एक बालक पिछड़ सकता है, अगर वह भौगोलिक दृष्टि से एक अलग जलम निम्न स्थान का निवासी हो।

एक बालक जो किसी दूरदराज, गाँव या बहुत छोटी सीपट्टी में रहता हो, उसे इस दृष्टि से असुविधा हो सकती है कि उसके लिए स्कूल की व्यवस्था उपयुक्त न हो या भौतिक सुविधाओं के कारण वह उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने में असमर्थ हो, या स्कूल में पढ़ाने की बात को उसके यहाँ विशेष मूल्य न दिया जाता हो। मिसाल के लिए उसके माँ-बाप की यह धारणा हो सकती है कि बालक को घर के काम का बनाने की दृष्टि से स्कूल की पढ़ाई अपेक्षाकृत महत्वहीन होती है।

ग्रामीय और नागरिक क्षेत्रों में सांस्कृतिक और भाषागत भेदों के कारण स्कूल में बालक की सफलता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ तक कि एक महानगर के क्षेत्र की गरीब और घनी बस्तियों में रहनेवाले बच्चे भी भौगोलिक विलगाव की स्थिति में हो सकते हैं, इस दृष्टि से कि अपनी बस्ती से बाहर की दुनिया के साथ उनका रैडियो और टेलिविजन के द्वारा हो सम्पर्क होता हो, जगहों बहुत कम या बिल्कुल नहीं। इस प्रकार गरीब और घनी बस्तियों के बच्चों के अनुभवों और स्कूल में दी जानेवाली पाठ्यपुस्तकों में उतना ही बड़ा अन्तर हो सकता है, जितना एक दूरदराज गाँव के बच्चों को महसूस होता है—इसलिए स्कूल में उसकी असफलता की सम्भावना भी उतनी ही बड़ी होती है।

८

एक विद्यार्थी स्कूल में पिछड़ सकता है, अगर वह लड़की है या अगर वह किसी विशेष धार्मिक सम्प्रदाय का सदस्य है।

विभिन्न संस्कृतियों में एक लड़की की शिक्षा का अलग-अलग मूल्य आता है। लड़कियों को स्कूल में कितने साल तक पढ़ाना चाहिए उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए और उनके लिए किस स्तर की योग्यता वांछित है, इनके बारे में विभिन्न संस्कृतियों की अलग-अलग धारणाएँ हैं।

कुछ समूह लड़कियों को स्कूल में भेजने की बात तक का विरोध करते हैं, विशेषकर अगर ऐसे स्कूलों में सहशिक्षा चालू है।

कुछ समाजों में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में इस बात को लेकर मतभेद है कि शिक्षा को कितना मूल्य दिया जाय और एक बच्चे की जीवन-सम्भावनाओं को बदलने में स्कूल की क्या भूमिका होती है। उदाहरण के लिए कुछ धार्मिक सम्प्रदायों का विचार है कि एक बच्चे की सामाजिक-आर्थिक विकास सम्भावना बढ़ाने में स्कूल का कोई योगदान नहीं होता, इसलिए वे स्कूल में सफलता को कोई महत्व नहीं देते।

९

एक बालक स्कूल सम्बन्धी अन्य जनक कारणों से भी पिछड़ सकता है।

अध्यापक-वर्ग, पढ़ाई के प्रोग्राम, सेवाएँ, पाठ्यसामग्री, संगठन, परीक्षा-विधि और उस समाज के साथ स्कूल के सम्बन्ध—जिसका वह एक अंग है—ये सब बातें एक बालक की सफलता की सम्भावनाओं को प्रभावित करती हैं। ऐसे अध्यापक जो तैयारी करके नहीं आते और अयोग्य हैं, ऐसा पाठ्यक्रम जो बिल्कुल असंगत है, स्कूल का अन्य सजाओ सामान जो अपर्याप्त या बेकार है, ऐसे बर्नबारी, जो विद्यार्थियों की उपलब्धियों के बारे में यथार्थपरक दृष्टि नहीं रखते या उनसे मामूली आशाएँ ही रखते हैं, विद्यार्थियों को ऐसे दृष्टि में बाँटना जो कुछ विद्यार्थियों की सम्भावनाओं को समिति कर देते हैं, जो ऐसे स्कूल या प्रोग्राम, जिनमें चुन-चुनकर ही विद्यार्थी भरती किये जाते हैं, और जो गरीबों के बच्चों के साथ भेदभाव या जाति भेद और भाषा भेद की नीति का पालन करते हैं—ये सब विद्यार्थी की सफलता पर प्रभाव डालते हैं।

अधिकांश समाजों में अधिकतर स्कूलों की वार्षिक प्रगतिमात्रों पर बहुसंख्यक सम्प्रदायों का प्रभुत्व चलता है, जिसके कारण सबसे भिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि में पले विद्यार्थियों के लिए विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि, अलग-अलग, गलत पाठ्यक्रम तथा प्रशासकीय विषमता, ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जो कुछ बालकों को पिछड़ी स्थिति में डाल दे, जिससे सफलता पाने की सम्भावनाएँ कम हो जाती हैं।

१०

सामाजिक पृष्ठभूमि एवं स्कूल में सफलता।

दुनिया भर के राष्ट्रों में, चाहे वे विकसित हों या विकासशील हों, जहाँ कम-

या ज्यादा मात्रा में नागरिकीकरण और औद्योगीकरण हो चुका है, विद्यार्थियों की काफी बड़ी संख्या पिछड़ेपन की स्थिति में स्कूलों में दाखिल होती है।

ऐसे विद्यार्थी अक्सर गरीब परिवारों से आते हैं, या अल्पसंख्यक कौमो और नीची जातियों के होते हैं, या ऐसी भाषा या बोली बोलते हैं, जो बहुसंख्यक सम्प्रदाय के मानदण्ड से भिन्न होती है, या किसी अलग बलग क्षेत्र के निवासी होते हैं, या औरत-जाति के होते हैं, या किसी ऐसे धार्मिक सम्प्रदाय से आते हैं, जो शिक्षा को नीची निगाह से देखता है, या प्रवासी होते हैं*। अर्थात् विद्यार्थी जिस पिछड़ेपन की अवस्था का सामना करता है वह उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि और परिवेश से उत्पन्न होती है, और अर्थात् वह स्कूल से ही पैदा होती है। सामाजिक पृष्ठभूमि और शिक्षा समस्याओं का वातावरण दोनों ही मिलकर सफलता असफलता का कारण बनते हैं।

शैक्षिक अवसर की बराबरी एक ऐसा विचार है जिसके पीछे शिक्षा सम्बन्धी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कई प्रकार की समानताओं का भाव अन्तर्निहित है। विद्यार्थी की सामाजिक पृष्ठभूमि और स्कूल में उसकी सफलता में जो महत्त्व सम्बन्ध है उसकी स्वीकृति ही इस समस्या को समझने की दिशा में पहला कदम है ही, कि उन लोगों की सफलता के अवसर बढ़ाने ■ लिए किस प्रकार के परिवर्तन करने जरूरी होंगे, जो अनेक कारणों से इस समय पिछड़ी अवस्था में हैं। ('यूनेस्को कूरियर' जुलाई, '७२ से साप्ताहिक पुनमुद्रित ।)

*शरणार्थियों, युद्धपीडितों और राजनीति से प्रभावित लोगों का एक ऐसा वर्ग भी है जिसे आश्रय देनेवाले राष्ट्र में न अधिकार ही मिलते हैं, न वे सुविधाएँ ही जिनमें शिक्षा की सुविधाएँ भी सम्मिलित हैं।—सम्पादक।



चेकोस्लोवाकिया के नर्सरी स्कूल

चेकोस्लोवाकिया में शिशु विहार (क्रेडेज) और नर्सरी स्कूल बच्चों और नौयुवकों की शिक्षा और प्रशिक्षण-प्रणाली की प्रथम कड़ी है । सन् १९६० के शिक्षा-कानून ने नर्सरी स्कूलों के लक्ष्य की इस प्रकार परिभाषा की है :

“परिवार के सान्निध्य और सहयोग में तीन वर्ष की अवस्था से लेकर नौ वर्षवाले बेसिक स्कूलों में जाना प्रारम्भ करने की अवस्था तक नर्सरी स्कूल बच्चों के चतुर्दिक विकास की देखभाल करते हैं ।”

यह शिक्षा-कानून राष्ट्रीय कमिटियो (प्रशासन के चुनाव द्वारा निर्मित स्थानीय संगठन) को नर्सरी स्कूलों के जाल को और विस्तृत करने का उत्तरदायित्व देता है ताकि वे नौकरी कर रही माताओं के बच्चों के अलावा पाँच वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को भरती कर सकें । ऐसे स्कूलों की भरती के सम्बन्ध में नौकरी कर रही माताओं के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है । इस तरह, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में नर्सरी स्कूल एक महत्वपूर्ण रोल भटा करता है । ये नर्सरी स्कूल झुलते भी ऐसी ही जगह हैं, जहाँ छोटी उम्र के कम-से-कम २० बच्चों की तरफ से दृष्टांति होती है कि ये नर्सरी स्कूलों में नियमित रूप से आकर पढ़ेंगे । ऐसा इसलिए करना पड़ता है; क्योंकि चेकोस्लोवाकिया के सभी नर्सरी स्कूल राज्य द्वारा संचालित होते हैं ।

कहीं-कहीं स्कूल में लगनेवाले छाषमों और उसके चलाने का सर्व कैबिड्रमो और कृषि सहकारी संस्थानों द्वारा ठठाया जाता है, विशेषतः जबकि स्कूल इन्हीं संस्थानों में काम करनेवाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए खोला जाता है । ऐसे नर्सरी स्कूलों की कुल संख्या स्कूलों की सारी संख्या की सिर्फ ५० प्रतिशत है । ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल-प्रशासन करता है और उन्हें वेतन वही देता है ।

सन् १९६९ और ७० के शिक्षा सत्र में चेकोस्लोवाकिया में आठ हजार एक सौ तिहत्तर नर्सरी स्कूल थे, जिनमें तीन लाख सवहत्तर हजार सात सौ बासठ, यानी तीन से ६ वर्ष की आयु के बच्चों की पूरी जनसंख्या के पचास प्रतिशत बच्चे पड़ते थे । नौ वर्षवाले बेसिक स्कूलों के प्रथम वर्ष के सत्तर प्रतिशत बच्चे पहले नर्सरी स्कूलों में ही शिक्षा पाते हैं । नर्सरी स्कूल अधिवासतः (८८ प्रतिशत) प्रतिदिन दस-ग्यारह घण्टे चलते हैं । इनमें पढ़नेवाले अधिकांशतः बच्चे नौकरी करनेवाली माताओं के होते हैं । शेष नर्सरी स्कूलों में बच्चे प्रतिदिन पाँच घण्टे रहते हैं । नर्सरी स्कूलों की एक बहुत ही छोटी संख्या (५९) सोमवार से लेकर शनिवार तक पूरे हफ्ते चलती है । इन स्कूलों में खासकर वही बच्चे

पढ़ते हैं जिनकी माताएँ घर में अकेली होने के कारण रोजी-कमाई में लगी रहती हैं या माँ की लम्बी बीमारी के कारण जिनकी कुछ समय तक और कोई देखभाल नहीं कर सकता। ऐसे स्कूल कुछ अंग्रेजों में बच्चों के घर की तरह ही होते हैं, जिनकी एक विशेषता यह भी होती है कि वे बच्चों के परिवार से बराबर सम्पर्क बनाये रखते हैं।

जिन जगहों में बच्चों की कम संख्या के कारण नर्सरी स्कूल नहीं खुल सकता, वहाँ स्थायी या कुछ समय के दिवा-घर स्थापित किये जाते हैं। ये तभी खोले जाते हैं जब कम-से-कम १० बच्चों की तरफ से इन्हें खोले जाने की दर्तास्त पड़ती है। इनमें दो वर्ष से ऊपर के बच्चे रखे जाते हैं। कोई तरह हुआर बच्चे इन दिवा-घरों में आते व रहते हैं। जहाँ लड़कों की कम संख्या के कारण नये नर्सरी स्कूल नहीं खोले जा सकते, वहाँ आसपास के नर्सरी स्कूलों में ही एक से तीन वर्ष के बच्चों के लिए बसाएँ बढ़ा दी जाती है। ये बच्चे शिक्षा स्वास्थ्य-विशेषज्ञ, नर्सों व अभिभावकों द्वारा देखे भाले जाते हैं, उसी तरह जैसा नर्सरी स्कूलों में नियम है।

विशेष स्कूल हॉल में, स्थानीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विहार और नर्सरी स्कूल दोनों एक ही भवन में रखे गये हैं और उन्हें एक मिली-जुली संस्था की तरह संचालित किया जा रहा है। इन सुविधाओं का मुख्य लाभ यह है कि इनसे पेटेवर कार्यकर्ताओं, नर्सों, डाक्टरों और शिक्षकों की एग टाइम बन जाती है, जिनसे बच्चों के, छोटी उम्र से लेकर स्कूल जाने की उम्र तक, सर्वांगीण विकास की गारण्टी मिल जाती है। नर्सरी स्तर से नर्सरी स्कूल तक परिवर्तन की इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है ताकि बच्चों और उनके माँ-बाप को कोई कठिनाई न हो।

नर्सरी स्कूल में सिर्फ तन्दुरस्त बच्चे भर्ती किये जाते हैं। मानसिक या शारीरिक छराबियों जैसे त्रुटिपूर्ण मानसिक विकास, बाणी सम्बन्धी खराबी, सुनने की खराबी, दृष्टि की कमजोरी, विकृष्ट या किसी बीमारी की वजह से कमजोर शरीर या दाँत से यों ही कमजोर रह गये बच्चों के लिए विशेष नर्सरी स्कूल खोले गये हैं जिनमें ऐसे बच्चों की खास परवाह की जाती है। ऐसे बच्चे, जिनमें मिली जुली अनेक प्रकार की खराबियाँ हों, उनसे लिए अस्पताल में नर्सरियों या चिकित्सा सम्बन्धी विशेष दैनिक संस्थाओं की व्यवस्था की गयी है।

नर्सरी स्कूलों में शिक्षा निःशुल्क है। माँ-बाप सिर्फ बच्चों के खाने का खर्च देते हैं। फीस माँ-बाप की आमदनी के हिसाब से रखी जाती है, फिर भी, ऊँचो-से ऊँचो फीस छाने के खर्च के बराबर ही आती है।

किसी नर्सरी स्कूल में नियमित रूप से दैनिक कार्यक्रम वर्णित रहता है। यह इस तरह रखा जाता है ताकि बच्चों के नियमित व ठीक रहने-सहने से उसका ठीक मेल बैठ सके और बच्चों को खेलवूद का, बाहर रहने व आराम करने का काफी समय मिल सके। नर्सरी स्कूल में बच्चों को तीन बार भोजन मिलता है। माँ के काम में लगे रहने पर बच्चा अपने ही भरोसे रहता है, लेकिन ६ घंटे शाम के बाद ऐसा नहीं होता। सब बच्चे सुबह नौ बजे के पहले इकट्ठा होते हैं और तीसरे पहर की घाम के बाद तितर-बितर हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में वे अपना ज्यादा समय नर्सरी स्कूल के बगीचे में बिताते हैं। लेकिन वे तुरन्त मौसम ठक में या जाड़े में भी कम से कम दो घण्टे प्रतिदिन नियमित रूप से ठहरने जाते हैं।

नर्सरी स्कूलों का शैक्षिक कार्य छोटे बच्चों और नर्सरी स्कूलों की शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के अनुरूप ही होता है। यह एक स्टैण्डर्ड कार्यक्रम होता है जो अपनी स्वरूपा में सबके लिए अनिवार्य होता है। यह पाठ्यक्रम की अलग-अलग आवश्यकताओं का प्रत्येक बच्चे की परिपक्वता, विशेषता तथा स्थानीय परिस्थितियों से सम्मेलन बैठता है। यह कार्यक्रम उन कामों का विस्तार से वर्णन करता है जो शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक तथा सौंदर्य-बोध सम्बन्धी शिक्षा के सम्बन्ध में पूरे किये जा सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में शिक्षक व शिष्य के वैयक्तिक सम्बन्धों पर जोर दिया जाता है।

शिशु विहार व नर्सरी स्कूलों के लिए गिब्लोने और शैक्षिक सहायक सामग्री एक विशेष फैब्रि द्वारा ही सफाई की जाती है। यह फैब्रि 'टीचिंग एड्स' (शैक्षिक सहायक सामग्री) नाम से जानी जाती है, जो सभी प्रकार के स्कूलों को सहायक सामग्री पहुँचाने की गारण्टी देती है। राज्य के अध्ययन शास्त्र सम्बन्धी प्रकाशक सभी आवश्यक छायांक साहित्य प्रकाशित करते हैं। शिक्षकों के उपयोग के लिए प्री स्कूल एजुकेशन (बाला पूर्व शिक्षण) नाम का एक व्यवस्थित मासिक भी प्रकाशित किया जा रहा है।

नर्सरी स्कूलों में माँ-बाप से सहकार-सम्पर्क पर काफी ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक नर्सरी स्कूल में माँ-बाप व शिक्षक सब होता है। इसका काम स्कूल को शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापों में मदद, बच्चों के माँ-बाप के बीच अध्यापन शास्त्र व स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों की जानकारी फैलाना तथा स्कूल को अच्छी तरह चलाने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति के सुधार में हिस्सा लेना है।

समय-समय की सम्मिलित गोष्ठियों में शिक्षक बच्चों के माँ-बाप व अभि-

भावरो को नर्सरी स्कूल की समस्याओं से परिचित कराते हैं और इस बात पर विचार-विमर्श करते हैं कि माँ-बाप इन समस्याओं का हल करने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। शिक्षण माँ-बाप से उनके बच्चों के बारे में व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि बच्चों पर किस प्रकार का असर डाला जाय ताकि उसके व्यक्तित्व का सही विकास हो।

स्कूल स्वास्थ्य अधिकारी नर्सरी स्कूल में नियुक्त समय पर नियमित आता रहता है। साठमर में एक बार बच्चों की बायीं गिटरा से स्वास्थ्य परीक्षा होती है। उनके दाँतों की नियमित जाँच होती रहती है और बच्चे दसमांक व चिकित्सा के लिए दाँत-बेग्गो को भेजे जाते हैं।

प्रशिक्षण

बच्चों की पूरे दिन दसमांक करनेवाले प्रत्येक प्रकार के नर्सरी स्कूल में दो शिक्षक होते हैं, जिसमें से एक पूर्वाह्न व दूसरा अत्रान्ह इपूटी पर रहता है। ये शिक्षक प्रति सप्ताह ३१ घण्टे पढ़ाते हैं। ये लोग शिक्षकों के चार वर्षीय स्कूल में प्रशिक्षित होते हैं, जिसके बाद उनसे उत्तर बेसिक के नौ वर्षीय स्कूलों में काम लिया जाता है। सभी के उत्तर बेसिक की नौ वर्षीय शिक्षा देने के अधिकारी ममझे जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग एक इन्सट्रान लेकर समाप्त की जाती है। इस इन्सट्रान का स्तर हायर स्कूल परीक्षा के बराबर माना जाता है। अगर जरूरी हुआ तो सेकण्डरी स्कूल के प्रेजुएण्टों के लिए दो साला पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। इन प्रेजुएण्टों को पढ़ते वारह वर्षों की स्कूली शिक्षा मिल चुकी रहती है। इन दोनों प्रकार के नर्सरी स्कूलों में शिक्षाविद्या की संगीत, शारीरिक व्यायाम व कला प्रतिभा की जाँच-परीक्षा देनी पड़ती है।

शिक्षकों की स्नातकोत्तर ट्रेनिंग अध्यापन शास्त्र के क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है। उनके लिए व्यवस्थित अध्ययनों के कई चक्रों तथा अनेक प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। जहाँ तक जिले का सम्बन्ध है, जिले के अध्यापन-शास्त्र-केंद्रों द्वारा व्यवस्थित कार्य की योजना होती है। ये जिला केन्द्र नर्सरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए थोड़े दिनों का पाठ्यक्रम चलाने, अच्छे शिक्षकों के लिए आपस में अनुभव के आदान-प्रदान की व्यवस्था करते और नर्सरी स्कूलों के पर्यवेक्षण का प्रबन्ध भी करते हैं। जिला पूर्व शिक्षा के जिला इन्सपेक्टर का काम शिक्षकों की निगरानी के साथ-साथ उन्हें व्यवस्थित सहायता देना भी है।

सौजन्य : जैन पेस्टल
रूपान्तरण ॥ रामभूषण

शिक्षक और अभिभावक : सहयोग की आवश्यकता

यह सर्वमान्य सत्य है कि घर, पड़ोस, समाज और शास्त्र सभी बालक पर प्रभाव डालते हैं। परिवार जीवन की अमर पाठशाला है—यह कहावत प्रसिद्ध है। अनन्तकाल से परिवार बच्चों की शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा है। वह बुनियादी शिक्षा देता रहा है जिसके आधार पर उनके भावी जीवन की भव्य इमारत खड़ी की जाती है। परिवार की यह शिक्षा उस समय तक चलती रहेगी जब तक अन्तिम मानव इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। इतिहास बताता है कि विश्व के प्रत्येक शिक्षाशास्त्री ने शिक्षा के इस महान केन्द्र 'घर' अथवा परिवार को सर्वाधिक महत्त्व दिया है। यह सत्य है कि ग्रीस में स्त्रियों को प्रधानता न दिये जान के कारण उनके परिवार को उतना महत्त्व नहीं दिया, किन्तु छाक, लसो, पेस्टालाजी इत्यादि शिक्षाविदों ने परिवार को शिक्षा के केन्द्र के रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। अभी-अभी कुछ वर्षों से परिवार की यह महान संस्था कुछ छिन्न भिन्न सी होती दिखायी दे रही है तथा इसका महान उत्तरदायित्व अब अन्य संस्थाओं द्वारा वहन किया जा रहा है।

जीवन पर अमिट प्रभाव

आधुनिक काल में औद्योगीकरण एवं वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप जीवन की जटिलता तथा संघर्ष बढ़ गया है। माता पिता अपनी जीविका अर्जन एवं जीवन-संघर्ष में इतने व्यस्त हो गये हैं कि उनके पास इतना समय नहीं कि वे बच्चों की ओर ध्यान दे सकें। इसलिए उनकी शिक्षा के लिए अधिक से अधिक शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। आज चाला बच्चों की शिक्षा का प्रधान केन्द्र हो गयी है तथा घर की जिम्मेदारी शास्त्राओं पर डाल दी गयी है। किन्तु यह

सत्य है कि बच्चा शाला में जो कुछ सीखता है वह उसके लिए पर्याप्त नहीं होता । वास्तव में शाला में प्राप्त किये गये उसके अनुभव अधूरे होते हैं तथा शाला से बाहर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त किये गये अनुभव ही उसकी पूर्ति करते हैं, फिर चाहे वे अच्छे हों अथवा बुरे । उदाहरण के लिए शाला बच्चों को नैतिक शिक्षा देती है तथा उन्हें सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाती है । किंतु शाला के बाहर जब उन्हें दूसरे प्रकार का वातावरण मिलता है तो वे झूठ बोलना और चोरी करना सीख जाते हैं । यहाँ शाला का प्रभाव बच्चे के लिए व्यर्थ सिद्ध हो जाता है । इसके विपरीत घर या परिवार के संस्कार बच्चे पर वह अमिट प्रभाव डालते हैं, जिसे कोई नहीं मिटा सकता । वास्तविकता में बच्चे का जीवन एवं उसके कार्यक्रम घर तक ही सीमित रहते हैं । अतः घर का वातावरण उसके सुकोमल अपरिपक्व मन पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है । इस समय जिस तरह के संस्कार उन पर पड़ते हैं, उनका प्रभाव सम्पूर्ण जीवन भर उन पर बना रहता है ।

आधुनिक शोधकर्त्ताओं का मत है कि शिक्षक भी घर की ही तरह प्रभाव-शाली हो सकता है, यदि वह शाला के बाहर जीवन के विभिन्न अनुभवों के निकट सम्पर्क में रहे तथा उनके और शाला के बीच समन्वय स्थापित करते हुए बच्चे को शिक्षा प्रदान करे । यद्यपि यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि बच्चा जब शाला में प्रवेश लेता है, तो घर के प्रभाव की नींव उसमें पहले से ही पड़ी रहती है तथा शिक्षक एवं शाला उसी पर आये कार्य कर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं । इस प्रकार बालक को एक विशेष राई में डालने तथा उसके जीवन को एक विशेष दिशा देने में आज भी घर या परिवार एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली माध्यम का कार्य करता है ।

इसमें कोई शक नहीं कि आज के शिक्षक यह महसूस करते हैं कि बालक को यदि उचित शिक्षा देनी है तो उसके व्यवहार, उसके घर तथा उसके आसपास के सामाजिक वातावरण का ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है । यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि अब माता-पिता भी यह महसूस करने लग गये हैं कि घर और समाज का वातावरण बालक के विकास पर बड़ा प्रभाव डालते हैं । चाहे वह नकारात्मक हो अथवा स्वकारात्मक । इस प्रभाव की उपयोगिता इस बात पर निर्भर है कि माता-पिता अपने बाल विकास के अनुभवों का परिवार में समुचित प्रयोग कर । माता-पिता की इसी अनुभूति का परिणाम है कि आज इस बात की अधिकाधिक माँग हो रही है कि अभिभावकों को भी बाल-संरक्षण एवं बाल विकास में प्रशिक्षण

दिया जाय। सर सिरिलवर्ट ने अपने शोध-कार्य के निर्णय में स्पष्ट कहा है कि यदि लेसेज फेंडर की नीति को चलने दिया गया तो पचास वर्ष की थोड़ी-सी अवधि के भीतर ही विद्याप्रिय छात्रों की संख्या घटकर आधी रह जायगी तथा कमजोर दिमाग के छात्रों की संख्या दुगुनी हो जायगी। संक्षेप में यदि प्रबुद्ध समाज का निर्माण करना है तो आज के एष भावी अभिभावकों के प्रशिक्षण के लिए उचित कार्यक्रम का आयोजन अनिवार्य है।

शिक्षक-अभिभावक का निकट सम्पर्क

उपर्युक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि शिक्षकों एवं अभिभावकों को एक दूसरे के निकट सम्पर्क में लाया जाय तथा उनके समान हितों के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाय। आज शाळा और घर के बीच निर्मित खाई को पटाने की जरूरत है। सभी आधुनिक युग के लिए उपयुक्त समन्वित व्यक्तित्वपूर्ण छात्रों का निर्माण सम्भव हो सकेगा और इसके लिए शिक्षक-अभिभावक सहयोग को प्राथमिकता देना अत्यन्त आवश्यक है। यह सहयोग अभिभावकों को उन कठिनाइयों एवं बाधाओं से परिचित करावेगा, जिनका सामना शिक्षकों को छात्रों को पढ़ाते समय करना पड़ता है। यह सहयोग शिक्षकों को भी छात्रों के माता पिता, घर के वातावरण, इत्यादि से सभसने में सहायता प्रदान करेगा और वे छात्रों की शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विशेषताओं का सही ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुसार उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करने में सफल हो सकेंगे।

यह सत्य है कि अत्यन्त प्राचीन काल में शिक्षक-अभिभावक सहयोग नहीं था, और इसकी उस समय आवश्यकता भी नहीं थी। उस समय समाज की आवश्यकताएँ और माँगें बहुत कम थी। परिवार का मुखिया ही घर का शिक्षक होता था, परिवार एवं समाज का जीवन ही पाठ्यक्रम था तथा जीवन की आवश्यक बातें सीखने के लिए अनुकरण ही एकमात्र शिक्षण-पद्धति थी। इस प्रकार बालक परिवार में रह कर ही सत्य, सेवा, स्नेह, त्याग, कष्टतृप्ति एवं न्याय सरीखे महान गुणों को सीख लेता था।

किंतु आज सभ्यता के विकास तथा समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं और माँगों ने जीवन को डुरूह और जटिल बना दिया है। आरम्भ में शिक्षा का उद्देश्य लिखना-पढ़ना सीखना था, किन्तु यह स्थिति उसी समय तक रही जब तक जीवन सरल था और समुक्त परिवार की व्यवस्था थी। कालान्तर में यह व्यवस्था टूट गयी और जीवन को कठिनाइयाँ बढ़ गयीं। यही कारण है कि आज बालकों के चरित्र-निर्माण तथा उसकी व्यावसायिक शिक्षा का उत्तरदायित्व शाळाओं पर आ पड़ा।

आज अभिभावक अपने बच्चों के भावी भाग्य निर्माण के लिए पूरी तरह से शिक्षकों एवं शालाओं पर निर्भर हैं। यह वाछनीय नहीं है। कारण, परिवार और समाज वास्तव में एक दूसरे के निर्माता हैं। वास्तव में माता-पिता और शिक्षक दोनों के पूर्ण सहयोग एवं निःस्वार्थ भाव से घर और शाला तथा समाज में बालकों एवं नौजवानों के हित में कार्य करना चाहिए।

अक्सर देखा जाता है कि बालक शाला में जिस तरह का व्यवहार करता है, घर में उससे भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। घर में अभिभावक तथा शाला में शिक्षक को इसे देखकर बालक के वास्तविक स्वभाव को समझने में कठिनाई होती है। बालक के असली रूप को समझने में असफल होने के कारण वे उसके वास्तविक विकास में मदद नहीं पहुँचा सकते और सम्पूर्ण स्थिति एक समस्या बनकर रह जाती है। इस समस्या का हल शिक्षक अभिभावक सहयोग से ही सम्भव हो सकता है।

यह भी अक्सर देखा जाता है कि बालकों को पाठ्यक्रम चुनाव की सलाह देते समय अभिभावक अपनी स्वयं की इच्छा एवं महत्वाकांक्षा को ही ध्यान में रखते हैं। प्रत्येक माता-पिता की इच्छा रहती है कि उनका बालक डाक्टर, इंजीनियर अथवा ऐसा ही कोई उँचा पद प्राप्त करे। अतः इसके अनुसार वे विज्ञान, गणित इत्यादि विषयों को लेने के लिए अपने बच्चों को बाध्य करते हैं। परिणाम यह होता है कि बालकों की इच्छा व योग्यता को ध्यान में रखे बिना जिन विषयों का चुनाव करा दिया जाता है, उसमें वे असफल होते हैं। बालकों को इससे निराशा तो होती ही है, साथ ही अभिभावकों को भी आर्थिक हानि के साप-साप पड़ती निराशा का सामना करना पड़ता है। शिक्षक-अभिभावक सहयोग के माध्यम से यह कठिनाई भी हल की जा सकती है। शाला में शिक्षक एवं विशिष्ट निर्देश अधिकारी बालक की रुचि एवं योग्यता का आकलन कर उसे अभिभावक को बता सकेंगे तथा अभिभावक इसके अनुकूल इच्छाओं तथा महत्वाकांक्षाओं का समायोजन कर सकेंगे।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए सही शिक्षा

यहाँ यह देना असंगत न होगा कि जनतंत्र के स्थायित्व के लिए मजबूत स्तम्भों की जरूरत होती है और इनकी शिक्षा उचित रीति से हो, यह आवश्यक है। चूँकि हमारा देश स्वतंत्र है और उसने जनतंत्रीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, अतः उसकी सफलता यहाँ के शिक्षित नागरिकों पर निर्भर है। आज के बालक कल के नागरिक होंगे, अतः आज शिक्षकों और अभिभावकों का उत्तरदायित्व बढ़ गया

है। अब हमें आनेवाली पीढ़ी की प्रवृत्तियों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन करना होगा। इसके लिए भी शिक्षक अभिभावक सहयोग नितांत आवश्यक है।

आधुनिक समय की बदलती हुई परिस्थितियों में नयी प्रगतिशील शिक्षण-पद्धतियों को अपनाया जा रहा है। किन्तु अभिभावकगण अब भी उनसे अपरिचित हैं। वे पुरानी परम्परागत पद्धतियों के आदी हैं, तथा चाहते हैं कि शिक्षक पूरे समय बोलते रहे। यदि वे देखते हैं कि बालक क्लाइबेरी में चुपचाप स्वयं अध्ययन कर रहे हैं अथवा प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हैं और शिक्षक केवल उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं तो अभिभावक उनकी आलोचना करते दिखाई देते हैं। शाला या शिक्षा व्यवस्था में किसी भी नये परिवर्तन को वे सन्देह की दृष्टि से देखते हैं तथा उसका विरोध करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि अभिभावकों को शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों व नयी शिक्षण-विधियों से परिचित कराया जाय और यह शिक्षक-अभिभावक सहयोग से ही सम्भव हो सकता है।

मेरा क्याल है कि जब तक शिक्षकों और अभिभावकों में पूरा-पूरा सहयोग नहीं होता तथा जब तक उनमें एक दूसरे के प्रति आत्मीयता और सहानुभूति की भावना नहीं आती तब तक 'शिक्षा' अपने वास्तविक अर्थ में पूरी नहीं हो सकती, तथा छात्रों का अहित ही होता रहेगा। पारंपार्य देशों में शिक्षक-पालक सहयोग सघ बढी सख्या में कार्य कर रहे हैं तथा अनेक तरह से शाला-कार्य में मदद पहुँचा रहे हैं। अमेरिका में 'राष्ट्रीय अभिभावक-शिक्षक' नामक एक पत्रिका निकलती है जो इस दिशा में प्रशसनीय कार्य कर रही है तथा, शिक्षा की अनेक समस्याओं को सहज ही हल करने में सहायता पहुँचाती है। आज समय आ गया है जब केवल 'घर' और अभिभावकों की महत्ता मान्य बता देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनका पूरा पूरा सहयोग प्राप्त कर शिक्षा को अधिक उपयोगी और प्रभावपूर्ण बनाया होगा तभी हम अपने देश और राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। ●

७१५० बैजनाथ पारा, रायपुर, मध्य प्रदेश एव

आचार्यकुल : गतिविधि

(मध्य प्रदेश मासिक कार्यविवरण, माह अगस्त १९७२)

धम्मलपाटी क्षेत्र में संगठन प्रखण्ड और ग्रामीण स्तर तक विकसित हुआ है। अभी तक ग्राम जिले के मुख्य स्थान पर आचार्यकुल की भावना और विचारों से प्रेरित रहनेवाले लोग एकट्ठा होकर स्वयं रूप से जिला आचार्यकुल बना लेते थे, और स्वयं जिला संयोजक प्रखण्ड और ग्राम स्तर तक उसे व्यापक करने का प्रयत्न करते थे। अब धम्मल पाटी क्षेत्र में स्वयं रूप से प्रयत्न के परिणामस्वरूप निम्नांकित जिला में संगठन नीचे तक गया है और इस मास में १५५ नये सदस्य बने हैं।

जिले	आचार्यकुल	प्राथमिक आचार्यकुल
ग्वालियर १	(सालबर्दी, डबरा, मितरवार)	१०
शिवपुरी ३	(मणरीनी, तरवार, पोहरी)	१२
भुरना १	(जीरा अम्बाह, सबरगढ)	८

भाषा है कि दतिया, भिण्ड और गुना में भी इसी तरह काय व्यापक होगा।

आचार्यकुल की शैक्षिक नीति और कार्यक्रम पर प्रखण्ड स्तर की गोष्ठियाँ . ३ अगस्त को ब्योपुर (भुरना) १८ अगस्त को डबरा (ग्वालियर), और २८ अगस्त को शिवपुरी में प्रखण्ड स्तरीय गोष्ठियाँ आयोजित हुईं। ब्योपुर गोष्ठी में उस समय वहाँ चल रहे पुलिस आतंक पर सदस्यों ने अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। डबरा और शिवपुरी की गोष्ठियों में श्री दादाभाई नार्दिक और श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तीनों गोष्ठियों में प्रदेशीय संयोजक की उपस्थिति रही।

प्रदेशीय स्तर पर कार्य-संगोष्ठी : ग्वालियर में दिनांक १३. ८. '७२ को प्रदेशीय स्तर पर एक कार्य-संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश आचार्यकुल सदस्य समिति के ९ सदस्य तथा भुरैना, शिवपुरी, दतिया, रामपुर, रतलाम, सरगौन और भोपाल ७ जिलों के १० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । इसमें निम्नांकित निर्णय लिये गये :

(१) नवम्बर में केन्द्रीय आचार्यकुल समिति की बैठक का स्थान शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर रखना तय हुआ । इसी अवसर पर मध्य प्रदेश आचार्य-कुल का द्विदिवसीय सम्मेलन बुलाने का तय किया गया ।

(२) प्रदेशीय सम्मेलन के अवसर पर सदस्य समिति के स्थान पर, प्रदेशीय आचार्यकुल का विधान के अनुसार संगठन किया जाय ।

केन्द्रीय आचार्यकुल का योगदान : १५ अगस्त, १९७२ ॥ श्री दादामाई नाईक जी ग्रामस्वराज्य-पदयात्रा में केन्द्रीय आचार्यकुल के संगठक श्री कामरेवर प्रसाद बहुगुणा २८ अगस्त तक साथ रहे और स्थान स्थान पर आचार्यकुल के विचार को फैलाया ।

मध्य प्रदेश ग्रामस्वराज्य-पदयात्रा : मध्य प्रदेश सदस्य समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री दादामाई नाईक जी ग्रामस्वराज्य-पदयात्रा के दौरान जब श्री प्रमोद उपाध्याय, जिला सघोजक आचार्यकुल, छिंदवाड़ा, दिनांक २८ अगस्त १९७२ से गाँव-गाँव में आचार्यकुल का विचार फैलाने और आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक एवं प्रत्यक्ष स्तर पर सदस्य सघोजक मनोनीत करने का कार्य करेंगे । उन्हें प्रदेशीय सदस्य समिति में सदस्य सहवर्तित कर प्रदेशीय संगठक के रूप में मनोनीत किया गया ।

राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में मध्य प्रदेश आचार्यकुल के सदस्य भाग लेंगे : सभी जिला संयोजकों की सेवाग्राम, वर्धा में होनेवाले राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन १४, १५ अक्टूबर, '७२ में भाग लेने के लिए लिखा गया, कार्य-संगोष्ठी का विवरण व ग्रामस्वराज्य-पदयात्रा में योगदान विषयक परिपत्र भेजे गये ।



आचार्यकुल : गतिविधि

(दिल्ली प्रदेश आचार्य कुल की अपील)

आज हम देश की आजादी की रजत-जयन्ती मना रहे हैं । वह आजादी एक लम्बी लड़ाई के बाद हासिल हुई थी । वह लड़ाई विचार, प्रेम त्याग तथा बलिदान के रास्ते से लड़ी गयी थी । जगत के इतिहास में महिसक लड़ाई का वह पहला और बड़ा सफल प्रयोग था । प्रयोगवीर या मानवता का मसीहा महात्मा गांधी ।

अब हम जनतन्त्र में जी रहे हैं । जनतन्त्र का जन यदि सूखता जायेगा और तन्त्र फूलता जायेगा तो जनतन्त्र को बड़ा खतरा है । इससे बचने के लिए अनेक निःस्वार्थ और सेवामय संगठनों के आधार पर लाक्षणिक को संगठित करना पड़ेगा । इस कार्य के लिए एक इन्सान ने अभी-अभी इस देश की पंद्रह साल तक पैदल परिक्रमा करके लोगों के दिलों को जगाया । छोटे बड़े लाखों किसानों ने एक भी पैसा लिये बिना प्रेम से १५ लाख एकड़ जमीन दी, जो बेजमीन, बसहारा, भेड़नरक या मजदूरों की बाँटी गयी । वह कमवीर है विश्वनाथ विनोबा ।

एक ने स्वराज का रास्ता दिखलाया, दूसरे ने सर्वोदय का । स्वराज के बाद अब सर्वोदय ।

एक ने राजनीतिशास्त्र में अहिंसा को सफल किया, दूसरे ने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में ।

एसी राजस्वी और पराक्रमी अहिंसा द्वारा स्वयं हमें हमारी छोटी-मोटी समस्याओं को सुलझाने की शक्ति हासिल करके सर्वोदय की ओर अग्रसर होना है ।

इसके लिए अच्छा अवसर है—११ सितम्बर, विनोबा जयन्ती, २ अक्टूबर, गांधी-जयन्ती । आपकी संस्था में व्यवस्थित आयोजन करके ये दोनों जयन्तियाँ उत्साहप्रद ढंग से मनायें । निम्न कार्यक्रमों में से अधिक-से-अधिक का आयोजन करके शिपकों तथा छात्रों को लामावित कीजिए ।

(१) छात्रों तथा शिक्षकों को समा में इन महापुरुषों के जीवन और विचारों में विविध पहलू प्रस्तुत किये जायें ।

सितम्बर, '७२]

[९३]

(२) विचार गोष्ठी का आयोजन करें ।

(३) शिक्षकों तथा छात्रों द्वारा सस्था की सफाई का कार्यक्रम रखा जाय ।

(४) किसी गाँव में या बस्ती में धर्मदान किया जाय ।

(५) शिक्षकों में, छात्रों में तथा नजदीक के मुहल्ले में सर्वोदय के साहित्य तथा पत्रिकाओं का प्रचार करें ।

(६) निवृत्त तथा विचार प्रतियोगिता रखी जाय ।

(७) शुभो-शोपणीवाले क्षेत्रों से मुलावात और सम्पर्क किया जाय तथा वहाँ की आवश्यकतानुसार कार्यक्रम रखा जाय ।

(८) अपनी सस्था के शिक्षकों तथा छात्रों को आचार्यकुल तथा तरुण शान्तिसेना के सदस्य बनाइए ।

(९) सस्था के किसी हॉल या कमरे में साहित्य चित्र प्रदर्शनी लगाइए ।

(१०) स्वदेशी प्रेम के रूप में प्रामोद्योग के द्वारा बनी चीजें तथा शादी आदि की खरीदों को प्रोत्साहन दिया जाय । और सादा जीवन तथा सात्विक आहार पर जोर दिया जाय ।

(११) प्रातः स्कूल या थालेज के प्रारम्भ के समय रोज ५-१० मिनट का सामूहिक स्वाभ्यास (एक पड़े, सब सुनें) का कार्यक्रम रखा जाय ।

ये कार्यक्रम ११ सितम्बर और २ अक्टूबर के बीच २० दिन के पूरे सर्वोदय पर्व में भी चलाये जा सकते हैं । और इनमें से कुछ स्थायी रूप से आगे भी जारी रखे जा सकते हैं ।

११ सितम्बर से २ अक्टूबर के दरम्यान आप जो भी कार्यक्रम आयोजित करें उसमें कहीं हमारी सहायता या सहभागिता की आवश्यकता हो तो हमें आपकी सेवा करने में आनन्द होगा ।

गांधीजी तथा सर्वोदय की सुन्दर पुस्तकें, आचार्यकुल तथा तरुण शान्तिसेना के पत्रें तथा फाग, प्रदर्शनी और अन्य बातों की सारी जानकारी आपको भी बस एक ब्यास, समोजक दिल्ली प्रदेश सर्वोदय मण्डल, सन्त समागम, २४ पार्क एरिया, करोलबाग, नयी दिल्ली-५ (फोन ५६३४७९) से प्राप्त होगी ।

(डा० सीताकृष्ण नम्बियार) (प्रेमछाल गोविल) (प्रेमराज शर्मा)

संयोजक

कार्याधिकारी

सह संयोजक

दिल्ली प्रदेश आचार्यकुल

राष्ट्रीय सेवा योजना

दिल्ली प्रदेश आचार्यकुल

दिल्ली विश्वविद्यालय



दैनन्दिनी

सन् १९७३ की दैनन्दिनी शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रही है। इस दैनन्दिनी में आप लोगों से समय-समय पर मिलनेवाले सुझावों का यथासम्भव समावेश किया गया है। इस बार के मुख्य परिवर्तन निम्न प्रकार हैं :

● हर माह के अन्त में एक कोरा पृष्ठ छोड़ा गया है। दैनन्दिनी के अन्त में ४ पृष्ठ सादे दिये गये हैं। कुल मिलाकर गत वर्षों को अपेक्षा १९७३ की दैनन्दिनी में १६ पृष्ठ अतिरिक्त जोड़ा गया है, फिर भी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अन्य विशेषताएँ

● प्लास्टिक का मुरुचिपूर्ण चित्ताकर्षक कवर। रूलदार पृष्ठ, सर्व सेवा संप और सर्वोदय आन्दोलन में लगी संस्थाओं, पत्र-पत्रिकाओं एवं अन्य प्रवृत्तियों की अद्यतन जानकारी। डाकवार विषयक जानकारी, सरकारी छुट्टियों की सूची और मासिक वेतन चार्ट।

साइज

माप

कीमत

क्राउन १८॥ सें०मी० × १२॥ सें०मी ४ रुपया प्रति

डिमाई २१॥ सें०मी० × १४ सें०मी० ५ रुपया प्रति

भाषा के नियम

● बिक्रेताओं को २५ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। एक साथ ५० या अधिक दैनन्दिनी मंगाने पर ग्राहक के निकटतम स्टेशन तक फ्री पहुँच भेजवायी जाती है। ५० से कम सख्या में दैनन्दिनी मँगाने पर पैकिंग, पोस्टेज और रेल महसूल का खर्च ग्राहक को वहन करना पड़ता है। भेजवायी गयी दैनन्दिनी वापस नहीं ली जाती। दैनन्दिनी को बिक्री पूर्णतया नकद, बी० पी० या बैंक के माफ़ेत रखी गयी है। आर्डर भेजवाते समय अपना नाम, पता और निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम सुवाच्य अक्षरों में लिखिए और यह स्पष्ट निर्देश दीजिए कि मँगायी गयी दैनन्दिनी के लिए आप रकम अग्रिम ड्राफ्ट द्वारा भेजवा रहे हैं या चिल्टी, बी० पी० या बैंक के द्वारा भेजवा दी जाय।

सर्व सेवा संप प्रकाशन, राजवाट, वाराणसी-१

सम्पादक मण्डल :

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

आचार्य राममूर्ति

घर : २६

अंश : २

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश की प्रारम्भिक शिक्षा का

सरकारीकरण

४९ सम्पादकीय

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम १९७२

५६

गांधी और विनोबा

६१ श्री बनारसीदास जगुर्वेदी

जीवन की बुनियादें

६७ गुणो मार्जरी साईक्स

स्कूल में सकलता के मार्ग में दस बाधाएँ

७४ श्री हरी पैसे

बेकोस्तोवाजिया के नर्सरी स्कूल

८२ जैन पेस्टल

शिक्षक और अभिभावक सहयोग की

आवश्यकता

८६ श्री सम्पुर्ण

आचार्यकुल गतिविधि

९१

सितम्बर, १७२

● 'नयी तालीम' का वर्ष जगस्त से प्रारम्भ होता है ।

● 'नयी तालीम' का वार्षिक खन्दा माठ रुपये है और एक अंक के ७० पैसे ।

● पत्र व्यवहार करते समय प्राहक अपनी प्राहक-सख्या का उल्लेख अवश्य करें ।

● रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट द्वारा सर्वे सेवा सब के लिए प्रकाशित;

बनुपम प्रेस, के २५/३० इमर्षाट, वाराणसी में मुद्रित

नयी तात्वीम : सितम्बर, '७२

पहिले से डाक-व्यय दिये बिना भेजने की स्वीकृति प्राप्त

साइसेंस नं० ४६

रजि० सं० एस० १७२३

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन सेवाग्राम

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन दिनांक १४, १५ और १६ अक्टूबर १९७२ को नयी तात्वीम समिति (सर्व सेवा संघ) और वर्षा शिक्षा मंडल के संयुक्त तत्वावधान में सेवाग्राम, वर्षा (महाराष्ट्र) में किया जा रहा है ।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने १४ अक्टूबर को ११-३० बजे इस सम्मेलन का उद्घाटन करना स्वीकार किया है । सम्मेलन के समय में आचार्य विनोबा भावे के भी शैक्षणिक विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा । केन्द्र के शिक्षा मंत्री, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, अधिकांश उप-कुलपतियों, प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों, गण्यमान्य सर्वोदय विचारकों एवं बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में काम करनेवाले प्रमुख कार्यकर्ताओं को इस सम्मेलन में भाग लेने और चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया है । इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्राश्मरी स्तर में लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में आपूर्ण परिवर्तन करने के बारे में विचार-विमर्श करना है, जिससे इसे राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप अधिक उद्देश्यपूर्ण और उत्तरदायी बनाया जा सके ।

सम्मेलन का कार्यक्रम प्रायः निम्न प्रकार में रहेगा :

१४ अक्टूबर	११-३०	उद्घाटन समारोह
	१-०० दोपहर	प्रथम अधिवेशन
	६-१० सायं	विचारणीय विषयों पर चर्चा
	८-३० रात्रि	आश्रम प्राचरणा (प्रतिदिन)
१५ अक्टूबर	सुबह	सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं शैक्षणिक फिल्मों का प्रतिनिधिगणों का आचार्य विनोबा भावे ने मिलना ।
	११-०० दोपहर	द्वितीय अधिवेशन-चर्चा
	८-१० रात्रि	तृतीय अधिवेशन-चर्चा
१६ अक्टूबर	८-१० सुबह	अंतिम अधिवेशन
		निवेदन का प्रस्तुतीकरण, वर्षा
		श्रीमन्नारायणजी का अध्यक्षीय भाषण, धन्यवाद आपन

इस सम्मेलन में भाग लेनेवाले लोगों से निवेदन है कि वे अपने पहुँचने और यदि कुछ विशेष अपेक्षा हो, तो उससे, मंत्री को अवगत कराने की कृपा करें ।

के० एस० आचार्य
मंत्री, नयी तात्वीम समिति
सेवाग्राम, वर्षा (महाराष्ट्र)

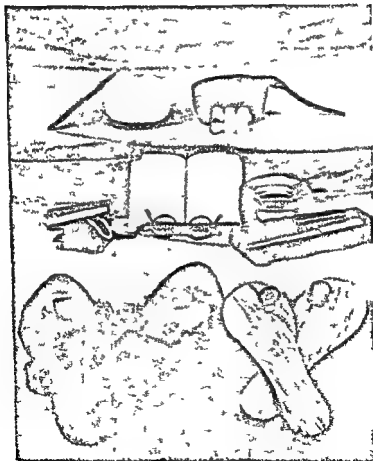
नयी तालीम

एन. टी. एन. का मासिक पत्र

वर्ष २१

अंक ३

अक्टूबर, १९७२



बापू कुटी (सेवाग्राम) में स्मृति क चिह्न

३२०० करोड़ रुपये की शिक्षा- योजना

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने पाँचवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर व्यय के लिए षत्सीस सौ करोड़ रुपये के प्राविधान की माँग की है। (इतना धन मिलेगा नहीं, यह बात दूसरी है।) इसमें से सोलह सौ करोड़ रुपये प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय किये जायेंगे। ६ से १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देना संविधान का लक्ष्य था और यह आशा की गयी थी कि १९६५ तक यह लक्ष्य पूरा कर लिया जायगा। परन्तु ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों के लिए भी अभी प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ नहीं हुई है। इसीलिए सितम्बर १९७२ की बैठक में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की ३२०० करोड़ रुपये की योजना स्वीकार करते हुए राज्यों से यह अपील की है (राज्यों से इसलिए कि शिक्षा राज्य का विषय है) कि वे १९७५-७६ तक ६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करें, और १४ वर्ष की आयु तक की शिक्षा का लक्ष्य पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् १९७८-७९ तक अवश्य पूरा कर लें। गणतंत्र में प्रारम्भिक शिक्षा भोजन, जल और आवास की भाँति नागरिक की न्यूनतम आवश्यकता है, अतः संविधान के इस लक्ष्य को पूरा करने को पाँचवी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी जाय।

परन्तु यक्ष प्रश्न यह है कि क्या पाँचवी पंचव-

वर्ष : २१

अंक : ३

पाँच योजना तक यह लक्ष्य पूरा हो सकेगा ? जो बात कही गयी है वही दूसरी, तीसरी और चौथी योजनाओं के आरम्भ में भी इतनी ही आतुरता के साथ कही गयी थी, परन्तु लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ । और आज जब फिर केन्द्रीय मंत्री इस सकल्प को दोहरा रहे थे तो केन्द्रीय परिषद् की बैठक में ही विशेषज्ञों ने शका प्रकट की कि सम्भवतः पाँचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भी यह लक्ष्य पूरा नहीं होगा । देश में चार राज्य ऐसे हैं—राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, जिनमें यह लक्ष्य पूरा होता दिखाई नहीं देता । इन राज्यों में, जिनमें आदिवासियों की संख्या पर्याप्त है, स्कूल न जानेवाले लड़कों का प्रतिशत ७६ है, जो पूरे देश के ६ से १४ वर्ष की आयुवाले बच्चों का ५६ प्रतिशत है । इसीलिए विशेषज्ञों ने यह शका की है कि सम्भवतः पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भी हमारा सवैधानिक लक्ष्य पूरा न हो ।

आखिर ऐसा हुआ क्यों है ? हम १९५० के बाद किये गये अपने शिक्षा प्रसार के प्रयासों का विश्लेषण करें तो निम्नांकित बातें देखते हैं:

(१) १९५०-५८ में (देश के स्वतंत्रता वर्ष में) देश में कुल १५० लाख प्रारम्भिक स्कूल, ४,००० हाई स्कूल, और १,००० उच्च शिक्षा के विद्यालय थे । शिक्षा-प्रसार के फलस्वरूप १९७०-७२ में देश में ५ लाख प्रारम्भिक स्कूल, ३५,००० हाई स्कूल, और ४,५०० उच्च शिक्षा की संस्थाएँ हो गयी हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि स्वातंत्र्योत्तर काल में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आठ गुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है, जब कि प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में यह वृद्धि चार गुनी से भी कम हुई है । अगर १९७८-७९ तक यानी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमें ६ से १४ वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का प्राविधान करना होगा, तो हमको १४.२१ करोड़ बच्चों को स्कूल में लाने की व्यवस्था करनी होगी । अब हम अगर एक प्रारम्भिक स्कूल में औसत संख्या २०० की भी मान लें तो हमें ५ वर्षों में ७ लाख प्रारम्भिक स्कूल खोलने होंगे । हम आशा करते हैं कि इतने स्कूलों को खोलने का प्राविधान योजना में होगा । प्राविधान का अर्थ है राज्यों को 'मैचिंग ग्राण्ट' देने का प्राविधान । परन्तु अनुभव यह है कि सभी राज्य केन्द्र से 'मैचिंग

ग्राण्ट' लेकर योजनाओं को प्रारम्भ नहीं करते। ग्राण्ट लेते भी हैं तो उसका पूर्ण उपयोग नहीं करते। पहले भी यह हुआ है और अब भी होगा। कुछ राज्य ऐसे होंगे जो अपने को मैचिंग ग्राण्ट लेने की अनुमूल परिस्थिति में ही नहीं पा सकेंगे। कश्ने का तात्पर्य यह है कि धावजूद केन्द्र को योजना के भी राज्य उतने प्रारम्भिक स्कूल न खोल सकेंगे, नितने स्कूलों की आवश्यकता प्रारम्भिक शिक्षा का अनिवार्य बनाने के लिए होगी। परिणाम निश्चय ही वही होनेवाला है जो पहले हुआ था। यानी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भी प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का सैमानिक लक्ष्य पूरा नहीं होगा।

(२) योजना के विश्लेषण से दूसरा तथ्य यह प्राप्त होता है कि प्रारम्भिक कक्षा के गुणात्मक पक्ष पर अपेक्षाकृत बहुत कम धन खर्च करने का प्रावधान है। शिक्षा के गुणात्मक पक्ष में सुधार अभी सम्भव होगा जब योजना को चलाने के लिए जहाँ एक ओर योग्य शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, वहाँ दूसरी ओर शिष्य विज्ञान आदि विषयों के वैज्ञानिक और पूर्ण शिक्षण के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। परन्तु १६०० करोड़ रुपये में से इस मद पर कुल १७० करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसका अर्थ केवल इतना होगा कि अप्रशिक्षित अधकचरे ज्ञान वाले शिक्षक अपर्याप्त साधनों से शिष्ट अथवा विज्ञान का दूषित शिक्षण करेंगे, जिससे त्रिवार्षिकों का ही अहित नहीं होगा, देश का धन भी बर्बाद होगा। बेसिक शिक्षा जिन राज्यों में असफल हुई, उसका असफलता के मुख्य दो ही कारण थे—प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और पर्याप्त साधन का अभाव। अगर ये दोनों कारण अब भी बने रहे, तो जिस 'कायानुभव' की प्रारम्भिक शिक्षा का अभिन्न अंग बनाकर योजना बनायी जा रही है वह भी असफल होगी और छात्र केवल फोरी साक्षरता प्राप्त कर सकेंगे, जिसका आज की परिस्थिति में, जब प्रत्येक नागरिक से उत्पादक इकाई होने की आशा की जा रही है, बहुत अधिक मूल्य नहीं है।

(३) तीसरी महत्त्व की बात यह है कि अगर इस प्रकार के स्कूल खुले भी तो उनके लिए कोई आकर्षण गॉज की उस गरीब जनता में नहीं होगा, नितके बच्चे उनकी कमाई में चार पैसे का योगदान करते हैं, चाहे गांव में चराकर, चाहे अपने माँ बाप की खेत खलिहान में

सहायता करके, चाहे घर पर रहकर अपने छोटे भाई-पढ़नों की देख-भाल करके। हमारे देश की योजना बनानेवाले यह क्यों नहीं सोचते कि स्कूल खोल देने से ही इस तथ्यके के लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। हमारे शिक्षा शास्त्री और योजना बनानेवाले ये क्यों नहीं समझते कि इन लोगों के लिए तो शिक्षा की ऐसी योजना बनानी पड़ेगी, जिसमें लड़के पढ़ने के साथ कुछ पैदा भी कर सकें। वैसिक शिक्षा एक ऐसी ही शिक्षा-पद्धति है। और कोठारी कमिशन द्वारा संस्तुत 'कार्यानुभव' की पद्धति भी अगर ईमानदारी के साथ पर्याप्त ध्यान दी जाये, तो इस प्रकार की पद्धति में विकसित हो सकती है। परन्तु हम कैसे मान लें कि योजना बनानेवालों की दृष्टि साफ है, जब हम यह देखते हैं कि जिन तत्वों से प्रारम्भिक शिक्षा का गुणात्मक विकास होगा उन पर योजना में इतना कम खर्च करने का प्राविधान किया गया है।

अतः बार-बार दोहराने के बावजूद एक बार और कहना पड़ रहा है कि जैसे सड़े गले आज के प्रारम्भिक स्कूल हैं, उनकी संख्या में वृद्धि मात्र करने से देश की किसी समस्या का हल नहीं होगा—न उनमें बेहतरों और शहरों के भी गरीब तबकों के बच्चे—पढ़ने जायेंगे और न उनमें शिक्षा पानेवाले लड़के इस योग्य हो सकेंगे कि अपनी प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जीवन में प्रवेश करके कुछ काम करने के साथ 'पार्ट टाइम' शिक्षा लेकर अपनी शिक्षा को पूरी कर सकेंगे। जैसी कल्पना इस योजना के बनानेवालों ने की है और जिस 'पार्ट टाइम' शिक्षा के लिए पर्याप्त धन का प्राविधान किया है, जिस 'मल्टीपुल एण्ट्री' के लिए इस योजना की इतनी प्रशंसा की जा रही है वह बेकार हो जायेगी। जब प्रारम्भिक शिक्षा—शिक्षा पानेवालों को किसी कौशल की ही शिक्षा नहीं देती, केवल साक्षरता ही सिखा रही है, तो 'मल्टीपुल एण्ट्री' यानी विभिन्न पेशों में प्रवेश करने की बात करना व्यर्थ है।

अतः आवश्यकता तीन बातों को समझ लेने की है : (१) प्रथम यह कि जैसे आज के प्रारम्भिक स्कूल हैं, वैसे स्कूलों को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे अच्छा होगा कि संविधान का लक्ष्य पूरा न हो।

(२) दूसरा यह जो भी प्रारम्भिक स्कूल खुलें, उनमें पढ़ने लिखने

के साथ वैज्ञानिक ढंग से समाजोपयोगी उत्पादक काम सिराने का प्रयत्न हो, और

(३) तीसरा यह कि दूर के गाँवों में, आदिवासी क्षेत्रों में और नगरों में जिन्हें 'स्लमएरिया' कहते हैं, उनमें दो दो तीन तीन घण्टों के स्कूल खोले जायँ, जहाँ लड़के जो काम कर रहे हैं उन्हें करते हुए भी आकर पढ़ सकें और कुछ उपयोगी धन्य सीख सकें। पूज्य धीरेन्द्र भाई कहते हैं, "हमारे योजनागारों को भैंस की पीठ पर स्कूल खोलने की योजना बनानी होगी।"

— वशीधर श्रीवास्तव

शिक्षा का माध्यम

यह स्वयंसिद्ध बात है कि जब तक किसी देश के नीचवान ऐसी भाषा में शिक्षा पाकर उसे पढ़ा न लें, जिसे जनता समझ सके, तब तक वे अपनी देश की जनता के साथ न तो जोता जागता सम्बन्ध पैदा कर सकते हैं और न उसे कायम रख सकते हैं।

मेरा विश्वास है कि राष्ट्र के जो बालक अपनी मातृभाषा के बजाय दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं वे आत्महत्या ही करते हैं। विदेशी माध्यम से बालकों पर अनावश्यक जोर पड़ता है। वह उनकी सारी मौलिकता का नाश कर देता है। विदेशी भाषा के माध्यम से उनका विकास रुक जाता है और वे अपने घर और परिवार से अलग पड़ जाते हैं। इसलिए मैं इस चीज को पहले दर्जे का राष्ट्रीय सबूत मानता हूँ।

अगर मेरे हाथों में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से ही विदेशी भाषा के माध्यम से अपने लड़के और लड़कियों की शिक्षा बन्द कर दूँ, और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरन्त बदलवा दूँ या उन्हें बरखास्त कर दूँ। मैं पाठ्यपुस्तकों की टीमारो का इन्तजार नहीं करूँगा। वे माध्यम के परिवर्तन के पीछे पीछे चली आयेगी। यह एक ऐसी बुझई है जिसका तुरन्त इलाज होना चाहिए। ...

— मो० क० गांधी

(शिक्षा का माध्यम पृष्ठ, १० से ११ तक)

शिक्षा की संरचना

मैं इस ख्याल का हूँ कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों शिक्षाओं को मिला दिया जाय। प्राथमिक शिक्षा की जो दावत आज है, मैंन उसे गाँवों में देना है और इधर तो मैं एन गाँव में ही रहने लगा हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हम देहातो को कुछ देना चाहते हैं तो जरूरी है कि सेमेण्डरी तालीम को प्राइमरी के साथ मिला दिया जाय। मेरा ख्याल है कि आजकल देहाती मंदिरों में लड़कों को जो कुछ पढ़ाया जाता है उससे देहातवालों का नुबसान ही होता है। जो लड़के स्कूल आते हैं उनमें से अधिकतर या तो चहरी बन जाते हैं या गाँव के प्रति अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। इसीलिए मैं अपने अर्थ तक के अनुभव से यह कह सकता हूँ कि हमारी मौजूदा प्राइमरी तालीम से गाँववालों को फायदा नहीं पहुँचता। तो सवाल होता है कि इस प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप क्या हो? मेरा तो जवाब यह है कि किसी उद्योग या दस्तकारी की बीघ में रखकर उसके जरिए ही सारी शिक्षा दी जाय। लड़कों को जो कुछ भी सिखाया जाय वह सब किसी न किसी उद्योग या दस्तकारी के जरिए ही सिखाया जाय। आप कह सकते हैं कि मध्ययुग में हमारे यहाँ लड़कों को सिर्फ घंघे ही सिखाये जाते थे। मैं मानता हूँ लेकिन उन दिनों घंघे के जरिए तालीम देने की बात लोगों के सामने नहीं थी। घंघा सिर्फ घंघे के ख्याल से सिखाया जाता था। हम घंघे या दस्तकारी के माध्यम में दिमाग को भी आला बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरी दूर ख्वास्त यह है कि हम सिर्फ उद्योग या दस्तकारी ही न सिखायें, बल्कि इनके जरिए बच्चों को सारी तालीम दें।

इस प्राथमिक शिक्षा को मैं सबसे अधिक महत्त्व देता हूँ। मेरे विचार में यह शिक्षा अपजी की छोड़कर और विषयों में आजकल की मैट्रिक तक होनी चाहिए। अगर कालेज के सब ग्रेजुएट अपना पढ़ना लिखना एकाएक भूल जायें तो इन लासों ग्रेजुएटों की माददास्त के एकाएक बेकार हो जाने से देश का जो नुकसान हो उसे एक पलट में रीखिए और दूसरे में उस नुकसान को रीखिए जो फरीडो स्त्री-पुरुषों को अज्ञाना प्रकार में धिरे रहन से हो रहा है।

हरिजन ११ सितम्बर '३९

—मो० क० गांधी

शोषणरहित बुनियादी तालीम

[ता. २५-१-७० को बारदोली (गुजरात) चत्रविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर दिया हुआ मंगल प्रवचन, मूल गुजराती से अनूदित ।-सम्पादक ।]

हमने समाज के विभाग बनाये, जातियाँ तैयार की, वर्णव्यवस्था की आजमा कर देखा। आजकल 'धनी और गरीब', 'शिक्षित और अशिक्षित', ऐसे कितने ही विभाग करते हैं। परन्तु प्रत्यक्ष व्यवहार में दो मुख्य वर्ग देखने में आते हैं। उनके कारण उत्पन्न समस्याओं को यदि हम हल कर सकें तो बहुत से सवाल हल हो जायेंगे।

वे वर्ग कौन से हैं ? एक है श्रमजीवी और दूसरा है परिश्रम, धारो-श्रम टालनेवाला। मनुष्य शिक्षा चाहता है, सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्न करता है। उसमें सांस्कृतिक लाभ होता होगा। परन्तु मनुष्य का मुख्य प्रयत्न एक ही रहता है—“श्रमजीवी वर्ग में शामिल न होना पड़े, श्रम टालकर, श्रमजीवी लोगों की सेवा प्राप्त कर बिना श्रमजीवी वर्ग में शामिल होना।”

एक दिन एक बुढ़ा अपने पोते को जरा बाराजी से परन्तु खूब प्रेम और धृष्टा से समझा रहा था : “कमबख्तो ! वक्त है सब सब चार शब्द सीख लो। बरना सारी जिन्दगी मेंहनत मजदूरी करनी पड़गी।” उस बुढ़े ने समाज-जीवन की केन्द्रीय बात पकड़ी थी। ‘चार शब्द सीखिये’, लिखना-पढ़ना सीखोगे तो बानून से लेकर मुहम्मद तक का और बकील से लेकर देश के नेताओं तक का कोई भी स्थान या सकोगे और हाथ से परिश्रम करने की तकलीफ से बच जाओगे। किसी के बूट साफ करने की अपमान भरी स्थिति भुगतनी नहीं पड़ेगी।

निर्दिष्ट लोग अनक प्रवृत्तियाँ करते हैं तरह तरह के काम करते हैं, खदान चलाते हैं, कलम चलाते हैं, सस्थाएँ और कारखाने चले रहते हैं। व बेकार नहीं बैठते। परन्तु उन्हें हाथ से परिश्रम नहीं करना पड़ता।

यही वस्तु अपन ढंग से समझाते हुए मैं कहता हूँ, 'मनुष्य धार शब्द सीख तो उसे हाथ में कलम लेकर तीन ऊँगलियों से ही काम लेना पड़ता है। धमजीवी को दसों ऊँगलियों को काम में लाना पड़ता है। वह चाहे हल चलाये, घास काट, बरतन साँज या रवा चलाये दस ऊँगलियाँ काम में लानी ही पड़ती हैं।

पढ़ा लिखा आदमी तीन ऊँगलियों से लिखेगा अथवा हिमाव करेगा। उसका प्रारम्भ अक और लिपि सीखने से होता है। छुटपन में हमारी पढ़ाई का प्रारम्भ 'अकलिपि नाम की किताब से होता था। हम उसे अकल्पी कहते थे। परन्तु उसका उद्देश्य तो दस ऊँगलियों के दस हाथों से धम करम की महत्तम डालन का ही होता है।

परिणाम यह हुआ कि दस ऊँगलियोंवाली महत्तम मजदूरी करनेवालों को विद्या कला न मिली। उनके श्रम-जीवन में बुद्धि उन्नति और प्रगति का लड़लगा भी नहीं मिलता। बुद्धिवाल सार शोषक और धमजीवी सारे जड़ अनरिक्शन खादी और गोपित एसी समाज रचना हुई।

ऐसा भेद समाज में जब तक बना रहेगा तब तक उच्च नीच का भाव, शोषण अत्याचार और अत्याचार समाज में रह्य ही। लड़कर, राज्य व्यवस्था में क्रांति करके अथवा असहयोग का शस्त्र चलाकर शोषणरहित समानतामूलक समाज हम कायम नहीं कर सकेंगे इस नियम पर पहुँचकर गांधीजी ने सर्वांगीण सावर्भौमिक क्रांति के प्रारम्भ में—बुनियाद में क्रांतिकारी शिक्षा का उपाय बताया जिसके अन्तर अक लिपिवाली विद्या ग्रहण करने के साधन के रूप में ही कुशल रचनात्मक, समाजोपयोगी उत्पादक परिश्रम को स्वीकार किया। ऐसे रचनात्मक परिश्रम के द्वारा गान प्राप्त कीजिए और उसे परिश्रम के साथ अनुबन्ध के रूप में अधरपान और अकी का ज्ञान दाजिए।

एसी बुनियादी शिक्षा का पुरस्कार करते हुए मैं एक बार स्पष्ट किया कि आज शिक्षा लेनेवाले तमाम वर्गों को और जातियों को परिश्रम की दीक्षा देंगे जिससे उनका जीवन निष्पाप हो और उसकी एकागिता मिले। शोषक का जीवन जीने का आदी य वग यदि समय पर बुनियादी शिक्षा को स्वीकार नहीं करेंगे तो मानकर चुप नहीं बैठेंगे। हम उन्हें उनके नसीब पर छोड़कर धमजीवी लोगो के पास जायेंगे और कहेंगे कि धम जीवन के द्वारा आप लोग निष्पाप

रह सके हैं। उस धर्म-जीवन का न छोकर आपके हुनर-उद्योगों की मार्फत ही हम आपकी अनुबन्ध के रूप में सामान्य विद्या-कलाओं की शिक्षा देने और आपके वर्ग का सर्वांगीण जीवन विकसित कर उस शोषक वर्ग को ही असहाय स्थिति में रख देंगे। 'निवारण से नहीं मानव को हारने से मानते' ऐसा अनुभव उन्हें करवे देंगे। आश्रम और विद्यापीठ में मेरे परिचय में आकर प्रेरणा पानेवाले श्री मोहन परीश बहुत दिनों से बुनियादी शिक्षा के इस दूसरे भाग का प्रयोग यहाँ बैठे कर रहे हैं। उन्होंने एक सुबह छपाखाना खोला है। उसमें श्रेष्ठ विषय सब काम सुबहपूर्व होगा हो। परन्तु उनका प्रधान उद्देश्य केवल छपाखाना चलाने का नहीं है, परन्तु उससे द्वारा धर्मजीवी वर्ग को अनुबन्ध के तौर पर छोटी-बड़ी विद्या कलाएँ सिखाने का है।

सुबह छपाखाना तो समन्वय का केवल साधन है। बुनियादी शिक्षा का प्रारम्भ तो चार प्रकार के सार्वभौम उद्योगों से हो हो सकता है। (१) खेती (अन्न निर्माण) (२) वस्त्र विद्या, (३) रहने के लिए भौतिक या आलीशान मकान बनाने की कला, और (४) इन तीनों उद्योगों के लिए जरूरी औजार का निर्माण। अन्न, वस्त्र, निवास और औजार इन चार के सिद्धांत से प्रारम्भ करके उसके अनुबन्ध में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा छाप-छाप देते के प्रयास का प्रारम्भ होगा।

और वही काम उसी इन से बड़े पैमाने पर चलाकर गांधी विद्यापीठ शोषक वर्ग को निष्पाप बनाने की कला सिखायगा। यह है बुनियादी शिक्षा का हुन और उसका कार्यक्रम। इसी के लिए गांधी विद्यापीठ की स्थापना हुई है। गांधीजी के विचार जिन्हें जँच गये हैं ऐसे हम तीन आपके सामने रखे हैं। गांधी विद्यापीठ का कुलपति मैं, चालीस वर्ष आदिवासियों के बीच अस्सन्न निष्ठा से काम करनेवाले श्री जुगतराम भाई दवे उपकुलपति हैं, और आश्रम में तथा गुजरात विद्यापीठ में जिन्होंने मुझे बड़ा कीमती साध दिया उन स्वर्गीय श्री नरहरिभाई परीश के स्वतंत्र मित्राज के विरजीव मोहन परीश विद्यालय के उपप्रमुख हैं। हम यहाँ शोषण-रहित, निष्पाप, सम्पूर्ण, समृद्ध जीवन की नींव डालनेवाली शिक्षा को लेकर बैठे हैं। इसमें मेरा हिस्सा केवल बुजुर्गों के तौर पर प्रेरणा, योजना, सूचना और सलाह देने का है और साथ ही सारी प्रवृत्ति को आगेवाँद देने का है। बाकी तो सर्वोपेक्ष के आदर्श को वरण करनेवाला, शोषणरहित सादा जीवन जीनेवाले शिक्षा-शास्त्रियों की यह प्रवृत्ति है। इसमें पुरातनकाल से चले आनेवाले अज-धर्म-जीवन को जरा भी स्थान नहीं है। परिश्रम तो करना ही है। परन्तु वह परिश्रम दिन

प्रतिदिन ज्यादा सुकर करने के लिए अच्छे अच्छे वैज्ञानिक औजार तैयार करेंगे । यहाँ कोई इजाद होगी वह सर्वोदयवृत्ति से प्रेरित होगी । यहाँ का अंगरक्षक, हिंसा का ज्ञान और साहित्य का अनुशीलन बहुमत के पोषण के लिए नहीं, परन्तु समस्त मानव परिवार के पोषण के लिए होगा ।

रक्षण के लिए छातिसेना, पोषण के लिए बुनियादी तालीम के साथ पेटो और उद्योग-दुर्गर, उत्कृष्ट के लिए तेजस्वी गढ़ाई और शोध-शोध एव वर्ग-विग्रह टालने के लिए द्वेषरहित सामाजिक साम्ययोगी सहयोग का जीवन सिखानेवाला सर्वोदय का आदर्श यह है हमारी योजना । अहिंसा प्रेरित क्षान्ति-साधक इस सर्वोदयी योजना की हमारी प्रार्थना के साथ इस विद्यालय का उद्घाटन (यानी उसका मंगलारम्भ) जाहिर करता हूँ ।

ॐ सह नौ भवतु ।

सह नौ भुनक्तु ।

सह वीर्यं करवावहे ।

तेजस्वि नौ अपीतम् अस्तु ।

मा विट्प्रियावहे ॥

ॐ क्षान्तिं क्षान्तिं क्षान्तिं ॥



चाराणमी के शिक्षकों के बीच जे० पी०

[साधना केन्द्र, चाराणमी में चाराणमी के आचार्यकुल के सदस्यों के साथ तय्यकाशजी की हुई चर्चा यहाँ दी जा रही है।—स०]



प्रारम्भ में आचार्य-कुल के सदस्यों का, जिनमें प्रमुख सर्वश्री रघुकुल तिलक, रोहित मेहता अनंतरामनजी, रावश्याम शर्मा, श्रीमती शुभदा सैलंग और श्रीमती लीला शर्मा आदि थे, परिषद जय-प्रकाशबाबू से कराया गया। चर्चा का रूप प्रमुखतः बातचीत का ही रहा। श्री रोहित मेहता ने पूछा—

जे०पी० जन्म दिन (विजयादशमी) पर हमारी शुभ कामनाएँ कारोकरण की आवाज जोर पकड़ रही है। इन दोनों में दोष है। इन दोनों से कैसे बचा जाय ?”

जे० पी० मैं गिला का विरोध नहीं हूँ, यह प्रश्न भी गम्भीर है। बिनो-बाजी न इसलिए आचार्यकुल की बात रखी है। वह एक ओर आचार्यों के पदस्थ की जागृति और आचारनिष्ठता की बात करते हैं तो दूसरी ओर शिक्षा को शासन-मुक्त रखकर आचार्यों के हाथ में शिक्षा को रखने की बात कहते हैं। शिक्षा को जैसे सरकार से मुक्त रखना है वैसे मैनेजरों से भी। आज देश में जो नया ट्रेण्ड है उससे शिक्षक की ऐकेडमिक स्वतंत्रता पर अकुश सगेगा। वह घातनीय नहीं है। इसे रोकने के लिए शिक्षकों को अपनी स्वतंत्र आवाज बुलन्द करनी चाहिए। आज

शिक्षकों छात्रों और अभिभावकों के चरित्र का पतन हो गया है। सब मिलकर नकल करते-करवाते हैं। फिर अगर परीक्षा और नौकरी का सम्बन्ध विच्छेद किया जाय तो शिक्षा में एक क्रान्ति होगी।

सबसे पहला काम यह करना होगा कि आचार्यों को दलगत राजनीति से अलग हाना होगा। यही विनोबा ने आचार्यकुल में कहा है। छात्रों को दलगत राजनीति से अलग रहना चाहिए। फिर दोनों साथ बैठकर सोचें और कोई रास्ता निचालें। अभिभावकों का भी साथ लें।

श्री रघुकुल तिलक जे० पी० के इस कथन का मैं समर्थन करता हूँ कि परीक्षा के प्रमाण-पत्र को नौकरी से विच्छिन्न किया जाय। गौहरी देनेवाले अपनी परीक्षाएँ स्वयं ले लें और किसी प्रमाण पत्र की माँग न करें। मैं जब रेलवे बोर्ड में था तब मैं डिपाटमण्टल परीक्षा ली और परीक्षा देनेवालों पर तृतीय श्रेणी के अभ्यासी परीक्षा न दें—यह बचन हटा दिया था, और तब प्रतिशोषिता में बड़े बर्गस के विद्यार्थी भी आये थे और आग चलकर नौकरी में अच्छा काम किया। वही प्रकार प्रमाण-पत्र का पूरा बचन ही हटा दिया जाय तो और अच्छा है। इससे नकल करने की प्रवृत्ति से बचा जा सकता है।

कुमारी सुभद्रा सैलंग : राजाजी ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति भी अपनी राय व्यक्त करते हैं उसका कोई असर नहीं होता। इसका क्या कारण है ?

जे० पी० : राजाजी एक पार्टीविशेष से जुड़ गये हैं। अतः विचारों को तटस्थ वृत्ति से नहीं देख पाते। वे तटस्थ होकर बात कहें तो आज से अधिक असर होगा। इसीलिए विनोबा ने आचार्यकुल के सदस्यों को पक्षमुक्त रहने की सलाह दी है।

इसके बाद जे० पी० ने मुाहरी के प्रयोग की जानकारी दी और कहा कि मैं इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि शिक्षा में परिवर्तन समाज के परिवर्तन के बिना नहीं होगा।

श्री राधेश्याम शर्मा सर्व सेवा सघ को एक छात्रों स्कूल चलाना चाहिए।

एक अन्य प्रश्न नयी तालीम दंग घर में क्यों नहीं चली ?

जे० पी० नयी तालीम नहीं चला। यह ठीक है, परन्तु इसका जो भी कारण रहा हो, एक कारण सच सच में नयी तालीमो सघ का विलयन था। परन्तु प्रधान कारण था नयी तालीम के वाटे-ट का पाठ्यक्रम में ईमानदारी से प्रयोग न करना। बेवस नाम बदला गया। स्कूल पुराने रहे—न उद्योग का यज्ञ-निर्वाण हुआ और न शिक्षा को जीवन से अनुश्रुति करने की चेष्टा हुई। ●

लोकात्मा के जागरूक प्रहरी: जयप्रकाश नारायण

[श्री जयप्रकाश नारायण ११ अक्टूबर, १९७२ को ॥० वर्ष के हुए । वे उसी दिन से एक वर्ष के लिए सार्वजनिक जीवन से अवकाश पर हैं । परन्तु चम्बल के भाग्य सम्पर्णकारी बागिया के कार्य में मार्गदर्शन देते रहने के लिए उन्होंने अपने सकलप में अपवाद माना है । दल और सत्ता की राजनीति से अलिप्त रहकर लोकात्मा के जागरूक प्रहरी के रूप में श्री जयप्रकाशबाबू देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं । देश के ऐसे अनिर्वाचित लोकमान्य नेता के मंगल स्वास्थ्य एवं दीर्घायुता की कामना करते हुए सुप्रसिद्ध विद्वान् भाचार्य दादा धर्माधिकारी का यह सारगर्भित—मौलिक लेख हम यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं ।

—सम्पदक]

श्री जयप्रकाश नारायण का व्यक्तित्व विभूतिकल्प है । ऐसा व्यक्तित्व, जिसमें विभूति के जनक आर्याम विद्यमान ह । अद्भुत रम्यता के साथ साथ उनके व्यक्तित्व में इन्द्र धनुष सी सुभावनी विविधता है । जयप्रकाश बाबू केवल जनता के बन्धी ही नहीं ह उस हृदय से भी आज हमारे देश में उनका व्यक्तित्व अद्वितीय ह । वे बसल निदनीय नागरिक ही नहीं हैं, अपितु निपक्ष लोकनिष्ठ व्यक्ति हैं । प्रचण्ड समूह या विशाल समुदाय के उपासक नहीं लोकात्मा के जागरूक प्रहरी हैं । इधर कुछ वर्षों से लोकात्मा और विश्वास के अभेद का साक्षात्कार प्रत्यक्ष लोक जीवन में करने की साधना उन्होंने की है । इसीलिए वे भारतीय नागरिक हैं, विश्व नागरिक हैं और विश्व मानव भी हैं । उनका निज देश अब भित्तिजग्यापी हो गया है । इसी कारण आज वे लोगो के अनिर्वाचित, स्वसिद्ध प्रतिनिध के रूप में मान जाते हैं । श्री बि ठामणराव देशमुख ने ठीक ही कहा था कि जयप्रकाशजी लोकात्मा के अभिभावक हैं । एमरसन ने कहा है कि जो बड़ होते हैं उनके विषय में हमारा गलतफहमी हुआ करती है । इस अर्थ में जयप्रकाशजी का व्यक्तित्व जितना विवादग्रस्त है, उतना ही मनोज भी है । उनका विपक्षी या शत्रु बिरला ही कोई होगा । अधिकतर विरोधियों की यही

आकांक्षा होती है कि यह हमारे साथ होता, तो अच्छा होता। इस विरोध में भी गमित प्रशंसा है। इस आलोचना में भी गौरव निहित है।

जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैंने उन्हें पहले पहल १९३३ या ३४ में नागपुर में श्री पी० वाइ० देशपाण्डे के यहाँ देखा। पहिली ही भेंट में प्रभावित करने वा गुण उनके व्यक्तित्व में थे। यों वे शास्त्रीय अर्थ में रूपवान नहीं हैं। लेकिन कुल मिलाकर उनके चेहरे में एक मधुरता है। एक सुभगता का भाव है। नीलोत्पल-वत्क्षमामवर्ण सरा सुभगता को बढ़ाता है। उसके बाद जब-जब खनसे मिलने का सुयोग हुआ, मेरे चित्त पर यह जो प्रथम प्रभाव पड़ा या वह दृढ़ होता गया। पी० वाइ० देशपाण्डे के यहाँ समाजवाद का विवेचन करते हुए उन्होंने जो विदलेपनात्मक भाषण किया उसमें उनकी प्रतिभा की झाकी मुझे दिखाई दी। अंग्रेजी में जिसे 'श्री पर्सेसिंग प्रेजेन्स' कहते हैं, उस तरह का कुछ प्रभाव उनकी पहिली ही भेंट में चित्त पर पड़ा।

वीर पुरुष के रूप में तो उन्हें इस देश के सभी लोग जानते और मानते हैं। स्वराज्य के सपना में सैनिक और सेनापति के रूप में जिस अतुल पराक्रम और साहसिकता का परिचय उन्होंने दिया, उसकी गाथा नीर-वास्य की तरह रोमाञ्चकारी और हृदयस्पर्शी है। परन्तु सच्चा वीर तो वह है, जिसका हृदय कठगापीड्यपूर्ण और अतएव नवनीतमृदुल होता है। जयप्रकाशजी के स्वभाव में ऐसी सरलता है, जो बट्टालों को भी भेद सकती है। प्रसंगानुसार उनमें आवेश और रोष भी आगूत होता है। लेकिन उसके मूल में कठगा की ही सहज प्रेरणा होती है। इसीलिए उसमें से प्रायः अशुभ परिणाम नहीं निकलते। बुद्धि और हृदय, ऋजुता और प्रांजलता का अद्भुत सामञ्जस्य उनके व्यक्तित्व में हुआ है। जिस समय जो सत्य देखते हैं उसे अपने सम्पूर्ण चित्त से ग्रहण कर लेते हैं। उसकी कार्य रूपा में परिणत करने के लिए प्राणवश से जुट जाते हैं। लेकिन दूसरे की बात समझने के लिए नित्य तत्पर रहते हैं। इसी का यह परिणाम है कि उनके व्यक्तित्व की कोई मतवाह, कोई सङ्गबाध, कोई सस्था या कोई सगठन अपनी सोमात्रों में बाँध नहीं सका है। वे पुरानी कांग्रेस में रहे, समाजवादी भी रहे और अब सर्वोदयी हैं। लेकिन उनका व्यक्तित्व इनमें से किसी विचारधारा से सीमित नहीं हो सका। आज भी वे सर्वोदय का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व उतना ही परिमित नहीं है। वे सर्वोदय के प्रतिनिधि हैं और अपने बहुत कुछ धर्म भी हैं। इसीलिए नये विचार को ग्रहण करने और पुराने विचारों की

मृत्युला तोड़ने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। उनके व्यक्तित्व की सजीवता का यह सबसे बड़ा प्रमाण है।

उनके एक गण्यमाय मित्र ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जयप्रकाश का जीवन खोपे हुए अवसरों की कहानी है। सच तो यह है कि वे कभी अवसरों की खाज में रहे ही नहीं। परिस्थिति में अवसर ही अवसर यदुच्छा से उपस्थित होते रह। उनसे अपने लिए लाभ उठाने की नीयत ही कभी पैदा नहीं हुई। ईसा ने कहा है, 'जो अपने जीवन का उत्सर्ग करता है उसी को जीवन की पर्याप्त म उपलब्धि होती है।' कुछ लोगो ने यह भी कहा है कि ज० पी० हमेशा 'बस चुकते गये।' इसी वृत्ति तो यह है, उन्होंने किसी 'बस' की प्रतीक्षा ही नहीं की। त्रिभुवन, कश्मीर, मंगलेश्वर, बागला देव, भारत पाकिस्तान सम्बंध आदि कई समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने केवल अपने प्राण ही सड़क में नहीं डाले, अपितु सारी प्रतिष्ठा और राजनैतिक जीवन को भी दाँव पर लगा दिया। जहाँ किसी प्रकार के स्वार्थ का भान हो नहीं, वहाँ अवसर खोने का भय भला कैसे हो सकता था ?

जयप्रकाशजी की पराक्रम-यात्रा जितनी उदात्त रही और मनोज्ञ है, उतनी ही उनकी विचार-यात्रा भी है। पराक्रम-यात्रा में क्रान्तिकारी जयप्रकाशजी की वृत्ति सशस्त्र क्रांति के माग का अनुसरण करने में जिस प्रकार कहीं कुण्ठित नहीं हुई, उसी प्रकार जब से उन्होंने शान्तिमय क्रांति की प्रक्रिया को बुद्धिपूर्वक अगा-कार किया, तब से उस मार्ग में उनकी भीरु वृत्ति की गति अकुण्ठित ही रही है। जब वे कश्मीर के मामले में और अकसाई चीन के मामले में लोकमत के प्रवाह के विरोध में अपना मत व्यक्त करने लगे, उस वक्त दिल्ली की एक सावजनिक सभा में कुछ लोगों ने उनको सबक सिखाना चाहा। उस सभा में जो आतंक का वातावरण था उसे देखकर कुछ तपस्वी शान्ति सेनिको ने अपने पीछे रुपटटे भी छिपा लिये थे। परन्तु जयप्रकाशजी तनिक भी विचलित नहीं हुए। इससे ठीक दूसरी तरह का प्रसंग बीनगर में था, जब उन्होंने शेख अबदुल्ला की उपस्थिति में कश्मीर की जनता से कहा कि कश्मीर की समस्या का हल भारतीय संघ राज्य से बाहर किसी हालत में सोचा नहीं जा सकता। यही उनकी विचार यात्रा के लिए भी साधू है। वे जिस विचार को ग्रहण करते हैं, उसे सम्पूर्ण निष्ठा के साथ ग्रहण करते हैं। परन्तु उनकी निष्ठा जिनासा का अन्त नहीं कर पाती है। उनकी जिज्ञासा अबाधित रहती है। इसलिए अपन मत का अभिनिवेश होते हुए भी उनकी बुद्धि में आपग्रह ठहर नहीं पाता। अनाग्रह तो

बुद्धिमत्ता का धन्य स्तम्भ है। दूसरी भूमिका समझने की सत्यता जय प्रकाशजी की बुद्धिनिष्ठा का स्थायीभाव है। फलतः उनके स्वभाव में उत्कटता होत हुए भी असहिष्णुता नहीं है। इसीका गुप्त परिणाम निकला है कि नये विचार ग्रहण करके समझने उनकी बुद्धि में से कभी तिरोहित हो नहीं हुई।

अनाग्रह के कारण ही उनका सौहार्द और सहृदयता मतभेदों को पीरकर प्रतिपक्षी के भी हृदय का स्पर्श करती है। जयप्रकाशजी के स्वमत प्रतिपादन का भावना कभी कभी असहिष्णुता की सीमा का स्पर्श करता सा प्रतीत होता है। लेकिन उनके हृदय की उदारता सारे मतभेदों को लाँघकर मानवीय सम्बन्धों का परिपोष करती है। लोहिया से उनके कई वाद विवाद हुए। कभी कटुता भी पैदा हुई। लेकिन चित्त की गहराई में जो सौहार्द था वह फिर भी अधुण ही रहा। डा० लोहिया की मृत्यु के समय वह प्रकट हुआ। किसी भी प्रकरण में तथ्यों की खोज करने की एक अदम्य आकांक्षा भी उनको युद्ध मत्ताग्रह से हमेशा बचाती रही है। साधारण रूप से साम्यवादियों के लिए उनसे मन में बहुत झट्टा या विश्वास नहीं है। फिर भी पिछले चुनावों के बाद ज्योति बसु ने जब कुछ गम्भीर आरोप सत्ताग्रह पर किए तब जयप्रकाशजी वास्तविक परिस्थिति की खोज की। ■ लिए बिना किसी हिचकिचाहट के तयार हो गए।

परम्परागत जब म जयप्रकाशजी उन व्यक्तियों में से नहीं हैं जिन्होंने सारम की खोज को अपने जीवन का प्रयोजन माना हो। लेकिन वस्तुनिष्ठा और सत्य निष्ठा के विषय में उनकी भूमिका सराहनीय रही है। नतीजा यह है कि बुद्धि ने जिस समय जिस सत्य को ग्रहण किया उसमें उनकी सहृदयता का कभी बाधा नहीं पहुँचाई। चाइल के सर्वोच्च सम्मेलन में विनोबा का अविस्मरणीय प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने भारी सभा में घोषणा की कि मर सार सदेह अनाग्रही गये हैं। मैं अपने ही विनोबा का पिण्ड कहलान के लिए तयार हूँ। इस प्रकार की निरह्वारिता का कई उदाहरण उनके जीवन में से दिये जा सकते हैं।

परिस्थिति में जब अनौपत्य उपस्थित होती है तो व सहज प्ररणा से छसका स्वीकार कर लेते हैं। उसमें उत्तजना नहीं होती है। उनके जीवन में जो-जो स्थित्यतर आय उन सभी प्रसंगों में उ होन चिरपरिणामकारी निणय भी सहज प्ररणा से लिये हैं। विनोबा के आन्दोलन में शामिल होन के बाद पार्टी छोडने की बात जब उनसे बार बार कही जान लगी तब उन्होंने कहा— मैं अपन जीवन में कोई महान निणय, कोई स्थित्यंतरकारी सव प इस प्रकार नहीं किया है। सारे निणय सहजप्ररणा से हुए हैं। घोषणया ने सर्वोदय सम्मेलन में उन्होंने जब

जीवनदान के सकल्य की घोषणा भी, तो उससे एक दण पहिले, स्वयं उन्हें भी पता नहीं था कि उनके मुँह से ऐसी किसी घोषणा का उच्चारण होनेवाला है। उन्होंने मुसहरी जान का सकल्य भी इस सहजव्यकृति से किया। उनके निर्णय के पीछे कोई नफा नुकसान का हिमाज या हानि लाभ का नापनील नहीं था।

उसी प्रकार किसी सामाजिक या राष्ट्रीय सकल्य के समय जब उन्होंने कुछ निर्णय किये तो वे भी अन्तस्फूर्ति से किये। जिसे दानमुक्ति या उदारता कहते हैं, उसका विकास उन्हें नहीं करना पड़ा। दान या उदारता विचार से पहले उनकी सहानुभूति प्रवृत्त हो जाती है। उनके स्वभाव की इस विशेषता को लक्ष्य करके ही शायद “इन्स्ट्रुटेड बीबी” के सम्पादक ने उनके विषय में लिखा कि “यह दास्त देना हा देना जानता है लेने या पाने की किराक में नहीं रहता।” बैंगलूर में एक दिन एक साधु पुरुष के दर्शनो के लिए उनके साथ जाने का सुयोग मिला। उन महात्मा न जयप्रकाशजी से बार-बार एक ही बात कही—“मानका हृदय बहुत धुल है।” उस महात्मा की वह बात निवार सत्य है। समाज में ऐसे कई साधुवैश्यारी व्यक्ति हैं जिनका हृदय पॉजिटिवियन और डिप्लोमे का होता है। जयप्रकाशजी एक ऐसे गृहस्थ हैं जिसका हृदय सन्त का है।

जयप्रकाशजी के हृदय में सन्ततुल्य शक्ति है। उसी प्रकार बालसुलभ ऋणता और सरलता भी है। सर्वोदय आन्दोलन में पहले पहल आये, वो उन्हें अपने रहन सहन के कारण बड़ा सकोष होता था। उनके रहन सहन में बिलासिता या प्रसाधन-प्रियता नहीं है। लेकिन सदमिहृति और रसिकता पर्याप्त है। इसलिए उनके रहन सहन में एक आरिस्टोक्राटिक ढंग का आभास होता है। कुछ सर्वोदय कार्यकर्ता कानाफूसी करने लगे। श्रीरेन्द्र मजूमदार ने—हज़ूर ‘मजूर’ शब्द बलाये थे। कार्यकर्ता भावस में बहने लगे जयप्रकाशजी का रहन-सहन हज़ुरों का है। बेचारे जयप्रकाशजी बड़े परेशान हुए। बहने लगे—“तब तो इस जमात में रहन के लायक नहीं हूँ।” बड़ी मुश्किल से उनकी यह परेशानी दूर हुई। वे सुशामदपधन्ध व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन शीघ्र प्रसन्न हो सकते हैं। बालक की तरह प्रसन्न भी शीघ्र होने हैं और रुठते भी शीघ्र हैं। उनकी स्फटिकवत प्रान्तता का यह परिणाम है। व्यवहार को सुन्दरता और सम्यता उनकी अनुकरणीय है। लेकिन उनके स्वभाव में औपचारिकता का अभाव है। इसलिए उनके स्वभाव देय भी बहुत घोट नहीं पहुँचाने।

अदम्य पराक्रमशीलता होते हुए भी महत्वाकांक्षा जयप्रकाशजी को कू तक नहीं गयी है। शायद इसीलिए उनके उस विद्वान मित्र ने उनके जीवन का खोये

हुए मौकों को कहानी कहा है। ऐसे कम से-कम दो या तीन अवसरों का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। जब लोगों ने, और ऐसे लोगों ने जिनका लोक-जीवन में प्रभाव है, उनसे साग्रह अनुशेष किया कि वे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हों। उन्होंने बहुत नम्रतापूर्वक और दृढ़तापूर्वक इनकार किया। उस वक्त यह भी कहा कि अहिंसा के लिए जिस हद तक मेरे चित्त में निष्ठा पैदा हुई है, उसका ध्यान रखते हुए मैं इन पदों को स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने जयप्रकाशजी से आग्रह देश प्रकरण के संदर्भ में यह भी बिना सकोच के कहा कि शायद मेरी अहिंसा उतनी सम्पूर्ण नहीं है जितनी कि एक शान्ति सैनिक को होनी चाहिए। इसलिए मैं शान्ति सेना से प्रणामपूर्वक हटने को तैयार हूँ। उनके एक बहुत पुराने प्रतिष्ठित समाजवादी मित्र ने उनसे यहाँ तक कहा था, “आप परिस्थिति के नाप के नहीं साबित हो रहे हैं।” फिर भी उन्होंने बहुत शान्ति से यह समझाने की कोशिश की थी कि उनका सत्ता से बाहर रहना भी ब्यो उपयुक्त था। अन्त-र्वाह्य प्रामाणिकता वीर-वृत्ति की अमिन्न सहचारिणी है। जे० पी० का व्यक्तित्व उससे लबालम है।

जयप्रकाशजी के हृदय की शुद्धता, असीम व्यापकता और अबाधित सदारता का अत्यंत परिचय चम्बल घाटी और बुंदेलखण्ड के बागियों के आत्म-समर्पण प्रकरण में हुआ है। बागियों को मनाने या समझाने के लिए जयप्रकाशजी नहीं गये थे। बागी स्वयंप्रवृत्ति से उनके पास आत्म-समर्पण करने गये। जब पिछली ३१ मई को बुंदेलखण्ड के बागियों को यह पता चला कि जयप्रकाशजी अस्थास्थ के कारण आ नहीं सकेंगे, तो यह विचार हुआ कि किसी अन्य समादरणीय व्यक्ति को उनकी जगह बिधि सम्पन्न करने के कहा जाय। तब बागियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जयप्रकाश बाबू का विकल्प कोई नहीं हो सकता। अगर वे नहीं आ सकते हैं, तो वहाँ जाकर उनके चरणों में आत्म-समर्पण करेंगे। सच तो यह है कि जयप्रकाशजी का व्यक्तित्व लुभावना ही नहीं, अपितु अनुपम है। उनका न कोई विकल्प हो सकता है और न ही प्रतिहस्तक। जहाँ प्रत्यक्ष मानवीय सम्बन्ध का प्रदन होता है, वहाँ जयप्रकाशजी ही अपना विकल्प और पर्याय है।

जयप्रकाशजी जिस काम को स्वीकारते हैं, उसमें अपने आपको बिना विन्दु-परंतु के पूरी तरह डोक देते हैं। उस कार्य को सम्पन्न करने में वे कुछ उठा नहीं रखते। ऐतिहासिक उनकी एकाग्रता एकाग्रता में कभी सो नहीं जाती। एकाग्रता के साथ-साथ उनमें निरन्तर सार्वजनिक सावधानता भी होती है। इसलिए देश में या अणु में घटित होनेवाली किसी भी महत्वपूर्ण घटना के विषय में वे

अपना मत बिना भय और संकोच के स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हैं। उस विषय में कोई सक्रिय बदम उठाना पड़े, तो प्रायः चुके नहीं हैं। कुछ लोग उन पर यह आरोप लगाते हैं कि राजनीति में इस प्रकार प्रच्छन्न रूप से हस्तक्षेप करने में जे० पी० की मजा आता है। वस्तुस्थिति यह है कि जयप्रकाश ने सत्ता की राजनीति के संकीर्ण क्षेत्र में से लोकनीति के या लोक कारण के दितिबव्यापी क्षेत्र में पदार्पण किया है, तालाब से निकल कर विशाल समुद्र में अपनी नौका छोड़ दी है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद की परिधि और दायरा बहुत ऊँचा और महान् अवश्य है, लेकिन निर्यादिक मायरिकता का क्षेत्र असीम है। इस दृष्टि से जयप्रकाशजी का व्यक्तित्व भी व्यापक बनता चला गया है।

जयप्रकाशजी को जीवनिर्वा प्रकाशित हुई है। उनके पढ़ने में पता चलता है कि उनका जीवन रोमहृषक घटनाओं से सम्पन्न रहा है। सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक-स्वर्गीय रामदूष बेनीपुरी ने उनकी जो जीवनी लिखी है, वह उपम्यास से भी अधिक रोचक है। परंतु जयप्रकाशजी कहते हैं, बेनीपुरीजी ने बहुत अत्युक्ति की है। बातों को बड़ा बड़ाकर लिखा है। असल में मैं वंशा अद्भुत पराक्रमी बोर नहीं हूँ। यह उनकी मज्जा या बिनयशीलता नहीं है। उनको वास्तविक आत्म-मर््यादा है। और यही उनके व्यक्तित्व का मेरुदण्ड है, जिसमें उनकी मानवता अविकल रूप से व्युत्पन्न रही है।

जयप्रकाशजी के जीवन में व्रत और संकल्प का कोई विशेष स्थान नहीं है। उन्होंने शायद ही कभी कोई व्रत लिया हो। ब्रह्मचर्य का व्रत तो स्यात् उनके सपने में भी नहीं था। लेकिन प्रभावतीजी ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। जयप्रकाशजी प्रभावतीजी के सहयोगी जो ठहरे। प्रभावतीजी के व्रत का अंगीकार करने में उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। सहजस्फूर्त दाम्पत्य ब्रह्मचर्य में जय प्रभा की जोड़ी लासानी है। जयप्रकाशजी के कुछ घनिष्ठ मित्रों की यह धारणा है कि प्रभावतीजी का व्यक्तित्व आकार में उतना मध्यम भले हो न हो, लेकिन गुणात्मकता में शायद कुछ श्रेष्ठ ही सिद्ध होगा। जहाँ तक अदम्य सत्यनिष्ठा और अर्बाह्य शुचिता का प्रश्न है प्रभावतीजी के मुकाबले के व्यक्ति बहुत बिरले होंगे। भय तो उन्हें छू तक नहीं गया है। यह कहने में जरा भी अत्युक्ति नहीं है कि जय प्रभा एक दूसरे से बढ़कर हैं। इस प्रकार का दूसरा कोई उदाहरण मुझे मालूम नहीं है।

जयप्रकाशजी की ७० वीं जन्म-अवधती पर प्रकाशित गुजराती पुस्तक "मारो विचार यात्रा" की प्रस्तावना से।

शिक्षा का मानवीय आयाम

[विनोबा जयन्ती के अवसर पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के अध्यापकों एवं छात्राध्यापकों के सम्मुख दिया गया भाषण ।—सम्पादक]

आज मैंने जो विषय अपने लिए पसन्द किया है, उसको शीर्षक दिया है—‘विनोबा के शिक्षण विचार’। लेकिन सम्भव है कि उन सारे विचारों में गांधी के शिक्षण का बहुत सारा हिस्सा समाविष्ट हो जाय। इसलिए गांधी विमोचा को अलग-अलग न करते हुए उन विचारों के मूल में से शिक्षण के सम्बन्ध में कुछ मौलिक चीजें, जो न सिर्फ हमारे देश को मिली हैं लेकिन ससार के सभी शिक्षाविदों ने यह स्वीकार किया है कि इनमें से बहुत सारी बातें जगत के शिक्षा शास्त्र के लिए भी मौलिक हैं। उन विचारों को, उन विचारों के केवल एक आयाम को आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ और वह आयाम है—शिक्षा का मानवीय आयाम (ह्यूमन डाइमेंशन)। आपमें से कई लोगों को शायद यह मालूम होगा कि जब १९२२ में गांधीजी वर मुकदमा चल रहा था उस समय उनसे जब ने पूछा कि ‘आपका पेशा क्या है?’ उन्होंने कहा, ‘मैं विद्वान हूँ और वुक्कर हूँ।’ इस प्रश्न का उत्तर करते हुए अक्सर विनोबा कहते हैं कि मुझसे कोई यदि पूछता तो मैं यही उत्तर देता कि मैं एक शिक्षक हूँ। विनोबा ने जैसे किसी अध्यापन मन्दिर में या किसी मुनिबसिटी-कालेजों में आकाशवाणी पढ़ाया गयी होगी। लेकिन जीवन भर अपने आपको एक शिक्षक मानते रहे हैं। यहाँ तक कि अभी अभी अपने भूदान के प्रतिष्ठानों कार्यक्रम से भी निवृत्त हो जाने के बाद, जिसको वे सूक्ष्म प्रवक्ष करते हैं, उन्होंने कहा कि ‘अगर मुझ कोई बड़े कि जितना महत्त्व का भूदान का विचार तुमने जनता के सामने रखा उतना ही महत्त्व का विचार तुमने और क्या रखा है? तो मैं कहूँगा कि मुझ लगता है कि आचार्यकुल का विचार, जो मैंने दिया है उसका महत्त्व भूदान-प्रामाण्य के आदोलन से कम नहीं है।’ शिक्षा और शिक्षक के सम्बन्ध में यह उनका अपना विचार है।

परंतु यही मैं यह भी निवेदन करना चाहता था कि एक तरफ से जबकि विनोबा मानते हैं अपना अगर कोई सर्वश्रेष्ठ विचार है तो वह विचार आचार्यकुल है। दूसरी तरफ वे मानते हैं कि मेरा कोई स्वधर्म हो तो शिक्षा है, वही तीसरी तरफ वे यह मानते हैं कि शिक्षा संस्था से बढ़ नहीं होना चाहिए। वह सहज स्वामयिक रूप से जितना हो सके, होता रहे। उसके लिए उन्होंने एक शब्द का संयोजन भी किया है। मनु महाराज का शब्द—‘निवृत्त कर्म’ से उन्होंने यह शब्द छटाया है—‘निवृत्त शिक्षण’। गीता में ‘सहज कर्म’ जिसे कहा है मनु महाराज ने उसके लिए ‘निवृत्त कर्म’ शब्द का इस्तेमाल किया है। जो करने में करनेवाले को और जिस पर वह हो रहा है दोनों को बोझ का अनुभव नहीं होता वह निवृत्त कर्म है। विनोबा कहते हैं जो शिक्षण है वह ‘निवृत्त शिक्षण’ होना चाहिए। पढ़ानेवाले को पढ़ाने का बोझ न हो और पढ़नेवाले को सीखने का बोझ न हो। दोनों का सहज स्वधर्म बन जाय। मेरे क्याल से विनोबा ने जो शिक्षा का विचार दिया है उसका प्रधान तत्व यदि है तो वह निवृत्त शिक्षण का है।

यह कैसे होगा? यह तब होगा जबकि शिक्षा ‘वन से ट्रैफिक’ न रहे। आम-शोर पर, यह माना जाता है कि शिक्षा ‘वन से ट्रैफिक’ है। गुरु बैठा है पढ़ाने के लिए, शिष्य बैठा है पढ़ने के लिए। इसकी कल्पना करीब करीब ऐसी है। गुरुकी बोतल में या गुरु के कुम्भ में ज्ञान का अमृत भरा पड़ा है और विद्यार्थी का पात्र रिक्त है। गुरु क्या नाम करता है? अपने कुम्भ में से विद्यार्थी के रिक्त-पात्र को भर देता है। यह है ‘वन से ट्रैफिक’। इधर से निकल कर उधर गिरता है। यह शिक्षा की परम्परागत व्याख्या है।

गुरु पढ़ाता है, विद्यार्थी ग्रहण करता है। गुरु बोलता है, वह ‘नोट्स’ लेता है। अगर सामने कोई प्रश्न पूछ लिया तो गुरु अपमानित भी हो उठता है। यानी पढ़ाने का काम एक ही दिशा में से होना चाहिए। यह जो पद्धति है इसका परिणाम क्या होता है? गुरु का कुम्भ जैसे-जैसे विद्यार्थी के पात्र को भरता जाता है गुरु का कुम्भ खाली होता जाता है और ये पात्र यदि पूरणरूपेण भर जाता है तो गुरु का कुम्भ छाय बन जाता है। यह ‘वन से ट्रैफिक’ का दोष है।

हम लोग अपनी शिक्षा-संस्थाओं में यह पाते हैं कि तीस साल के पुराने नोट चल रहे हैं और जिसके उसी नोट के अनुसार पढ़ा रह है। उसके पास जो पात्र है, उसमें जो भर है, वही उसे खाली करना है न कि उसे सामने से ग्रहण करना है।

यह जो पद्धति है एक तरफ से बहनेवाले प्रवाह की पद्धति है, उससे शिक्षा

या जो असली व्यापार है, वह कुष्ठित होता है। वह व्यापार दोनों तरफ का होना चाहिए। इस मूल श्रद्धा में से विनोबा का सारा शैक्षिक विचार उत्पन्न हुआ।

दूसरी चीज, जो विनोबा के लिए कभी-कभी इस्तेमाल होता है वह 'आचार्य' शब्द है। गांधीजी के आश्रम में किसी एक विद्यालय के वे आचार्य थे, इसलिए उनका नाम आचार्य रखा होगा या जो 'आचार्य' शब्द का मूल अर्थ है उस अर्थ में आचार्य है, इसलिए रखा गया होगा, मैं नहीं कह सकता।

आचार्य वह है जो अपने आचरण में किसी विचार को, किसी दर्शन को और जीवन को साठा हो तथा जिसके आचरण से दूसरे को आचार करने की प्रेरणा मिलती हो। कर्म जो है वह अपने लिए है और दूसरे के लिए कर्म की प्रेरणा। छुड़ करना है काम, दूसरे के काम को देखकर काम करने की प्रेरणा होती है।

हमने अक्सर देखा है कि जहाँ कर्म और विद्या सम्मिलित होते हैं जिन विद्यालयों में कभी नयी तालीम का नाम होता है, कभी-कभी किसी दूसरे प्रोजेक्ट का भी नाम रहता है उसमें जो कर्म और ज्ञान का मेल है, उसमें यह माना गया है कि शिक्षक अक्सर कर्म की प्रेरणा देगा। इतना ही नहीं, विद्यार्थी कर्म करेगा और शिक्षक कर्म करायेगा। परन्तु आचार्य शब्द की परिभाषा में जरा भेद है। इसकी जो कल्पना है, इसमें भेद यह है कि शिक्षक आचरण स्वयं करेगा और आचरण की प्रेरणा विद्यार्थी लेगा। न कि उससे आचरण करना-करवाना यही उसका काम हो।

मेरे क्वाल से शिक्षा के सम्बन्ध में ड्यूई, पेस्टेलोजी इत्यादि लोगों ने जो चीजें कही उनमें और विनोबा के विचार में यह मूल भेद है।

विनोबा ने सोचा, शिक्षा में धर्म का स्थान होना चाहिए, यह मैं कहूँ उससे पहले शिक्षा में धर्म का स्थान कैसा होना चाहिए? यह जरा आचरण करके देखूँ। उन्होंने माना कि शिक्षा से समाज में कुछ मूल्यों की स्थापना होनी चाहिए। सदाहरण के लिए स्वातंत्र्य का मूल्य और समत्व का मूल्य। उन्होंने सोचा मैं अपने जीवन में स्वातंत्र्य और समत्व का मूल्य स्थापित कर सकता हूँ या नहीं, यह पहले देख लूँ। बाद में उसके विषय में जो कुछ कहना हो वह कहूँगा। उन्होंने देखा कि हमें कुछ कहना है। कहना यह है कि जो सबसे पीछे है, जो नीचे है उसके उत्थान की बात अगर करनी है तो मुझे स्वयं उसके साथ समरसता या अनुभव करना चाहिए। पहले उन्होंने इसका अनुभव किया और उसके बाद कहा। उन्होंने सोचा कि सबसे कम मजदूरी किस काम में मिलती है? उन दिनों

उन्होंने देखा कि कताई करने में कम से कम मजदूरी मिलती थी। उन्होंने देखा कि कताई करने के कारण जो मजदूरी मिलेगी उस मजदूरी में जीवन यापन कर सकता है या नहीं? यह पहले प्रयोग करके देखूँ और उस प्रयोग को करने लग। उससे प्रतिदिन उनका पुराने पाँच पैसे मिल जाते थे। पुराना पाँच पैसे अर्थात् सवा आना। उस सवा आने में ही जीना, यह निश्चय करके बर्षों तक उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने देखा कि इसमें परिश्रम उतना नहीं करता पड़ता। अतः उन्होंने सोचा सबसे अधिक परिश्रम जिसमें करना पड़ वैसे कोई काम करने का मौका मिल जाय तो वही मौका खूँया। वह मौका मिला, जब जेल में गये। उनमें पूछा गया कि आठ कौन-सा काम करेंगे? उन्होंने कहा, 'अपके पास जो सबसे अधिक मेहनतवाला काम है वह मुझे दे दीजिए।' वहाँ पाथर तोड़ने का काम, मिट्टी बनाने का काम उन्होंने दस महीने तक किया। उन्होंने कहा कि यदि कृषिप्रधान देश में कोई प्रगति बरनी है तो कृषि के कोई प्रयोग करने चाहिए। सामान्य किसानों को कई प्रकार की भुजबर्नें हैं तो मैं क्या करूँ? औसत व्यक्ति को जितनी जमीन मिलती है उतनी ही जमीन भूंगा यानी पौन एकड़ प्रति व्यक्ति। हमारे देश में कृषि पर निर्भर रहनेवाले को पौन एकड़ प्रति व्यक्ति जमीन मिलती है। अतः पौन एकड़ सामान्य स्तर की जमीन प्रति व्यक्ति के हिसाब से ली। किसानों को कम साधन मिलते हैं, अतः बिना साधन के कुदासी लेकर खेती का काम करना शुरू किया। इसे उन्होंने नाम दिया—अपि कृषि। अपि लोग बैलों का उपयोग करते थे या नहीं? मालूम नहीं। नृषियों के पास बहुत अधिक साधन तो क्या होंगे आश्रम में? इसलिए कुदासी से ही काम करना शुरू दिया। इस तरह पहले उन्होंने प्रयोग किया और उस प्रयोग के साथ उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया। इसलिए आचरण से जिन विचारों का आरम्भ हुआ और आचरण से जिन विचारों की अभिव्यक्ति हुई, वह विचार विनोबा के शिक्षा विचार के मूल में था।

नयी सालीम यानी समवाय पद्धति

शिक्षण विचार के साथ उद्योग को तरह-तरह से जोड़ा जाता है। कुछ लोग कहते हैं केवल कि शिक्षा से उन्हें सम्बन्ध है। विनोबा ने उसका नाम दिया मात्र-पद्धति। 'मात्र' शब्द का उपयोग मराठी भाषा के अर्थ में किया। हिन्दी में 'मात्र' किसी शब्द के पीछे जोड़कर कहते हैं। केवल पढ़ने लिखने की 'मात्र पद्धति' कहा। यह एक पद्धति है। दूसरी पद्धति 'परिनेष' पद्धति है जिसमें पढ़ना लिखना सब कुछ करते जाइए उसमें थोड़ा-सा 'उद्योग' जोड़ दीजिए। जैसा उत्तर प्रदेश

की बुनियादी शालाओं में जोड़ा गया था। एक रात में बुनियादी शालीम की सरकार ने स्वीकार कर लिया एव उसमें रोज एक पीरियड थम का जोड़ दिया गया और यह मान लिया गया कि यह हो गयी बुनियादी शालीम। तो विनोबा ने इसे 'परिशेष पद्धति' नाम दिया। उस पद्धति से भी कुछ होगा नहीं। तीसरी पद्धति जो उन्होंने बताया वह है 'समुच्चय-पद्धति'। जिसमें थोड़ा उद्योग भी रखो, थोड़ा ज्ञान भी रखो और दोनों को इकट्ठा कर लो। इसे उन्होंने 'समुच्चय-पद्धति' माना। तो इस पद्धति में भी शिक्षा के जो मूल तत्व हैं उनका आना सम्भव नहीं है। उन्होंने चौथा प्रकार बताया कि उद्योग की शिक्षा का माध्यम बनाना, जैसा बुनियादी शिक्षा में गांधीजी ने बताया था और इसे समवाय पद्धति कहा। समवाय का गलत अर्थ समझा गया है ऐसा मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। मैं अध्यापन मन्दिर का ही एक उदाहरण देता हूँ। एक अध्यापन-मन्दिर में गया। वहाँ पर समवाय पद्धति का पाठ चल रहा था। बताया जा रहा था कि समवाय पद्धति वैसी होती है सभी बच्चे बैठे हुए थे। साथ-साथ अपनी सकली भी बला रहे थे। शिक्षकों ने प्रश्नोत्तर पद्धति का उपयोग पढ़ाने के लिए किया। पूछा—बच्चों! "तुम लोग क्या कर रहे हो?" बच्चों ने उत्तर दिया, "गुरुजी! हम लोग कताई कर रहे हैं।" पहल प्रश्न का उत्तर तो अभीष्ट था वही मिला। "अच्छा बच्चों! तुम वैसा सूत कात रहे हो?" बच्चों कहा, "मोटा सूत कात रहे हैं।" "अच्छी बात है? मोटे सूत से क्या बनता है।"—गुरुजी ने पूछा। किसी ने कहा, 'दरी बनती है, किसी ने कहा चादर बनती है।' सब शिक्षक को पूछता पड़ा, "कोट बनता है या नहीं?" "हाँ, कोट भी बन सकता है।" 'कोट बोन पहनता है?' गुरुजी ने पूछा। "साहब आप पहनते हैं," बच्चों ने कहा। "बच्चों और बोन पहनता है?" "मेरा आप पहनता है।" "और कौन पहनता है।" गुरुजी बतलाने लगे, 'राजा पहनता है या नहीं?' "हाँ राजा भी पहनते होगे।" और गुरुजी न अपना पाठ प्रारम्भ कर दिया—'एक ऐसे राजा की कहानी सुनको सुनाता हूँ और फिर कहानी शुरू कर दो।

यह जो शिक्षण की समुच्चय पद्धति है, जिसे लोगों ने बलनी से समवाय कहा था नयी शालीम नहीं है। समवाय पद्धति उस पद्धति का नाम है जहाँ शिक्षा को ठोड़ मरोड़ कर उद्योग के साथ नहीं बैठाया जाता। समवाय सहज स्फूर्त होना चाहिए। उस सहज स्फूर्त समवाय में तीन चीजें होगी, उससे पहली चीज होगी—मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है विचारों और शिक्षक के सम्बन्धों के बीच मुक्त वातावरण का अनुभव हो। आपस का वातावरण ऐसा मुक्त हो, जिससे वह

विद्यार्थी के गुण विकास में सहायक हो सके। दूसरी चीज है—प्रीति, जो इसी मुक्ति के विचार में से विनसित हुई है। विद्यार्थी और शिक्षक का सम्बन्ध प्रीति का हो—परस्पर स्नेह का हो। जहाँ एक दूसरे के दोष के हिस्सेदार एक दूसरे बन पाते हैं, वहाँ प्रीति होती है। गुण के हिस्सेदार तो सब बनना चाहते हैं। लेकिन अगर दोष के हिस्सेदार बनने की तैयारियाँ हों तो वहाँ प्रीति पैदा होती है। अगर मेरा विद्यार्थी फेल हुआ तो मैं फेल हुआ। शिक्षक के मन में जब ऐसी अनुमति होती है तो आपस में प्रीति का वातावरण बना, ऐसा मानना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि उसे पास करवाने के लिए अव्यक्त पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ। यदि विद्यार्थी का अध्ययन नहीं बढ़ रहा है तो मुझमें कुछ त्रुटि है, यह अध्यापक महसूस करता है तो उसमें से यह भाव पैदा होता है। जिस प्रीति के भाव में मे मुक्ति के भाव को और मुक्ति के भाव में प्रीति के भाव को परस्पर सहायता मिलती है, उसे प्रीति कहते हैं। और तीसरी चीज जो इन्हीं दोनों चीजों में से फलित होती है वह है, अभिव्यक्ति। विद्यार्थी की अभिव्यक्ति किसी काम के द्वारा हो सकती है, विचार या दर्शन के द्वारा भी हो सकती है अथवा अनेकों प्रकार से हो सकती है—भावना के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में। इन तीनों में विद्यार्थी की अभिव्यक्ति का अवकाश वहाँ मिले, वहाँ नयी तालीम का समवाय है—मुक्ति, प्रीति और अभिव्यक्ति।

समवाय के तीन पहलू

नयी तालीम के समवाय के तीन पहलू हैं। उनमें से एक विद्यार्थी और शिक्षक के सम्बन्धों का समवाय हुआ जिसके विषय में मैंने अभी कहा। दूसरा है ज्ञान और कर्म का समवाय, यानी कर्म से ज्ञान का प्रादुर्भाव हो। विद्यार्थी को यह अनुभव ही न हो कि कहीं और कब कर्म समाप्त हुआ और कहीं और कब ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरा शिक्षा की संस्था और समाज का समवाय। अगर यह नहीं होता है तो शिक्षा संस्था अपने पाठ्यक्रमों, अपने समय पत्रकों, अपने निरीक्षण के प्रण्यों तथा अपनी परीक्षाओं को लेकर चलती रहेंगी और समाज किसी दूसरे ही मार्ग से चलता रहेगा। यह पता ही नहीं चलेगा कि आज जो शिक्षक ४ घण्टे ६ घण्टे पढ़ायेगा उससे बाकी जो दिन २ घण्टे है (और वे स्कूल के घण्टों से बहुत ज्यादा है) उन घण्टों में, समाज दूसरी चीजों को पढ़ाता रहेगा। शिक्षा के बहुत सारे माध्यम हैं जिन माध्यमों से विद्यार्थी पढ़ता है।

अगर वह शिक्षक उसके साथ-साथ नहीं रहता है तो उसके पिछड़ जाने का डर रहता है ।

मैं रेडियो के सम्बन्ध में जितना जानता हूँ या बिजली के सम्बन्ध में जितना जानता हूँ, मेरा ग्यारह बारह साल का लड़का, उससे कहीं अधिक जानता है । क्योंकि उसने अपने आतावरण में से वह शिक्षा प्राप्त की है । अपनी शिक्षण-सत्पात्रों में कभी-कभी इस विचार को मूल जाते हैं कि जीवन गत्यात्मक है । जीवन कोई स्थिर चीज नहीं है, स्टैटिक नहीं है । वह कोई बद्ध चीज नहीं है, और गतिशील चीज के साथ शिक्षा की वस्तु में, शिक्षा की पद्धति में और शिक्षा की परम्परा में भी गतिशीलता आनी चाहिए । इसका अगर ध्यान न रखा जाय तो समाज और शिक्षण संस्था में समवाय होना सम्भव नहीं है ।

विद्यार्थी और शिक्षक के सम्बन्धों का समवाय, समाज और शिक्षा का समवाय और विद्यार्थी के कर्म और अनुभव के साथ ज्ञान का समवाय, इसे ही हमी तालीम कहते हैं ।

हमारी शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है जीवन विमुक्तता । और जीवन के साथ विमुक्तता ऐसी हो जाती है कि जिसके कारण एक तरफ जीवन विमुक्त पूर्वार्द्ध और दूसरी तरफ शिक्षा विमुक्त उत्तरार्द्ध । इस तरह जीवन के दो विभाग बना छिड़े गये हैं । हालाँकि कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उत्तरार्द्ध में भी शिक्षा का धन्धा करना पड़ता है । जैसा आप लोगों को करना पड़ेगा । आप लोग समझते होंगे कि हमने उत्तरार्द्ध में शिक्षा के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है । लेकिन वह किस शिक्षा के साथ सम्बन्ध जोड़ा है आपने ? इस प्रश्न पर उत्तर निर्भर करता है कि सधमूख शिक्षा विमुक्त जीवन है या नहीं । वास्तव में तो वह एक पद्धति अभिमुख जीवन है । शिक्षा अभिमुख जीवन सभी समझो जायगी जब जीवन के अंतिम क्षण तक आपको अपनी शिक्षा होती रहगा । इसलिए आप दावे के साथ कहेंगे कि जब से मैं शिक्षिका अथवा शिक्षक बना हूँ उसके बाद का एक दिन भी मेरा गुण-विकास से नावा नहीं गया है । प्रतिदिन मैं भी सीखता गया । तब आपका शिक्षाभिमुख जीवन होगा । वरना उस पद्धति से अभिमुख आपका जीवन होगा जिस पद्धति के एक पुर्जे के नाते आप लोगों को चलना पड़ता है । जैसे किसी बगीच को अपना धन्धा करना पड़ता है, और दूसरे को दूसरा धन्धा करना पड़ता है । कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि और कुछ काम नहीं मिला तो शिक्षक बन गये । वह स्थिति आपकी नहीं है यह मानस में चलता है । तो भी दूसरा काम जो वह है वही आपका यदि न हो तो भी जीवन अभिमुखता नहीं मानो जानी चाहिए ।

इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो जिस शिक्षा-विचार के बारे में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ उसमें विद्यार्थी और शिक्षक, जीवन और शिक्षण, समाज और शिक्षा सस्या तीनो का समन्वय होना चाहिए। इन तीनों के समन्वय के लिए 'समवाय' शब्द विनोबा ने अविकल पसन्द किया।

शिक्षा का कण्टेण्ट

शिक्षा की वस्तु (कण्टेण्ट) क्या हो ? इस सम्बन्ध में देखना हो तो किसी सिलेबस कमिटी में देख लीजिए।

विनोबा ने, शिक्षा की जो वस्तु है, जो कण्टेण्ट है, उसको एक शब्द में बता दिया है। वह है—प्राचीन आध्यात्मिक परिभाषा का शब्द—सन्धिदानन्द। सत् बिन् आनन्द इन तीनों शब्दों का समावेश यानी शिक्षा का कण्टेण्ट।

सत् से उन्होंने सम्बन्ध जोड़ा है जीवन के व्यवहार के लिए आवश्यक ऐसा सारा कर्म, वित्त के साथ जोड़ा है जीवन को उन्नति लिए के आवश्यक ऐसा सारा ज्ञान और आनन्द के साथ जीवन की सारी आध्यात्मिकता।

कहने का मतलब यह हुआ कि उद्योगशीलता, ज्ञान-प्राप्ति और आध्यात्मिकता इन तीनों को शिक्षा की वस्तु में विनोबा ने जोड़ा है। बाकी जो सारी चीजें हैं वे उसके माध्यम के रूप में आयेंगी। उसके विषय में उनका एक बड़ा आग्रह है। उनका आग्रह यह है कि विद्यार्थियों को सारी चीजें जो आपके पास हैं उसे दिमाग में भरकर स्कूल से छोड़ना नहीं चाहिए। अधूरा रहेंगे तो आपत्ति नहीं। लेकिन मेरे पास जो है उसे ठूस कर भर दूँ, और मेरा काम शिक्षक के भाते समाप्त हुआ यह मानना गलत है, ऐसा वे मानते हैं। उनका कहना है कि हमसे इण्टेलिक्चुअल डिसेण्ट्री अर्थात् 'बौद्धिक पेचिश' हो जायगी। उनका कहना है कि हमारा उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि विद्यार्थी बाहर निकलने के बाद अपनी प्रेरणा, अपने पुरुषार्थ से शिक्षा प्राप्त कर सके, इतना काम कर देना ही हमारा फर्ज है। न कि जो भी हमारे पास है वह हमारी जेब से निकाल कर उसकी जेब भर दिया। जब उसकी जेब खाली हो जायगी तो जैसा हम पहले बता चुके हैं वह बेकारा पगु हो जायगा। क्योंकि फिर वह कहेगा कि जो अपनी जेब में भर-भर कर दे रहा था वह तो अब रहा नहीं। अब तो मैं भवसागर में बूढ़ रहा हूँ, तैर रहा हूँ। देख तो लिया भवसागर को, लेकिन तैरना नहीं सीख सका। अब आप तैरना सिखा देते हैं तो सागर में क्या क्या है यह दिखाना आपका काम नहीं। हम लोग कभी-कभी मोती देने की उत्सुकता में तैरने का जो मूल काम है वही भूल जाते हैं। यदि हमने तैरना सिखा दिया तो

उत्तम ही काफी है। वे कहते हैं कि स्वावलम्बन की परिभाषा की सबसे पहली कसौटी यह है कि विद्यार्थी ज्ञान के बारे में स्वावलम्बी हो। वह अपने पैर पर खड़ा रह जाय, यह उसकी दूसरी परिभाषा है। 'स्वावलम्बन' शब्द गांधीजी की परिभाषा में तो बार-बार आता है। विनोबा ने भी इसे स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि मेरी स्वावलम्बन की परिभाषा का मतलब होता है ज्ञान-प्राप्ति के बारे में स्वावलम्बी बनना। जैसे, डिक्शनरी का उपयोग करना जानता हो। (मेरे पास काफी पढ़े लिखे लोग आये हैं, जो कहते हैं कि असम जाने के लिए रेलवे टाईम टेबुल देख दोजिए। मुझे आता नहीं। एक भाई साहब जो काफी पढ़-लिख चुके थे, जब मैं बीमार पड़ा था तो मेरी सेवा में लगे थे। मुझे टाइफाइड था ज्वर था। अतः उसे रेकर्ड करना पड़ता था। बहुत देर के बाद मुझे यह समझ में आया कि थर्मामीटर कैसे देखा जाता है यह वह जानता ही नहीं। क्योंकि उसने प्रैजुएशन तो हिस्ट्री में किया था, साइंस में तो किया नहीं था। तो वह मुझे दिखाने लगा कि टेम्परेचर किनारा है। आमतौर पर रोगी की थर्मामीटर नहीं दिखाया जाता है। उस बेचारे को मरीज से शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी।) जीवन की उपयोगी चीजें, इतना ही नहीं, जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपयोगी चीजें जैसे डिक्शनरी देसना, इन्साइक्लोपीडिया का उपयोग करना, रेफरेन्स-बुक को क्लसट करना, लोगों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना, टैप रिकॉर्डिंग का उपयोग करना, इण्टरव्यू की पद्धतियों का उपयोग करना आदि, आज इतनी पद्धतियाँ विकसित हो चुकी हैं कि उसका यदि उपयोग किया जाय तो आदमी अपने आप बहुत धारा ऐमा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो शायद स्कूल के बच्चों में उसे प्राप्त होना सम्भव ही नहीं है।

स्वावलम्बन के तीन पक्ष

सबसे पहले शिक्षा सम्बन्धी स्वावलम्बन, दूसरा जीवन में वह खुद खड़ा हो सके निर्भयता के साथ, इसलिए आर्थिक स्वावलम्बन और तीसरा है चारित्र्य के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होना। यह स्वावलम्बन का मैं तीसरा अर्थ समझता हूँ, जिसमें निर्भयता और धौल के साथ का सम्बन्ध और विचार-स्वातन्त्र्य इन तीन तत्वों को उसमें जोड़ा है। निर्भयता को चारित्र्य के महल का प्रवेश-द्वार विनोबा मानते हैं। शिर्ष विनोबा ही मानते हैं ऐसा नहीं, भीता भी मानती है। देवी सम्पति का लक्षण जब भीता जाती है तो 'अभय सत्त्वसन्नुद्धि' से ही शुरू करती है। 'सत्त्वसन्नुद्धि' भी बाद में आ जाती है और जो-जो बताती है वह सब बाद में आती है। लेकिन सबसे पहला अभय है। आप कहिए कि सत्य की तो

मुझे पूजा करनी है, लेकिन अभ्यधीत है। वह सत्य की पूजा कर नहीं सकता बिना अभय के। गुण प्रवेश बिना अभय सम्भव नहीं है। इसलिए निर्भीकता गुण विकास की पहली सीढ़ी है। दूसरा उन्होंने जो माना है—विचार स्वातन्त्र्य। उन्होंने माना है कि शिक्षक के विचार का चुनौती देने का गुण अगर नहीं आया तो वह विद्यार्थी उसका सही माने में चेला नहीं हो सकता। अगर चुनौती नहीं देता है और उसने जो कहा, उसकी नकल ही कर लिया अथवा पृष्ठपोषण ही कर लिया तो वह सुशामदी, चापलूस माना जायगा, विद्यार्थी नहीं। 'चुनौती देना' इसलिए आवश्यक है, क्योंकि जिज्ञासा पहला गुण है विद्यार्थी के माते और जिज्ञासा के बाद, जो उसे बनाया जा रहा है उसे जीव करके देना। जिज्ञासा और परीक्षण इन दोनों का जब मिलन होता है तो उसमें से चुनौती आती है। अतः चुनौती देने की उसकी तैयारी होनी चाहिए। अन्त में, विचार-स्वातन्त्र्य उसे कहाँ तक ले जायगा? चाहे जो विचार सुनेगा, सुनने का उसे हक है लेकिन अपना विचार स्वतन्त्र रखने का भी उतना ही हक है।

विद्यार्थियों के धारे में जब कभी बोलते हैं तो वह कहते हैं कि लोग हमको कहते हैं कि इस सगठन में है उठ सगठन में है। हम कम्युनिस्ट सगठन में हैं, हम सोशलिस्ट सगठन में हैं और भी अनन्त प्रकार के सगठन हैं उसमें होने का दावा करते हैं। विनोबाजी का यह कहना है कि अगर आपने यह बबूल कर लिया कि हम कम्युनिस्ट सगठन में हैं, हम सोशलिस्ट सगठन में हैं, हम गांधीवादी सगठन में हैं या किसी और सगठन में हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने-अपने विचार स्वातन्त्र्य को बेच दिया। आपने जो उसके विचार को बबूल कर लिया। अतः विद्यार्थी का यह जमसिद्ध हक है कि यूनिट का मेम्बर न रहे। हम लोग यह मानते हैं कि विद्यार्थी का जमसिद्ध यह हक है कि वह लोग यूनिट सगठित करें। विनोबाजी का यह विचार है कि अपने विचारों को सगठित करें ताकि उसमें अपना स्वतन्त्र विचार बना सकें। उसके बाद अगर सगठन करने की जरूरत हो तो वह बनायें। दूसरे कि विचारों का अनुसरण करने के लिए, भेड़िया-धसान करने के लिए, हमको सगठन में शामिल करना, जो यह कहता है वह अपना विचार-स्वातन्त्र्य तो खो देता है और गुण-विकास में वह बाधक हाड़ा है। उसी में से जब दो गुणों के विकास में, उससे सोल का चारित्र्य का विकास हो सकता है।

शिक्षा के उद्देश्य

गिना के उद्देश्य में व्यक्तिगत रूप से गुण विकास, और सामाजिक रूप से

मूल्य विकास ये दो उद्देश्य, विनोबा ने जिस शिक्षण-विचार को दुनिया के सामने रखा है, उसके मूलभूत तत्व हैं। मूल्यों का विकास होते रहना चाहिए। स्वराज्य के पूर्व आजादी का मूल्य इस देश का प्रधान मूल्य था अब स्वराज्य के बाद समता का मूल्य समाज का प्रधान मूल्य बनना चाहिए। आज समता का गुणगान होता है लेकिन उसकी प्रतिष्ठा अभी तक नहीं हुई है। समत्व का मूल्य समाज में स्थापित करना, शिक्षा के उद्देश्य में शामिल होना चाहिए। सामाजिक मूल्यों की स्थापना समाज की शिक्षा का उद्देश्य न हो तो यह व्यक्तिगत शिक्षा कुछ इने गिने लोगों को वस्तु बन जायगी, और वह सार्वजनिक वस्तु नहीं बन पायगी। विनोबा की भाषा में अगर कहें तो समाज कुछ लोगों को राह ही बनाता और कुछ लोगों को केतु ही बनाता कुछ को सिर ही देता और कुछ को शरीर ही देता। लेकिन हरेक आदमी को सिर और शरीर दोनों दिया है। इसका मतलब है कि हरक को बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए और हाथ पैर का भी उपयोग करना चाहिए।

विनोबा की शिक्षा जगत में देन

विनोबा की देन क्या मानी जायगी शिक्षा के सम्बन्ध में? बहुत-सी सारी चीजें उठोने नयी कही हैं। मैं आपसे इतना जरूर निवेदन करूँगा कि विनोबा की एक किताब है—शिक्षण विचार। उसमें काफी मौलिक चीजें उन्हींसे रखी हैं। उसमें विनोबा के शिक्षा-सम्बन्धी विचार एकत्रित मिलेंगे। (वह अपनी लिखी हुई पुस्तक नहीं है। यह उनके अनेक प्रवचनों का संग्रह है। इसलिए जो मर्मादाएँ प्रवचनों के संग्रह में आती हैं वह उसमें भी हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा की दृष्टि से यह एक अनिवार्य पुस्तक मानी जा सकती है।) उसे आप लोगों को जरूर देखना चाहिए।

अगर लोगों के पास अपनी सामर्थ्य की व्यक्त करने के लिए कोई 'मिशन' रहता है तो वह सिनिक नहीं होते हैं। विनोबा ने देश को एक मिशन दिया—शासनाभिमुखता के बदले लोकाभिमुखता की ओर जाने का।

विनोबा के अनुसार जीवन का अर्थ साम्य है और इस अर्थ तक पहुँचने के लिए जीवन की जिस पद्धति की रचना की है वह है—योग। कुछ भिन्नकर यह कहा जा सकता है कि विनोबा के शिक्षण का दर्शन साम्ययोग पर आधारित है।

(१४ सितम्बर '७२ को टीचर्स ट्रेनिंग कालेज चाराणसी में दिये गये भाषण से।)

यूरी राइटरव्यू

सुदूर उत्तरी सोवियत के स्कूल

[यूरी राइटरव्यू सोवियत संघ में एक खेलक के रूप में काफी प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म एक खानाबदोश चुक्चा समुद्री शिकारी के परिवार में चुकोत्का प्रायद्वीप में बेरिंग जलडमरूमध्य के तट पर हुआ था। सोवियत सुदूर उत्तर के बारे में उनकी पुस्तकों का चुक्चा से रूसी तथा सोवियत संघ की अनेक दूसरी कौमी भाषाओं में भी प्रकाशन हुआ है।—सम्पादक]

उत्तरी ध्रुव प्रदेश, सैकड़ों-हजार किलोमीटर तक फैला दुष्कृत और ताइगा, नदियाँ और झीलें जहाँ लगभग बारहों महीने बर्फ जमी रहती है, यह प्रदेश जिसकी ध्रुवीय रातें बेहद लम्बी होती हैं, जलवायु अत्यंत कठोर है और जहाँ रहने की परिस्थितियाँ असम्भव जैसी हैं, उत्तर की 'छोटी छोटी कौमो'—चुक्ची और कोरयक, कनाडाई, इण्डियन शेल्कप, सामी, केच, अल्युत तथा अनेक दूसरे कबीलों का देश है, जो आमतौर पर उत्तरी ध्रुव सागर के तट पर बसते हैं। इस सागर का बर्फ जैसा ठण्डा पानी रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, नावो, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के तटों को प्रक्षालित करता है। इन असरम्य तटों पर और उनके निकट मदिषों से शिकारी, मछुए और बारहसिंघों का पालन करनेवाले रहने और वहाँ के क्रूर वातावरण से, न्यूनाधिक सफलता से सघर्ष करते आये हैं।

अब सभी छोटी कौमों की तरह उत्तरी ध्रुव प्रदेश में बसनेवाले इन कौमों को भी इस सदी के आरम्भ में एक विरोधाभासपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। एक ओर तो वे लोमों की सीधे दिलचस्पी का कारण बन गये, और उनके रीति-रिवाजों का वैज्ञानिक सोसाइटियों ने अध्ययन करना शुरू कर दिया, और विद्वानों के साथ-साथ साधारण लोगों ने भी उनकी विदेश संस्कृति में दिलचस्पी दिखायी।

दूसरी ओर, कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने इन कौमों के भविष्य के बारे में गम्भीर चिन्ता दिखायी, विशेषकर इस सत्य के बारे में कि ये प्राचीन लोग, जिनकी जीवन-मदति पितृसत्तात्मक थी, अब विश्व अर्थ-व्यवस्था में बरबस खोबे जा रहे थे, जिसके लिए वे कठईं तैयार नहीं थे, और निरीह थे। यह नहीं कि इस अर्थ-व्यवस्था में वे अपना लिये जायेंगे, बल्कि वे बिल्कुल मिट जायेंगे। यह खतरा उनके सामने था। उकागीर जाति, जिसकी जनसंख्या कभी इतनी बड़ी थी कि किवदन्तियाँ प्रचलित हो गयी थी कि उनके बसंस्थ कैम्पो से उठनेवाली आग की लपटें ध्रुवीय ज्योति को फीका बना देती थी, अब मिटने के करीब थी। सन् १९१७ तक कुल १०० उकागीर ही बाकी रह गये थे—एस्कीमो जाति का एक कबीला इल्लानुल, जो किसी जमाने में कनाडा की बजर भूमि पर निवास करता था—हमारे अपने जमाने में सन् १९५० के दशक में मिट गया।

महागुरु गोरों द्वारा लारी गयी साराब और विभिन्न प्रकार की बीमारियों ने, जिनके विरुद्ध उत्तरी ध्रुव प्रदेशों के लोगों में असक्षमता नहीं थी, निर्दय व्यापारियों द्वारा लनका क्रूर और निर्मम धोषण, लूट और सरकारी की उदासीनता ने उन्नीसवीं सदी के अन्त तक उत्तरी ध्रुव प्रदेश की अनेक छोटी कौमों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से तबाह कर दिया था। अस्तित्व रक्षा के अपने दीर्घकालीन संघर्ष में उन्होंने जिन मूल्यों का विकास किया था और अनुभव की ओ सम्पदा जमा की थी, वह एकाएक ध्वंश हो गये थे। नाव के महान अन्वेषक राइडल अमडसेन ने, जो इन लोगों को अच्छी तरह जानता था, अपनी एक पुस्तक में कहा है “अपने मित्रों, नैचिकली ऐस्किमी लोगों के लिए मेरी सन्देशवाणी शुभकामना यही हो सकती है कि ‘सम्पदा’ उन्हें छुए बगैर ही आगे निकल जाये।”

यह लम्बी भूमिका उन कारणों को पेश करने के लिए जरूरी थी जो एक ऐसी सामाजिक पुष्टभूमि में, जहाँ शिक्षा अब तक अज्ञात थी, स्कूल में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की सफलता के अवसरों पर प्रभाव डालते हैं।

इस सदी के आरम्भ तक उत्तरी ध्रुव प्रदेश की छोटी छोटी कौमों तबाहली समाज व्यवस्था के अन्तर्गत ही रहती थी, और कुछ इलाकों में वे आज भी उसी प्रकार रहती हैं। सन् १९२० ई. बाद जब रूसी अफ्यापको का पहला दल साइबेरिया के साइगा और टुन्डा क्षेत्र में पहुँचा, तब तक स्थानीय खानाबदोश कबीलों ने कभी स्कूल का नाम तक या नहीं सुना था। उत्तरी भाषाओं में ‘स्कूल’ या ‘छात्रालय’ आदि के लिए शब्द ही नहीं थे। उदाहरण के लिए चुक्ची भाषा में

‘सोजने’ आदि के लिए जो शब्द था वह ‘सोखने’ के लिए और ‘किसी विन्दु या शब्द की ओर देखने के लिए जो शब्द था उसका ‘पढ़ने’ के लिए इस्तेमाल किया गया। वहाँ लोग शिक्षा को जरूरी चीज नहीं समझते थे। उन्होंने पूछा, “हम लोग क्यों सीखें? क्या इससे हमारे बारहसिधों का रेवड बड़ा हो जायेगा? और अगर नहीं तो हम लोग स्कूल क्यों जायें? हमें सिर्फ ऐसी तालीम की जरूरत है जो हमारे सड़को को बारहसिधों के रेवड की ओर सड़कियों को रंग की देखभाल करना सिखा सके।”

उनकी स्कूली शिक्षा के मार्ग में एक दूसरी जबरदस्त रुकावट यह थी कि उसरी ध्रुव प्रदेश की बौनों की भाषाएँ अनेक दृष्टियों से विकास की आदिम अवस्था में थी और प्रायः उनमें से कोई भी भाषा लिखी नहीं जाती थी। यह सब उनके सांस्कृतिक पिछड़ेपन, अधिकांशतः मूर्त-चिन्तन और उनके अत्यन्त सीमित विचार क्षितिज के कारण था, जहाँ तक उनके प्राकृतिक परिवेश और उनके पेशों से सम्बद्ध क्रियाओं के वर्णन का प्रश्न था, उनका शब्द-भण्डार काफी समृद्ध था। (शिकारी और भट्टए सरल अमूर्त संज्ञाओं का प्रयोग करते थे, जैसे ‘जंगल’ और ‘नदी’ आदि, उनके साथ ही विभिन्न प्रकार के जंगली, नदियों, नदी के तटों, झीलों और वृक्षदलों को परिभाषित करने के लिए अलग शब्द थे), बारहसिधे पालनेवालों के पास भी बारहसिधों के गर मादा सेक्स, उम्र, रंग और प्रयोजन सूचित करनेवाले शब्द थे।

इन लोगों में सामान्यीकरण तक पहुँचने की असमर्थता की एक दिलचस्प मिसाल थ्योने स्कोरिक के सस्मरणों में दी गयी है, जो एक रूसी अध्यापक था और सन् १९२८ में सुदूर अलास्का से करीब ६० मील की दूरी पर स्थित डेम्नेब अठरीप के वेस्लेन स्थान पर पढ़ाने के लिए गया था।

‘मुझे गणित का वह सबक याद है जिसे मैंने बड़ ध्यान से सीखा किया था, विद्यार्थियों के लिए सबक को दिलचस्प बनाने की खातिर मैं स्थानीय जीवन से मिसालें चुनी थीं। सबक इस तरह शुरू होता था

एक शिकारी से मैंने पूछा, ‘पाँच सोल मछलियाँ मारी, दूसर शिकारी ने तीन मारी। दोनों ने मिलकर कितनी मछलियाँ मारी?’

अचानक चारों ओर से मेरे ऊपर प्रश्नों की बौछार शुरू हुई।

‘उन्होंने सोल मछलियों को क्या मारा?’

‘कल’, मैंने बिना सोचे ही जबाब दिया।

‘कल तो शिकार खेलने कोई भी नहीं गया था। थोड़ा खराब था।’

पाँच सौ लछलियाँ किसने मारी थी ?'

'ल ले न', मेरे दिमाग में जो सबसे बढिया नाम आया, मैंने बताया ।

विद्यार्थियों ने जोर के ठहाके लगाते दुरू किये और मैं भी अनायास उनमें शामिल हो गया । शायद उस कैम्प में लेन्ले सबसे असफल शिकारी था ।

भौगोलिक अलगाव की स्थिति ने भी इन लोगों की शिक्षा के प्रश्न को अधिक जटिल बना दिया था । उत्तरी ध्रुव के लोग आमतौर पर एक दूसरे से दर्जनों और सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे छोटे छोटे समूहों में रहते थे । वे अक्सर जानवरों का पीछा करते हुए या अपने रेवडों के लिए बेहतर खरागाहों की तलाश में स्थानान्तरण करते रहते थे । इसलिए व्यावहारिक रूप से सुदूर उत्तरी प्रदेशों में, जहाँ प्रकृति इतनी निर्दय थी कि कुछ प्रकार के जानवर वहाँ जीवित तक नहीं रह सकते थे, शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना अत्यंत कठिन काम था । (जिनकी घोषणा सन् १९१८ में रूसी फेडरेशन के संविधान में की गयी थी) । करीब बीस सालों तक लगातार आर्थिक सङ्कटनात्मक, शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उठाने के बाद ही वहाँ वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सके ।

उत्तर के सीमावर्ती इलाकों के लोगों की सहायता के लिए सन् १९२० में एक समिति की स्थापना की गयी । इसने उत्तरी ध्रुव प्रदेश की छोटी छोटी कोमों के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा किया । सन् '१० के बाद चौथे दशक के आरम्भ में ही समूचे साइबेरियाई दुष्कृत और वादगा में राष्ट्रीय क्षेत्र स्थापित किये गये, ताकि राज्य के प्रशासनिक कार्य में स्थानीय निवासी पूरा-पूरा भाग ले सकें । इस प्रकार उत्तरी क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए आवश्यकतापूर्ण अनेकविध कार्यक्रम अयनाया गया । कामचलाऊ या आधी अधूरी कार-वाहियों से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता था । सुदूर उत्तरी क्षेत्रों से भेजे गये नौजवानों को मध्य रूस के स्कूलों में बाखिला पाने के लिए वित्ताधिकारी पत्र दिये गये । सन् १९२२ के अगस्त में अनादीर निवासी तन्जियान्तो नाम के एक चुनचा नौजवान को निम्न पत्र दिया गया था, जो बाद में सोवियत संसद में चुनचा बोम का सबसे पहला प्रतिनिधि चुन कर आया था ।

"कम्युक क्षेत्रीय जातिकारी समिति के प्रस्ताव के अनुसार इस पत्र का वाहक चुनचा या अनादीर निवासी तेन्जियान्तो है, जिसे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए रूस भेजा जा रहा है । आशा की जाती है कि कुछ वर्षों के पढ़ाई समाप्त करने पर वह लोगो का वह अपना नया ज्ञान अपनी बोम के लोगों को देगा ।

“तेल्लियान्तो ने अपना सारा जीवन क्रूर और कठोर टुष्ट्रा में, ऐसी परिस्थितियों में गुजारा है जो सिर्फ उत्तर घुवीय प्रदेश में ही मिलती हैं। वह अब जिस देश में भेजा जा रहा है वह अनादीर से बिल्कुल नहीं मिलता। क्रान्तिकारी कमिटी को डर है कि इसी भाषा और स्थानीय रीति-रिवाजों से अपरिचित होने के कारण कहीं उसे ऐसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, जिनको झेलना उसके बस में न हो।

“वह दाखिले के लिए जिनको भी आवेदन पत्र दे, उनसे हमारा आग्रह है कि वे तेल्लियान्तो को हर सम्भव मदद करें। वह उनकी मदद का अधिकारी है। क्योंकि चाहे उसे पढ़ना-लिखना न आता हो, लेकिन इन सारे क्षेत्र के चुन्ना नौवानों में वह सबसे ज्यादा प्रतिभासम्पन्न और जिज्ञासु नौजवान है। एक इसी स्कूल तेल्लियान्तो के अन्दर दबो पड़ो प्रतिभा को उभार कर ऊपर ला सकता है जिससे उसको अपनी कौम को उन्नति करने में मदद मिलेगी।”

तीसरे दशक में लेनिनग्राद में स्थित उत्तरी प्रदेशों की कौमो का इन्स्टीट्यूट अस्थापन का मुख्य केन्द्र बन गया। १९ विद्यार्थियों का (जो उत्तरी प्रदेशों की ११ कौमो से आये थे) सबसे पहला दल सन् १९२५ में भरती हुआ था। सन् १९३० तक इस इन्स्टीट्यूट में विद्यार्थियों की संख्या १९५ हो गयी (जिनमें ५० लड़कियाँ भी थीं), कहना न होगा कि इन सभी विद्यार्थियों को सरकारी वजीफा दिया जाता था।

अपने इसी छात्रियों की मदद से उत्तरी क्षेत्र के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी भाषाओं के लिए लिपियाँ तैयार कीं, ताकि वे मातृभाषा में लिख सकें।

तीसरे दशक के और चौथे दशक के आरम्भ तक सोवियत के सुदूर उत्तरी क्षेत्रों में सर्वत्र सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किये गये। इन केन्द्रों ने वहाँ की अर्थ-व्यवस्था और लोगों की जीवन-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने के लिए बड़ा काम किया। ये केन्द्र ऐसे स्थानों पर कायम किये गये थे, जो बर्फाना हवाओं से सुरक्षित थे और जहाँ नदी या समुद्र के मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता था। हर सांस्कृतिक केन्द्र में एक बोंडिंग, स्कूल, फ़ैक्टरी, अस्पताल, बैकरी, मछली पकड़नेवाले बेटे के लिए भरण-पोषण की दुकानें और मानव के घरों का दल थे।

मैं भी उन बच्चों में से एक था। जब मैं एक नन्हा-सा बालक था और जब मैं मुबह अपना दारण छोड़कर स्कूल के लिए खाना होता दो मानों में एक काल यत्र लेकर सुदूर भविष्य में प्रवेश करने के लिए यात्रा पर निकलता था।

शाम की जब मैं घर लौटता तो वह मुझे हजारों साल पीछे खींच ले जाता

या । मैं वहाँ सील मछली की खाल पर बैठकर एक दिन अपना स्कूल का काम कर रहा था, जबकि मेरे रिश्तेदार मेरे पास बैठे समुद्री पानी से भरे एक घर्तन में समुद्र का टुकड़ा हुबोकर उसकी गतिविधि देख रहे थे, ताकि खाड़ी में समुद्री घाराओं या पूर्वानुमान कर सकें और उथले पानी में सील मछलियों के आने तथा अनेक दूसरी बातों के बारे में भविष्यवाणियाँ कर सकें । वे लाडकूँ के भय बढ-भडा रहे थे और उनकी आवाज मेरी आवाज में घुलमिल गयी थी, क्योंकि मैं उस वक्त जोर-जोर से सोल कर एक कविता बठस्थ कर रहा था । फिर एक मिनट के लिए अपनी कापी अलग रखकर मुझे अपने बुजुर्गों के आगे सिर झुपा कर अपने माथे पर बलि का रक्त मलवाना पडा ।

सन् १९३० में उत्तर के राष्ट्रीय क्षेत्रों और जिलों में निर्विकल्प सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा लागू की गयी । बारहसिंघे पालनेवाले छानाबदोश लोगों के बच्चों के लिए, 'भ्रमणशील' स्कूलों ने हजारों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की । सन् १९३० में स्कूलों की संख्या १२३ थी, जो सन् १९३६ में बढ़कर ५०० तक पहुँच गयी । पौचवें दशक के आरम्भ में स्कूल के पहले और दूसरे वर्षों के लिए छतरी ध्रुव प्रदेश की सभी धीमों के लिए अपनी मातृभाषाओं में पूरी पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित की गयी और कुछ पाठ्यपुस्तकें सोसरे और बोये वर्षों के लिए भी छापी गयी, साथ ही कुछ सहायक पुस्तकें और बाल पुस्तकें भी प्रकाशित की गयी । इनके अलावा स्थानीय भाषाओं में विभिन्न विषयों पर लगभग ६० और पुस्तकें छापी गयी । बाद में १९४५ और १९४८ के बीच स्थानीय भाषाओं में उत्तरी क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रारम्भिक और प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें छापी गयी जिन्हें लिखित भाषा प्राप्त हो गयी थी, और स्थानीय भाषाओं (चुक्चा, एरिक्मो, जोरपक तथा अन्य) का अध्ययन का कार्यक्रम तैयार किया गया ।

सुदूर उत्तर के माध्यमिक स्कूलों में भी शिक्षा का वही प्रोग्राम है, जो सोवियत यूनियन के किसी अन्य भाग के स्कूलों में है। प्रारम्भिक और प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषा में होती है, ताकि चुबचा, एस्क़िमो, नैनेत्स, मासी तथा अन्य कौमों के बच्चे अपनी-अपनी मातृभाषाओं में पढ़ना और लिखना सीख सकें। अपनी प्राथमिक शिक्षा के अंतिम चरण में वे अपनी मातृभाषा के साथ साथ रूसी भाषा सीखते हैं।

यह स्मरण रखना चाहिए कि मातृभाषा में शिक्षा देने से विचार की तर्क-संगत विधि का विकास करने में मदद मिलती है और मातृभाषा में बोझों की आदतें विश्व की एक मौलिक तहवीर बनाती हैं।

अपनी मातृभाषा के इस बुनियादी ज्ञान से विद्यार्थी को लिखने-पढ़ने और गणित में दक्षता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। और, इसी कारण रूसी भाषा बोलने और पढ़ने में भी, जिसको उभे माध्यमिक शिक्षा के दौरान विभिन्न विज्ञानों के बुनियादी तत्त्वों की सुगमवस्थित जानकारी प्राप्त करने के लिए जरूरत पड़ती है। रूसी भाषा सोवियत यूनियन की सभी कौमों के बोझ आदान प्रदान की भाषा है। अपने पुराने ऐतिहासिक रिछडपन के कारण उत्तरी क्षेत्रों के लोगों के लिए रूसी भाषा का विशेष महत्व है, क्योंकि वह उनके लिए ज्ञान और संस्कृति का द्वार खोलती है, जिसके बगैर विज्ञान और तकनीक के तैजों से विकास करते हुए वर्तमान युग में जीवन असम्भव हो जायेगा।

(“यूनेस्को करियर” जुलाई १९७२ से साभार पुनर्मुद्रित)

स्वाधीन भारत में शिक्षा

आज से २५ वर्ष पूर्व जब हम स्वतंत्र हुए थे तब देश में शिक्षा की क्या दशा थी ? उस समय क्या चुनौतियाँ सामन आयी और राष्ट्र के कर्णधारों ने उन्हें किस दृष्टिकोण से देखा, और उन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

इस सन्दर्भ में पहला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देश में सभी स्तरों पर शिक्षा के कार्यक्रमों में बहुत कमो धी, विशेषकर एक स्वाधीन और सर्वप्रभुतासम्पन्न गणतन्त्र के दृष्टिकोण से। उस समय साक्षरता मात्र १४ प्रतिशत थी। प्राथमिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत सीमित था। ६ से ११ की आयु वर्ग के बच्चों में ३ में से केवल एक बच्चा तथा ११ से १४ की आयु वर्ग के बालकों में ११ में से केवल एक ही बालक स्कूल जाता था। माध्यमिक कक्षाओं में १२५ में से केवल एक पठता था और विश्वविद्यालय स्तर पर देश में कुल विद्यार्थियों की संख्या २५६ ००० जयवा इस आयु-वर्ग की संख्या का आधा प्रतिशत थी।

सीमित सुविधाएँ

विज्ञान दृष्टि, दशोन्नियारिग अथवा चिकित्सा की शिक्षा की सुविधाएँ अत्यन्त शून्य थी और छवि, उद्योग तथा स्वास्थ्य सेवासो के उचित विकास के लिए अपर्याप्त थी।

वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की अल्प सुविधाओं से अतिरिक्त देश में लड़कों और लड़कियों की शिक्षा, समाज के प्रगतिशील तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे वर्गों चहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, केरल जैसे प्रगतिशील और उदीसा जैसे पिछड़े राज्यों तथा उन राज्यों में भी उन्नत और पिछड़े जिलों के विकास में अनेक असमानताएँ थी।

प्राचीन काल से ही ज्ञानार्जन के लिए आतुर भारत में उस समय शिक्षा का ध्रमाव था क्योंकि विदेशी सत्ता की लम्बी अवधि के दौरान उस पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय देश के सभी भागों

और सभी वर्गों के लोगों को सबसे पहली माँग यह थी कि उन्हें सभी स्तरों पर अधिक-से-अधिक शिक्षा की सुविधाएँ दी जायें। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें भी इस माँग को पूरा करने के लिए उत्सुक थी और इसीलिए देश के सभी हिस्सों में सभी स्तरों की शिक्षा के प्रसार, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने तथा समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षित बनाने की योजनाओं को अन्य कार्यक्रमों की अपेक्षा प्राथमिकता दी गयी और यह उचित भी था।

दूसरी माँग

इसी के साथ साथ देश में शिक्षा का स्तर उठाने की माँग भी जोर पकड़ रही थी। इस सताब्दी के प्रारम्भिक काल में यह निश्चय किया गया था कि देश में एक विशेष स्तर तक हो शिक्षा-सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी तथा वह लोग जो ऊँचे स्तर की शिक्षा चाहेंगे, उन्हें उन्नतरील देशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी होगी। १९२१ तक इस दृष्टिकोण का विरोध बड़ गया और यह दलील दी जाने लगी कि हम अपने देश में ही उन्नत विस्म के शैक्षिक-संस्थान चला सकने में समर्थ हैं और अपने विद्यार्थियों के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा-सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं।

शिक्षा में आत्मनिर्भरता की यह माँग १९४७ के बाद अधिक तीव्र हो गयी। ऐसा विशेषकर इसीलिए भी हुआ, क्योंकि अब नवयुवकों को उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में भेजना न तो श्रेयस्कर था और न सम्भव ही। यह सच है कि यह दूसरी माँग उतनी हमदार नहीं थी जितनी कि शिक्षा के प्रसार की माँग। जनसाधारण में भी इस माँग के लिए कोई विशेष रुचि न थी। फिर भी देश के वर्णधारियों ने शीघ्र ही इसके महत्त्व की समझ लिया और शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में कुछ ठोस कार्यक्रम जारी किये।

तीसरी माँग

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के ४० वर्ष पूर्व से ही वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवर्तन की माँग चली आ रही थी। अंग्रेजी द्वारा प्रारम्भ की गयी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में कुछ अच्छी बातें भी थी जिन्हें समस्त विश्व ने माना था। किन्तु राष्ट्रीय विचारधारा के नेताओं ने धीरे-धीरे अनुभव कर लिया था कि इसमें कुछ बहुत बड़ी कमजोरियाँ भी हैं। ये देश प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाते तथा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हनन करने में भी प्रयत्नशील हैं। अधिक-से-अधिक इस प्रणाली द्वारा ऐसे लोग उत्पन्न किये जा रहे हैं जो रंग और रक्त से तो भारतीय हैं लेकिन चेतना सभी बातों में अंग्रेज। देश की उत्पादन-शक्ति से इनका तनिक

भो सम्बन्ध न था और इनका मूलतत्त्व यह था कि भारत विलायत को कच्चा माल भेजेगा तथा वहाँ का बना तैयार माल खरीदेगा। अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त उच्च शिक्षा हमारी मूल मान्यताओं को पनपाने में तथा चरित्र-निर्माण में नितान्त असमर्थ थी। पढ़े-लिखे और बुद्धिजीवियों को इसने भारतीय जनमानस से विरत कर दिया और एक ऐसा छोटा वर्ग तैयार करने की चेष्टा की, जो अपने ही देशवासियों का शोषण करता रहे।

अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली की इन मूलभूत कमजोरियों के विरोध में सन् १९०६ में राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन का सूत्रपात किया गया, जब टैगोर ने विश्वभारती तथा पान्तिनिकेतन स्थापित किये, जब गांधीजी ने राष्ट्रीय विद्यालयों की शृंखला का सृजन किया तथा बेसिक शिक्षा का प्रचार किया, जब १९२१ के असहयोग आन्दोलन के अन्तर्गत कुछ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इसीलिए यह माँग मुज़र हुई कि स्वाधीन भारत में सरकार अपनी शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवर्तन करके एक राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का सृजन करे जो हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं पर आधारित हो और जिसके द्वारा देश सत्तार में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके।

प्रसार की चुनौती

इस प्रकार देश की स्वाधीनता के प्रथम प्रभात की बेला में यहाँ की जनता और नेतृत्व के सम्मुख शिक्षा सम्बन्धी तीन बड़ी चुनौतियाँ थीं। यह चुनौतियाँ थी—(१) शिक्षा का प्रसार, (२) शिक्षा के स्तर में सुधार, तथा (३) शिक्षा का स्वरूप में आमूल परिवर्तन। उपरोक्त तीनों चुनौतियों को अच्छी तरह समझा जा चुका था और इसमें कोई संदेह नहीं कि इन सभी चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करने की एक उत्कट इच्छा थी।

शिक्षा के प्रसार की चुनौती को सबसे अधिक सफलता के साथ स्वीकारा गया जिसके फलस्वरूप स्वातन्त्र्योत्तर अवधि में आज हमें चारों ओर शिक्षा की प्रगति दिखाई पड़ती है। इस लेख के अन्त में चार पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शिक्षा-प्रसार के आँकड़े स्वयं ही सत्य को प्रकाशित करेंगे। यदि हम स्वातन्त्र्योत्तर काल के २५ वर्षों की उपलब्धियों पर हो चर्चा करें तो यह बड़े विश्वास के साथ प्रकट हो जायगा कि सभी स्तरों पर शिक्षा का प्रसार अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक रहा है। एक स लेबर पाँच तन की बसाओं में सन् १९४७ में जहाँ शिक्षा पानेवाले बालकों की संख्या एक करोड़ ४१ लाख थी वहाँ आज यह संख्या बढ़कर ६११ लाख हो गयी है—२५० प्रतिशत की वृद्धि। छठी से आठवीं

चक्र की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या २० लाख से बढ़कर १४९ लाख हो गयी है—६५० प्रतिशत। नवीं से ग्यारहवीं कक्षा के बीच आज संख्या ८५ लाख से बढ़कर ८४ लाख हो चुकी है—लगभग ९०० प्रतिशत की वृद्धि, तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भी लगभग इतनी ही वृद्धि हुई है—२५६ लाख से २५४५ लाख तक। ये उपलब्धियाँ कुछ इस प्रकार की हैं जिन पर हरेक भारतीय गर्व कर सकता है।

पिछले २० वर्षों के दौरान देश के कमजोर वर्ग को भी शिक्षा की समुचित सुविधाएँ प्रदान की गयी थी जो उसे कभी नहीं मिली थी। उदाहरणार्थ, स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था में अमृतपूर्व अभिवृद्धि हुई। १९४७ और १९७२ के बीच प्रति १०० बालकों की तुलना में लड़कियों की संख्या ९ से ११ वर्ष के आयुवर्ग में ३५ से बढ़कर ६०, ११ से १४ के आयुवर्ग में १८ में बढ़कर ३८, १४ से १७ के आयुवर्ग में १२ से बढ़कर २८ तथा विश्वविद्यालय स्तर पर ८ से १८ हो गयी है।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा का प्रसार और भी तेज हुआ है। सन् १९६५-६६ में सबसे पहले इसी वर्ष के आँकड़े उपलब्ध हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की सभी स्तरों में मिलाकर संख्या ७६८६ लाख तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या २९६५ लाख थी। प्रति सौ बालकों की संख्या ६८४ प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या ५७५ प्रतिशत थी।

यह सच है कि इन कमजोर वर्गों में प्रारम्भिक स्तरों में अपेक्षाकृत कम बालक-बालिकाओं के नाम स्कूलों में दर्ज कराये जाते हैं तथा आगे के स्तरों पर भी वह अधिक संख्या में पढ़ाई छोड़ देते हैं। अतएव साधारण बालकों की अपेक्षा उनका अनुपात कम होता जाता है। इस पर विगत २५ वर्षों में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो अमृतपूर्व विकास किया है वह सराहनीय है और उस पर गर्व किया जा सकता है।

अन्याय और असमानताओं के बारे में भी यही बात लागू है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा-प्रसार की खाई उन्नतशील तथा पिछड़े हुए राज्यों की असमानताएँ तथा एक राज्य में विभिन्न जिलों में शिक्षा-सुविधाओं में व्याप्त असमानताओं को बहुत हद तक दूर कर दिया गया है, यद्यपि इस क्षेत्र में अभी काफी कुछ करना सेष है।

शिक्षा के स्तरीकरण की चुनौती का सामना भी बड़े प्रभावशाली ढंग से किया गया है यद्यपि उसे आसानी से आकड़ों द्वारा नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन हम कुछ स्पष्ट उदाहरण ले सकते हैं। इण्डियन इस्टीमेट ऑफ टेक्नाजॉजी तथा रोजनल एजोनियरिंग कालेजों की स्थापना और तकनीकी तथा औद्योगिक शिक्षा (पॉलीटेक्निक व इंडियन ट्रेनिंग इस्टीमेट) का सम्पूर्ण ढाँचा स्वातन्त्र्योत्तर काल की ही देन है। इसीके द्वारा तेजी से औद्योगीकरण सम्भव हो सका है और सुरक्षा के मामले में हम आत्मनिर्भर बने हैं। मयो दिल्ली स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान तथा विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा भी हरित क्रांति सम्भव हो सकी है। इण्डियन इस्टीमेट ऑफ मेडिकल साइंसेज तथा विश्वरसा, शिक्षा-सुविधाओं के अभूतपूर्व प्रसारण के परिणामस्वरूप ही स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार सम्भव हुआ है और हम मृत्यु दर को तेजी से घटाने में समर्थ हुए हैं। हमने कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं का सृजन किया है, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद एवं विभिन्न राज्यों के शिक्षा-संस्थान। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का अधिकांश स्वातन्त्र्योत्तर काल की उपलब्धि है।

विज्ञान व औद्योगिक अनुसंधान समिति तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, एटॉमिक एनर्जी कमिशन, सामाजिक विज्ञान तथा ऐतिहासिक अनुसंधान की भारतीय समितियाँ और विश्वविद्यालयों ने अपना स्तर इतना ऊँचा उठा लिया है तथा अनुसंधान कार्य का इतना विस्तार कर लिया है कि द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज देश में सभी स्तरों पर प्रथम श्रेणी की अनेक संस्थाएँ बन गयी हैं। पिछले २५ वर्षों में अनेक विश्वविद्यालयों में उच्च स्तर के विभाग स्थापित हो गये हैं, जिन पर गर्व किया जा सकता है। इस अवधि में सभी स्तरों पर विज्ञान की शिक्षा के समान क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में भी तीव्रता आयी है।

जनता की यह धारणा रही है कि पिछले २५ वर्षों में शिक्षा का स्तर गिर गया है किन्तु यह सत्य नहीं है। यह सच है कि अच्छी संस्थाओं के साथ साथ सभी स्तरों पर नीचे स्तर की संस्थाएँ बड़ी तादाद में बढ़ गयी हैं। इन संस्थाओं की भारी संख्या होने के कारण सम्पूर्ण शिक्षा स्तर के ही गिर जाने का आभास होने लगता है। किन्तु जैसा शिक्षा आयोग द्वारा कहा गया है—“स्वातन्त्र्योत्तर काल में शिक्षा के विकास पर की गयी अधिकतर आलोचनाओं में यह कहा गया-

है कि इसके स्तर में गिरावट आयी है। इसके समर्थन में दो बात कही जाती है। नीचे स्तर की शिक्षा सस्याओं की सख्या में बढ़ोत्तरी और कम योग्यतावाले विद्यार्थियों की अधिक सख्या। इनमें पहली बात बहुत अधिक गम्भीर है और दूसरी बीमारों की जमदायिनी है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिक्षा के विषय में की जानेवाली इस आलोचना में काफी वजन है और हम इसकी गुरुता को घटाना नहीं चाहते, किन्तु इसके दूसरे पहलू की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। इस बात को याद रखना है कि—

कम योग्यतावाले विद्यार्थियों की सख्या में बढ़ोत्तरी की एक वजह यह थी कि अपने बच में पड़नेवाली यह पहली पीढ़ी है, जिसके कारण कुछ दूर तक शिक्षा के स्तर में गिरावट हुई है, किन्तु इनका बड़ी सख्या में माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर की बस्ताओं में प्रवेश, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति का घोटक है।

अभी हाल के कुछ वर्षों के भीतर कुछ विषयों की पढ़ाई में बड़ा विकास किया गया। अच्छे विद्यालय और प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी अब बहुत बड़ी सख्या में तथा इनका स्तर बेसा हो है, यदि अधिक श्रेष्ठ नहीं, जैसे पहले बर्मा हुआ करता था।

समाज में शिक्षा का कुल खाता पहले से किसी भी समय से अब बहुत बड़ा हुआ है।

कुल मिलाकर जो स्थिति है वह सफलताओं और त्रुटियों की, सुधार और गिरावट की, तथा कुछ स्थानों में शिक्षा के स्तर में उन्नति तो दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में अवनति की मिली जुमी तस्वीर है। जहाँ एक ओर हम शिक्षा के स्तर में सुधार की आवश्यकता तथा तत्कालिकता के प्रबल समर्थक हैं वहाँ दूसरी ओर हम यह भी चाहेंगे कि विगत कुछ वर्षों के दौरान उच्च स्तर की शिक्षा की हमारी जो उपजश्रियाँ हैं उन्हें भी स्वीकार किया जाय। वह हमारे लिए प्रेरणा-स्वरूप है तथा मार्गदर्शन भी करती है। वह हमें और साहस के साथ सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सहायक होगी।

शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन

शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन की जो तीसरी चुनौती थी उस ओर सम्भवतः सबसे कम काम हुआ है। आज भी, बावजूद इसके कि स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन के लिए लम्बी-लम्बी बातें होती रहती हैं, शिक्षा का बही स्वरूप बना हुआ है, जो ब्रिटिश शासन काल के दोषन था। पाठ्यक्रम समयानुकूल नहीं है तथा हमारी सामाजिक आवश्यकताओं-आकांक्षाओं से उनका तनिक भी सम्बन्ध नहीं है,

पढ़ान का तरीका वही पुराना और परम्परागत है परीक्षा प्रणाली अपरिवर्तित रही है तथा उमम व्याप्त अनकानव बुराइयों के कारण वह खडखडा कर ढहने वाली है। माध्यमिक स्तरों में पाठ्य पुस्तकों निम्नकोटि की हैं तथा विश्वविद्यालय पर विज्ञानी पुस्तकों की अनिवार्यता को हम दूर नहीं कर सकते हैं। हमारी शिक्षा-प्रणाली अभी भी हमारी मूलभूत मायताओं को उचित प्रकार से प्रकाशित नहीं करती और न हमें अपन राष्ट्रीय रुढ़ियों के प्रति सजग हो करती है। यह अभी तक उत्पादकता के साथ तनिक भी सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पायी है और न यह बुद्धिजीवियों को जनमानस के समीप लाने में समर्थ है। शिक्षा के स्वरूप में आमूक बृहत् परिवर्तन के लिए यदि १९४७ में ही क्रांतिकारी उपाय किये गये होते तो काम अपेक्षाकृत सरल हो जाता क्योंकि उस समय इसका ढाँचा इतना विंगल न था। अब यह काम अत्यन्त कठिन हो गया है तथा प्रतिदिन कठिनतर ही होता जा रहा है। इस बीच, बिना स्तर उठाये या स्वरूप में परिवर्तन किये, शिक्षा के प्रसारण के कारण उच्च विद्यार्थी आन्दोलन, शिक्षित युवकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा शिक्षा पद्धति के प्रति विद्यार्थी वर्ग का विराग ऐसी व्याधियाँ उत्पन्न हो गयी हैं।

भविष्य के लिए सम्बल

स्वतंत्रता की रगत अयन्ती का यह वर्ष केवल लेखा अथवा समीक्षा करने का ही वर्ष नहीं है। यह ऐसा समय भी है जब हम विश्लेषण करें, अपनी सफलताओं असफलताओं के कारणों का अध्ययन करें और भविष्य की कार्यवाही के लिए कुछ साहसपूर्ण निश्चय लें। अतएव पिछले २५ वर्षों के दौरान शिक्षा के विकास के हमारे जो अनुभव हैं उनके आधार पर अपनी शिक्षा के स्वरूप के पुनर्गठन के भावी वागजनों के विषय में हम क्या कह सकते हैं ?

जो पहला बड़ा प्रश्न उभर कर आता है वह यह है १९४७ में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सामने जो विभिन्न चुनौतियाँ थीं उनको कुछत्र क्षेत्रों में हमने उपलब्धता के साथ सामना किया है। यद्यपि यह स्पष्ट ही है कि हमारी सकल शक्तें आधुनिक चुनौतियों के क्षेत्रों में अधिश्रु हैं। कठिनतर समस्याओं के क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियाँ अपेक्षाकृत कम हैं। उदाहरण के लिए तीन मुख्य चुनौतियों में से शिक्षा के प्रसार की समस्या सबसे अधिक आगमन की और इसी क्षेत्र में हमने सर्वाधिक उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। इस क्षेत्र में भी जो अधिक कठिन कार्य था कि इन १४ वर्षों की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक की शिक्षा को स्थापन बनाने तथा प्रीवियों में निरन्तरता का समूल मूला करने, उसमें हम सफल नहीं हो पाये।

शिक्षा के स्तर में सुधार करने का काम और अधिक कठिन था तथा इस क्षेत्र में हमारी उपलब्धियाँ अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली रही हैं। यहाँ यह बता देना उचित ही है कि इस क्षेत्र में भी हमारी सफलता केवल कुछ अच्छे शिक्षा मस्थानों के सृजन तक ही सीमित है (यह अपेक्षाकृत उसी प्रकार सरल है जिस प्रकार एक पुराने नगर का विकास करना)। तथा हम शिक्षा के स्तरों में सुधार नहीं कर पाये (यह इस प्रकार है जैसे कि एक पुराने नगर का पूरी तरह से पुनर्निर्माण)। शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन सबसे अधिक कठिन समस्या थी। इस क्षेत्र में भी हमारी उपलब्धियाँ अत्यन्त निम्न रही हैं। विशाल किन्तु अपेक्षाकृत सरल चुनौतियों की समस्याओं के क्षेत्र के महान सफलताओं न छोटी किन्तु कठिन समस्याओं के क्षेत्र में हमारी असफलताओं को लगभग बराबर कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि सारे के सारे शिक्षा क्षेत्र में ग्वाधियाँ बढ़ गयी हैं।

कठिन दौर

इस प्रकार अब हम अपने शिक्षा के इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। विगत २५ वर्षों में, हममें कोई सन्देह नहीं, हमने अभूतपूर्व काम किये हैं। किन्तु हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि ऐसा हम केवल अपेक्षाकृत सरल क्षेत्रों में ही कर सके हैं। अब कठिन समस्याओं से जूझने का समय आ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन, ६ से १४ वर्ष की आयु के बच्चों के लिए व्यापक रूप से शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध, निरक्षरता को समूल रूप से नष्ट करना तथा सभी और शिक्षा-स्तर में सुधार। निश्चय ही इसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी। किन्तु यह तो उस कहानी का छोटी-सा भाग ही है। हमें अन्य जो आवश्यकताएँ होंगी अपने शिक्षा के क्षेत्र में यह है। नियोजन तथा प्रशासन की क्षमता, कठिन परिश्रम, उत्सर्ग की भावना से ओतप्रोत अध्यापक वर्ग, विद्यार्थी तथा प्रशासकजन एवं आदर्शवाद तथा सचेष्टता का वातावरण।

शिक्षा के क्षेत्र से बाहर सशक्त और स्थायी सरकारों तथा निरन्तर आर्थिक प्रगति की आवश्यकता भी है। थीमती इंदिरा गाँधी के धाँक में आ जान तथा उनके महान् और सुधारवादी नेतृत्व के कारण उपरोक्त नयी समस्याएँ सुलझ हो जायेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में लगे कार्यकर्ताओं के सामने अब पहला मुख्य प्रश्न यह है कि वह शिक्षा के स्वरूप के परिवर्तन के लिए प्रथम प्रयास कहाँ, कब और कैसे करे। यह हमारे लिए चुनौती भी है और अवसर भी। पचासवीं पंचवर्षीय योजना इस बात की कसौटी होगी कि हम समस्या के अनुरूप अपने आपको ढालकर इसका निवारण कर सकते हैं। ●

आचार्य कुल की गतिविधि

चम्बल घाटी में डाकू-समर्पण और उसके बाद की परिस्थिति के आकलन की दृष्टि से वहाँ एक नयी बुनियाद पर काम आरम्भ करना होगा। लगभग ५०० डाकुओं ने ज़िम तरह से आत्म-समर्पण किया है वह अपने आपमें दुनिया के इतिहास की बेजोड़ घटना हुई है और उसके उत्तर-प्रभाव अत्यन्त गहरे हुए हैं। उन प्रभावों का रचनात्मक संगठन और दिशा-निर्देशन होना अत्यावश्यक है, वरना वे समाज पर अनेक नकारात्मक प्रभाव भी पैदा कर सकते हैं। इस एह-सास के कारण ही मध्य प्रदेश सर्वोदय मण्डल और अन्य रचनात्मक संस्थाओं ने यह निश्चय किया कि इस क्षेत्र में सर्वोदय की प्रवृत्तियों को सघन और सक्रिय किया जाय।

मध्य प्रदेश आचार्यकुल ने भी इस संदर्भ में अपनी भूमिका निभाने की दृष्टि से कुछ कार्य आरम्भ करने का निश्चय किया है। सर्वोदय मण्डल और आचार्यकुल के आमंत्रण पर मैं गत ८ अगस्त से २९ अगस्त तक उस क्षेत्र के खालियार और शिवपुरी जिलों में श्री दादा भाई की यात्रा में साथ घूमा। मेरी यह यात्रा एक छात्र की अध्ययन-यात्रा ही थी। अपने अध्ययन के आधार पर आगे के काम की दृष्टि से कुछ बातें मैं सुझाव के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ :

१. सतत पदयात्रा का कार्यक्रम जारी रहना चाहिए। इन यात्राओं में राहत कार्यों के बजाय ग्रामस्वराज्य (ग्रामसभाओं तथा ग्रामकोष और शान्तिसेना के गठन के) कार्य पर जोर दिया जाना चाहिए। हर गाँव में ऐसी सदस्य ग्राम सभाएँ बनें और हर प्रकार के राहत-कार्य उसके ही माध्यम से हो, सरकार यह मान्य करे।

२. शिक्षकों, पंचायत सेवकों, ग्रामसेवकों, सरपंचों और प्रमुख नागरिकों की पंचायत या दो पंचायतस्तरीय त्रिदिवसीय शिविर शृंखलाएँ चलायी जायें।

क्षेत्र के विद्यार्थियों में आचार्यकुल और तरुण-शान्तिसेना या गठन करने और उनके भी शिविर खोलने का एक शृंखलाबद्ध कार्यक्रम आचार्यकुल और शान्ति सेना मण्डल चलाये। फिर आचार्यकुल के माध्यम से गाँवों में रात्रि पाठ-शालाएँ चलाए जा सकें का पहला काम धारा में लिया जाय।

३. क्षेत्र के हर ज़िले में कम-से-कम एक प्रखण्ड स्तर पर ग्रामस्वराज्य का सघन कार्य किया जाय और उसे प्रगंड स्वराज्य संगठन तक पहुँचाये बिना न छोड़ा

जाय। जोग स्थित माई श्री सुवबारावजी का आश्रम यह काम उठाये। सर्व सेवा संघ इस कार्य को भी राष्ट्रीय स्तर पर उठाये। मध्य प्रदेश गांधी निधि के पास बहुत अच्छे अनुभवी कार्यकर्ताओं को एक बड़ी टीम है वह, इस काम में लगे। चम्पल घाटी शान्ति मिशन अब राहत कार्यों में अधिक न फँसकर इस बुनियादी कार्य में लगे। राहत कार्य तो सरकार भी कर सकती है और उसने उसके लिए ही विवाम घोटें बना लिया है। मिशन के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के प्रशिक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है। वह किया जाना चाहिए।

४ डाकू लोगों को आज जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह जारी रहे। श्रद्धेय सरता बहन और श्री काशीनाथजी त्रिवेदी ने इस दिशा में अत्यन्त ही मूल्यवान् भूमिका निभायी। किन्तु जेल से छूटने के बाद भी उनसे सम्पर्क बना रहे, यह आवश्यक है। उन्हें जेल में और बाहर भी पढ़ाने-लिखाने की व्यवस्था बने और उन्हें सर्वोदय मित्र, सहयोगी, लोकसेवक आदि के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

मुझे आशा है कि इन कार्यक्रमों के आधार पर डाकू-समर्पण से उत्पन्न सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक परिस्थिति का रचनात्मक उपयोग किया जा सकेगा।

—कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

उत्तराखण्ड सर्वोदय मण्डल का निर्णय

पिछले वर्षों में यद्यपि सभी गांधी अपने अपने क्षेत्रों में अपने-अपने ढंग से कार्य करते रहे हैं, परन्तु सम्मिलित पुरुषार्थ से कोई काम नहीं हो पाया, अतः पूरे उत्तराखण्ड में ग्रामस्वराज्य के काम को फिर से गति देने के लिए पहले कदम के रूप में आचार्यकुल व तरुणशक्ति सेना के संगठन के काम को हाथ में लेने की आवश्यकता महसूस की गयी। तय किया गया कि पूरे उत्तराखण्ड क्षेत्र में इस काम की जिम्मेदारी श्री योगेश चन्द्र बहुगुणा लें। इस निर्णय के आधार पर दिसम्बर '७२ तक का कार्य क्रम इस प्रकार बनाया गया है।

२ अक्टूबर से ९ अक्टूबर—जिला टिहरी

२० अक्टूबर से २८ अक्टूबर—जिला देहरादून

७ नवम्बर से १५ नवम्बर—जिला अल्मोड़ा

२१ अक्टूबर से ६ नवम्बर—जिला पौड़ी

सम्पादक मण्डल :

श्री घीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक
श्री वशीधर श्रीवास्तव
आचार्य राममूर्ति

वर्ष : २१

अंक . ३

मूल्य : ७० पैसे

अनुक्रम

३२०० करोड़ रुपये की शिक्षा योजना	१७ सम्पादकीय
शिक्षा का माध्यम	१०१ श्री मो० क० गांधी
शिक्षा की सरचना	१०२ " "
शोषणरहित बुनियादी तालीम	१०३ श्री काका वाणेलकर
वाराणसी के शिक्षकों के बीच जे० पी०	१०७
लोकार्पण के जापूष्क ग्रंथी जयप्रकाश ना०	१०९ श्री दादाधर्माधिकारी
शिक्षा के मानवीय आयाम	११६ श्री गंगाराम देसाई
मुद्रर उत्तरी सोवियत के स्कूल	१२७ " श्री राधकृष्ण
स्वतंत्र भारत में शिक्षा	१३४ " जे० पी० नायक
आचार्यकुल की गतिविधि	१४२ " कमेश्वर प्र० बहुगुणा

अक्टूबर, '५२

- 'नयी तालीम' का वष अगस्त से प्रारम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक खन्दा बाठ रुपये है और एक अंक में ७० पैसे ।
- पत्र व्यवहार करते समय बाहक अपनी बाहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

भा आरुणिक मद्र, द्वारा रचित सेवा सत्र के लिए प्रकाशित,
अनुपम प्रेस, के ११/३० दुगावाट, वाराणसी में मुद्रित

आठवें दर्जे से अनिवार्य अंग्रेजी हटाओ

मैं गत २७ सितम्बर १९७२ को कलकत्ता में जब पटना आया तो बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री रामदयाल पाण्डेय ने मिलकर मुझे सूचित किया कि बिहार सरकार ने अंग्रेजी की शिक्षा एवं उत्तीर्णता आठवें दर्जे से लेकर माध्यमिक उच्च विद्यालय परीक्षा तक पुनः अनिवार्य कर दी है !.....

मैं इस प्रश्न पर काफी विचार करने के पश्चात् यह बसन्तव्य प्रकाशित कर रहा हूँ। मेरा यह निश्चित मत है कि स्वतन्त्र देश में कोई विदेशी भाषा अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए !.....

शायद मुख्य मंत्री और उनकी सरकार का यह तर्क है कि अखिल भारतीय सेवाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में बिहार के शिक्षितों को स्थान दिलाने के लिए शिक्षा में त्रिभाषा सिद्धान्त को लागू करने के लिए अंग्रेजी की शिक्षा को अनिवार्य करना आवश्यक है। परन्तु मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अनिवार्यता अंग्रेजी पढ़ने से ही उक्त सेवाओं में स्थान मिलने की अनिवार्यता नहीं हो जायेगी !...

जहाँ तक त्रिभाषा-सिद्धान्त को लागू करने की बात है मातृभाषा तथा राज्यभाषा की शिक्षा के साथ कुछ भाषाओं का एक वर्ग निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें से तीसरी भाषा का चयन शिक्षार्थी तथा उनके अभिभावक अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। हाँ, इस तीसरे वर्ग की भाषाओं में अंग्रेजी का भी स्थान हो सकता है !.

मेरा यह सुनिश्चित मत है कि विदेशी भाषा के अनिवार्य रहने पर हमारे शिक्षार्थियों में राष्ट्रीय स्वाभिमान का विकास नहीं हो सकता। स्वतन्त्र भारत में अंग्रेजी का अनिवार्य करना वस्तुतः राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतिकूल है। ...

—जयप्रकाश नारायण

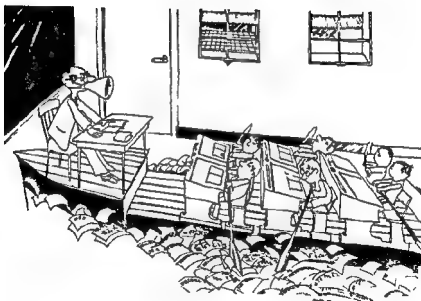
नयी तालीम

सर्व सेवा-संघ की मासिकी

वर्ष : २१

अंक : ४

नवम्बर, १९७२



राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन : सेवाग्राम
विशेष अंक

राष्ट्र की शिक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी

जिस सेवामाग में बापू ने गुलामी के दिनों में नयी तालीम बुनियादी शिक्षा का विचार देश और दुनिया को दिया था उसी सेवामाग में फिर एकबार स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा का नारा सुलन्द हुआ है। यह बात अब कहने का नहीं रह गयी है कि हमारे देश में जो शिक्षा है उसे किसी अर्थ में राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्र राष्ट्र को राष्ट्रीय शिक्षा चाहिए।

हम राष्ट्रीय शिक्षा किसे कहेंगे ? १४, १५, १६ अक्टूबर को सेवामाग में राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा कि हमारी शिक्षा हमारे राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ी हुई हानी चाहिए। यह हर एक जानता है कि प्रचलित शिक्षा वास्तविकताओं से जुड़ी हुई नहीं है। इस शिक्षा से देश का मामूली अहित नहीं हुआ है। नये गुणों का विकास तो दूर, जो गुण तथा जो क्षमताएँ मनुष्य सहज रूप से अपने परिवार, समाज, देश की परम्पराओं से प्राप्त और विकसित करता है, भले ही वह कभी किसी स्कूल में न गया हो, उन्हें भी यह शिक्षा कायम नहीं रहने देती। देश के करोड़ों युवकों युवनियों को यह शिक्षा अ भारतीय, अ मानवीय अ वैज्ञानिक घना रही है। न उनका चित्त भारतीय रह पाता है, न उनकी प्रेरणाएँ मानवीय हो पाती हैं और न उनका मस्तिष्क ही वैज्ञानिक घन पाता है। ऐसी शिक्षा को लेकर राष्ट्र क्या करेगा ?

राष्ट्रीय शिक्षा वह है जिसका राष्ट्र की परंपरा,

वर्ष : २१

अंक : ४

राष्ट्र की प्रतिभा, और राष्ट्र को परिस्थिति से मेल हो। हमारी देश की परंपरा सह-अस्तित्व की है। भारत ने जाति या धर्म के नाम में कभी किसी समूह का सहार नहीं किया है। उसने समाज के व्यापक घुत्त में हर एक को स्थान दिया है। हमारी प्रतिभा ने हमेशा अनेकता में एकता की खोज की है। अनेकता को कभी उसने वर्जित नहीं किया है। आज हमारे देश की परिस्थिति यह माग कर रही है कि हम समता और समृद्धि का समाज बनायें, देश के जन जन की अभाव, अज्ञान और अन्याय से मुक्त करें।

गांधीजी ने कहा था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उत्पादन, प्रकृति, और समाज से अनुबधित हो। यह अनुबंध जीवन का है। जीवन के इस अनुबंध को छाड़कर शिक्षा तोता-रट के सिवाय दूसरा क्या रह जाती है? आज इतने वर्षों के बाद हम राष्ट्रीय शिक्षा के नाम में उसी सत्य को दोहरा रहे हैं जिसे पैंतीस वर्ष पहिले गांधीजी ने नयी तालीम का नाम से हमारे सामने प्रस्तुत किया था। लोकतंत्र और समाजवाद जैसे लक्ष्य घोषित करनेवाले भारत के लिए नयी तालीम तो चाहिए ही बल्कि नित्य नया तालीम चाहिए। नित्य नयी तालीम के बिना हमारे-जैसा पिछड़ा देश दुनिया के साथ नहीं चल सकेगा। हमारे और उन्नत ससार के बीच बहुत बड़ी दूरी है जिसे हमें तय करना है। अब भारत दुनिया का लगभग सबसे गरीब देश है। इस दयनीय स्थिति को हम कबतक दर्शात करेंगे?

एक गरम देश जिसकी आधी जनता कगालियत की जिन्दगी बिता रही हो, और उस अनुत्पान्दक शिक्षा : भला इन दोनों का मेल बैठ सकता है? जिस देश की तीन-चौथाई जनता खेती पर जीती हो उसमें लोगों की क्या काम मिलेगा, क्या काम मिलेगा और क्या आराम मिलेगा? विज्ञान ने जीविका के जो असंख्य साधन बनाये हैं वे सब विवेक के साथ, अपनी परिस्थिति के अनुसार हमें अपने लिए प्राप्त करने हैं। यह तब सम्भव होगा जब शिक्षा में नीचे से ऊपर तक हर विद्यार्थी किसी-न किसी उत्पादक हुनर में निपुण हो। इतना ही नहीं, जैसाकि प्रधान मंत्री ने सेवाग्राम में कहा, हर फार्म, हर करखाना, तथा निर्माण का हर प्रोजेक्ट शिक्षण का केन्द्र और माध्यम हो। एक बार शिक्षण को यह मोड़ दे दिया जाय तो उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग कोशिश नहीं

करनी पड़ेगी, न शरीर-राम का महत्व सिग्याना पड़ेगा; न ऊँच नीच का भेद मिटाने के लिए भाग्य देने पड़ेगे और, न नीचरी पागे के लिए किसी तरह हिमी बढोरने की होद रह जायेगी। शिक्षा अपने पैर पर खडा होने के लिए है, प्रचुद्ध नागरिक बनने के लिए है; मात्र नीचरी के लिए नहीं है। इन गुणों की शिक्षा से जो समाज घनेगा वह उत्पादकों का भास्चारा होगा, शोषकों और शोषितों का संघर्ष क्षेत्र नहीं रहेगा। नयी शिक्षा और नया जीवन दोनों एक हो जायेंगे।

ज्ञान शिक्षक की बागी या विद्वान के ग्रन्थ में नहीं है। इनमें भी है, लेकिन इनमें ही नहीं है। ज्ञान अनुबन्ध के उस कृत में है जिसमें मनुष्य की क्रियाएँ, मृत्यु रूप से जीविषा की क्रियाएँ, तथा उसमें चारों ओर की प्रकृति और सुमान है। यह शरीर ही है। न मूल स्रोत है। सारे ज्ञान विज्ञान इसी स्रोत में निकले हैं। शिक्षा का काम है शिक्षार्थी को सहज रूप से आदर्श, प्रकृति और समाज के अनुबन्ध (कारिलेशन) ज्ञान के इस में अक्षय स्रोत तक पहुचने देना, न कि नियमों, पुस्तकों और परीक्षाओं के चक्कर में फँसाकर उसकी शक्तियों को समाप्त करना। विज्ञान खुद नियमों और पुस्तकों में फँसकर नहीं रहता। वह सीमाओं को तोड़कर ज्ञान तक पहुचता है। इसके विपरीत हमारी शिक्षा हमारे और हमारे ज्ञान के बीच नया-नयी दीवारें खड़ी कर दी हैं। जीवन समझ है, समझाना समझ है, उनके समाधान समझ हैं। तो शिक्षा समझ हुए बिना रह सकती है ?

हमारे देश की शिक्षा ऐसे बिन्दु पर है जहाँ यह या तो देश का घास्तिकता के साथ जुड़कर उसके विश्वास और नय-निर्माण का साधन बनेगी या सत्ता से जुड़कर उसकी दासी रहेगी। बीच की कोई स्थिति नहीं है। सेनाग्राम-सम्मेलन ने घोषणा की है कि शिक्षा में सरकार का काम से कम हस्तक्षेप हो। हस्तक्षेप जोडा भी क्यों हो ? अगर अभ्यास क्रम में आवश्यक सुधार हो जायें तो कोई कारण नहीं कि व्यवस्था के लिए हर विद्यालय शिक्षक-शिक्षार्थी-अभिभावक को एक स्वायत्त इकाई न बन सके। अगर लोपतन्त्र का अभ्यास स्वायत्त विद्यालय में नहीं होगा तो और कहाँ होगा ? सहकारी व्यवस्था, सर्वसम्मति निर्णय, असहमति, विरोध, यहाँ तक कि शान्तिपूर्ण प्रतिवार के भी शिक्षण और अभ्यास की सुविधा विद्यालय में होनी चाहिए। सरकार के शिक्षा में

राष्ट्र की प्रतिभा, और राष्ट्र की परिस्थिति से मेल हो। हमारी देश की परंपरा सह-अस्तित्व की है। भारत ने जाति या धर्म के नाम में कभी किसी समूह का संहार नहीं किया है। उसने समाज के व्यापक वर्ग में हर एक को स्थान दिया है। हमारी प्रतिभा ने हमेशा अनेकता में एकता की खोज की है। अनेकता को कभी उसने वर्जित नहीं किया है। आज हमारे देश की परिस्थिति यह मांग कर रही है कि हम समता और समृद्धि का समाज बनायें, देश के जन-जन को अभाव, अज्ञान और अन्याय से मुक्त करें।

गांधीजी ने कहा था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उत्पादन, प्रकृति, और समाज से अनुबंधित हो। यह अनुबंध जीवन का है। जीवन के इस अनुबंध को छोड़कर शिक्षा तोता-रट के सिवाय दूसरा क्या रह जाती है? आज इतने वर्षों के बाद हम राष्ट्रीय शिक्षा के नाम में वही सत्य को दोहरा रहे हैं जिसे पैंतीस वर्ष पहले गांधीजी ने नयी तालीम का नाम से हमारे सामने प्रस्तुत किया था। लोकतंत्र और समाजवाद जैसे लक्ष्य घोषित करनेवाले भारत के लिए नयी तालीम तो चाहिए ही बल्कि नित्य नया तालीम चाहिए। नित्य नयी तालीम के बिना हमारे-जैसा पिछड़ा देश दुनिया के साथ नहीं चल सकेगा। हमारे और उन्नत संसार के बीच बहुत बड़ी दूरी है जिसे हमें तय करना है। अब भारत दुनिया का लगभग सबसे गरीब देश है। इस वयनीय स्थिति को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे?

एक तरफ देश जिसकी आधी जनता कगालियत की जिन्दगी बिता रही हो, और उस अनुत्पादक शिक्षा : भला इन दोनों का मेल बैठ सकता है? जिस देश की तीन-चौथाई जनता खेतों पर जीती हो उसमें लोगों को क्या काम मिलेगा, क्या काम मिलेगा और क्या आराम मिलेगा? विज्ञान ने जीविका के वो असंख्य साधन बनाये हैं वे सब विवेक के साथ, अपनी परिस्थिति के अनुसार हमें अपने लिए प्राप्त करने हैं। यह सब सम्भव होगा जब शिक्षा में नीचे से ऊपर तक हर विद्यार्थी किसी-न किसी उत्पादक छुनर में निपुण हो। इतना ही नहीं, जैसाकि प्रधान मंत्री ने सेनाग्राम में कहा, हर फार्म, हर करखाना, तथा निर्माण का हर प्रोजेक्ट शिक्षण का केन्द्र और माध्यम हो। एक बार शिक्षण को यह मोड़ दे दिया जाय तो उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग कोशिश नहीं

करनी पड़ेगी, न शरीर थम का महत्व सिखाना पड़ेगा, न ऊँच नीच का भेद मिटाने के लिए भाषण देने पड़ेगे और, न नौकरी पाने के लिए किसी तरह डिग्री घटोरने की होड़ रह जायेगी। शिक्षा अपने पैर पर खड़ा होने के लिए है, प्रबुद्ध नागरिक बनने के लिए है; मात्र नौकरी के लिए नहीं है। इन गुणों की शिक्षा से जो समाज घनेगा वह उत्पादकों का भाईचारा होगा, शोषकों और शोषितों का संघर्ष क्षेत्र नहीं रहेगा। नयी शिक्षा और नया जीवन दोनों एक हो जायेंगे।

ज्ञान शिक्षक की चाणी या विद्वान के ग्रन्थ में नहीं है। इनमें भी है, लेकिन इनमें ही नहीं है। ज्ञान अनुबन्ध के उस वृत्त में है जिसमें मनुष्य की क्रियाएँ, मुख्य रूप से जीविका की क्रियाएँ, तथा उसके चारों ओर की प्रकृति और समाज है। यह तभी हो ज्ञान का मूल स्रोत है। सारे ज्ञान विज्ञान इसी स्रोत से निकले हैं। शिक्षा का काम है शिक्षार्थी को सहज रूप से उत्पादन, प्रकृति और समाज के अनुबन्ध (एन्वारिलेशन) ज्ञान के इस से अक्षय स्रोत तक पहुँचने देना, न कि विषयों, पुस्तकों और परीक्षाओं के चक्कर में फँसाकर उसकी शक्तियों को समाप्त करना। विज्ञान खुद विषयों और पुस्तकों में फँसर नहीं रहता। वह सीमाओं को तोड़कर ज्ञान तक पहुँचता है। इसके विपरीत हमारी शिक्षा हमारे और हमारे ज्ञान के बीच नयी-नयी दीवारें खड़ी कर दी हैं। जीवन समग्र है, समस्याएँ समग्र हैं, उनके समाधान समग्र हैं। तो शिक्षा समग्र हुए बिना रह सकती है?

हमारे देश की शिक्षा ऐसे बिन्दु पर है जहाँ वह या तो देश का घातविधता के साथ जुड़कर उसके विकास और नए निर्माण का साधन बनेगी या सत्ता से जुड़कर उसकी दासी रहेगी। बीच की कोई स्थिति नहीं है। सेनाग्राम-सम्मेलन ने घोषणा की है कि शिक्षा में सरकार का धर्म से कम हस्तक्षेप हो। हस्तक्षेप थोड़ा भी क्यों हो? अगर अभ्यास क्रम में आवश्यक सुधार हो जायें तो कोई कारण नहीं कि व्यवस्था के लिए हर विद्यालय शिक्षक-शिक्षार्थी-अभिभावक को एक स्वायत्त इकाई न बन सके। अगर लोकतन्त्र का अभ्यास स्वायत्त विद्यालय में नहीं होगा तो और कहाँ होगा? सहकारी व्यवस्था, सर्वसम्मति निर्णय, असहमति, विरोध, यहाँ तक कि शांतिपूर्ण प्रतिहार के भी शिक्षण और अभ्यास की सुविधा विद्यालय में होनी चाहिए। सरकार के शिक्षा में

को ही मुख्य काम है—आर्थिक सहायता, और 'कोआइनेशन'। सच्चे लोकतन्त्र और समाजवाद को मानने वाली सरकार को इन्हें से संतोष मानना चाहिए। इसके बाद समाज का दायरा है, सरकार का नहीं। शिक्षा के सरकारीकरण का अर्थ है दिमाग या सरकारीकरण। दिमाग भी सरकार का हो जाये तो समाज के पास दूसरा रह क्या जाता है ?

सेनाग्राम का सम्मेलन हो चुका। यह मित्र हो गया कि राष्ट्रीय शिक्षा के युनियादी मुद्दों पर मतों की काफी गूढ़ता है। जिस सम्मेलन में अनेक शिक्षामंत्री थे, विद्याविद्यालयों के उप मुखपति थे, शिक्षक और समाजसेवक थे उसको सिफारिशों पर अमल होना चाहिए—अविलम्ब होना चाहिए। यह देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के देखने का काम है कि अमल हो। निरन्त्री शिक्षा लेने से विद्यार्थियों को, देने से शिक्षकों का, दिलाने से अभिभावकों को इनकार करना चाहिए। अगर विद्यालय महोनों यों ही हड़ताल में बन्द रह सकते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा के लिए उन्हें कुछ दिन तक बन्द रहना पड़े तो क्या बिगड़ जायेगा ! सरकार अपनी है इसीलिए समाज उसे गलत-सही कुछ भी करने का अधिकार नहीं दे सकता। देश का भाग्य देश के लाखों गाँवों और शहरों में है, इन्हीं-गिनी राजधानियों में नहीं। राष्ट्र की शिक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी है।

—राममूर्ति

बुनियादी शिक्षा का क्रमिक विकास

आज से करीब ३५ साल पहले मध-निषेध की आर्थिक दृष्टि से आलोचना करते हुए महारमा गांधीजी ने राष्ट्र से कहा था, 'प्रत्येक बालक में जो थोड़ा तत्व है उसकी सहायता से ही उसका सर्वांगीण मानी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास करना, यही शिक्षा का एकमात्र ध्येय होना चाहिए।' यह कहते समय महात्माजी के मन में पक्की श्रद्धा थी कि मानव के मन का उच्चतम विकास सभी शक्य है जब बालक को यत्नत नहीं, किन्तु वैज्ञानिक ढंग से ही हस्तोद्योग सिखाया जाय। बाद में 'हरिजन' के अपने सम्पादकीय लेख में भी उन्होंने शिक्षा के क्रांतिकारी सिद्धान्त की विशदतापूर्ण स्पष्टता की थी और कहा था, 'ऐसी शिक्षा एक ऐसे शान्त सामाजिक परिवर्तन का आधारबिन्दु है जो न्यायपूर्ण और शोषण-विहीन समाज रचना की आधारशिला बन सकती है।'

अखबारों में और अनेक सभाओं में गांधीजी के इन विचारों की काफी चर्चा हुई। जनता ने इसने बारे में आलोचनाएँ की। इन सभी बातों पर गांधीजी ने बहुत धाँति से ध्यान दिया और हर एक को अपनी स्वभावगत गम्भीरता से उत्तर भी दिये। इस विषय पर विशेष विचार हो सके इसलिए उन्होंने अक्टूबर १९३७ में वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन बुलाया। राष्ट्र ने विद्वान एवं पारंगत शिक्षा-शास्त्री, विविध राज्यों के शिक्षामन्त्री और शिक्षा जगत के सक्रिय कार्यकर्ता इस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। गांधीजी स्वयं इस सम्मेलन के सभापति थे। बहुत कुछ विचार-विमर्श के बाद सभा ने गांधीजी के विचारों को अनुमोदन दिया और स्व० डा० जाकिरहुसेन की रहबरी के नीचे अभ्यासक्रम निर्माण समिति बनायी गयी। फरवरी १९३८ में समिति ने गांधीजी को अपनी रिपोर्ट दी और बाबू ने उसे मान्यता देकर हरिपुर कांग्रेस की बैठक में स्वीकृति के लिए पेश किया। महासभा ने समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकृति दी। कांग्रेस ने अपनी शिक्षा की नीति के रूप में उसको स्वीकार करके तत्काल अमल के लिए गांधीजी के मार्गदर्शन में अखिल भारत समिति की नियुक्ति कर दी। इस समिति के अध्यक्ष डा० जाकिरहुसेन थे और मंत्री थे श्री आर्यनाथय्यम्।

इसी तरह अग्रेल १९३८ में सेवाग्राम, वर्धा में 'हिन्दुस्तानी तालीमो सभ' की स्थापना हुई। प्रयोगों के द्वारा इस नये विचार की सिद्धान्तों को प्रस्थापित करना उसका पहला काम था। सेवाग्राम में 'नयी तालीम' संस्था की स्थापना हुई। उसके बाद कई प्रांतों में भी उसका अनुकरण हुआ और नयी तालीम के क्षेत्र में प्रयोग होने लग। प्रांतीय सरकारों ने अपने अपने प्रदेश में बुनियादी शिक्षा का प्रारम्भ किया और कश्मीर, विल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और मद्रास में गैर-सरकारी संस्थाओं ने बुनियादी शिक्षाएँ शुरू की।

सन् १९३९ में जब पहला सम्मेलन पूना में हुआ तो अध्यक्ष ने कहा, 'शिक्षा का कह नया आदर्श न्याय, सहकार, उत्पादक धर्म और प्रत्येक मानव की ओर सम्मान की भावना पर आधारित है और ऐसी ही शिक्षा शान्ति, न्याय एवं मानवता की सबसे अधिक प्रत्याभूति (गारण्टी) है।' सन् १९४० में जामिया नगर के द्वितीय सम्मेलन के समय गांधीजी ने यही बात कही कि हमारे इन प्रयत्नों की सफलता का आधार आत्मनिर्भरता है, सरकारी सहायता नहीं। इस सिद्धान्त से इस दिशा में कई प्रांतों में जो प्रयत्न शुरू किये गये थे वे बढ़ हो गये। केवल बिहार के चम्पारण जिले में यह प्रयोग जारी रखा गया, क्योंकि इसका राज्य के बहुत ही नजदीक था। १९४२ का समय सारे राष्ट्र के लिए

अस्थिरता वा काल था। इसका महत्त्व असर नयी तालीम के क्षेत्र में भी हुआ। सत्पाएँ बन्द हुईं, हमारे कई कार्यकर्ता भाई-बहन कारागृह में थे और कुछ समय के लिए तो ऐसा ज्ञात होता था मानो हमारे राष्ट्रीय जीवन में नयी तालीम का चित्र धुँधला पड़ गया है।

लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि ऐसी अग्नि-परीक्षा से नयी तालीम विरोध शक्ति सम्पन्न बनकर बाहर आयी। उसी समय नये दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर गांधीजी ने कहा कि “नयी तालीम माँ-बाप को शिक्षित करने के लिए घर घर पहुँचनी चाहिए।” उनका कहने का तात्पर्य यह था कि नया तालीम अवरण जीवन की तालीम बन जानी चाहिए। अपना यह मतव्य विरोध स्पष्टता से समझाने हुए गांधीजी ने बाद में कहा था कि एक ऐसी तालीम होनी चाहिए जो जीवन के लिए, जीवन व्यवहार द्वारा प्राप्त हो सके। इसलिए इस शिक्षा-पद्धति में जीवन की प्रत्येक अवस्था में हर एक व्यक्ति को शिक्षा का विचार एवं आयोजन होना अत्यन्त आवश्यक है।

सेवाग्राम में और कई अन्य स्थानों पर इस नये सिद्धान्त पर आधारित प्रयोग किये गये और जब अधिक स्पष्टता को अलरत हुई तो १९४५ में सेवाग्राम के सम्मेलन में उन्होंने कहा, ‘नयी तालीम का केन्द्र ग्राम्य विस्तार और उसका माध्यम ग्रामोद्योग होना चाहिए। उसमें बालक के गर्माधान से लेकर उसकी मृत्यु तक की शिक्षा का प्रबन्ध होना जरूरी है।’ गांधीजी कि इस मतव्य का अर्थ यही हुआ कि नयी तालीम के क्षेत्र में काम करनेवाला शिक्षक ग्राम जनता का सच्चा सेवक हो और इस तालीम का खर्च इसके सामन कितना हा विरोध बना न हो, शिक्षा म से ही निकलना चाहिए। गांधीजी की ध्वा थी कि अगर यह शिक्षा सुयोग्य ढंग और पद्धति से दी जाय तो भारत के सरत लाख गाँव, जो आज गरीबी में डूबे हुए हैं वे स्वमेव सम्पत्तिवान होंगे। उनकी यह सम्पत्ति बाहरी नहीं किन्तु भीखरी होगी। हमारे सामने नयी तालीम के दर्शन को जो नयी दृष्टि रखी गयी इससे तालीम के समग्र कार्यक्रम को निम्नलिखित चार विभागों में बाँटा गया है—पूर्व बुनियादी, बुनियादी, उत्तर बुनियादी और प्रौढ़ शिक्षा।

शिक्षा की इस नयी संकल्पना को ध्यान में रखकर उसी समय चार समि-
J त्तियाँ नियुक्त कर दी गयी और नयी तालीम के सम्पूर्ण कार्यक्रम के अमल के लिए सेवाग्राम को पसंद किया गया। यहाँ पूर्व बुनियादी शाला शुरू की जिसके साथ प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम भी शुरू हुआ। यह प्रौढ़ शिक्षा न केवल निरक्षरता निशरण के लिए थी किन्तु प्रौढ़ नटनारियों को ग्रामोद्योग पेसे और मनोरंजन के जरिये उच्चतर जीवन के लिए तैयार करने के लिए भी थी।

१९४५ में सेवाग्राम में अखिल भारत गयी तालीम सम्मेलन हुआ। इस समय सभी के मन में यही प्रश्न था कि सम्पूर्ण बुनियादी अभ्यासक्रम के बाद क्या? उत्तर बुनियादी शिक्षा के कार्यक्षेत्र और पद्धति के बारे में खास नियुक्त की गयी समिति ने एक घोषणापत्र तैयार किया। इस समिति के सदस्यों की गांधीजी जी के साथ विचार विमर्श करने का मौका मिला और चर्चा के बाद उत्तर बुनियादी तालीम के बारे में कई निष्कर्ष निकाले गये। नयी तालीम का उद्देश्य और कार्यक्रम निर्दिष्ट किया गया। अब सेवाग्राम उत्तर बुनियादी शिक्षा का शालाग्राम (स्कूल विन्जे) में विरासत हुआ। यहाँ छात्रगण और शिक्षकगण ग्राम समुदाय के अंग बरकर निवास करते थे। कृषि, गोपालन और ग्रामोद्योग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। शाला समाज में छा शिक्षा दी जाती थी उसमें हाथ और मस्तिष्क की तालीम के साथ जिम्मेदारी के स्विकार और भावनाओं के सम्पूर्ण विकास का मोहा भी मिलता था। इसी समय हिंदुस्तानी तालीमी सघ ने राजपुरा और फरीदाबाद सहरो को पुनर्वास का अति महत्व का राष्ट्रीय कार्य अपने हाथ में लिया उसका निर्देश करना यहाँ पर उचित होगा।

उत्तर बुनियादी शिक्षा के बाद क्या नयी तालीम पूरा हो जाती है? इस प्रश्न का विचार करने के बाद सन् १९५१ में उच्चकक्षा की बुनियादी तालीम शुरू करने का कदम उठाया गया। इसके लिए जिन समिति की रचना हुई उसने नयी तालीम के भावनों पर गिरर विश्वविद्यालय शुरू करने की सिफारिश की। कृषि, पशुपालन, सामाजिक स्वास्थ्य, ग्रामव्यवस्था इत्यादि विद्याशाखाओं की शिक्षा की सुविधा के साथ एक वर्ष शुरू किया। इस वर्ष में उत्तर बुनियादी शिक्षा समाप्त करनेवाले छात्र थे। १९५१ में हिंदुस्तानी तालीमी सघ ने वर्षा के जनपद की इच्छानुसार पड़ोस की २० ग्रामशाखाओं की शिक्षा और निरीक्षण-कार्य की जिम्मेदारी भी उठाई। ७ से ८ मील का यह शालाओं का प्रदेश एक घनिष्ठ विस्तार बना और उसमें सर्वांग सम्पूर्ण शिक्षा का आयोजन तैयार किया गया। यहाँ के छात्रों की परीक्षा लेन की और उनको प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था सघ को सौंपी गयी।

बाद में ग्राम पुनरचना के कार्य के शिक्षक, अधिकारी और कार्यकर्तागण तैयार करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी सस्थाओं से सेवाग्राम में हजारों की संख्या में शिक्षार्थी भेजे। सघ न विदेशी छात्रों और शिक्षाविशारदों के साथ भी अपना सम्बन्ध जारी रखा जिसके कारण सेवाग्राम अभ्यास एवं सशोधन का राष्ट्रीय केंद्र बन चुका। अब तो सघ के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से भी भाग लेने लगे हैं।

तालीम विषयक सकल्पना के क्षेत्र में संघ का अति महत्व का और अन्तिम विकास तब हुआ जब उसने पू० विनोबा प्रेरित सामाजिक एवं आर्थिक अहिंसक क्रान्ति को अपना ध्येय के नाते स्वीकार किया। विनोबाजी ने अपने भूदान-ग्रामदान के कार्य में संघ के कार्यकर्ताओं को जोड़ा और संघ राष्ट्र की सामाजिक शान्ति की एक महत्वपूर्ण सत्ता बन गयी।

हुजारी की सत्ता में संघ के कार्यकर्ता न केवल इस नयी शान्ति का सन्देश पहुँचाने के लिए, किन्तु राष्ट्र के दूर-दूर कोनों के ग्राम विस्तारों में सामाजिक और शिक्षा के नये आदर्श को संगठित करने के विचार से पहुँच गये।

१९५९ के पठानकोट के सम्मेलन से इस दिशा में एक नया परिवर्तन आया। विनोबाजी ने कहा कि नयी तालीम संघ और सर्व सेवा संघ मिलकर एक ही सत्ता बन जाए और उन्होंने नयी तालीम के कार्यकर्ताओं को ग्रामदान, ग्रामोद्योग, छादी और शान्ति-सेवा के क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा दी। अब तो सभी सर्वोदय और रचनात्मक संस्थाओं को नयी तालीम का चालक बनाना था। आज तक नयी तालीम का क्षेत्र एक छोटी-सी छाडी जैसा था, मगर अब महानगर बन गया और सर्व सेवा संघ, जो इन सभी सत्ताओं की मातृ-सत्ता थी, उसमें नूतन-शान्ति की विविध रचनात्मक प्रवृत्तियों में सभी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नयी तालीम का काम शुरू किया, और इन प्रश्नों के निराकरण के लिए वह पौष्टिक सत्ताओं के सम्पर्क में रहने लगा।

१५, १६ अप्रैल १९६५ में श्री ड० न० डेवर की अध्यक्षता में नयी दिल्ली में अखिल भारत नयी तालीम सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें केंद्र सरकार के मंत्रियों को तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और सर्वोदय प्रवृत्तियों में प्रवृत्त शिक्षाविचारकों को भाग लेने का निमन्त्रण दिया गया था। राष्ट्र की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर सम्मेलन ने नयी तालीम के बारे में विचार-विमर्श किया और इस तालीम के आधारभूत प्रश्नों को ध्यान में रखकर तालीम का भावी अभ्यासक्रम, शिक्षकों की तालीम और वारोच र इत्यादि प्रश्नों की चर्चा की। इसी सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि सर्व सेवा संघ नयी तालीम की एक ऐसी समिति का निर्माण करे जो इनकी योजना का अमल चालू रखने का सतत कार्य करती रहे। इस प्रस्ताव के अनुसार सर्व सेवा संघ ने समिति की रचना की, जिसमें ४१ सदस्य थे। श्री मनुभाई पचोली दय समिति के अध्यक्ष और श्री अरुणाचलम् एंव श्री आचार्य इसके संयोजक बने। समिति का कार्य निम्नलिखित रहा :

(१) नयी तालीम के साथ सम्बन्ध रखनेवाली समस्याओं एवं व्यक्तियों के साथ सम्पर्क.

(२) इस तालीम के क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञान और अनुभव का विविध स्रोतों में वितरण ।

(३) देश के विविध प्रदेशों में और विदेशों में जो प्रयोग होते हैं उनकी जानकारी ।

(४) जनसमुदायों की शिक्षा की नीति की चर्चा के लिए परिसंवाद और सम्मेलन का आयोजन ।

(५) शिक्षा क्षेत्र में मार्गदर्शनीय प्रयोग को प्रोत्साहन ।

इसी समय भारत सरकार ने डा० कोठारी के नेतृत्व में एक कमीशन की नियुक्ति की । नयी तालीम समिति ने उस कमीशन को एक आवेदन-पत्र दिया । कमीशन ने इस आवेदन-पत्र के आधार पर समिति और सर्वोदय-विचार धारा के शिक्षा-विशारदों को अपने विचार तथा सुझाव देने के लिए निमंत्रित किया । जब कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो देखा गया कि कमीशन ने बुनियादी शिक्षा का नाम राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में से निकाल दिया था । हमारे राष्ट्रपिता ने एक विशिष्ट शिक्षा-पद्धति को जो नाम प्रदान किया था उस नाम के लिए ही केवल नहीं परन्तु राष्ट्रीय शिक्षा के मूल में बुनियादी शिक्षा-सिद्धान्तों को प्रस्तावित करने के लिए समिति ने पत्र, सार और सभाओं के द्वारा बड़ा आन्दोलन शुरू किया और नवम्बर २२, २३ को मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के कुण्डेश्वर में कमीशन की सिफारिशों पर सोच-विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया । सम्मेलन ने नयी तालीम की शिक्षा-पद्धति के मूलभूत सिद्धान्त और ध्येय के बारे में अपनी बड़ा व्यक्त की और कार्यानुभव 'बर्क एक्सपीरिएन्स', कृषि-शिक्षा, भाषा-नीति, प्रौढ़ शिक्षा आदि की समालोचना की । व्याख्यानों, सभाओं, अल्लधारों और परिसंवादों के द्वारा सम्मेलन का संदेश कमीशन और सरकार को पहुँचाने की खरित करवाई शुरू हुई । अपने प्रस्ताव के समर्थन में समिति ने राष्ट्रव्यापी आन्दोलन शुरू किया ।

दूसरी ओर ग्रामदान आन्दोलन में जो तात्त्विक सिद्धि प्राप्त हुई थी इससे इस क्षेत्र में आर्थिक ध्यान देने की आवश्यकता हुई । शिक्षित बेरोजगारों, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन और सामान्य जनता में बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए बौद्धिक समानता के विकास की आवश्यकता तथा शिक्षा में नये विचार, नयी क्रान्ति के संचार के लिए जागृति का निर्माण करना । इन सभी

घातों के लिए सर्व सेवा सब स्तर हुआ और उसने नव-निर्माण कार्य की रीढ़ान्तिक एवं प्रायोगिक कार्यवाही कर लके, ऐसी नयी तालीम समिति की रचना की ।

१९७० में नयी तालीम सच की पहली सभा नयी दिल्ली में हुई । समिति ने अन्य कार्रवाई के साथ १९७०-७२ के लिए समिति ने निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त किया :

श्री श्रीमन्नारायण—अध्यक्ष

श्री मनुमाई पचोली—उपाध्यक्ष

श्री के० अरुणाचलम्—मंत्री

श्री के० एस० आबालू—मंत्री

नयी तालीम समिति की तीन सभाएँ क्रमानुसार अहमदाबाद, भावनगर और सेबाग्राम में हुईं । समिति की प्रवृत्तियों के मुख्य लक्ष्य ये हैं

(क) राज्यों की विविध समस्याओं को सहकार देकर प्रोत्साहित करना ।

(ख) शिक्षा के विविध प्रश्नों की चर्चा के लिए विचारार्थ, अध्यापक और समाज के इस क्षेत्र के अधिकारियों के परित्याग और समालोचका आयोजन करना ।

(ग) माचार्यकुल और स्कूलों के बीच सहकार का निर्माण करना ।

(घ) शान्तिसेना के कार्य का समर्थन करना ।

(ङ) शैक्षणिक क्रान्ति में सक्रिय भाग लेना ।

(च) शिक्षा की नीति और प्रवृत्तियों के सम्पादन के लिए अध्यापकों, शिक्षा-विचारदो और अन्य नेताओं को एक मंच पर एकत्र करना ।



शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक

इन्दिरा गांधी

शिक्षा एक ऐसा विषय है, जो व्यक्ति और देश के जीवन में बुनियादी महत्व रखता है। लेकिन हमने तो आजाद होने के बाद भी शिक्षा में विदेशी राज का बनाया हुआ ढाँचा ही कायम रखा। थोड़े से सुधार हुए, लेकिन वे भी नाम मात्र के। यद्यपि देश में शिक्षा का फैलाव तो बहुत हुआ, तकनीकी शिक्षण से देश के विकास कार्यक्रमों में मदद मिली, फिर भी राष्ट्र-जीवन में शिक्षा का जो महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए वह हमारे यहाँ नहीं है, और मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए इस बारे में आज सब जगह मचन चल रहा है।

यहाँ अभी कहा गया कि मैं आप लोगों को कुछ प्रेरणा दूँ। अब मैं क्या प्रेरणा दूँगी? आप सब लोग इस क्षेत्र के इतने अनुभवी हैं कि मुझसे प्रेरणा की अपेक्षा रखना उचित नहीं है। मैं तो आप लोगों के सामने थोड़े से सुझाव रखूँगी।

आज का शिक्षण जीवन से, भारत की परिस्थिति से अलग भारत के सभी महापुरुषों ने शिक्षा के बारे में कुछ-न-कुछ कहा ही है। उन्होंने एक बात यह कही है कि आप क्या 'सोचते' हैं, यह मुख्य नहीं है, लेकिन आप क्या 'बनते' हैं, यह मुख्य है, महत्वपूर्ण है। केवल जानकारी प्राप्त कर लेना पूरा शिक्षण नहीं है। जीवन जीने के लिए आपको तैयार करे, दूसरों के अनुभवों का लाभ उठाना सिखाये, यह शिक्षा का मुख्य ध्येय है। परन्तु आज तो हमारी शिक्षा हमारे जीवन से अलग है, भारत की परिस्थिति से दूर है, दुनिया की प्रगति से अलग है, भारत की जनता से दूर है।

हमें लगता है बीता हुआ जमाना बहुत शान्ति का था, यद्यपि उस जमाने में लोगों को ऐसा नहीं लगता होगा। हर एक युग में समाज में कुछ-न-कुछ तनाव और तगदिली रहती ही है। और यह स्थिति बनी रहनेवाली है। शिक्षा उसमें

संतुलन लाती है। वैसे तो हमारी शिक्षा में अत्यन्त-सी कमियाँ हैं, लेकिन मुख्य कमी यह है कि व्याज की क्यास्थिति कैसे कायम रहे और मजबूत बने, ऐसी उसकी दिशा है। इस स्थिति में कैसे परिवर्तन आये, इस ओर उसका ध्यान नहीं है। सचमुच में तो शिक्षा को बच्चों को इस तरह तैयार करना है कि चाहे जैसी बदली हुई परिस्थिति में भी अपनी पैरों पर खड़े रह सकें और विविध धाराओं को जान सकें, पहचान सकें, उनके बीच अपना संतुलन कायम रख सकें।

स्कूल-कालेज में कैद शिक्षा

परन्तु आज तो हमलोगों ने शिक्षा को कैद कर दिया है स्कूल और कालेज की चहारदिवारी में। मैं तो यह महसूस कर रहो हूँ कि मेरी जो कुछ भी शिक्षा हुई है, वह स्कूल-कालेज से बाहर के जीवन के अनुभवों से हुई है। मैं आँख फोड़ में पड़ने गयी। मेरा खास विषय या इतिहास। इसलिए मैं तो इतिहास के बारे में सब कुछ रट कर गयी थी, लेकिन रु-ब-रु मुलाकात में उसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया। अन्य तरह-तरह के विविध प्रश्न पूछे गए। मुझे आश्चर्य हुआ। मुश्किल के आखिर में प्राध्यापकों से मैंने पूछा भी कि ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा कि आपको कितनी जानकारी है आप कितना रट सकती हैं, यह हमको नहीं जानना था, लेकिन आप कितना सीख सकती हैं, आपको कितनी रुचि है, यह हमें जानना था।

खैर, मैं यह कह रही थी कि शिक्षा द्वारा विद्यार्थी को इस तरह तैयार करना है कि वह दूसरों के पास से, समाज से बराबर मीलने की, जन्म से मरण तक लोखने की, शक्ति प्राप्त करे। शिक्षा प्राप्त करके आदमों को एक युग से दूसरे युग तक छकाव मारने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेना, यह कोई शिक्षा नहीं है।

गांधी जी ने तो सभी नये रास्ते दिखाये और पुराने में भी नये अर्थ भरे। उन्होंने बुनियादी तालीम का जो विचार रखा है, उसमें बहुत गुण थे और आज भी हैं। उसको थोड़ा और भी विस्तार करना है। उसमें थोड़े संकुचितता आ गयी थी। मुख्य बात यह है कि शिक्षा का जीवन के प्रत्येक विषय के साथ, प्रत्येक पहलू के साथ कैसा सम्बन्ध है? बालक को पुरुष ही यह समझाना है कि वह समाज का एक अंग है।

जीवन की चुनौतियों का जवाब प्रस्तुत करनेवाली शिक्षा दूसरी बात यह कि बड़े आदमियों को जो काम लगता है, वह बच्चों के लिए खेल होता है। खेल और काम को अलग क्यों करना है? दोनों साथ साथ

चखना चाहिए । ऐसा होगा तो शिक्षा में ख़र्च पैदा होगी । आज तो शिक्षा की धोर ज्यादातर नौकरी की दृष्टि से देखा जाता है । लड़कियों के पास डिग्री होगी तो अच्छा घर मिलेगा, इसी तरह का अधिकतर चिन्तन चलता है । लेकिन शिक्षा तो वह चीज़ है, जो बच्चों के शरीर और मन को तैयार करे और जीवन में जो कुछ चुनौतियाँ आयें, उनका सामना करने के लिए समर्थ बन ये । इस तरह आज की शिक्षा-व्यवस्था में परिवर्तन जाना है । लेकिन यह वास्तव नहीं है । सब जगह की तरह यहाँ भी निहित स्वार्थ है । उनका सामना करते हुए हमें जाति करनी है ।

आज की शिक्षा : जातिवाद बढ़ानेवाली

स्कूल काँचन की शिक्षा से आज एक प्रकार का जातिवाद भी बढ़ रहा है । शिक्षित आदमी अपने को कुछ ऊँचा मानने लगा है । यद्यपि पढ़ने से कुछ गुण तो आदमी में आते ही हैं, लेकिन इस तरह देखने लयें तो खेती का काम करने से भी थोड़े गुण आते ही हैं । इसलिए शिक्षित आदमी खड़े बड़कर है, ऐसा भाव नहीं रहना चाहिए ।

पहले आम चुनाव के समय की बात है । उस समय प्रचार के लिए हमने दलाशव द में अपना कार्यालय खोला था । कुछ शिक्षित बहनें मेरे पास आयी और कहने लगी कि हमको गाँवों में जाना है । मैंने उनसे पूछा कि गाँव की परिस्थिति का आप लोगों का कोई अम्यास या अनुभव है ? अनुभव तो उनको कोई था नहीं, लेकिन व गयी । उनसे मन में ऐसा होगा कि हम तो पढ़ी लिखी हैं, इसलिए हम को सब कुछ आता है । गाँव के तो गरीब, गँवार लोग, उनको हम सब कुछ सिखा सकेंगी ! न बहन गाँव में गयी, बहुत तरह की जानकारीयाँ गाँव के लोगों की दी, लेकिन गाँव के लोगों ने उनसे सवाल पूछे । उन्होंने पूछा कि “हमारी यह समस्या है, इसका समाधान आपके पास क्या है ?” उन बहनों के पास इसका तो कुछ अनुभव था नहीं, इसलिए वे गाँव के लोगों को समाधानकारक जबाब नहीं दे सकी ।

मेरा कहना यह है कि प्रत्येक आदमी के पास, चाहे वह गरीब हो, आदिवासी हो, कुछ-न कुछ योग्यता, जीवन के अनुभव आदि होते ही हैं । हम शहरवाले और शिक्षित हैं, इसलिए उनसे ऊँचे और ज्यादा समझदार हैं, ऐसा भाव रखना उचित नहीं है । हमें भी उन लोगों से कुछ-न-कुछ सीखना है ।

बाबूगिरी बढ़ानेवाली शिक्षा

आज तो लड़का पढ़ लिया तो गाँव में रहना नहीं चाहता । कृषि का स्नातक भी गाँव में नाम करना नहीं चाहता । श्रम के काम से नफ़रत करता है । इस

सरह के दृष्टिकोम से कितना नुकसान होता है ? कोई भी काम नीचा नहीं है, कम महत्व का नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा के साथ बाबूगिरी बढ रही है। शिकार में खुद भी इसका शिकार बनो हैं। मैं कोई फाईल या कुछ उठाने जाऊँ तो दो तीन आदमी दौड आते हैं, और मुझे उठाने नहीं देते। धरे भाई इतनी छोटी सी फाईल में खुद क्यों नहीं उठा सकती ?

शिक्षण में क्रान्ति करनी हो तो

मैं तो क्रान्ति में विश्वास करती हूँ। और क्रान्ति को कोई नहीं रोक सकता है। गांधीजी काफी परिवर्तन लाये, लेकिन एक क्रान्ति ही पर्याप्त नहीं है, परिवर्तन तो हरपल होते रहना चाहिए, शान्ति को क्रान्ति निरन्तर चलती रहनी चाहिए। शिक्षा में भी कोई चीज अन्तिम नहीं है। नये-नये प्रयोग चलते रहने चाहिए। मुझे कोई आदेश देने की आवश्यक नहीं। मैंने तो आप लोगों के सामने ये कुछ प्रश्न रखे हैं।

शिक्षा में परिवर्तन लाना है तो अभिभावकों को भी साथ लेना होगा। सभी कोई भी सही सुधार हो सकेगा। अपने बच्चों को शिक्षा के बारे में अभिभावकों की रुचि बढ़ानी होगी। उनको मालूम होना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं तो आज देख रही हूँ कि मेरे बच्चों की जितनी जानकारी है, उतनी मुझे भी नहीं है, साफ़कर विज्ञान की नयी नयी खोजों के बारे में। क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी बड़ी जो खोजें हुई, वे मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हुई, उसके बाद की हैं।

अन्त में मुझ इनका हो कहना है कि चारों ओर को हवाओं से हमलाग परिवर्तन रहें, लेकिन जैसा गांधीजी ने कहा था, 'मे हवाएँ हमारे घर को ही अपनी जमीन पर से उड़ाड न दें, यह देखना होगा।' हम अपनी शिक्षा का ढांचा इस तरह बनायें कि जिससे नया समाज बनाने में सफलता मिले। ●

राष्ट्रीय शिक्षा और विकास व सामाजिक न्याय

श्रीमन्नारायण

पच्चीस वर्ष पूर्व स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद भारत अनेक दिशामें सल्लेखनीय प्रगति कर रहा है जिसके लिए हमें शीरस अनुभव करना स्वाभाविक है। फिर भी, हमें मानना होगा कि अनेक समितियों और आयोगों की सिफारिशों के बावजूद हमारी प्राथमिक व विश्वविद्यालय के स्तरों की शैक्षणिक पद्धति में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, और वह राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने में कारगर नहीं है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि स्वाधीनता के रजत-जयन्ती वर्ष में हम अपने शैक्षणिक सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर गहराई और गम्भीरता से विचार करें, ताकि समय की आवश्यकताओं के अनुकूल अपनी विद्यमान शैक्षणिक पद्धति को ढालने की दृष्टि से कुछ ठोस कदम उठाये जा सकें। संक्षेप में, हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में शिक्षा को एक अत्यन्त उच्च प्राथमिकता देनी होगी और समय-समय पर विभिन्न समितियों द्वारा दिये गये कुछ विशेष सुझावों को अविलम्ब अमल में लाना होगा।

स्वर्गीय जमनालाल बजाज द्वारा स्थापित शिक्षा मण्डल की रजत जयन्ती के अवसर पर पैंतीस वर्ष पहले, वर्षा में अक्टूबर १९३७ में एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस बैठक की अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी ने की थी और परिणामस्वरूप बुनियादी शिक्षा का जन्म हुआ, जिसे गांधीजी ने राष्ट्र को अपना “अन्तिम और उत्कृष्ट उपहार” कहा था। इस पद्धति में रचनात्मक और उत्पादक प्रवृत्तियों द्वारा बच्चों को सर्वांगीण शिक्षा देने पर सबसे अधिक महत्व दिया गया था, जो उनमें स्वावलम्बन तथा श्रम की गरिमा के सद्गुणों का सम्पादन करे। बुनियादी शिक्षा की योजना भारत के लगभग सभी प्रांतों में कहीं सफलता और कहीं विफलता के साथ लागू की गयी थी। यह समय एक दूसरे पर दोष डालने या मनमुटाव पैदा करने का नहीं है। लेकिन यह तो जाहिर है कि कई कारणों की वजह से बुनियादी शिक्षा को अभी तक देश में उचित स्थान नहीं दिया जा सका है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (१९४८-४९) ने सिफारिश की थी कि इस पद्धति को न केवल प्राथमिक व माध्यमिक स्तरों पर, बल्कि विश्वविद्यालयों में भी लागू किया जाय। माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५२-५३) ने भी सिफारिश की थी कि स्कूलों में अध्ययन के तरीके इस तरह के होने चाहिए जिससे कार्य के प्रति वास्तविक ज्ञान तथा उसे अत्यन्त कुशलता, ईमानदारी और भरमक पूर्णता के साथ करने की इच्छा पैदा हो सके। शिक्षा आयोग (१९६४-६६) ने भी यह बात स्पष्ट कर दी थी कि उनके विचार में बुनियादी शिक्षा के मूल तत्व इतने महत्वपूर्ण हैं कि वस्तुतः उन्हें शिक्षा के सभी स्तरों पर लागू कर देना चाहिए। तबिन फिर भी इस विचारों को वास्तविक व्यवहार में अमली बनाने के लिए बरों से गणप्य-सा ही कार्य हुआ है। हाँ, बुनियादी (Basic) शब्द के स्थान पर ‘काय-अनुभव’ (Work experience) और ‘व्यवसायीकरण’ (Vocationalisation) जैसे नये शब्द जरूर तैयार किये गये हैं। गांधीजी न बड़े साफ शब्दों में कहा था कि ‘नयी तालीम’ का अमल जम से मृत्यु पर्यंत होना चाहिए। मैं यहाँ शब्दों के बारे में विवाद सटा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हमें ‘बुनियादी तालीम’ शब्द इस्तेमाल करने में क्यों हिचक महसूस होती है। डॉ॰ जान ड्यूई ने इस पद्धति को सभी अन्य पद्धतियों से एक कदम आगे बताया है। प्रो॰ गुनार मिरडाल ने अपनी महान रचना ‘एशियन ड्रामा’ में स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि “बुनियादी शिक्षा भारतीय प्राथमिक स्कूलों में सबसे, '०२]

अध्यापन और पाठ्यक्रमों के परम आवश्यक गुणों की दृष्टि से आदर्श हल हो सकती है ।”

बुनियादी शिक्षा के मूल सिद्धान्तों का आज भी उतना ही औचित्य है जितना कि पेंतोग वर्ष पहले था । हाँ, अध्यापन के ढंग और साधनों में आवश्यक परिवर्तन जरूर हो सकता है । सन् १९३७ में भारत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था; उस समय कोई पंचवर्षीय योजनाएँ भी नहीं थी । अब हमारा देश स्वाधीन है । शहरी व देहाती इलाकों में अनेक कार्यक्रमों व परियोजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से हजारों करोड़ रुपये की लागत से पंचवर्षीय योजना शारम्भ करने की तैयारियाँ हो रही हैं । ऐसी स्थिति में, बुनियादी और उत्तर बुनियादी स्कूलों में, बुनाई और कढ़ाई पर और देने के अलावा अपने पड़ोस में सभी विकास योजनाओं के साथ अपने अध्ययन के विषयों को सम्बद्ध किया जा सकता है । प्रशिक्षण-केन्द्रों को छोड़कर इन शिक्षा-संस्थाओं के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनके पास अपने खेत और वर्कशॉप हों । हाँ, उसके पास बुनियादी औजार और उपकरण होना चाहिए । लेकिन अनुबन्ध के लिए समस्त प्राकृतिक व सामाजिक परिवेश उनकी बुनियादी प्रशुति बन सकती है । छात्र समुदाय का विकास कार्य के साथ इस प्रकार का तालमेल बैठाने से शिक्षा और नियोजन दोनों की ही लाभ पहुँचेगा । गुजरात सरकार ने हाल ही में इस प्रकार की विकास लक्ष्यीय शिक्षा-योजना राज्य भर में दाखिल की है । आशा है सभी सम्बन्धित लोगों के सहयोग से पंचवी योजनावधि में यह एक ठोस शैक्षणिक गुणों का मार्ग प्रस्तुत करेगी ।

शैक्षणिक ढाँचा

विभिन्न स्तरों के शैक्षणिक ढाँचे के बारे में शिक्षा आयोग और भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्ताव (१९६८) ने १० + २ + ३ की पद्धति की सिफारिश की थी । मेरे विचार से सभी राज्य सरकारों की अब इस पद्धति की बिना अधिक वर्षों के स्वीकार कर लेना चाहिए । प्रथम १० वर्षों को दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है । पहले ७ वर्षों की बुनियादी शिक्षा और उसके बाद के ३ वर्षों की उत्तर बुनियादी शिक्षा । वैसिक स्कूलों में बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्तियों के जरिये आम शिक्षा तथा सामाजिक परिवेश की अच्छी जानकारी देनी चाहिए । उत्तर बुनियादी स्कूलों से अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक दृष्टि से लाभप्रद तथा उत्पादक दस्तकारियों का प्रशिक्षण दें, जो स्थानीय जरूरतों और जनशक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप हों ।

हायर सेकेंडरी शिक्षा के दो वर्षों में विद्यार्थियों को तकनीकी किस्म के

अनेक विविष्ट पाठ्यक्रमों की तालीम लेना चाहिए जो उन्हें अपनी जीविका कमाने तथा स्वावलम्बी बनने में मददरूप हो। किन्तु ऐसे छात्रों के लिए भविष्य में कभी भी उच्चतर अध्ययन करने का मार्ग खुला रहना चाहिए। इस प्रकार के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में कृषि, पशुपालन, डेयरी-उद्योग, देहाती इंजीनियरिंग, एकाउंटेंटसी, बैंकिंग और बीमा, सहकार, प्रबन्ध, बिक्री व्यवसाय, अध्यापन, इमारतों का निर्माण, सोहारगोरी, कपड़ों की धुलाई, बड़ईगोरी, रेडियो तथा मोटरों की मरम्मत, नर्सिंग आदि अनेक विषयों का समावेश किया जा सकता है। यह सूची केवल नमूने के तौर पर दी गयी है। ससे नगरों और गांवों में उपलब्ध शौकरारों के अवसरों की दृष्टि से निरन्तर बढ़ाया जा सकता है। सरकार के विभिन्न विभाग भी अपने-अपने क्षेत्रों के अनुरूप डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार के द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों को कालेजों की अथवा हायर सेकण्डरी स्कूलों में रखना ठीक रहेगा, हालांकि इस बारे में कुछ लवकौलापन रखना शायद आवश्यक हो।

विश्वविद्यालयों में डिग्री का पहला पाठ्यक्रम तीन वर्षों का होना चाहिए। उसके बाद विभिन्न अवधि के पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च पाठ्यक्रम होने चाहिए। यहाँ भी कृषि, विज्ञान, टेक्नालॉजी मेडिकल, वाणिज्य और व्यापार के पाठ्यक्रमों पर अधिक जोर देना उपयोगी होगा।

अध्ययन के पाठ्यक्रम

सभी स्तरों के अध्ययन-पाठ्यक्रमों में इन तीन मूलतत्वों पर बल देना चाहिए

- (१) राजनैतिक कार्यक्रम के रूप में शारीरिक धर्म की गरिमा,
- (२) सामुदायिक सेवा के सार्थक कार्यक्रमों में छात्रों और शिक्षकों की सक्रियता के जरिये सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना, और
- (३) सर्व धर्म समभाव के दृष्टिकोण का प्रसार।

पाठ्यक्रमों में इन मूल तत्वों के समावेश के लिए विभिन्न कार्यक्रम अपनाये जा सकते हैं -

- (क) अहाते की सफाई और देखरेख,
- (ख) स्कूलों, पारिवारिक या पड़ोस के खेतों में कृषि से सम्बंधित उत्पादक काम में हाथ बँटाना। इसके लिए छुट्टियों के समय में उचित परिवर्तन किया जा सकता है,
- (ग) सामाजिक दृष्टि से लाभप्रद और उत्पादक दस्तकारियाँ सिखाना,

(घ) छात्रों में रुचियों (हॉबीज) का प्रसार,

(ङ) निम्न के नये ऐसे तरीके अपनाना, जो प्रत्येक विषय में हाथ से काम करने के अवसर देते हों,

(च) पारस्परिक सेवा के कार्यक्रमों के जरिये शैक्षणिक संस्थाओं और समुदाय के बीच निकट का सम्पर्क स्थापित करना,

(छ) अकाल, बाढ़, संक्रामक रोगों और प्राकृतिक आपत्तियों के निवारण कार्यक्रमों में भाग लेना, तथा

(ज) प्रौढ़ निम्न के उपयुक्त कार्यक्रम आयोजित करना ।

अध्ययन के विषयों में विज्ञान गणित कृषि और टेक्नालॉजी के अन्वेषण पर विशेष जोर देना चाहिए । पाठ्यक्रमों में भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन का सक्षिप्त इतिहास, राष्ट्रीय एकता अहिंसा सामाजिक न्याय और हमारे संविधान के अनुसार सत्य धर्म समभाव का समावेश होना चाहिए । स्वाधीनता के बाद की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय प्रगति की भी पर्याप्त जानकारी देना चाहिए ।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को अच्छी विराम की पाठ्य-पुस्तकें देनी चाहिए । N C E R T इस दिशा में काफी अच्छा कार्य कर रहा है । उसे अधिक व्यापक और उपयोगी बनाया जाय । साथ ही साथ, अध्ययन के नये तरीकों के बारे में जानकारी देनवाली उपयुक्त पुस्तकें शिक्षकों के लिए भी तैयार की जानी चाहिए ।

सर्व माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तरों पर अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र और दशन जैसे विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों में गंभीर विचारधारा के अध्ययन का समावेश होना चाहिए ।

आशिक्र समय की शिक्षा

देश के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा के स्तरों को ऊँचा उठाने की भरपूर कोशिश के साथ साथ आशिक्र समय की शिक्षा और पत्र व्यवहार पाठ्यक्रमों को भी बढ पैमाने पर प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है खासकर विश्वविद्यालयों में जिससे कि निजी व सरकारी सेवाओं में नया कृषि, उद्योग या अन्य व्यवसायों में काम करनेवाले लोगों को लाभ मिल सके । इस प्रकार की सुविधाएँ ऐसे कमजोर वर्गों के छात्रों को विशेष रूप से मददगार होंगी जो पूरे समय की शिक्षा का फायदा नहीं ले सकते हैं । लेकिन मुझे यह बताना है कि इस प्रकार के

आशिक समय के पाठ्यक्रमों की शिक्षा की पूर्ण समय की शिक्षा के समान मायता प्रदान करना कहाँ तक उचित होगा। इस प्रकार की आशिक समय की शिक्षा के लिए प्रस, फिल्म, रेडियो और टेलीविजन जैसे आम संचार की आधुनिक सुविधाओं का भी समुचित उपयोग किया जा सकता है।

प्रवेश की आयु

युनियादी स्तर पर बच्चा १ में भर्ती की आयु सामान्यतया ६ वर्ष से कम नहीं हानी चाहिए। इसी प्रकार किसी भी छात्र को हाईस्कूल परीक्षा में तब तक नहीं बैठने देना चाहिए जब तक कि वह १६ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर सता। १३ और १४ वर्षों की आयु में छात्रों को मेट्रिक की परीक्षा में बैठने देने की वर्तमान व्यवस्था बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए अत्यन्त हानिकारक है।

छात्रों का अपने दो वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को १८ वर्ष की उम्र में पूरा करना चाहिए। इसी उम्र के छात्रों की सीमित संख्या में विश्वविद्यालय के वर्गों में प्रवेश देना चाहिए।

हमारा अनुमान है कि हाई स्कूल परीक्षा पास करनेवाले नवयुवक काफी संख्या में इस प्रकार के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नहीं भर्ती होंगे। वे उपर्युक्त रोजगार प्राप्त करने और जीवन में स्थिर होने के लिए सहायक होंगे।

उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि योग्यता और प्रतिभा के आधार पर विभिन्न छात्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए छात्रों की एक सीमित संख्या चुनकर विश्वविद्यालयों में प्रविष्ट कराया जाय। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में, कृषि, उद्योग, मेशिन, व्यापार, सरकारी सेवा, आदि में आवश्यक जनसंख्या का एक सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करना बहुत आवश्यक होगा।

शिक्षा और आर्थिक विकास

जैसाकि पहले कहा जा चुका है, शिक्षा और आर्थिक विकास के बीच निकट का सम्बन्ध होना जरूरी है। प्राथमिक या बुनियादी स्तर पर बच्चों को भौतिक और सामाजिक दृष्टियों के अनुरूप मरदा दस्तकारियों और रचनात्मक प्रवृत्तियों के द्वारा गिना देनी चाहिए। इसे दोनों, देहाती और शहरी, क्षेत्रों के स्कूलों में बिना भेदभाव के लागू करना चाहिए।

माध्यमिक या उत्तर बुनियादी अवस्था में टेक्निकल और व्यावसायिक शिक्षा

की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थी उत्पादक प्रवृत्तियों और अध्ययन के साथ कमाने में अपने को लगा सकें और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ा सकें। उन्हें अपने निकट के विस्तारों की विभिन्न विरासत प्रवृत्तियों, सासुर दहाती विस्तार में कृषि, पशुपालन, डेयरी और वृक्षारोपण तथा शहरी विस्तार में उद्योग, निर्माण, व्यवसाय और वाणिज्य में भाग लेने के अवसर मिलन चाहिए।

द्वितीय उच्च माध्यमिक स्तर पर भी विद्यार्थियों को शहरों और गाँवों के अनुकूल विविध व्यावहारिक अभ्यासक्रमों में प्रशिक्षित कराना चाहिए, ताकि उसके बाद वास्तविक आवश्यकतानुसार उनको विभिन्न व्यवसायों में लगाया जा सके।

विश्वविद्यालयों में कृषि फार्मों विभिन्न आकार की औद्योगिक इकाइयों तथा विविध विकास योजनाओं को अनेक कालेजों तथा उच्चशिक्षा केन्द्रों के साथ जोड़ा जा सकता है। NCC तथा N D S कार्यक्रमों को रचनात्मक एवं उत्पादक प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख करना चाहिए। इस स्तर पर अध्ययन के साथ अर्जन सिद्धांत की अधिक व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है।

शिक्षा और सामाजिक न्याय

भारत में जनतांत्रिक, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र को स्थापित करने के लिए यह जरूरी है कि प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तरों तक के सभी विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता सामाजिक भाईचारा तथा समाज-सेवा की भावना उत्पन्न की जाय। हम न अक्सर और सामाजिक माय पर आधारित जातिविहीन, बहुधर्मी तथा बहुभाषी समाज की स्थापना करने से ही वास्तविक राष्ट्रीय एकीकरण दृढ़ किया जा सकता है। इस दृष्टि से स्कूलों और कालेजों में सभी धर्मों के प्रति समान आदर तथा सामाजिक समानता का वातावरण पैदा किया जाना वांछनीय है।

यह केवल सभी सम्भव हो सकेगा जब सार्वजनिक शिक्षा की एक सामान्य स्कूल पद्धति अपनायी जाय और आगामी पाँच वर्षों में उसे कारगर ढंग से तगरी और गाँवों में समल में लाया जाय, जैसे कि शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल सभी बच्चों के लिए समान स्तर पर खुले हान चाहिए, चाहे उनकी जाति, भाषा, धर्म या आर्थिक-सामाजिक स्तर कुछ भी हो। परिणामस्वरूप वर्तमान पब्लिक स्कूल और अन्य निजी संस्थाएँ, जो अधिक ट्यूशन फीस लेती हैं और मुख्यतया धनवान बर्गों के बच्चों को दाखिल करती हैं, उन्हें अपना फीस और अन्य खर्चों को आम स्कूल-पद्धति के अनुस्यू बना लेना चाहिए।

इन स्कूलों को भी, अन्य संस्थाओं की तरह सरकारी अनुदान प्रदान किये जा सकेंगे। वगैरे और आम जनता के बीच मौजूदा अन्तर को कम करने का यहो व्यावहारिक तरीका है।

इसके अलावा विभिन्न जातियों, समुदायों और धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित संस्थाओं को भी देश के वृहद् हितों की दृष्टि से सार्वजनिक शिक्षा की आम पद्धति के अनुरूप बन जाना चाहिए। कालेज और विश्वविद्यालय स्तरों पर इन संस्थाओं के नामों से 'हिन्दू', 'मुस्लिम', 'क्रिश्चन', 'खालसा', 'जाट', 'कायस्थ और 'बैश्य', जैसे छद्म निकाल देने चाहिए। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष समाज में इन शब्दों का तालमेल नहीं बैठता है।

खासकर कमजोर वर्गों के छात्रों को पर्याप्त व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा की सभी अवस्थाओं में योग्यता-छात्रवृत्तियाँ काफ़ी संख्या में उपलब्ध करायी जायें। देश में उपलब्ध उच्चतम शिक्षा से कोई भी छात्र सिर्फ इसलिए वंचित न रह जाय कि उसके माता पिता गरीब हैं और वे उसे स्कूल या कालेज में नहीं भेज सकते।

नये प्रयोगों की गुंजाइश

सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूल की एक आम पद्धति वांछनीय है, फिर भी राज्य सरकारों को चाहिए कि वे विभिन्न सतहों की शैक्षणिक संस्थाओं को अध्ययन तरीकों, परीक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम में विषय के सकल पाठ्य पुस्तकों की तैयारी और शिक्षकों को तालीम की दिशा में नये प्रयोगों की सक्रिय प्रोत्साहन प्रदान करें। एकरूपता पर दिय जानेवाले भार की शैक्षणिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोगों और अनुमान को दिशा में बाधक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के प्रयोग करनेवाले स्कूलों या कालेजों को विभिन्न दिशाओं में, शिक्षा विभाग के हस्तक्षेप के बिना, अनुभव प्राप्त करने देना चाहिए। 'स्वायत्त कालेजों' को कल्याण की ओर एक निश्चित रूप देना चाहिए। इन संस्थाओं के सफल विद्यार्थियों को प्रबंधकों की सिफारिशों पर राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा नियमित रूप से प्रमाणपत्र देना होगा। हाँ, शिक्षा विभागों को चाहिए कि वह कुशलता और ऊँचे स्तरों को बनाये रखने के हित में समय-समय पर इस प्रकार की प्रयोग-संस्थाओं के कार्य की समीक्षा करते रहें।

सांख्यिक स्कूलों और कालेजों ने भी राष्ट्रीयकरण के लिए शिक्षकों की चर्चा रही भाँति शिक्षा सम्बन्धी सुधारों के सतुलित दृष्टिकोण पर आधारित दिखाई नहीं देती हैं। यद्यपि निजी संस्थाओं में मौजूद अनेक मुद्दों को हटाने के भरसक

प्रयत्न होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारों को समाजवाद के नाम पर इन स्कुलों को चलाने की समस्त जिम्मेदारी उठा लेने के दबाव में नहीं आ जाना चाहिए। हम यह नहीं भूल जाना हैं कि हमारे देश में अनेक निजी संस्थाओं ने दशान्वियों से दौलतिया सुधार की दिशा में अनेक बंदम उठाये हैं। इसलिए हमें इस क्षेत्र में निजी पहल और सयम को बुण्ठित बनाने में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना है। जाहिर है कि राज्य के बहुत राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से इस प्रकार की संस्थाओं पर नियमन, देखरेख और नियंत्रण रगना है।

समुदाय-सेवा

शिक्षा की सभी संस्थाओं में सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा को उठा एक अविवर्ज्य अंग बनाना चाहिए। ऐसा सभी हो सकता है जब स्कुल और कॉलेज के अहाड़ा में और अंदर भी शिक्षा की विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं में छात्रों के सक्रिय सहयोग की व्यवस्था हो।

दौलतिया संस्थाओं के अहाड़ों के अंदर छात्रों को बगरी और हमारती की सफाई, खेल के मैदान को समतल बनाना, बागवानी, कर्मीचर को पालिश करना दीवारों की पुताई और दरवाजों व खिड़कियों की रंगाई जैसे कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। छात्रों में सामुदायिक जीवन पर विशेष बल देना चाहिए ताकि विद्यार्थी अपनी ज़रूरतों को गौरव के बिना पूरा कर सकें। विकास प्रवृत्तियों में नियमित रूप से भाग लेने की दिशा में सावजनिक सफाई, सू सारक्षण, मृशारोपण छोटी सिंचाई योजनाएँ, सड़क निर्माण और प्रोढ़-शिक्षण जैसे कार्यक्रमों का समावेश होना हितकर होगा।

प्रत्येक स्कुल और कॉलेज को सामुदायिक विकास खण्डों और राज्य सरकारों के सम्बन्धित विभागों से निकट का सम्पर्क स्थापित कर समाज की सेवा की अपनी योजनाएँ तैयार करनी चाहिए। सामुदायिक सेवा के इस प्रकार के कार्यक्रमों को निर्धारित पाठ्यक्रमों के साथ जुड़ा होना चाहिए, उन्हें केवल कोई बाहरी प्रवृत्ति न माना जाय। इस प्रकार की विकास परियोजनाओं में छात्रों द्वारा किये गये काम की ठीक ढंग से समीक्षा की जाय और उसका सम्बन्ध परीक्षा पद्धति से जोड़ा जाना चाहिए।

इसके अलावा प्रत्येक जिले में छुट्टी के समय हर घण्टा और सामाजिक सेवा शिविरों का आयोजन होना चाहिए। इसके लिए जिले की एजन्सियों के परामर्श से किसी खास विकास परियोजना का चयन किया जा सकता है। इस

प्रकार के शिविरो' के लिए आवश्यक निधियों के कुछ भाग को स्थानीय देहाती निर्माण कार्यक्रमों से प्राप्त कर सकते हैं ।

शिक्षा का माध्यम

(क) अब यह बात सभी मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम हरेक स्तर पर मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए । लगभग सभी राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक अवस्थाओं में तो इस प्रकार की व्यवस्था है । अब भारतीय विश्व-विद्यालयों में, टेक्निकल और मेडिकल शिक्षा देनेवाली कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़कर शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने की दिशा में योजनाबद्ध कदम शीघ्र चलाने चाहिए । जहाँ तक हो सके सभी भारतीय भाषाओं में टेक्निकल शब्द एक प्रकार के हों । जहाँ आवश्यक हो वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों का उपयोग किया जा सकता है । जिन शहरों में भाषाई अल्पसंख्यकों की गणना काफी हो, वहाँ कुछ संस्थाओं में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम चालू रखा जा सकता है ।

(ख) देश में अभी भी ऐसे अनेक अंग्रेजी माध्यमवाले निजी माध्यमिक स्कूल हैं जिनका संचालन मुख्यतया विदेशी इंग्रैड मिशनरी द्वारा होता है । इन स्कूलों को अब शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति के अनुरूप बन जाना चाहिए तथा शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग और समान पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए । राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इस प्रकार के सभी निजी स्कूलों के लिए 'रजिस्टर' बनाना अनिवार्य बनायें और उनमें निर्धारित पाठ्यक्रमों को दाखिल करें । इस प्रकार के मिशन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम को जारी रखना न केवल राष्ट्रीय शिक्षा के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है, बल्कि उससे वर्गभेद भी बढ़ता है और राष्ट्रीय एकता में बाधा पड़ती है । हाँ, आम पद्धति को अपनाते हुए भी वे संस्थाएँ अनुशासन, स्वच्छता और व्यापक-तरीकों की अपनी विशिष्टता कायम रख सकती हैं ।

(ग) यह बात स्वीकार करने की होगी कि अंग्रेजी माध्यमवाले स्कूल अभी भी काफी छात्रों के लिए आकर्षण बने हुए हैं, खासकर इसलिए कि अखिल भारतीय सिविल तथा मिलिटरी सेवाओं की परीक्षाओं का माध्यम अभी तक केवल अंग्रेजी भाषा बनी हुई है । इसलिए यह जरूरी है कि इस प्रकार की प्रतियोगिक परीक्षाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाय और उम्मीदवारों को प्रत्येक राज्य के लिए नियत कोटा के अनुसार तर्कयुक्त आधार पर चुना जाय, न कि केवल

बाबादी के आँकड़ों पर। इन सेवाओं का अखिल भारतीय स्वरूप कायम रखने के लिए चुने गये सम्मोदबारों की हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान कराया जाय तथा उह राष्ट्रीय इतिहास, संस्कृति, भारतीय संविधान और आर्थिक संयोजन की भी जानकारी दी जाय।

भाषाओं का अध्ययन

माध्यमिक स्तर पर, शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट 'तीन-भाषा फार्मूला' को सभी राज्य सरकारों द्वारा तेजी से अमल में लाया जाना चाहिए। शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा रहे, लेकिन भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के अध्ययन पर उचित ध्यान दिया जाय। साथ-साथ, एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का भी बामचलाऊ ज्ञान जरूरी है। जिन छात्रों की मातृभाषा हिंदी हो उनके लिए पाठ्यक्रम में खासकर दक्षिण की एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शुरू किया जाय। यह भी बाछनीय है कि अंग्रेजी के अलावा विश्वविद्यालयों में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रूसियन, चीनी, जापानी और हमारे एशियाई पड़ोसियों की दूसरी अनेक भाषाओं को प्रोत्साहन मिले।

भारतीय भाषाओं की अभिवृद्धि और विनाश की वृद्धि से संस्कृत का विशेष महत्त्व है। इसलिए राज्य सरकारों को अधिक उदारता के साथ स्कूलों और विश्वविद्यालयों में उसके अध्यापन के लिए सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए।

नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा

राधाकृष्णन् तथा कोठारी आयोगों की सिफारिशों के अनुसार स्कूलों तथा कॉलेजों में विद्यार्थियों को नैतिक और धार्मिक शिक्षा देने के लिए एक क्रमिक और योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर, सभी धार्मिक संस्थाओं का कार्य कुछ समय की सामूहिक अथवा मौन प्रार्थना तथा ध्यान से आरम्भ हो। सभी धर्मों में एकता लाने के लिए स्वस्थ बातावरण पैदा करने के उद्देश्य से समाज में एक या दो घण्टे ऐसी शिक्षा के लिए टाइम टेबल में सुरक्षित रखना चाहिए। आरम्भिक अवस्थाओं में छात्रों की महान धार्मिक नेताओं की जीवनो, उनकी सुविदित कृतियों तथा ऐसे बुनियादी उपदेशों से परिचित कराना चाहिए, जो सभी धर्मों में प्रचलित हों। ऊँची कक्षाओं में विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की प्रोत्साहन देना चाहिए। भारत में तथा एशिया और अफ्रीका के अन्य विकासशील देशों में एक बहु धर्मी समाज की रचना के लिये ऐसा करना बहुत जरूरी है।

बधाओ में दो जानेवाली शिक्षा के बलावा हमारी शैक्षणिक संस्थाओं का आम बानावरण तथा बाहरी प्रवृत्तियाँ ऐसी होनी चाहिए जिनसे धार्मिक समन्वय और एकता को बढ़ावा मिल सके। भारत के सामने आज चरित्र निर्माण की समस्या प्रमुख है और हमारे नवयुवक और नवयुवतियों में नैतिक मूल्यों को जगाना बड़ महत्व का है। यह जिम्मेदारी सभी शिक्षकों की होनी चाहिए, न कि केवल उनही जो विभिन्न धर्मों या विषयों को पढ़ाते हों।

परीक्षा पद्धति में सुधार

जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उचित बल दिया है, विश्व विद्यालया में यदि कोई अकेला सुधार करना है तो वह परीक्षाओं के बारे में होना चाहिए। यही बात प्राथमिक और माध्यमिक अवस्थाओं की परीक्षा-पद्धति को भी लागू होती है। परीक्षा के वर्तमान ढंग से छात्रों की शारीरिक मानसिक और नैतिक क्षमताओं पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। उससे शैक्षणिक स्तरों में गिरावट हुई है, अनुशासन कमजोर हुआ है और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्रियों की प्राप्ति करने के लिए अनुचित और अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल होने लगा है।

इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि परीक्षा-पद्धति में अविलम्ब आमूल सुधार किया जाय। इस विषय पर समय समय पर अनेक समितियों और आयोग ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और कई व्यावहारिक सुझाव दिये हैं। उनमें से कुछ सिद्धांतों को तुरन्त लागू कर देना चाहिए। संक्षेप में, निम्न सुझावों को स्वीकृत कर देना चाहिए

(क) बाहरी परीक्षाएँ अधिक वस्तु निष्ठ (Objective) तथा तर्क-संगत हों, प्रश्न पत्र ऐसे हों जो रटने की क्रिया को प्रोत्साहन न दें बल्कि स्वतंत्र विचार और मौलिकता का सर्जन करें। जैसाकि विश्वविद्यालय आयोग ने सुझाव दिया है, बाहरी परीक्षाओं के प्रत्येक प्रश्न-पत्र को जाँचने के लिए दो परीक्षकों की नियुक्ति की जाय। छात्रों को अन्वय के आधार पर आकलन के बजाय परीक्षक उन्हें प्रथम और द्वितीय ऐसी दो श्रेणियों में विभाजित करें।

(ख) कई सामयिक परीक्षाओं द्वारा आन्तरिक मूल्यांकन पर अधिक बल देना उचित होगा जिससे कि सिर्फ अंतिम परीक्षा के अनुचित महत्त्व को कम किया जा सके। पूर्णांकों में से भाव नहीं, तो कम-से-कम एक तिहाई अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित करना चाहिए। यह मूल्यांकन छात्रों के शैक्षणिक अध्ययन, बाहरी प्रवृत्तियों, उपस्थिति में नियमितता, कार्य-

परियोजनाओं में परिष्कृत तथा सामान्य आचरण के आधार पर किया जाय। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे आन्तरिक मूल्यांकन लगातार तथा वस्तु-स्थिति पर आधारित रहें, शिक्षकों की वैयक्तिक पसन्दगी या नापसन्दगी पर नहीं।

(ग) छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तित्व तथा बौद्धिक सिद्धि को आँकने के लिए मौखिक परीक्षाओं पर अधिक बल देना होगा।

हालांकि, परीक्षकों को मेहनताना देना बन्द कर देने सम्बन्धी शिक्षा आयोग का सुझाव अमल में लाना शायद सम्भव न हो, लेकिन शिक्षकों में ज्यादा-से ज्यादा विषयों के परीक्षक बनने की अस्वस्थ खींचतान को कारगर ढंग से कम करना होगा। इस उद्देश्य से उपयुक्त नियम बनाये जायें। जो शिक्षक लापरवाही, अकुशलता और आचारहीनता के लिए दोषी पाया जाय उसको यदि स्थायी तौर पर नहीं तो दीर्घ समय के लिए परीक्षक बनने से रोका जाना चाहिए।

परीक्षा-पद्धति न केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक सिद्धि की जाँच करे, बल्कि उत्पादक प्रवृत्तियों और खेल-कूद, व्यायाम, समाज-सेवा जैसी सह-प्रवृत्तियों में उनके सक्रिय सहयोग और उनकी चारित्रिक श्रेष्ठता पर भी ध्यान दे।

नौकरियों से छिप्रियों का सम्बन्ध तोड़ना

अभा विभिन्न सरकारी विभाग उम्मीदवारों को लोक सेवा आयोगों के जरिये भर्ती करते हैं। इस प्रकार की भर्ती मुख्यतया विश्वविद्यालय की छिप्रियों के आधार पर की जाती है। परिणामस्वरूप इस प्रकार की छिप्रियाँ प्राप्त करने के लिए छात्रों में उचित या अनुचित तरीकों से परीक्षाएँ पास करने की वृत्ति पैदा हो गयी है। कुछ वर्ष पहले केन्द्र सरकार ने इस विषय का गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रो० हुमायूँ कबीर की अध्यक्षता में एक विशेष समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने सिफारिश की थी कि आई० ए० एस० जैसी कुछ जसिल भारतीय सेवाओं को छोड़कर शेष नौकरियों के लिए सरकारी विभागों को अपने स्वतंत्र पाठ्यक्रम निर्धारित करने चाहिए और भर्ती के लिए विश्वविद्यालय की छिप्रियों को अनिवार्य माने बिना अपनी परीक्षाएँ आयोजित करनी चाहिए। इस प्रकार के पाठ्यक्रम उच्च माध्यमिक शालाओं में १० + २ + ३ की प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत संचालित किये जा सकते हैं।

सरकारी नौकरियों में छिप्रियों का सम्बन्ध-विच्छेद कर देने से न केवल विश्वविद्यालयों में भर्ती की भोड और परीक्षाओं में आचारहीनता कम हो जायगी,

शक्ति सरकार को अपने विभागीय कार्यों के लिए अधिक अच्छे उम्मीदवार मिल सकेंगे। इस कदम से कई प्रगतिशील संस्थाओं को शैक्षणिक क्षेत्र में भी अनेक परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

शिक्षकों का कर्तव्य

जाहिर है कि शिक्षा पद्धति में शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान है। सघन प्रयासों के द्वारा शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाये बिना हमारी शैक्षणिक संस्थाओं को अधिक उपयोगी बनाना सम्भव नहीं हो सकेगा। शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बहुत ठसुक्क है। वे चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षकों के महत्त्व को केवल उनके वेतन से नहीं बल्कि समाज के प्रति किये जानेवाले उनके धर्म के आधार पर आँके। शिक्षकों का कर्तव्य है कि जिस युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गयी है उसके चरित्र निर्माण में वे अपना योगदान दें। वास्तविक अर्थ में वे राष्ट्र के सच्चे निर्माता हैं। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे छात्रों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रशिक्षित करने का भरसक प्रयास करें। लेकिन सरकार का भी यह फर्ज है कि वह शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊँचा उठाये और उन्हें दैनिक आर्थिक चिंताओं से मुक्त करे। जनतांत्रिक तथा समाजवादी व्यवस्था की प्रक्रिया में एक असंतुष्ट शिक्षक निश्चित ही अभिशाप बन जाता है।

शिक्षक भी अपनी शिकायतों को दूर कराने के लिए हड़ताल तथा आम आन्दोलनों में भाग लेकर सकीर्ण दलगत राजनीति तथा सस्ते अमिक संघवाद में अपने को न डलवायें। वे अपनी कठिनाइयों को समय और अनुशासन से सम्बन्धित अधिकारियों के सामने पेश कर सकते हैं। शिक्षा विभाग भी उनकी शिकायतों पर ध्यान से सुने और हल करे। देश के राजनैतिक दल एक आचार-संहिता अपनायें जिसके अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के कामकाज में दखलशायी न की जाय और वहाँ का शांतिपूर्ण दूषित न हो।

माता-पिता का सहयोग

भारत में शैक्षणिक पुनर्रचना के महत्वपूर्ण कार्य में सभी संस्थाओं के लिए छात्रों के माता पिता का सहयोग प्राप्त करना निरन्तर आवश्यक है। प्रारम्भिक अवस्थाओं से ही माता-पिता अपने बच्चों की घर तथा स्कूल में हुई प्रगति पर उचित ध्यान दें तथा उनके व शिक्षकों के बीच निरन्तर का सम्बन्ध कायम हो। इस उद्देश्य से हमारी शैक्षणिक संस्थाओं में पालक-शिक्षक मण्डल की एक सामान्य व्यवस्था बन

जानो चाहिए। दोनों में इस प्रकार के सम्पर्क से शैक्षणिक स्तरों में सुधार और छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों में अनुशासन जगाने और उनके आम बर्ताव में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से भी संस्थाओं के प्रमुखों को उनके पालकों का सहयोग लेना चाहिए। वास्तव में प्रत्येक परिवार को सही अर्थ में एक बुनियादी शिक्षा की इकाई के रूप में विकसित होना चाहिए।

छात्रों का सक्रिय योग

मौजूदा शैक्षणिक पद्धति में विभिन्न स्तरों की पुनर्रचना करने के लिए स्कूलों और कालेजों में छात्रों का सहकार लेना जरूरी है। स्वतंत्र भारत में पैदा हुए बच्चे अब प्रौढ़ और देश के जिम्मेदार नागरिक बन रहे हैं। उनमें नयी उम्रग और महत्वकांक्षाएँ हैं और वे चाहते हैं कि बेरोजगारी और निराशा का सामना किये बिना ही वे एक प्रतिष्ठा-प्राप्त नागरिक के रूप में अपना जीवन बितायें। इसलिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों को बदलने, पाठ्य-पुस्तकों तैयार करने, सामुदायिक सेवा और विकास प्रवृत्तियों में उनके सहयोग, परीक्षा सम्बन्धी सुधार तथा अध्ययन के तरीकों में फर्क लाने के बारे में छात्रों के विचारों पर उचित ध्यान देना होगा। उनका सहयोग न केवल विभिन्न छात्र कल्याण कार्यक्रमों को अमल में लाने, बल्कि शैक्षणिक सुधारों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी प्राप्त करना चाहिए। छात्र-सचो का उपयोग आत्मसमय लागू करने और तरुणों में अधिक जिम्मेदारी की भावना जागृत करने की दृष्टि से दिया जाय। विश्व-विद्यालयों में छात्रों के कुछ प्रतिनिधियों को सिनेट और एकेडेमिक कौन्सिल में भी शामिल किया जा सकता है।

नवयुवकों को यह बात समझायी जाय कि हिंसा और जनता की सम्पत्ति को गंवा करने के वर्तमान तरीकों से देश के लोकतांत्रिक ढाँचे की अपार हानि पहुँचेगी। हिंसा ने अनिश्चय रूप में प्रतिहिंसा की भावना जागती है और वस्तुतः एक गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है जिससे राज्य प्रशासन में फासिस्ट प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। डा० आरनॉल्ड टायनबी ने अपनी नवीनतम कृति 'सर्वो-विंग दो पयूषर' में नयी पीढ़ी को इस प्रकार की महत्वपूर्ण सलाह दी है - "सबसे महत्व की बात यह है कि धैर्यवान बनो और हिंसा से दूर रहो। महान दर्शनों और घमों के नेतृत्वों से सबक सीखो। भगवान बुद्ध, ईसा और हमारे समय में ही पैदा हुए महारमा गांधी जैसी महान आत्माओं की शांतिनता, धैर्य, और दीर्घ-कालीन सहनशीलता का अनुसरण करो।"

देश के अन्दर और बाहर भारत खेलकूद के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। म्युनिख ओलिम्पिक में हुए हाक ही के अनुभव से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारी सामी स्पष्ट रूप से दिखायी दी है।

इसलिए यह वाञ्छनीय है कि स्कूलों और कालेजों में खेलकूद का बड़ा पैमाने पर विकास किया जाय और हम प्रतिभाशील नवयुवकों का भलिभांति चयन कर उन्हें हर तरह से प्रोत्साहित करें। देहाती और शहरी विस्तारों में खेल के मैदानों तथा अन्य शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी प्रवृत्तियों के लिए उदारता से सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

ग्रौंड शिक्षा

यह बड़ी चिन्ता थी बात है कि पिछले २५ वर्षों में किय गये अनेक प्रकार के प्रयत्नों के बावजूद हमारी जावादी का ७० प्रतिशत भाग निरक्षर बना हुआ है। महिलाओं में निरक्षरता का प्रमाण स्वभावतया अधिक है। महारत्ना गांधी का यह स्पष्ट मत था कि ग्रौंड शिक्षा का आधार बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों पर ही हो। पढ़ाई लिखाई सम्बन्धी शिक्षा का ज्ञान देने की अपेक्षा यह जरूरी होगा कि भूमिहीन श्रमियों, किसानों, कारीगरों और कामगारों की उत्पादक कुशलताओं को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रदर्शन किये जायें। दूसरे शब्दों में हमारा उद्देश्य 'कृषि-तन्त्र', साक्षरता का होना चाहिए। इस प्रकार की कार्य प्रेरित शिक्षा से विभिन्न व्यवसायों में निःसन्देह कार्य-कुशलता बढ़ेगी। ऐसी साक्षरता से जनता में अच्छी नागरिक जागरूकता पैदा होगी जो उनके व्यक्तिगत, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक जीवन को समृद्ध बनायगी।

शिक्षकों व विद्यार्थियों की समाज-सेवा प्रवृत्तियों को ग्रौंड शिक्षा के कार्य क्रमों में लगाना जरूरी है। इस अ उद्यम के लिए पूरा समय के बतन प्राप्त कार्यकर्ताओं को रखना बहुत महंगा पड़ेगा और शायद वैसा सम्भव भी न हो सके। इसलिए इस राष्ट्रीय अभियान की सफलता के लिए ऐच्छिक संगठनों, सरकारी कर्मचारियों, बकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों तथा अन्य लोगों की मुफ्त सेवाएँ ली जायें। रेडियो और टेलीविजन सहित दृश्य-श्रव्य उपकरणों का भी समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। जब तक इस प्रकार का एक-पक्षीय और मुख्यतया ऐच्छिक राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू नहीं किया जायगा, तब तक भारत से निरक्षरता हटाना बहुत कठिन और खर्चीला साबित होगा।

मैंने यहाँ ऐसी अनेक समस्याओं का उल्लेख किया है जिन पर हमें गम्भीरतापूर्वक और अविलम्ब विचार करना चाहिए। इनके अलावा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों का प्रशासनिक ढाँचा, वित्तीय साधनों की प्राप्ति और शिक्षा-विभागों की पुनर्रचना आदि अनेक समस्याएँ हैं। यद्यपि इनका महत्व कम नहीं है, फिर भी अच्छा होगा यदि हम कुछ खुले हुए विषयों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें शीघ्रता से अमल में लाने के उद्देश्य से किसी सर्व-सम्मति पर पहुँचें। मेरा विश्वास है कि यदि हम स्वराज्य की रजत-जयन्ती वर्ष से अपनी शिक्षा पद्धति को ठोस आधार पर मोड़ देने में कामयाब रहें तो निःसंदेह मातृभूमि के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी निभा सकेंगे। यदि हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई स्पष्ट और ठोस सुधार होता है तो बेरोजगारी, अल्प आयवा निम्न श्रेणी का उत्पादन, अनुशासनहीनता और नागरिक अव्यवस्था जैसी मौजूद अनेक समस्याएँ लगभग अपने आप ही हल हो जायेंगी और भारत एक अधिक ग़ुली देश बन सकेगा। ●

शिक्षा की तीन बुनियादें

विनोबा

इन दिनों बाबा के शरीर में कई रोग हैं। उनमें एक रोग है चक्रम्। बाबा के चक्रर आता है, वह शारीरिक चक्र है ही, लेकिन मानसिक चक्रम् भी है। उस हालत में आरके सामने क्या कहें, बड़ा मुश्किल है। एक ऐसे ही चक्रम् आये थे और उन्होंने बाबा से प्रश्न पूछा, 'आपको अगर दूसरा जन्म मिले, पुनर्जन्म, तो आप क्या करेंगे?' मैंने कहा, 'पुनर्जन्म का मेरा विचार तो नहीं है, बहुत जन्म लिये, बहुत हो गया, लेकिन फिर भी अगर भगवान् अबरदस्ती करके भेजेगा, तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या कहूँगा? जो गलतियाँ इस जन्म में की, वह नहीं कहूँगा।' तो पूछ बैठे, 'कौन-सी गलतियाँ आपने इस जन्म में की?' मैंने थोड़े में कहा, 'मुख्य गलती तो यह हुई कि मैं स्कूल में गया। मैं सिर्फ फेट्रिक की परीक्षा पास हूँ। फेट्रिक क्या है आप लोग जानते नहीं होगे। यह बाबा का बहुत पुराना शब्द है। मैट्रिक के बाद कालेज का फर्स्ट इयर (प्रथम वर्ष) होता है, उसे बाबा ने फेट्रिक नाम दिया है। उसी परीक्षा पास कर बाबा निकला। लेकिन सतना भी स्कूल में जाना ठीक नहीं रहा। दूसरी गलती यह भी पढ़ना-लिखना सीखा। अगर पढ़ना-लिखना न सीखा होता, तो जो अनुभव लेने में इस जन्म में बहुत समय पड़ा, कम समय में वह अनुभव आ जाता। ऐसे विचित्र मेरे विचार हैं। इसलिए आपकी सभा के लिए मैं विलकुल बेकार हूँ।

मुझे अभी याद आ रहा है उदाहरण मुहम्मद पैगम्बर का। पैगम्बर भगवान् का ध्यान कर रहे थे। भगवान् ने अव्यक्त रूप में एक पर्चा उनके सामने रखा और कहा, 'पढ़।' पैगम्बर ने धल्लाह से कहा, हे भगवान्, मैं पढ़ना-लिखना नहीं जानता।' इस वास्ते भगवान् को सामने आना पड़ा और बातचीत करती पड़ी। अपना संदेश सुनाता पड़ा। बहुत प्रसिद्ध है यह कहानी। कुरआन में उसका जिक्र है। नवीनयुन् उम्मीयुन् 'मनपढ़ प्रोफेट'। तो पैगम्बर हमेशा कहते थे लोगों को कि अगर मैं पढ़ा-लिखा होता, तो भगवान् का शब्द सुनने को मिलता नहीं और पर्चे पर समाधान मानना पड़ता। शिक्षित लोगों की यह हालत है कि उनके और परमात्मा के बीच पर्चा खड़ा होता है। पुस्तक दीवार बन जाती है और सृष्टि और आत्मा के बीच पुस्तक खड़ी होती है। मेरे सामने अनेक लेखक, अनेक विद्वान बैठे हैं, उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि आगे 'मन-लविग' का 'प्रोसेस'

करिएगा। जितना आपका 'लॉनिंग' हुआ होगा उतना मूलने की प्रक्रिया शुरू करिए, तो अच्छा जान होगा।

‘मूले कुठार’

एक बात मेरे मन में आती है, जो ‘मूले कुठार’ है, यह यह कि शिक्षा सरकारी तंत्र से मुक्त होनी चाहिए। शिक्षा पर सरकार का कोई बरदहस्त नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को तनखाह सरकार जरूर दे। वह सरकार का वर्तव्य है। परन्तु जैसे ग्याय विभाग—ज्युडिशियरी—स्वतंत्र है, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ भी फैसले दिये जा सकते हैं, और दिये गये हैं, अगरचे उस ग्यायाधिपति को तनखाह सरकार से मिलती है, वैसे सिला-विभाग स्वतंत्र होना चाहिए। यह अगर नहीं होगा तो बहुत बड़ा खतरा अपने देस के लिए है।

डिमोक्रेसी में यानी लोकशाही में हर एक को आजादी है, विचार की स्वतंत्रता है। एक बाजू से डिमोक्रेसी का दावा करना और दूसरी बाजू से विद्या-पियों का विभाग एक ढाँचे में ढालना, यह डिमोक्रेसी के मूलभूत विचार के खिलाफ है। ऐसी कोशिश रशिया में हुई। ऐसी कोशिश जापान में हुई। उसका परिणाम क्या आया, आप लोग देखते हैं। रशिया में दो-दो, तीन-तीन दफा इतिहास बिल्ले गये। नये-नये इतिहास। इतिहास यानी क्या है? ‘इति ह आम्’—वास्तव में ऐसा हुआ। परन्तु इन दिनों इतिहास का अर्थ है ‘इति हास’—ऐसे हँसना, हास्यास्पद। इतिहास यानी हास्य का विषय। जिस प्रकार का विद्यापियों का विभाग बनाना चाहते हैं, उसके अनुकूल इतिहास बनाते जायेंगे। परिणाम क्या आता है? शिक्षा अधिकारी के हाथ में ऐसी सत्ता आती है, जो सत्ता आपने न बाहर को दी, न रामानुज को दी, न तुलसीदास को दी, न बबीर को दी।

आज शायद उत्तर भारत में तुलसीदास की रामायण जितनी पढ़ी जाती है लोगों में, आम जनता में, भाइयों और बहनों में, उतनी दूसरी कोई किताब पढ़ी नहीं जाती। मैंने देखा बिहार में। बिहार की बहनें श्री अरविंद से बढकर योगी हैं। श्री अरविंद बीस-पचोस साल एक कोठरी में रहे। बिहार की बहनें जिनगी भर एक कोठरी में रहती हैं। बाहर के बागन में भी नहीं आती। सादो के बाद घर में प्रवेश किया, उसके बाद, मृत्यु के बाद ही बाहर जायेंगे। अगर दफनाने का रिवाज होता तो उन्हें घर में ही दफनाते, लेकिन जलाने का रिवाज है, इसलिए उन्हें बाहर निकाल कर जलाना पड़ता है। लानारी हैं। हमने उन बहनों से पूछा कि कुछ पढ़ती हो क्या? तो बोली, ‘पढ़ना-लिखना तो जानती नहीं, याद पढ़ना सीखा है इसलिए तुलसीदास की रामायण पढ़ती हैं।’ आज भी जो

चर्ममावना उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में है, वह तुलसीदास की कृति है। लेकिन तुलसीदास को आपने वह अधिकार नहीं दिया, जो आज शिक्षा अधिकारी को है। शिक्षा अधिकारी आज जो किताब तय करेगा, वह हर एक बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा। उसकी परीक्षा देनी पड़ेगी, और परीक्षा में फेल होगा, तो आगे उसकी प्रगति होगी नहीं। तुलसीदास की किताब छोग खूब पढ़ते हैं इच्छा से पढ़ते हैं, लेकिन जबरदस्ती अपनी पुस्तक बच्चे पढ़ें, यह शक्ति तुलसीदास को नहीं। वह अधिकार आपन दे रहा है शिक्षा-अधिकारी को। शिक्षा अधिकारी के दिमाग में आपने ऐसी कोत-सी बुद्धिमत्ता पायी, जो तुलसीदास, कबीर, शंकर और रामानुज में बँककर है। इस वास्ते यह जो अधिकार दिया जाता है वह नहीं होना चाहिए। उससे बहुत नुकसान होता है देश का। तो ये भरे शिक्षा के बारे में विचार 'मूले फुटार' है। लेकिन, फिर भी शिक्षा के बारे में, वह जरूर एक आपने हाथ में है, सब तक अच्छी से अच्छी योजना आप सब मिलकर करें यह ठीक ही है। उसमें तीन चीजें सिखानो चाहिए। एक है योग, दूसरा उद्योग और तीसरा सहयोग। ये शिक्षा के मुख्य तीन विषय हैं।

योग

योग का अर्थ आसन लगाना, व्यायाम करना यह नहीं है। योग यानी चित्त पर कैसे अकुश रखना, इंद्रियो पर कैसे सत्ता रखना, मन पर कैसे काबू पाना, जुबान पर कैसे अपनी सत्ता पाना, यह योग का सच्चा अर्थ है। इन चित्तों चित्त पर सच्चा रखना, चित्त अकुशल रखना, स्थिर रखना जिसको गीता स्थिर-प्रज्ञा कहती है, ऐसी स्थिर-प्रज्ञा की बहुत आवश्यकता है। पहले कभी जितनी नहीं थी, उतनी आज है। क्यों है? क्योंकि आज रोजमर्रा की सैकड़ों घटनाएँ बाग पर पड़ती हैं, बाँस पर पड़ती हैं। भाँसों और से विचारों का आक्रमण होता है। जितना आक्रमण मनुष्य के दिमाग पर आज होता है, उतना पहले कभी नहीं होता था, क्योंकि साइंस का जमाना आया है। ऐसी हालत में चित्त को शांत रखना, स्थिर रखना, काबू में रखना अत्यन्त महत्व का विषय है। इस वास्ते स्थिर-प्रज्ञा-दर्शन की आज जितनी आवश्यकता है, उतनी पहले कभी नहीं थी। तो प्रज्ञा स्थिर करना योग का मुख्य विषय है।

उसके लिए कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों की मदद हो सकती है। लेकिन हम लोगो में 'सेक्युलरिज्म' के नाम से एक गलत विचार पैठ गया है।

'सेक्युलरिज्म' का अर्थ वास्तव में, गांधीजी की भाषा इस्तेमाल करूँ तो 'सर्व धर्म समभाव' है। परन्तु 'सेक्युलरिज्म' का अर्थ हमने समझ लिया है 'सर्व

धर्म सम अभाव'। अब परिणाम इसका यह है कि उन आध्यात्मिक ग्रंथों का विद्यार्थियों को स्पर्श होने देते नहीं। लेकिन इनकी लाचारी है कुछ। क्या लाचारी है ? जो आध्यात्मिक ग्रन्थकार हमारे कुछ हो गये, वे दुर्देव से यानी इन सेव्युल-रिज्म लोगो से दुर्देव से साहित्यिक भी थे। इस वास्ते साहित्य की दृष्टि से उनके साहित्य का कुछ 'पीस' (छोटा हिस्सा) रखना ही पड़ता है। उसे कहते हैं, 'पीस' (टुकड़ा)। अब, बी० ए० तक सीख लिये और ज्ञानेश्वरी से सम्बन्ध नही, तो कैसे चलेगा ? इस वास्ते ज्ञानेश्वरी का एक छोटा सा अध्याय रख लेते हैं बी० ए० में। बी० ए० के पहले तो कुछ या ही नहीं, बी० ए० में एक अध्याय ज्ञानेश्वरी का रख लिया। ऐसा इन लोगो का—सेव्युलरिस्ट लोगो का—ज्ञानेश्वर्य है। जिन ग्रन्थ से महाराष्ट्र का हृदय बना, उस ग्रन्थ का परिचय न हो ऐसी कोशिश करते हैं और लाचारा से साहित्य के छोर पर कुछ 'पीस' रख लेते हैं। यही हाल पुलसीदास के है।

यह ठीक है कि इन ग्रन्थों में ऐसी कुछ चीजें हैं, जो इस जमाने के ब्याल से 'आठट डेटेड' (कालबाह्य) हैं। तो उतना अक्ष निकालना होगा। ऐसी कोशिश बाबा ने की है। बाबा ने कई धर्मग्रन्थों का चराम-से-उत्तम अक्ष निकाल कर लोगों के सामने रखा है। जैसे कुरान सार है, ख्रिस्त धर्मसार है, भागवत धर्मसार है, मनुशासनम् है, इत्यादि, इत्यादि। ऐसे पद्दत बीस ग्रन्थ बाबा ने निकाले हैं, जिनमें उन उन ग्रन्थों का सार रख दिया है। तो उन ग्रन्थों का उपयोग भी आप कर सकते हैं। उनसे पुराने ग्रन्थों के गलत विचारों से हम बचेँगे और जो अच्छे विचार हैं, उनको ग्रहण करेंगे।

सवाल यह है हमारे सामने नि पुराने जमाने के लोगो के आध्यात्मिक विचार रखें, इसकी जरूरत क्या है ? आधुनिक जमाने के विद्वानों की किताबें रखने के बजाय पुराने प्रकारों के विचार क्यों रखे जायें ? इसका उत्तर है, होमियोपैथी। होमियोपैथी में क्या होता है ? थोड़ा आता है—थोटा...थोटा...थोटे से ही वो पोटेन्सी (शक्ति) बढ़ती है। तो जो आध्यात्मिक प्राचीन ग्रन्थ हैं, उनकी पोटेन्सी बढी हुई है। आज तक लाखों लोगो ने, अनेक महापुरुषों ने पढ़ पढ़कर उन्हें थोटा है। इस वास्ते उन ग्रन्थों की पोटेन्सी बढी है।

असम में दो महापुरुष हो गये—शंकरदेव और माधवदेव, जिनका नाम वहाँ बि घर-घर में है। लेकिन यहाँ हम लोग जानते नहीं। हमको ऐसी सालीम मिली है कि हम पोप, बायरन, शेरेन-यारन ऐसे अनेक 'रन' जानते हैं, परन्तु असम के घर-घर में जो नाम चलते हैं, वे नाम हम जानते नहीं। माधवदेव ने कहा है—

‘विष्णुसहस्रनाम सदा—अरे मूरखो, ‘विष्णु का सहस्र नाम तुम्हारे पास है, फिर भी—विरोध वचन मात्र रट्य—विरोधी वचन रटते हो, विरोधी भाषा बोलते हो !’ तो उन्होंने विष्णुसहस्रनाम को अविरोध साधक माना। यानी हमारे सबके हृदयों को जोड़नेवाला, विरोध मिटानेवाला। और वही विष्णुसहस्रनाम चरुता है केरल में। और वही विष्णुसहस्रनाम चलता है सौराष्ट्र में। हिन्दुस्तान के प्रिकोण में विष्णुसहस्रनाम चरुता है। इतना घोटा हुआ होने के कारण उसकी पोटेन्सी बढ़ गयी है। तो, जो पोटेन्सी वेद की है, कुरान की है, बाइबिल की है, ज्ञानेश्वरी की है, सुलसीदास की है, वह पाटेन्सी हमारे आत्र के विद्वानों के ग्रंथों में नहीं हो सकती, अगरचे विद्वानों के ग्रंथ अच्छे भी होंगे। इस वास्ते पुराने ग्रंथों का विचारियों को स्पर्श होना चाहिए।

दूसरी भी एक बात है। कालपुरुष है। वह कालपुरुष परीक्षा करता है। कालपुरुष की परीक्षा में जो निकम्मी चीज है, वह पचास साल में, सी-दो-सी साल में गिर जाती है। और जो अत्यन्त उत्तम है, वह कालपुरुष की परीक्षा में टिकती है। जो परीक्षा वेद की हो गयी। दस-बारह हजार साल से कालपुरुष ने उसकी परीक्षा की। अगर वह चीज काम की नहीं होती, तो दस-बारह हजार साल टिकती नहीं। आज, हमारे ग्रंथों में से कितने ग्रंथ सी साल के बाद पड़े जायेंगे ? मैं आपको मिलाऊँ।

लोकमान्य तिलक का केसरी। हमारे बचपन में हम हर हफ्ते राह देखते थे कि केसरी कब आयेगा और कब पढ़ेंगे ! उसके लेख पढ़ते थे। उससे हमको बहुत ही प्रेरणा मिली। आज क्या है ? पचास साल हो गये उनको, उनके लेखों में से एक भी पढ़ा नहीं जाता। वे केवल गीतारहस्य के कारण जीवित हैं। अगर गीतारहस्य लिखा होता, तो लोकमान्य का एक भी लेख उमारे पास पढ़ने लिए नहीं होता। पचास साल के बाद वे लेख आऊटडेटेड हो जाते हैं।

हमारे बचपन में त्रिमूर्ति थी—भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव। इस त्रिमूर्ति के जैसी त्रिमूर्ति लाल-बाल-पाल ! लाल यानी लाला लाज-पतराम, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिनचंद्र पाल। आज विपिनचंद्र पाल का नाम हमारे पास है, परन्तु उनकी कोई चीज पढ़ी नहीं जाती। लाला लाजपतराम ने अनेक ग्रंथ लिखे, लेख लिखे, एक भी लेख उनका आज पढ़ा नहीं जाता। उनका नाम आज इसलिए है कि पीपुल्स सोसायटी नाम की एक सोसायटी उन्होंने बनायी और वह आज कुछ सेवाकार्य कर रही है। लेकिन ग्रंथ, उनका एक भी पढ़ा नहीं जाता। लोकमान्य के हालात आपको सुनाये। यह मैंने

आपको इसलिए कहा कि जिन ग्रंथों की काल ने परीक्षा की—और जो प्रत्यक्ष हजार-हजार, पाँच पाँच, दस-दस हजार साल की परीक्षा में बचे हुए हैं उनकी परीक्षा हो चुकी—उन ग्रंथों में से हमको मदद लेनी पड़ती है, इतनी अरल हमका सेबुलरिज्म में होनी चाहिए। तो यह बात मैंने कही योग के बारे में।

उद्योग

शिक्षा का दूसरा विषय है उद्योग। उद्योग में केवल घरता हो या तकली हो, यह मेरा विचार नहीं। आधुनिक यंत्र भी हो, यंत्रज्ञाप भी हो। कुछ भी हो, लेकिन खेतों तो होनी ही चाहिए। वेद में शब्द आया है पचजन। अब भगवान का शब्द पाँचजन्य है। यानी पाँच जनो के लिए भगवान का शब्द है। वेद कहता है, पचजन। कौन से पचजन? रक्त, श्वेत, पीत, कृष्ण, भिन्न श्याम। हमारे देश के लोग श्याम हैं। कुछ लोग हैं रक्त वर्ण के रेड इंडियन्स बगैरह। कुछ लोग हैं बाले, सिंदी, हवशी बगैरह। कुछ लोग हैं मोरे, सफेद, मालो यूरोपियन बगैरह। कुछ पीत, बर्मा, चीन, जापान बगैरह व लोग। तो रक्त, श्वेत, पीत, कृष्ण, भिन्न श्याम, ऐसी पच प्रजा दुनिया में है। श्याम हिंदुस्तान का शास्त्र वर्ण है। हम श्यामवर्ण लोग हैं। भगवान कृष्ण का वर्ण श्याम था। श्यामसुंदर बगैरह शब्द प्रचलित है ही। कृष्ण शब्द का अर्थ है किसान, खेती करनेवाला। खेती करनेवाले शरीर का जो रंग होता है वह कृष्ण का वर्ण है। ऐसे पचजनो का जिक्र वेद में आता है। और भगवान का शब्द पाँचजन्य है, इन पाँच जनो के लिए है यानी कुल दुनिया के लिए है।

जैसे पचजन शब्द है, वैसे दूसरा एक शब्द वेद में आया है बार—बार पचकृष्टि यानी पाँच किसान। उसका अर्थ यह है कि हर एक मनुष्य किसान है। खेती के साथ वह दूसरा काम कर। मान लीजिए, वह बुनकर है, उसे कहना कि आठ घंटे बैठे बैठे तुम बुनते रहो। यह बिल्कुल जुर्म है उस पर। आठ घंटे एक जगह बैठ कर बुनते रहने को कहना ठानी उसकी शक्ति की क्षीण करना है। लेकिन, मान लीजिए, दो घंटे वह खेत में काम करे और ३ घंटे बुने, तब तो उसका जीवन अच्छा होगा। ऐसे ही साहाय्य होगा। वह मुख्यतः अध्ययन करे। लेकिन वह भी दो घंटे खेती करे और बाकी समय अध्ययन करे, तो उसका जीवन अच्छा होगा। प्रधान मंत्री होगी आपकी, तो वह भी दो घंटे खेती में लगावे और बाकी समय अपना काम करे प्रधानमंत्री का, तो क्या होगा? उनका दिमाग ताजा रहेगा। और खेती के साथ सम्बन्ध होगा तो उनको प्रतिभा उज्ज्वल होगी। फिर, आज जितना सूझता है, उससे बहुत कुछ अधिक भी सूझ सकता है। इस वास्ते वेद में

समृद्ध है पक्कूटि । पाँच प्रकार के किसान । इसलिए मैंने कहा कि हमारी समाज रचना, शिक्षा की रचना, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, सहर में विद्यालय हो तो भी, कि विद्यालय के साथ दो-तीन एकड़ का खेत जुड़ा होना ही चाहिए । बच्चों को और शिक्षकों को थोड़ी देर इकट्ठा होकर खेत में काम करना चाहिए ।

इस सिलसिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वाक्य मुझे कहा था । वह वाक्य एक मंत्र के समान मुझे याद रह गया । उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, इस वास्ते अंग्रेजी में आपके सामने रखूँगा, 'नेशन-स डीके स्ट्रेन दे लूज ग्राटवुड बिथ नेबर'—जिन राष्टों का आसपास की कुदरत के साथ सम्बन्ध नहीं रह जाता व राष्ट्र क्षीण होते हैं, उनका क्षय होना है । इस वास्ते खेती के साथ, प्रकृति के साथ, सम्बन्ध होना अत्यन्त आवश्यक है । इस सम्बन्ध में वेद में एक वाक्य आया है कि सृष्टि में होना चाहिए सौंदर्य और समाज में सौजन्य । समाज का सौजन्य और सृष्टि का सौंदर्य दोनों मिलकर जोइन परिपूर्ण है । सौजन्य को यद में वसु नाम दिया है । वसु यानी सौजन्य । सौंदर्य को वामन नाम दिया है । वामन यानी सौंदर्य । सो कहा गया, जो पृथ्वी पर काम करेगा, उसके लिए जरूरी है वसु, यानी इन्फ्रस्ट्रिक्चर नेबर (मेलजोस की वृत्ति), वसु धानु का यह अर्थ है । सौजन्य भावार्थ हुआ । और दिव्यधाम यानी सृष्टि होनी चाहिए वामम्—सुंदर वामनाम दो दिव्याय धामे । वसुवसु व पार्थिवाय सुन्वते । दो चीजें एक होनी चाहिए । इस वास्ते खेती के साथ हर मनुष्य का सम्बन्ध होना ही चाहिए, यह मेरा आग्रह है ।

सहयोग

एक हो गया योग । दूसरा हो गया उद्योग । तीसरा है सहयोग । इस सहयोग के अंदर सारा समाजशास्त्र, मानवशास्त्र इत्यादि आ जायेगा । लेकिन मुख्य वस्तु क्या होगी ? हमको सबको इसका जीना है । सहजीवन जीना है । सहजीवन में अनेक भापाएँ, अनेक प्रात, भेद इत्यादि इत्यादि सब खत्म होने चाहिए । कल हमको किसी ने कहा, 'हम भारतीय हैं' ऐसी भावना होनी चाहिए, नकि हम 'महाराष्ट्रीय हैं,' 'गुजराती हैं,' 'तमिल हैं,' इत्यादि इत्यादि । 'सन्धमिष्ठ नाइलुम् पांदिनिले जिन्व तेन् वन्दु पायुदु कादिनिले, अगप्पु तन्दैयर नाइन्न् पेच्चिनिले ओरु शक्ति पिरक्कुडु मूच्चिनिले ।' 'अंगव्द' यानी 'हमारा' उच्चारण करते हुए उल्हास आता है । सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां, 'हमारा' कहते हर्ष होता है । 'हमारा' इसलिए हर्ष, 'आमार सोनार बागला'—अरे 'आमार' इसलिए सानार । हम बचपन में बोलते थे—'बारा तुझ्या स्पर्शने' 'शुद्ध साला मला रामला भाग्य हे

बेबड़े ?' राष्ट्रों के राष्ट्रगीत होते हैं । मेरे पास राष्ट्रगीतों का सप्रहं था । उसमें झाबिया का राष्ट्रगीत था—मेरा कितना भाग्य, तेरी सुंदर हवा मिली, तेरा प्रकाश मिला इत्यादि-इत्यादि ! इसका प्रमाण कौन है ? 'मैं' हूँ मुख्य । वायु से पूछा जाये, अरे वायु, तू कहाँ का है ? झाबिया का है कि भारत का तो वह क्या जवाब देगा ? लेकिन हमारे देश की हवा का मतलब क्या है ? 'हमारा' यह है । अहम्—ग्रहण्ड । तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्रीय, गुजराती, ये सब जाना चाहिए, हम भारतीय हैं । मैंने कहा, यह सबसे छोटी माँग है । मैक्सिमम (अधिक से अधिक) नहीं, और अष्टितम् (इष्टतम) भी नहीं, यह कम-से-कम । तो क्या जरूरी है ? जरूरी है विश्वमानव । हम विश्वमानव हैं ।' ऐसी भावना चाहिए ।

हम आज गाते हैं भारत के गीत, प्राचीन के गीत । लेकिन वेद में पृथ्वीसूक्त है, भारतसूक्त नहीं । नाना धर्माण पृथिवीं विवाचसम् । यह पृथ्वी हमारी मातृ भूमि, इसमें अनक धर्म हैं और विवाचसम् अनेक प्राणियों, अनेक भाषाएँ हैं । तो अनक भाषाओं से भरी अनेक धर्मों से भरी हमारी यह पृथ्वी ! इस वास्ते हमको समझना चाहिए कि हमको विश्वमानुष बनना चाहिए । इसी वास्ते बाबा ने उद्घोष निकाला जय जगत् ।' जय जगत् से हम चीज अब नहीं चलेगी । लेकिन मिनिमम अगर रखना है कम-से-कम रखना है, वी हम भारतीय हैं, यह ठीक है, माफ है ।

यह सारा मैं आपको कह रहा हूँ सहयोग के बिलसिले में । सहयोग में मानना होगा कि सारी पृथ्वी एक है । पृथ्वी के सारे मानव एक हैं और केवल मानव ही नहीं, आसपास के पशु, पक्षी, प्राणी, वनस्पति सब एक हैं । क्रॉव का बंध देखा तो कविता स्फुरित हुई । तो आसपास की सृष्टि के साथ भी एक होना चाहिए । ये चिन्टिया हैं, सुंदर गाती हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए । ये कौएँ हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए, ये गायें हैं उनकी भी रक्षा होनी चाहिए । बटवुज की भी रक्षा हमारी चाहिए । तुरुसी की भी पूजा होनी चाहिए । यह भारत का पागलपन है । यह भारतीय पागलपन अत्यन्त महत्त्व का है, कि कुछ के कुछ मानव हम हैं और उनका अलावा आसपास के जो प्राणी हैं, वनस्पति हैं, सब हम ही हैं, इतनी एकरूपता हमको आसपास की सृष्टि के साथ होनी चाहिए । यह आज के जमाने की, विज्ञान के जमाने की माँग है । क्योंकि विज्ञान ने क्या किया है ? सबको नजदीक नजदीक लाया है । इसलिए सहयोग में सबका सहयोग—प्राणियों का, मानवों का, सबका सहयोग अपेक्षित है ।

सहयोग के लिए क्या चाहिए ? गुण ग्रहण करना चाहिए । हम जितने यहाँ

बैठे हैं, उनमें से हरएक में अण्डस्य दोष और एकाग्र गुण भगवान ने रखा है । दाप है देह ॥ साथ जुड़ हुए और गुण है आत्मा के साथ ॥ देह तो जलनेवाली है, मरनेवाली है, तो दोष सारे उसके साथ जग जायेग । मनुष्य के जो गुण हैं, वही उसको आत्मा का मुख्य स्वरूप है । इस वास्ते हमारा गुण ग्रहण करना चाहिए । इस सिलसिले में माधवदेव का वाक्य प्रसिद्ध है । उन्होंने मनुष्यों के चार वर्गों की कल्पना की । मनुष्य के चार वर्ग होते हैं—अधम, मध्यम, उत्तम और उत्तमोत्तम ।

अधम केवल दोष लवय

अधम होता है वह केवल दोष लेता है । दूसरों के दोष देखता है ।

मध्यमे गुण-दोष लवे कारिया विचार

मध्यम गुण-दोष दोनों देखकर विचार करता है । गुणदोष दोनों देखता है । अकस्तर राजनीति में लोगों को गुण, दोष दोनों देखना पड़ता है । वे मध्यम श्रेणी में आ जाते हैं ।

उत्तमे केवले गुण लवय

उत्तम केवल गुण ग्रहण करता है । उत्तमोत्तम क्या करता है ।

उत्तमोत्तमे अल्प गुण करय विस्तार

अल्प गुण का विस्तार करता है । किसी में थोड़ा सा गुण देखा तो पहाड़ करके देखता है, बढ़ाकर देखता है वह उत्तमोत्तम पुरुष है । इस प्रकार हमको एक दूसरे के गुण बढ़ाना चाहिए । हमेशा गुणगान ही करना चाहिए । मेरे रणारी में गोविन्द गुण गाना । मीराबाई कहती हैं मुझ केवल गोविन्द के गुण गाना है और कुछ नहीं । गोविन्द हरएक में भरा हुआ है । इसलिए हर एक के गुण गाये । नानक भी यही कहते हैं, 'बिन गुण के कोसे भक्ति न होई ।' जब तक गुण ग्रहण नहीं करते तब तक आपको भक्ति का स्पर्श होगा नहीं । तो नानक की यही राय है । मीरा की यही राय है । और माधवदेव की भी यही राय है ।

बचपन में बाबा हरएक को अकल की परीक्षा करता था । इसमें यह दोष है, उसमें यह दोष है । फिर बाबा ने यह धागा छोड़ दिया । बाबा ने सोचा, बिना दोषवाला आदमी दीखता नहीं । फिर अपना दोष देखना शुरू किया । तो वहाँ भी वाली दोष सीते । लेकिन वह सबके दोष देखने के बाद दोसे । पढ़ते देखा होता तो दूसरे में देखने की इच्छा न होती । सदा तुकाराम ने कहा है— 'कासया गुणदेव बाणू आनिहांचे । मज काय त्याचे उणें असे ।' दूसरों के दोष

क्यों देखें, अपने क्या कम पड़े हैं, इस वास्ते अपना ही दोष देखना अच्छा रहेगा। फिर गायत्रीजी के पास आये। तो उन्होंने कहा, 'दूसरों के गुण बढ़ाकर देखें और अपने दोष बढ़ाकर देखें।' मैंने कहा, 'आप तो सत्यनिष्ठ हैं, सत्य को महत्त्व देते हैं, क्यों बढ़ा चढ़ा कर देखना चाहिए, जो है सो देखें। गणित में बढ़ाना-घटाना चैठता नहीं।' मैं तो गणितशास्त्र का विद्वान था। सो बोले, 'तेरी बात ठीक है, पर तु सोचने की बात है, यह खेल बढ़ाने की बात है। अपना जो दोष होजा है, वह छोटा दोषता है, इसलिए बढ़ाकर देखें तो 'प्रापर पारस्पेक्टिव' (सही दर्शन) आ जाता है। ऐसे ही दूसरों के गुणों की बात। वह कम सीखता है। उसे बढ़ा-कर देखें तो ठीक पारस्पेक्टिव आ जाता है।' तो वह प्रक्रिया हमने शुरू कर दी।

उसके बाद तीसरी अवस्था आयी, जिसमें बाबा बाबा है। वह अवस्था है, दूसरे के भी गुण देखें और अपने भी गुण देखें। गुण अलावा देखना ही नहीं। बाबा से पूछते हैं, सातत्ययोग कैसे सधना चाहिए। बाबा जवाब देता है, जैसे बाबा को सधता है वैसे। बाबा ने एक विचार मन में तय किया, तो सतत, निरंतर करता रहेगा। यह बाबा का गुण है। और क्या गुण है बाबा का? दोनों के लिए कृपा है। और क्या है? स तों के वाक्यों पर ध्यान है। एक है श्रद्धा, दूसरा है श्रद्धा और तीसरा है सातत्ययोग। और बाकी है असह्य दोष। लेकिन इन चीजों का बाबा विचार करता नहीं। सीम गुण हैं, उनको आपके सामने रखता है। उसी प्रकार दूसरों में भी अनक गुण है। तो अपने भी गुण गाना और दूसरों के भी गुण गाना। मेरे राणाजी ने गोविन्द गुण गाना। यह आगे की, तीसरी अवस्था अभी बाबा को प्राप्त हुई है। वही बाबा ने आपके सामने रखी। सहयोग के लिए यह आवश्यक, लाभदायी है गुण-ग्रहण वृत्ति।

इसको बाबा ने नाम दिया है गुणचु चक वृत्ति। लोहचुम्बक होता है। वह क्या करता है? मिट्टी के अनेक कणों में लोहे के कण हैं तो उनको खींच लेता है। उसका नाम है लोहचुम्ब। वैसे हमको समझना चाहिए गुणचुम्बक। मनुष्य में जो गुण दोष पड़े होंगे, उनमें से गुण एकदम खींच लेना चाहिए। यह शक्ति अगर हममें हो तो सहयोग अच्छी तरह सधेगा।

ब्रह्मविद्या मंदिर, पवनार : १४ १० ७२

सेवाग्राम का राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन

कान्ति शाह

अखिल भारत राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन श्रीमन्नारायण की अध्यक्षता में गत १४-१५-१६ अक्टूबर '७२ को सेवाग्राम में सम्पन्न हुआ। सर्व सेवा सच की नयी तालीम समिति द्वारा यह आयोजन हुआ था। देशभर से लगभग ३०० प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। शिक्षणशास्त्रियों और समाज-सेवकों के अलावा दो-चार विद्यार्थी प्रतिनिधियों करीब २० उप कुलपतियों दो राज्यों को छोड़कर बाप समी राज्यों के शिक्षामंत्रियों, छात्र के मुख्य मंत्री और केन्द्र के उपशिक्षा मंत्रियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री मुवल हसन भी इस सम्मेलन में भाग लेने वाले थे, लेकिन रूबि उन्हें यून्स्को की एक बैठक में भाग लेने जाना था अतः जा नहीं सके। यह सफाई स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में दी। इस प्रकार पूरे देश की शिक्षण व्यवस्था का दायित्व अतिन मुख्य लोगों पर है, लगभग वे सभी लोग इस सम्मेलन में उपस्थित थे। इस लिए सहज ही यह अपेक्षा होती है कि जो कुछ विचार-विमर्श हुआ, उसके अनुसार कुछ नया प्रभावकारी परिवर्तन वर्तमान शिक्षण-व्यवस्था में लाया हो सकेगा।

यद्यपि सम्मेलन में चर्चा कोई बहुत उत्तरदायी और सतोषकारक नहीं रही। इसका मुख्य कारण हम लोगों की मापणवाजी की आदत है। थोड़े में विषय-सन्निहित विचार व्यक्त करने के बदले आधे-आधे, गोल गोल घण्टे के भाषण हुए। सेवाग्राम की पवित्र भूमि बापूजी की प्रेरणा, श्री थोमन् जी का आभार वगैरह औपचारिक और भावपूर्ण भूमिकाओं में ही वक्ताओं ने अच्छा खासा समय खर्च किया। नतीजा यह हुआ कि बहुत थोड़ा लोफ बोल सके और चर्चा किन्हीं खास विषयों पर केन्द्रित नहीं रह सकी। श्री थोमन् जी का श्रुकाव कुछ सत्ता की तरफ है, इसलिए दो थोड़े वक्ताओं में भी सरकारी अधिकारियों की ही सट्टा

अधिक रही। कुछ 'राजकीय घर्म-बायों' के गैर-जरूरी भाषणों को रोका जा सकता था।

सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान मंत्री ने किया। बैठक शुरू होने पर सा विद्या या विमुक्तये' मंत्र का अच्छा खासा उपहास मंच के ऊपर देखने को मिला। वक्ताओं ने अपने सम्बोधनों में वहाँ उपस्थित राज्यपालों, मुख्य मंत्रियों, शिक्षा-मंत्रियों, उप-कुलपतियों वगैरह का लम्बा उल्लेख जरूरी माना, लेकिन इनके आलावा भी शिक्षा जगत के अनक साधक वहाँ उपस्थित थे, तो भी उनका जिक्र तक लोगों ने उल्लेखनीय नहीं समझा। मंच पास बैठा एक विद्रोही मरे कान में फुलपुसाया, और बाका साहब जैसे कुछ छिपपुट "इतना और जोड़ देते तो अच्छा रहता।

'प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ मंत्र दिया है। इसी प्रकार शिक्षण में भी सुधार का मंत्र दें।' 'प्रधानमंत्री इस सम्मेलन को प्रेरणा हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें बहो गयीं, जिनमें विवेक और सुरुषि का दर्शन नहीं होता था, बल्कि चारण-वृत्ति की झलक मिलती थी और खुशामद की बू आती थी। यद्यपि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विवेक का परिचय दिया। उन्होंने साफ कहा 'मैं क्या प्रेरणा दे सकती हूँ? मैं तो कुछ मुझाव आपके सामने रखूँगी।' सुरुआत भी आपने इस प्रकार की, यहाँ गांधीजी के बहुत सारे साथी और शिक्षण शास्त्री बैठे हैं, बिनके-किनके नाम का उल्लेख करूँ, इसलिए सबके लिए एक साथ ही भावों और बहनों का सम्बोधन करती हूँ।'

इंदिराजी का भाषण सरल, सामान्य सूत्रबद्ध और सत्तारमक ऐंठ और आश्चर्य से रहित था। सुनकर ऐसा लगा कि अगर कोई सूत्रबद्ध बाला आदमी आज की शिक्षा-भ्यवस्था में नया मोड़ लाना चाहता है, तो उसको इंदिराजी की ओर से पूरा समर्थन ही मिलेगा। लेकिन तब एक सवाल यह जरूर उठता है कि आज की शिक्षण-व्यवस्था में इतने दोष स्वयं प्रधान मंत्री गिना रही हैं तो इसका लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं या नहीं? या फिर सत्ता खुद ही आज बितनी असमर्थ हो गयी है, इसका यह आँख खोल देनवाला उदाहरण है।

सम्मेलन की एक बैठक पवनार में विनोबा के पास रखी गयी थी। यह पूरी बैठक बहुत ही स्फूर्तिदायक थी। विनोबा ने पूरे एक घंटे के प्रवचन में निर्दोष शिक्षण प्रक्रिया के मागदमाक तत्वों को अपनी अनोखी सीरी में प्रस्तुत किया। उनका पारंगमित सूत्र, मार्मिक विनोद हृदयस्पर्शी मूलम दृष्टि, मधुर सौंदर्य ने

जादू का असर पैदा किया। प्रवचन के बाद काफी देर तक प्रश्नोत्तर भी हुए। सबकी घोष के साथ आनन्द का रसास्वादन हुआ।

सम्मेलन की पूरी चर्चा का सार लिखना तो यहाँ सम्भव नहीं होगा। फिर भी कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख करने की कोशिश करूँगा। सम्मेलन में आये शिक्षा मंत्रियों ने अपने समक्ष उठ खड़ी हुई वास्तविक कठिनाइयों की तरफ ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न किया 'जिस अनुपात में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उस अनुपात में शिक्षकों की संख्या और साधनों की वृद्धि नहीं होती है। इसलिए अनिवार्य मूल्य शिक्षण की बात राज्य की क्षमता के परे है।, 'स्कूल-बालेज से बाहर निकलने वाले शिक्षित लोगों को कोई काम मिल सके, ऐसी कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षित बेकारों की समस्या विरट होती जा रही है। शिक्षण नीति और रोजगार नीति में कोई आपसी सामंजस्य नहीं है।' शिक्षण का माध्यम प्रादेशिक भाषा को बनाने के साथ साथ सरकारी काम और सार्वजनिक व्यवहार में प्रादेशिक भाषा को योग्य स्थान नहीं मिला है। इसलिए भी समस्या जटिल हुई है।' उप-कुलपतियों ने खासकर विश्वविद्यालयों की व्यवस्था, परीक्षा पद्धति, आंतरिक मूल्यांकन, विचारियों के साथ के सम्बन्ध आदि सवाल पर चर्चाई की। बम्बई विश्वविद्यालय के श्री टोपे ने कहा कि, 'देश में सभी क्षेत्रों में समान ध्यान हो, इसकी हमारी समस्या है। नहीं तो अच्छे और सज्जवी लोग शिक्षण क्षेत्र में कहीं से आयेंगे।' केरल के श्री जैन्स ने अत्यन्त धार्मिक ढंग से कहा, 'शिक्षक तो ३० की उम्र में ही मर जाता है, लेकिन उसे चक्रवर्ति किया जाता है ६० की उम्र पूरी होने पर।'

यहाँ विद्यार्थी मण्डल के अध्यक्ष श्री जामसवाल ने कहा, 'दफ्तरों की नौकरी के लिए आज की शिक्षा हमें नहीं चाहिए। शिक्षण पूरा करने के बाद कुछ समाज-सेवा का मौका विचारियों को मिलना चाहिए। सदन शान्ति सेना के श्री सतोप भारतीय ने १०-१२ मिनट के अपने वक्तव्य द्वारा पूरे सम्मेलन में सरगर्मी पैदा कर दी। हरणाई की गरमजोशी के साथ उसने दो दूक बातें कही 'आज की शिक्षण को ये दूकानें और कारखाने बन्द करो, यहाँ छिपियों की बिक्री होती है।' 'उत्पादक थम के द्वारा शिक्षण हो, नयी तालीम का यह सत्त्व स्वीकार करो।' विद्यार्थी से पीस के बदले काम लो। बेबन्ध मेरे बाप के के पास पैसा है इसलिए मैं चाहे जहाँ पड़ सकूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए।' 'प्राइमरी से लेकर पी० एच० डी० तक उत्पादक थम को जोड़ना आवश्यक है।' शिक्षण-व्यवस्था में विचारियों प्रतिनिधित्व हो नहीं, सक्रिय भागीदारी मिलनी चाहिए।' 'शिक्षण को सरकार से

बिल्कुल मुक्त रखा जाय ।' 'पब्लिक स्कूल के सामने सत्याग्रह करो और आप सब लोग जो बोलते हो, उसके अनुसार आचरण करो ।'

शिक्षण सरकार से मुक्त हो, इस बात की सम्मेलन में खूब जमकर चर्चा हुई । विनोबा ने तो पूरा जोर देकर कहा ही, काका साहब ने भी कहा, "आज बिन सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना है । व्यक्तिगत और सरकारी से बलग यह तीसरा क्षेत्र होगा । बाकी, सरकारी काम कभी असरकारी होनेवाला नहीं है । दुनियाँ का नेतृत्व अब यमानायों या सरकार के हाथ में नहीं, शिक्षण-शास्त्रियों के हाथ में आनेवाला है, कौशलयुक्त परिश्रम को शिक्षण का माध्यम बनाना चाहिए ।"

मार्जरी साहस ने बहुत से उदाहरण देते हुए सरकारी दखलदाजी और मौकुराही प्रवृत्ति के ऊपर सख्त प्रहार किया । और अग्रहपूर्वक इसमें सुधार की माँग की । 'बट हार्ड (ऐसा क्यों ?)-पुण्य प्रकोपयुक्त जनका बार बार दुहराया गया यह वाक्य आज भी कानों में गूँज रहा है ।

गुजरात में नयी तालीम के जो प्रयोग हुए हैं उनकी जानकारी थी मनु भाई और श्री बबल भाई ने अच्छी तरह दी । उनकी बातों में अनुभव और आत्म विश्वास का बल था । श्री मनुभाई ने कहा, "शिक्षित बेकार कहना तो पुनर्वती-धाम कहने जैसा है । अशिक्षित और निरक्षर बेकार हो, तो बात समझ में आती है, लेकिन शिक्षित अनुभ्य क्यों बेकार रहते हैं ? आपने शिक्षण ही ऐसा दिया है । इसलिए शिक्षित बेकारों की बात पढ़ते क्यायात जैसी बात लगती है । नयी तालीम इसका जवाब है । यह जीवन के साथ, समाज के साथ जुड़ी हुई है । केवल कोई अमुक काम करा लिया और उसे कार्यानुभव कह दिया, इतने ॥ कोई नयी तालीम नहीं हो जाती । नयी तालीम तो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी और उत्पादक श्रम के माध्यम से शिक्षण देने की पद्धति है । सामाजिक जवाबदेही शिक्षण में, यह एक "केडलिटिक एजेंट है ।"

नयी तालीम के विषय में वहाँ आये हुए कुछ पदाधिकारियों के मन में दुरास की भावना है, ऐसा लगा । इस शब्द से कई लोगों को एलर्जी है ऐसा भी महसूस हुआ । परन्तु योजना आयोग के शिक्षण विभाग के मंत्री श्रीनाथर ने उन लोगों को जरा कठे स्वर में जवाब दिया, 'इस सम्मेलन से एक तरह से मुझे निराशा हो गई । मुनिमाचो तालीम के विषय में अगर यहाँ वैज्ञानिक रीति से विचार किया गया होता और उसके परिणामस्वरूप अगर उसे आपने अस्वीकार किया होता, तो वह उचित बात होती । लेकिन इसके बिना ही आपने बुनियादी तालीम के

विषय में जो गलत अभिप्राय बना लिया है, वह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बुनियादी तालीम का विचार एक शुद्ध वैज्ञानिक विचार है, और आधुनिकतम विचारधाराओं का अनुमोदन उसे प्राप्त है। इस विषय में मैं किसी के साथ भी चर्चा करने के लिए तैयार हूँ।”

खैर, सम्मेलन के अन्तिम दिन सर्वानुमति से एक निवेदन पारित हुआ। (देखें पृष्ठ १९२) उससे आज की शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए सम्मेलन ने क्या सुझाव पेश किये हैं, इस बात का पता चलता है। एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण के सुधार को लेकर विचार करने का यह अच्छा प्रयास था। सर्व सेवा सच की नयी तालीम समिति ने इसके लिए जो अभिक्रम किया, वह उचित ही है। श्रीमन्त्री बार बार यह कहते हैं कि गांधी विनोबा के विचारों की मात्र गांधीभक्तों के हाथों में सीमित रखने के बदले उनको व्यापक पैमाने पर फैलाना चाहिए। समाज की अन्य धाराओं को भी नज़रदीक लाने का प्रयत्न करना चाहिए और उन्हें अपने विचार और काम में ‘इन्वाल्व’ करना चाहिए। नयी तालीम समिति के अध्यक्ष के रूप में इस सम्मेलन द्वारा उन्होंने इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण पेश किया, ऐसा मुझे लगता है। सम्मेलन का संचालन एक हद तक उन्होंने अच्छी तरह ही किया। निवेदन स्वीकृत कराने में उन्होंने समामान-कारक धृति और सबको साथ लेने पर जोर दिया, यह अच्छी बात मालूम हुई।

(मूल गुजराती से अनूदित)

सम्मेलन में स्वीकृत निवेदन

अखिल भारत राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन सेवाग्राम, वर्षा में दिनांक १४, १५, १६ अक्टूबर, '७२ को सम्पन्न हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया, और अध्यक्षता नयी तालीम समिति के अध्यक्ष एवं गुजरात राज्य के राज्यपाल श्री श्रीमन् नारायण ने की। इस सम्मेलन में केन्द्रीय शिक्षा उपमंत्री, विभिन्न राज्यों के शिक्षामंत्री, अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद् और बुनियादी शिक्षा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा तैयार किये गये "राष्ट्रीय शिक्षा और विकास व सामाजिक न्याय" शीर्षक के अन्तर्गत एक विचार-पत्र सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया जिसके विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वानुमति से निम्न निष्कर्ष रहे :

(१) शिक्षा हर स्तर पर सामाजिक दृष्टि से उपयोगी एवं उत्पादक क्रिया-कारणों के द्वारा विकास और आर्थिक वृद्धि से सम्बद्ध रहकर ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में एक-सी प्रचलित हो।

विस्तार का आयोजन हो पर गुणात्मक विकास पर बह हावी न हो।

(२) प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तरों के पाठ्यक्रमों में तीन मूल तत्वों पर बल देना चाहिए।

(क) आत्मनिर्मरता, आत्मविश्वास तथा शैक्षणिक कार्यक्रम के अविभाज्य अंग के रूप में कार्यों के द्वारा श्रमप्रतिष्ठा,

(ख) सामुदायिक सेवा के सार्थक कार्यक्रमों में छात्रों और शिक्षकों के सहयोग के द्वारा राष्ट्रीयता एवं सामाजिक दायित्व की भावना और,

(ग) नैतिक मूल्यों का गुंजन, सर्व धर्म समभाव और उनके मूलभूत सिद्धान्तों की एकता को समझना।

इन पाठ्यक्रमों में हमारी सम्पुष्टि सांस्कृतिक परम्परा की आम जानकारी, भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास, राष्ट्रीय एकता पर बल, अन्तराष्ट्रीय सहयोग तथा अहिंसा, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और हमारे तत्विधान में निहित सर्व धर्म समभाव के मूल तत्वों का समावेश होना चाहिए।

माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तरों पर अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शिक्षा-शास्त्र, समाज-शास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों में गांधी विचारधारा का अध्ययन भी आरम्भ किया जाना चाहिए।

सन्तों के विचार में न पड़कर प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर बुनियादी शिक्षा दृष्ट की पद्धति किया जाना चाहिए।

(३) शैक्षणिक ढाँचे के विभिन्न स्तरों को १० + २ + ३ होना चाहिए ।
 माध्यमिक शिक्षा को १० वर्षों की पढ़ाई के उपरान्त २ वर्षों के ऐसे अनेक पाठ्य-
 क्रम होने चाहिए जिनसे छात्र रोजगार के अवसर प्राप्त कर जीवन गुरु कर सकें ।
 विभिन्न सरकारी विभाग अपनी आवश्यकतानुसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ कर
 सकते हैं । माध्यमिक शिक्षा स्तर के बाद विश्वविद्यालय में पहला डिग्री का
 पाठ्यक्रम तीन वर्षों का होना चाहिए उसके बाद स्नातकोत्तर और अनुसंधान
 पाठ्यक्रम आरम्भ हो ।

दो वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का स्वरूप अंतिम होना चाहिए लेकिन इसे
 पूरा करने के बाद छात्र के लिए भविष्य में उच्च अध्ययन का काम पूरा तरह
 सुझा होना चाहिए ।

स्वातंत्र्य आवश्यकताओं के अनुसार गहन शिक्षा देने के सहस्र सं छुट्टियों में
 समुचित गेट आउट कर अनुसूचना लागू चाहिए ।

(४) प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल सभी बच्चों के लिए समान स्तर पर
 खुले होने चाहिए चाहे उनकी जाति, भाषा, धर्म या आर्थिक सामाजिक स्तर कुछ
 भी हो । शिक्षा आयोग द्वारा सुझाये गये बहुस्तरीय स्कूल के विचार के प्रयोगों को
 उचित अवसर मिलना चाहिए । सामाजिक न्याय की दृष्टि से शिक्षा के विभिन्न
 स्तरों पर अनेक मोधता व साधन छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध होनी चाहिए ताकि
 कोई भी छात्र इस कारण उच्चतम शिक्षा से वंचित न रह सके क्योंकि उसके
 माता-पिता निधन हैं ।

(५) सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूल की एक आम
 पद्धति वांछनीय है, फिर भी राज्य सरकारों का चाहिए कि वे विभिन्न संतुष्टों को
 शैक्षणिक संस्थाओं की अभ्ययन के तरीकों, परीक्षा पद्धति पाठ्यक्रम में विषय के
 सहूलता, पाठ्यपुस्तकों की सीधारी और शिक्षकों की तालीम की दिशा में नये
 प्रयोगों को सक्रिय प्रोत्साहन प्रदान करें । एकस्वता पर शिष्टे जानेवाले भार को
 शैक्षणिक क्षेत्र में नवीन प्रयोगों और अनुसंधान की दिशा में बाँक नही होना
 चाहिए । शैक्षणिक आगमों में राज्य का अनुचित हस्तक्षेप नही होना चाहिए ।

शिक्षा आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त स्वायत्त महाविद्यालयों की कल्पना को अव
 सकारामक तरीके से अमल में लाना चाहिए ।

(६) यद्यपि निजी संस्थाओं में मौजूद अनेक सुझावों की हटाने के भरसक
 प्रयत्न होने चाहिए लेकिन प्रशासन की माध्यमिक स्तरों और कालेजों की अकाने
 को समस्त बिम्बेगारों उठा लेने के दबाव में नही आ जाना चाहिए ।

(७) लगभग सभी राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा का

माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है। उसको विश्वविद्यालय स्तर पर भी शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत करने के लिए तात्कालिक कदम उठाये जाने चाहिए।

भारतीय भाषाओं के लिए एक वैकल्पिक लिपि के रूप में नागरी लिपि को प्रोत्साहन दिया जाय।

(८) इस शैक्षणिक सुधार में खोघ्रता लाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि सिविल तथा मिलिटरी सेवाओं के लिए अखिल भारत प्रतियोगिक परीक्षाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में लिया जाय और सम्बोद्धवारों को प्रत्येक राज्य के लिए नियत कोटे के अनुसार सर्क्युलर आधार पर चुना जाय। इन सेवाओं का अखिल भारतीय स्वरूप कायम रखने के लिए चुने गये प्रत्याशियों को हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान कराया जाय तथा उन्हें राष्ट्रीय इतिहास, संस्कृति, भारतीय सभ्यता और आर्थिक संयोजन की भी जानकारी दी जाय।

(९) परीक्षा के वर्तमान ढंग से छात्रों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक क्षमताओं पर बड़ा घुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि परीक्षा-पद्धति में अविलम्ब आमूल सुधार किये जायें। बाहरी परीक्षाओं के अतिरिक्त प्रत्येक विषय विभाग द्वारा आन्तरिक मूल्यांकन पर सतत पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि अन्तिम परीक्षा के अनुचित महत्त्व को कम किया जा सके। व्यावहारिक कार्य और मौखिक परीक्षाओं को प्रोत्साहन दिया जाय।

परीक्षा-पद्धति न केवल शिक्षाधियों की केवल बौद्धिक सिद्धि की जाँच करे, बल्कि उत्पादक और विकास प्रवृत्तियों के सहगामी कार्यक्रमों, समाजसेवा और निमित्त उपस्थिति तथा सामान्य व्यवहार पर भी ध्यान दे।

(१०) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में नौकरियों में डिग्री का सम्बन्ध-विच्छेद कर देने के लिए भरसक प्रयत्न किये जाने चाहिए। इस उद्देश्य से भर्ती के नियमों में समुचित संशोधन किया जाय इससे विश्वविद्यालयों में प्रवेश की भीड़, परीक्षाओं में आचारहीनता कम हो जावेगी और एक ठोस आधार पर प्रगतिशील शैक्षणिक विकास को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

(११) कोई भी शैक्षणिक सुधार शिक्षकों की गुणवत्ता और प्रशिक्षण में सुधार लाये बिना सम्भव नहीं है। अस्तु शिक्षकों का वर्तव्य है कि वे छात्रों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रशिक्षित करने का भरसक प्रयास करें। लेबिन सरकार का भी यह वर्तव्य है कि वह शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊँचा उठाये और उन्हें दैनिक आर्थिक चिन्ताओं से मुक्त करे।

शिक्षक दलगत राजनीति में न चलें। वे इस दिशा में एक समुचित आचार-

सहिता का पालन करें। विनोबाजी द्वारा प्रवर्तित आचार्यकुल का उपयोग इस दिशा में शिक्षकों के द्वारा किया जा सकता है।

(१२) शैक्षणिक पुनरचना के महत्वपूर्ण कार्य में सभी स्तरों पर माता पिता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है। इस उद्देश्य से विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पालक शिक्षक मण्डल एक सामान्य व्यवस्था बन जानी चाहिए। वास्तव में प्रत्येक परिवार को सहोदर्य में एक बुनियादी शिक्षा की इकाई के रूप में विकसित होना चाहिए।

(१३) शैक्षणिक सुधार की नीति निर्माण प्रक्रिया में छात्रों का सहकार लेना जरूरी है। छात्र सघों का उपयोग विद्यार्थियों में आत्मसदम लागू करने और अधिक जिम्मेदारी की भावना जाग्रत करने की दृष्टि से किया जाय।

नवयुवकों को यह बात समझायी जाय कि हिंसा के वर्तमान तरीकों से अनिवार्य प्रतिहिंसा उत्पन्न होगी और हमारे लोकतांत्रिक ढाँचे को हानि पहुँचेगी।

(१४) यह वास्तव में अत्यन्त विचारणीय विषय है कि पिछले २५ वर्षों में किये गये विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं के बावजूद हमारी आजादी का ७० प्रतिशत जरा जमी भी निरक्षर बना हुआ है। इसलिए जनता में व्यावहारिक साक्षरता ज्ञान के लिए संगठित प्रयत्न किये जाय ताकि जनता में श्रेष्ठतर नागरिक जागरूकता पैदा होने के असावा उनकी कुशलताओं में सुधार हो सके। इस राष्ट्रीय अभियान में सामुदायिक सेवा की प्रवृत्ति के रूप में छात्रों और शिक्षकों का सहयोग प्राप्त किया जाय।

(१५) विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेल-कूद का बड़े पैमाने पर विकास किया जाय और प्रतिभाशील नवयुवकों का भौलीभाँति चयन कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाय।

(१६) सम्मेलन आशा करता है कि केन्द्र और राज्य सरकारें, शिक्षाविद और सामान्य जनता शिक्षा को अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में अत्यन्त उच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी और इस अनुशासनों को शीघ्रता और दृढ़ता के साथ हमारी स्वाधीनता की इस रजत जयन्ती वर्ष में अमल में लायेगी।

सम्मेलन के अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है कि वे एक पन्द्रह सदस्यीय कार्य समिति की नियुक्ति करें और उन्हें इस निवेदन में निहित शैक्षणिक सुधारों की प्रक्रिया को तीव्र बनाने के उद्देश्य से अन्य सदस्यों को सहवर्तित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। ●

शिक्षा में सुधार के लिए पन्द्रह सदस्यीय समिति का गठन

अहमदाबाद १ नवम्बर । गुजरात के राज्यपाल तथा अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायण ने अभी हाल में सैयाग्राम में आयोजित सम्मेलन द्वारा जारी किये गये मोति विपयक वक्तव्य के अनुसार शिक्षा सम्वन्धी सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निमित्त १५ व्यक्तियों की एक समिति गठित की है ।

एकत समिति में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश के शिक्षामंत्री, काशी विद्यापीठ, केरल, नागपुर, विश्वभारती और गुजरात कृषि विद्यालय के उप-कुलपति हैं । गार्गी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री आर. आर. दिवाकर और केन्द्रीय आचार्यकुल समिति भी के संयोजक श्रीवंशीधर श्रीवास्तव समिति में हैं ।

समिति की समस्त बैठकों में केन्द्रीय शिक्षामंत्री श्री तुलल हसन-डा. डी. एस. कोठारी और योजना आयोग के सदस्य श्री एस. चक्रवर्ती, को विशेष रूप से बुलाया जायगा ।

समिति की पहली बैठक ३ दिसम्बर को दिल्ली में होगी ।

—यू. न्यू—

दलमुक्त शिक्षक, सरकारमुक्त शिक्षण

२८, -९ अक्तूबर को पवनार (वर्धा) में महाराष्ट्र की जो 'आचार्यकुल परिषद' हुई, वह अपने आप में एक नयी बात मानी जायेगी। महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले के लगभग चार सौ शिक्षकों (प्राचार्य, आचार्य) का इकट्ठा होना, दो दिन तक आचार्यकुल की वैचारिक भूमिका को समझना, हर बात को तर्क की कठोर कसौटी पर कसना, और अन्त में मूल विचार को स्वीकार करना, और पूरे महाराष्ट्र के लिए संगठन का ढाँचा तय करना, यह सब ऐसा काम है जो इस पैमाने पर इस तत्परता के साथ अभी तक किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ है। इसलिए विनोबाजी ने अपने अन्तिम भाषण में ठीक ही कहा 'आशा की जा सकती है कि यह बीज किसी दिन बट वृक्ष बनेगा।'

आचार्यकुल में बुद्धि की सत्ता का संदेश है। यह संदेश लगता है, महाराष्ट्र की बुद्धि प्रधान योजना को स्पर्श कर रहा है, और अब उससे से स्फूर्ति प्रकट होने लगी है। ऐसा होना भी चाहिए। और, यह मानने का कोई कारण नहीं कि जो काम महाराष्ट्र में हो सकता है, वह दूसरे राज्यों में नहीं हो सकता। जरूर हो सकता है, बशर्ते महाराष्ट्र की तरह हर राज्य को एक मामा क्षीरसागर मिल जाये, जिन्होंने पिछले चार वर्ष अनवरत परिश्रम कर महाराष्ट्र भर में शिक्षकों से संपर्क किया है और उन तक आचार्यकुल का संदेश पहुँचाया है।

हम आज वर्षों से जिस ग्रामस्वराज्य की कल्पना समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वह आज के सामाजिक ढाँचे में सम्भव नहीं है। इसलिए हम समाज-परिवर्तन की बात कहते हैं। किन्तु समाज-परिवर्तन की वह शक्ति क्या है जिसका प्रयोग हम परिवर्तन के लिए करना चाहते हैं ? हमने वर्ग-संघर्ष को अस्वीकार किया है। हमने माना है कि वर्ग-संघर्ष से सत्ता का परिवर्तन होता है, समाज का नहीं। समाज के सम्बन्धों और जीवन के मूल्य वर्गों-त्रे-द्वयों वने रह जाते हैं। कोई भी सरकार हो कितनी भी कल्याणकारी हो, वह अपनी सत्ता के मुकाबले जनता की सत्ता नहीं कायम होने दे सकती। इस स्थिति में यह निर्विवाद है कि सामाजिक क्रान्ति के बिना समाज परिवर्तन सम्भव नहीं है। प्रश्न है कि यह परिवर्तन किस शक्ति से आयेगा ?

हमने परिवर्तन की दो ही शक्तियाँ मानी हैं : एक, धर्म की शक्ति-दूसरी, बुद्धि की शक्ति। आज के समाज में धर्म और उत्तापन की दो इकाइयाँ हैं—गाँव और कारखाना। बुद्धि की इकाई विद्यालय है। गाँव, कारखाना, और विद्यालय ये तीन हमारे आन्दोलन के ऐसे धिन्दु हैं जहाँ हमें शक्ति संगठित करनी है। गाँव के लिए हमने माध्यम माना है ग्रामस्वराज्य तथा विद्यालय के लिए आचार्यकुल और तरुण-शान्ति सेना को कारखानों के लिए 'ट्रस्टीशिप' के आधार पर संगठन का कोई स्वरूप विकसित करना अभी बाकी है। क्रान्ति की व्यूह रचना में इन चीनों मोर्चों पर साथ साथ लड़ना होगा, आगे पीछे लड़ने का प्रश्न नहीं है। महाराष्ट्र के साधियों ने विद्यालय के मोर्चे के महत्त्व को समझा है। उनके उदाहरण का अनुकरण दूसरे राज्यों में भी होना चाहिए।

आचार्यकुल के सम्बन्ध में शिक्षक-मित्रों की ओर से दो प्रश्न विशेष रूप से उठाये जाते हैं। एक है, राजनीति के साथ सम्बन्ध, और दूसरा सरकार के साथ सम्बन्ध। अन्य लोगों की तरह शिक्षक भी, जिनमें बड़े नामधारी विद्वान भी शामिल हैं, मानता है कि राजनीति-दलगत राजनीति—के साथ जुड़े बिना वह प्रभावकारी नहीं हो सकता, और सरकार के संरक्षण के बिना उसकी जीविका सुरक्षित नहीं हो सकती। इसलिए आज जगह-जगह शिक्षकों की ओर से माँग हो रही है कि शिक्षा का सरकार अपने हाथ में ले ले। यों तो शिक्षा बहुत कुछ सरकार के नियंत्रण में है ही, फिर भी शिक्षक मुख्य रूप से अपने वेतन

का गारण्टी सरकार से चाहता है। विद्यालयों के मालिकों की घाँटली से मुक्ति पाने के लिए शिक्षक शासकों की शरण में जाना चाहता है। कुछ भा हो, वेतन की गारण्टी मिलना चाहिए। लेकिन शिक्षा में प्रश्न मात्र शिक्षकों के वेतन का नहीं है, सबसे बड़ा प्रश्न है विद्यार्थियों के शिक्षण का, देश के भविष्य का, लोकतंत्र और विज्ञान की भूमिका में स्वतंत्र बुद्धि के विकास का। यह चीन हिंसी पार्ग की आज घनने कल विगडनेवाली सरकार और उसकी नौकरशाही के हाथों में नहीं सोंपी जा सकती। बुद्धि, स्वतंत्र बुद्धि, मनुष्य की सबसे बड़ी पूजी है, और यह समान के दायरे की चीज है, राजनीति और सरकार के दायरे की नहीं। इसीलिए शिक्षण की स्वतंत्रता की माँग है। हर विद्यालय एक स्वायत्त इकाई हो, जिसका आन्तरिक जीवन, अभ्यासक्रम, परीक्षा, विनय, व्यवस्था आदि—शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की सम्मिलित समिति पर हो। इसी आधार पर नीचे से ऊपर तक शिक्षक की यह जिम्मेदारी नहीं मानो जा सकती कि वह नौकरियों के लिए 'पासपोट' दे। उसका काम है शिक्षित प्रशिक्षित करना। सरकार तथा अर्द्ध सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएँ अपने लिए उपयुक्त व्यक्तियों के चुनाव के लिए अपने अपने भलग टेस्ट रखें और नौकरियाँ दें।

इस प्रकार आचार्यकुल की योजनाओं में वेतन की गारण्टी के साथ दलमुक्त शिक्षक और सरकार मुक्त शिक्षा का मेल मिलाया जा सकता है, मिलाया जाना चाहिए। आचार्यकुल उन लोगों का भाईचारा है जो बुद्धि की सत्ता में विश्वास रखते हैं। दल, ग्रन्थ या गुरु की सत्ता में विश्वास का उसके साथ मेल नहीं है। बुद्धि का एक ही पक्ष है—सत्य। आचार्यकुल सत्य की वाणी है।

विद्यालय का आन्तरिक जीवन सरकार से मुक्त हो, और गाँव का आन्तरिक जीवन सरकार से मुक्त हो। भूमि पर से मालिक की मालकियत हटे, और शिक्षण पर से सरकार की हुकूमत। ये देश की जनता की मुक्ति के प्रश्न हैं, करोड़ों के सच्चे स्वराज्य के प्रश्न हैं, इस पर समझौता नहीं किया जा सकता।

—राममूर्ति

सम्पादक मण्डल :

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक

श्री बशीर, श्री वास्तव

आचार्य राममूर्ति

वर्ष : २१

अंक : ४

मूल्य : ७० पैसे

अनुक्रम

राष्ट्र की शिक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी	१४५ सम्पादकीय
मुनियारो शिक्षा का क्रमिक विकास	१४९ मनी, नयी तालीम समिति
शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक	१५६ इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय शिक्षा और विकास व सामाजिक न्याय	१६० श्रीमन्नारायण
शिक्षा की तीन मुनियारो	१७७ विनोबा
सैबाग्राम का राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन	१८७ काति शाह
सम्मेलन में स्वीकृत निबंद	१९२
दलमुक्त शिक्षक, सरकारमुक्त शिक्षण	१९७ राममूर्ति

नवम्बर, १९२

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्दा आठ रुपये है और एक अंक के ७० पैसे ।
- पत्र व्यवहार करते समय छाहक अपनी छाहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट, द्वारा सर्व सेवा सच के लिए प्रकाशित,
अनुपम प्रेस, के २९/१० दुर्गाबाट, वाराणसी में मुद्रित

नयी तालीम : नवम्बर, '७२

पहिले में टाक-व्यय दिये बिना भेजने का स्वीकृति प्राप्त

लाइसेंस नं० ४६

रजि० सं० एल० १७२३

विनोबा-कृत लोकनोति-साहित्य सेट

२५) का सेट १७)५० में

* तीसरी शक्ति	३-००
लोकनोति	२-००
स्त्री-शक्ति	१-५०
गांधी जैसा देखा समझा	३-००
ग्रामदान	२-००
आचार्यकुल	१-००
साधो विचार	४-००
शान्ति-मेला	२-००
शिक्षण विचार	३-००
विनोबाजी की अन्य पुस्तकें	४-५०
	<hr/> २५-००

इस सेट में विनोबाजी के अद्यतन प्रकाशनो को भी समाविष्ट करने हृष्टि से कुछ परिवर्तन करते रहने का खयाल है, फिर भी अधिकांश वित्तार्थ कायम रहेगी।

विनोबा-कृत धर्म-साहित्य-सेट

२५) का सेट १७)५० में

गीता प्रवचन	२-५०
स्वित्तप्रज्ञ दर्शन	२-००
कुरान-सार	३-००
ख्रिस्त धर्म-सार	३-००
धम्मपदम् (नव-महिता)	४-००
भागवत-धर्म-मीमांसा	२-००
जपुजी	२-००
अध्यात्म-तत्व-मुषा	२-००
सप्त-शक्तियाँ	१-००
अन्य विनोबाकृत धर्म-साहित्य	३-५०
	<hr/> २५-००

एकमे २५-०० की कीमत के ये सेट रु० १७-५० में प्राप्त होंगे। १६ सेटों का पूरा बटल लेने पर प्रति सेट रु० १-५० कमीशन और निकटतम रेलवे स्टेशन तक फ्री डिलीवरी दी जायगी। यह सुविधा केवल धाराणसी से दी जायगी। टाक से मँगाना हो तो प्रति सेट रु० २-५० पोस्टेज का जोड़कर रु० २०-०० भेजना होगा।

सर्व-सेवा संघ प्रकाशक-राजघाट, धाराणसी-१

दिसम्बर १९७२



“हिमाद्रि तुंग शृंग से ”

शिक्षातंत्र अ-सरकारी मार्बजनिक बने

व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए चाहे जो साधना पसन्द करे और चलावे, अपने आनन्द के लिए चाहे जो प्रवृत्ति अपनावे, वह उसकी अभिरुचि का सवाल है।

सामाजिक जीवन की बात उससे बिलकुल अलग है। इसमें केवल अपनी अभिरुचि का ख्याल करके हम चल नहीं सकते। समाज का वायुमण्डल, समाज की आवश्यकताएँ, नेताओं की अभिरुचि, सामान्य जनता का आकर्षण सब बातों का ख्याल करना ही पड़ता है।

आज हमारे राष्ट्रीय जीवन में दो प्रधान तत्वों का विशेष बोलबाला है। एक है प्रधानतया सत्ता और सम्पत्ति के द्वारा होनेवाले काम। और दूसरी है, सेवा और शिक्षा के द्वारा विकसित होनेवाली प्रवृत्तियाँ।

आदर्श समाज में 'सत्ता और सम्पत्ति' की प्रभावना नहीं होनी चाहिए। 'शिक्षा और सेवा' ही संस्कृति के प्रधान तत्व होने चाहिए। यह भेद मान्य करके भी हम कह सकते हैं कि आखिरकार सामाजिक जीवन एक ऐसी समृद्ध और जटिल प्रवृत्ति है कि उसमें ये चारों तत्व मिले-जुले रहते हैं। जीवन इन चारों में से एक भी तत्व को आज छोड़ नहीं सकता; तो भी इन दोनों जोड़ियों का अलग अलग विचार करना उपयोगी है।

वर्ष : २१

अंक : ५

रहे हैं किअथ साकृति के आदर्श अथवा आध्यात्मिक सस्कृति के प्रधान साधन 'शिक्षा और सेवा' सरकार के ही सुपुर्दे करने की सूचनाएँ समाज के सामने आ रही हैं, और मान्य भी हो रही हैं।

सरकार की सत्ता का अनुभव शहर के और गाँव के लोगों को एक सा होता है। सरकार की मल्लो बुरी 'सेवा' का अनुभव शहरों तक ही सीमित है। 'सरकार की सेवा' गाँवों तक पहुँचनी चाहिए, इस आदर्श का स्वीकार सब करते हैं किन्तु प्रत्यक्ष अनुभव को देखने जायँ तो वह उसके अभाव में ही यहाँ प्रतीत होता है। सरकार नामक सस्था की एकांगिकता पहचानने का साधन इसी में हमें मिल रहा है।

सरकार नामक सस्था का संगठन हमारे देश में मुस्लिम काल में ही विशेष रूप से हुआ। यानी विदेशी राज शुरू होने पर उनकी राज-नैतिक और छरकरी शक्ति के द्वारा हुआ। भारत के लोगों में संगठन का अनुभव बिल्कुल सामान्य किन्तु चातुर्यपूर्ण था। उसका लाभ विदेशी राज्यों को मिला। फलतः सार्वजनिक संगठन की अपेक्षा सरकारी संगठन अधिक मजबूत हुआ। उसकी प्रतिष्ठा तो 'युद्ध में हारकर ही' हमें मान्य करनी पड़ी थी। वही परम्परा पोर्तुगीज, फ्रेंच और अंग्रेज इन तीन पश्चिमी राज्य सत्ता के द्वारा बढ़ती गयी। आज भारत में प्रजाराज्य है। सरकार की चोटी तत्त्वतः पूर्णतया जनता के हाथ में है। लेकिन जनता इतनी संगठित नहीं है जितनी सरकार संगठित है, और हर कोई काम जोर कर सकता है संगठन के द्वारा ही। इस लिए लोग भी चाहने लगे हैं कि सब प्रजाकीय काम जहाँ तक हो सके सरकार के द्वारा ही किया जाय।

'सरकार और सार्वजनिक जीवन दोनों पूर्णतया एक ही हैं' ऐसा समझकर लग चलने लगे हैं। और इसी में हमारे राष्ट्रीय जीवन में खतरा शुरू हो गया है।

इस परिस्थिति का विश्लेषण एक दफे मैंने जवाहरलालजी के सामने किया था। मैंने उनसे कहा था कि, "आप डेमोक्रेटिक सोशियोलिज्म (Democratic Socialism) भारत में लाना चाहते हैं और ला सके हैं ब्यूरोक्रेटिक सोशियोलिज्म (Bureaucratic Socialism)। सार्वभौम मतदान के कारण तत्त्वतः वर्गभौम सरकार की चोटी जनता के हाथ में है। किन्तु असल में आपका समाजवाद 'अमलदार-शाही समाजवाद' होने जा रहा है।"

जो हो, इसका एक उदाहरण सारे खतरों को स्पष्ट करने के लिए काफी है।

भारत में प्राचीन काल में शिक्षा का सारा प्रबन्ध ब्राह्मणों के हाथों में था। (उद्योग हुनरों की शिक्षा उन-उन विषयों के निष्णातों के हाथों में थी और वह 'जाति संस्था' द्वारा संगठित होती थी।) अंग्रेजों के आने के बाद सरकारी तंत्र मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना 'नया अंग्रेजी शिक्षातंत्र' सरकार के द्वारा चलाया। और उसमें जो स्नातक तैयार होते थे उनको अच्छी-अच्छी नौकरियाँ दिलाकर उन्हें सरकारी तंत्र में ग्वाँच लिया। शिक्षा मिले सरकार के द्वारा और उसके फलस्वरूप अच्छी-अच्छी नौकरियाँ मिलें सो भी सरकार द्वारा; यह नयी परिस्थिति ध्यान में आते ही (और नयी शिक्षा का सांस्कृतिक प्रभाव देख करके भी) जनता के स्वराज्यवादी नेताओं ने राष्ट्र भक्ति और त्याग के बल पर 'दानगी' यानी दिना सरकारी शिक्षा संस्थाएँ चलायीं। लेकिन शिक्षा के अन्त में जो उपाधि, डिग्रियाँ मिलती हैं वह तो सरकार निर्मित युनिवर्सिटियाँ ही दे सकती थीं। सभी तो सरकारी नौकरियाँ मिल सकती थीं !

'राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा' के आदर्श से प्रेरित होकर जो हांग्याएँ शुरू हुईं, वे सब 'सरकारी तंत्र की मदद के लिए किन्तु सरकारी तंत्र से अक्षिप्त' चलने लगीं। लेकिन उन्हें युनिवर्सिटी के मातहत हो काम करना पड़ा।

(अब यहाँ से कलबुग शुरू होता है।) सरकार के कॉलेज और हाईस्कूलों का पूरा खर्चा सरकार को ही करना पड़ता था। इस खानगी हाईस्कूल-कॉलेजों का तंत्र राष्ट्रसेवा और त्याग-भावना से किया जाता था। अब इन संस्थाओं को सरकार ने अनुदान (ग्राण्ट) देना शुरू किया। किन्तु नियम किया कि आपके खर्चों के हिसाब से अमुक टका आपको ग्राण्ट मिलेगी। अध्यापक कम तनखाह लेकर नौकरी करते थे। इसलिए उस हिसाब से ग्राण्ट कम मिलेगी। तब देश के नेता अगर कहते कि 'हमारे खर्चों के हिसाब से नहीं किन्तु कार्य के हिसाब से ग्राण्ट देने के बलगत नियम आपको बनाने होंगे' तो अच्छा होता। लेकिन सरकारी तंत्र की प्रतिष्ठा ब्यादा ! हम लोगों ने आसानी

देखकर एक खराब रास्ता निकाला। केवल हिसाब में सरकारी प्रोफेसरों को जैसी तनखाह मिलती थी वैसी ही खानगी सस्था के प्रोफेसरों को देने का हिसाब रखने लगे। और अध्यापकों को असली तनखाह ही दी जाती थी। बाकी की रकम अध्यापकों की ओर से 'सस्था को दान के रूप में' मिल रही है ऐसा बताया जाता था। (यह एक तरह से सर्वमान्य ठगी ही थी।) यह कहाँ तक चले ?

खानगी सस्थाएँ खूब बढ़ी थीं। उनमें और दोष तो घुस गये ही थे। इनमें तनखाह की रकम बतानी अलग और देनी अलग यह नियम घुस गया। तब से अध्यापकों में असन्तोष बढ़ने लगा। और इन्हीं की ओर से शिक्षा सस्था के साठन के बारे में नये कानून होने लगे। अध्यापक चाहते हैं कि सरकारी नौकरों को जो तनखाह, जो प्रतिष्ठा, जो अवधान मिलने हैं वे सब हमें कानून द्वारा मिलने चाहिए।

और अब तो स्वराज्य यानी प्रजा राज्य हुआ है। सारी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने के नाम से सरकारीकरण हो रहा है। देश के नेता जानते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था सरकार के हाथ में जाने से उसमें सरकारीकरण के सब दोष आ जायेंगे। और अध्यापक तो सरकारीकरण के पक्ष में ही हैं। (मात्र सरकारीकरण नाम अच्छा नहीं, इसलिए उसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है।)

सेवा और सत्ता का इस तरह से एकत्र आना एक तरह से अपरिहार्य ही है लेकिन उससे खतरा कम नहीं होता।

—काका काळेकर

ज्योति भाई देसाई

एक शैक्षिक प्रयोजना : घर, शाला और समाज

[राणी विद्यापीठ, चेडडी, गुनराव में नयी तालीम का एक बड़ा और सफल प्रयोग केन्द्र है । उसके अन्तर्गत चलनेवाले स्नातक अध्यापन मन्दिर के आचार्य श्री ज्योति भाई देसाई द्वारा यहाँ के लिए तैयार की गयी यह शैक्षिक प्रयोजना अन्य अध्यापन संस्थानों तथा अध्यापकों के लिए विशेष उपयोगी होगी, ऐसी आशा है ।—सम्पादक]

इसीलिए यह कहा जाता है कि शिक्षकों को उनके जीवा मूल्यों के बारे में स्पष्टता होनी आवश्यक है । आम शिक्षक समाज के मौजूदा मूल्यों को ही विद्यार्थियों तक पहुँचाता है 'पढ़ोगे नहीं तो खेती करनी होगी, पंवार बने रहोगे, और भ्रष्ट के पोछे पोछे जिन्दगी भर घटवोगे । मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगे तो और दूसरा क्या होगा । आगे बढ़ना, प्रयत्न आना, सबके आगे निकल जाना यही तो जीवा का लक्ष्य है ।' ऐसी बातें शिक्षक विद्यार्थी को सिखाता है । वह समाज के मूल्यों को प्रसारित करने का धन्धा करता है । क्योंकि उसे अपने जीवन में यही प्राप्त हुआ है । येन केन प्रकारेण सफलता प्राप्त करना यानी पोषण के साधन प्राप्त करने का लक्ष्य समाज के सामने है । तो ये सारे मूल्य विद्यार्थी को देने का ही काम शिक्षक भी करते हैं । जिज्ञा की दृक्कानदारी करनेवाले शिक्षक आमतौर पर कह देते हैं, 'हमने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया, अधिक नम्बर प्राप्त करने की सब युक्ति प्रयुक्तियाँ सिखा दी । अब नीकरी नहीं मिलती, इन्जीनियर बनकर भी बेकार और निऊले बैठ हो, तो हम क्या करें ।' लाचार शिक्षक, लाचार विद्यार्थी ।

ही नहीं करते, समाज को नये मूल्य प्रदान करते हैं। इसी कारण शिक्षक और शिक्षा को समाज में आमूल परिवर्तन लाने के माध्यम माने गये हैं। नयी तालीम के शिक्षक की यह परिवर्तना है। उसे साकार करने की हम कोशिश करें।

ऐसे शिक्षक बनने की इच्छा स्वेच्छा से प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रयोजना द्वारा ऐसी स्वेच्छा जयने की कल्पना है। क्योंकि इस प्रयोजना में समाज के बीच जाना, नये मूल्यों के बारे में सोचना आदि अपेक्षा है। इसके लिए नयी तालीम के सच्चे शिक्षक बनने के लिए तथा समाज में सनातन सत्यों को पकड़ रखने की ताकत पैदा करने के लिए, जीवन भर की कोशिश भी अल्प ही होगी, ऐसा सम्भव है।

इस प्रयोजना के द्वारा हम स्कूल को पहचानने को चेष्टा करेंगे। इसका अर्थ यह कि ऊपर बतायी हुई बातों को अपने सामने रखकर शिक्षक क्या पढ़ता है, वह देखना होगा। हम बच्चों को भी समझने की कोशिश करेंगे। उनके मन में क्या क्या करने की इच्छाएँ हैं? नयी-नयी प्रवृत्तियों में दिलचस्पी क्यों है? काम करने में आनन्द क्यों आता है? जीवन में काम बच्चों को पसन्द नहीं? जानी का नामसन्दर्भ और पतनदशा के मूल क्या? कहाँ है? अभिभावकों को भी समझने की चेष्टा करेंगे। उनकी स्कूल से क्या अपेक्षाएँ हैं? यह सब जानने की कोशिश विद्यार्थी के जाने स्वस्थ और तटस्थ भाव से करेंगे। हमारी इस नीति का एक महत्त्व का अंग यह है कि हम प्रत्यक्ष काम के द्वारा यह जानकारी प्राप्त करेंगे। नागजी जाँच नहीं करेंगे। एक महत्त्व का काम समाज के समाने लेकर जायेंगे और उससे द्वारा हमें जो समझना है, वह समझेंगे। 'शिक्षा में प्राप्ति' का कार्यक्रम उठावेंगे। स्कूल में शिक्षकों, बच्चों को उसमें शामिल होने के लिए कहेंगे। समाज का भी सहकार माँगेंगे।

यह काम ठीक ढंग से हो, इसके लिए शिक्षार्थी के दिमाग में सैद्धांतिक स्पष्टताएँ हों, ऐसी व्यवस्था करेंगे। अपने पाठ्यक्रम में मानसशास्त्र एवं नयी तालीम के सिद्धान्तों को, प्रश्न-नामों के महत्त्व को समझा देंगे। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के प्रश्न-पत्रों का भी अध्ययन किया जायेगा।

'शिक्षक बनना यानी सही मूल्यों की प्राप्ति करना' यह विचार हमें अपने सामने रखना है। क्योंकि मूल्यों का आदान-प्रदान ही शिक्षा है। शिक्षार्थी यह बात इस प्रयोजना के द्वारा समझने की कोशिश कर सकें, ऐसी अपेक्षा है।

ता० २७।८।'७२ अद्वैत तैयार करें, मृत्यान्त करे, परस्पर अनुभवों का ऐन-देन करें।

प्रयोजना के दिनों में दिनचर्या

- १०-३० बजे तक अपने गाँव पहुँचना,
 १०-३०—११-०० स्कूल की वास्तवता का सन्धान करना,
 ११-००— २-०० स्कूल में प्रवृत्ति धरना,
 २-३०— ५-३० लोक-सम्पर्क और गाँव के काम करना,
 ६-३० बजे तक सस्था में लौटना,
 रात को ८-०० से ९-०० हर दल अपना अद्वैत पेश करे। और बाद में मार्ग-दर्शक अध्यापक के साथ बैठकर दूसरे दिन के काम का आयोजन करे।

प्रयोजना में ली जाने लायक प्रवृत्तियाँ

शाला में

- | | |
|------------------------------------|---|
| (१) वागधानी | (८) अभिभावक सम्मेलन |
| (२) दीवारों पर आलेख लिखना | (९) खेल बूद |
| (३) हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन | (१०) संगीत, नृत्य, नाटक, रास |
| (४) प्रदर्शनी | (११) शिशुओं के साथ मुलाकातें |
| (५) स्वाध्याय | (१५) राष्ट्रीय शण्डे की वदना का प्रशिक्षण |
| (६) प्रदत्त पेटी | (१३) राष्ट्रगीत का अभ्यास |
| (७) विरवास बैंक | (१४) बालकों का व्यक्तिगत अभ्यास |

घर में

- | | |
|----------------------------|---|
| (१) घर सजाना | (४) अम्बर चरते की मरम्मत |
| (२) अभिभावकों से मुलाकात | (५) आरम्भिक उपहार की जीवधियाँ
(घर में रहने लायक) |
| (३) लेटी के काम में मदद | (६) बच्चों के लिए टट्टी, पेशाब घर,
स्नान घरों का निर्माण |

समाज में

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| (१) नामजमा | (५) जमात्र दिखाना |
| (२) पाप छपाना | (६) बालवाहो |
| (३) सामूहिक प्रार्थना | (७) व्यययज |
| (४) मुक्क मरहम | (८) बबेयन |

प्रश्नपत्र-१

मुद्दा ३—शिक्षण पर प्रभाव डालनेवाले तत्व (घर, खाला, समाज और राष्ट्र)

मुद्दा ४—शिक्षण और सामाजिक परिवर्तन

मुद्दा ८—प्रवृत्ति शिक्षण शास्त्र और बुनियादी शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन ।

प्रश्न पत्र-२

मुद्दा २—बालक के विकास में अनुवर्णिक और परिवर्तितजय प्रभावकारी तत्व

मुद्दा ३—बालक का सामाजिक विकास, व्यक्तिगत विकास की शिक्षण-पद्धति

मुद्दा ३—बुद्धि की वसुधों और उसका उपयोग

मुद्दा ४—शिक्षण में उत्प्रेरण (मोटिवेशन)

मुद्दा ५—बालक की मानसिक और सामाजिक आवश्यकताएँ, शास्त्रों के व्यवहार में दोष और उन्हें दूर करने के उपाय ।

प्रश्नपत्र-३

(१) समूह जीवन

मुद्दा १—सामाजिक आलेख उसका ज्ञान और उपयोग

मुद्दा ५—राष्ट्रीय, सामाजिक और स्थानीय उत्सवों द्वारा स्फूर्ति प्रचार करना ।

(२) पूर्व बुनियादी शिक्षण

मुद्दा ५—बालकको जैसे कागज का काम, मिट्टी का काम, धागधानी

मुद्दा ७—बालकको—शालकों की बनाई चीजों की प्रदर्शनी बालकता, उपरालत कामों के प्रति सही दृष्टि का विकास

मुद्दा ९—बाल अवलोकन—विषय प्रसार करें बालको की मानसिक हलचलों को समझने के तरीके

मुद्दा १२—बालको को अभ्यास के पठ वैसे दिय जायें ? इसकी जानकारी प्राप्त करना ।

(३) सामान्य शिक्षण

मुद्दा २—प्रौढ़ों का मानस, प्रौढ़ों को प्रेरित करनेवाले प्रभावकारी तत्व, प्रौढ शिक्षण के काम में नित्यक का स्थान, योगदान ।

कुशल और निरुक्ति की समस्याएँ ।

प्रश्नपत्र-४

मुद्दा ३ शिक्षण विधियाँ, प्रोजेक्ट पद्धति ।

मुद्दा . ५—शाला समाज की व्यवस्था—स्वशासन, सुसंचालन, विद्यार्थी मण्डल, स्वामलम्बन, न्यायारम्भ की शक्ति, उत्साह, सहकार और नेतृत्व-शिक्षण,

मुद्दा . ६—शाला और समाज, शाला और शाला के बाहर की सामूहिकप्रवृत्तियाँ, शाला और समाज के सम्बन्धों में भावनात्मक विकास, अभिभावकों का सहकार, शाला और समाज सेवा, सामाजिक सर्वेक्षण, सामूहिक उत्सवों आदि सहायक प्रवृत्तियों का वाक्य के विकास में योगदान :

विद्यार्थियों से अपेक्षाएँ

- १—विद्यार्थी शाला के शिक्षाविदों, शिक्षकों, अभिभावकों से सम्पर्क करेंगे । शिक्षा के बारे में उनकी सकारणता और अपेक्षाओं को समझेंगे ।
- २—विद्यार्थी घर-शाला, समाज के परस्परिक प्रभावों को समझेंगे और पर पर एक दूसरे के विकास में किस प्रकार योगदान कर सकेंगे इन पर विचार करेंगे और उसके लिए निश्चित प्रवृत्तियों को शुरुआत करेंगे ।
- ३—शिक्षार्थी जिन प्रवृत्तियों को चलायेंगे, उनका भी असर होता है, इसका निरीक्षण करेंगे, मोट देखेंगे, पचा करेंगे और प्रयोजना के अन्त में उसकी समग्र रिपोर्ट तैयार करेंगे ।

चा उसाह सब शिक्षकों का सहकार और पूरी दान्य और ग्रामजनों की समिलित शक्ति होगी तो बहुत से काम हो सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए ऐसी सम्पूर्ण सहकार और उसाहपूर्ण वातावरण बनाने के लिए हम प्रयत्न करें।

अभिभावकों और ग्रामीणों से निवेदन

आपके गाँव में हम हर वर्ष ५-७ लोगों की टुकड़ी में आते हैं। उसी तरह इस साल भी इस प्रयोजना के सदस्य में आयेंगे। हम इस काम की अपनी तालीम के एक भाग के रूप में करते हैं। केवल पुस्तक पढ़कर शिक्षक नहीं बना जा सकता लेकिन गाँव में सभी छोटे बड़े लोगों के साथ रहकर, उनके बीच समान भाव से हिल मिलकर काम करने की कला विकसित करके हम प्रगति कर सकते हैं। इसलिए ग्रामजनों का सहकार किस तरह प्राप्त किया जाय, इस शिक्षण का भी हमने प्रयोजना में समावेश किया है।

जिनका भाव सहकार है उन्हें, यह हमारा निवेदन है। आगामी वर्ष से शिक्षण-कार्य में सब कोई सब से, ऐसी अपना सर्वोच्च कार्यकर्ताओं ने व्यक्त की है। यह बात 'शिक्षण में जाति' के उद्घोषणा के रूप में बाहिर की गयी है। हम लोग इन दिनों में इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे, ऐसी भाशा है।

(१) आगे जानेवाले जमाने में हमारे गाँव का नागरिक कैसा हो ?

(२) उसे क्या क्या जानना चाहिए ?

(३) समाज की प्रगति के लिए हमें किस दिशा में धक्का बल बढ़ाने की इच्छा है ?

(४) शिक्षण प्राप्ति के बाद आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्ति बनने की जगह नीकरी बिना लाचार और बेकार बनानेवाली शिक्षा को क्या कम दें ?

(५) हमारी इच्छा क्या है ? बच्चों को क्या देना है ?

इस विषय की चर्चा जब घर-घर और गाँव-गाँव में होगी और उसमें से शिक्षण का कोई सच्चा स्वरूप विकसित हो, तभी हम स्वयंसेवक के लायक बन सकेंगे।

हम अपने देश के अविध्य का निर्माण करें, इसकी स्वतंत्रता हमें २५ वर्षों से प्राप्त है। इस वर्ष २५ साल पूरे हो रहे हैं, तो अब और २५ साल सच्चा स्वयंसेवक बनने की दिशा में हमें प्रयत्न करना है।

हमारे शिक्षार्थी इस तरह की चर्चाएँ करें, प्रश्नोत्तर करें, ऐसी हमारी कोशिश है। इससे गाँव का आदमी किसी न किसी रूप में अपना योगदान करे, ऐसी अपेक्षा है। (मूल गुजराती से अनूदित) ●

बुनियादी शिक्षा : नयी दिशाएँ, नये समाधान

युग-युग्य महारत्ना याचों ने अपने समय की अनेक शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने हेतु बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रचलित नवीन शिक्षा-प्रणाली का प्रतिमोदन एवं समर्पण किया। इस शिक्षा-प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य जन-जन को व्यावहारिक, उपयोगी तथा सस्ती शिक्षा प्रदान करना था, क्योंकि उस समय साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही कम था, शिक्षा सैद्धांतिक तथा जीवन की वास्तविकताओं से पर्याप्त दूर थी और भारत के सीमित आर्थिक साधनों के द्वारा बर्बाद शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करना कठिन हो गया, असम्भव ही था। इन परिस्थितियों में एक नयी शिक्षा का प्रतिमोदन किया जो भारत की तत्कालीन आवश्यकताओं के पूर्ण अनुकूल थी। वास्तव में देखा जाय तो इस नयी शिक्षा-प्रणाली में इतनी शक्ति थी कि वह उपरोक्त समस्याओं का समाधान कर देश की प्रगति की राह पर बढ़ाती। किंतु देश के उच्च वर्ग ने इस शिक्षा-प्रणाली को हृदय से स्वीकार नहीं किया और यही कारण है कि आज उच्च और यहाँ तक कि मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपने बालकों को बेसिक विद्यालयों में न भेजकर पब्लिक स्कूलों तथा विदेशी मिशनरियों द्वारा संचालित विद्यालयों में भेजना अधिक प्रसन्न करते हैं और जो कुछ भी देशी प्रबन्ध में निजी या सरकारी स्कूल है भी, जिनमें भी बेसिक शिक्षा-प्रणाली को पूरी तरह से नहीं अपनाया गया है। अब स्थिति यह है कि बेसिक शिक्षा के लकीर के फकीर आज चौड़े से वे विद्यालय हैं जिनमें समाज के निम्न वर्ग के बालक सामान्यतया शिक्षा ग्रहण करते हैं या फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इस प्रवृत्ति ने बेसिक शिक्षा को एक नयी दिशा प्रदान की है कि आज बेसिक शिक्षा पर आधारित विद्यालयों में वे ही छात्र जाते हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सामान्य से निम्न होती है।

असामान्य व्यक्तित्व

सामाजिक आर्थिक बाधित बालकों का व्यवहारक असामान्य होता है। इसका प्रमुख कारण इन बालकों में सुरक्षा तथा विश्वास की भावना का अभाव है। समाज के निम्न आर्थिक एवं सामाजिक वर्ग से आये बालकों में एक प्रकार का शय, बिन्ता तथा भ्रमण होती है, जोसब समाज से भिन्न तथा पृथक उनके जीवन-दर्शन, मूल्य तथा मान्यताएँ होती हैं तथा इनकी आवश्यकताएँ भी अपने से पृथक होती हैं। इन सब विनिष्टताओं के कारण ये बालक समाज के सामान्य तथा उच्च वर्ग से आये बालकों से भिन्न होते हैं।

इन बालकों की विचार-संचार प्रक्रिया भी अन्य बालकों से भिन्न तथा कम-जोर होती है। इसके प्रमुख रूप से दो कारण हैं। प्रथम इनके परिवार तथा पड़ोस में अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा विचार-संचार के लिए सीमित भाषा का प्रयोग किया जाता है, दूसरा इन बालकों को अध्ययन हेतु पर्याप्त मात्रा में पाठ्य पुस्तकें, सहायक पुस्तकें, पत्रिकाएँ तथा समाचार पत्रादि नहीं मिल पाते हैं। वे ज्ञान-शक्ति के इन बहुमूल्य साधनों के प्रयोग से वंचित हो रहे जाते हैं। वे सीमित भाषा-शैली का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनका अध्ययन बड़ा ही सीमित होता है। वे विभिन्न कवियों, लेखकों तथा सम्पादकों की भाषा शैली से भी अनभिज्ञ रह जाते हैं। संक्षेप में, इन बालकों में अपने विचारों को संचारित करने तथा दूसरों के द्वारा संचारित विचारों को ग्रहण करने की शक्ति तथा शब्द-संग्रह नितान्त कम होती है।

सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ

सामाजिक-आर्थिक रूप से बाधित बालकों का जीवन-दर्शन, मूल्य तथा व्यवहार-परक प्रक्रिया सामान्य बालकों से पृथक् होती है। विद्यालयों में जब ये बालक आते हैं तो पाते हैं कि विद्यालय के अन्य छात्रों की विचार संचार प्रक्रिया काफी उच्च है, उनके स्वीकृत मूल्य भी ऊँचे हैं तथा उनके व्यवहार भी पर्याप्त परि-मात्रित हैं और उनकी अधिगम गति भी तीव्र है। इस प्रकार के अभाव के कारण इन बाधित बालकों में हीनता की भावना और भी अधिक बढ़ जाती है जो उनके अधिगम पर पुनः कुप्रभाव डालती है।

सामाजिक आर्थिक-बाधित बालक शंकासु, शर्मीले तथा सधरत होते हैं। परिणामस्वरूप वे कक्षा में न तो प्रश्न ही पूछते हैं और न अपनी आवश्यकताओं का समाधान करने की चेष्टा ही करते हैं। इनमें सामाजिकता का भी विकास आवश्यक मात्रा में नहीं होता है।

कुछ विशेषताएँ

इन ग्यूनटामों के साथ ही साथ इन बालकों में कुछ विशेष शक्तियाँ भी होती हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से बाधित बालक शारीरिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक सशक्त होते हैं। वे शारीरिक कार्यों की अधिक सफलता के साथ कर सकते हैं। ये बालक उन खेलों में सफलता प्राप्त करते हैं जिनमें शारीरिक शक्ति का महत्व अधिक होता है। इन बालकों में हवाई बिले बनाने की शक्ति अधिक होती है। ये बालक काल्पनिक उद्यतों में तेज होते हैं। उनमें बल्पना-

शक्ति की मात्रा अधिक होती है। वे अपने दैनिक जीवन में द्राइवर, घुड़सवार, नेता, देवी-देवता आदि का पात्राभिनय सामान्यतया करते रहते हैं।

सामाजिक-आर्थिक बाधाओं से ग्रसित बालक अपने स्वभाव में परिणामात्मक (Inductive) होते हैं, अधिगम खण्ड से पूर्ण की ओर तथा विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। उनमें सामान्यीकरण की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। परिणामस्वरूप वे उन कार्यों में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं जिनमें उच्च विचार तथा सामान्यीकरण की कम आवश्यकता होती है। वे धार्मिक विधि से सम्पादित किये जानेवाले कार्यों को बड़ी सुगमता के साथ कर लेते हैं।

इन बालकों का व्यवहार समस्या-प्रधान होता है। वे ऐसे कार्य अधिक पसन्द करते हैं जो समस्या-प्रधान होते हैं। पाठ्य पुस्तकें पढ़कर निष्पत्ति करना उन्हें पसन्द नहीं होता। साथ ही साथ वे दृश्य-कला में अधिक रुचि लेते हैं इसलिए वे अधिगम के ऐसे साधन अधिक पसन्द करते हैं जो दृश्य होते हैं। अन्त में, वे अपने विचारों को सक्षिप्त भाषा के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, अधिक भाषा का प्रयोग करना उन्हें नहीं आता।

धुनियादी शिक्षा की सफलता के लिए

धुनियादी शिक्षा, जो समाज के उच्च वर्ग द्वारा किन्हीं विशेष मनोवृत्तियों के कारण स्वीकृत नहीं की गयी, समाज के विच्छेद तथा निर्धन वर्ग द्वारा भी स्थाप्य कर दी जायेगी, यदि यह सामाजिक-आर्थिक बाधित बालकों की समस्याओं का समाधान तथा उनकी क्षमताओं का सदुपयोग करने में असफल रही। इस कार्य में शिक्षक काफी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। धुनियादी विद्यालयों में शिक्षण-कार्य करनेवाले अध्यापक अपने कक्षा-कक्ष व्यवहार के द्वारा सामाजिक-आर्थिक-बाधा ग्रसित बालकों की पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा एवं आत्म विश्वास जागृत कर सकते हैं। अध्यापक इन बालकों में से हीनता की भावना का निराकरण अपने समुचित व्यवहार के द्वारा कर सकता है। यदि अध्यापक कक्षा-कक्ष में अपने व्यवहार की विषयासज्जक, स्वीकारात्मक, समदृष्टिपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण करते तो बालक न केवल अधिगम की ही अधिकतम कर लेंगे, बल्कि वे अनेक आवश्यक स्थितियों का भी विकास कर लेंगे। जॉन वाथल (John Wathall) कक्षा-कक्ष में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करने हेतु निम्न उपायों का उल्लेख करते हैं :

१. बाधित बालकों को विभिन्न उपायों द्वारा प्रोत्साहित किया जाय, जिससे वे अपने अधिगम की मात्रा अधिकतम कर सकें।

२. इन छात्रों में किसी विचार, सुझाव या व्याख्या के सम्बन्ध में गम्भीर रूप से चिन्तन करने की तत्परता जागृत हो जाय ।

३. समस्या प्रधान प्रश्न करना, समस्या प्रधान कथन कहना तथा समस्या-समाधान-पद्धति से शिक्षण-कार्य करना ।

४. इन बालकों के विचारों को बड़े ध्यान से सुना जाय ।

५. उद्देश्यों को समझने में छात्रों की सहायता करना ।

अध्यापकों के लिए कुछ खास बातें

जैसाकि ऊपर कहा गया है इन बालकों की विचार-संचार प्रक्रिया दुर्बल होती है, वे दूसरे के द्वारा व्यक्त विचारों को सीधेता एवं सरलता के साथ ग्रहण नहीं कर सकते और न अपने विचारों को सफलतापूर्वक दूसरों तक पहुँचा ही पाते हैं । अतः अध्यापक का यह परम कर्तव्य हो जाना है कि वह विभिन्न शिक्षण-साधनों—विशेष कर दृश्य साधनों—की सहायता से अपने विचारों को सरल एवं सुगम बनाकर इनके अधिगम की भाषा को बढ़ावें । इन साधनों से अधिगम की भाषा बत हो जाती है किन्तु फिर भी बाधित बालकों की ओर अनक मनोसामाजिक समस्याएँ असमाधित ही रह जाती हैं । इन बालकों की अनक मनोवैज्ञानिक समस्याएँ होती हैं, जैसे समूह में स्थान, समूह द्वारा स्वीकृति तथा अनुमोदन आदि । अध्यापक इन बालकों को सम्मान एवं दायित्व देकर कक्षा एवं विद्यालय की अनेक क्रियाओं में भाग लेने के अवसर प्रदान कर इनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है । सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न सामूहिक कार्यों के द्वारा की जा सकती है । इन कार्यों में नाटक, खेलकूद, भ्रमण, सामूहिक गान आदि को सम्मिलित किया जा सकता है ।

अध्यापक के कक्षा कक्ष व्यवहार उन सीमाओं को निर्दिष्ट करते हैं जिन तक बाधित बालक अपनी अनक मनोसामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं । अपने व्यवहार के द्वारा अध्यापक बाधित बालकों की चिन्ताएँ, भय, भ्रमणाशा आदि का दूर कर आत्मविश्वास एवं सुरक्षा की भावना जागृत कर उनके अधिगम के लिए परिपुष्टता (Reinforcement) प्रदान कर सकता है । अध्यापक अपना तथा अन्य छात्रों के साथ प्रतिसम्पर्क (Interaction) स्थापित करके इन बाधित बालकों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है । अध्यापक का प्यार एवं स्नेह तथा इनके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार इनके लिए अत्यन्त आवश्यक है । इनके साथ सव्यवहारमक सम्बन्धों की भी मधुर बनाना आवश्यक है । दूसरे शब्दों में, सामाजिक सव्यवहारमक प्रतिसम्पर्क उच्च अधिगम के लिए अत्यन्त आवश्यक है ।

संक्षेप में, अध्यापक अपने कक्षा-कक्ष के समुचित व्यवहार एवं सुन्दर सामाजिक सवेगात्मक प्रतिसम्पर्क के द्वारा बुनियादी विद्यालयों में आये सामाजिक-आर्थिक बाधा-ग्रस्त बालकों की अधिकांश मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसीसे उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। अध्यापक अपने प्रयासों से इनके मन की हीनता का निराकरण कर सकता है। कक्षा-कक्ष में सुन्दर व्यवहार इन बाधित बालकों के मन में बसी असुखा तथा आत्मविश्वास की भावना को दूर कर उनके अधिगम को उच्चतम कर सकता है।

अध्यापक के कक्षा-कक्ष व्यवहार का माप करने हेतु अनेक विधियों का आविष्कार एवं विकास किया जा चुका है। लेखक के द्वारा प्रमाणीकृत 'सामाजिक सवेगात्मक व्यवहार-सूची' के द्वारा अध्यापक के कक्षा-कक्ष व्यवहार का बंधो सरलता से पता लगाया जा सकता है। यह सूची आठ क्षेत्रों से सम्बन्धित अध्यापक व्यवहार का माप करती है। ये आठ व्यवहार अप्रलिखित हैं :

१. संवेगात्मक सम्बन्ध, २. समदृष्टि, ३. स्वीकारोन्मुखता, ४. विश्वसनीयता, ५. समायोजनात्मकता, ६. सम्मान, ७. संवेगात्मक सम्बन्ध तथा, ८. विचार-संचार योग्यता। इस सूची का राजस्थान राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का कक्षा-कक्ष व्यवहार का माप करने हेतु व्यापक प्रयोग किया गया है। इन प्रयोगों के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पुरुष अध्यापकों के कक्षा-कक्ष व्यवहार की अपेक्षा महिला अध्यापकों का कक्षा-कक्ष व्यवहार अधिक सुन्दर तथा अधिगम के अनुकूल होता है। बुनियादी विद्यालयों को इस प्रकार के परिणामों की सहायता लेकर उचित कदम उठाने चाहिए। ●

—जियालाल, शिक्षक प्रशिक्षण-संस्थान, अजमेर

श्री गांधी आश्रम के खादो भण्डारों में सर्वोदय साहित्य पर विशेष रियायत

रु० २५) का साहित्य सेट	रु० ११) मे
रु० १५) का साहित्य सेट	रु० ६) में
रु० ११) का साहित्य सेट	रु० ४) मे
ये सेट बिना खादो खरीदे भी हरेक को रियायत से मिलेंगे।	
अन्य खादो भण्डारों से भी यह रियायत प्राप्त कर सकते हैं।	

सर्व सेवा सघ प्रकाशन, राजघाट, वागणसो-१

डॉ० जयदेव

बिहार के राजकीय बनाम अराजकीय माध्यमिक शिक्षक

[लेखक बिहार शिक्षा-सेवा में हैं, अच्छे शिक्षाशास्त्री हैं। अपनी अनुशासनप्रियता और कर्तव्यपरायणता के लिए अपने साथियों के बीच प्रिय हैं। सहरसा जिला आचार्यकुल के संयोजक के नाते भी वे पिछले सालभर से कार्य कर रहे हैं और जिले में आचार्यकुल की प्रगति के लिए सक्रिय हैं। सहरसा जिला हाई स्कूल के प्राचार्य के नाते उन्होंने विद्यालय के लिए अच्छी प्रविष्टा कमाई है। प्रस्तुत लेख में ध्यान किये गये लेखक के विचारों से आचार्य-कुल पूर्णतया सहमत भले न हों, किन्तु एक शिक्षाशास्त्री और राजकीय सेवा में होने के नाते डॉ० जयदेव के इस लेख का महत्त्व है, वृत्त इस विषय पर पाठकों की सम्मति सादर आमंत्रित करते हैं।—सम्पादक]

दुनिया के प्रायः सभी देशों एवं भारत के सभी राज्यों की तरह बिहार में भी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की दो श्रेणियाँ हैं : राजकीय एवं अराजकीय। राजकीय एवं अराजकीय शिक्षकों का यह भेद बड़ा असंगत, हास्यास्पद एवं एक दुःखद स्थिति का द्योतक है। परन्तु यह एक वास्तविकता है और बहुत ज्यों में राजकीय शिक्षक राजकीय हैं और अराजकीय शिक्षक अराजकीय।

बिहार राज्य की माध्यमिक शिक्षा आज इन्हीं दो राजकीय एवं अराजकीय संघर्षों, जिन्हें "हठों" की सज़ा दी जग्य तो उत्तम होगा, में आकात है। राजकीय हठ है, "राजकीयकरण" सम्भव नहीं। अराजकीय (शिक्षकों) का हठ है, "अब अराजकीय स्थिति सहा नहीं।"

राजकीय एवं अराजकीय दोनों पक्षों की जड़ों में आर्थिक विपन्नता एवं विवशता छिपी है। दोनों पक्षों के तर्कों में न्यूनाधिक सत्य भी है। अतः यह क्यों न देश जाय कि क्या इस राजकीय एवं अराजकीय भेद को मिटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है ?

परन्तु इस प्रश्नोत्तर के पूर्व हमें सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि बिहार में माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व अवशः भारत किस पर है ? क्या राजकीय शिक्षकों एवं शिक्षण संस्थाओं पर अवशः अराजकीय शिक्षकों एवं शिक्षण-संस्थाओं पर।

एक तरफ मान जिरसठ राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत मात्र तेरह सौ राजकीय शिक्षक, तो दूसरी ओर करीब तीन हजार अराजकीय

विद्यालयों में कार्यरत करीब तीस हजार अराजकीय शिक्षक । (आशिक स्वीकृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को लेकर) । प्रतिवर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से माध्यमिक विद्यालय परीक्षोत्तीर्ण होनेवाले तीन लाख छात्रों में अराजकीय विद्यालयों से उत्तीर्ण होनेवाले छात्रों की संख्या करीब-दो लाख चौरासठ हजार, तो दूसरी ओर राजकीय विद्यालयों से उत्तीर्ण होनेवाले छात्रों की कुल संख्या मात्र करीब ६ हजार ।

हमारे इस प्रश्न का 'उत्तरदायित्व अथवा भार किस पर' का उत्तर इन उपर्युक्त तथ्यों को देखकर निस्संदेह अराजकीय विद्यालयों एवं शिक्षकों के पक्ष में जाता है और तब इस 'पक्ष' के साथ प्रश्न उठता है कि मात्र ६ हजार छात्रों की माध्यमिक परीक्षोत्तीर्णता के निमित्त ये मात्र तेरह सौ राजकीय शिक्षक अथवा मात्र तिरसठ राजकीय विद्यालय ही क्यों ?

कुछ लाख सुविधा प्राप्त विशिष्ट शहरी अथवा सुदूर निष्ठ अमुविधा प्राप्त देहाती पिछड़े लोगों (जहाँ राजकीय सर्वोदय विद्यालय स्थित हैं) के बच्चों के लिए ही यह राजकीय विद्यालय और राजकीय शिक्षक क्यों ? क्या यह भारतीय सभ्यता की आत्मा के विपरीत नहीं ? क्यों ? इसलिए कि ये इन अराजकीय शिक्षकों एवं विद्यालयों के निमित्त आदर्श बनकर उन्हें माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा देते हैं ? जबकि कभी इनसे अपेक्षा की गयी थी और आज भी की जा रही है ?

इन सारे प्रश्नों के सम्बन्ध में उसकी चुप्पी उसके भूत प्रश्न-राजकीय एवं अराजकीय के भेद—की समाप्ति के उत्तर के निकट उसे अवश्य ला देता है और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इस समस्या के निराकरण के निमित्त राज्य या तो इन तीस हजार अराजकीय शिक्षकों एवं तीन हजार विद्यालयों का राजकीयकरण करे अथवा गांधी, दिनेश एवं आचार्यकुल के बचतानुसार शिक्षा सातकर माध्यमिक शिक्षा के प्रति अपना मोह त्यागकर राजकीय परतन्त्रता की ध्वजा तिरंग मुक्त करने की नीति अपनाकर अपन द्वारा संचालित बिहार के इन तिरसठ राजकीय विद्यालयों और उनके शिक्षकों का अराजकीयकरण करने का साहसिक कदम उठावे ।

राज्य के प्रबन्धकों के मतानुसार सर्वेयानिक पैरीदमियों के अतिरिक्त राज्य को जो अभी वित्तीय स्थिति है उसमें इन अराजकीय विद्यालयों का राजकीयकरण सम्भव नहीं । हाँ राज्य के लिए अभी यहो सम्भव है कि यह सन् १९७६ तक ५ ठारो सामान्य द्वारा अनुसूचित वेतनमान ६० २२० से ४०० का वेतन देकर एवं उनकी सेवा गुराह के निमित्त एक स्वशासी निवास समिति का गठन कर सकेगा ।

ऐसा स्थिति में यह तो सम्भव नहीं कि इन अराजकीय विद्यालयों के शिक्षकों

को बिहार के राजकीय माध्यमिक शिक्षकों के निमित्त तृतीय बिहार बतन पुन-रोक्षण समिति (अगस्त, '७२) द्वारा अनुमानित बतनमान रु० ४१५-०० से रु० ७४५ ०० अथवा रु० ३८७ ०० से रु० ६०० ०० का बतन एवं अन्य राजकीय लाभों सहित उनका राजकीयकरण कर ।

ऐसी स्थिति में ' एक दाम, एक काम ' एवं माध्यमिक शिक्षा सरकार मुक्त के संवेदेश्य से उसके सामन एक ही निष्कर्ष यह जाता है कि वह अपने राजकीय विद्यालयों का अराजकीकरण करे । राज्य का यह निष्पत्ति न केवल अराजकीय शिक्षकों की वित्तीय स्थिति में अपने आदर एवं राजकीय विद्यालयों एवं शिक्षकों की ओर देखने की प्रवृत्ति की समाप्ति की घोषण करन में समर्थ हो सकेगा, बल्कि राजकीय शिक्षकों के बीच पान सेवा निवृत्ति की वृद्धि एवं नागरिक स्वतन्त्रतादि के निमित्त बढ़ती हुई भाँगी की जड़ मूल से समाप्ति की भी । साथ ही साथ वैचारिक जगत में बिहार सरकार के इस निष्पत्ति से उस सिद्धांत की भी बल मिलेगा जो राज्य एवं सरकार से शिक्षा की स्वतन्त्रता की सही शिक्षा के निमित्त अन्तर्गत आवश्यक है और इसके निमित्त सन्त विवेक व १४ अक्टूबर, ७२ की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जो उनसे मिलने गयी थी से अपने पत्रकार के परधाम आग्रह में आपह भी किया है । सरकार के इस निष्पत्ति के साथ स्वाभाविक रूप से और कई प्रश्न उठेंगे । इन राजकीय विद्यालयों की सम्पत्ति का क्या होगा ? इनमें बायबल शिक्षकों का क्या होगा, आदि ।

इनका उत्तर सहज में ढूँढा जा सकता है । " विश्वविद्यालय सेवा की तरह एक स्वशासी निधाय ' विद्यालय सेवा ' का संगठन सरकार कर और माध्यमिक शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व वह इस पर सौंप दे जिस प्रकार उसने माध्यमिक परीक्षा का पूरा उत्तरदायित्व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का संगठन कर सौंप रखा है ।

इन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के स्वामित्व को राज्य सरकार इस स्वशासी निधाय ' विद्यालय सेवा संगठन ' की स्थानांतरित कर दे, जो इन्हें आदर्श विद्यालयों के रूप में संगठित कर संचालन कर ।

इस स्थिति में राज्य एवं सरकार का एक मात्र काम इस निधाय की पर्याप्त आर्थिक सहायता एवं अनुदान देन का रहे, जिससे यह भी राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों को कोठारी आयोग के नेतृत्वमानों को अविलम्ब कार्यावित्त कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर सकन न पूर्ण समर्थ हो सके । साथ ही इस निधाय की इतनी शक्ति भी अवश्य होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, कि यह माध्यमिक शिक्षकों की सेवा की सुरक्षादि की निश्चितरूप से दे सके, दिला सके ।

जहाँ तक राजकीय माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों एवं उसके प्रधानों को 'बचा किया जाय' का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में राज्य सरकार इन राजकीय शिक्षकों के सम्मुख चयन का विधान्त रखे। जो व्यक्ति विद्यालय सेवा संगठन के अधीनस्थ विद्यालयों में कार्य करना चाहें, उन्हें वहीं रहने दिया जाय, एवं जो लोग अपनी सेवा राजकीय क्षेत्र में ही रहने की इच्छा प्रकट करें उनकी सेवा का बिहार के ५८७ प्रखण्डों के विस्तृत प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के राजकीयकरण के निर्णय से उत्पन्न विकराल समस्या को सुलझाने एवं माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक विकास के निमित्त निरीक्षी पदाधिकारी के रूप में उपयोग किया जाय। साथ ही-साथ राज्य स्तर से प्रखण्ड स्तर तक विद्यालय सेवा की शाखाएँ भी स्थापित की जायें, जिनमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इनकी सेवा का सदुपयोग किया जाय।

यदि बिहार सरकार ऐसा निर्णय लेती है तो उसका यह निर्णय एक साङ्ख्यिक निर्णय होगा। स्वतन्त्र भारत के इतिहास में असमानान्तर एवं अद्वितीय माना जायगा।

सम्भव है, प्रारम्भ में सरकार के इस निर्णय से आज के राजकीय एवं अराजकीय दोनों प्रकार के माध्यमिक शिक्षकों में असन्तोष की भावना जाग्रत हो। एक को अपने भविष्य में अपनी प्रोन्नति की सम्भावनाओं के अभाव की आर्द्रताओं को लेकर एवं दूसरे को अपने 'आदर्श' की खण्डित प्रतिमा को देखकर।

लेकिन राज्य सरकार की घोषणा-शी समझदारी एवं इस सम्बन्ध में उसकी उदारता की नीति उनके बीच जाग्रत होनेवाली असन्तोष की भावना की समाप्ति कर सकती है। परन्तु एतदर्थ राज्य सरकार राजकीय शिक्षकों की परिवर्तित स्थिति में प्रोन्नतियों की गारण्टी तो दे। विद्यालय संगठन के अन्तर्गत कार्य करनेवाले शिक्षकों को न केवल राष्ट्रीय वेतनमान देने, बल्कि उसके परामर्शानुसार उनके वेतनमान का प्रति पाँचवें वर्ष पुनरीक्षण करने एवं राजकीय कर्मचारियों को मिलनेवाली महँगाई आदि की राशि देने की घोषणा तो करे। उसकी यह घोषणा आज के राजकीय एवं अराजकीय दोनों प्रकार के माध्यमिक शिक्षकों को विश्वास दिला सकेगा कि माध्यमिक विद्यालयों की उसकी यह अराजकीयकरण की नीति वस्तुतः उनके (शिक्षकों के) राज्य के लाखों-करोड़ों लोगों एवं स्वयं राज्य के हित में सर्वोत्तम है।

अतः आज की स्थिति में आज के सन्दर्भ में लेखक का अभिमत है 'माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण नहीं अराजकीयकरण की आवश्यकता है।'।

प्राचार्य, जिला स्कूल सहरसा, एवं संयोजक, जिला आचार्यकुल समिति

श्री अरविन्द और शिक्षा द्वारा क्रांति

बोसनी घाटी के आरम्भ में श्री अरविन्द ने भारतीय राजनीति में सक्रिय भाग लिया और इसीके साथ-साथ उन्होंने यह भी अनुभव किया कि भारतीय क्रांति की सफलता केवल राजनैतिक प्रयासों से ही नहीं हो सकती, वरन् सर्वांग परिवर्तन के लिए सभी दिशाओं, सभी क्षेत्रों में क्रांति लानी होगी।

सर्वांग क्रांति

बैंगेरी 'क्रांति' से प्रायः राजनैतिक क्रांति की ही ध्वनि निकलती है, लेकिन श्री अरविन्द की दृष्टि में क्रांति का स्वरूप सर्वांगपूर्ण है। यदि समाज में क्रांति लाना है तो व्यक्ति के जीवन में भी क्रांति लानी होगी। यदि सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में क्रांति लानी है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी क्रांति आवश्यक है।

यही कारण है कि सन् १९०५ से १९१० तक देश की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लेने के उपरान्त उन्होंने सर्वांगपूर्ण योग (इण्टीग्रल योग) की साधना पाण्डिचेरी के अपने आश्रम में आरम्भ की। पाण्डिचेरी में जाकर सर्वांगपूर्ण योग की साधना का विचार श्री अरविन्द ने अचानक नहीं किया। उनका यह निर्णय भारतीय स्वतंत्रता के लिए विद्ये व ज्ञे प्रयासों का अभिन्न अंग था।

इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि श्री अरविन्द ने सन् १९०५ में अपनी पत्नी श्रीमती मृणालिनी देवी को एक पत्र में लिखा था कि मेरी तीन प्रबल इच्छाएँ हैं :

१. पहली प्रबल इच्छा अपने देशवासियों के साथ सदासम्य करने की है।
२. दूसरी प्रबल इच्छा ईश्वर के साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अनुभव करने और,
३. तीसरी प्रबल इच्छा विदेशी शासन की राक्षस शक्ति भारत माता को स्वतंत्र कराने की है।

अतः जब किसी के मन में यह बात आती है कि श्री अरविन्द ने भारत की आजादी की लड़ाई से मुँह मोड़ लिया था, तो यह उसका अज्ञान का ही परिचायक है। श्री अरविन्द ने स्वतंत्रता के साध्य की प्राप्ति के लिए राजनैतिक साधन के स्थान पर आध्यात्मिक साधन को अनायास, बाह्यक्रांति के स्थान पर अन्तर्गत मान्तरिक क्रांति की ओर अधिक ध्यान दिया। इसका कारण यह था कि बाह्यक्रांति अर्थात् राजनैतिक क्रांति के लिए कार्य करनेवाले अनेक नेता थे। लेकिन बाह्यक्रांति की सफलता तो आन्तरिक क्रांति पर ही निर्भर करती थी।

और इस क्षेत्र में कार्य करनेवाले लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इसीलिए श्रीअरविन्द ने सर्वांगपूर्ण योग दर्शन द्वारा सर्वांग क्रांति की भूमिका तैयार की।

सर्वांग योग

श्री अरविन्द के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दिव्य शक्ति का वाहक है और व्यक्ति के वायों एवं व्यवहारों में दिव्य चेतना का प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। इसी दृष्टि से मानव शरीर का भी महत्त्व है। मानव शरीर के माध्यम से ही भौतिक एवं दैविक जगत में सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। श्री अरविन्द के शब्दों में "शरीर का काय दिव्य चेतना की भौतिक जगत् से सम्बद्ध रहना है।"

शरीर में आत्मा एवं दिव्य चेतना का आभास व्यक्ति के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। जब मनुष्य अपने को 'शरीर' न मानकर आत्मा स्वीकारता है, जब वह अपने अह से ऊपर उठकर परम सत्ता एवं भागवत चेतना की ओर अप्रवृत्त होता है तब उसके जीवन में ऐसी आन्तरिक एवं आध्यात्मिक क्रांति होती है, जो बाह्य जगत् को बिना प्रभावित किये नहीं रहती।

श्री अरविन्द के शिक्षा दर्शन में इसी क्रांतिकारी परिवर्तन की बात प्रमुख है। इसी दृष्टि से श्री अरविन्द न केवल भारतीय क्रांति के उन्नायक थे वरन् विश्ववन्द्य तथा मानव एकता के पोषक थे। श्री 'र्षा' के निर्देशन में श्रीअरविन्द आश्रम में जिस जीवन-शैली को विकसित किया गया है वह इस दृष्टि से क्रांतिमूलक है कि उसमें सांसारिक मान्यताओं, रीति रिवाजों के स्थान पर परमार्थ, धर्म साधना, समता, भ्रातृत्व एवं मैत्री को अपनाया गया है।

श्री अरविन्द अठरावीं शताब्दी केन्द्र पाश्चिमी में शिक्षा द्वारा मानव-जीवन एवं समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए सफल प्रयोग किये जा रहे हैं। सर्वांगपूर्ण शिक्षा श्री अरविन्द की अनुपम देन है। इसके द्वारा एक नये मानव का, एक नये समाज का, एक नये विश्व का निर्माण हो सकता है।

सर्वांगपूर्ण शिक्षा

अगस्त सन् १९६५ में श्री अरविन्द आश्रम की श्री माताजी ने कहा कि सर्वांगपूर्ण शिक्षा के द्वारा न केवल भारत में वरन् विश्व में नवीन चेतना का विज्ञान स्थापित जा सकता है। इसी सन्दर्भ में श्री माताजी ने कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिये थे, जिनके आधार पर सर्वांगपूर्ण शिक्षा के निम्नांकित लक्ष्य अथवा उद्देश्य हैं।

१ सर्वांगपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बालकों को इस योग्य बनाना है कि वे असत्य को अस्वीकार करें और अपने जीवन में सत्य को अभिव्यक्त करें।

२. सर्वांगपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य भौतिक जगत में आत्मिक विकास को सम्भव बनाना है ।

३. सर्वांगपूर्ण शिक्षा का लक्ष्य यह बताना है कि भौतिक तत्व तब तक निष्क्रिय एवं असत्य है जब तक कि वह आत्मा की अभिव्यक्ति का वाहन नहीं बनता है ।

४. सर्वांगपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है ।

५. सर्वांगपूर्ण शिक्षा का लक्ष्य जीवन के विविध कार्यों के माध्यम से व्यक्ति का सत्य एवं अशौकिक सत्त्व से परिचय कराना है ।

सर्वांगपूर्ण शिक्षा के जो लक्ष्य एवं उद्देश्य ऊपर बताये गये हैं उनकी पूर्ति का अनुमान सामान्य सांसारिक सफलताओं के आधार पर नहीं लगाया जा सकता । इसीलिए श्री अरविन्द आश्रम के अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र में जो सर्वांगपूर्ण शिक्षा-पद्धति है उसमें किसी प्रकार की परीक्षा अथवा उपाधि देने की व्यवस्था नहीं है ।

सर्वांगपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का अन्तरिक तथा आध्यात्मिक विकास करना है । यह स्पष्ट है कि आध्यात्मिक एवं आन्तरिक विकास का मूल्यांकन सामान्य लौकिक आधारों पर नहीं किया जा सकता । यही कारण है कि सर्वांगपूर्ण शिक्षा-पद्धति में न किसी प्रकार की परीक्षा होती है और न डिग्री ही दी जाती है । इसका मूल्यांकन तो व्यक्ति स्वयं करता है कि सर्वांगपूर्ण शिक्षा के उद्देश्यों को उसने अपने जीवन में किस रूप में उतारा है, और उसमें किस सीमा तक अपनी चेष्टना को विवक्षित किया है ।

यह स्मरणयोग्य है कि सर्वांगपूर्ण शिक्षा आधुनिक युग में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति की अवहेलना नहीं करती । वह केवल इस बात पर बल देती है कि इनका उपयोग करते समय व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण को न भूले । जैसा कि ऊपर श्री माताजी ने संकेत किया है, भौतिक तत्व के माध्यम से ही आध्यात्मिक तत्व की अभिव्यक्ति हो सकती है । इसीलिए सर्वांगपूर्ण शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में ज्ञान-विज्ञान का महत्त्वपूर्ण स्थान है ।

इस प्रकार श्री अरविन्द जिस ज्ञाति के अग्रदूत थे, वह आज भी अपनी ज्योति विखेर रहा है और तब तक इस ज्योति एवं दिव्य जीवन का प्रसार करता रहेगा, जब तक कि मनुष्य अपनी अतिमानसिक चेष्टना के विकास द्वारा न केवल नये भारत का वरन् कल्याणकारी विश्व का निर्माण नहीं कर लेता ।

रोडर, शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

सितम्बर, '४३]

[२२५]

विज्ञान की गति और इन्सान की मति

[उत्तर प्रदेश तरुण-शांतिसेना के द्वितीय सम्मेलन में सुप्रसिद्ध हिन्दी-कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया यह श्रेष्ठ उद्बोधन भाषण आशा है नयी तालीम के पाठकों को भी चिन्तन की प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करेगा । —सं०]

मैं शिविर के लिए, विचार गोष्ठियों के लिए, सेमिनार के लिए बहुत काम का आदमी नहीं हूँ । वर्षों में एक शिक्षा-सम्मेलन हुआ था अभी दोडे ही दिन पहले । वहाँ तरुण-शांतिसेना के सन्तोष भारतीय, अरुण और राजाजी से मेरा परिचय हुआ । और उन लोगों ने कहा कि दिसम्बर में हम एक सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें आयेंगे क्या ? तो मैं अपने को इस सवाल के लिए उचित नहीं समझता था । मैं जानता था कि मैं इसके लायक नहीं हूँ । लेकिन जब उन्होंने कहा तो मैंने सोचा कि मैं कहूँ कि नहीं जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा । अतः कह दिया कि मैं वहाँ जाऊँगा । मैं तो साठ साल बिया हूँ, तीस साल तक पढ़ाया है, ४० साल तक कविता लिखी है, हजारों छात्रों में कविता पढ़कर लोगों के मन को मुग्ध किया है, तो थोड़ी देर जवानों के सिर के हिलने का आसार पैदा कर सकूँगा, वही न बही, बिरबुल स्पष्ट नहीं, लेकिन वही न बही मन में यह भावना थी । लेकिन यही माने पर ऐसा लगता है कि न मैं बेघा कर सकता हूँ न मुझे करना चाहिए । फिर भी वहाँ जा गया तो मुझको ऐसा मानना चाहिए कि मैंने अच्छा किया ।

अभी जानकी बहन (सम्मेलन का उद्घाटन करनेवाली एक सावित्री सैनिक) कह गयी कि यह जमाना चाहे और जिस चीज का हो, मार्गदर्शन का जमाना नहीं है; इसमें कोई शक नहीं । और सब तरह की चीजें इस जमाने में चल सकती हैं, लेकिन इसमें मार्गदर्शन नहीं चल सकता । और उसका कारण है ।

मैं एक बूढ़े आदमी की बात कहना चाहता हूँ । दुर्भाग्य है कि बूढ़े आदमियों से हमारा वास्ता पड़ता रहा । यह बात विनोबाजी ने कही । पवनार में बैठे हुए वे हल लीम । कुछ जवान विद्यार्थी गाँवों में काम करने के लिए जा रहे थे । तो वे विनोबा का आशीर्वाद लेने आये थे । उन्होंने कहा, 'बेवल मेरे आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा । फिर भी अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो मैं दे देता हूँ । लेकिन बेवल आशीर्वाद से काम नहीं चलगा, क्योंकि वहाँ तो विराट रूप का दर्शन होता है । तुम अगर गाँव में जाओगे, तो उस विराट रूप का दर्शन होगा तरह तरह की बातें दिखेंगी । घबरा कर घर भाग जाओगे । इसलिए सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलता । क्योंकि समय की गति बहुत तेज है ।'

जीवन और मरण की तेज रफ्तार

मैं तो एक शब्दशिल्पी हूँ और इसे भगवान का वरदान कहिये, या मेरा आलस्य कहिये, इसके सिवाय मुझे कुछ आता नहीं । और शब्दों के माध्यम से ही मैं सारा काम चलाता हूँ । बितनी बड़ी बड़ी समस्याएँ कितने बड़े बड़े सवाल और हमारे पाम शब्द के सिवाय कुछ भी नहीं । अग्रजी में जिसे कहते हैं 'मैन ऑव लेटरर्स', बिल्कुल वैसा ही मैं एक 'मैन ऑव लेटर्स' हूँ । और इसलिए मुझे शब्द की निर्बलता की प्रतीति हर समय होती है । और सबसे अधिक जिन कारणों से होती है वह है समय की तेज रफ्तार । यह जो विज्ञान की तकनीक है आप देखिए हमारा जो साहित्य या उसका क्या हाल है ? पुराने जमाने में एक हजार साल तक एक तरह की कविता चल जाती थी फिर पाँच सौ साल तक एक प्रकार की कविता चली, और फिर धीरे धीरे कविता का, साहित्य का स्वरूप तेजी से बदलने लगा और आज तो गिरफ्तार उसमें तीव्रगति से परिवर्तन होत जा रहे हैं । तरह-तरह के वाद साहित्य में आये और गये । तो आज की जो दुनिया है उसमें विज्ञान के कारण जितनी तेजी से जीवन आया है उतनी ही तेजी से मरण आया है । इसमें सबसे बुरी बात यह है कि सोचना करने का तरीका मर रहा है । सोचना बंद हो रहा है । इतना ही नहीं, सोचना बंद करने के उपाय बढ़ रहे हैं । सोचना किस तरह बंद हो जाय, उसके लिए तरह-तरह के प्रयत्न चल रहे हैं ।

हमारा सोचना बन्द बिया जा रहा है और हम खुश हैं और बल्कि उसके लिए आतुर हैं कि यह हमारा सोचना क्यों नहीं बंद हो रहा है जल्दी से । क्यों नहीं हमको सिनेमा का टिकट कन्नेशन रेट पर मिलता है, इसके लिए आप आदोषन करते हैं । अरे भाई, जितनी देर आप आकर बैठते हैं सिनेमा हाल में,

उतनी देर आपका सोचना बन्द हो जाता है, आप जितनी देर स्कूलों में जाकर बैठते हैं आपका सोचना बन्द हो जाता है, आप जितनी देर अफिसों में जाकर काम करते हैं, उतनी देर आपका सोचना बन्द हो जाता है, आप जितनी देर मशीन चलाते हैं आपका सोचना बन्द हो जाता है। तो यह सोचना बन्द होने की स्थिति जितनी तेजी से विज्ञान के कारण बनी है, उतनी ओर किसी कारण से नहीं। और आप जानते हैं कि सोचना बन्द होने से आदमी मरता है। आदमी के लक्षण क्या है ? जिसको सोचना नहीं आता वह आदमी नहीं होता। वह पशुवत् होता है। आहार, भय, मैथुन आदि सब लक्षण आदमी और पशुओं में समान है। एक चीज शायद हममें विशेष है। हो सकता है कि वह बहुत सही नहीं हो, लेकिन हमने मान लिया कि पशुओं को सोचना नहीं आता है और हम सोच सकते हैं। अगर सोचना हमारा रोज रोज किसी-न किसी कारण से खरम होता जा रहा हो, तो हमको यह मानना चाहिए कि हमारा मानव दिनों दिन क्षीण हो रहा है।

शिक्षा यह जो सोचना सिखाये

शिक्षा यह है जो सोचना सिखाती है। जो सोचना बन्द बरानी हो, वह और कुछ भले हो, शिक्षा नहीं हो सकती। अब, सोचना सिखानेवाली शिक्षा कौसी होगी ? पारो दुनिया के चिन्तक, सोचनेवाले यह कह रहे हैं कि भविष्य में हम किताबों से नहीं, जीवन से सीख सकते हैं। अब, जीवन जीने की कला बड़ी मुश्किल है। जीवन कैसे जीयें। हमको याद है, हमारा बचपन कितना आसान था। सबेरे उठते थे, स्कूल जाने तक हमको, हमारा ऐसा ख्याल है कि हमारे माँ बाप को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। सुबह उठे, ऐसे ही मुँह-हाथ धोया, कोई मंजन नहीं था, कोई पेस्ट नहीं था, कोई साबुन नहीं था कोई घाम की प्यालों नहीं थी; कोई मारता नहीं था। थोड़ा सम्पन्न हुए तो एकाध रुप दूध मिल गया, अपना चले गये स्कूल। लौटकर आये खाना खाया, सो गये। बड़ी सरल चीज है अगर आपको खाना मिल जाय और सोने को मिल जाय। और चाहिए भी क्या ? और थोड़ा-सा खेलने-बुढ़ने को सापिणों का साथ मिल जाय, हँसने-रोने को मिल जाय। और चाहिए भी क्या ?

गिटायर लोग कहने हैं, सहजता से दिन 'काट' लेते हैं। कोई सोचना, करना नहीं रहता। हममें से अधिकांश लोग समय 'काटते' हैं। यह जो समय काटना है, यह हमारी लाचारी है ! विज्ञान ने समय काटने की लाचारी में हमको डाल दिया है। जिस तरह मुकद से घाम हो जाय और घाम से जिस तरह मुकद हो

भाषण देना पड़ रहा है। भगवान की दया से मुझे भाषण देने नहीं पड़ते। जो कुछ मुझ बहना रहता है कविताओं के माध्यम से मैं कह लेता हूँ। लेकिन जहाँ काम अब मुझे कहा करे तबवार। तो वह जो बचता रूपी तबवार है, वह ऐसे शिविरो म काम आता नहीं है। मुझे आपने यही कहा है कि माई, भाषणों से काम नहीं बनता। कुछ निहाली। इसके लिए जो सबसे सही चीज है निकाउन की, वह सबसे सरल है और सबसे कठिन है। इसलिए उसको कोई नहीं निकालता, ऐसा मुम लगता है। सबसे सरल चीज यानी सादा-सादा रहना। मोटा खाना, मोटा पहनना। जो मोटा खाता है, जो मोटा पहनता है उसको आप प्रतिष्ठित कर दीजिए। आदमी प्रतिष्ठा का भूखा है, सम्मान का भूखा है। अगर आप मोटा पहननेवाले और मोटा खानेवाले की प्रतिष्ठित कर दीजियेगा, तो हममें सबका भ्रम होगा। आपका जीवन भी सरल होगा और दूसरे का जीवन भी। यह ऐसा आनन्दार सूत्र है। मान लीजिए मारन किसी की, आज जो उसे उपलब्ध है उससे अधिक कठिन और कीमती चीज के लिए प्रोत्साहित किया और उसने वह चीज दूसर महीने बेइमानी करके प्राप्त कर ली, तो आपने उसका भी जीवन कठिन किया और अपना भी और समाज का भी। और अगर आपन उसे सरल बनान में मदद की तो अपना जीवन भी सरल बनाया और साथ साथ अनेक लोगों का भी।

पीढ़ी के फासले

यह जो विधान नाम की चीज है जिसने आदमी को आदमी के निबट ला दिया है, उनमें आदमी आदमी का गला भी काट सकता है और गले भी मिल सकता है। अब आप चुनिए कि आप क्या चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि गले लगाने की बात आप चुनना चाहेंगे। और अगर गला दशने की बात चुनना चाहें तो चुन सकते हैं सामर्थ्य है यामें। लेकिन इसमें जवानी क्या है? हम साथ हुए हैं तो आभिगन करें, एक दूसरे की बात समझें, न समझे तो समझायें। हमारा इस बात का आग्रह होना नहीं चाहिए कि जो आदमी नहीं समझ रहा है, उसको समझायेंगे नहीं। तुम अगर समझना नहीं चाहते, तो क्या हुआ? हम तो समझाना चाहते हैं। तुम गले लगना नहीं चाहते तो क्या हुआ, हम तो गले लगाना चाहते हैं। तुम कैसे इनकार करोगे मुझसे। अगर मैं तुम्हारे बीच आ जाऊँ और कहूँ कि भायो हम सब मिलकर यह काम करना चाहते हैं और यह काम तुम्हारे जीवन का है, तो तुम कैसे इनकार करोगे? क्या यह कहाने नि नहीं, यह कैसे होगा? हम पचीस साल के, तुम उचास साल के। क्या हुआ

जो हो गये पचास साल के " इतना ही न होगा कि हम तुमसे अन्तरी एक जायेंगे । तो तुमसे कहकर ५ मिनट ज्यादा सुस्ता लेंगे । क्या तुम इन्कार करोगे ? लेकिन अगर हम यह कहें कि हम यहाँ आ गये हैं और हम बैठे-बैठे उपदेश करें कि तुम यह करो, वह करो, और हम बैठे बैठे देखेंगे, तो आप वेशक लात मार कर ऐसे मुजुर्गों को हटा दीजिए ।

जो दसनघट करके आपको दुनिया भर में सडाने हैं, टेबुल पर बैठे हैं, और आपको चाँद एक सडात है, जवान हो उड़ाये जाते हैं न उसमें । उस जवान को इन बातों से इनकार कर देना चाहिए । क्या मनुष्य है दुनिया भर में दौड़ने से, चाँद तक पहुँचने से, क्यों हर्ष करना चाहिए ? हम जान बूझे तैयार हैं, लेकिन आप किसलिए भेज रहे हैं ? आप हमको सेना में भर्ती कर रहे हैं, हमको लाना रहे हैं, निम्नलिखित सडा रहे हैं ? हमको समझाइए । जहरत पड़ेगी तो हम खून भी दे सकते हैं, लेकिन किस लिए ? यह तो हमको समझाइए । सही वजह हो तो हम कभी रुक भी सकते हैं, खून भी दे सकते हैं ।

जानकी बहम ने बिलकुल ठीक कहा कि आज जिन्दा दाहीधो भी आवश्यकता है । यह बात समझने की है कि देश के लड़ जौना बहुत मुश्किल है, यानी कि किसी भी सही मूल्य के लिए जौना बहुत मुश्किल है । आप मडन पर जा रहे हैं किन्ती बहुत को किसी ने माली दे दी, तो आप उससे भिड जायेंगे, वह आपको छुरा मार देगा आप मर जायेंगे, यह ही सक्ता है । लेकिन आप २४ घण्ट इस बात के लिए आगमन रहे कि कोई जवान ऐसी मन स्थिति हो न बना पाये कि इस तरह के सही काम के लिए उसका मन हो, उसके लिए मैं कोमिश बरता रहूँगा, रोज तिल तिल , तो यह बहुत ही कठिन है । कोई भी प्रारम्भ छोटा ही होना है, और प्रारम्भ महत्वपूर्ण होता है । अगर आप सही चीज को सही नहीं मानते, और गलत चीज को गलत नहीं मानते, तो आप बड़ी-ते-बड़ी ज्ञाति का मारा देकर भी बेईमानी करनेवाले हैं इसमें कोई शक नहीं ।

कैसी शिक्षा में क्रान्ति ?

शिक्षा में क्रान्ति आप चाहते हैं । कैसी शिक्षा में क्रान्ति, जो स्कूलों और बालेजों में पढाई होती है उसी में क्रान्ति ? उसमें तो शिक्षा होती ही नहीं । उसमें तो जो जितना ज्यादा शिक्षित होता है उसका ही बेईमनता है । कैन गलत बातों को उछाल कर सही स्थापित करता है, शिक्षित करना है या गाँव का किसान करता है ? इसीलिए जब विनोबा से राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अभी जो शिक्षा चल रही है, उसे बदल देना चाहिए । गाँवों ने जब जातिकारी शिक्षा

शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो

आज सबसे अधिक आवश्यकता यदि किसी चीज की है तो शिक्षा में क्रांति की है। विदेशी मत्ता ने हमारे देश में जिस शिक्षा-प्रणाली को चलाया था, वह भारतवासियों के अनिर्णय को नष्ट करके उन्हें परावलम्बी, टपसरी, बर्बर बनाने के लिए थी। दुर्भाग्य से हम आज भी उसी शिक्षा प्रणाली में बंधे हुए हैं। मेरा लज्जा मे गिर शुक पाता है, जब मैं देखता हूँ कि विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त युवक हमारे कार्यालय में आकर कहता है कि यदि आपके यहाँ लिखने पढ़ने का काम नहीं है तो बन्दल बांधने का डी काम दे दीजिए। इससे बढ़कर शिक्षा की निरर्थकता और क्या हो सकती है ?

शिक्षा में पाँच गुण होने अत्यन्त आवश्यक हैं। पहला यह कि उससे शारीरिक विकास हो दूसरा ज्ञानवर्द्धन हो, तीसरा बलात्मक दृष्टि बने, चौथा चार्मिक उन्नति हो और पाँचवा स्वावलम्बन की भावना विकसित हो। मुझे यह कहने में कोई सवाच नहीं कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में इन पाँचों ही गुणों का निरान्त भाव है। यही कारण है कि शिक्षा न पिछले पचीस वर्षों में जितना हानि पहुँचाया है, उतना लाभ नहीं पहुँचाया है।

यिनोवा ठीक कहते हैं कि शिक्षा न देने से उतनी हानि नहीं होती, जितनी कि गलत शिक्षा देने से होती है।

महर्षि माधी ने बुनियादी शिक्षा द्वारा शिक्षा में महान क्रांति लाने का उपक्रम किया था। बुनियादी शिक्षा में उपरोक्त पाँचो गुण थे। वह देश काल के अनुकूल थी। उसका जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। लेकिन हमारे शिक्षा-शास्त्रियों तथा शासकों के वह गूँठे नहीं उठती। यदि उस पर देश ने अमल किया होता, तो आज भारत का रूप ही कुछ और होता।

मैं मानता हूँ कि जब तक शिक्षा में आमूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक वह उपयोगी नहीं होगी। बुनियादी शिक्षा के अतिरिक्त क्रांति का मुझे और कोई उपयुक्त मार्ग दिखायी नहीं देता।

आज अधिकांश छात्र पढ़ लिखकर बाकू बनते हैं। वे शरीर-धर्म को हेय दृष्टि से देखते हैं, यान्त्रिक टपसरी में नौकरी के पीछे रहते हैं। अपनी मेहनत से काम पेश करने की वृत्ति उनमें नहीं होती। बुनियादी शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि वह युवकों को उत्पादक श्रम के लिए तैयार करती है।

धारम्भ से ही निर्माण की दृष्टि पदा हो जान से वे कुछ न कुछ चीजें बनाते रहते हैं और उनके हाथ काम के अम्यस्त हो जाते हैं। बाम में भैत्र आने है।

आज इसी की जरूरत है। जिस देश में मानव श्रम विपुलता से उपलब्ध हो उसमें हाथ को महान का बड़ा मूल्य है।

कितने बुद्ध की बात है कि आज की पढ़ाई में बच्चों का समय बेकार जाता है। माना पिता की कमर टटनी है और सरकार को परेशानी होती है।

मैं जाना करता हूँ कि देश का विकास आग्रत होगा और वह बुनियादी शिक्षा जमी किसी शिक्षा प्रणाली को अपनाकर शिक्षा में क्रांति का अंगण करना।

जब तक शिक्षा में इस प्रकार की क्रांति नहीं आती, तब तक के लिए शिक्षा सत्याओं को बंद कर देने में कोई हज़ नही है।

—गंगाधर जन साहित्यकार, सम्पादक, 'जीवन साहित्य', मासिक

शिक्षा में मानवीय तत्व

स्वतंत्रता के उपरांत देश की शिक्षा पद्धति के विषय में निरंतर विचार होता रहा है। अनेक आयोग और समितियाँ नियुक्त हुई हैं और वहाँ वही इनकी सस्तुनियों को कार्यान्वित भी किया गया किन्तु परिणाम बहुत सन्तोषजनक नहीं रहा। कारण यही है कि हमने अब तक शिक्षा के ढाँचे की ओर अधिबद्ध दिया है और उसने मानवीय तत्वों की दरावर उपेक्षा की है। मैं समझता हूँ कि इस समय मुख्यतः निम्न चार तथ्यों पर विचार होना चाहिए

(१) शिक्षा का मभी स्तरों पर वास्तविक जीवन तथा उत्पादक श्रम से किस प्रकार का सम्बन्ध जोड़ा जाय।

(२) शिक्षा सत्याओं से राजनैतिक गंदगी को किस प्रकार अलग रखा जाय।

(३) शिक्षकों के शैक्षिक एवं चारित्रिक स्तर का ठठाने के लिए क्या व्यवस्था की जाय?

(४) इस समय अधिकतर नौकरियाँ और पेशा के लिए स्नातक उपाधि अनिवार्य होती जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उच्च माध्यमिक शिक्षा का स्तर इतना उचा कर दें कि इसके बाद ही हमारे युवक विभिन्न नौकरियों और पेशों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद प्रवेश कर सकें। विद्वत्विद्वान्-एम्पों में बंधन वह मुक्त प्रवेश करें जिनकी इस ओर विवशता हो या जो दोष अथवा अप्रत्याशक का कार्य करना चाहते हों।

—प्रमुकुल तिलक, कुलपति, काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी

द्वितीय उत्तर प्रदेश तरुण-शान्तिसेना सम्मेलन का घोषणा-पत्र

व्यापक छात्र असन्तोष और उनकी आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तियों द्वारा आन्दोलित वातावरण में उत्तर प्रदेश शान्तिसेना का यह द्वितीय सम्मेलन अपनी कुछ विशेष जिम्मेदारियाँ महसूस करता है। छात्र एवम् आज सत्ता वाली दलों और निर्रिक्त स्वाधियों के दलदल में फँसी हुई खोतली है। मौजूदा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक गण और दमनकारी तंत्र द्वारा तरुण-चेतना निरन्तर कुण्ठित की जा रही है, तथा यथास्थिति को मुदूद करने की दृष्टि से रोज-द-रोज 'फैशन' की तरह नये-नये आकर्षणों से जोखवर तथाकथित आधुनिक जीवन के प्रतिमान समाज में पेश किये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप आज के असह्य सामाजिक ढाँचे को दुनियादी सौर पर बदलने में तरुणों की शक्ति नहीं लग पा रही है, बल्कि वह गुमराह हाकर मात्र छिन्नुट विराधों तक ही सीमित रह जा रही है, जिनसे निपटने की कला यथार्थतः पपक खूब विकसित किये हुए है। हम तरुण शान्ति-सैनिक हम स्थिति के प्रति गहरी चिन्ता महसूस करते हैं और अपने प्रयत्नों द्वारा सभी तरुणों की सरणार्थ को एक विधायक विद्रोह के रूप में विकसित करने की आशावा व्यक्त करते हैं।

तरुण-शान्तिसेना लोकतन्त्र, धर्म-समभाव, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समता, आर्थिक न्याय और विश्व शान्ति, इन दुनियादी जोखन और सामाजिक मूल्यों पर खड़ी है। वह एक ऐसी शान्ति करना चाहती है जिसमें आदमी आदमी की तरह जी सके। आज तो आदमी बिकने की बेइसरी और श्रय करने की सामर्थ्य के साथ कुछ मोर ही बनकर जी रहा है।

इस क्रान्ति के प्रथम चरण के रूप में हमने शिक्षा में क्रान्ति की आवाज बुन्द की है और वहाँ से हमने कार्यारम्भ किया है। क्योंकि यह आज की शिक्षण प्रक्रिया ही है जो हमारी सृजनशीलता को समाप्त कर हम यथास्थिति का एत पुर्जा बना देती है। शिक्षा में क्रान्ति के कुछ प्रारम्भिक पहलू हैं। फीस के बढ़ते पाम, डिग्री का नौकरी से सम्बन्ध विच्छेद, शिक्षण संचालन और व्यवस्था में

शिक्षक, शिक्षार्थी और अधिभावक की संयुक्त शक्ति के रूप में मुख्य । मगदारी की हमारी यह माँग भी है कि गुलामी के दिनों के अवशेष अधिशासकों में से एक प्रगासद तैयार करनेवाले अति महँगे पब्लिक स्कूल बन्द हों, क्योंकि वे हमारी लोकतंत्र और समाजवाद की राष्ट्रीय घोषणा के ऊपर एक ऐसा व्यंग है ।

देश के आर्थिक जीवन में एक तरफ अभाव और बेकारी का नृम्य नृत्य हो रहा है, तो दूसरी ओर वैभव और विलासिता के नित नये साधनों में वृद्धि हो रही है । यह स्थिति बिल्कुल निन्दनीय है और हमारी माँग है कि देश में अन्तिम आदमी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होने तक वैभव विलास सामग्रियों के उत्पादन और उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाय ।

क्रान्ति की प्रक्रिया और शक्ति के सम्बन्ध में हमने यह माना है कि परिवर्तन का प्रारम्भ मनुष्य ■ दिल और दिमाग से होता है इसलिए हमारी प्रक्रिया और शक्ति बहो हो सकती है जो इन दोनों बिन्दुओं पर परिवर्तन की प्रबल प्रेरणा पैदा कर सके । हम विचार की सचिन और नये-नये प्रयोगों द्वारा इसकी नयी पद्धतियाँ खोजने की तैयारी करते हैं, क्योंकि क्रान्ति की अब तक शांत पद्धतियों की विफलताएँ हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ।

विद्यालय की बहारदीवारी तरुण-शान्तिसेना की सीमा नहीं । हमारा सपना है कि हम देश के हर तरुण तक पहुँचें और इस नयी क्रान्ति के लिए उसकी तरफाई को जगावें । हम औरतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत जवानों, कामदिलाऊ दकतों के दरवाजों पर एहन तथा नीकरो के लिए दर-दर भटकते तरुणों तक इस क्रान्ति विचार को पहुँचाना चाहते हैं ।

बत्तर प्रदेश तरुण-शान्तिसेना के इस द्वितीय सम्मेलन में अपने उदय की ओर और अधिक दृढ़ता के साथ बढ़ने का आत्मविश्वास हम अपने अन्दर महसूस करते हैं, और प्रदेश के अपने तरुण सावियों से यह स्नेहपूर्ण अपील करते हैं कि देश की, अपने भविष्य की, नाजुक स्थिति को आँख खोलकर देखें, समझें, अपने आप तक ही सीमित न रहें, या किसी समुदाय या दलविशेष की सकुचित रुढ़-प्राप्ति का साधन न बनें; बल्कि इस सम्पूर्ण समाज के नुनिपादों परिवर्तन हेतु साथ-साथ कम्बे-से-कम्बा मिलाकर इस अभिनव क्रान्ति पथ पर आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे समस्त खड़ी बिकराल समस्याओं का समाधान एक सम्पूर्ण और समग्र क्रान्ति द्वारा ही सम्भव है ।

कानपुर,

२० नवम्बर, '७२

मध्य प्रदेश आचार्यकुल : वार्षिक सम्मेलन सम्पन्न

श्री काशीनाथ त्रिवेदी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश आचार्यकुल का द्विदिवसीय द्वितीय वार्षिक सम्मेलन दिनांक ८ और ९ नवम्बर, १९७२ को महात्मा गांधी सेवा आश्रम जोरा के प्रांगण में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में प्रदेश के २० जिलों से सयोजक व सदस्यगणों ने लगभग १०० की संख्या में सक्रिय भाग लिया।

सम्मेलन की पहली बैठक में श्री एस० एन० मुखाराम ने चम्बलवाटी में आचार्यकुल के योगदान विषय पर एक विचार-पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि, 'क्षेत्र में शान्ति और सहज जीवन की दृष्टि से आचार्यकुल महत्वपूर्ण योग दे सकता है। क्षेत्र में सज्जन शक्ति का संगठन और विकास आचार्यकुल का मुख्य कार्य है।' पहली बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बोल्ते हुए सुश्री सरला बहन ने कहा कि, "समाज में आधी संख्या स्त्रियों की है। व सामाजिक मनोमालिन्य और वैर विरोध को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है जैसीकि उन्होंने हाल के आरम्भ-समर्पण के समय निभायी भी है। माताओं की दृष्टि सही हो गयी तो बच्चे बिगड़ ही नहीं सकते।" जोरा क्षेत्र के विधायक श्री रामचरण लाल मिश्र ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि, 'समय आ गया है कि अपराध, दण्ड और पुलिस व्यवहार के बारे में पुनर्विचार किया जाय।' गोष्ठी के आरम्भ में आचार्यकुल, जोरा ■ सयोजक श्री दर्शन लाल सिंह ने स्वागत किया और मध्यप्रदेश आचार्य कुल के सयोजक श्री गुरुशरण ने पिछले वार्षिक सम्मेलन से इस सम्मेलन तक एक वर्ष का विवरण प्रस्तुत किया। गत वर्ष सदस्य-संख्या कुल १६५ थी, जो अब ५०० हो गयी है।

सम्मेलन की दूसरी बैठक में शिक्षा महाविद्यालय ■ प्राचार्य डा० अमरनाथ कौल अदालती ने शिक्षा में व्यावहारिक प्रयोगों पर विचार-पत्रक प्रस्तुत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि, 'शिक्षक चाहे तो शासकीय नीति-नियमों के होते हुए भी कैंसा भी पाठ्यक्रम हो, वह बालकों को आचारवान बनाने की दिशा दे सकती है।' जिला शिक्षा अधिकारी, टीकमगढ़, श्री प्रेम नारायण छडिया ने अदालतीजी के विचारों का समर्थन करते हुए टीकमगढ़ जिले में अपने प्रयोगों

की चर्चा की जिनमें वाला विकास समितियों के माध्यम से अद्भुत सहयोग प्राप्त हुआ है। श्री हरीशकर त्रिवेदी, एडवोकेट, प्राचार्य श्री शिवनाथ उपाध्याय, श्री रामगोपाल गुप्ता, श्री तत्त्वमल जैन, श्रीमती चन्द्रकला सहाय और श्रीमती प्रेमकली कसिया ने भी इस अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किये।

दूसरे दिन समापन समारोह श्री राजगोपालन् के भजन से शुरू हुआ। अध्यक्ष श्री काशिनाथ त्रिवेदी ने राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, सेवाग्राम के पारित प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया, जिसकी समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों ने पुष्टि की। श्री ग० ज० पाटणकर ने 'ग्रामस्वराज्य में शिक्षा विषयक अपना विचार पत्र पढ़ते हुए बरजगाँव में हुए व्यावहारिक प्रयोगों की चर्चा की। श्री नर्मदा प्रसाद शर्मा, बिलासपुर, श्री शशिधर पण्डा, रायगढ़, श्री सरयूकांत झा, रायपुर, श्री बी० के० गोरे, ग्वालियर, डा० बी० एम० सिंह, इधोपुर मुरैना, और श्री स्वामी प्रसाद अरजरिया, पाना, ने अपने अपने विचार प्रकट करते हुए, आचार्यकुल के अपने अपने जिले के कामों का जिक्र किया और बताया कि यह शब्द इसका सद्देश्य और आधार सभी प्रभावकारी है। शिक्षा केवल अक्षरज्ञान नहीं, बरन जीवन जीने की कला की जानकारी का नाम है। जीवन शिक्षा की दृष्टि से जगह जगह आचार्यकुल प्रयासो मुख है। वैचारिक दृष्टि से संगठन बढ़ रहा है।

अन्त में श्री काशिनाथ त्रिवेदी ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि, "आज शिक्षा सरकार के साथ जुड़ी हुई है। शिक्षा जनता के हाथ में कैसे आय इस पर आचार्य कुल को कुछ करना होगा। पासन की हम पर पकड़ न हो। अतुर्मुखता के साथ हमारे काम का विकास होगा।

एक प्रस्ताव में जोरा में नयी तालीम की भावना का एक औद्योगिक विद्यापीठ स्थापित करने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन के अवसर पर न० प्र० आचार्यकुल उदर्य समिति की दूसरी बैठक करके उसे विघटित किया गया और विधान सम्मेलन मध्य प्रदेश आचार्यकुल का गठन हुआ, जिसमें हर जिले का समोजक अपना उनका प्रतिनिधि सदस्य रहगा। कुल सदस्य संख्या ४४ का घोषाई ११ सदस्य मनोनीत किये गये। इस प्रकार ५५ सदस्य रहेंगे। और निम्नांकित सात सदस्यों की कार्यकारिणी समिति रहगी

१. सर्वश्री काशिनाथ त्रिवेदी, इंदौर, २. ग० ज० पाटणकर, भोपाल, ३. नर्मदा प्रसाद, बिलासपुर, ४. दुर्गा प्रसाद आय, सीवा ५. डा० सरयू कांत झा, रायपुर, ६. राम कुमार शर्मा, जबलपुर, ७. गुरुधरण, ग्वालियर, समोजक। ●

सम्पादक मण्डल :

श्री घीरेन्द्र मजूमदार, प्रधान सम्पादक

श्री बंशीधर श्रीवास्तव

आचार्य राममूर्ति

वर्ष : २१

अंक : ५

मूल्य : ७० पैसे

अनुक्रम

शिक्षातंत्र न-सरकारी सार्वजनिक बने	२०१ सम्पादकीय
एक शैक्षिक प्रयोजना घर, शाला	
और समाज	२०५ श्री ज्योति भाई देसाई
दुनियावी शिदा : नयी विशाएँ, नये समाधान	२१४ श्री रामपाल सिंह
बिहार के राजकीय बनाम अराजकीय	
माध्यमिक शिक्षक	२१९ डा० जमदेव
श्री अरबिंद और शिक्षा द्वारा काति	२२१ , श्रीताराम जामसवाल
विज्ञान की मति और इमसान की मति	२२६ श्री मबानी प्रसाद मिश्र
शिक्षा में आम्बूक परिवर्तन हो	२३३ श्री यशपाल जैन
सत्तर इदेश तक्षण सातिसेना का बोधवा-नत्र	२३६
मध्य प्रदेश आचार्यकुल वार्षिक सम्मेलन	२३८

दिसम्बर, १७२



सूचना—चूँकि पिछले नवम्बर '७२ माह का विशेष अंक ५६ पृष्ठों का था, इसलिए यह अंक ४० पृष्ठों का ही प्रकाशित हो रहा है।—व्यवस्थापक

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्दा आठ रुपये है और एक अंक ७० पैसे।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री श्रीगणेशाय नमः, द्वारा सर्व सेवा सच के लिए प्रकाशित;

अनुपम प्रेस, के १९/३० दुर्गाघाट, वाराणसी में मुद्रित

दैनंदिनी १६७३

सन् १९७३ की दैनंदिनी प्रकाशित हो गयी है। इस दैनंदिनी में आप लोगों से समय-समय पर मिलनेवाले सुझावों का यथासम्भव समावेश किया गया है। इसवार की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं

- हर माह के अन्त में एक साली पृष्ठ रसा गया है।
- अन्त में भी पृष्ठ साली रसे गये हैं।
- कुल मिलाकर गत वर्षों की अपेक्षा १९७३ का दैनंदिनी में १६ पृष्ठ ज्यादा हैं।
- श्री अरविन्द शताब्दी के अवसर पर हर पृष्ठ पर श्री अरविन्द के प्रेरक वचन दिये गये हैं।
- सौर तिथियाँ दी गयी हैं।
- सरकारी घुट्टियों की तालिका।
- मासिक दैनिक वेतन का सार।
- कीमत वही।

अन्य विशेषताएँ

- प्लास्टिक का सुरक्षितपूर्ण चित्ताकषक कवर।
- फलदार पृष्ठ।
- सर्व सेवा भण्ड और सर्वोदय आन्दोलन की सन्धाओं, पत्र पत्रिकाओं एवं अन्य प्रयुक्तियों की अद्यतन जानकारी।
- डाकतार विषयक जानकारी।

साइज	माप	कीमत
क्राउन	१८।।। सें० मी० X १२। सें० मी०	॥ रुपया प्रति
छिमाई	२१।। सें० मी० X १४ सें० मी०	५ रुपया प्रति

आपूर्ति के नियम

- विक्रेताओं को २५ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है।
- एक साथ ५० या अधिक दैनंदिनी मँगाने पर निकटतम स्टेशन तक फ्री पहुँचारी भेजवायी जाती है।
- ५० से कम संख्या में दैनंदिनी मँगाने पर पैकिंग, पोस्टेज और रेल महसूल का खर्च ग्राहक के जिम्मे रहेगा।
- भेजवायी गयी दैनंदिनी वापस नहीं ली जाती।
- दैनंदिनी की बिक्री पूर्णतया नकद, बी० पी० या बैंक के माफत रखी गयी है।
- आर्डर भेजवाते समय अपना नाम, पता और निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम सुवाच्य अक्षरों में लिखिए और यह स्पष्ट निर्देश दीजिए कि मँगाया गयी दैनंदिनी के लिए आप रकम अग्रिम ड्राफ्ट द्वारा भेजवा रहे हैं या दिष्टी बी० पी० या बैंक के द्वारा भेजवा ली जाय।

दैनंदिनी समाप्त हो रही है। अतः अपने क्षेत्र के लिए आवश्यक प्रतियों के लिए शीघ्र ही सूचित करने की कृपा करें।

नयी तालीम

सर्व सेवा-संघ की मासिकी

वर्ष : २१

अंक : ६

- देश के प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों के बीच विनोबा
- उत्तर प्रदेश में शिक्षा के पचीस वर्ष
- चीन में शिक्षा के उद्देश्य और समस्याएँ

इस अंक से चन्द्रा समाप्त

जनवरी १९७३

शिक्षा में आमूल परिवर्तन का प्रथम चरण

आनेवाले समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा के वर्तमान ढाँचे में जो भी आमूल परिवर्तन किये जायें, पूरा क्रान्तिकारी काम करना होगा शिक्षा को शिक्षा संस्थाओं की चहारदीवारी से बाहर निकालने का। अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा का समुदाय के जीवन से सम्बन्ध हो तो यह अनिवार्य होगा कि पूरा समान विद्यार्थी की शिक्षा का क्षेत्र हो और आज समुदाय के विकास के लिए जो भी काम हो रहे हैं उन्हें विद्यार्थी की शिक्षा का माध्यम बना दिया जाय। इसीलिए 'नयी तालीम' की प्रारम्भ से यही नीति रही है कि स्कूल और समुदाय का पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध रहे और अध्यापककुल की शिक्षा नीति में वो हमने स्पष्ट कहा है कि—'शिक्षा को स्कूलों और कालेजों की चहारदीवारी के भीतर ही सीमित न किया जाय और पूरा समान उसका क्षेत्र हो तथा समुदाय के विकास के लिए जो भी काम हो रहा है उसे विद्यार्थी की शिक्षा की प्रक्रिया बना दिया जाय।' इसीलिए अक्टूबर १९७२ में वर्धा में जो राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था उसमें पड़े जानेवाले एकमात्र सद्धर्म लेख का शीर्षक था—'शिक्षा को समाज के विकास के साथ जोड़ना।' शिक्षा के क्षेत्र को इस प्रकार व्यापक बनाना दीक्षिक क्रान्ति का पहला चरण होगा।

वर्ष : २१

अंक : ६

३ दिसम्बर, १९७२ को मैं दिल्ली गया था और गांधी-स्मारक-निधि के अतिथि-भवन में ठहरा था। उन दिनों लेटिन अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक डा० इवान इल्लिच दिल्ली आये थे और गांधी-शान्ति-प्रतिष्ठान केन्द्र में ठहरे थे। वहाँ ५ दिसम्बर को उनका भाषण 'उत्तर-औद्योगिक समाज' (पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी) विषय पर होने वाला था। चूँकि अ० मा० गांधी स्मारक निधि के मंत्री श्री देवेन्द्र कुमार गुप्त ५ ता० को दिल्ली नहीं रहनेवाले थे, अतः उन्होंने डाक्टर इल्लिच से प्रार्थना की कि वे कुछ देर के लिए राजघाट आ जायें तो उनसे बातचीत हो जाय और जब वे आये तो देवेन्द्र कुमारजी ने कृपा-कर मुझे भी बुला लिया। डा० इल्लिच हम लोगों के साथ आध घण्टे से अधिक रहे और इस बीच श्री देवेन्द्र भाई और डा० इल्लिच के बीच जो बातचीत हुई मैं उसका मौन श्रोता ही बना रहा। अन्त में मैंने तो कबल एक ही प्रश्न किया कि आज भारत में ही नहीं, संसार में जो शिक्षा-प्रणाली चल रही है, उससे कल आनेवाले सुपर टेक्ना-लॉजिकल युग की समस्याओं का हल किस हद तक होगा? डाक्टर इल्लिच, जो एक प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री भी हैं, बोले, "मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा, उसके लिए आज समय भी नहीं है, परन्तु इतना अवश्य कहूँगा कि आज की विद्यालयी शिक्षा 'उत्तर औद्योगिक समाज' के लिए अपर्याप्त ही नहीं हानिप्रद भी है। मैं विद्यालयी शिक्षा से व्यक्ति की मुक्ति चाहता हूँ—'डी स्कूलिंग'—(अविद्यालयीकरण) चाहता हूँ। आज शिक्षा 'स्कूली-शिक्षा' का पर्याय हो गयी है और विद्यालय के बाहर हम व्यक्ति की शिक्षा की कल्पना ही नहीं कर पाते। यह ठीक नहीं है, परन्तु मैं इस विषय में आप से अधिक कुछ नहीं कहूँगा। शिक्षा के विषय में मैं जो सोचता और कहता हूँ, उसे विनोबाजी ने कदा अधिक स्पष्टता से व्यक्त किया है।"

५ दिसम्बर, १९७२ को गांधी शान्ति प्रतिष्ठान में भाषण करते हुए शिक्षा के सम्बन्ध में उन्होंने कहा, "स्कूलों के कमरों में बन्द आज की विद्यालयी शिक्षा-प्रणाली, आज के उपेक्षित जनों (अण्डर प्रिविलेज्ड) की आकांक्षाओं का स्तर इतना ऊँचा कर देगी कि विद्यालयी शिक्षा से उस स्तर को प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा। यह शिक्षा-प्रणाली उत्तर औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए

पर्याप्त नहीं होगी। अतः हमें इसके ढाँचे में आमूल परिवर्तन करना होगा।... आज के विद्यार्थी को एक साल में ९ महीने स्कूल में बिताना पड़ता है। इस शेड्यूल को बदल कर ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि विद्यार्थी को स्कूल में एक दिन में २ घण्टे से अधिक न व्यतीत करना पड़े। विद्यार्थी-जीवन के तीस वर्षों में समय का वितरण इसी हिसाब से किया जाय। इस समय जो काम स्कूल करते हैं, उनमें से अधिकांश काम उद्योग-केन्द्रों को करना चाहिए। समुदाय में स्थित फार्म और कारखानों का प्रयोग विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण-केन्द्रों की तरह करना चाहिए। फार्म और उद्योग-केन्द्रों को इस प्रशिक्षण की सुनियोजित योजना बनानी चाहिए।”

इस भाषण से स्पष्ट होता है कि क्रान्तिकारी समाज-शास्त्री डाक्टर इतिरिच ने जब कहा था कि शिक्षा के सम्बन्ध में मैं जो सोचता और कहता हूँ उसे अधिक स्पष्टता से विनोबाजी ने कहा है तो उनके ध्यान में शायद विनोबाजी को एक घण्टे की पाठशाला की योजना थी और सम्भवतः यह विनोबाजी के उस विचार से भी परिचित थे जिसमें उन्होंने ‘उद्योग’ की शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य बताया है। (और जाहिर है कि सभी विद्यार्थियों को उद्योगों की शिक्षा स्कूलों के भीतर नहीं दी जा सकती।)

जो भी हो, हम जिस अति विकसित औद्योगिक समाज की कल्पना कर रहे हैं, आज की स्कूल रूपी कारखानों में बन्द शिक्षा-प्रणाली उस समाज के अनुकूल नहीं है। इसीलिए ससार के क्रान्तिकारी चिन्तक इस विद्यालयी शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन करना चाहते हैं और इस परिवर्तन का जो भी रूप हो, एक परिवर्तन, ज़ा अनिवार्य है वह है शिक्षा को विद्यालयों के कारखानों से मुक्त करके उसे समुदाय-योग्य बनाना। बात यह है कि आनेवाले वर्षों में समाज इतना टेक्नालॉजिकल हो जायगा कि अति औद्योगिक समाज की जिस शिक्षा की जरूरत होगी, वह पूरी शिक्षा स्कूल की चहारदीवारी के भीतर नहीं दी जा सकती।

अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक ‘फ्यूचर शॉर’ में अमेरिका के विख्यात चिन्तक और समाजशास्त्री एल्विन राफ़लर भी ‘सुपर टेक्नालॉजिकल’

युग के अनुकूल शिक्षा-प्रणाली की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि "कारखानों के पैटन पर बने हुए आज के स्कूलों-कालेजों में दी जाने वाली अधिकांश विद्यालयी शिक्षा उस 'सुपर टेक्नालॉजिकल' युग के लिए बेकार सिद्ध होगी, जिस युग में अधिकाधिक शिक्षा रेडियो-टेलिविजन और कम्प्यूटरों आदि के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। चूँकि ये साधन समुदाय में उपलब्ध होंगे, अतः बहुत कुछ स्कूल के बाहर समाज में सीखा जा सकेगा। न्यूयार्क के वेस्टफार्ड-स्टेवसेन्त जिले में प्रयाग के तीर पर एक ऐसा स्कूल खोला गया है जिसने अपनी कक्षाओं को समुदाय की दुकानों, कार्यालयों और घरों में बाँट दिया है और यह कहना कठिन है कि कहीं स्कूल समाप्त होता है और कहीं समुदाय प्रारम्भ होता है। समुदाय में काम करनेवाले वयस्क स्कूल के विद्यार्थियों को वांछित कला कौशल की शिक्षा देते हैं। स्कूल और समाज का यह सहयोग और स्कूल का अधिकाधिक समुदाय-यन्मुख होते जाना आज की शिक्षा में आमूल परिवर्तन का एक बहुत महत्त्वपूर्ण आयाम बनेगा।"

और, भारत में वा इस परिवर्तन को क्रान्ति का प्रथम चरण होना ही चाहिए। यह सब जानते हैं कि अमेरिजो ने अपने स्वार्थ के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया था। शिक्षा के माध्यम से उन्हें एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति करनी थी, लार्ड मैकाले के शब्दों में उसे 'रंग में काले परन्तु चाल-चलन में गोरे' का का निर्माण कहिए अथवा 'अमेरिजी हुकूमत चलाने के लिए वायुओं की तैयारी' कहिए। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमेरिजो ने स्कूलों और कालेजों के रूप में ऐसे कारखाने खोले, जहाँ पश्चिम 'पुस्तक और कक्षा' के माध्यम से भारत में घुसा और जिन कारखानों में शिक्षा पानेवाले भारतीय जन जीवन से अलग हो गये। चूँकि आज भी वह शिक्षा पद्धति बदली नहीं है और शिक्षा के कारखाने पहले की तरह ही चल रहे हैं, अतः आज की शिक्षा जन-जीवन से पहले की तरह से ही कटी हुई है। इसलिए अगर हम शिक्षा के स्वरूप में इस उद्देश्य से परिवर्तन करना चाहते हैं कि वह भारतीय जन-जीवन और भारतीय संस्कृति से जुड़े तो हमको शिक्षा को स्कूलों की चहारदीवारी से बाहर निकालना होगा। शिक्षा में आमूल परिवर्तन का यह पहला

कदम होगा। जब तक शिक्षा स्कूली कारखानों के कैद से मुक्त नहीं होगी और समुदाय के उन्मुक्त वातावरण में नया जीवन नहीं प्राप्त करेगी तब तक शिक्षा में वास्तविक क्रान्ति नहीं होगी। ऊपर से तो लगेगा कि इससे परिवर्तन केवल शिक्षा के बाहरी ढोंचे में ही होगा परन्तु व्यवहार में यह उस अविद्यालयीकरण (डी स्कूलिंग) की प्रक्रिया का सत्रसे दृढ़ चरण होगा जिसकी वकालत डा० इवान इल्लिय ने की है।

इस कदम का अर्थ होगा स्कूल के टाइम टेबुल में मौलिक परिवर्तन। शिक्षा का समुदाय के जीवन से अन्तरंग सम्बन्ध, समुदाय में चल रही उत्पादन और सृजन की समस्त प्रक्रियाओं से एकाकार होना और स्कूल के भीतर किताब और कक्षाओं के माध्यम से जो एक अनुत्पादक अर्थार्थ वातावरण बन गया है, उससे मुक्ति। अतः जिनकी ही जल्दी यह कदम उठाया जाय उतना ही शुभ होगा।

—धर्मीधर धीवास्तव

क्षमा करें

उत्तर प्रदेश के विजिली इंजीनियरों की हड़ताल के कारण प्रेस बन्द था, इसलिए नयी तारीख का प्रमाण थक काफी देर से छप पाया है।

—स०

देश के प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों के बीच विनोबा

प्रश्न आज की माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ायी जाती है। बहुसंख्य बच्चों पर उसका बोझ होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है ?

विनोबा : बहुत महत्व का विषय है। अंग्रेजी में कहावत है, 'लिटिल मालिज द्रज ए डेंजरस थिंग' (अल्प ज्ञान खतरनाक होता है)। इसलिए सब बच्चों की थोड़ी-थोड़ी अंग्रेजी सिखाने की जो बात है उसका लाभ नहीं। इस बास्ते सब बच्चों पर अंग्रेजी लादना ठीक नहीं, बल्कि यहाँ तक होना चाहिए कि बिना अंग्रेजी के बच्चे बी० ए० और एम० ए० भी हो रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ खास विषयों के साथ अंग्रेजी का ज्ञान लाभदायी होता है, इसलिए थोड़े विद्यार्थियों को उत्तम अंग्रेजी सिखायी जाये। थोड़ी-थोड़ी सिखाने में फायदा नहीं, थोड़े विद्यार्थियों को उत्तम सिखानी चाहिए, ऐसा मैंने कहा। लेकिन केवल अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। लोग

समझते हैं कि अंग्रेजी एक 'खिड़की' (खिड़की) है, दुनिया के दर्शन के लिए— उसमें से दुनिया को देख सकते हैं । लेकिन अबलनाले मनुष्य के घर में एक ही खिड़की नहीं होगी । चार दिशाओं में खिड़कियाँ रखनी पड़नी हैं, तब ठीक प्रकाश आता है, ठीक दर्शन होता है । एक ही खिड़की से सीमित प्रकाश आता है, सीमित दर्शन होता है । इस वास्ते मेरी राय में अपने देश में कम-से-कम 'सप्तवाणी', सात भाषाओं की पढ़ाई होनी चाहिए । अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और जर्मन, चार यूरोप की भाषाएँ, मध्य एशिया के लिए अरबी, और इधर चीनी और जापानी । भारत की भाषाओं के अलावा, इन सात में से एक भाषा का उत्तम ज्ञान होना चाहिए । तब इन सातों में से दुनिया का सब तरह की अच्छी जानकारी होगी । आज चीन की जानकारी हमको अंग्रेजी के द्वारा मिलती है । अंग्रेज लोगों के घरों से हम चीन की तरफ देखते हैं । चीन की तरफ चीन के घरों से देखना चाहिए । वैसे ही अरबी मुल्कों की तरफ अरबी लोगों की दृष्टि से देखना चाहिए । तो हमको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा । आज अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है अंग्रेजी के द्वारा ।

एक, हमारे बच्चे बिना अंग्रेजी के ४० ए० हो । दो, केवल अंग्रेजी नहीं, और भाषाओं का भी उत्तम ज्ञान हमारे देश में हो । तीन, मैंने कहा, सात भाषाओं की सात खिड़कियाँ होनी चाहिए यह तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी अभी जो सहुलियत हम लोगों को है, उसका ब्याल करते हुए अंग्रेजी की खिड़की, जरा बड़ी होगी ।

प्रश्न . शिक्षा सरकारी तन्त्र से मुक्त हो, यह आपका कहना जबरता है, लेकिन पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए ?

विनोबा इस विषय में मैं खास विचार रखता नहीं । लेकिन पाठ्यक्रम हर गाँव में अलग-अलग भी हो सकता है । अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ायी जा सकती हैं । इस वक्त मुझे पढ़ित मालवीयजी का एक वाक्य याद आ रहा है—“ग्रामे ग्रामे सुभा कार्या ग्रामे ग्रामे शुभा कथा पाठशाला मल्बशाला ग्रामे ग्रामे ।” हर गाँव में अपनी पाठशाला होगी और उस पाठशाला में वे जिस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हो जो पाठ्यक्रम रखना चाहते हो, वैसा होगा । सरकारी तौर पर जो टेक्स्टबुक्स (पाठ्यपुस्तकें) रखनी होगी, वे उन्हीं को समिटी के द्वारा तय हो, लेकिन वे पुस्तकें रिकामेण्डरी (सिफरिस के तौर पर) हो, “बम्बलसरी” (लाजमी तौर पर) न हो ।

प्रश्न : आप कहते हैं कि शिक्षा सरकारी तन्त्र से मुक्त हो, पर यह सारा

आयोजन (राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का) सरकार की ओर ही हो हुआ है । क्या इस तरह शिक्षा सरकारी तंत्र से मुक्त हो सकती है ?

विनोबा मैं समझता हूँ कि यह सम्मेलन केवल आरम्भ है । इसमें कुछ चर्चा होगी, तब उसको पूर्णतया आयेंगी । आरम्भ में सरकारी तंत्र के लोग आते हैं, तो अच्छा ही है । हम किसी पेड़ को काटते हैं, तो भी पेड़ की छाया में बैठकर काटते हैं । काटते समय यह ख्याल रखें कि पेड़ गिरेगा, तब थोड़ा अलग हो जायें । शिक्षा सरकारी तंत्र से मुक्त हो, इसकी चिन्ता और कोशिश आगे सरकार ही करेगी । मेरा कहना इतना ही है कि जैसे न्याय-विभाग सरकारी पैसे पर चलाता है, पर सरकारी तंत्र से मुक्त है, वैसे शिक्षा भी हो । विद्यापियों का दिमाग एक छान्ने में डालना सोचनाही के खिलाफ है । मेरा मानना है कि सरकार सोचनाही का बाका करती है, इसलिए यह बलीस स्वीकार करेगी ।

प्रश्न एक लिपि होने से देश में एकता आयेंगी यह कहना हाथ पाँव एक होने से हृदय एक होगा कहने जैसा नहीं है ? यूरोप में एक लिपि है, पर यूरोप का एक हृदय नहीं बना है ।

विनोबा ये भाई शायद भूल गये हैं कि मैंने शिक्षा व सहयोग प्रधान है, कहा था, एक लिपि प्रधान हो, नहीं कहा था । लिपि स्वतंत्र विषय है । सहयोग में विश्वमानव बनना है, और सबके साथ एकता महसूस करनी है । यह मुख्य कार्य है । यह नहीं कहा कि लिपि एक होगी तो हृदय एक होगा । लिपि एक होगी तो उससे एक हृदय होने में मदद मिलेगी, एक-दूसरे के साहित्य का परिचय होगा । इतना लाभ होगा । लाभ यह लाभ कम नहीं है । सारे भारत की दृष्टि से बेला जाय तो बहुत बड़ा है । इतना लम्बा-चौड़ा देश है, चौदह चौदह पन्द्रह पन्द्रह विविध भाषाएँ हैं । ऐसे देश की एकता के लिए—एक-दूसरे की अण्डरस्टैंडिंग (समझने) के लिए उससे मदद होगी, यह मैंने कहा था । इसका लाभ सीमित है, फिर भी महान है ।

आप का कहना है यूरोप में लिपि एक है, पर हृदय एक नहीं है । बाबा कालेज में था, तब अंग्रेजी सीखा और थोड़ा फ्रेंच सीखा । बाद में बाबा ने जर्मन सीटिव भाषाएँ पढ़ाई पढ़ाई दिन में सीख लीं, क्योंकि सबकी लिपि एक थी । अभी यूरोप का एक हृदय बन रहा है और उसको एक लिपि की मदद हो रही है । यूरोप में 'इकनामिक कम्युनिटी', जिसको 'कमन मार्केट' कहते हैं होगा सबको जोड़ने के लिए । ऐसी वृत्ति वहाँ बन रही है, जो भारत में

प्राचीन काल में थी। द्वाविंशौ शताब्दी। आसिंधेरा परावतः। वेद में मय है। भारत की दोनो बाजू से हवा बहती है। एक बाजू से, आसिंधो-समुद्र से आती है और दूसरी बाजू से आपरावज-हिमालय की गुफा से आती है। दक्षिण भारत से और उत्तर भारत से हवाएँ चलती हैं और ये हवाएँ भारत को एक करती हैं। सात्वत्यं, भारत अनेक भाषाओं और धर्मों को मिल कर एक देश हम बना सके। लेकिन यूरोप में 'ट्रायबलिज्म' (टोलीवाद) चलता है। छोटे-छोटे, एक-एक भाषा के देश हैं। एक, रशिया को छोड़कर वहाँ के सब देश उत्तर प्रदेश से छोटे हैं। लेकिन अब उनमें भावना पैदा हुई है कि हमको एक होना है। जितना पश्चिमी हिस्सा है यूरोप का, वह एक होने की कोशिश कर रहा है। और वह करने में एक लिपि उनकी मदद कर रही है। यह समझने की जरूरत है। एक लिपि के कारण उनको बहुत मदद हो रही है, और एक लिपि तही होती, भिन्न-भिन्न, निपियाँ होती तो सम्भव है तकलीफ होती। दुनिया की लिपि एक हो जाय, यहाँ तक उनकी कोशिश हो रही है। सारे भारत के लिए एक लिपि एक हो जाती है, तो चीन और जापान उसको स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भाषाओं की रचना हमारी भाषा के समान है। लेकिन हम ही उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं भारत में। इसलिए रोमन लिपि जोर कर रही है।

प्रश्न : शिक्षकों को जितने घण्टे काम करना चाहिए ?

विनोबा मेरा विचार है कि शिक्षकों को रोज विद्यालयों के साथ तीन घण्टे शरीरधर्म का काम करना चाहिए और तीन घण्टे वे विद्यालयों की बौद्धिक शिक्षा दें। इस तरह छ घण्टे पर्याप्त काम होगा। बाबा ने तो दस घण्टे से कम काम लिया नहीं। गांधीजी के पास रहते थे, तब शरीरधर्म के लिए आठ घण्टे तो देना ही पड़ता था। उसके अलावा स्वतंत्र अध्ययन-अध्यापन के लिए दो-चार घण्टा अलग काम तो चलता ही था। परन्तु सामान्य शिक्षक को, उसकी बदनी भी जिम्मेवारी होती है, इसलिए छ घण्टे काम पर्याप्त है।

प्रश्न : शिक्षकों की तनखाह सरकारी नौकरों को अपेक्षा अधिक होना चाहिए या नहीं ?

विनोबा : इस विषय में बाबा की राय इतनी ही है कि सरकार के जितने सेवक हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे दूसरे कामवाले हो—पोस्टवाले या रेलवेवाले, सबको उनकी तनखाह का एक हिस्सा अनाज में देना चाहिए। उत्तम-से-उत्तम अनाज सरकार अपने सेवकों को दे। तनखाह कम-बेशी हो सकती है,

पर अनाज निश्चित मात्रा में होगा। उतना निश्चित अनाज मिल जाये तो जीवन सुरक्षित रहेगा। कम-से-कम खाने में तो चिन्ता नहीं रहेगी। पचास साल पहले मैं यहाँ आया, तब यहाँ के सालदार (वार्षिक तनखाह पर खेत में काम करनेवाला मजदूर) को छः कुटो (लगभग १० सेर की एक नाप) जवारी और तीस-चालीस रुपया साल का मिलता था। आज भी छः कुटो जवारी कायम है और चार-सो-पाँच-सो रुपया मिलता है; क्योंकि रुपये की कीमत गिर गयी है। लेकिन, जवारी कायम है इसलिए यहाँ के मजदूर बचे हैं। नहीं तो बचते नहीं, मार खाते। पाँच से के बदले हज़ार रुपया मिलता तो भी बचते नहीं। क्योंकि उससे 'सिक्कूरिटो' (सुरक्षितता) नहीं रहती। इस वास्ते जीवन की मुख्य वस्तु अनाज, वह सरकारी सेवकों को सरकार की ओर से मिलना चाहिए।

लोग तो उल्टा काम कर रहे हैं। किसानों को कहते हैं कि टैंक्स पैसे में दी। इससे अधिक मूल्यता हो नहीं सकती। पैसा क्या है? नोटें तो नास्तिक में छपती हैं। एक 'ठप' में एक रुपया और एक 'ठप' में सौ रुपये। एक किलो गेहूँ के लिए हमको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उससे सौ गुना मेहनत सौ किलो के लिए करनी होगी। पर नोटें सब एक ही 'ठप्' में; ऐसा इन्द्रजाल है। मैं इसको इन्द्रजाल कहता हूँ। पैसे ने हमको निकम्मा कर दिया है। इसलिए पैसे से मुक्त होना चाहिए। पैसे की कीमत तो गिरती रहती है। अनाज में टैंक्स लेने को हानि नहीं, लाभ है। किसानों से टैंक्स अनाज में लें और सरकारी सेवकों को तनखाह का एक हिस्सा अनाज में दें। इससे मध्यम वर्ग, जो सरकारी नौकरी पर आधार रखता है, उनको बहुत लाभ होगा। मैंने सुना है कि चीन में किसानों से अनाज में टैंक्स लेते हैं, न कि पैसे में। इससे काफी समस्याएँ हल होगी; ऐसा मैं मानता हूँ, और उसके बिना समस्याएँ हल नहीं होगी, ऐसा भी मानता हूँ।

प्रश्न : यम-नियमों की शिक्षा कैसे दें? उसके लिए कौन से संघ आवे सुझावेंगे?

दिनावा : मैंने कहा था कि इस बारे में मदद करने के लिए आध्यात्मिक ग्रन्थ पढ़ें हैं। जैसे योगसूत्र है, योग सिखानेवाला। यह कहनेवाला कि इंद्रियों पर काबू कैसे पा सकते हैं, योगसूत्र से बढ़कर दूसरा ग्रन्थ दुनिया में देखा नहीं। स्वयं भीता बताती है स्थितप्रज्ञ-दर्शन में कि मन पर काबू रखने के लिए क्या करना चाहिए। ब्रह्मसूत्र है। कुरान है। बाइबिल है। इन ग्रन्थों से मदद मिलेगी, इंद्रियों पर काबू कैसे पाना? ईसा की सूली पर चढ़ाया, बहुत वेदना

हो रही थी, तो वेदना का उद्गार निवला मुख से। तब तुरत एक क्षण में उनकी मानवता जाग्रत हो गयी, कहा भगवान से—दाय विभ बी डन, घाट माईन—मेरी ईच्छा नहीं, तेरी ईच्छा पूर्ण हो। और जिन्होंने सूती पर चढ़ाया था, उनके लिए ईश्वर के पास क्षमा मांगी। इससे बढ़कर सयम क्या हो सकता है? ऐसे आध्यात्मिक ग्रन्थ यानी अनुभव के बावय, महापुरुषों के चरित्र, जिनसे हमको तालीम मिलती है, काम में आयेंगे।

प्रश्न : राज सरकार के पास पैसा है ही नहीं। इसलिए छ से बारह साल तक के सब बच्चों को तालीम दी ही नहीं जा सकती। तो क्या करें?

विनोबा : छ से बारह साल तक के बच्चों को शिक्षा दी नहीं जाती, वह भारत के बच्चों पर कृपा है। हमको हमारी माँ ने बचपन में तालीम दी भक्ति की। भक्ति सिखायी। कैसे सिखायी? दिन भर काम करती थी। फिर हम चले जाते थे स्कूल-कालेज में। विताजी दफ्तर में चले जाते थे। तब वह पूजन के लिए बैठती थी। खाना तब तक नहीं होता था। तब तक भूँह में कुछ नहीं जाना था। घण्टा भर घोड़शोषचार पूजा चलती थी। और आखिर में कान पकड़ कर कहती थी, हे अनतकोटि ब्रह्माण्ड नायक। मेरे अपराधों को क्षमा कर। तब उसकी आँखों से आँसू बहते थे। यह तालीम मिली बाबा की। उसमें से जो पाया, वह बाबा की किसी भी स्कूल में मिला नहीं। इस वास्ते यह भ्रम है हमारा कि स्कूल में बच्चे जायेंगे सभी तालीम पायेंगे। लेकिन एक बात है। पाकिस्तान और चीन के साथ मेलजोल हो जाता है, सेना पर खर्च कम होना है तो उस हालत में तालीम के लिए ज्यादा पैसा मिल सकता है। यह कितनी मात्रा में हम एशिया के देशों के साथ मेल-जोल करते हैं सफल होते हैं, उस पर निर्भर है। आज बहुत सारा पैसा सेना पर खर्च हो रहा है। पाकिस्तान का तो सेना पर ७० फीसदी खर्च होता है, हिन्दुस्तान का ३०-४० फीसदी होता है।

प्रश्न : प्राचीन धर्म ग्रन्थों के अध्ययन पर आप जोर देते हैं, लेकिन आधुनिक साहित्य के बारे में कुछ नहीं कहते। क्या आईन्स्टीन का साहित्य अक्षर साहित्य नहीं है?

विनोबा : इस विषय में बाबा का कहना है कि विज्ञान के लिए 'रीड दी माउनेस्ट' (आधुनिकतम विचारों) पढ़ें। और अध्यात्म के लिए 'रीड दी ओल्डेस्ट' (प्राचीनतम विचारों पढ़ें)। यह थोड़े से नुस्खा है, युक्ति है। विज्ञान में नयी-नयी खोजें होती रहती हैं। विज्ञान निरन्तर बदलता रहेगा। न्यूटन

के जमाने में न्यूटन से बढ़कर दूसरा वैज्ञानिक नहीं था । परन्तु, आज स्कूल का बच्चा भी उससे अधिक जानता होगा । आज न्यूटन के ग्रन्थ केवल ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं । यह ख्याल गलत है कि आइंस्टीन का साहित्य अक्षर है । विज्ञान बहुत गति से बढ़ रहा है, इसलिए यह गारण्टी (विश्वास) नहीं कि आइंस्टीन का साहित्य अक्षर रहेगा । नयी नयी खोजें होगी और पुरानी पिछड़ जायेंगी ।

आज रेडियो अस्ट्रोनॉमी का ज्ञान बढ़ रहा है । पहले सात प्लैनेट थे—प्लैनेट यानी यहाँ है वैसी ही हवा जहाँ है—उनमें एक-दो और बढ़ें । अब तो कहते हैं हजारों ग्रह हैं—नये-नये ग्रहों की खोजें हो रही हैं, मंगल पर और दूसरे ग्रहों पर मनुष्य जैसे प्राणी भी हो सकते हैं । बाइबल मेरे मन में तो यहाँ तक विचार आता है । मेरा अपना विचार है वह यह है कि परमेश्वर की सृष्टि में सर्वत्र अनन्तता दिखायी देती है, तो इद्रियाँ ही सीमित कैसे हो सकती हैं ? एक खून के बिन्दु में लाखों जंतु हैं और हवा हाथी जैसा बड़ा प्राणी है । सर्वत्र अनन्तता है, तब इद्रियों की कैसी सीमा हो सकती है ? अभी तक पाँच इद्रियों के प्राणी पाये गये हैं । तो मेरी आशा है कि इन ग्रहों पर छ, सात, आठ या उससे भी अधिक इद्रियोंवाला प्राणी हो सकता है । वह हमको मार्ग दर्शन भी कर सकता है । एक बार मेरे मन में बिचार आया कि ऐसा, पाँच इद्रियों से अधिक इद्रियोंवाला प्राणी होगा कहीं, तो वह हमको सन्देश क्यों नहीं भेजता ? फिर इसका उत्तर सुझा ही मिला गया कि हम वहाँ चींटियों को भ्रमण भेजते हैं ?

तो विज्ञान निश्चय नयी खोजें कर रहा है इसलिए विज्ञान में आधुनिकतम प्रथम पढ़े और अध्ययन में प्राचीनतम, क्योंकि ये प्रथम काल की परीक्षा में खड़े उतरे हैं ।

प्रश्न यहाँ उपकुलपति, शिक्षामंत्री, शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षाविद् लोग इकट्ठा हुए हैं । कृपया उन्हें आप आचार्यकुल के बारे में कुछ कहें ।

यिनोया बाल एसी है कि हम एकाध साल के लिए नौकर रखते हैं अपने खेत पर या घर में । उसका नाम पसंद आया तो आगे भी उसी को रखते हैं । नहीं तो बदल देते हैं । वैसे ये राजनैतिक नेता प्रजा के पाँच साल के लिए रखे नौकर हैं । उनकी नौकरी अच्छी लगी तो उन्हें दूसरे पाँच साल के लिए भी रखा जायेगा, नहीं तो नौकरी से हटा देंगे । मतलब राजनैतिक नेताओं की सत्ता पाँच साल चलेगी । परन्तु शिक्षक जो है वह सत्तत तीस साल सेवा कर सकता है । इसलिए इन राजनैतिक नेताओं की अपेक्षा शिक्षक की शक्ति

अधिक है। दूसरी बात यह है कि शिक्षक की परम्परा चलती है। यह शिक्षक जायेगा, परन्तु उसने जिसको सिखाया है ऐसा ही कोई विद्यार्थी शिक्षक बन कर उसकी जगह पायेगा। राजनीति में क्या होता है? साम्राज्य आते हैं और आते हैं। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में 'गुप्त साम्राज्य' था—मैं प्राचीन काल के गुप्त साम्राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। एक समय में उसी का बोल-वाला था, पर धाज उसकी कोई परम्परा रही नहीं। शिक्षकों की परम्परा चलती है और शिक्षकों की शक्ति भी अधिक है। दुनिया में जितनी क्रान्तियाँ हुई हैं, वह सब शिक्षकों ने ही की है। चाहे वह रशिया की क्रान्ति हो, चाहे फ्रांस की हो, सब जगह शिक्षकों के द्वारा क्रान्ति हुई है। इसलिए शिक्षकों को अपनी स्वतंत्र शक्ति सँभाल करनी चाहिए। हिन्दुस्तान के तमाम शिक्षक आचार्यकुल में आ जायें, तो 'तीसरी शक्ति' सँभली होगी। एक ग्रामशक्ति और दूसरी आचार्यों की ज्ञान शक्ति, मिलकर एक असम शक्ति बनेगी, जिसके आधार से भारत खड़ा रहेगा। आचार्यकुल की यह मूल वस्तु है।

प्रश्न : आज समाज में सर्वत्र स्वार्थ-भावना, लातब, भ्रष्टाचार की वृत्ति दिखाई देती है। उसके लिए क्या उपाय है ?

बिनोया : आप जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं, वह भ्रष्टाचार नहीं होता है, वहाँ वह निभ्रष्टाचार है। इसके लिए हमारे समाज में बहुत अच्छे शब्द रूढ़ हैं। कहते हैं, "कुछ मामूल दिया जाये", यानी यह मामूली चीज है। कही तो कहते हैं, "दक्षिणा दिया जाये।" "कुछ भेंट दिया जाये।" मूलतः यह शिष्टाचार ही गया है। इसका मूल कारण है बदमाश लफंगा पैसा।

परन्तु हम लोगों ने उसको अपने व्यवहार का माध्यम बना दिया है। आज समाज में जो व्यवस्था है वह दोषपूर्ण है, इसलिए यह सब करना पड़ता है। समाज की व्यवस्था गलत है। लेकिन व्यक्ति गलत नहीं है। व्यक्ति असंग है। समाज जो बना है सबका मिल कर बना है, बाल पुरुष के कारण बना है। व्यक्ति का हृदय स्वतंत्र है। व्यक्ति के हृदय में गुण मरे हैं। मनुष्य पर विश्वास करते हैं तो उसका परिवर्तन होता है। इस मामले में मुहम्मद पंगवर ने मिसाल दी है ईसा मसीह की। ईसा मसीह रास्ते से आ रहे थे। सामने एक आदमी जा रहा था। दूसरे एक आदमी ने उसकी जेब में हाथ डाल कर पैसा निकाल लिया। ईसा ने उससे पूछा कि, "तूने यह क्या किया", तब वह आदमी बोला कि, "मैं भगवान का नाम लेकर कहता हूँ कि मैंने पैसा नहीं

लिया। तब ईसा मसीह ने कहा, “यद्यपि मैंने तुम्हें खोरी करते हुए देखा है, लेकिन परमात्मा के नाम पर मैं अपनी आँखों से ज्यादा विश्वास करता हूँ।” यह सुनकर उस आदमी का हृदय-परिवर्तन हो गया और वह सज्जन बना। विश्वास में परिवर्तन की यह शक्ति है।

प्रदत्त १९४० में मैं आपके साथ जेल में था। सभी संगीत विद्यापीठ का उपकुलपति हूँ। संगीत विद्यापीठ के लिए सदेश देने का अनुग्रह करें।

विनोदा आध्यात्मिक भावना पैदा करने के लिए और चित्त के विकास लिए संगीत से बढ़कर दूसरा साधन नहीं। इसलिए उत्तम से उत्तम चरित्रवान जो गीत हैं भजन हैं, जैसे तुलसीदास, सूरदास के भजन, उनका संगीत होना चाहिए और वह अच्छों को सिखाना चाहिए। न कि तरह तरह के गाने, जिसमें अच्छे विचार नहीं होते। खराब संगीत रहा तो वह चित्त को बिगाड़ सकता है, भ्रष्ट कर सकता है। उत्तम संगीत रहा तो वह उन्नत करता है। इस वास्ते संगीत विद्यालय में जैसे नामदेव का गाना था, वैसे गाने सिखाये जायें। नामदेव ने गाया है

काठ देहासी आला खाऊँ

आम्ही आनदे नाचूँ गाऊँ

अरे, काल मेरे शरीर को खाने के लिए आया है और मैं अनंद से नाच रहा हूँ। मृत्यु का समय आयेगा, तब क्या करेंगे? ‘अरेरे, मृत्यु का समय आया, ऐसा रोयेंगे? अरेरे-अरेरे नहीं, आनंद से नाचेंगे, गावेंगे।’ मरने के समय गाना चाहिए, ऐसा होगा, तब संगीत विद्यापीठ के आचार्य पास होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, सेवाश्रम में आये प्रतिनिधियों के साथ।

दिनांक १५ १०, '७२

ब्रह्म विद्यामंदिर, पंचमार।

सेवाग्राम में नयी तालीम का नया मोड़

(१) बापू ने आधुनिक और नयी तालीम के बीच फर्क नहीं किया। नयी तालीम की जरूरत को मुख्य मानकर विरोध के बावजूद सब तरह की सहूलियतें दे कर देते थे। सेवाग्राम नयी तालीम का केन्द्र हो और उससे देश को मार्गदर्शन मिले यह उनकी अपनी इच्छा रही। नयी तालीम उनकी “आखिरी और सर्वोत्तम देन” थी।

(२) नयी तालीम का आधार स्वावलम्बन है। स्वावलम्बन, स्वदेशी वस्त्र तथा शरीर-अभ्युत्थान के बिना सध बही सक्ता। नयी तालीम की सफलता के लिए इन दोनों तत्वों का शिक्षकों से आना पहली शर्त है।

(३) नयी तालीम का प्रयोग पिछले कई साल (१९६०) तक चला, काफी सफलता भी प्राप्त हुई।

(४) पिछले दस साल से नयी तालीम की प्रवृत्ति यहाँ घीमी चल रही है। इस पर विचारवान लोग विवर्तित हो हैं। सम्पादन कार्य में अड़ान-उतार दोनों स्वाभाविक है। उतरा तो उत भी सकता है।

(५) आज सेवाग्राम में नयी तालीम का एक अच्छा स्कूल चले, ऐसा भी कई लोग चाहते हैं। लेकिन यह कठिन हो नहीं असम्भव भी होगा, क्योंकि आज यह कृत्रिम दिखेगा।

(६) पर यहाँ एक प्रशिक्षण का केन्द्र चल सकता है। उसके दो विभाग हो सकते हैं। एक, शिक्षकों का, जो दो साल का हो, और दूसरे १६ साल के ऊपर के छात्रों का, जो तीन साल से पाँच साल तक हो। पचास शिक्षकों का प्रशिक्षण और करीब एक सौ युवकों का समूह स्वावलम्बन का प्रयोग चले, और आसपास के गाँवों को भी अपने शिक्षा-कार्य में मिला दे, तो देश के लिए काफी लाभ हो सकता है। बापू का स्वप्न भी साकार होगा।

नयी तालीम का यह नया पर्व कैसे शुरू हो? जिस तरह १९४२ में स्व० आर्यनाथनम्जी ने नयी तालीम द्वारा शिक्षक तैयार करने का शुभारम्भ किया, इसी तरह आज शिक्षक तैयार करने में शुरू करें। १९४२ में प्रार्थना के लिए जो मंत्र धोमती आशा देवी ने उपयुक्त समझा और जिसे बापू ने तारोफ की थी, उसे फिर यहाँ का मंत्र मानें। 'विज्ञानम् ब्रह्म इति म्यजानात्'। पच्चीस या पचास शिक्षकों से आरम्भ करें। यह अखिल भारतीय स्तर का हो। वस्त्र-स्वावलम्बन से शुरू करके धीरे-धीरे अन्न, शिक्षा, आरोग्य तक पहुँच जायें।

प्रशिक्षण अवधि में आसपास के चार या पाँच गाँवों में स्थानिक पाठशाला, पचायत आदि के माफ़ेत शिक्षा का अग्र-पाठ भी हो। गाँव से प्रत्यक्ष सम्बन्ध के साथ प्रशिक्षण भी हो। जबकि कम-से-कम दो साल की हो। शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था को बैठाने के छ महीने बाद, छात्रों को भी शिक्षण देना आरम्भ करें। इसमें २० साल के ऊपर के अन्दर के छात्र, जो सरकारी परीक्षाओं में पास या नापास होकर निराश हो गये, ऐसे लोगों को अधिक लें। स्वेच्छा से आज की पढ़ाई छोड़नेवालों को भी लिया जा सकता है।

इस तरह डेढ़ सौ की संख्या होगी। साथ ही शिक्षक-परिवार आदि मिलाकर दो सौ लोगों का समाज इस नये प्रयोग में लगेगा तो नया रास्ता खुलेगा। शुभस्य सीधम्। अगर जल्दी ही शुरू करें, तो अनायास पूज्य विनोबा का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन भी मिलेगा। क्योंकि यह ग्रामदानी प्रखण्डों के लिए नितान्त आवश्यक है। जबकि कइयों को देश भर की शिक्षा की चिन्ता थी, तब गांधीजी ने अपने नयी तालीम केन्द्र को सेवाग्राम के अन्दर सीमित रखा था। हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की कोई प्रांतीय शाखा खोलने की गुंजाईश नहीं रखी थी। यहाँ के प्रयोग को दूसरे स्वेच्छा से अपनायें।

आगे चलकर प्रशिक्षण केन्द्र की मजदूती से यहाँ स्वतन्त्र नयी तालीम पाठशाला भी पन सकेगी। क्योंकि नयी तालीम तो वर्तमान समाज-व्यवस्था को बदलने के लिए है।

—स्वयंम्

उत्तर प्रदेश में शिक्षा के पचीस वर्ष

[आजादी के पचीस वर्षों में उत्तर प्रदेश की शिक्षा में जो प्रगति हुई है उसका आकलन इस लेख में किया गया है। जाहिर है कि यह प्रगति मात्रात्मक ही अधिक है, क्योंकि शिक्षा के रूप में आमूल परिवर्तन न तो देश में कहीं हुआ है और न इस प्रदेश में। फिर भी भारत के इस सबसे बड़े प्रदेश में शिक्षा के प्रसार के लिए स्वातन्त्र्योत्तर काल में जो कुछ किया गया, संक्षेप में उसका वर्णन इस लेख में किया गया है।

—सम्पादक]

छात्रों की संख्या में वृद्धि

संविधान में निहित विदेशक तत्वों के अनुरूप चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक एवं बालिका को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना लोकतन्त्र की सफलता के लिए अनिवार्य है। इस उद्देश्य से स्वतन्त्रता-प्राप्ति के प्रस्ताव प्रारम्भिक स्तर पर शत-प्रतिशत बालक-बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने, माध्यमिक स्तर पर बहुदेशीय शिक्षा की व्यवस्था करने तथा विश्वविद्यालयीय स्तर पर उच्च शिक्षा एवं अनुसन्धान की सुविधाएँ प्रदान करने की ओर उत्तर प्रदेश में अनेक साहसिक कदम उठाये गये। जिसके परिणाम स्वरूप

- जहाँ वर्ष १९५०-५१ में शिशु विद्यालयों के छात्रों की संख्या केवल ८०६ थी, आज ३१,००० हो गयी है।

- जहाँ वर्ष १९४६-४७ में जूनियर वेसिक स्तर पर छात्र-संख्या २०.०५ लाख थी, वर्ष १९७१-७२ में ११४.१८ लाख हो गयी। वय-वर्ग ६-११ की कुल संख्या के अनुपात में बालकों का नामांकन १०० प्रतिशत तथा बालिकाओं का ८७.०५ प्रतिशत है, जो कि वर्ष १९५०-५१ में क्रमशः ५७.५१ प्रतिशत तथा ६०.७८ प्रतिशत था।
- जहाँ वर्ष १९४६-४७ में सीनियर वेसिक स्तर पर छात्र-संख्या १.९४ लाख थी, वर्ष १९७१-७२ में १९.५१ लाख हो गयी। वय-वर्ग ११-१४ की कुल संख्या के अनुपात में बालकों का नामांकन ४४.८० प्रतिशत तथा बालिकाओं का १२.१५ प्रतिशत है, जो कि वर्ष १९५०-५१ में क्रमशः २०.१९ प्रतिशत तथा २.१० प्रतिशत था।
- जहाँ वर्ष १९४६-४७ में माध्यमिक स्तर पर छात्र-संख्या ०.७१ लाख थी, वय १९७१-७२ में ११.३३ लाख हो गयी। वय-वर्ग १४-१८ की कुल संख्या के अनुपात में बालकों का नामांकन २१.९० प्रतिशत तथा बालिकाओं का ५.९२ प्रतिशत है, जो कि वर्ष १९५०-५१ में क्रमशः ६.७० प्रतिशत तथा ०.५९ प्रतिशत था।
- जहाँ वर्ष १९५०-५१ में उच्च शिक्षा के स्तर पर छात्र संख्या ०.२९ लाख थी, वर्ष १९७१-७२ में १.४९ लाख हो गयी।

छात्र-कल्याण-योजनाएँ

शिक्षा-प्रसार के प्रयासों के अन्तर्गत एक ओर बालकों को विद्यालयों की ओर आकृष्ट करने के लिए तथा दूसरी ओर उन्हें आवश्यक सुविधाएँ देने के लिए राज्य द्वारा अनेक सीमित साधनों में कई छात्र-कल्याण-योजनाएँ भी लागू की गयीं, जिनमें से विवेक उल्लेखनीय ये हैं

- निःशुल्क शिक्षा—कक्षा ६ तक सभी बालकों, कक्षा १० तक सभी बालिकाओं, सौ रुपये तक आयवाले समस्त राज्य कर्मचारियों तथा माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों के आश्रितों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी गयी है।
- बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन—बालिकाओं की शिक्षा को प्रारम्भिक स्तर पर प्रोत्साहन देने के ध्येय से स्कूल-माताओं की नियुक्ति की गयी तथा विद्यालय के समीप अध्यापिकाओं के लिए आवासगृह निर्मित किये गये।
- बालाहार—यह योजना बालकों की निःशुल्क वीटिक स्वस्थानाहार प्रदान

करने की दृष्टि से आरम्भ की गयी और इसके अन्तर्गत इस समय ३० जिलों के लगभग साढ़े तेरह लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं ।

- छात्रवृत्तियाँ—स्वतंत्रता के पश्चात् जूनियर हाई स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा-स्तर तक योग्यता, प्रतिभा तथा विधनता के आधार पर छात्रवृत्तियों की अपेक्षाकृत अधिक व्यापक व्यवस्था की गयी । इसके अतिरिक्त सुरक्षा सैनिकों तथा पी० ए० सी० के जवानों के आश्रितों एवं निर्धन छात्रों के लिए भी छात्रवृत्तियों एवं पुस्तकीय सहायता की व्यवस्था की गयी ।
- मनोवैज्ञानिक सेवाएँ—राष्ट्र के मवनिर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और क्षमता का सङ्ग्रहण हो सके तथा उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थान पर पहुँच सके, इस दृष्टि से इस प्रदेश द्वारा नैतृत्व ग्रहण कर भारत में सर्वप्रथम बालकों के शिक्षक और व्यवसायिक निर्देशन की व्यवस्था के लिए राज्य मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद की स्थापना वर्ष १९४७ में की गयी है । इसके तत्वावधान में वर्ष १९७२ से 'कैरियर मास्टर' का प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है ।
- छात्र कल्याण अधिष्ठाता—छात्र-सेवायोजन व्यूरो—विश्वविद्यालय-स्तर पर छात्रों की निजी एवं व्यावसायिक समस्याओं से समाधान हेतु 'छात्र-कल्याण-अधिष्ठाता' (डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेल्फेयर) नियुक्त किये गये तथा 'छात्र-सेवायोजन व्यूरो' स्थापित किये गये ।

शिक्षक : संख्यात्मक वृद्धि

राष्ट्र के भावी कर्जधार छात्रों के निर्माण का दायित्व मुख्यतः शिक्षकों पर है । वस्तुतः वे ही राष्ट्र के निर्माता हैं । अतः समाज में उन्हें पुनर्प्रतिष्ठित करने की योजनाएँ बनाने की गयी, छात्रों की निरन्तर वृद्धि की ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार उनकी संख्या में वृद्धि की गयी तथा उन्हें व्यावसायिक दक्षता प्रदान करने की सुविधाएँ प्रदान की गयीं । इन दिशाओं में किये गये उत्त्सेखनोद्य प्रयास इस प्रकार हैं :

- जहाँ स्वतंत्रता-प्राप्ति के आरम्भिक काल में जूनियर बेसिक स्तर के शिक्षकों की संख्या ७०,२९९ थी, वर्ष १९७१-७२ में यह २,२७,९७३ हो गयी, जिनमें ८६ प्रतिशत प्रशिक्षित हैं ।
- इसी अवधि में सीनियर बेसिक स्तर पर शिक्षकों की संख्या २३,७८७ से बढ़ कर ६३,३७८ हो गयी, जिनमें ७५ प्रतिशत प्रशिक्षित हैं ।

- माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की संख्या ८,९४५ से बढ़कर ४८,७०० हो गयी, जिनमें ७५ प्रतिशत प्रशिक्षित हैं।
- उच्च शिक्षास्तर पर अध्यापकों की संख्या १,३४३ से बढ़कर लगभग १२,००० हो गयी।

प्रशिक्षण-संस्थाओं की संख्या में वृद्धि

- स्वतन्त्रोत्तर काल में ही सर्वप्रथम एक राजकीय शिशु-प्रशिक्षण महा-विद्यालय की इलाहाबाद में स्थापना हुई और इस समय दो राजकीय तथा तीन मान्यता-प्राप्त शिशु-प्रशिक्षण महाविद्यालय चल रहे हैं।
- वर्ष १९४६-४७ में प्रारम्भिक स्तर (कक्षा १-५) के लिए अध्यापक-प्रशिक्षण की संस्थाएँ ८० तथा माध्यमिक स्तर के लिए ११ थीं। वर्ष १९७१-७२ में इनकी संख्या क्रमशः २६३ और ६६ हो गयी।

प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम तथा शोध

- स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् महारमा गांधी द्वारा प्रतिपादित वैसिक शिक्षा-पद्धति प्रारम्भिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के रूप में अपनायी गयी, जिससे कि शिक्षा जीवन से सम्बन्ध हो सके और नये राष्ट्र के अनुरूप नये नागरिकों का निर्माण हो सके। इस शिक्षा-पद्धति के कार्यान्वयन के लिए अध्यापक-प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को शिल्प-केन्द्रित कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता-काल में ही स्थापित राजकीय वैसिक प्रशिक्षण महा-विद्यालय में प्रशिक्षकों एवं निरीक्षकों को तैयार करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये।
- प्रारम्भिक स्तरीय एच० टी० सी० तथा जे० टी० सी० के प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का एकीकरण करके शिल्प-केन्द्रित बी० टी० सी० प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी तथा प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल निर्धारित कर दी गयी।
- अप्रशिक्षित अध्यापकों की दीक्षा के लिए सबल प्रशिक्षण दल, सेवारत प्रशिक्षण तथा पत्राचार-प्रशिक्षण योजनाएँ चलायी गयीं। प्रसार-अध्यापक की दीक्षा के लिए 'प्रसार-अध्यापक प्रशिक्षण-केन्द्र' स्थापित किये गये। इण्टरमीडिएट-स्तर पर विज्ञान शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए विश्वविद्यालयों में एक वर्ष के स्नातकोत्तरीय 'कम्प्लेन्स कोर्स' चलाये गये।
- माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाया गया। उसमें मनोवैज्ञानिक शिक्षण विचारधाराओं तथा शिक्षण तकनीकों का समावेश किया

गया। माध्यमिक स्तर तक वर्गीकृत पाठ्यचर्या के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजकीय गृह विज्ञान, महिला महाविद्यालय तथा शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की गयी।

- प्रशिक्षण संस्थाओं एवं विद्यालयों में पारस्परिक सम्पर्क स्थापित करने तथा शिक्षकों को नवीनतम ज्ञान से अवगत कराते रहने के लिए प्रमुख प्रशिक्षण-संस्थाओं में विस्तार सेवा केन्द्रों अथवा विस्तार सेवा-इकाइयों का गठन किया गया।
- पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, शिक्षण-विधि एवं तकनीक, मूल्यांकन एवं अनुचारात्मक शिक्षण, प्रशासन एवं परिवीक्षण आदि शैक्षिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा शोध-कार्य के लिए वर्ष १९४८ में राजकीय सेंट्रल पेडागॉजिकल इन्स्टीट्यूट तथा प्रारम्भिक स्तरीय शैक्षिक पाठ्यचर्या एवं प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं पर शोध-कार्य तथा प्रारम्भिक शिक्षा के निरीक्षक वर्ग के मार्गदर्शन हेतु राज्य शिक्षा संस्थान (१९६४) की स्थापना स्वातन्त्र्योत्तर काल की प्रमुख उपसम्पत्तियाँ हैं।
- अग्रजी, विज्ञान तथा हिन्दी के प्रशिक्षण अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अग्रजी भाषा शिक्षण-संस्थान (१९५६), राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान (१९६५), इलाहाबाद तथा हिन्दी संस्थान (१९६९), वाराणसी की स्थापना की गयी।
- ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रमों (समर कोर्स) के माध्यम से माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के अध्यापकों को नवीनतम विषय ज्ञान प्रदान किया गया।
- उच्चतर योग्यता प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहन-पुरस्कार देने की नीति अपनायी गयी।

शिक्षक-कल्याण

- स्वातन्त्र्योत्तर काल में सभी स्तरों के सहायता-प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की निरन्तर वेतन वृद्धि करके राजकीय संस्थाओं के शिक्षकों के प्रायः समाव वेतनक्रम एवं महंगाई भत्ता प्रदान करने के लिए साहसिक कदम उठाये गये तथा वेतन-भुगतान का महत्वपूर्ण दायित्व भी शासन द्वारा ग्रहण किया गया।

लाभप्रयी योजना

- सहायता-प्राप्त समस्त शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों के लिए अश्वदायी-भविष्य निधि, अनिवार्य बीमा तथा पेंशन की लाभप्रयी योजना चलायी

गयी। इसके अतिरिक्त सेवा-काल में शिक्षक के आकस्मिक निधन पर प्रेच्युटी देने का प्राविधान किया गया।

- समाज में शिक्षक का सम्मान तथा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए 'शिक्षक-दिवस' समारोह आरम्भ किये गये और 'राज्य पुरस्कार' तथा 'राष्ट्रीय पुरस्कार' की योजनाएँ चालू की गयी।
- राष्ट्रीय अध्यापक-वल्याण-प्रतिष्ठान की योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६४ से सकट ग्रस्त तथा दिवंगत अध्यापकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गयी। अब तक लगभग १,००० अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

शिक्षा-सस्याओं की सख्या में वृद्धि

हमारे विद्यालय ही राष्ट्र के भावी कर्णधारों के निर्माण-केन्द्र हैं। अतएव उन कर्णधारों का स्वस्थ अ्यवित्तव निर्मित करने के लिए इनकी सम्यक् व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप इन विद्यालयों की सख्या में वृद्धि तथा वह विविध प्रकार की आवश्यक साज-सज्जा से युक्त करने की दिशा में राज्य द्वारा स्वातन्त्र्योत्तर काल में विशेष ध्यान दिया गया। जिसके फलस्वरूप

- शिशु विद्यालयों की सख्या ६ से बढ़कर २४५ हो गयी है।
- जूनियर वैसिक विद्यालयों की सख्या २०,०४८ से बढ़कर ६२,२९८ हो गयी है।
- सीनियर वैसिक विद्यालयों की सख्या १,८५० से बढ़कर ९,०२४ हो गयी है तथा इसके अतिरिक्त १,३५० अमीत्तर कक्षाएँ भी चल रही हैं।
- उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सख्या ५०६ से बढ़कर ३,६३३ हो गयी है।
- महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की सख्या क्रमशः १६ तथा ५ से बढ़कर २८२ तथा ११ हो गयी है।
- स्वातन्त्र्योत्तर काल में विद्यालयों के लिए नये भवनों के निर्माण, पुराने भवनों के सुधार तथा वह वर्णित साज सज्जा से युक्त करने के लिए अथिकाधिक अनुदान की व्यवस्था की गयी।
- प्रारम्भिक विद्यालयों के भवनों के अभाव की पूर्ति की दिशा में कम लागत वाले पूर्व-निर्मित (प्री फैब्रिकेटेड) भवनों की योजना विशेष रूप से उत्प्रेरणीय है।

- पुस्तकालयो, प्रयोगशालाओं एवं क्रीडास्थलों के विकास के लिए विशेष अनुदान दिये गये ।

- उत्तम विद्यालयों को दक्षता-अनुदान देने की नीति अपनायी गयी ।

पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम

भारतीय संविधान में हमने स्वतन्त्रता, समता, बन्धुता तथा न्याय के षादशों को अंगीकार किया है । इन षादशों के अनुरूप हम एक नये भारतीय समाज की संरचना की ओर उन्मुख हैं । स्वातन्त्र्योत्तर काल में उस नवीन समाज के लिए बालकों का नवनिर्माण हमारी पाठ्यचर्या का प्रमुख लक्ष्य रहा है । इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में परिवर्तन, पाठ्यपुस्तकों एवं निर्देश पुस्तिकाओं की रचना तथा पाठ-सहगामी क्रियाओं में वृद्धि के लिए इस अवधि में विशेष प्रयास किये गये ।

नये राष्ट्र की नयी आकाशवाणी के अनुरूप प्रदेय की शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के अन्तर्गत

- महात्मा गांधी की वैश्विक शिक्षा-योजना के अनुरूप प्रारम्भिक शिक्षा को शिल्प-कै-द्रित कर उसे प्रत्यक्ष जीवन से सम्बद्ध किया गया, जिससे कि धर्म के प्रति निष्ठावान, आत्मनिर्भर, योग्य, समाज के लिए उपयोगी एवं सन्तुलित ब्यक्तिरव वाले बालक का निर्माण हो सके ।
- आचार्य नरेन्द्र देव समिति की संस्तुतियों के आधार पर वर्तमान एवं ऐंग्खी वर्तमान शिक्षा का भेद समाप्त कर दिया गया ।

बहुद्देशीय शिक्षा

- प्रारम्भिक स्तर पर आरम्भ की गयी सामान्य शिक्षा की पूर्ति तथा उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए तैयारी के रूप में माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या को साठ बर्गों—साहित्यिक, वैज्ञानिक, रचनात्मक, ललित कला, वाणिज्य, कृषि तथा उत्तर वैश्विक—में विभाजित किया गया, जिससे प्रत्येक छात्र एवं छात्रा की अपनी रुचि तथा योग्यता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा प्राप्त हो सके । हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट स्तर पर प्राविधिक पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की गयी ।

विज्ञान-शिक्षा

- आधुनिक युग में विज्ञान के महत्त्व को देखते हुए प्रारम्भिक स्तर पर विज्ञान के पाठ्यक्रम को गहन बनाया गया तथा माध्यमिक स्तर पर विज्ञान एवं गणित के पाठ्यक्रमों को अग्रतन तथा उच्चस्तरीय बनाया गया ।

- अनेकता में एकता भारत की प्रमुख विशेषता रही है। इसी राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को सबल, सुदृढ़ और अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए निभापा सूत्र के अन्तर्गत दक्षिणी एवं अन्य प्रादेशिक भाषाओं की शिक्षण का प्राविधान किया गया।
- उत्तर दक्षिण को भावात्मक स्तर पर और अधिक निकट लाने के लिए प्रदेश के ग्यारह जिलों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम भाषाओं के शिक्षण की सायकलीन कक्षाएँ चलायी जा रही हैं। इनकी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रथम वर्ष के अन्त में ₹० २०० तथा द्वितीय वर्ष के अन्त में ₹० २५० का पुरस्कार दिया जाता है और दक्षिण भारत में भ्रमण-अध्ययन के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
- सीनियर बैसिक स्तर पर सामाजिक विषय के अन्तर्गत नागरिक शास्त्र तथा भारतीय संविधान का समावेश कर उनका अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया और माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय भावना के अनुरूप ब्रिटेन के इतिहास को हटाकर राष्ट्रीय इतिहास का अध्ययन निर्धारित किया गया।

राष्ट्रभाषा हिन्दी

- सम्पूर्ण विद्यालयीय शिक्षा (कक्षा १ से १२ तक) में हिन्दी को अनिवार्य विषय बना दिया गया। हिन्दी के ज्ञान को पुष्ट करने के लिए उसके साथ संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य किया गया। उच्च शिक्षा के स्तर पर अध्ययन, अध्यापन एवं परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को भाष्यता प्रदान की गयी। अंग्रेजी का अध्ययन माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में ऐच्छिक कर दिया गया।
- विद्यालयीय एवं शिक्षक-प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम के समस्त क्षेत्रों में शोध-कार्य के लिए राजकीय सेंट्रल पेडागॉजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद में पाठ्यचर्या इकाई की स्थापना की गयी।

पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

- स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और आदर्शों के अनुरूप पठन सामग्री प्रदान करने की दृष्टि से सीनियर बैसिक स्तर तक की पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति अपनायी गयी और बालकों को उचित मूल्य पर अच्छी से अच्छी पाठ्यपुस्तकों उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी। अब तक ४९ पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, जिनकी लगभग डेढ़ करोड़ प्रतियाँ हिन्दी तथा उर्दू दोनों माध्यमों में प्रतिवर्ष प्रकाशित करायी जाती हैं।

- जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्तर के शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु लगभग ३,४०० पृष्ठों की १,४०० से अधिक चित्रों से युक्त ६ खण्डों में निर्देश-पुस्तिकाएँ प्रकाशित की गयीं।

हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

- उच्च शिक्षा में हिन्दी के माध्यम से अध्यापन की सुविधा हेतु हिन्दी में पाठ्यपुस्तकों की रचना एवं अनुवाद बनाने के लिए हिन्दी ग्रन्थ अकादमी स्थापित की गयी तथा प्रकाशन के लिए विश्वविद्यालयों को अनुदान भी दिया गया।

पाठ-सहगामी क्रियाएँ

- बालकों के बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास की दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर विद्यालयों में खेल-कूद, युवक समारोह तथा राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता-अभियान चलाये गये।
- वर्ष १९५५ में उत्तर प्रदेश खेल-कूद परिषद की स्थापना की गयी और तब से खेल कूद सम्बन्धी अनेक निर्माण कार्य पूरे किये गये, जिनमें एक बहुदेशीय क्रीडागण, एक ओलम्पिक-आकार का सैरने योग्य तालाब और एक केंद्रीय क्रीडागण तथा १ सत्रोय क्रीडागणों का निर्माण सम्मिलित है।
- सुरक्षा एवं अनुशासन की भावना जागृत करने के लिए प्रदेशीय शिक्षा दल ए० सी० सी० तथा एन० सी० सी० की योजनाएँ चलायी गयीं।
- छात्रों के बहुमुखी विकास की दृष्टि से साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर अधिकारधिक बल दिया गया। इसके अन्तर्गत राज्य-स्तरीय सम्पूर्णनिर्देशवाद-विवाद प्रतियोगिता निबन्ध-प्रतियोगिता विज्ञान क्लब, मेर्बों और प्रदर्शनियों का आयोजन आरम्भ किया गया।

मूल्यांकन

- हाईस्कूल स्तर तक की परीक्षाओं में प्रायोगिक परीक्षा तथा प्रश्न-पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया जा रहा है।
- इण्टरमीडिएट (कृषि) तथा उच्च शिक्षा की परीक्षाओं में द्विबाषिक परीक्षा के स्थान पर सार्वजनिक, वार्षिक एवं सत्रोय (सेमेस्टर) परीक्षाएँ आरम्भ की गयी हैं।
- जूनियर हाईस्कूल परीक्षा का जिला-स्तर पर विकेंद्रीकरण किया गया।
- माध्यमिक शिक्षा परिषद के विकेंद्रीकरण की दिशा में आवश्यक कदम उठाये गये तथा मेरठ में इसकी एक शाखा स्थापित की गयी।

हमारी प्राच्य भाषाएँ

हमारी प्राच्य भाषाएँ—संस्कृत, अरबी और फारसी—हमारी बहुमूल्य सांस्कृतिक निधियाँ हैं। इनकी शिक्षा और इनका विकास हमारी समन्वयारम्भ संस्कृति का पोषण और संरक्षण है। अतएव इनकी समृद्धि की दिशा में भी हमारा राज्य विरन्तर जागरूक रहा है।

संस्कृत-शिक्षा

- संस्कृत शिक्षा को सुविधानित करने के ध्येय से वाराणसीय संस्कृत विश्व-विद्यालय की स्थापना की गयी। इस विश्वविद्यालय से ५७५ माध्यम-स्तरीय विद्यालय तथा ३२५ पास्त्री, आचार्य-स्तरीय महाविद्यालय सम्बद्ध हैं।
- इन संस्थाओं में लगभग ६०,००० विद्यार्थी और ५,००० शिक्षक हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रति वर्ष लगभग १२,००० छात्र प्रविष्ट होते हैं।
- प्रथम श्रेणी के ४३ तथा द्वितीय श्रेणी के ५८ संस्कृत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के लिए आकर्षक वेतनक्रम निर्धारित किये गये।
- संस्कृत बाह्य मय के प्रचार, प्रसार एवं अनुसन्धान हेतु विशिष्ट विद्वानों को आर्थिक, प्रसार सहायता देने की नीति अपवायी गयी।
- संस्कृत की शिक्षा संस्थाओं को राज्य द्वारा दी जानेवाली सहायता वर्ष १९५०-५१ में रु० २ ५३ लाख से बढ़कर वर्ष १९७०-७१ में रु० ३५ ७३ लाख हो गयी।

अरबी फारसी शिक्षा

- वर्ष १९७७ में अरबी फारसी की शिक्षा के मदरसों की संख्या ६९ थी जो इस समय बढ़कर १३७ हो गयी है।
- इनके विद्यापियों की संख्या, जो १९५५ ५६ में १४, १९० थी, बढ़कर २९,५७८ हो गयी है।
- इस शिक्षा के लिए अनुदान की धनराशि वर्ष १९४७ में रु० ६६,०५३ थी। यह धनराशि इस समय बढ़कर रु० ३,७५,५८५ हो गयी है।

हमारी अल्पसंख्यक भाषाएँ

अल्पसंख्यकों की भाषा एवं साहित्य का हमारे राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। संविधान में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था

लिए निर्देश है। हमारा शासन इस ओर सजग है। इस दृष्टि से अल्पसंख्यकों की भाषाओं के संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास के लिए शासन द्वारा कई प्रभावी कदम उठाये गये।

उर्दू भाषा और साहित्य

- उर्दू माध्यमवाले विद्यालयों, मकतबों और मदरसों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों के प्राइमरी स्कूलों में कक्षा में १० या पूरे विद्यालय में ४० छात्रों की मातृभाषा उर्दू होने पर उनको उर्दू माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गयी।
- जूनियर हाई स्कूलों तथा हाई स्कूल कक्षाओं में शिक्षा के सम्बन्ध में शासन द्वारा यह नीति अपनायी गयी कि यदि एक तिहाई छात्रों की मातृभाषा उर्दू हो तो वे पूरी शिक्षा उर्दू माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
- कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, ससनऊ, बरेली, रामपुर तथा मुरादाबाद के नगरों में जूनियर हाई स्कूल तक के विद्यालयों में यह व्यवस्था की गयी कि यदि हर विद्यालय में उर्दू माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था सम्भव न हो तो कुछ स्कूलों का समूह बनाकर उनमें से एक विद्यालय को केन्द्र मानकर उर्दू माध्यम विद्यालय घोषित किया जाय।
- स्थानीय निकायों की माँग पर अलग से उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था है।
- उर्दू अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए स्थानीय निकायों के सेवारत अध्यापकों के लिए उर्दू अध्यापक दक्षता-प्रमाण-पत्र परीक्षा आयोजित की गयी।
- जूनियर बैसिक स्तर तक उर्दू माध्यम से पढ़नेवाले बालकों के लिए पाठ्यपुस्तकें उर्दू भाषा में उपलब्ध करायी गयी तथा उसी शृङ्खला में सीनियर बैसिक स्तर के लिए भी उर्दू माध्यमवाले छात्रों के लिए विविध विषयों में राष्ट्रीयकृत एवं स्वीकृत पाठ्यपुस्तकें उर्दू में उपलब्ध करायी गयी।
- उर्दू शिक्षा की समुचित देख-रेख एवं उर्दू शिक्षा को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद में उप-शिक्षा निदेशक (उर्दू माध्यम) की नियुक्ति की गयी।
- उर्दू शिक्षा-व्यवस्था की देख-रेख, उसके साहित्य के निर्माण, पुस्तकालयों को अनुदान तथा उर्दू लेखकों को सहायता देने के कार्य के लिए 'उर्दू एकेडेमी' की १९७१ ई० में ससनऊ में स्थापना की गयी।

- अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देनेवाले आंग्ल-भारतीय विद्यालयों की संख्या स्वतंत्रता से पूर्व ३० थी, इनकी संख्या इस समय ५५ है।

आंग्ल-भारतीय शिक्षा

- इन शिक्षा संस्थाओं के कार्यक्रम में राष्ट्रीय भावनाओं के अनुरूप हिन्दी, संस्कृत तथा भारतीय इतिहास की शिक्षा सम्मिलित की गयी। इनमें से कुछ विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा मान्यता-प्राप्त हैं तथा कुछ विद्यालयों की परीक्षा केवल ऑब इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नयी दिल्ली द्वारा संचालित की जाती है।
- शासन द्वारा इन संस्थाओं को आवर्तक अनुदान भी दिया जाता है।

प्राविधिक शिक्षा

आज का युग विज्ञान और टेक्नालॉजी का युग है। इन दोनों का बड़ी द्रुतगति से विकास हो रहा है। जननायक स्व० प० जवाहर लाल नेहरू ने स्वतंत्रता के प्रथम चरण से ही देश को उद्योग तथा व्यापार, कृषि तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में सुदृढ़ एवं स्वावलम्बी बनाने के लिए विज्ञान और टेक्नालॉजी के विकास पर विशेष जल दिया। उसी क्रम में हमारी राज्य सरकार द्वारा भी अपने प्रवेश की प्राविधिक शिक्षा के विकास की ओर अनेकानेक कदम उठाये गये।

- प्राविधिक व्यक्तियों के अत्यधिक अभाव की पूर्ति हेतु तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उपयुक्त अहर्ताओंवाले एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पूर्ति के निमित्त प्रचलित संस्थाओं का विस्तार, विकास एवं पुनर्गठन किया गया तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नवीन संस्थाएँ खोली गयी।
- वर्ष १९४७ में डिप्लोमा स्तर की ११ संस्थाओं की संख्या बढ़कर १९७२ में ४६ हो गयी तथा इनमें प्रवेश की क्षमता ६५५ से बढ़कर ६,९०० हो गयी।
- वर्ष १९४७ में इस स्तर पर केवल पाँच प्रकार के पाठ्यक्रम थे—सिविल, एलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, टेक्स्टाइल, आयन तथा फाइन आर्ट। नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप वर्ष १९७२ में इनकी संख्या २५ हो गयी।
- वर्ष १९४७ में डिग्री-स्तर की केवल दो अभियन्ता संस्थाएँ थी और उनकी प्रवेश-क्षमता मात्र १२८ थी। वर्ष १९७२ में उच्च संस्थाओं की संख्या ७ और प्रवेश क्षमता १,००० हो गयी।

- वर्ष १९४७ में इस स्तर पर २ स्नातक तथा ३ स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रम प्रचलित थे। अब स्नातक-स्तरीय १५ तथा स्नातकोत्तरीय ४१ प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में घोष-कार्य की भी सुविधा उपलब्ध है।

प्रा वधिक शिक्षा निदेशालय : प्राविधिक शिक्षा परिषद

- प्राविधिक संस्थाओं के प्रभावी संचालन के लिए एक पुष्क प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्थापित किया गया।
- राज्य सरकार को प्राविधिक शिक्षा के समन्वित विकास के बारे में परामर्श, परिषद से सम्बद्ध संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों की तैयार करने तथा परीक्षाएँ लेने मुख्य उद्देश्यों से 'प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश' का गठन किया गया।
- उद्योगों तथा तकनीकी संस्थाओं के मध्य घनिष्ट सम्पर्क स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक औद्योगिक सम्पर्क परिषद की स्थापना की गयी।
- स्वतंत्रता से पूर्व प्राविधिक शिक्षा का कोई पुष्क बजट-प्राविधान नहीं था, स्वातंत्र्योत्तर काल में इसकी समुचित व्यवस्था की गयी। वर्ष १९७१-७२ में इसका बजट-प्राविधान रुपये १,८२,९६६ लाख किया गया जिसके अन्तर्गत विदेशों में, प्रदेश के बाहर एवं प्रदेश के भीतर अध्ययन करने के लिए भ्रम-छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था की गयी।

शिक्षा-प्रसार विभाग

- प्रान्तीय स्वायत्तता-काल में ही प्रौढ-शिक्षा की महत्ता का अनुभव करते हुए राज्य सरकार द्वारा शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत प्रौढ शिक्षा की इकाई के रूप में शिक्षा-प्रसार विभाग की स्थापना की गयी। स्वातंत्र्योत्तर काल में इस विभाग की जन-शिक्षा के नवीनतम साधनों—फिल्मस्ट्रिप, रेडियो आदि—से सुसज्जित किया गया।
- प्रौढ़ों को साक्षर बनाने तथा कार्यपरक शिक्षा देने के लिए राजि-पाठशालाएँ, किसान-साक्षरता, योजना, सचल साक्षरता एवं सचल प्रदर्शनी दल और साक्षरता अभियानों के कार्यक्रम चलाये गये।

पुस्तकालय-सेवा

- प्रौढ़ों की साक्षरता को बनाये रखने तथा उनके ज्ञानवर्धन के लिए नव-साक्षरोपयोगी साहित्य का सृजन किया गया तथा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों

में प्रौढ़ पुस्तकालय एवं पाठशालाएँ बनाये गये जिनकी संख्या क्रमशः १,४०० और ३,६०० है। सचन पुस्तकालय सेवा भी उपलब्ध करायी गयी।

- उत्तरोत्तर बढ़ते हुए ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार के लिए राज्य-स्तर पर केन्द्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद तथा जिला-स्तर पर ९ सम्बद्ध पुस्तकालयों की स्थापना की गयी जिनमें इस समय लगभग १-१४ लाख पुस्तकें हैं।

चल-चित्र-केन्द्र तथा चलचित्रालय

- प्रौढ़ों में आधुनिकतम साधनों द्वारा शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से शिक्षा-प्रसार विभाग में एक चलचित्र-निर्माण इकाई तथा चलचित्रालय की स्थापना की गयी। इस केन्द्र द्वारा अब तक १४० शैक्षिक चलचित्र निर्मित किये जा चुके हैं। नव चिन्तालय में १,०९१ शैक्षिक फिल्मों, १,१०४ फिल्मस्ट्रिप्स तथा ४२२ स्लाइड संग्रहीत हैं।
- फिल्म, फिल्मस्ट्रिप तथा रेडियो जैसे आधुनिक उपादानों से युक्त सबल वाहनो द्वारा समाज शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था की गयी।

अव्य-दृश्य उपकरणों में प्रशिक्षण तथा व्य-दृश्य शिक्षा सघ

- शिक्षा में अव्य-दृश्य उपकरणों के प्रयोग के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा प्रसार विभाग, इलाहाबाद में अव्य दृश्य शिक्षा-सघ स्थापित किये गये।

हमारा विभागीय संगठन : लोकतन्त्रात्मक शैक्षिक प्रशासन

स्वतन्त्रता के पश्चात् नये राष्ट्र की नयी शैक्षिक आवश्यकताओं, आकी कामों और नये आदर्शों के अनुष्ण हमारे शैक्षिक प्रशासन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं परिवर्द्धन हुए। वहाँ एक ओर विभिन्न स्तर के विद्यालयों एवं शिक्षकों की बढ़ती हुई संख्या तथा उनसे सम्बन्धित बढ़ती हुई समस्याओं के कारण शैक्षिक अधिकारियों में वृद्धि हुई, विभाग का पुनर्गठन हुआ, वहाँ दूसरी ओर हमारे शैक्षिक अधिकारियों के द्वार जन-साधारण के लिए खुल गये और इस प्रकार, निरीक्षक और अध्यापक तथा अधिकारी और जनता के बीच का अंतर समाप्त हो गया। हमारे शैक्षिक अधिकारी समाज के सेवक हो गये।

प्रारम्भिक स्तर पर प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों तथा सहायक धालिका विद्यालय निरीक्षकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। आज इनकी संख्या १,२९७ है जो वर्ष १९४७ की संख्या की चार गुनी से भी अधिक है। आवश्यक-

वतानुसार अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षकों तथा उप विद्यालय निरीक्षिकाओं के पद सृजित किये गये ।

वैसिक शिक्षा परिषद की स्थापना

लोक की माँग के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा के सुधार, विकास एवं व्यापक प्रसार हेतु उसे साधन द्वारा अपने नियंत्रण में लेने का वर्ष १९७२ में एक अन्तिमकारी कदम उठाया गया तथा सभी जिलों में वैसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किये गये । इसके लिए वैसिक शिक्षा विधेयक पारित किया गया तथा वैसिक शिक्षा में नवजीवन का संचार कर उसे प्रगतिशील बनाने के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश वैसिक शिक्षा परिषद' की स्थापना की गयी ।

माध्यमिक स्तर पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रत्येक जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक नियुक्त किये गये तथा आवश्यकतानुसार सह जिला विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्तियाँ हुईं । इस स्तर पर विद्यालयों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं की शिक्षा की प्रभावी देख रेख के लिए कतिपय प्रमुख जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षिकाओं की नियुक्तियाँ भी की गयी ।

शैक्षिक प्रशासन की मुख्यवस्था के लिए प्रदेश को ग्यारह मण्डलों में विभक्त किया गया और मण्डलीय उप शिक्षा निदेशकों तथा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं की नियुक्तियाँ की गयी ।

निदेशालय का सुदृढीकरण

राज्य-स्तर पर शिक्षा निदेशालय का सुदृढीकरण किया गया । बालिकाओं की शिक्षा की देख रेख तथा विदेशन के लिए उप शिक्षा निदेशक (महिला) तथा समुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) की नियुक्तियाँ की गयी । नियोजन, शिक्षण प्रशिक्षण, उद्ग, सस्कृत तथा विज्ञान की शिक्षा के विकास और उसको व्यवस्था की देख रेख के लिए उप शिक्षा निदेशकों के लिए दो नये समुक्त शिक्षा निदेशकों के पद भी सृजित किये गये । प्रशासनिक कार्य के लिए एक अतिरिक्त शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की गयी ।

परन्तु प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में प्रतिदिन बढ़ते कार्यभार के समुचित सम्पादन एवं उसमें वांछित गुणामक सुधार लाने के लिए उपर्युक्त प्रशासनिक व्यवस्था ही पर्याप्त न थी । अतएव शिक्षा के प्रत्येक स्तर के कार्य की सम्मत् देख रेख के लिए कार्य-विभाजन की दृष्टि से राज्य के शिक्षा

निदेशालय का प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के रूप में पुनर्गठन किया गया । ये तीनों अंग अब तीन शिक्षा निदेशकों के निदेशन में कार्य करेंगे ।

बजट प्राविधान

स्वतन्त्र देश में शिक्षा के महत्त्व पर बल दिये जाने से फलस्वरूप उसके अनवरत प्रसार, गुणात्मक उन्नयन तथा बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक प्रशासन की समुचित व्यवस्था के कारण मौद्रिक बजट में प्राविद्यालयों में उत्तरोत्तर वृद्धि की गयी । फलतः यह प्राविधान जहाँ वर्ष १९४६-४७ में रु० ३१८ करोड़ तथा वर्ष १९५०-५१ में रु० ७३७ करोड़ (कुल राज्य-बजट का १४.१ प्रतिशत) था, वर्ष १९७१-७२ में बढ़कर रु० ९१.१७ करोड़ (कुल राज्य-बजट का १९.८ प्रतिशत) हो गया । प्रसिद्ध वर्ष के लिए आयोजन-नेतर रु० ९४.२८ करोड़ तथा आयोजनागत रु० १७.२३ करोड़ (कुल योग रु० १११.५१ करोड़) स्वीकृत है । राज्य की शिक्षा में प्रति बालक व्यय वर्ष १९५०-५१ में ११५ रुपये था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसके ९०८ रुपये तक पहुँच जाने की आशा है ।

प्रार्थना, राजकीय शैक्षिक वेबसाइट्स इन्स्टीट्यूट,
इलाहाबाद ।

चीन में शिक्षा के उद्देश्य और समस्याएँ

किसी भी साम्यवादी शासन में समाज को संगठित करने के लिए शिक्षण का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण-सिद्धान्त, विचार और उनकी सहायता से सोचने के ढंग में परिवर्तन करना साम्यवादी शासन के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि केवल बल प्रयोग या भय-प्रदर्शन किसी-न-किसी दिन घुरके-घुपके ही बयो न हो, लोगों के मन में शासन के प्रति वितृष्णा जगा देते हैं और कम-ज्यादा शक्ति के साथ स्थापित 'क्रांतिकारी राज्य' का हस्ता चलटने की तैयारियाँ होने लगती हैं। कम्युनिस्ट सत्ता इस तत्त्व को धोषित करते हुए हिचकिचाती भी नहीं है। चीन में भी १९४९ में ही यह कह दिया गया था, 'साम्यवादी, प्रजातान्त्रिक, डिक्टेटरशिप आदेश निर्देश और शिक्षण सबका समान रूप से प्रयोग करेगी' और ये शब्द भावों से तुङ्ग के हैं। आदेश और निर्देश के अन्तर्गत जिन्हें प्रतिक्रियावादी अथवा क्रान्ति-विरोधी व्यवहार जनता के शत्रु मान लिया जायेगा, उनकी सजाएँ देना तथा किसी भी रूप से दबाया या कुचलवाया जाता है। खदाने और कुचलने की बात क्रान्ति-समर्थक उन लोगों पर लागू नहीं की जाती जो इस घेरे से बाहर समझे जाते हैं और जो जनता के शत्रु न माने जाकर जनता के हाथों में गिने जाते हैं। उनके प्रति कम्युनिस्ट शासन का रुख यह होता है कि उन्हें विचार-प्रचार और शिक्षण के द्वारा उद्देश्य की आवश्यकता और सम्भावनाएँ समझायी जायें। 'जनता के शत्रुओं' को भी समझा-बुझाकर रास्ते पर लाने की कोशिश की जाती है। इसमें सन्देह नहीं है कि 'समझाना-बुझाना' कई बार जोर-जबरदस्ती का ही रूप है। फिर भी वे इस बात की कोशिश करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को सीधे-सीधे शारीरिक चोट न पहुँचायी जाय और जब तक शरीर पर सीधे आघात न करके अन्य उपायों का सहारा लिया जाता है, तब तक उसे साम्यवादी शासनकर्ता शिक्षण ही मानता है। साम्यवाद में विश्वास करनेवाली

जनता भी ऐसा ही मानती है कि जनता के शत्रुओं को नये समाज का सही सदस्य बनाने की दिशा में दण्ड शिक्षा का अंश है।

विचार के प्रति केवल चुप्पी साध लेना या सिर झुका कर आज्ञा मानकर चलते जाना साम्यवादी शासन में पर्याप्त नहीं माना जाता। शासन के ऐसे लोग सीधा-साधा विरोध करनेवालों के लिए अधिक खतरनाक होते हैं और इसलिए वे ऐसे लोगों पर अधिक निगाह रखते हैं और उनके बाहरी कामों से सन्तुष्ट न रहकर उनकी समस्त चिन्तन प्रक्रिया को पूरे अवधान के साथ बदलते रहने में लगे रहते हैं।

इस तरह यदि कारीकी से देखा जाय तो तर्क, बुद्धि और हृदय की बदलने की यह प्रक्रिया चीन में हर स्तर पर पायी जाती है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत पूँजी अथवा निजी उद्योग-धन्यों की समाप्ति, केवल आर्थिक बदल, पर्याप्त नहीं माने जाते। उसके साथ-साथ 'समाजवादी शिक्षण' चलाया जाता है और लोगों को पूँजीवाद के दोष और समाजवाद के गुण तरह-तरह से समझाये जाते हैं। व्यापारियों और उद्योगपतियों का आदेशों के सामने केवल आत्मसमर्पण कर देना ही काफी नहीं माना जाता। सन्द्भाववाद और लेनिनवाद का पाठशालाओं में जाकर अध्ययन करना पड़ता है और समाजवाद के सिद्धान्त हृदयस्थ कर लेने पड़ते हैं। इसे पुनर्शिक्षण कहा जाता है। जब तक कोई पुराना पढ़ा लिखा जादमी नयी समाज-व्यवस्था के गुणों के प्रति उत्साह में भर कर तदनुसार कहने और करने नहीं लगता, उसे दीक्षित करते ही रहते हैं।

इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि साम्यवादी समाज में शिक्षण का अर्थ केवल साक्षरता अथवा किसी कार्य में कुशलता प्राप्त कर लेना नहीं है। छोटे-छोटे काम करनेवाला भजवूर, सफ़ाया, गृहिणी या घर-गृहस्थी में उपरान्त बुद्धिया भी सिद्धान्तों को बिना समझे नये समाज के सही अंश और अंग नहीं माने जाते। पूँजीवादी समाज के तीर-तरीकों को जगह-जगह से निकालना है इसलिए खान-पान, पहनावा, यहाँ तक कि बाल काटने सेवारने के ढंग भी नयी शिक्षा में अंग हो जाते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण की भी कोई सुस्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती और न विचार-प्रचार और सर्व-सामान्य शिक्षा में कोई अन्तर किया जाता है। ठीक मुट्ठी बाँधकर पूरा हाथ उठाकर अधिक से-अधिक मुँह फाड़कर राजनीतिक नारे लगाना भी शिक्षण का एक अंग है। प्रतिक्रियावादी, किसी भी भूमिहर या पूँजीवादी पर कार्य-

जनिक धुकदमा चलाये जाने की परिस्थिति में लोगों का वहाँ इकट्ठा होकर उस सबको देखना और समझना भी उनके लिए सबक है। घर, खेत-खलिहान, सरकारी दफ्तर, कारखाने, खदानें, रगमच और इसी प्रकार की तमाम मनोरंजन स्थाएँ भी शिक्षण लेने या देने के साधन हैं। आप जहाँ जो काम कर रहे हों, वही अवकाश के घण्टों में काम को बिना कोई नुकसान पहुँचाये और यथासम्भव मनोरंजन और आराम की सुविधाएँ देकर भी समाजवादी शिक्षण चलता रहता है। शिक्षण के इस प्रकार सर्वव्यापी बना देने की मिसाल साम्यवादी राज्यों में भी कहीं उतनी उज्ज्वल नहीं है जितनी चीन में है। अवकाश में दिये जानेवाले शिक्षणों के अतिरिक्त ऐसी शालाएँ भी होती हैं जहाँ विद्यार्थी कुछ घण्टे काम में और कुछ घण्टे लिखने-पढ़ने में लगाते हैं। केवल लिखने-पढ़ने की शालाएँ तो बिरल ही हैं। पत्राचार और सिद्धान्त प्रचार वर्गों की भी यदि इसमें जोड़ लिया जाय तो कहा जा सकता है कि चीन की पूरी जनता के चौपायी भाग को किसी-न-किसी रूप में सतत शिक्षा दी जाती है।

शिक्षा के चीन में तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। एक, उससे राजनीतिक विचार को पोषण मिलना चाहिए, दो, वह उत्पादन से समुक्त रहे, तीन, उसका सचासन साम्यवादी दल के द्वारा हो। ये तीन सिद्धान्त अर्थात् त्रिसिपल पी पीज के नाम से उल्लिखित किये जाते हैं। पहली दृष्टि से मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी विचार-पद्धति की समझना सब प्रकार के शिक्षण का मूल आधार है। शिक्षण चाहे साक्षरता से सम्बद्ध हो, चाहे प्राथमिक शालाओं, माध्यमिक शालाओं, विश्वविद्यालयों अथवा उद्योग-वृत्तियों से सम्बन्धित हो, उक्त विचार-पद्धति का पढ़ना-लिखना तो उसमें शामिल है ही। विचार-पद्धति का किताबी ज्ञान आवश्यक तो है, किन्तु वह तब तक पर्याप्त नहीं माना जाता जब तक नये समाज का हर सदस्य उसके अनुसार राजनीतिक आचरण नहीं करता। कौन-सा आचरण राजनीतिक है और कौन-सा नहीं, इसे भी साम्यवादी शासन से बाहर के लोग एकाएक नहीं समझ सकते, जैसे साम्राज्यवाद के विरोध से निकाले गये जुनूस जितने राजनीतिक हैं, फसलों को नष्ट करनेवाले कोड़े मकोड़ों को समाप्त करनेवाले अभियान भी उतने ही राजनीतिक हैं। गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों को साम्राज्य विरोधी आन्दोलन से जोड़ने के पीछे जो दृष्टि थी, वही दृष्टि इस प्रकार के विचार के पीछे भी है—उसके सन्दर्भ अवश्य ही दूसरे हैं। और यह कौन नहीं जानता कि सन्दर्भों का अन्तर सब कुछ बदल देता है।

शिक्षा का दूसरा उद्देश्य नये चीन में यह है कि हरेक व्यक्ति कुशल से कुशलतर उत्पादक होता जाये। माओ त्से तुंग ने एक बार शिक्षा को दो भागों में बाँटा था। उन्होंने कहा था कि शिक्षण केवल दो चीजों के ज्ञान में सीमित किया जा सकता है। एक क्षेत्र है वर्ग-सघर्ष का ज्ञान, दूसरा क्षेत्र है अधिक उत्पादन-सघर्ष का ज्ञान। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि केवल इन दो प्रकारों का ज्ञान देनेवाले स्कूल ही न खोले जायें बल्कि इन दोनों को एक दूसरे में पिरो देनेवाली पद्धति भी अपनायी जाय, जिससे उत्पादन की समस्याओं को सर्वथा मान्य शाखाओं के वर्ग में भी समझा जा सके और सर्वसामान्य प्राप्त किये गये ज्ञान को उत्पादन बढ़ाने के काम में लाया जा सके। उत्पादक थम में भाग लेना शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का काम है। जो पूरे समय के स्कूलों में पढ़ते या पढ़ाते हैं उन्हें भी कुछ समय बचाकर खेतों, खलिहानों या कारखानों में काम करना पड़ती होता है।

शिक्षा की अन्तिम आवश्यकता यह बतायी गयी है कि उसे साम्यवादी दल के द्वारा परिचालित होना है। इसलिए चीन के हरेक स्कूल में दल का नेतृत्व होता है जो इस बात पर बड़ी निगाह रखता है कि जो कुछ हो रहा है, दलीय पद्धति के अनुसार हो रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि साम्यवादी योजना को लागू करनेवाले शिक्षण को नये समाज के गठन का सीधा-सादा साधन मानते हैं। जो लोग साम्यवादी पद्धति से सहमति रखते नहीं, वे शिक्षण के इस प्रकार के उद्योग पर आपत्ति कर सकते हैं। किन्तु इसे मानने में कोई बाधा नहीं है कि सचमुच ही शिक्षण समूचे जीवन में अद्भुत व्यापक और सन्तुलित रहना चाहिए। वास्तविक जीवन से दूर पढ़े हुए कोरे साहित्यिक या दार्शनिक या अन्य किसी भी प्रकार के शिक्षण का कोई अर्थ नहीं है। प्रजातंत्र भी अपनी योजनाओं की सफलता के लिए शिक्षण को आवश्यक मानता है। किन्तु अभी उसने उसकी सच्ची भूल महसूस नहीं की है। और, इसलिए समस्त प्रजातंत्रीय देशों में शिक्षण-पद्धतियाँ बम-ज्यादा यथापं जीवन से कटी हुई मिलती हैं।

यदि आँकड़ों के हिसाब से देखें तो साम्यवादी शासनकाल में चीन ने शिक्षा का जो प्रसार किया है, और केवल साक्षरता में भी जैसी वृद्धि करके दिखायी है वह मन पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। एक अमूलपूर्व पैमाने पर लगभग समूची आबादी की शिक्षण सुलभ हो गया है और हर स्तर पर शिक्षा प्राप्त करनेवालों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है।

शिक्षण के इस प्रसार के कारण कुछ समस्याएँ भी उत्पन्न हो गयी हैं और उनमें कुछ तो ऐसे हैं कि उनका हल प्रायः कठिन ही दिखायी देता है। इन समस्याओं का मूल साम्यवादी शिक्षण अथवा साम्यवादी समाज स्वभाव में निहित है। सभी जानते हैं 'वर्ग शिक्षण' का अर्थ तो साम्यवादी समाज के पहले के समाज के तौर-तरीकों के प्रति घृणा उत्पन्न करना और आज के तौर-तरीकों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना होता है। इसके लिए विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों को पहले अपनी शाला का इतिहास और अपने परिवारों का इतिहास बताया जाता है। शाला के इतिहास का अर्थ होता है वर्तमान शाला का पुरानी शालाओं से अन्तर बतावा। यह बताया जाता है कि पुरानी शालाएँ धनी और गरीब, ऊँची जाति और नीची जाति आदि के आधार पर भेदभाव बरतती थी और तदनुसार शिक्षा-व्यवस्था भी करती थी, जबकि साम्यवादी पाठशालाएँ सबको समान मानकर चलती हैं और समान रूप से देश के उपयोगी नागरिक बनाकर वर्गहीनता की दिशा में अग्रसर होती हैं।

इसी प्रकार परिवारों के इतिहास को पढ़ाते हुए पूँजीवादी रहन-सहन के प्रति घृणा और मजदूर तथा किसान वर्ग के प्रति प्रेम उत्पन्न किया जाता है। पूँजीवादी और मध्यमवर्गीय पद्धति के परिवारों के माता पिताओं के प्रति भी बच्चों में घृणा पैदा हो जाती है और इसी प्रकार बड़े-बड़े पूँजीपतियों और भूमिहरो के प्रति। कारखानों का इतिहास पढ़ाते भी समय इसी बात पर जोर दिया जाता है और इसमें शिक्षा के साधन होते हैं पुरानी व्यवस्था में काम कर चुकनेवाले मजदूर किसान, सैनिक और अन्य प्रकार के कमचारी। वे नये शिक्षार्थियों का अपने पुराने बटु अनुभव सुनाते हैं और पुरानी व्यवस्था के प्रति रोष तथा घृणा को भावना पैदा करते हैं।

शिक्षा के तत्वों में घृणा और क्रोध का इतना बड़ा स्थान देने की जरूरत वहाँ इसलिए पड़ी कि नये शासन को वर्ग चेतना तथा समाजवादी भावना को फैलाने के काम में बंदम बंदम पर बाधाओं का सामना करना पड़ा है। जो लोग शांतिपूर्वक विकास का नाम लेते हुए दिखायी देते थे वे सब वास्तव में समाजवाद के खपने को चूर करने में लगे हुए थे। नये शासकों को इस बात के प्रति पूरी तरह जागरूक रहना है कि घुसघोर मुनाफाखोर और अन्य दूसरे कारणों से जीने के इच्छुक लोग साम्यवादी शासन को अच्छे भले शब्दों की आड़ में हानि न पहुँचा पायें। इसीलिए शासन के लिए यह जरूरी हो गया कि पुराने जमाने के बचे हुए लोगों को पुनर्शिक्षित तथा नये जमाने में पैदा हुए और

नये लोगों को 'शिक्षित' किया जाय। चीन और रूस के मतभेदों ने एक नया भय पैदा कर दिया है और यह है सुधारवादियों का भय। रूस के सौर-यरीके क्रांतिकारी नहीं माने जाते हैं सुधारवादी माने जाते हैं। तो चीन के, और पूर्व तक चीन और रूस की दाँत काटो दोस्ती भी इसलिए चीन में ऐसे इतिहासकारों, दार्शनिकों, नाटककारों, उपन्यासकारों और अन्य बुद्धिवादियों के हर जगह होने की सम्भावना तो बनी हुई ही थी जो चीन की साम्यवादी पार्टी की पद्धति से किसी-न किसी अर्थ में क्रिन्तित हटे हुए हों। दल के सदस्यों पर भी इसलिए पूर्ण शिक्षित होने का भरोसा नहीं किया जा सकता और उनकी शिक्षा दीक्षा भी निरन्तर चलती रहती है। यांग सेन चेंग १९६४ तक एक जबरदस्त साम्यवादी नेता माना जाता था और अभी-अभी तक दल के बुद्धिजीवियों में उसका नाम बड़े आदर से लिया जाता था। वह मार्क्सवादी सिद्धान्तों का अधिकारी शिक्षक होने के नाते विचार के प्रचारकों में बहुत ऊँचा स्थान रखता था किन्तु अब उस पर सुधारवादी और मध्यमवर्गीय होने का आरोप लगाया गया है।

इन कारणों के सिवाय समस्या के तीव्र होने के अन्य और भी कारण हैं। जैसे एक कारण यह है कि समानता और सम्पन्नता दुनिया के अनेक देशों में साम्यवादी पद्धति को लागू किये बिना ही आती चली जा रही है। कोई भी सच्चा साम्यवादी उस समानता अथवा सम्पन्नता को स्वीकार नहीं कर सकता जो मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी विचारों से निम्न किसी पद्धति द्वारा आ सकती है या लायी जा सकती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि अन्य पद्धतियों के प्रति सहानुभूति से सोचनेवालों पर भी निगाह रखी जाय और उन्हें शिक्षित किया जाय। इसके अतिरिक्त यह सवाल भी है कि जो अभी शासनाखंड हैं उनकी जगह कौन लेगा। पुराने क्रांतिकारी बूढ़ हो रहे हैं नये लोगों की क्रांतिकाल में जो सघन करने पड़े उनका पता नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि वे पुरानी पद्धतियों के प्रति जरा भी मरम पट जायें और करा धरा चौपट हो जाय। इसलिए नये लोगों की पुराने सघन की याद दिलाते रहकर उन्हें पुराने प्रति विद्रोहवादी भी बनाये रखना है।

एक समस्या सख्या और गुण की भी सामने आती है। जो निरक्षर हैं उन्हें कम से कम समय में साक्षर बनाना है और साथ ही साथ कम से कम समय में इन सिद्धान्तों को उनके मन में उतार देना है। फिर कुशल कारीगर तैयार करने हैं ताकि पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी की जा सकें। राजनीतिक-शिक्षण, साहित्यिक

ययवा अन्य प्रकार के बौद्धिक शिक्षण से ठीक भेन नही साता । इसलिए देखा गया है कि चीन में साहित्य, कला आदि का पिछले कुछ दिनों में हास हुआ है । शिन लोगो की हम दिशा में रवि होती है वे भी मन में कही-न-कही यह सोचते रहते हैं कि हमें राजनीतिक दृष्टि से अधिक समर्थ दिखने के लिए अपनी कवियों पर बहुत जोर नही देना चाहिए । एक ओर बात भी सिद्धा है स्तर को गिरानेवालो है । किसानों और मजदूरों के कम योग्य बच्चे भी थोड़े बहुत शिक्षण के बाद आगे के पाठ्यक्रमों में भेज दिये जाते हैं ।

शामन को इन सब नुटियों का अनुमान है । उसने देख लिया है कि नय साधारों की वृद्धि भी बहुत अर्थ नही रखती, क्योंकि उन्हें जो कुछ सिखाया गया है, नाम के बीच जल्दी में सिखाया गया है और एसी उम्र में सिखाया गया है, जब एक बार सीखा हुआ सतनी ही जल्दी मुला भी दिया जाता है । इसी तरह जो पड़े-निले लोग वे उन्हें उत्पादन की जो शिक्षा दी गयी है, अधूरी सिद्ध हुई है । इसलिए अब यह कोशिश की जा रही है कि सक्ष्मा के साथ-साथ शिक्षा के स्तर को भी ऊँचा उठाया जाय । शिक्षकों को बताया जा रहा है कि राजनैतिक शिक्षण पर थोड़ा-बहुत कम जोर देकर अन्य अनिवार्य गुणों में भी वृद्धि की जानी चाहिए । प्रायः शिक्षण सम्बन्धी पद्धतियों में फेर-फार किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि सिद्धान्त और वस्तुस्थिति में सामंजस्य बैठाया जा सके । इसीलिए हम एक बार यह देखते हैं कि सांस्कृतिक क्रान्ति को उठासा जा रहा है तो दूसरी बार देखते हैं कि उसे दबाया जा रहा है । बहुत दिनों तक किताबी ज्ञान की दिस्तगी उढ़ायी जाती रही, फिर उसे बहुत हद तक आवश्यक भी मान लिया गया । साधारण तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी सक्ष्मा की गुण पर तटब्रीह देती है । विज्ञान का समाजवादी समाज में प्रमुख स्थान माना जाता है । किन्तु दल यह भी चाहता है कि वैज्ञानिक, तत्सम्बन्धी ज्ञान के आस-पास फँसे हुए प्रभा मण्डल का निराकरण करे और इस समझ को दूढ करे कि जनता, मजदूर और किसान भी इस लोह द्वार को तोढकर उसके अहाते में मनमाना विचरण कर सकें । इसीलिए उन किसानों को कीर्ति का गायन यह कहकर, जिन्होंने नये औत्रारो को समझा, किया गया कि यह हमारे सच्चे वैज्ञानिक हैं । किन्तु बाद में अन्य उत्पादन में भयकर कमी हुई तो इस विचार का प्रचार करनेवाले लोग थोके ओर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वैज्ञानिक फूँक मारते ही तैयार नही किये जा सकते । विचारो में 'नाल' होना कार्यकुशल और ज्ञानकुशल होने का पर्यायवाची नही हो सकता । इसलिए

अब यह कहा जा रहा है कि चीनी को 'लाल' भी होना चाहिए और फिर उसी अनुपात में कार्यकुशल भी। इन दोनों उद्देश्यों को एक साथ कैसे साधा जाय ? इस सवाल पर विचार करनेवाली पर्याप्त सामग्री साहित्य के रूप में इन दिनों सामने आ रही है। 'लाल' होने के सवाल पर तो कोई हरफ आ नहीं सकता, इसलिए उपाय इसी बात के खोजे जा रहे हैं कि विचार की दृढ़ता के साथ साथ कार्यकुशलता कैसे दी जाये।

साम्यवादी पद्धति को अपनाने के पहले चीन में विद्रोह का बड़ा सम्मान था, इसलिए आज भी विद्रोह के प्रति आकर्षण देश की नयी पीढ़ी से बिलीन नहीं हो गया है। विद्यार्थी शासकों में विभिन्न विषयों का ज्ञान लेने, उत्पादन-क्षम होने और राजनैतिक विचार को आत्मसात् कर लेने की दृष्टि से जाते हैं। किन्तु उनके मन में यह प्रश्न निरन्तर उठता रहता है कि यदि केवल उत्पादन-क्षम और राजनीतिक दृष्टि से अवशिष्ट बचना है तो सब लोगों को जपवा बहुत से लोगों को जप प्रकार का ज्ञान देने का प्रयत्न क्यों किया जाता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि व्यावहारिक दृष्टि से पर्याप्त पाठशालाओं का निर्माण सम्भव नहीं है, इसलिए कम पढ़े-लिखे होने का प्रशस्त कहा जाता है। किन्तु किताबी ज्ञान की व्याप्त सुझती नहीं। प्रायः पुस्तकालय के अंदर और बाहर भीड़ देखी जाती है। अध्ययन के लिए उरगुन लोगों को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिल पाती और कुर्सी खाली होने की प्रतीक्षा में वे दालानों में घूमने रहते हैं। विदेशी भाषाओं के ज्ञान की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। कई बार तो एक एक व्यक्ति तीब-तीव चार चार बाहरी भाषाएँ सीखने का प्रयत्न करते पाया जाता है। इतने बहुत से क्यों के बाद भी चीन के नये शिक्षण ने वहाँ के नये तहण समाज को रुचियों और इच्छाओं की दृष्टि से अभी तक पूरी तरह खेतिहर और मजदूर नहीं बनाया है। यह सब देखकर यह विचार बुझ हो जाता है कि शिक्षण क्यों कि मूलतः विचारों में सम्मिश्रित है, कठोर काम काजी सीने में नहीं ढाला जा सकता। जिस प्रकार चीन के बुद्धि-वादियों ने शासन पद्धति की समीक्षा करने की प्रवृत्ति कई बार दिखलाई है उसी प्रकार अब वहाँ के विद्यार्थी भी अपनी ज्ञान विप्लावा व्यक्त करने लगे हैं। देखना है कि बुद्धिवादियों के दमन की तरह उनका दमन भी किया जाता है या नहीं।

(रूप ऊपस द्वारा संपादित कमटेम्पोरेरी चाइना' से हर्षांतरित)

आचार्यकुल का सघन कार्य : अब तक के अनुभव

अक्तूबर, '७० में सर्व सेवा सभ के सेवाग्राम अधिवेशन में लिये गये निश्च-
मानुसार देश में कुछ सघन ग्रामस्वराज्य-क्षेत्र लेकर काम करने का जो कदम
उठाया गया, उसमें बिहार में मुसहरी, कपोती (इन दोनों ही जगहों पर
वास्तव में इस निश्चय से पहले से ही काम शुरू कर दिया गया था) और
सहरसा को लेकर काम आरम्भ किया गया। यह भी तथ्य हुआ कि इन क्षेत्रों
में सर्वोदय आन्दोलन के तीनों मुख्य काम शांतिसेना, आचार्यकुल और पुष्टि-
कार्य साय-साय चलाये जायें। इसके अनुसार ही केन्द्रीय समिति की ओर से
उसके सयोजक श्री बंशीधरजी ने समिति के सगठक श्री कामेश्वर प्रसाद
बहुगुणा को सहरसा के काम की जिम्मेदारी दी। श्री बहुगुणा यद्यपि बीच-
बीच में थोड़े समय के लिए इधर-उधर भी जाते-जाते रहे हैं किन्तु जनवरी '७१
से अभी तक का समय (बीच में अप्रैल '७२ से लेकर अक्तूबर '७२ तक तो
पूरे समय को छोड़कर) वे लगभग इन क्षेत्रों में ही देते रहे हैं।

इन क्षेत्रों में आचार्यकुल को मुख्यतः ग्रामस्वराज्य के प्रत्यक्ष कार्य (पुष्टि-
कार्य) के सन्दर्भ में काम करना था। इससे वहाँ आचार्यकुल के काम को
स्वभावतः ही एक निम्न परिप्रेक्ष्य मिला और वहाँ पर उसके काम का मूल्यांकन
इस परिप्रेक्ष्य में रहकर किया जाना उचित होगा।

इस परिप्रेक्ष्य में अनुसार यहाँ हमें आरम्भ में ही दो बातों को ध्यान में रखकर काम करना पड़ा। एक तो यह कि आचार्यकुल का विचार सारे क्षेत्र में फैले और उस आधार पर कुछ संगठनात्मक भूमिका बनाने का प्रयास किया जाय। दूसरे यह कि जो कुछ भी विचार फैले और संगठन का सके, वह आचार्यकुल के अन्य वैधानिक मामलों के अतिरिक्त ग्रामस्वराज्य और पुष्टि के प्रत्यक्ष काम में लगे।

जहाँ तक पहली बात का सम्बन्ध है इन दोनों आचार्यकुल का विचार खूब फैला है। श्री बहुगुणा ने सहरसा के सारे जिलों में स्वयं घूमकर जिले के सभी २३ प्रखण्डों में शिक्षा-गोष्ठियों का आयोजन किया। आचार्यकुल का विचार समझाया और प्रखण्ड स्तर पर आचार्यकुल के सदस्य संगठन बढ़े दिये। २३ II से १७ प्रखण्डों में ऐसी समितियाँ गठित की गयीं। ये समितियाँ शिक्षकों को आचार्यकुल का विचार समझाने और उस आधार पर जो लोग सदस्यता फार्म भरते थे ऐसे ही शिक्षकों को लेकर बनायी गयी और उनमें से ही प्रधानिकारी बना दिये गये। इस प्रकार से जिले में लगभग ७०० से भी अधिक लोगों ने आचार्यकुल की सदस्यता ग्रहण की और वे अलग-अलग प्रखण्डों में समितियों के रूप में संगठित हुए। इसी प्रकार की गोष्ठियाँ विरोल (दरभंगा जिला), कपोली और भवानोपुर (दोनों पूर्णिया जिला), और मुसहरी (मुजफ्फरपुर जिला) प्रखण्डों में भी की गयी। इन सभी में पुष्टि का सघन कार्य चल रहा है। इन सभी प्रखण्डों में भी ऐसी सदस्य समितियाँ बनायी गयी हैं। इस प्रकार से बहुत व्यापक स्तर पर विचार फैलाने का पहला कार्य सम्पन्न हुआ।

ये सभी समितियाँ अपनी-अपनी जगहों पर थोड़ा बहुत सक्रिय भी हैं। जैसे यह कि वे आपस में बैठकें करती हैं, पुराने अधिकारियों के बदल जाने पर नये अधिकारियों का चुनाव करती हैं, और स्थानीय स्तर पर पुष्टि के काम में मदद करती हैं।

प्रखण्ड स्तर पर समितियाँ बनाने के बाद उनके शिविर लिये गये। ऐसा एक बड़ा शिविर सहरसा जिले में मधेपुरा में आयोजित किया गया था जिसमें १७ में से ११ प्रखण्ड समितियों के अलावा काफी अन्य शिक्षक भी शामिल हुए थे। इसमें ही जिला आचार्यकुल का गठन किया गया। इस शिविर का सारा भार आचार्यकुल के सदस्यों ने स्वयं वहल किया और ३५ व्यक्तियों को पूरे तीन दिन तक ठहराने और भोजन कराने आदि का खर्च उठाया। मधेपुरा

में ही फिर तरुण शांतिसेना और आचार्यकुल का एक सह-जीवन शिविर भी लगाया गया जिसमें जिले भर के लगभग ४० विद्यालयों से ७८ छात्र और आचार्य शामिल हुए थे। यह शिविर भी तीन दिन का था और इसके लिए एक दिन का भोजन भी आचार्यकुल ने दिया। इसी प्रकार के शिविर और गोष्ठियाँ विरौन, रुपौली और भवानीपुर प्रखण्डों में भी की गयीं, जहाँ क्रमशः दो सौ, एक सौ पचास एक सौ १०० शिक्षकों ने भाग लिया। यह शिविर दो से पाँच दिन तक के हुए और इनका सारा व्यय स्थानीय आचार्यकुल ने वहन किया। पिछले साल से अखिल भारत शांति सेना मंडल ने शिक्षा में अति के लिए ९ अगस्त का दिन मनाना तय किया है। सहरसा के आचार्यकुल ने भी इस कार्यक्रम में पूरा भाग लिया और गत वर्ष तथा इस वर्ष दोनों ही साल सहरसा में छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर जैसा जुलूस निकाला, वैसा अगस्त नहीं नहीं निकला है। पिछले साल के प्रदर्शन में २३०० छात्र-शिक्षकों ने और इस साल के प्रदर्शन में १००० छात्र-शिक्षकों ने भाग लिया था। छात्रों ने आचार्यकुल के शिक्षक मार्गदर्शकों के नेतृत्व में विद्यालयों और गाँवों में मकानों की दीवारों पर नारे सुवचन आदि लिखने का भी बहुत अच्छा काम किया है और सहरसा में कोई भी किसी भी गाँव या विद्यालय में जाय तो उसे आज भी यह नारे लिखे मिलेंगे। सहरसा में आचार्यकुल और तरुण-शांतिसेना आरम्भ से ही मिलकर काम करते रहे हैं और यही कारण है कि जिले में इस तरह का वातावरण बन सका है। जिले भर में लगभग ४०० प्राथमिक विद्यालयों से आचार्यकुल का प्रवेश हुआ है और कुल ७२ तरुण-शांतिसेना की इकाइयाँ बनी हैं। हर स्थान पर, जहाँ भी तरुण-शांतिसेना की इकाई है, वहाँ विद्यालय का एक शिक्षक इकाई का मार्गदर्शक बनाया गया है। इससे छात्रों को काम करने में बहुत सुविधा होती है और यही कारण है कि सहरसा से काफी तरुण-शांतिसेना की संख्या ग्रहण की गयी है। शुक्ल भी भेजा है।

इन नामों के अलावा आचार्यकुल की स्थानीय विद्यालय या नगर इकाइयों ने आचार्यकुल के अन्य कार्यक्रमों में भी सक्रिय भाग लिया है। खासकर सहरसा नगर में गत नगरपालिका चुनाव में मतदाता प्रशिक्षण का अच्छा काम किया गया है। सभी हलों और उम्मीदवारों को संयुक्त बैठकें आमंत्रित की गयीं और लोग आये। अच्छे उम्मीदवार को ही वोट देने, दल बदल करनेवाले, शराब पीने और बेचनेवाले, जाति, पैसे या शस्त्र के बल पर वोट मांगनेवाले उम्मीदवारों को वोट न दिया जाय, शान्तिपूर्ण और पक्षपात रहित होकर ही

चोट दें, आदि बातों के साथ परचे भी छापकर बाँटे गये हैं। इसका सब पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। आचार्यकुल भी शिक्षा-नीति और कार्यक्रम का भी हवाइयों में प्रचार प्रसार किया गया है और कुछ स्थानों पर हवाइयो ने उस पर बहस भी की है।

इन कार्यक्रमों के अलावा इन क्षेत्रों में शिक्षा में क्रांति का नाम भी लिया जा रहा है। बिहार के विशेष संदर्भ को ध्यान में रखते हुए वहाँ इसे दो भागों में बाँटा गया है। बिहार के वर्तमान माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम को यदि देखा जाय तो उसमें सुनियामी शिक्षा के मूल तत्व काफी भज्युत हैं। किंतु आज उन पर अमल नहीं होता। अतः यह सोचा गया है कि उस पर अमल करने के लिए आवश्यक बातावरण बनाया जाय और उनके तमूने पर कुछ आदर्श विद्यालयों का चयन और क्रियाचयन किया जाय। शिक्षा में सुधार के इस कार्यक्रम पर रुपौली (पूर्विया) और मुसहरी (मुजफ्फरपुर) दोनों ही जगहों पर पहले काम आरम्भ हुआ है और अब सहरसा में भी काम आरम्भ हो गया है। मुसहरी में श्री जयप्रकाश नारायणजी के आदेश से गुजरात के वैडली विद्यापीठ के श्री ज्योति भाई देसाई के नेतृत्व में कुछ प्रायोगिक सिमिर सम्पन्न किये गये हैं और कुछ विद्यालयों को लेकर प्रायोगिक कार्य करने का निश्चय किया गया है। प्रसन्न भद्र से वे शिक्षकों को चुनकर पहले वैडली विद्यालय में कुछ अनुभव लेने के विचार से भी भेजा गया था। इन सारे कार्यों में वहाँ केन्द्रीय समिति के संयोजक श्री बशीरखी का विशेष योगदान रहा है और वे वहाँ के इन कामों में हर सम्भव मागदर्शन और मदद करते हैं। रुपौली में यह काम श्री वैद्यनाथबाबू, जो उस क्षेत्र में पुष्टि कार्य के लिए जमकर बैठे हैं, और बिहार के प्रख्यात सर्वोच्च सेवक हैं, कि देखरेख में चल रहा है। सहरसा में स्वयं श्री बह्मगुणा इस काम को देख रहे हैं और पूरे धीरे-धीरे भाई का मार्गदर्शन उन्हें मिल रहा है।

शिक्षा में सुधार के इस कार्यक्रम के मुख्यतः दो भाग हैं (१) यह कि कुछ ऐसे विद्यालयों का चयन हो जो बिहार के पाठ्यक्रम को पूरे और सही अर्थ में अपने यहाँ स्वेच्छा से लागू करने की परिस्थिति बनाये और जहाँ जो आवश्यक हो वहाँ शासन से भी मदद ली जाय। (२) दूसरे यह कि ऐसा करते समय शिक्षा में स्वायत्तता का भी प्रयोग हो। अतः इन विद्यालयों का संचालन शासन की सामान्य परम्परा से भिन्न तरह पर हो। वह शिक्षा—अभिभावक और जहाँ सम्भव हो वहाँ छात्र के साथ शासन के प्रतिनिधियों को

लेकर बड़ी स्वायत्त समितियों के माध्यम से हो। सहरसा में इस काम के लिए वहाँ के पुराने अनुभवों रिटायर्ड शिक्षा संचालक श्री सुखदेवजी ठाकुर का सहयोग प्राप्त हुआ है और जिला आचार्यकुल की शिक्षा-सुधार उर्ध्व-समिति जिला शिक्षा पदाधिकारी के संयोजकत्व में श्री ठाकुर के संचालन में काम कर रही है। मुसहरौ में श्री जयप्रकाश नारायणजी की सलाह पर बिहार सरकार ने एक प्रयोग के लिए कुछ विद्यालय चुनकर काम करने की स्वीकृति दी है जिसे प्रदेश के अन्य पाँच स्थानों पर भी चलाया जायगा।

शिक्षा में सुधार कार्यक्रम का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें शिक्षकों ने एक आचार्यसहिता का निर्माण किया है जिसे खासकर इन विद्यालयों में सभी शिक्षक स्वेच्छा से मान्य करेंगे। उसमें समय की पाबन्दी, विद्यार्थी के साथ और शिक्षण-कार्य में प्रामाणिकता, सादगी, पूर्ण व्यसन भुक्ति और समाज सेवा का कुछ प्रत्यक्ष दैनिक काम करने की बातों के साथ ही विद्यालय और पढाई के स्तर में सुधार के लिए सतत प्रयास करना भी शामिल है। इस प्रकार से शिक्षक के निजी और व्यावसायिक स्तर में सुधार होगा। यह इसका उद्देश्य है।

किन्तु इतने से ही आचार्यकुल के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाती। उसे तो शिक्षा में क्रांति ही दृष्ट है। अतः यह भी प्रयास है कि शिक्षा में कुछ स्थायी नये प्रयोग किये जाय। इस सन्दर्भ में प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने आचार्यकुल के लिए ग्राम-गुरुकुल का एक कार्यक्रम बताया है जिस पर सहरसा में विचार हो रहा है। और स्वयं धीरेन्द्र भाई के नेतृत्व में ऐसे शिक्षकों और विद्यालयों तथा ग्रामसमाजों की खोज की दृष्टि से उनकी भोड़गंगा-यात्रा में एक यह काम भी शामिल किया गया है। वे आज कन जिले के गाँवों का भ्रमण कर रहे हैं।

शिक्षा में क्रांति और सुधार के अलावा ग्रामस्वराज्य के काम में प्रत्यक्ष मदद का काम भी वहाँ आचार्यकुल ने उठाया है और खासकर सहरसा में तो उसने इसमें बुनियादी जिम्मेदारियाँ निभायी है। जिले में पिछले दो साल में तीन बार बड़े-बड़े अभियान चले हैं उनमें आचार्यकुल के लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। जगह-जगह टोलियों का स्वायत्त करने, उनके टिकने आदि की व्यवस्था करने से लेकर समार्ण करने, प्रघात-फेरियाँ निकालने और जुलूस निकालने आदि का काम किया गया है। गाँव-गाँव में साहित्य-

बिक्री के काम में भी आचार्यकुल का अल्पदा योगदान रहा है। और पहले दो मानों में त्रिले में हजारों रुपयों के सर्वोदय-साहित्य की बिक्री हुई है। अब वहाँ सर्वोदय मित्र और सहयोगी बनाने का नया कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। उसमें भी आचार्यकुल के सदस्य पूरा सहयोग कर रहे हैं और स्वयं मित्र और सहयोगी बन रहे हैं। ग्रामसभाएँ बनाने से, बीपा-मट्ठा बाँटने और माँगने से और ग्राम-कोष चालू करने में भी आचार्यकुल का योगदान हो रहा है। स्वयं कई शिक्षकों ने अपनी जमीनें बाँटी हैं और दूसरों से बँटवाने के लिए भी काम किया है। कई स्थानों पर स्वयं गाँव के शिक्षक ही ग्रामसभा के मंत्री या मार्गदर्शक हैं।

इस प्रकार से ग्रामस्वराज्य के सघन कार्यक्रम के अन्तर्गत सहरसा में आचार्यकुल का स्वतः एक त्रिविध कार्यक्रम विरचित हुआ है जिसमें हमने (१) आचार्यकुल-दीक्षा कार्यक्रम, (२) निता में क्रांति और (३) ग्रामस्वराज्य नाम दिया है। उपरोक्त विवरण से ज्ञात होया कि बिहार के इन पुष्टि क्षेत्रों में ये तीनों का कार्यक्रम हो रहे हैं।

किन्तु इस सन्दर्भ में कुछ ऐसे प्रश्न भी सामने आये हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि लोग सदस्यता शुल्क कम देते हैं। सहरसा में पिछले वर्ष कोई ३५ लोगों ने शुल्क दिया था। इस साल यह संख्या ५० के करीब आयी है। रुपयों की और मुसहुरी आदि में तो अभी तक लगभग नहीं के बराबर ही शुल्क दिया गया है। जो लोग आचार्यकुल के सभी कामों में भाग लेते हैं वे भी सब के सब शुल्क नहीं देते। हमारे विचार में इसका कारण यह हो सकता है

(१) शुल्क अधिक है। खासकर प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों ने हमसे कई बार कहा है कि वे इतनी रकम नहीं दे सकते हैं। फिर वे एक बार भी नहीं दे सकते। निश्चय में ही तो शायद दें।

(२) हम फालोअप का काम नहीं कर पाते। एक बार प्रत्यक्ष सम्पर्क होकर फिर सम्पर्क नहीं रह पाता और केवल कागजी (पत्र)-व्यवहार से ही हमारा सम्पर्क रह पाता है। हम लोगों में सुस्ती का जो राष्ट्रीय चरित्र है उस सन्दर्भ में सम्पर्क के अभाव से फिर शुल्क वसूलना काफी कठिन होता है।

(३) बिहार में शिक्षक सघ बहुत पत्रबद्ध है और शायद ही कोई शिक्षक हो जो उसका सदस्य न हो। वह उसे शुल्क देता है और ऐसी व्यवस्था बनी है कि वह उसके वेतन में से ही काट लिया जाता है हमारे पास ऐसी कोई

व्यवस्था नहीं है और यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या हमारे पास भी ऐसी कोई व्यवस्था हो और हम उसका सहारा लें।

भुलक का प्रश्न केवल बिहार का ही नहीं समूचे देश का है। सिमाय मध्य प्रदेश के और कहीं से कोई भुलक नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश तक से, जहाँ आचार्यकुल काफी पुराना, प्रभावी और सक्रिय भी है, भी लगभग कुछ नहीं आता। इस प्रश्न पर तटस्थ रूप से विचार किया जाना चाहिए। अभी तो आचार्यकुल सर्व सेवा सच के बत पर चल रहा है। किन्तु यह बत सदा ही प्राप्त नहीं होगा, न होना चाहिए। आचार्यकुल को अपने पैरों पर ही खड़ा होना होगा।

सचन क्षेत्रों (बिहार) के अन्दर में एक बात और भी आती है। वहाँ हमारा जोर ग्रामस्वराज्य पर है और वह शिक्षक को "भार" भालूम होता है। उसमें (आचार्यकुल) शामिल होने का अर्थ वे मानते हैं, और शायद सही ही मानते हैं कि, अपनी जमीन देनी होगी, ग्रामसभा के साथ काम करना होगा आदि। कपीली में जब एक बड़ी गोष्ठी में शिक्षकों से शिक्षा में स्वायत्तता के बारे में पूछा गया कि वे बतायें कि उन्हें अपने काम में किस प्रकार की कितनी स्वायत्तता चाहिए तो वे सब इस बात पर राजी थे कि उन्हें आज भी काफी स्वायत्तता प्राप्त है और वास्तव में उन्होंने स्वायत्त समितियों के गठन में अक्षि ही दिखाई। वे मानते हैं कि ग्रामसभा या अन्य तरह की समिति में माध्यम से बजाय इन्स्पेक्टर के माध्यम से काम करना कही आसान है। इस प्रश्न पर भी हम विचार करें। क्या अन्य क्षेत्रों में, जहाँ हम ग्राम-स्वराज्य पर जोर नहीं देते, भी यही अनुभव आता है ?

जहाँ तक बिहार के सचनक्षेत्रों का सवाल है, वहाँ आचार्यकुल की भूमिका बहुत काम की रही है और अपने उद्देश्यों में वह सफल रहा है। वह यहाँ पर अन्दोलनात्मक स्तर पर काम कर रहा है और हमारा विश्वास है कि इसी में से फिर संगठनात्मक रूप भी निखरेगा। अन्त के बजाय सम्भवत यह भूमिका हमारे लिए अधिक अनुभूत है।

(केन्द्रीय आचार्यकुल समिति, वाराणसी)

सम्पादक मण्डल :

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक
श्री बंशीधर श्रीवास्तव
आचार्य राममूर्ति

वर्ष : २१

अंक : ६

मूल्य : ७० पैसे

अनुक्रम

शिक्षा में आमूल परिवर्तन का प्रथम चरण १४२ सम्पादकीय
देश के प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों

■ बीब बिनोबा

२४६ विनोबा

सेवाग्राम में नयी तालीम का नया मोड़

२५५ स्वयंभू

उत्तर प्रदेश में शिक्षा के पचीस वर्ष

२५७ द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी

चीन में शिक्षा के उद्देश्य और समस्याएँ

२७१ विद्योदोद सिपन शान

आचार्यकुल का सचल कार्य :

अब तक के अनुभव

२८१

जमशेरी, '७३

- 'नयी तालीम' का वर्ष जगत् से प्रारम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्दा आठ रुपये है और एक अंक के ७० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त जट्ट, द्वारा सर्व सेवा संध के लिए प्रकाशित;
मनोहर प्रेस, जतनवर, वाराणसी में मुद्रित

नयी सालीम : जनवरी, '७३

पहिले से हाफ-अय्य दिवे बिना मेजने की स्वीकृति प्राप्त

साइसेंस नं० ४६

रजि० सं० एल० १७२३

सूतांजलि-संग्रह के लिए अपील

सारे देश में १२ फरवरी का दिन पूज्य गांधीजी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए 'सर्वोदय-दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह वर्ष खादी की स्वर्ण-जयन्ती और आजादी की राजत-जयन्ती का वर्ष है। इस निमित्त से हमलोग ग्रामस्वराज्य का सन्देश घर-घर और गाँव-गाँव पहुँचाएँ और अहिंसक क्रान्ति के लिए सूतांजलि के रूप में सम्मति प्राप्त करें।

'सर्वोदय दिवस' के अवसर पर अनेक स्थानों पर सर्वोदय मेले का आयोजन भी होता रहा है जो एक अच्छी परम्परा है। इसके साथ ही हमें अपने सेवा-केन्द्रों पर, खादी के उत्पादन और बिक्री-केन्द्रों पर, रचनात्मक संस्थाओं के मुख्यालय तथा सेवा केन्द्रों पर भी सर्वोदय-दिवस का आयोजन करना चाहिए तथा उस दिन सूतांजलि-संग्रह तथा सूतांजलि-समर्पण का विशेष आयोजन करना चाहिए।

आशा है, गाँधी-विचार में श्रद्धा रखनेवाले सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे।

—सिद्धराज ढड्डा

अध्यक्ष

सर्व-सेवा-संघ



वर्ष : २१

अंक : ७

- हिन्दुस्तान की सब भाषाओं के लिए नागरी लिपि
- सर्वोदय-शिक्षा-दर्शन
- ईसवी २००० में शिक्षा
- लोक भारती
- सामुदायिक विकास और शिक्षा

फरवरी १९७३

नयी तालीम और पुराना समाज

आमतौर पर जब नयी तालीम की चर्चा चलनी है तो लोग सहजता से कह देते हैं कि नयी तालीम फैल गयी। कुछ यह भी कहते हैं कि गांधीजी के जमाने की नयी तालीम में आज की परिस्थिति के अनुसार कुछ संशोधन जरूरी है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि सड़ी दिशा में नयी तालीम की शुरुआत ही नहीं हुई। गांधीजी ने नयी तालीम को समाज के मूल्य और मान्यताओं को बदलने के लिए संगठित करना चाहा था। वे चाहते थे कि देश में बुद्धि चीवी और भ्रमजीवी के नाम से वर्गीकरण न रहे। वे हर व्यक्ति को शिक्षित तथा वैज्ञानिक शरीर भ्रमिक के रूप में तैयार करके एक वर्गहीन समाज बनाना चाहते थे और चाहते थे, कि बुद्धि चीविका का नहीं, सेवा का साधन रहे और जीविका का साधन बुद्धिपूर्वक लिया गया शरीरभ्रम ही रहे। देश ने गांधीजी के इस सामाजिक सिद्धांत को स्वीकार न करते हुए बुनियादी शिक्षा चलाने का प्रयास किया।

वर्ष : २१

अंक : ७

वास्तव में समाज के पुराने मूल्यों तथा मान्यताओं को पृष्ठभूमि में नयी तालीम को चिपकाया नहीं जा सकता था। इसीलिए उसकी शुरुआत नहीं हो सक्ती थी। पुरानी तालीम में कुछ उद्योग जोड़ देने से वह नयी तालीम नहीं हो सकती है। नयी तालीम की शुरुआत नये समाज की कल्पना की बुनियाद पर ही की जा सकती है।

समाज की पुरानी बुनियाद पर चल रही पुरानी तालीम समाज और शिक्षा के क्षेत्र में सकट पैदा

कर रही है। इसके लिए शिक्षा में सुधार की बात कही जा रही है। लेकिन शिक्षा में जिन दोषों की बात की जाती है, वह शिक्षा-जगत की कोई अलग चीज नहीं है। वह आज की समाज व्यवस्था का अनिवार्य फलित मात्र है, इसीलिए उस मन्वन्ध में किसी प्रकार का सुधार अलग से किया नहीं जा सकता। सुधार की बात सम्पूर्ण सामाजिक भूमिका में ही सोची जा सकती है। —घोरेन्द्र मजूमदार

घूरेवाली विद्या ?

जब से बाबा ने यह बोलना शुरू किया है कि पढ़ना लिखना सीखा यह बाबा ने गलती की, तब से हमारे शिक्षित लोग सब घबड़ा गये हैं। इसमें समझने की बात यह है कि हम बीच में हैं मन के रूप में। मनुष्य के सामने सृष्टि गड़ी है, अन्दर परमात्मा है, दोनों के बीच मन है। जब मनुष्य पढ़ना-लिखना सीखता है, तब मन और सृष्टि के बीच पुस्तक खड़ी होती है। सामने सूर्योदय हो रहा है लेकिन वह सूर्योदय चित्र में ही देखना पसन्द करेगा।

चित्रे आह्लादिनी शोष्यमाने चित्रेन्दुमालोकयितुं क इच्छेत् ?

शकराचार्य पूछ रहे हैं, यागने चित्रोदय हो रहा है, वह छोड़कर चित्र में चित्रोदय देखने की इच्छा कौन करेगा ? लेकिन आजकल लोग फोटो में ही चित्रोदय देखना पसन्द करते हैं।

रामकृष्ण परमहंस की कहानी है। उनके पास बहुत विद्वान लोग आते थे। तो उन्होंने एकवार माँ भगवती से प्रार्थना की, कि हे माँ मुझे विद्या दे। रात को सपने में भगवती ने दर्शन दिया और पूछा, “तुमको क्या चाहिए ?” रामकृष्ण ने जवाब दिया, “मुझे विद्या चाहिए” तब माँ ने, सामने घूरा था, वह दिखाते हुए कहा, “वह विद्या है, ले लो, चाहे जितनी।” रामकृष्ण बोले, ‘घूरेवाली विद्या मुझे नहीं चाहिए। घूरा साफ करनेवाली विद्या चाहिए।’ ऐसी कहानी है। लिखने पढ़ने का भी एक फायदा है लेकिन वह गौण है मुख्य नहीं। (मैत्री फरवरी '७३ से सामार)

—विनोबा

रामचरित्र

बिहार में राजकीय बनाम अराजकीय माध्यमिक शिक्षक

नयी तालिम के दिसम्बर (१९७२ अंक में पृष्ठ १ से पृष्ठ ६ तक)
प्रकाशित डा० जयदेव के विचार 'बिहार के राजकीय बनाम अराजकीय
माध्यमिक शिक्षक' के सन्दर्भ में मेरे विचार निम्न हैं

भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास को नहीं दुहरा कर मैं इतना ही
कहना चाहता हूँ कि 'राजकीय एवं अराजकीय' अंग्रेजों के द्वारा 'फूट डालो एवं
शासन करो' की नीति की उपज है। प्रारम्भ से ही अंग्रेजों ने इस देश में ऊँच-
नीच, बड़े छोटे, सवर्ण अवर्ण, गरीब-अमीर, शासक शासित एवं शोषक शोषित
की दीवारें खड़ी की। राजकीय जिला स्कूल ऑफिसर एवं उच्च वर्ग के लिए
ही खुला था। साधारण नागरिक, जन-जीवन से तो उसको कोई मतलब नहीं
था। क्या अनतांत्रिक भारत में आजादी के पचीस वर्ष पूरे होने तक भी हम
उसी पद्धति एवं नीति से चर्नेंगे ? जब स्वतंत्र देश में सभी नागरिक समान
हैं, सबों को समान अवसर मिलना चाहिए। समान काम के लिए समान
सुविधा मिलनी चाहिए। क्या मात्र नारा लगाने से ही लोकतांत्रिक समाजवाद

स्थापित होगा ? हमारा जीवन सामाजिक हो । सोवतन तो एव जीवन-वृद्धि है—सत्य-अहिंसा, प्रेम और सेवा एव साहचर्य हवें जीवन में उतारना है ।

जैसा कि स्वयं डा० जयदेव ने कहा है, 'आर्थिक विपन्नता एव विवशता दोनों के लिए समान है ।' मैं उसको और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । एक ओर एव लाख से ढाई लाख रुपये वार्षिक व्यय, दूसरी ओर सर्व सम्पन्न अराजकीय विद्यालय पर पचास हजार रुपये मात्र । सत्य तो यह है कि जितना वेतन एव अन्य सुविधाएँ राजकीय विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्राप्त है उतना वेतन एव उस प्रकार की सुविधाएँ अराजकीय विद्यालय के शिक्षकों को भी नहीं । इस विषमता का औचित्य क्या है ? एक एम० ए० पास अराजकीय विद्यालय में एक सौ या एक सौ पचास रुपये पर काम करता है—वह भी समय पर नहीं मिलता—वही एक एम० ए० पास राजकीय विद्यालय में तीन सौ से पाँच सौ रुपये पाता है और प्रत्येक महोने की पाँच सारीय तक तो अवकाश वा लेता है । इसके अतिरिक्त राजकीय शिक्षकों को आवास एव चिकित्सा की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं—कुछ शिक्षकों के लिए तो यह भी भ्रम का स्रोत बन गया है । डॉक्टर, दूकानदार एव शिक्षक मिलकर व्यापार घड़त्ते से चलाते हैं—मरती है बेचारी गूंगी जनता । दूसरी ओर अराजकीय शिक्षक एव उनके बच्चे दवा के अभाव में तड़प कर रह जाते हैं ।

बिहार में माध्यमिक शिक्षा का दायित्व निश्चित रूप से अराजकीय शिक्षकों एव शिक्षण-संस्थाओं पर है ।

जहाँ तक अराजकीय की राजकीय या राजवीय की अराजकीय बनाने का प्रश्न है—वह तो सुविधाएँ देने एव विषमताओं को मिटाने से जुड़ा हुआ है । मात्र नाम बदलने से नहीं । विचारणीय प्रश्न है कि बिहार टेक्स्ट बुक कमिटी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें—चाहे वह मिन्नकोटि की हो क्यों न हो—पूरे बिहार के सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य है और वह टेक्स्ट बुक कमिटी पूर्णरूप से सरकारी संस्था है । क्या यह जनतंत्र के लिए सच्चे एवं स्वतंत्र सोच-मानस के लिए खतरा नहीं है ?

एक ही डी० पी० आई०, आर० डी०डी० एव एस० डी० ई० जो० दोनों विद्यालयों के वर्गधर्ता हैं—तो फिर या तो सरकार सभी विद्यालयों पर से अपना नियंत्रण हटा ले, जो शायद वह नहीं चाहती है, और नहीं, तो दोनों को समान सुविधाएँ प्रदान करे—चाहे उसके लिए केन्द्र से जुझना ही क्यों न पड़े । एक बात की ओर मैं डा० जयदेव एव अन्य मन्त्रियों का ध्यान दिलाकर अपनी

बात समाप्त करता हूँ। बिहार में महा विद्यालयों में भी विद्यालयों की तरह ही वेतन एवं अन्य सुविधाओं की विषमता अभीभूत एवं सम्बद्ध महा-विद्यालयों के नाम पर वषों से चली आ रही थी। जब सारे बिहार में सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों को मान दो सौ रुपये से साढ़े पात सौ और वहीं-कहीं तो दो सौ से पांच सौ का वेतनमान था—तो कस्टीयूएण्ट कालेजों को सरकार ने यू० जी० मो० का चार सौ से आठ सौ का वेतनमान देना शुरू किया। बिहार के सम्बद्ध कालेजों के शिक्षकों के लिए यह अपमानजनक एवं असह्य था—अतः १९६७ में समान काम के लिए समान वेतन की मांग की गयी। सरकार ने संवैधानिक रूप में इसे स्वीकार किया। पुनः उसे कार्य रूप देने के लिए १९७० में हड़ताल एवं सत्याग्रह के माध्यम से चार सौ से नौ सौ पचास का वेतनमान सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को सरकार ने देना स्वीकार किया। १९७२ में भी हमने सरकार से स्पष्ट रूप से सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को कस्टीयूएण्ट बनाने की मांग की—सरकार ने समझौता द्वारा समय पर एवं समान वेतन की मांग स्वीकार की—जिस पर तीन करोड़ रुपये व्यय होंगे।

यह तो सभी जानते हैं कि जब तक इस देश के शिक्षक भूखे हैं, शिक्षण-संस्थाएँ विरग्नावस्था में हैं—तब तक देश का विकास सम्भव नहीं। अतः जहाँ अन्य मशें में जरूरी रुपये पानी की तरह बहाया जाता है, वहाँ मनुष्य-निर्माण में करोड़ पर भी बचम बची नहीं बड़े ?

शिक्षा में परिवर्तन के सम्बन्ध में जिस बात की गांधीजी ने १९१७-१८ में तथा बिनोबा ने १९४७ में कहा, उसे कल-परसों गांधीग्राम में दीक्षान्त-समारोह में धोलती हुई प्रधान मंत्री इन्दिराजी ने भी स्वीकारा। उन्होंने कहा कि २५ वर्ष पूर्व शिक्षा में परिवर्तन नहीं करके लोगों ने एक बड़ी गलती की।

अन्ततः एक बात और, वह यह कि आज सभी शिक्षण-संस्थाएँ शिक्षा की तरह ही अनुराधक हैं। अतः प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक शिक्षण-संस्था के लिए कोई-न-कोई उत्पादक श्रम-प्रधान कार्यक्रम स्वीकार करना चाहिए। शिक्षकों को भी जनतांत्रिक ढाँचे में चतुरता चाहिए—समाज के मार्गदर्शक आदर्श उन्हें ही बनना है। आचार्यकुल, तरुण-शान्तिसेना, सोचसेवक तथा एक शिक्षक के नाते ही मैंने अपने कुछ विचार यहाँ पर रखे।

“सा बिद्या या विमुक्तये”

व्याख्याता, अग्रजी विभाग, हरिसिंह महाविद्यालय,
हवेलीखणपुर, मुंगेर (बिहार)।

नरेन्द्र दुबे

तीसरी दुनिया की करुण कहानी

(विश्व के चिन्तक विकासशील देखो—जिन्हें तीसरी दुनिया कहा जा रहा है—की समस्याओं का एक अध्ययन, टेक्नालॉजी के वर्तमान स्वरूप और हथियारों के व्यापार के सम्बन्ध में यह चिन्तनीय लेख नबी सासीम के पाठकों के लिए प्रस्तुत है ।—सम्पादक)

आज के विश्व में एक मजीब प्रकार का धम-विभाजन हो गया है । इस धम-विभाजन का स्वाभाविक परिणाम 'अमीरों के लिए शांति और गरीबों के लिए युद्ध' के रूप में हुआ है । दूसरे विश्वयुद्ध के पश्चात तब २६-२७ सालों में बिड़ने भी युद्ध हुए हैं, उदका विवरण देना तो कठिन है, लेकिन एक बात निरपवाद रूप से सही है कि ये सारे ही युद्ध तीसरी दुनिया में हा लड़े गये हैं । आज थेयर ने अपनी पुस्तक—"मर्चेंदिस ऑव वार—द इण्टरनेशनल आर्म्स ट्रेड" में लिखा है कि सन् '४२ से अब तक ५५ बड़ी लड़ाइयाँ हुईं और ३०० सौ से ज्यादा फौजी सघर्ष हुए । इन सबके इतिहास की प्रभावित किया है । यह एक बारम्बार्यजनक तथ्य है कि ये सारे ही युद्ध और फौजी सघर्ष तीसरी दुनिया में ही हुए । वस्तुतः यह कोई संयोग या आकस्मिक घटना नहीं वरन्

एक स्यास दग की टेक्नालॉजी और थम विभाजन का ही दुःख परिणाम है। इस तथ्य से आम जनता को सावधान करना बहुत आवश्यक है।

औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश या अमीर देश, जिनमें जनसंख्या का घनत्व गरीब देशों की तुलना में बहुत कम है, सस्तरक हथियारों का निर्माण करते हैं और दूसरे देशों को इस्तेमाल करने के लिए बेचते हैं। सामान्यतः इनकी खरीदनेवाले मुल्क गरीब देश ही होते हैं। यद्यपि इस बात की कल्पना ही कठिन है, पर यह सत्य है कि गरीब लोग एक-दूसरे को खत्म करने के लिए अमोरों से साधन खरीद रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बिलसन ने "वियतनामीकरण" के नाम से जिस नीति का आविष्कार और अनुसरण किया उसके कारण परिस्थिति और भी बिगड़ बन गयी है। इस नीति के कारण लाशों का रंग बदल गया और तीसरी दुनिया एक दूसरे को मारने के नारकीय क्रय में उलझ गयी है।

स्विटजरलैण्ड के प्रसिद्ध पत्र "नैशनल जीडुग" में प्रकाशित श्री रुडोफ के एक लेख में अमीर देशों द्वारा नवजात राष्ट्रों को हथियारों के व्यापार में फँसाने के कुचक्र की कटु आलोचना की गयी है। लेख में कहा गया है कि विकसित औद्योगिक देश पहले अपने हथियार इन गरीब देशों को मुफ्त में सहायता के रूप में देना शुरू करते हैं जिससे बाद में वे शुरू उनके हथियारों के खरीददार बन जायें। उदाहरण के लिए समुक्त राज्य अमेरिका ने १९६१ में जिसने हथियार निर्यात किये उनका केवल १८ प्रतिशत ही बिक्री किये गये हथियार वे और दोष अन्य देशों को सहायता के रूप में दिये गये थे। लेकिन सन् '६६ में हो स्थिति बदल गयी और इस वर्ष अमेरिका ३३ निर्यात किये जायेवाले ७० प्रतिशत हथियारों की बिक्री को गयी और अनेक व्यापारिक अनुबन्धों के आधार पर इनका निर्यात किया जाने लगा। लगता है तब से यह प्रतिशत निरन्तर बढ़ रहा है। अमेरिका द्वारा अन्य देशों की निर्यात की जायेवाली युद्ध-सामग्रियों में ३० गुना वृद्धि सन् १९६३ और १९६७ के चार वर्षों में ही हो गयी थी। (पता नहीं पिछले चार वर्षों में इसमें कितने गुना वृद्धि हुई है।) वस्तुतः जैसे-जैसे छोटे छोटे देश आजाद होने गये वे-वे-से हथियारों के मामले में वे अमीर औद्योगिक देशों के चंगुल में फँसते गये। अमीर देशों ने भी अपने हथियारों की बिक्री का एक भी अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। कभी पुराने हथियारों की भेंट देकर इन्हें प्रभावित किया गया तो कभी ठीके सैनिक-प्रशिक्षण का लोभ देकर अपने हथियारों की बिक्री का

बाजार इन गरीब मुल्कों को बनाया गया । एक बार इन छोटे-बड़े विकासशील मुल्कों के पास अपनी फौज हो जाने पर और थोड़े-बहुत हथियार आ जाने पर सहज ही ये देश घास्त्रों की दौड़ में पड़ गये और औद्योगिक देशों के हथियारों के अच्छे खरीददार बन गये । स्टॉकहोम स्थित शांति-शोध-संस्थान ने गन् १९६९ के वर्ष के आंकड़े देकर यह बताया है केवल इस एक वर्ष में गरीब देशों ने १४ अरब डॉलर का व्यय अपनी "राष्ट्रीय-प्रतिरक्षा" पर किया है । यह व्यय गरीबी और बेकारी हटाने और लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो जानेवाले व्यय से कई गुना अधिक ॥ ।

अध्ययन करने से ऐसा लगता है कि युद्ध-सामग्री के निर्माण से ही विकसित औद्योगिक देशों से पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है । यह बात स्पष्ट है कि यदि युद्ध-सामग्री खरीदनेवाले देश एक साथ इनकी खरीदी बन्द कर दें तो निश्चित ही इनके निर्माता देशों में रोजगार की अत्यन्त गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी । हथियारों के उत्पादन का चक्र चलाये रखने के लिए यह जरूरी है कि इनकी बिक्री हो और यदि खरीदनेवाले के पास पैसे न हों तो उन्हें उधार देना पड़ेगा । यह बात भी काम उल्लेखनीय नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में बड़ी उदारता से उधारी दी जाती है ।

यद्यपि मोत के सोदागरो का वह जमाना अब चला गया है जब उनके द्वारा बेचे गये हथियारों से वे बहुत मुनाफा बमाते थे । आज हथियारों का सारा व्यापार सभी देशों में सरकारों के हाथ में है । इन सरकारों के वास्तविक हित राजनैतिक है । इसके कारण सरकारों को अपना प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाने में और परिष्कृत उत्पादन-प्रक्रिया और बड़े-बड़े उद्योग चालू रखने में ही सहायता मिलती है । शांतिकाल में इन उद्योगों के उत्पादन की वास्तविक माँग न रहते हुए भी मात्र रोजगार बनाये रखने और अपना प्रभाव-क्षेत्र बनाये रखने में ही इन उत्पादन इकाइयों का उपयोग होता है ।

यदि हम अपने जमाने की इस भयंकर विसंगति से निकलना चाहते हैं तो हमें इन तथ्यों का और परिस्थितियों का सामना करना होगा ।

आज एक ओर हमारे पास ऐसा तंत्र है जो जनता की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए बलम है और सदा कुनिम और खतरनाक माँगों की पूर्ति में लगा हुआ है; तो दूसरी ओर अरक्षित आम जनता के भयंकर शोषण ॥ विषम

स्थिति बन रही है। इस शोषण के कारण अनेक हितक विस्फोट होते हैं जिनसे निपटने के लिए पुन हथियारों का उपयोग करना पड़ता है। कभी कभी इनके सुविधा प्राप्त वर्ग के स्वार्थों की रक्षा की जाती है तो कभी सामाजिक धर्म नाम पर इनका उपयोग होता है। यह एक ऐसी दुःखद स्थिति है जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है।

इस दुःखद और विषम परिस्थिति का बहुत बड़ा कारण आज की औद्योगिक टेक्नालाजी है। ऐसा लगता है मानों हमने आज की टेक्नालाजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और उसके अनुसार ही अपने को ढालने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक प्रकार की यंत्रों की गुलामी है। जहाँ तक हथियारों का प्रश्न है इस टेक्नालाजी ने ऐसा अम विभाजन कर दिया है कि गरीबों के लिए युद्ध और अमीरों के लिए शांति और समृद्धि भोगना रह गया है। दूसरे सत्रों में इस टेक्नालाजी ने सब प्रकार के प्रदूषण की विचित्र समस्या पैदा कर दी है। वस्तुतः इसका एक ही विकल्प है। हम लोगों को हुनियादी और वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नयी टेक्नालाजी का विकास और प्रसार करना होगा। आज की विसंगतियों और निहितस्वार्थों के विरुद्ध यह क्रान्ति हमें करनी होगी। टेक्नालाजी में परिवर्तन के लिए सारे विश्व में महान क्रान्ति का आह्वान करने की आवश्यकता है। (सत्रों के सौजन्य से)

२१ वाँ अखिल भारत सर्वोदय समाज सम्मेलन, कुरुक्षेत्र की तारीखों में परिवर्तन

सम्मेलन सम्बन्धी पहली सूचना में २१ वाँ अखिल भारत सर्वोदय समाज सम्मेलन ता० २२ से २४ अप्रैल १९७३ को कुरुक्षेत्र में होगा ऐसा घोषित किया था। परन्तु कार्यक्रमों में कुछ परिवर्तन होने से सम्मेलन की तारीखों में भी थोड़ा बदल करना जरूरी हो गया है।

अब सम्मेलन ता० ११ से १४ अप्रैल १९७३ को होगा। ता० ११ अप्रैल को दोपहर २-३० बजे सम्मेलन प्रारम्भ होकर ता० १४ अप्रैल १९७३ को दोपहर १२ बजे समाप्त होगा।

गोपुरी दर्था (महाराष्ट्र)

दिनांक २१-२-१९७३

युवा आक्रोश : भविष्य क्या है ?

संतोष भारतीय

आज जीवन की प्रत्येक दिशा से केवल एक ही बात उभर कर सामने आती है—और वह है असुरक्षा। सीमाओं की असुरक्षा, राष्ट्र की असुरक्षा, आनेवाली पीढ़ी की असुरक्षा। कौन-सी चीज है जो इस देश में सुरक्षित है ? बाजारों में हम नयी पीढ़ी को काला बाजारी और भ्रष्टाचार करनेवालों से सामना करना पड़ता है। सरकारी दफ्तरो में रिश्वत खोरी और जी-हुजूरी का सामना करना पड़ता है। विद्यालयों में उसे गैर-जिम्मेदार अध्यापकों का सामना करना पड़ता है, और दल दारी कुम्भवत्सा के विरुद्ध आवाज उठाने पर उसे पुलिस के ठण्डों का तो सामना करना पड़ता ही है। समाज के हर मोर्चे पर उसे पीड़ा और निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इस देश की नयी पीढ़ी के साथ इससे बढ़कर मजाक और क्या होगा कि अब वह असतोप में घुटकर जीती है, तब कहा जाता है कि उसमें अनुशासनहीनता बढ़ गयी है। आज हम यह देखते हैं कि युवा वर्ग असतोप में है, न कि युवा असंतुष्ट है।

ध्यान से देखें तो युवा असतोप एवं अनुशासनहीनता का दायित्व इस देश के गतिहीन समाज पर है। बीसवीं सदी का कोई भी आगस्त्य नवयुवक इस सामाजिक शोषण से अपनी आंख नहीं मूंद सकता, जिसमें किसान बाप, जो

अपने सून-पसीने से सींच कर इस देश की धरती को सजाता है, सवारता है, उसके साथ न्याय नहीं होता; उसका मजदूर भाई, जो किसी मिल में इस्पात को पानी की तरह सांचे में ढाल रहा होता है, उसके साथ न्याय नहीं होता। इस देश का विद्यार्थी उस कड़वाहट को भी नहीं पचा सकता, जिसमें उसकी माँ की बीमारी और बहन की दम तोड़ती हुई जबानी से छुटे वातावरण में उसे अपनी शिक्षा जारी रखनी पड़ती है। असंतोष तब जनकता है जब किसी विद्यार्थी को अपनी फीस भरने के लिए अपनी माँ के कंगन बेचने पड़ते हैं। ऐसी आर्थिक और सामाजिक विषमता से युवा वर्ग को घमनिष्ठों में आक्रोश एवं असंतोष का संचार होना स्वाभाविक ही है।

इस स्वाभाविक असंतोष का अस्वाभाविक इस्तेमाल आज वे लोग कर रहे हैं जो इस समाज को टिकाये रखना चाहते हैं। ऐसे लोग आज धार्मिक संस्थाओं से हैं, सेवा-संस्थाओं में हैं तथा सबसे ज्यादा संख्या में राजनीतिक दलों में हैं। वर्तमान सामाजिक स्थिति से विमुख नवजवानों का असंतोष निहित स्वार्थों को टिकाये रखने में अनजाने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विडम्बना तो यह है कि आज नवजवान स्वयं विभक्त हो गया है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं गरीब के नाम पर, तो कहीं किसान और मजदूर के नाम पर।

जब तक यह नकली बँटवारा नहीं समाप्त होता, और नवजवान, नवजवान के नाम पर नहीं एकत्र होता, तब तक यह व्यवस्था चलती रहेगी। अतः आज एक बड़ी उपल-पुल की आवश्यकता है।

इस उपल-पुल में से क्या निकलेगा? यह मुख्यतः उस विकल्प के ऊपर निर्भर करेगा जिसके लिए संघर्ष शुरू होगा। जरूरत इस बात की है कि लड़नेवाली शक्तियों को सम्मान दिया जाए और ठोस माँगों के ऊपर क्रान्तिकारी आन्दोलन शुरू किया जाए। तब, और केवल तब ही, नवजवानों के विराट् समुदाय के सामने भविष्य का साफ नक्शा उभरेगा।

[एक तर्ज़ की उक्त अभिव्यक्ति को प्रकाशित करके हम एक परिचर्चा शुरू करना चाहते हैं जिसका विषय यही होगा—‘युवा आक्रोश : भविष्य क्या है?’ हम आशा करते हैं कि राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ के इस उबलते विषय पर नयी तालीम के प्रबुद्ध पाठक अपना विचार इस परिचर्चा के अन्तर्गत प्रकाशनाथ भेजेंगे।—सम्पादक]

विनोबा

हिन्दुस्तान की सब भाषाओं के लिए नागरी लिपि मान्य हो

जिन कारणों से सबकी बोली के तौर पर हिन्दी को मान्यता दी गयी, उन्ही कारणों से नागरी को सबकी लिपि के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक वैसी मान्यता नहीं मिली। राष्ट्रभाषा हिन्दी नागरी में लिखी जायेगी। इसमें कोई द्विविधा नहीं। लेकिन हिन्दुस्तान की अग्याग्य भाषाएँ भी नागरी में लिखी जायें, यह निर्णय अभी होने का बाकी है। वैसा निर्णय होने पर दूसरी भाषाओं के लिए आज जो लिपियाँ चल रही हैं उनका निषेध नहीं होगा। वे लिपियाँ भी चलेंगी, इतना ही निर्णय का अर्थ होगा।

कुछ लोग यह स्वान नागरी को देने के बजाय रोमन को देने का सुझाते हैं। मैंने इस पर बहुत सोचा है और तटस्थ भाव से सोचा है। रोमन लिपि में अनेक गुण हैं इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि उसमें अनेक दोष भी हैं। और वे दोष इतने समर्थ हैं कि उनसे तय आकर बर्नार्ड शा ने अंग्रेजी के लिए नयी लिपि का आविष्कार पाहा। और उसके लिए अपनी 'हस्टेट' में से कुछ पैसा भी रखा। बर्नार्ड शा की भाँग के अनुसार जो लिपि सुझायी गयी उसका नमूना अभी 'लन्दन टाइम्स' में मुझे देखने को मिला। तो क्या पाया? रोमन के साथ जिसका कुछ भी साम्य नहीं, ऐसी लिपि वह थी, और उसमें नागरी के गुण छाने की चेष्टा की गयी थी। और उधर हमारे लोग हिन्दुस्तान की भाषा के लिए रोमन लिपि सुझाना चाहते हैं।

इसके मानी यह नहीं कि नागरी परिपूर्ण लिपि है, या उसमें सुधार की गुजाइश नहीं। नागरी लिपि में सुधार की जरूरत है ऐसा माननेवालों में मैं भी शुमार हूँ। और 'लोक-नागरी' लिपि मेरे नाम से लोगों को थोड़ी बहुत

अवगत भी हो गयी है। लेकिन नागरी में सुधार किये बिना आज की हालत में वह देश की भाषाओं के लिए लागू नहीं हो सकती, या लागू नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, बल्कि पहिले नागरी सुधारी जाय और बाद में वह भारतीय भाषाओं में लागू की जाय, इस विचार में मैं खतरा देखता हूँ। आज की हालत में भी नागरी भारतीय भाषाओं के लिए चल सकती है और चलनी चाहिए, ऐसी मेरी राय है। और तदनुसार मैंने 'गोता प्रवचन' के अनेक भाषाओं के तजुमे नागरी लिपि में छपवा दिये हैं। उनका उपयोग करके अनेक भाषाएँ आसानी से सीख सकते हैं, ऐसा भी अनुभव आया है।

अगर हमने नागरी को भारत भर में चलाया तो आगे जाकर संसदा भारत के बाहर भी उपयोग होने का सम्भव मैंने देखा। मिसाल के तौर पर मेरी पदयात्रा के दरम्यान भिक्षु जापानी इमानी के पास से मुझे जापानी भाषा सीखने का मौका मिला तो मैंने देखा कि जापानी भाषा की रचना हिन्दुस्तान की भाषाओं के समान है। यानी पहिले वर्ता, पीछे कर्म, अन्त में क्रियापद। यह हमारा वाक्य विचार और शब्दयोगी अव्ययसज्ञा के बाद में लगाने का हमारा सम्प्रदाय जापानी भाषा में चलता है। जापानी लोग नयी लिपि की तलाश में हैं, क्योंकि उनकी लिपि जो चित्रलिपि है और अत्यन्त बिजो से बनती है, प्रचार के लिए अनुकूल नहीं पड़ती। ऐसी हालत में अगर नागरी अपने देश में हम चलायें तो जापानी के लिए भी वह चलेगी, ऐसा सम्भव है। यही बात चीनी भाषा को भी लागू है। इस तरह नागरी एशिया के पूर्व भाग की लिपि आसानी से बन सकती है। लेकिन उतनी व्यापक वह बने या न बने, भारत भर में वह चले तो भी हमारा बहुत कुछ काम बन जायेगा।

यहाँ सवाल हो सकता है कि अगर ऐसे मेरे विचार हैं, तो नागरी लिपि में सुधार पेश करके लोक-मानस की क्या मैंने इतिवृत्ति में नहीं डाला? यह आक्षेप मुझ पर लागू हो सकता है यह मैं कबूल करता हूँ और इसीलिए सफाई के वास्ते मैंने यह लेख लिखा है। लिपि सुधार का मेरा सुझाव है, आप्रह्व नहीं। लिपि 'प्रचार' का मेरा आग्रह है। 'आग्रह' के मानी यह कि समझा जाय कि वह मैं किसी पर लादना चाहूँगा। लादनेवाली बात अहिंसा में आती ही नहीं, यह तो सब समझ सकते हैं।

अनूपराहर : २३-४-६०

सर्वोदय-शिक्षा-दर्शन

[श्री काचरियाजी की स्मृति से जापोजित व्याख्यानमाला के फल से गाँधी विद्यालय, गुलाबपुरा में सर्वोदय-शिक्षा-दर्शन के सम्बन्ध में श्री त्रिलोक चन्द्र, मंत्री, राजस्थान समग्र सेवा संघ द्वारा प्रस्तुत विचार । —सम्पादक]

जमी जो समय बीत रहा है वह देश के शिक्षा-जगत के लिए संक्रान्ति कात है । परिवर्तन का युग है । इसलिए बड़ा संवेदनशील है । इस समय सारे राष्ट्र में शिक्षा के बारे में बड़ी तेजी से चिन्तन चल रहा है । क्योंकि देश का सम्पूर्ण शिक्षा-क्षेत्र ज्वालागुली के कगार पर खड़ा है । यह विस्फोटक स्थिति से गुजर रहा है । लेकिन दुस इस बात का है कि यह विषम स्थिति कोई शिक्षा-क्रान्ति की प्रसव-वेदना नहीं है । बल्कि पिछले २५ वर्षों में प्रचलित शिक्षा-नीति ■ दुष्परिणामजन्य निराशा, भ्रष्टकारमय प्रविष्टि के आक्रोश के स्फूर्तिग हैं, जो सारे समाज को भस्म कर देने के लिए बिना-दिन भयंकर रूप लेते जा रहे हैं । यदि इसके गर्भ में नव-सृजन की प्रेरणा होती, उमंग होती तो नव-संस्कृति के स्फुरण की उज्ज्वलसंपूर्ण अवधिमा सबाज के क्षितिज पर प्रदीप्त बिजे हुए होती । जारी जोर आशका के स्थान पर आनन्द की लहरें हिमोरे लेती । किंतु शिक्षा-जगत तो आज एक विषम एवं गम्भीर परिस्थिति से गुजर रहा है ।

मैं सर्वप्रथम एक बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि शिक्षा एक मला है । संस्कृति के सृजन की प्रक्रिया है । पद्धति है । शिक्षा कोई निरपेक्ष मूल्य नहीं है । वह नव-संस्कृति के उद्भव के लिए सापेक्षिक परिकल्पना है, परियोजना है । इसलिए किसी भी प्रकार के शिक्षा-संयोजन को कल्पना करने के पहले उसके उद्देश्य तथा उसके पीछे के समाज-दर्शन का स्पष्टीकरण आवश्यक है । शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसका हमारे विचारों के परिष्करण, नव-संस्कारों के निर्माण ■ सहज सम्बन्ध है । इसलिए जो शिक्षा के बारे में सोचते हैं, उनकी प्रथम निष्ठा अनुष्य में, अनुष्य की विचार-शक्ति में और विचार-

परिवर्तन एवं सस्कार-सशोधन में गहरी होनेी चाहिए। जिसकी निष्ठा मनुष्य की विचार-शक्ति पर न हो और बिन्ही बाह्य उपकरणों, शास्त्रों इत्यादि पर हो, तब शिक्षा का मूल आधार ही समाप्त हो जाता है। भय अज्ञान का धोतक होता है, उससे ज्ञान की प्रसूति नहीं हो सकती है। इसलिए जिस समाज-दर्शन में श्रद्धा मानव की विचार-शक्ति पर है वही शिक्षा की बड़ी महत्ता है। क्योंकि वहाँ शिक्षा समाजक्रान्ति का माध्यम है। इसलिए जिस समाज-दर्शन का वैचारिक-क्रान्ति में विश्वास है, वहाँ शिक्षा समाज-परिवर्तन के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित होती है। भय और दण्ड से मुक्त समाज में नये मूल्यों की स्थापना और परिस्थिति परिवर्तन के लिए शिक्षा ही एक सबसे साधन है। सर्वोदय-समाज-दर्शन नव सस्कृति के सृजन के लिए शिक्षा को ही एकमात्र क्रान्ति का साधन समझता है। इसलिए उसकी लोक-शिक्षा में गहरी श्रद्धा है।

सर्वोदय-समाज के शिक्षा-दर्शन को समझने के लिए सर्वोदय-सस्कृति के आधारभूत सिद्धान्तों से परिचित होना होगा। क्योंकि उसमें ही नयी तालीम की तरफ अन्तर्निहित है। सर्वोदय-विचार एक ऐसे अहिंसक समाज-रचना की परिकल्पना करता है, जो वर्ग एवं शोषण मुक्त हो, स्वातंत्र्य एवं समतायुक्त हो। जहाँ पारस्परिक सहयोग हो और जिसकी रचना विकेंद्रित हो। राष्ट्र-निर्माण की बेला में एक सुनिश्चित एवं स्पष्ट समाजदर्शन की आवश्यकता होती है। जो राष्ट्र की आवाजाओं का प्रतीक हो और उसके पुरुषार्थ को सतत जागृत रखता हो। आज हमारे सामने हमारी स्वतन्त्रता की अधुण्ण रखने का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि उसे समाज की गहराइयों तक ले जाने का प्रश्न है ताकि सबको उसकी प्रतीति हो सके। उसके साथ सर्वोदय-विचार के समस्त पारस्परिक सहयोग एवं प्रेम की शक्ति पर आधारित मानवीय मूल्यों से अपूरित अहिंसक सस्कृति के निर्माण का प्रश्न है। अब शिक्षा की ऐसी तजवीज चाहिए, जिससे बालकों के मनों में उन सांस्कृतिक चेतनाओं का विकास हो सके, जिससे समाज में प्रेम एवं मानवीय सहानुभूति से अनुप्रेरित उत्साह एवं पुरुषार्थ का नया वातावरण पैदा हो सके। नयी जिज्ञासाओं और कसरनाओं का सागर हिचोरे ले सके।

स्पष्ट है कि ऐसी सस्कृति के विकास के लिए समग्र दृष्टि एवं सन्तुलित व्यक्तित्ववाला मानव चाहिए। नव सस्कृति के लिए नयी तबोयतवाला इन्सान चाहिए। ऐसा इन्सान, जिसके मन-बुद्धि एवं शरीर समन्वित रूप से

विकसित हो, जो ज्ञान, बर्मे एव शक्ति का समान उपासक हो। ऐसे व्यक्ति एव सन्तुलित व्यक्तित्व एव समग्र दृष्टिवाले मानव का निर्माण ही सर्वोदय-शिक्षा विधि का बुनियादी दर्शन है। उनके सामने बालक लड़ा है, विस्तार प्रकृति के मध्य, अपनी नैसर्गिक रुझानों के साथ, अपने जीवन-विकास के तत्वों को लेकर। सर्वोदय शिक्षा दर्शन मानता है कि प्रकृति और समाज का परिवेश ऐसा होना चाहिए जिसमें हर बालक अपनी प्रतिभा के विकास के लिए निर्वाह अवसर प्राप्त करता चला जाय। जीवन की कक्षा का सजोता मत्ता जाय। यदि कभी भी विकारों का उभार हो, अवाञ्छनीय एव असंस्कृत वृत्तियों का आक्रमण हो और बालक के व्यक्तित्व में असन्तुलन पैदा करती हो, उसको विभक्त करती हो, तो शिक्षा की परियोजना ऐसी हो, दैहिक वातावरण की धूँधी ऐसी हो कि वृत्ति परिशोधन तथा वृत्ति-संस्करण की प्रक्रिया सहज सध जाय। इस प्रकार शिक्षार्थी अपनी मन, बुद्धि और शरीर, तीनों शक्तियों का समन्वित विकास करता हुआ, दैहिक वातावरण में मुक्त विचरण करता हुआ, अपनी प्रतिभा के विकास की हरम सीमा को प्राप्त कर सके। यही सर्वोदय शिक्षा नीति का शिक्षाक्रम है।

सर्वोदय विचार ने जिस नयी शिक्षा की परम्परा की है, वह जीवन के साथ समन्वित है। एक प्रकार से वह एक जीवन-शिक्षा है। जिसका शिक्षा-क्रम प्रकृति और समाज से अनुवधित है। विनोबाजी के अनुसार ऐसे शिक्षा-क्रम के तीन आधार हो सकते हैं। एक योग, दूसरा उद्योग और तीसरा सहयोग। यही तालीम शिक्षाक्रम मोटे तौर से ये तीन मुख्य आधार हैं। ज्ञान की साधना और उसकी प्राप्ति के लिए आज योग साधना की आवश्यकता है। आज मानस की विज्ञान द्वारा उपलब्ध साधनों के कारण हर रोज कितने पाठ प्रत्यापाठ सहन करने पड़ते हैं? हर समय मानसिक तनाव की स्थिति रहती है। कितने ही आकर्षण हैं। रेडियो, टेलिविजन, सिनेमा, पत्र पत्रिकाएँ इसने द्रुत साधन है जो सतत समाज-शिक्षण बताते रहते हैं। जिनका मानस और आँखों पर दुनिवार आक्रमण होता है। इसलिए आज बुद्धि की निर्मलता व शुद्धता दुर्लभ हो गयी है। जिसके लिए मानसिक अनुशासन की आवश्यकता है। एक सनत, सदाय एव स्वस्थ मानस की आवश्यकता है। जो शाश्वत मूल्यों के प्रति अनुकूल रह सके। अनुपम व सद्ज्ञान का विकास हो, वह भी सहजगति से ही, उसकी जिज्ञासाएँ जागृत रहे, कुतूहलता बराबर बनी रहे, जिससे नयी-नयी बातें जानने की जिज्ञासा प्रसर होती जाय। ताकि नवीन

ज्ञान की प्राप्ति के लिए मानस संग उमुक्त रहे। इस प्रकार की मानसिक शक्ति के लिए योग की आवश्यकता है।

इसी प्रकार मनुष्य की श्रम शक्ति का भी पूरा विकास होना चाहिए। श्रमशक्ति का विकास हो श्रम का शोषण न हो और श्रम की प्रतिष्ठा बड़े यह सर्वोन्मय विचार की मायता है। श्रमशक्ति मानव की गत्यात्मक शक्ति है। शरीर जीवन के उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। इसलिए मानस के साथ उसका भी विकसित होना आवश्यक है। अतः श्रम शक्ति के विकास की योजना भी शिक्षाक्रम का होना चाहिए। मनुष्य की अंगुलियों में प्रकृति ने जा अद्भुत और अगार शक्ति दी वह अद्वितीय है। इसलिए हम शक्ति को विकसित कर इससे जीवन उर्जा अर्जित कर सकें ऐसा शिक्षाक्रम होना चाहिए। इससे जीवन में आनंद प्रत्यय स्वावलम्बन प्राप्त होना। इससे बालक में सृजनात्मक गुणों का विकास होगा। इसलिए उत्साहक उद्योग नयी तालीम के शिक्षाक्रम का मुख्य आधार है। जो शिक्षक लोग कृपि का प्रयत्न काम करते हैं केवल कार्यानुभव से काम नहीं चलाते हैं उन्हें हर रोज प्रकृति के बीच रहकर उसके सौंदर्यपूर्ण एवम्ब का दृश्य करने का अवसर मिलता है। वे जानते हैं कि प्रकृति कितनी रहस्यमयी है और वह हर क्षण नूतनज्ञान अनादन करती रहती है। जिससे व्यक्ति आवश्यकताओं से उठता है। आत्मविमोह जाता है। यह श्रमशक्तिजनित सज्जनशीलता की महिमा है। उसका विभूतियोग है। श्रमशक्ति के माध्यम से जिस परिष्कृत रचनात्मक एवं उपयोगी ज्ञान का विकास होता है वह मानव के व्यक्तित्व की सौंदर्यपूर्ण बनाता है। यदि उद्योग शिक्षा के साथ नहा जुड़ा है तो उद्योग से केवल उसमें कुशलता आ सकती है किन्तु मानवीय गुणों का विकास नहीं हो सकता है। जीविका का साधन ऐसा होना चाहिए जिससे मनुष्य की मनुष्यता का विकास हो। यह शिक्षा का सांस्कृतिक पहलू है। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से मुक्त उद्योग के विकास से जीवन में व्यापक दृष्टिकोण सापेक्षारी तथा महकारिता की भावना का विकास होता है। यह नैसर्गिक उद्योग का संग्रह है।

यदि श्रम का तत्त्व शिक्षा में दाखिल नहीं होता है तो जो ज्ञान मिलेगा वह परोक्ष विद्या होगी। परोक्ष ज्ञान जीवन में पुरुषाय को प्रेरणा नहा दे सकता। उद्योग से शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों का विकास होता है और सृजन के आनन्द की अनुभूति होती है। इसलिए नयी तालीम में श्रम और ज्ञान

का अनुबध है। यहाँ विद्यालयों और कारखानों का समन्वय है। ज्ञान एवं कर्मयोग की सह साधना है। दृढ़ प्रचार ज्ञान और श्रम का समन्वय नहीं तालीम शिक्षा क्रम का प्रमुख तत्व है।

सर्वोदय-शिक्षा-दर्शन का तीसरा तत्व है मन की शक्ति का विनाश। जब तक मानवीय गुणों व रुद्धस्वभावों का विनाश नहीं होता है, तब तक व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास नहीं होता। यह सामाजिक नहीं हो सकता है। उसमें प्रेम, करुणा, सहानुभूति और सहकारिता की उदात्त भावनाएँ विकसित नहीं हो सकती। पारस्परिक सहयोग की भावना स्फुरित नहीं हो सकती। हमारा देश विविध जातियों, धर्मों, भाष्यशास्त्रों, संस्कृतियों, भाषा-भाषियों और प्रदेशों में विभक्त है। यदि मन की विनाशिता और हृदय की उदारता का विकास नहीं होता है तो हम अधिक वर्षों तक एक होकर नहीं रह सकेंगे। विज्ञान ने साधनों की जो प्रचुरता मानव समाज के सामने रख दी है और समृद्धि की विपुलता का जो दुर्निवार आकर्षण पैदा किया है, उसका सदुपयोग पारस्परिक सहयोग की उदात्त भावना के बिना असम्भव है। इसी प्रकार बालक का सहज ज्ञान गुणा के विकास की ओर हो, उसमें विनम्रता, शालीनता के संस्कार विकसित हो, इनके लिए शिक्षाक्रम की योजना ऐसी हो, जिससे सहजीव और सहश्रुति का भावना का विकास हो, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा के तत्व विरोधित हो, विद्वेष, तिरस्कार घृणा के स्थान पर प्रेम और करुणा के अक्षुर प्रस्फुटित हो। यह सर्वोदय शिक्षण संयोजना का ध्येय है। क्योंकि हर बालक देशी सम्मदा है। छोटे परिमाण में है, बीज रूप में है, जिसमें पूर्णता की गुणाद्वय है। शिक्षा-विधि का काम उसको ढूँढ़ना और उसमें पूर्णता के विकास की राह पर सहाय्य देने का है।

इस विज्ञान के युग की माँग है कि परस्पर मित्रता, अक्रोध और निर्भय भावना का अधिकाधिक विकास हो। मैत्री इस युग की आकांक्षा है। मनो की सन्तुष्टता आज दुनिया में प्रलय की आह्वान कर रही है। इसलिए जीवन के प्रति सम्मान की भावना से ही मानव सभ्यता की सुरक्षा है। समाज के ये उन्नत प्रश्न हैं, जो शिक्षा शास्त्रियों को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए सहयोगी संस्कृति का निर्माण और उसके लिए बालक के हृदय का विकास, यह सर्वोदय-शिक्षा-नीति का नैतिक पक्ष है। जो अहिंसक शक्ति में उदगम का श्रोत है।

इस प्रकार सर्वोदय-शिक्षा-दर्शन बालक के सवादी व्यक्तित्व के विकास का विचार है, बालक की नैसर्गिक शक्तियों का सुसंवादी विकास। इस प्रकार सुसंवादी व्यक्तित्व का बालक शिक्षित होकर जन-समन्वित व्यक्तित्ववाला

नागरिक बनेगा, तब सन्तुलित समाज का निर्माण होगा और सर्वोदय सस्कृति का उद्भव । इससे स्पष्ट है कि यह शिक्षण विधि कोई बंधो-बधार्द परम्पराओं, एवं रुढ़िग्रस्त शैक्षणिक विधियों द्वारा परिचालित शिक्षण-योजनाओं, निश्चित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर नहीं चल सकती है । नयी तालीम के शिक्षक की विशाल प्रकृति और सामाजिक परिवेश के मध्य हर रोज शिक्षण का पाठ्यक्रम बनाना पड़गा । यह एक मुक्त विचार है । मुक्त प्रवाह है । शिक्षक जब वर्ग में जाकर खड़ा होता है, बालकों का जो समूह उसके सामने होता है, वह अनेक प्रकार की रुझानों, विविध वृत्तियों एवं सस्कारों को लेकर खड़ा होता है । विविध प्रकार की जिज्ञासाओं का पारावार उमड़ता हुआ होता है । हर रोज नव-रूपी प्रकृति की गोद से और नवीन सामाजिक घटना-घटकों से घुमते हुए बालक एक शिक्षक के सामने वर्ग में सामूहिक रूप में खड़े होने हैं । तब पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें, समय-विभाग अपर्याप्त और क्षुद्र, निरुपयोगी मालूम होते हैं । बालक का व्यक्तित्व कितना बिराट, उसका व्यक्तित्व कितना चहुँमुखी और विशाल होता है जिसे निर्धारित एवं परिचालित पाठ्यक्रमों की परिधि में नहीं बाँधा जा सकता । शिक्षक का विशाल दृष्टिकोण उसकी उमड़ती हुई असीम कल्पनाओं और ज्ञान की स्वय-स्फूर्त एवं वैविध्यपूर्ण स्फुरणाएँ ही उनको सस्कृत कर सकती हैं ।

सत्य जीवन का सत्य हो, समय जीवन की स्फूर्ति और सेवा जीवन का धर्म हो । बालकों के ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो भा शिक्षा-पद्धति हो, वही सर्वोदय-शिक्षा नीति है । इसलिए सर्वोदय-विचार, शिक्षाक्रम, शिक्षक और शिक्षणानुसंगों की स्वतंत्रता का समर्थक है जो न्यायपालिका की तरह सरकार-मुक्त शिक्षा-व्यवस्था का हामी है ।

इस प्रकार नयी तालीम स्वतंत्रता, समता एवं सहयोग पर आधारित नवीन अहिंसक सस्कृति का निर्माण करना चाहती है । जो भय, भ्रूत, विभेद और अज्ञान से मुक्त हो । इसके लिए समग्र दृष्टिकोण एवं सन्तुलित व्यक्तित्व वाले इनसान चाहिए । ऐसे इनसानों का निर्माण योग, उद्योग एवं सहयोग से अनुबधित शिक्षा-योजना के जरिए ही हो सकता है । ऐसा सर्वोदय-विचार का विश्वास है । शिक्षा ही इस प्रकार की नवसंसाधन-रचना की क्रान्ति का वाहन है । इसलिए सर्वोदय-समाज ने जीवन-मूल्यों की क्रान्ति की निष्ठा शिक्षा पर रखी है । इसलिए शिक्षा सर्वोदय-दर्शन की गत्यात्मक शक्ति ।

ब्रह्म सत्यम् जगत् स्फूर्ति, जीवनम् सत्यं शोधनम्, यह नयी तालीम का बीज मंत्र है । ●

मनुभाई पंचोली

लोकभारती : ग्राम-उच्च विद्या का एक प्रयोग

इश्वरीय श्री नानाभाई भट्ट गुजरात के प्रख्यात शिक्षाकार थे। भावनगर में दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन नामक संस्था कायम करके उसके द्वारा उन्होंने गुजरात भर में शिक्षा के नये विचारों का प्रचार किया।

भावनगर दक्षिणामूर्ति में पचीस साल तक प्रयोग करने के बाद वे महसूस करने लगे कि उन्हे ग्राम प्रदेश में बचकर ग्राम बालकों के और ग्रामीणों के बीच बुनियादी शिक्षा के प्रयोग जारी करने चाहिए।

पतप और फूले फूले विख्यात विद्यार्थी भवन को अपने सहयोगियों के हवाले छोड़कर वे खुद सन १९३० में भावनगर के पास आवला गांव में जाकर बसे और वहाँ उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के क्षण में प्रयोग जारी किये। प्राग-जीवन सब कुछ भीर गोपालन केन्द्रित हो रहा है। इससे उन्होंने अपनी इस प्रायोगिक शाला का मूलोद्योग या बुनियादी उद्योग कृषि गोपालन ही रखा और वस्त्रविद्या यानी कढ़ाई बुनाई को दूसरे ग्रामोद्योग का स्थान दिया। प्रारम्भ से लेकर अंत तक का सारा अभ्यासक्रम उन्होंने स्वयं ही रचा और वे उसे क्रमशः ग्यारहवीं श्रेणी तक बढ़ाते गये।

आठवें से बारहवें दर्जे तक की माध्यमिक शिक्षा को उन्होंने छात्रालय केन्द्रित बनाया और उस ग्राम माध्यमिक शिक्षा विभाग को लोकशाला नाम दिया।

स्वातंत्र्य मिलने पर और उसके अंतर्गत सौराष्ट्र राज्य का जन्म होने पर राज्य सरकार ने नानाभाई के अनुभवों की नींव पर बुनियादी शिक्षा का एक सुत्रित अभ्यासक्रम निश्चित किया जो आगे चलकर अन्य राज्यों के लिए भी प्रणारूप बना।

उसके बाद वे धीरे-धीरे महसूस करने लगे कि अब इस बुनियादी और उत्तर बुनियादी प्रयोग के क्षेत्र में अगला कदम उठाना निहायत जरूरी है, जिससे प्रयोग सम्पूर्ण हो। सौराष्ट्र राज्य सरकार ने गैर सरकारी लोब-शालाओं की मान्यता दी थी और कई स्थानों पर सरकारी लोबशालाएँ भी कायम की थी। ऐसी उत्तर बुनियादी शालाओं के विद्यार्थियों को वर्तमान बालेजों में भरती होना अनुकूल नहीं होता था। राधाकृष्णन् कमिशन की रिपोर्ट में भी ग्रामविद्यापीठों की आवश्यकता का सूचन डा० भागव ने किया ही था।

इन सबके फलस्वरूप 'लोकभारती' का जन्म हुआ। २५ मई सन् १९५३ यानी उस विक्रम संवत् की वैशाखी पूनो या बुद्धजयन्ती के मंगल के दिन पर काफ़ी साहस कालेलकर के हाथों लोकभारती की स्थापना हुई। इस प्रसंग पर बोलते हुए सौराष्ट्र राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री डेबरभाई ने 'लोकभारती' की सौराष्ट्र के ब्राह्मण श्रेष्ठ की सौराष्ट्र की उत्तम देन या भेंट बताया। अन्न, आधन, आरोग्य और आनन्द इन चार नीबों पर उत्तम बुनियादी शिक्षा का रचना करना 'लोकभारती' का उद्देश्य रखा गया। उन दिनों तक कुरल इन्स्टीट्यूट के विचार का जन्म भी भारत में नहीं हुआ था, यह विचार बाद में, करीब १९५५ में श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट में पेश हुआ। 'लोकभारती' सारे भारत में ग्राम-उच्चविद्या के क्षेत्र में ऐसा सबसे पहला प्रयोग था जिसमें स्नातक और अनुस्नातक स्तर पर बुनियादी शिक्षा का आयोजन हो।

'लोकभारती' के आदर्श के अनुसार ग्राम-उच्चविद्या के उद्देश्य और विरोधनाएँ ये हैं एक, शिक्षा छात्रासय-केन्द्रित ही होनी चाहिए। विद्यालय में सिर्फ पढ़ने के लिए कोई भर्ती नहीं हो सकता। जीवन और समूह जीवन जीते हुए ही शिक्षा पानी है। दो, सहशिक्षा रचना का आवश्यक अंग माना जाना है। बच्चों के और युवा-युवतियों के विकास की स्वाभाविक और साधारण (नार्मल) बनने में सहशिक्षा ने काफी योग दिया है। तीव, शिक्षा-फीस नकद न ली जाती, फिर चाहे शिक्षा पानेवाला गरीब हो चाहे धीमान्। चार, लेकिन हर एक शिक्षार्थी को चाहे वह गरीब हो चाहे धीमान्, साल भर में गोशाला, सफाई, रखोई घर, खेती या बागवानी, स्थाविक स्वच्छता, रोगी-शुश्रूषा आदि के रूप में चार सौ घण्टे थम या सेवा के काम करने पड़ते हैं। पाँच, अन्तिम वर्ष के अन्तिम सत्र में हरेक शिक्षार्थी को अपने-अपने मुख्य शिक्षा विषय से सम्बद्ध प्रत्यक्ष अनुभव और प्रत्यक्ष काम के लिए निश्चित

किये हुए क्षेत्र या स्थान में रहकर प्रत्यक्ष अनुभव और उसके साथ ग्राम सम्पर्क और शिक्षा-व्यापन करना पड़ता है। और वहाँ बिये हुए काम और पाये अनुभव अन्तिम मूल्यांकन में गिने जाते हैं। गोपानन और दुग्ध व्यवसाय विषय का विद्यार्थी किसी प्रगतिशील गोशाला या दुग्धशाला में, पागवानी सीखता हुआ किसी फलवाग में, सहकार विषय सीखनेवाला किसी अच्छी सहकारी मण्डली में पचायती राज्य का अभ्यास करनेवाला किहीं अच्छी पचायती में और ग्राम शिक्षा को मुख्य विषय रखनेवाला किसी उत्तर बुनियादी विद्यालय में जाकर मुख्यतया वहाँ रहकर मग्न भर काम करता है। छ चार सान के अभ्यासकाल में एकवार हरेक वर्ग के एक सहोने भर का शिविर किसी पिछड़ हुए आदम जाति प्रदेश में रखा जाता है—यहाँ विद्यार्थी कृषि विस्तारण, धानक्रीड़ागण आरोग्य सेवा भजन मण्डलियों वगैरह के माध्यम से आदिवासी समाज का परिचय पाते हैं। सात तीसरे अभ्यासकाल में संस्था के इर्द गिर्द गाँवों में चुने हुए कृषक परिवारों से मिलकर विद्यार्थी सह आयोजित और अद्यतन कृषि सिखाते हैं। आठ, लाकभारती के अभ्यासक्रम में प्रवेश पाने के लिए अग्रणी भाषा का ज्ञान होना लाजिमी नहीं है।

इसके फलस्वरूप इन गाँवों की खेती आदि को शिविर आय गाँवों की स्थिति के मुकाबल में सुधरी हुई मिलती है।

ऐसा भी नहीं कि लोकभारती के काम का प्रभाव इर्द गिर्द के गाँवों तक ही सीमित है। सारे गुजरात से विद्यार्थी यहाँ भर्ती होते हैं। उनके द्वारा संस्था का प्रभाव थोड़ा बहुत गुजरात के बने कोवेष्टितक दिखाई दे सकता है। कहीं गेहूँ के सुधरे हुए बीज के उपयोग के रूप में कहीं अच्छी नस्ल के सांड के उपयोग के रूप में या कहीं यहां के ही स्नातकों से संचालित उत्तर बुनियादी विद्यालय के रूप में।

आज तक ला-भारती के करीब एक हजार स्नातक स्नातिकाएँ समाज में गये हैं। उनमें १० प्रतिशत ग्राम प्रवेशों में भी काम कर रहे हैं। कोई खादी काम, कोई सर्वोदय योजना का संचालन कोई कृषि विस्तारण अधिकारी की हैसियत से कृषि विस्तारण काम तो कोई सहकारी मण्डलियों का संचालन करते हैं। कभी कभी इनमें से विधायक भी चुने गये हैं। कोई अच्छी तरह से अपनी ही खेती करते हुए प्रगतिशील किसान के रूप में स्वीकृत हुए हैं। सबसे ज्यादा स्नातक उत्तर बुनियादी विद्यालयों और हाई स्कूलों में काम करते हैं।

पिछले चार वर्षों से लोकभारती का लोकसेवा महाविद्यालय सोराष्ट्र

युनिवर्सिटी की प्राथमिकता (रूल फंडली) के अन्तर्गत सम्मिलित है। युनिवर्सिटी ने उसे इतना स्थान और स्वीकृति देकर जागरूकता और दीर्घ दृष्टि का सूत्र दिया है। न केवल इनका ही, युनिवर्सिटी ने लोकभारती के अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धति, कार्यक्रमों, अध्यापकों की पात्रता, और वेतन प्रमाण वगैरह बानें जैसी की तैसी मान्य करती हैं। ऐसा करके युनिवर्सिटी ने लोक उच्च-शिक्षा के प्रयोग को आगे बढ़ाने में सहायता दी है।

इस तरह 'लोकभारती' उच्च विद्या को सस्था होने हुए साध-साध ग्राम-पुनरुत्थान के हेतु का भी भनीभाति निर्वाह करती है।

'लोकभारती' ग्राम पंचायत के मंत्रियों की और सरपंच, उप सरपंचों की सान्नीय का काम भी करती है। न केवल आने ग्राम में, बल्कि गाँवों में जाकर वहाँ भी शिविरों के कार्यक्रम रखे जाते हैं। इस तरह आज तक सैकड़ों व्यक्ति मंत्री और सरपंच आदि के काम की तालीम पा चुके हैं। यह कार्य विद्या-विस्तार द्वारा किया जाता है।

इन सब उद्देश्यों के पीछे दृष्टि यह है कि हमें वास्तविक जीवन के अनुभव और शास्त्र दोनों की मजूर के सामने रखना चाहिए—दोनों के सम्मिलन और समन्वय से ही सच्चा ज्ञान प्रकट होता है।

अभ्यासक्रम में एक ओर भाषा, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र आदि मानवीय विषयों तथा दूसरी ओर कृषि-गोपानन और उनके आनुपणिक विषयों की, शिक्षा को समग्रमानव सर्जनक्षम बनाने की दृष्टि से समन्वित और सन्तुलित रखने की कोशिश की गयी है।

विद्यार्थी को दूसरे वर्ष से अपना मुख्य विषय चुन लेना होता है। लेकिन कृषिशाला के किसी मुख्य विषयवाले विद्यार्थी के अभ्यासक्रम में दोप विषयों में से चालीस प्रतिशत स्थान मानवीय विषयों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं।

इससे उलटा, जो विद्यार्थी किसी मानवीय विषय, भाषा, अर्थशास्त्र आदि को चुनेगा, उसे बाकी के विषयों में चालीस प्रतिशत कृषि सम्बन्धी विषय पढ़ने ही पड़ेंगे।

विद्यार्थी का विकास और ज्ञान एकांगी न होकर सर्वाङ्गीण हो, इस बात को 'लोकभारती' के आरम्भकाल से ही सामने रखा गया है। इसी दृष्टि से 'लोकभारती' का ध्यानमत्र ईशोपनिषद् का विख्यात मंत्र रखा गया है।

विद्याम् अविद्याम् च यस्तद्वेदोमय सह।

अविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्याया मृतमश्नुते॥

स्वर्गीय गानाभाई के अर्थघटन के अनुसार योगक्षेम और स्थूल जीवन व्यवहार हैं जिन विषयों का ज्ञान और जिनमें दक्षता की जरूरत है वे अविद्या के अंतर्गत और जो विषय हमें नागरिक भावना, मानवीय दृष्टि, धर्मपरायणता हैं विकास में सहायक हो वे हैं विद्या के अन्तर्गत। स्वस्थ मानव समाज के लिए दोनों का समन्वय, सन्तुलन आवश्यक है। इसीसे कृषि विद्या के विद्यार्थी को प्लेटो से आज तक का राजनीति विज्ञान और हिन्दी को मुख्य विषय के रूप में चुननेवालों को सहकार पचायत कानून पढ़ने होते हैं।

अभ्यासक्रम की शिक्षा पाना, इसका इर्द-गिर्द विस्तरण करना, विस्तरण करते हुए जो प्रश्न, समस्याएँ उपस्थित हो, उनके हल के लिए शोध करना, यही क्रम है—शिक्षा, विस्तरण सशोधन।

इस हेतु से लोकभारती वे आसपास का ग्राम प्रदेश इसका विद्या-विस्तरण क्षेत्र है। इन गाँवों के कृषि, गोपालन, सहकार, पचायती कारोबार आदि के प्रश्नों को समझना और उनका हल ढूँढना विद्यार्थियों के अभ्यासक्रम का ही एक भाग माना जाता है।

ग्रामीण पुनरुत्थान का काम ग्राम प्राथमिक शिक्षकों को नयी तालीम का सैद्धान्तिक और व्यावहारिक ज्ञान दिये बचैर करना सम्भव नहीं है। इस हेतु से 'लोकभारती' वर्षों से सुनियादी तालीम अध्यापन भवन चला रही है। 'लोकभारती' के अपने प्रमाणपत्र को गुजरात राज्य सरकार ने मान्यता और स्वीकृति दी है। राज्य की इस कद्रदानी और सहानुभूति का खास तौर पर यहाँ जिक्र करना चाहिए।

पिछले चार सालों से लोकभारती ने स्नातको के लिए नयी तालीम प्रशिक्षण-केन्द्र भी जारी किया है। इसके द्वारा प्राथमिक सुनियादी शाखाओं में निरीक्षक और माध्यमिक शाखा के शिक्षक-आचार्य तैयार किये जाते हैं।

लोकभारती की स्थापना के समय उसके प्रायण पर एक पङ्क तन का नामोनिशान न था। इस भूमि विस्तार की गाँव ने लोग 'आबलियाट कहाँ करते थे। 'आबलियाट' या तो 'आबलिध्यात', आबलिङ जगली पोथो से व्याप्त। स्व० गानाभाई ने समझ-बूझकर ऐसा उत्तर स्थान चुना था। वे कहा करते थे, 'मवसन में लगन लगना कौन सी बड़ी बात है? पत्थर को तोड़कर पानी बहानेवाला ही सच्चा धूर है। और उनके इस महान निश्चय में सबूत की तरह इसी उत्तर में आम, नींबू, नारियल, नींबू आदि के पत्रहूँ से बड़े पैड़ प्रायण को सीमा दे रहे हैं। और किसी प्राचीन आश्रम की शक्ति

की तरह भूमि में छात्र छोटे-बड़े चार सौ विद्यार्थी जीवन-साधेय पा रहे हैं।

ऐसी लोकाधारित संस्थाओं की हर साल अपने निर्वाह हेतु चन्दे के लिए जाना ही पड़ता है। यह आज का अनुभव है। संस्था के मुख्य आदमियों का समय और शक्ति इस कार्य में ही व्यय होती है। इस तरह समय और शक्ति देना स्व० नानाभाई को नागवार था। वे मानते थे कि संस्था अपने विद्यार्थियों की कृषि-गोपालन का व्यवसाय सिखाना और उसी पर निर्भर बनना सिखना चाहती हो ता उसकी अपनी खेती आधुनिक, समृद्ध और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। ऐसा करने का अनुरोध उन्होंने अपने सहयोगियों से किया और कार्यकर्ताओं ने खोटा उठाकर उनकी इस मनीषा को साकार बना दिया।

आज हमारी खेती बिना साधन सम्पत्ति की और केवल कठिन श्रम पर निर्भर नहीं रही—जैसा कि पहले हुआ करती थी। लेकिन फिर इजन, दबाएँ, नये संशोधित बीज वगैरह को पूँजी की आवश्यकता रहती है। 'लोकभारती' ने इस पूँजी का खर्च निःशुल्क उसके अलावा सरकारी ग्राण्ट की पूरक रकमों के बराबर मुनाफा कृषि आदि से पाया है। अन्दाज़न यह तफा साताना करीब पौन लाख रुपया होता है।

'लोकभारती' की मोशाला स्वावलम्बी है। अठारह वर्ष में उसका दुग्ध उत्पादन दुगुना हो गया है। उसकी गौर नस्ल की गायें अलिल भारतीय हरीफाश्यों में कई बार प्रथम पारितोषिक पा चुकी हैं। यहाँ ३ गाय-बैल ब्राजील, न्यूजीलैण्ड आदि विदेशों में भी भेजे जाने हैं।

'लोकभारती' के सफल प्रयोग की देखकर गुनराव में अन्य तीन ग्राम विद्यापीठ काम चलाने लगे हैं।

इस सारी सफलता का श्रेय दो बातों को मिलना चाहिए। एक है सर्वथा योग्य कार्यकर्तागण। आदर्शनिष्ठ, समझदार, कार्यरक्ष और अध्ययनशील कार्यकर्ताओं के बिना ऐसा प्रयोग कभी पक्का नहीं सकता। इस बारे में 'लोकभारती' भाग्यशाली है। 'लोकभारती' में कार्यकर्ताओं की वेतन थोड़ी अन्य कालेजों की अपेक्षा काफी नीची है और ऐसा भी सघटनकर हो किया है। जिस ग्वायपूर्ण समाज की हम स्थापना शिक्षा के जरिये करना चाहते हैं उसका जितना शक्य हो उतना व्यवहार हमें भी आरम्भ से ही करना चाहिए। परापदेशे पाठित्य से शिक्षा का प्रयोग हो नहीं सकता। इस बात को खयाल में रखकर 'लोकभारती' में निम्नतम और उच्चतम वेतन का अनुपात एक ओर छ का ही रहा है। कार्यालय के चपरासी या डाक बाँटनेवाले की जो

वेतन मिलता हो, उससे छ गुना से ज्यादा सस्था के किसी भी कार्यकर्ता या प्राध्यापक का नहीं हो सकता। फिलहाल तो वह अनुपात दो और नौ का ही है—फिर प्रथम श्रेणी का कार्यकर्ता कितना ही पढ़ा-लिखा हो या सबसे पुराना हो।

इसी तरह 'लोकभारती' में दूसरी बात यह है कि यहाँ वेतन का सम्बन्ध ओहदे की हैसियत के साथ नहीं है। ग्रेजुएट कार्यकर्ता को उसके ग्रेड का वेतन ही मिलेगा चाहे वह सामान्य अध्यापक हो, उपनियामक हो या आचार्य हो। आदमी को काम करना है। जो काम जिसको सौंपा जाता है वह उसे जी जान से करता है—इस तरह ओहदा और वेतन एक दूसरे के साथ सलग्न नहीं है।

एक और अनुकूलना 'लोकभारती' को प्रारम्भ से मिली थी। उसकी नींव डालनेवालों ने १९३८ से १९५२ तक उत्तर बुनियादी क्षत्र में जो काम किया था, उसके मूल्यवान अनुभव।

गुजरात में आज अनेक राज्यों से ज्यादा बुनियादी विद्यालय हैं। इन्हीं उत्तर बुनियादी शालाओं के विद्यार्थी लोकभारती में भरती होते हैं। इस परिस्थिति ने लोकभारती के काम को आसान बना दिया। इस तरह इसकी मजबूती बनी रही।

दूसरी अनुकूलता जो 'लोकभारती' की सवभाग्य से मिलती रही है वह है—राज्य सरकार की सहानुभूति। लोकभारती की प्रवृत्ति को सौराष्ट्र राज्य ने अपना ही काय माना था। उसके बाद बम्बई राज्य और गुजरात ने वही सद्भावना कायम रखी है। सहानुभूति की इस उष्मा ने 'लोकभारती' के विकास में काफी सहयोग दिया है। राज्य सरकार ने लोकभारती के स्नातकों को अन्य स्नातकों के समकक्ष स्थान दिया। दूसरी ओर राज्य सत्ता के नाम पर कभी भी राज्य सरकार ने इस प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया।

परंतु अभी 'लोकभारती' के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। चारों ओर विपन्न और प्रतिगामी परिस्थिति बलमान है। कहीं उसके चंगुल में न पैसें जायें, इसकी सार्वभौमिता तथा आवश्यक है। सदयहीन और बराजित प्रवृत्तियों को रोककर सच्ची दिशा का दर्शन करने कराने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ●

प्रेमनारायण रूसिया

ईसवी सन २००० में शिक्षा

‘आज का बालक कल का नागरिक है’ इस कथन पर जब हम विचार करते हैं तो अनेक प्रश्न उठने लगते हैं—क्या आज जिस प्रकार की समाज व्यवस्था है वैसे ही व्यवस्था बालक को २०-२५ वर्ष की आयु में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् भी मिलेगी? क्या आज की जिन समस्याओं के निदान हेतु हम बालक को शिक्षित बना रहे हैं वे सभी समस्याएँ २०-२५ वर्ष बाद नागरिक जीवन में प्रवेश करने तक उसी प्रकार बनी रहेंगी? क्या हमने ‘भविष्य की’ उन समस्त बातों को सोचकर बतमान शिक्षाक्रम बनाया है जो आज से २०, २५ वर्ष बाद बच्चे की शिक्षा प्रदान करने में पश्चात् समाज में प्रवेश करने पर मिलेगी? इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर राष्ट्रीय बोर्ड स्वीडन द्वारा एक शोध प्रामाण्यना तैयार करायी गयी है। उसका विषय है ‘दो हजार वर्ष में शिक्षा’। इस शोध प्रयोजना से निम्न अनेक दिशारणीय तथ्य सामने आते हैं। यह शोध प्रयोजना राजस्थान की नया शिक्षक नामक पत्रिका १५ (१) जुलाई सितम्बर ७२ में प्रकाशित हुआ है। उस लेख के आधार पर कुछ विशेष उल्लेखनीय तथ्य संक्षेप में प्रस्तुत है

हमारी बीसवीं सदी द्रुत परिवर्तनों की सदी है। कहना न होगा कि विगत तीस वर्षों में हमने जितने परिवर्तन देखे हैं उतने निश्चय ही गत कई सौ वर्षों में नहीं हुए हैं। गगन मण्डल की शोधें प्रारम्भ हुईं तो विश्व को अजीब लगा किन्तु देखते ही देखते मनुष्य ने चन्द्र के घरातल पर अपने पैर रोप दिये। गगन मण्डल के अनेक रहस्य आज हमारे ज्ञान की सीमा में आ गये हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों ने इस जीवलोक में अनेक चमत्कार उत्पन्न कर दिये हैं। इन वैज्ञानिक विस्फोटों के परिणामस्वरूप हमारी अनेक प्राचीन मान्यताएँ आज टूट रही हैं।

इस व्यापक वैज्ञानिक शक्ति का प्रभाव विश्व के अनेक समस्त देशों के साथ साथ हमारी उत्पादन व्यवस्था अथवा व्यवस्था एवं समाज व्यवस्था पर भी पड़ा है। हमारे देश में भी स्वतंत्रता के पश्चात् से एक नयी औद्योगिक क्रांति आयी है। उत्पादन के पुराने साधन एवं सरजाम धीरे धीरे तिराहित हो रहे हैं तथा उनके स्थान पर विद्युत द्वारा संचालित तीव्र गतिवाले यन्त्र आ रहे हैं। इनसे हमारा जीवन और जीवन दशन तेजी से प्रभावित हो रहा है।

औद्योगीकरण के कारण हम अध्यात्मवाद से भौतिकवाद की ओर अग्रसर होने लगे हैं। शहरों का तीव्र गति से विस्तार हो रहा है। जातीयता और प्रांतीयता के बंधनों को छोड़कर औद्योगिक बस्तियाँ बन रही हैं। किन्तु वही बूसरी ओर इस औद्योगिक क्रान्तिजनित नयी संस्कृति से हमारी पुरानी मान्यताओं का मेल न बैठने से समाज में एक विभ्रलता आ गयी है।

औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ हमारे राजनीतिक जीवन में भी क्रांति आयी है। स्वतंत्रता के पश्चात् देश में लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना हुई है देश तीव्र गति से समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित यह लोकतन्त्रात्मक प्रणाली भी भारतीय मानस में जीवन के नये मूल्य स्थापित कर रही है।

अतः हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन की दिशा तीव्र गति से बदल रही है नयी मान्यताएँ नित नये अन्त में रही हैं और जीवन में नये मूल्य स्थापित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सोचना पड़ता कि जिस बालक को आज हम शान्त में भेज रहे हैं वह शिक्षण प्राप्त करने के बाद जब २०, २५ वर्ष की आयु का होगा तब उस समय की परिस्थिति क्या होगी, समस्याएँ क्या होंगी

और जीवन की आवश्यकताएँ क्या होंगी ? प्रश्न उठता है कि क्या आज की वर्तमान शिक्षा को प्राप्त करनेवाला बालक उस नये समाज में सुख से जीवन-यापन कर सकेगा ?

सच तो यह है कि वर्तमान समस्याओं और आवश्यकताओं के आधार पर आज हम अपनी शिक्षा-योजना निर्धारित करते हैं। हमारी शिक्षा-योजना भी विकास की अन्य योजनाओं की तरह अधिक्त-से-अधिक पाँच वर्ष आगे तक के लिए बनाई जानी है, २० वर्ष के आधार पर नहीं। अतः परिणाम यह होता है कि जब बालक शिक्षण प्राप्त करके २० वर्ष की आयु में समाज में प्रवेश करता है तो उसे वहाँ सब कुछ नया ही नया दिखाई देता है—नया समाज, नयी समस्याएँ और नयी आवश्यकताएँ। वह अपने आपको इस नये समाज के लिए अक्षम पाता है। किन्तु विषम होकर जब वह जीवित रहने के लिए छटपटाता है तो उसकी वही छटपटाहट अनुशासनहीनता एवं विद्रोह बन जाती है।

यदि हम चाहते हैं कि आज बाला में प्रवेश लेनेवाला प्रत्येक बालक भविष्य में सुयोग्य नागरिक बनकर निकले तो शिक्षा-व्यवस्था निश्चित करते समय हमें वर्तमान के साथ-साथ इस शताब्दी के अन्त में जन्म लेनेवाली सभी आवश्यकताओं, समस्याओं एवं मान्यताओं को प्रमुख रूप से ध्यान में रखना होगा।

भावी शिक्षा के नीति निर्देशक तत्व

शिक्षा की नीति को निर्धारित करते समय भविष्य को प्रभावित करनेवाले निम्नांकित तत्वों पर विचार करना आवश्यक है :

(१) विज्ञान का विस्फोट : नित नवीन प्रयोगों के कारण विश्व में तीव्र गति से विस्फोट हो रहा है। इससे प्रभावित होकर हमारे विचार, संस्कृति, मान्यताएँ और जीवन-क्रम नयी दिशाएँ ले रहा है। आज हमारी प्राचीन मान्यताएँ तेजी से ढहती जा रही हैं। निश्चय ही यह परिवर्तन हमें अगले २०, ३० वर्षों में ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर देगा जहाँ समाज कि प्रत्येक व्यक्ति को तकनीकियन, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक बनना होगा, तभी वह सुसमय जीवन व्यतीत कर सकेगा।

(२) सामाजिक परिवर्तन : हम देख रहे हैं कि इस शताब्दी में परम्परागत रुढ़िवादी बंधन तेजी से टूट रहे हैं, जातीयता क्षीय हो रही है और

छुआछूत का भेदभाव, मोटर सिनेमा तथा हाट-बाजार से भागकर चूल्हे में जा दिया है। माँ-बाप और गुरुजनों की सनातन मर्यादाओं को तोड़कर आज का युवक स्वच्छन्द बन गया है। लक्षणों से स्पष्ट है कि दानेवाले घरों में युवक आज की अपेक्षा अधिक मूखर होगा। युवक-आन्दोलन का जोर बढ़ेगा और इसके परिणामस्वरूप उन्हें अधिक स्वतन्त्रता तथा अधिकाधिक अधिकार दिये जायेंगे।

(३) पारिवारिक विघटन - भारतीय संस्कृति में अभी तक पितामह से लेकर पोते तक के सह-निवास से युक्त बड़े परिवार एवं गौरव का विषय माने जाते हैं। किन्तु उनका भी तेजी से विघटन होने लगा है। विघटन का यह क्रम भौतिकवादी प्रभाव बढ़ने के कारण चलता ही रहेगा। तथा अन्त में पति-पत्नी और एक या दो बच्चों का छोटा परिवार रह जायगा। पति और पत्नी दोनों घनोपाजन करेंगे। गृहस्थी के जिन कामों को अभी तक हाथ से सम्पन्न किया जाता था अब उसी काम को मशीनों के द्वारा करके व्यय और समय की बचत की जायेगी। अनेक कार्य जिनको पारिवार में अभी गौरवपूर्वक किया जाता था अब वे बाह्य सगठना द्वारा सम्पन्न होंगे—जैसे कि तैयार शुद्ध सिधे हुए कपड़ों का उपयोग बढ़ेगा और तैयार भोजन भी अधिक प्रसन्न किया जायगा।

(४) विश्राम एवं मनोरंजन में वृद्धि : आन्दोलन के परिणामस्वरूप काम के घण्टों में निरन्तर कमी होती रहेगी, मशीनों का उपयोग बढ़ने से घर गृहस्थी के कामों में समय की बचत हेतु प्रयास किये जायेंगे। जनमानस में परिश्रम से बचने और अधिकाधिक विश्राम करने में सुख की अनुभूति परिलक्षित होगी। यात्रिक गुण की नीरस मशीनों से जूझने के कारण मनुष्य मनोरंजन की ओर तेजी से बढ़ेगा। अतः आनेवाले युग में मनोरंजन के नये-नये प्रकार सामने आयेंगे और उनकी संख्या में वृद्धि होती रहेगी।

(५) स्वास्थ्य में गिरावट : स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल, ताजी हवा, सन्तुलित भोजन और पर्याप्त व्यायाम की आवश्यकता होती है किन्तु यन्त्रों, कलों और कारखानों की वृद्धि से जल और वायु दोनों ही दूषित हो जायेंगे। सर्वविदित है कि कारखानों के गंदे पानी से नदियों का शुद्ध जल विषाक्त हो रहा है तथा महानगरों में धुएँ और मोटरों से पेट्रोल से वायुमण्डल दूषित हो रहा है। मशीनों की सेवाएँ सुलभ होने से आदमी में श्रम-निष्ठा कम होगी, यातायात के यात्रिक साधनों की सुविधा बढ़ने से मनुष्य

के पैरो का धम करने का अवसर नहीं मिलेगा, जीवन में तनाव बढ़ेगा और मनुष्य का जीवन सघर्षमय बनेगा, इसे सब कारणों से हृदय रोग भविष्य में सामान्य रोग बन जायगा ।

(६) व्यावसायिक परिवर्तन : यह औद्योगिक क्रान्ति की शताब्दी है । इसमें उद्योग के साथ पैतृक जन्मजात बन्धन टूटे हैं । कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्योग-धन्धे को इच्छानुसार स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकता है । उद्योगों में तो मशीन प्रवेश कर हो गयी है । शिल्पकला में भी मशीनों के उपयोग की प्रवृत्ति प्रबल हाठी जा रही है । जो अभी तक अपने हाथ से काम करनेवाले धर्मिक थे वे अब मशीनों पर काम करके तकनीशियन कहलायेंगे और केवल मशीन को संचालित करके नियन्त्रण में रहेंगे । उत्पादन में प्रतियोगिताओं के कारण दक्षता की भाँग बढ़ेगी, तब शिल्लो अपनी दक्षता और कौशल बढ़ाने हेतु प्रयत्नशील रहेंगे । अब अध्यापन की प्रवृत्ति बढ़ेगी ।

(७) शैक्षणिक विस्तार : इस शताब्दी में शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है । शासन ने शालाओं की स्थापना में सहायक विस्तार किया है । अनेक उद्योग व्यवसायों तथा समाज सेवा संगठनों ने इसमें सक्रिय योगदान देकर शैक्षणिक सुविधाओं को विस्तृत बनाया है । इस विस्तार की गति से यह सुनिश्चित है कि आगामी २०, २५ वर्षों में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हो जायगी और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा भी सबके लिए सुलभ हो सकेगी । इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे देश की आबादी का लगभग एक चौथाई समाज आज से २०, २५ वर्ष बाद विद्यालयों में होगा । इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को शिक्षित करने के लिए मात्रिक उपकरणों, टेलीविजन सेटों व कम्प्यूटरों को प्रयोग में लाया जायगा । शिक्षण के स्थान पर सदृश होना और प्रत्येक छात्र अपनी-अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करके प्रगति करेगा ।

उक्त तथ्यों के आधार पर विद्यालय के सम्बन्ध में निम्नांकित निष्कर्ष निकलते हैं :

- १—विद्यार्थियों में शिक्षा-व्यवस्था इस प्रकार की हो, जिससे छात्र स्वाध्याय एवं स्वशिक्षण के लिए प्रेरित हो ।
- २—विद्यालयों में परिवर्तनशीलता ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए ।
- ३—विद्यार्थियों में छात्रों का शिक्षण इस प्रकार किया जाय कि वे बड़े होने पर विविध मूल्यों से युक्त समाज में सफलता से जीवन-यापन कर सकें ।

इनमें ऐसी क्षमता या आये कि ये नये परिवर्तनों के अनुरूप अपने आपको तेज कर सकें ।

४—विद्यालयों में सामान्य शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, दोनों की व्यवस्था आवश्यक है ।

५—सूचना के उत्पादन हेतु अनुसंधान-केन्द्रों तथा उपयोग के लिए विद्यालयों की स्थापना हेतु सविषय शास्त्री परिकल्पना करें ।

६—ज्ञान-विस्फोट के निपटने के लिए विद्यालयों में कम्प्यूटर की भाषा और तकनीक व्यवस्था आवश्यक है ।

७—विद्यालयों में ऐसी शिक्षा-व्यवस्था की जाय जिससे बालक विज्ञान जन्म दूषण और तकनीक युग के जीवन में सामंजस्य स्थापित कर सकें ।

हमारी शिक्षा की विशेषताएँ

(१) अभी तक ऐसी मान्यता है कि विद्यालय में कुछ निश्चित वर्षों तक प्राप्त की गयी शिक्षा जीवन भर के लिए ही पर्याप्त होती है किन्तु अब यह धारणा बदलनी होगी, क्योंकि नित नवीन आविष्कारों के परिणामस्वरूप ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है । अतः कोई भी विश्वासपूर्वक यह नहीं कह सकेगा कि उसे सब कुछ आता है । अब शिक्षा समयावधि में वृद्धि को छोड़कर जन्म से मृत्यु तक चलनेवाली प्रक्रिया बनेगी ।

(२) आज उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अर्द्धमूर्खी होने के साथ साथ सामान्य भी है । उसको उत्तीर्ण करने के पश्चात् बालक विश्वविद्यालयों, तकनीकी महाविद्यालयों या प्रशिक्षण-संस्थाओं में आते हैं । ११ वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् भी बालक कोई स्वतन्त्र उद्योग करने योग्य नहीं बनता है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि कक्षा ९ से छात्र को तकनीकी शिक्षा देकर स्वावलम्बी बनाया जाय ।

(३) धन और समय की वृद्धि परनेवाली पद्धतियाँ एवं साधनों की व्यवस्था विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में करनी होगी । प्रोजेक्टर, टेप रेकार्डर तथा पुस्तकें, पत्रिकाएँ आदि साधनों से ज्ञानागो को सुसज्जित करना होगा ।

(४) वर्तमान कक्षा-व्यवस्था, वर्गविभाजन-प्रणाली, शिक्षा-पद्धति एवं वाणिज्य परीक्षा द्वारा कक्षा-उन्नति की रुढ़िगत व्यवस्थाएँ समाप्त होंगी । इनके स्थान पर शिक्षण-विधि के आधार पर कक्षा की छान सख्या निश्चित की जायगी, अर्थात् यदि प्रसारण-कार्य एक तरफ शिक्षक की ओर से होगा तो

एक कक्षा में छात्र अधिक रह सकते हैं, यदि शिक्षक और छात्रों के बीच आदान-प्रदान आवश्यक है तो कक्षा में १५-२० छात्र रहेंगे।

(५) परीक्षा-पद्धति समाप्त करके समीक्षा के आधार पर छात्र को निजी क्षमता एवं उपलब्धियों के अनुसार प्रगति करने की सुविधा सुगम होगी।

(६) बालक को स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान और अभ्यास कराके स्वस्थ जीवन-यापन की कला से दस बनाना होगा ताकि वह वैज्ञानिक आविष्कारों के दूषण से बचकर स्वस्थ एवं सुखी जीवन यापन कर सके।

(७) मनोरंजन हमारे सुखी जीवन के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य है। भावी शिक्षा-व्यवस्था में बालक से स्वस्थ मनोरंजन को समझने और आनन्द लेने का सृजन होगा। उसकी रूचि इतनी अधिक परिपूरित बना दी जायगी कि उसे अच्छे साहित्य के अध्ययन से, अनुसंधान से, परोपकार में, सृजन तथा रचनात्मक कामों में, खेलों और स्काउटिंग आदि में आनन्द अनुभव होने लगे।

(८) आज के सघर्षमय जीवन में परिवार ही एक मात्र ऐसा स्थान रह गया है जहाँ व्यक्ति की निराशाओं और चिन्ताओं को कुछ सुखद अभिव्यक्ति मिल सकती है। बाल विकास की दृष्टि से तो परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। अतः शिक्षा के द्वारा बालक में पारिवारिक भावना का सृजन करना होगा।

(९) शिक्षा को बहारदीवारी से निकाल कर समाज के छेत, कल्याण, हाट-बाजार और कल-कारखानों पर ले जाना होगा। ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि बच्चे शांति में स्वाध्याय करें और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शाला से बाहर जा सकें।

(१०) शिक्षा के सस्यात्मक विकास के इस युग में यह आवश्यक है कि शिक्षा सबके लिए सुलभ हो। अतः ग्रहण शालाएँ, रात्रि शालाएँ, संचल शालाएँ तथा अल्पकालीन शालाओं की व्यवस्था करनी होगी।

आगामी २००० ईस्वी में शिक्षा-व्यवस्था के लिए अभी से नियोजन करना आवश्यक है। भविष्यशास्त्रियों को उस समय के समाज, आवश्यकताओं, जीवन स्तर और जीवनक्रम की कल्पना करके खरब निर्धारित करते रहेंगे। जनसंख्या वृद्धि-ज्ञान विस्फोट तथा औद्योगिक क्रांति के युग में शिक्षा-व्यवस्था हेतु पंचवर्षीय नियोजन के स्थान पर १० वर्षीय नियोजन करना अनिवार्य हो गया है।

मिता शिक्षा अधिकारी,
छतरपुर (म० प्र०)

डा० दामोदर शर्मा

सामुदायिक विकास और शिक्षा

मानव के सामाजिक इकाइयों में आवद्ध होने के समय से ही सामुदायिक विकास की प्रक्रिया जारी है, यह भिन्न बात है कि वही इसकी गति मन्द तथा कहीं द्रुत रही। अविकसित तथा अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में समुदायों के विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है, इसलिए उन्निवेगवाद के जुए से मुक्त होने पर, इन कोटि के राष्ट्रों ने बरने यहाँ सामुदायिक विकास की योजनाएँ बनाई हैं। सामुदायिक विकास के विवेचन से पूर्व 'समुदाय' शब्द के सामान्य अर्थ की विवेचना आवश्यक प्रतीत होती है, अतएव पहले इस पर विचार करना होगा।

समुदाय 'समुदाय एक जीवित सामाजिक संगठन है। यह केवल भौतिक जन-समूह ही नहीं है जो कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। बल्कि इस जनसमूह की समान सांस्कृतिक परम्परा भी होती है तथा इसके हितों में साम्य होता है। श्री एल० ए० कुबू ने 'समुदाय' के निम्नांकित आवश्यक तत्त्व माने हैं :

- (१) जन-समूह
- (२) निवास का सामीप्य
- (३) समान सांस्कृतिक परम्परा
- (४) स्थानीय एकाता की चेतना
- (५) सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकजुट होकर कार्य करना
- (६) बुनियादी सेवा-संस्थाओं का समूह

अभिप्राय यह है कि एक ऐसा जनसमूह ही समुदाय की संज्ञा प्राप्त कर सकता है जो निरुद्ध रहते हुए समान सांस्कृतिक परम्परा से आवद्ध है तथा जिसके समान हित हैं जिनकी पूर्ति के लिए वह एकजुट है। इस परिभाषा के आधार पर समुदायों के प्रकारों का विवेचन किया जा सकता है किन्तु यह यहाँ विवेच्य नहीं है। यहाँ मुख्य विवेच्य 'सामुदायिक विकास' है।

सामुदायिक विकास : सामुदायिक विकास का प्रमुख लक्ष्य समुदाय विशेष का सर्वांगीण विकास करना है। संसार के विभिन्न देशों में सामुदायिक विकास का भिन्न-भिन्न इतिहास है। भारतवर्ष में ग्रामीण समुदाय को आधार मानकर सामुदायिक विकास योजना का श्री गणेश २ अक्टूबर, १९५२ को किया गया तथा समुदाय की सबसे छोटी इकाई ग्राम को माना गया, जिसमें १०० परिवार या ५०० व्यक्ति हों। प्राचीन भारत में जबकि ग्राम आत्मनिर्भर थे, तथा वैभव एवं समृद्धि के केन्द्र थे, तो भारत की श्री संसार में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था और जब इन ग्रामों में ही निर्धनता, अज्ञानता तथा पराबलम्बन का साम्राज्य हो गया तो इनके पुनर्निर्माण हेतु सामुदायिक विकास की योजना को चुना गया। प्रारम्भ में हमारा नेतृत्व इसके प्रति बहुत आशावादी रहा। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व० प० जवाहरलाल नेहरू ने एक अवसर पर इसे अद्भुत एवं आश्चर्यकारी योजना बताया।

सामुदायिक विकास के सामान्य उद्देश्य और शिक्षा : संयुक्त राष्ट्र संघ ने कार्य व्यापार के लिए सामुदायिक विकास की परिभाषा स्वीकार करते हुए इसे यह प्रक्रिया बताया है जिसमें उस समुदाय के व्यक्ति अपने प्रयासों की सरकारी अधिकारियों के साथ सगठित कर समुदाय की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशा में सुधार का प्रयास करते हैं, जिससे वे समुदाय को राष्ट्रीय जीवन से तादात्म्य स्थापित कर, राष्ट्रीय उत्थति से अपना पूर्ण योग प्रदान कर सकें। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास का लक्ष्य समुदाय का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा का लक्ष्य यहाँ

व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है वहाँ सामुदायिक विकास का लक्ष्य समुदाय का सर्वांगीण विकास है। इस तरह शिक्षा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आधार-शिला मानी जा सकती है क्योंकि समुदाय की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है जिसके सर्वांगीण विकास का दायित्व शिक्षा का है। यदि इस लघु इकाई का विकास हो गया तो समुदाय का विकास भी निश्चित है। सामुदायिक विकास की प्रक्रिया समुदाय की पारम्परिक जीवनशैली में परिवर्तन कर उसे प्रगतिशील जीवन शैली की ओर ले जाती है। यह सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप जब तक शैक्षिक कार्यक्रम में परिवर्तन नहीं होता तब तक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। अतएव शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का घनिष्ठ सम्बन्ध है।

सामुदायिक विकास के आधार एवं शिक्षा - सामुदायिक विकास के कुछ आधार हैं जिनके सुदृढ़ हुए बिना सामुदायिक विकास के कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। इन आधारों को सुदृढ़ बनाने में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योग हो सकता है, जैसा कि आगे की बातों से स्पष्ट होगा।

मनोवृत्ति में वाछनीय परिवर्तन - सामुदायिक विकास का प्रमुख लक्ष्य समुदाय की पारम्परिक जीवन से हटाकर प्रगतिशील जीवन की ओर अग्रसर करना है। इस प्रकार के परिवर्तन के लिए समुदाय के जनों की मनोवृत्ति में वाछनीय परिवर्तन परमावश्यक है। शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति की मनोवृत्ति में सदासम्भव वाछनीय परिवर्तन कर, उसका बदलते हुए परिवेश के प्रति अनुकूल करना है।

नेतृत्व का विकास - ग्रामीण समुदाय के लिए बाहर के व्यक्तियों का नेतृत्व थोड़ा समय के लिए मिल सकता है। एक सीमा तक बाहर से आये हुए ये अधिकारी उनके विकास में सहायता कर सकते हैं, किन्तु अन्ततः सामुदायिक विकास के नेतृत्व की बागडोर समुदाय के व्यक्तियों को स्वयं सम्भालनी होगी। इसके अभाव में समुदाय का विकास अवरुद्ध हो जायगा। व्यक्ति में नेतृत्व के गुणों का विकास करना—यह शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। शिक्षा के माध्यम से समुदाय के उस अभाव को पूर्ति सम्भव हो सकेगी और सामुदायिक विकास इस उद्देश्य की पूर्ति में शिक्षा का यह महत्वपूर्ण योगदान होगा।

आत्मनिर्भरता की भावना का विकास : विकासशील समुदाय में आत्मनिर्भरता की भावना का जगाना अत्यावश्यक है। इस प्रकार पूर्णतः आत्मनिर्भर

अर्थ में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तो इस युग में व्यावहारिक नहीं है किन्तु अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य समुदाय को स्वयं करना होगा। परावलम्बन उत्पत्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। शासन पर आधित रहने की वृत्ति का परित्याग करके ही समुदाय विकास कर सकता है। शिक्षा को आत्मनिर्भरता प्राप्ति की दिशा में कार्य करना चाहिए। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि केवल पुष्पकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा। हमें उस शिक्षा को आवश्यकता है जिससे कि व्यक्ति अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सके।

नागरिकता की भावना का विकास : समुदाय के जन अपने अधिकार तथा कर्तव्यों के प्रति सचेत हों—उनमें सामाजिक एवं राजनीतिक उत्तरदायित्व की भावना हो—वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के विषय में जागरूक हो तभी राष्ट्रीय जीवन सुचारु रूप से चल सक्ता है। लोकतन्त्रात्मक समाज में तो इस भावना का विकास अत्यावश्यक हो जाना है, अतएव लोकतन्त्र में नागरिकता की शिक्षा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। यदि शिक्षा नागरिकता का प्रशिक्षण देने में असफल हो जायगी तो लोकतन्त्र भी असफल हो जायगा। प्लेटो ने तो नागरिकता की शिक्षा देनेवाली शिक्षा को ही शिक्षा माना है। हारन ने भी शिक्षा के आदर्शों में नागरिकता के प्रशिक्षण को प्रमुख माना है।

नैतिक चरित्र का विकास जिस समुदाय में नैतिक चरित्र विद्यमान है वह समुदाय कभी भी पतनोन्मुख नहीं हो सकता। यह किसी समुदाय की नहीं अपितु राष्ट्र की महान निधि है। समुदाय के विकास का भव्य भवन इसी के ढाँचों पर खड़ा रह सकता है। अतएव समुदाय के जनों का चारित्रिक तथा नैतिक विकास होना या इस दिशा में प्रशिक्षण अत्यावश्यक है। किसी भी समुदाय के शिक्षा तन्त्र का यह दायित्व है कि वह इसके लिए वातावरण तैयार करे और अपने कार्यक्रम के माध्यम से चरित्रवान तथा नैतिक व्यक्ति तैयार करे, क्योंकि डॉ॰ राधाकृष्णन् के अनुसार चरित्र भाग्य है। चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्र के भाग्य का निर्माण होता है। तुच्छ चरित्रवाले मनुष्य श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हरबर्ट के अनुसार शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। वस्तुतः शिक्षा का मुख्य लक्ष्य चरित्र का प्रशिक्षण ही होना चाहिए, जैसा कि प्लेटो ने कहा है, "शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य और कार्य मानव-प्रकृति और चरित्र को प्रशिक्षित करना है।" वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षा अपने इस मूल उद्देश्य को भूलकर मानसिक

विकास पर हो अपना सारा बल दे रही है। यही सब कठिनाइयों का कारण है। डा० राधाकृष्णन् ने इसी तथ्य को अच्छी तरह स्पष्ट किया है।

सांस्कृतिक विकास : समुदाय की एकरा या मूल उसी समान सांस्कृतिक परम्परा है। इसलिए सांस्कृतिक चेतना को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक विकास किया जाय। सांस्कृतिक विशेषताओं को अक्षुण्ण रखने हुए, सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप सांस्कृतिक विकास जारी रह—इस हेतु यह आवश्यक है कि कोई ऐसा माध्यम हो जो इस कार्य को सुचारु रूप से चला सके। शिक्षा से अधिक उत्तम अन्य कोई माध्यम हम शिक्षा में नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा का कार्य है कि समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को, अपने तरुण एवं शक्तिशाली सदस्यों को प्रदान करे।

शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा 'शरीर माघसप्त धर्म साधनम्' व धर्मार्थ काम मोक्षाना आरोग्यम् मूल मुल्यम्।' ये दो सूत्र हम बात के प्रमाण हैं कि स्वस्थ शरीर के बिना कोई भी कार्य अच्छे ढंग से सम्पन्न नहीं हो सकता, सारे कार्यों का साधन शरीर है इसलिए समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक स्वस्थ हो, प्रत्येक व्यक्ति सन्तुष्ट हो। सभी सामुदायिक विकास सम्मन है। हमारे यहाँ एक लोकोक्ति है कि 'बहुला सुख निरोगी काया'—निरोग शरीर को गुलों में प्रथम स्थान दिया है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य की महत्ता स्पष्ट होती है। दूसरी बात यह है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क भी रहता है। इसलिए इस दृष्टि से भी सामुदायिक विकास के कार्यक्रम में शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। सामुदायिक विकास के इस कार्यक्रम में शिक्षा का कार्यक्रम बहुत सहायक होगा, क्योंकि व्यक्ति का शारीरिक विकास भी शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्यों में से एक है।

ज्ञान का विकास ज्ञान के विकास के लिए प्रथम कार्य साक्षरता-प्रसार माना जा सकता है। साक्षरता ज्ञान का साधन हो सकती है। ज्ञान का माध्यम मस्तिष्क है जो कि ज्ञान का ग्राहक है, शरीर का सर्वश्रेष्ठ अंग है। इसके विकास के बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता। इसलिए व्यक्ति का मानसिक विकास उसके ज्ञान में वृद्धि, सामुदायिक हित एवं विकास के लिए अत्यावश्यक है। मानसिक विकास ही मानव को प्राणि-जगत में श्रेष्ठता प्रदान करने वाला है। इसलिए यदि सामुदायिक विकास जारी रखना है तो मानसिक विकास का कार्यक्रम भी जारी रखना होगा।

इसका एकमात्र माध्यम शिक्षा है। भारतवर्ष में प्राचीनकाल में तो शिक्षा का अर्थ ज्ञान प्रदान करवा या मानसिक विकास हो रहा। अब भी हम अधिक जोर मानसिक विकास या ज्ञान पक्ष पर ही देते हैं। प्रो० हुमायूँ कबीर ने ज्ञान प्राप्ति की शिक्षा के उद्देश्य को वैयक्तिक तथा सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक माना है। साक्षरता एवं समाज-शिक्षा से लेकर ज्ञान के उच्चतम स्तर की शिक्षा का प्रावधान सामुदायिक विकास के लिए आवश्यक है।

आर्थिक विकास आज के इस भौतिक युग में अर्थ का ही प्राधान्य है—'सर्वे शुभा काचन भाभयन्ति।' जिसके पास पैसा है या जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है वह व्यक्ति धोखे है, गुणवान है। वह समुदाय श्रेष्ठ समुदाय है विकसित समुदाय है जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है। अभिप्राय यह है कि सब चीजों का मापदण्ड पैसा ही रह गया है। इसके बिना कोई सासारिक कार्य सम्भव नहीं है। इसलिए सामुदायिक विकास की योजनाएँ बनाते समय आर्थिक विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया और इस हेतु ग्रामीण समुदाय के प्रमुख उद्योग कृषि की उन्नति की बहुमुखी योजनाएँ बनायी गयी और इनमें काफी सफलता भी मिली है। किन्तु मुख्य समस्या यह रही कि हम कृषि तथा कृषि पर आधारित अन्य उद्योगों के प्रति ग्रामीण समुदाय के तथाकथित प्रबुद्ध एवं शिक्षित वर्ग को अधिक आकृष्ट नहीं कर सके। यह वर्ग सामुदायिक विकास इस कार्यक्रम में अपना योगदान नहीं कर पाया। जिसका परिणाम हुआ, समुदाय के आर्थिक विकास की गति धीमी होना। यदि शिक्षा की समुदाय की आवश्यकताओं से जोड़ा जाता, समुदाय के जीवन से जोड़ा जाता, तो यह स्थिति नहीं उत्पन्न होती। शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर ही शिक्षा के व्याव-सयीकरण की जो बात आज ओरों से की जा रही है तथा अभी पाचवी पंच वर्षीय योजना के लिए प्रस्तुत ब्युजिट में भी की गयी है, यदि इसे व्यावहारिक रूप दिया जाय तो समुदाय के आर्थिक विकास की गति बहुत तीव्र हो जाय तथा साथ ही शिक्षण वेरोजगारी की जिस विकट समस्या से हम परेशान हैं, वह भी कुछ हद तक हल हो जाय। और यह छात्र-आक्रोश भी जो कि देश के नेतृत्व की चिन्ता का महान विषय है—समाप्त हो जाय। अभिप्राय यह है कि शिक्षा को समुदाय की आवश्यकताओं से जोड़ना होगा, सामुदायिक जीवन से जोड़ना होगा, तभी समुदाय की एवं अन्ततोगत्वा राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि सम्भव है, अन्यथा नहीं। यदि यह जल्दी से सम्भव नहीं हो पाया तो इस प्रकार का विस्फोट होगा जो सारे जनतन्त्रीय आधार को हिला देगा। अभी

१६ दिसम्बर, १९७२ को नागपुर निव्विद्यालय के ५६वें दोहात समारोह के अवसर पर बोले हुए प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री तथा गुजरात के राज्यपाल श्री श्रीमधारायण ने कहा कि "शिक्षा को देश के विवास से जोड़कर शिक्षा के क्रान्तिकारी परिवर्तन साने होंगे अथवा शिक्षा के क्षेत्र में यह विस्फोट हागा जो सारे जनतन्त्रीय आधार की मण्ट बर देगा ।" इस प्रकार शिक्षा का आर्थिक विकास से जो सम्बन्ध है उसे भुनाया नहीं जा सकता ।

सामुदायिक विवास के प्रमुख आधार एव सद्यों के साथ शिक्षा का पनिष्ठ सम्बन्ध है, यह उरयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है । सामुदायिक विवास का कार्यक्रम किसी भी देश में बनाया जाय, उरयुक्त आधार एव सदय उस कार्यक्रम को यनाते समय सामने रखने हों होंगे । उदाहरण के लिए भारतवर्ष में सामुदायिक विवास के कार्यक्रम को ले ले स्पष्ट होता है कि कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो आर्थिक विकास के लिए हैं—जैसे कृषि-उत्पादन बढ़ाना, कुटीर उद्योगों का विकास यातायात के साधनों का विवास इत्यादि, तो कुछ ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध सांस्कृतिक विकास, समाज बर्याण से है । एक दूसरा वर्ग ऐसा है जिसका मानसिक विकास या ज्ञान के विवास से है, जिन्हें शिक्षा के कार्यक्रम भी कहा जा सकता है । सामुदायिक विवास कार्यक्रम में इन वर्गों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि सामुदायिक विकास का सदय समुदाय की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वास्थ्य सम्बन्धी एव ज्ञान सम्बन्धी उन्नति कर उसका सर्वांगीण विवास करना है । शिक्षा का सदय भी जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास (मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, आर्थिक आदि) करना है । इस तरह सामुदायिक विकास जहाँ पूरे समुदाय के सर्वांगीण विकास को सामने रखकर चलता है, वहाँ शिक्षा समुदाय के समुत्तम घटक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सामने रखकर, सामुदायिक विकास की आधारशिला तैयार करती है, इसलिए शिक्षा को, सामुदायिक विकास में कार्यक्रम को ध्यान में रखकर ही, अपना कार्यक्रम तय करना चाहिए सभी यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हो सकेंगी और सभी सही शिक्षा कहाने की अधिकारिणी भी होगी । केवल ज्ञान के उद्देश्य को पूरी करनेवाली शिक्षा इस युग में शिक्षा नहीं कही जा सकती । ●

श्री० टी० टी० कालेज, सरदारनहर

राष्ट्रीय शिक्षा

एक सर्वोदयी दृष्टिकोण

[अक्टूबर १४, १५ और १६, १९७२ की वर्षा में राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके ठीक पहिले सर्व सेवा सघ प्रबन्ध समिति की कलकत्ता में बैठक थी। इस बैठक में एक सुझाव आया कि शिक्षा के सम्बन्ध में सर्वोदयी दृष्टिकोण सम्मेलन के आयोजन कर्ताओं के पास भेजा जाय। इस कार्य के लिए सचची सिद्धराज डड्डा ठाकुरदास बग आचार्य राममूर्ति, बरीधर श्रीवास्तव, पूर्णचन्द्र जैन श्यामकृष्ण और के० एस० आचार्य की एक उपसमिति बनायी गयी। यह टिप्पणी उसी उपसमिति द्वारा तैयार की हुई है।—सम्पादक]

१ उद्देश्य

शिक्षा की वर्तमान प्रणाली की सबत्र निन्दा हुई है लेकिन इसे बदलने और इसे मानवीय एवं राष्ट्रीय विकास का उपयुक्त साधन बनाने के लिए अधिक प्रयास नहीं किया गया है। हम लोकतन्त्र और समाजवाद के प्रति प्रतिबद्ध हैं जिसका हमारे लिए अर्थ है अहिंसात्मक एक ऐसे समाज का निर्माण जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त हो गया हो। हमारी मान्यता है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक तथा सस्थागत दोनों प्रकार की शिक्षा से थकड़ा और कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता।

२. परिवर्तन सम्बन्धी सुझाव

हमारा सुझाव है कि शिक्षा-प्रणाली में निम्नोक्त परिवर्तन घुसना जिये जायें

१ शिक्षा की विषय वस्तु

पाठ्यक्रम में सभी स्तरों पर सुधार होना चाहिए। पाठ्यक्रम प्रत्येक स्तर पर शिक्षार्थी में जो कुछ सर्वोत्तम है उसे उद्घाटित करनेवाला अवसर हो। अतएव, उसका सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादन क्रिया तथा क्षेत्र के सामाजिक तथा प्राकृतिक परिवेश से अभिन्न रूप से सम्बन्धित होना चाहिए। सभी स्तरों पर काम एवं उपसम्पन्न के निदिष्ट सदैव सुनिश्चित किये जायें।

२ विज्ञान व प्रविधि

विज्ञान व प्रविधि मुख्यतः उत्पादन क्रिया, ज्ञान के दैनिक कार्य व क्षेत्र के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के चारों ओर केन्द्रित हो।

३ सभी बच्चों के लिए न्यूनतम शिक्षा

सभी बच्चों को कम से कम १० वर्षों की शिक्षा उपलब्ध हो। शिक्षार्थी की सारी शालीय शिक्षा ३ वर्ष की उम्र से १८ वर्ष की उम्र तक १५ वर्षों की हो। प्रारम्भिक शिक्षा में पहली से आठवीं कक्षा तक का समावेश हो जो सबके लिए निशुल्क हो। माध्यमिक शिक्षा नवीं से बारहवीं कक्षा तक की हो। इसके बाद विश्वविद्यालयीय शिक्षा का क्षेत्र है।

हम की आस (लिखना, पढ़ना व छोड़ी गणित) उन्मुख शिक्षा का बहिष्कार व सुनियोजित शिक्षा के सावधानीपूर्ण से माय सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। आधुनिक समाज में शिक्षा को हम किसी सस्या की चहारदीवारी में परिधीमित नहीं कर सकते। उसे सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन के अधिक विस्तृत क्षेत्रों में प्रवाहमान होना ही चाहिए।

४ माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा बहुमुखी तथा विशेषज्ञतापूर्ण होनी चाहिए।

५ उच्च शिक्षा

उच्चशिक्षा योग्यता व जिज्ञासा की दृष्टि से उचित मात्र तक ही सीमित होनी चाहिए।

६ प्रत्येक स्तर पर अपने में पूर्ण पाठ्यक्रम

इन तीनों (प्राथमिक, माध्यमिक व विश्वविद्यालयीय) में से प्रत्येक स्तर

पर पाठ्यक्रम यदि अपने में पूर्ण नहीं तो निर्दिष्ट सत्रवाला हो। कोई स्तर जानेवाले दूसरे स्तर के लिए तैयारी मात्र न माना जाय।

७. उपाधियाँ और नौकरियाँ

मौलिक सुधार के एक कदम के रूप में हम शैक्षिक उपाधियों का अखिल भारतीय सहित सभी प्रकार की नौकरियों से तुरन्त सम्बन्ध-विच्छेद की सन्तुति करते हैं।

८. सामान्य शाला-प्रणाली

हम एक 'सामान्य शाला-प्रणाली' का सुझाव देते हैं जिसमें प्रयोग की पूरी स्वतन्त्रता हो। भिन्न भिन्न या आवधिक वर्गों के लिए अलग से स्कूल न हो और, निजी लाभ या वर्ग, जाति या सम्बन्ध अछूता के पोषण के लिए किसी शैक्षिक-संस्था को चलाने की सुविधा न दी जाय। सभी शालाओं के सामान्य लक्षण ये हों : फीस का एक-सा तरीका, मातृ या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा व समाज-सेवा तथा सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक क्रिया में सहायक प्रशिक्षण का एक क्रमबद्ध कार्यक्रम।

९. व्यवस्था में स्वायत्तता

शैक्षिक-संस्थाएँ स्वायत्त स्थापना हो जिन्हें वही चलायें और जिनकी वही व्यवस्था करें जो उससे सर्वाधिक सम्बद्ध हों, यानी, अभिभावक, शिक्षक और शिष्याएँ।

३. राज्य और शिक्षा

शिक्षा राज्य द्वारा हस्तक्षेप तथा नियंत्रण के मामले में कम-से-कम उतनी स्वतन्त्र हो जितनी न्यायपालिका। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के दो महत्त्वपूर्ण कार्य हैं—आविक सहायता व समन्वयन जिसके लिए स्थानीय, जिले, राज्य व राष्ट्र के स्तरों पर संयुक्त समन्वय बनाये जा सकते हैं। पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त किया जाना चाहिए।

४. परीक्षा-प्रणाली

हम परीक्षाओं की वर्तमान प्रणाली को समाप्त करने की सन्तुति करते हैं। इसके स्थान पर शाला के पहले वर्ष से लेकर उसके अन्त तक लगातार मूल्यांकन की प्रणाली चलायी जाय। प्रत्येक स्तर को समाप्त पर शिष्याओं के व्यक्तित्व और विभिन्न विषयों में उसकी प्रगति, रुचान तथा जानकारी बताने वाला प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाय।

५ शिक्षा व सामाजिक न्याय

गहरी गदी बस्तियों व मुदूर गाँवों के निम्न आय-वर्गों से आनेवाले बच्चों को विशेष सुविधाएँ दी जायें। छात्रवृत्तियों व बपट तथा पुस्तकों की व्यवस्था गरीब बच्चों को समस्या का समाधान नहीं है। उनकी आवश्यकता है, जैसा कि सभी बच्चों की होनी चाहिए ऐसी शिक्षा की प्राप्ति जो उन्हें उनकी धार्मिक व सामाजिक स्थिति से उछाड़ न फेंके बल्कि उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ कमाई साधन बनाये। इस सम्बन्ध में एक या दो घण्टे के स्कूल उपयोगी हो सकते हैं।

६ सामाजिक शक्ति के रूप में शिक्षा

हमें इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि लोकतन्त्र की सकलता निम्नांकित पर निर्भर है

- (क) व्यक्तियों का स्वायत्त तथा आरम्भ निर्भर रूप में विकास और,
- (ख) व्यवस्था बनाने व निणय देनेवाली स्थानीय इकाइयाँ।

इसलिए शिक्षा सभी व्यक्तियों व उनके विभिन्न क्रिया-क्षेत्रों को अपने में समाविष्ट करनेवाली हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह एक निरन्तर प्रक्रिया हो। हमारे विकास कार्यों की योजना शक्ति के रूप में हो और उनके क्रिया-क्षेत्र में हमारे स्कूल सक्रिय रूप से लगे। इसकी आवश्यकता है कि हमारे देश के नागरिक सहभागिता स्वतन्त्र राय लोकतान्त्रिक असहमति, सर्वसम्मति या सर्वानुमतिपूर्ण निर्णय अधिकार के दुरुपयोग पर अहिंसात्मक प्रतिरोध व समानता तथा अच्छे पड़ोसीपन पर आधारित सहकारी जीवन पद्धति में दक्ष बनें। शिक्षा व लोकतन्त्र के इस युग में शिक्षा एक विधायक सामाजिक शक्ति के रूप में परिकल्पित की जाय। हम शिक्षा की केवल जीवन के लिए ही नहीं बल्कि उसे सम्पूर्ण जीवन का समावेश करनेवाली क्रिया उसे ही जीवन समझते हैं। हमारा विकासशील राष्ट्र इससे कम से सन्तुष्ट हो यह गुजाइश नहीं है।

आचार्यकुल की गतिविधि

मध्य प्रदेश आचार्यकुल कार्यकारिणी की बैठक

ब्रह्मविद्या मन्दिर, पवनार में गत १५ जनवरी ७३ की हुई मध्य प्रदेश आचार्यकुल कार्यकारिणी की बैठक के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे

गत दो मास की प्रगति का विवरण ग्वालियर में शिक्षा सगोष्ठी दो दिन ११ और १२ नवम्बर ७२ को सम्पन्न हुई। टीकमगढ़ जिला आचार्यकुल का सम्मेलन हुआ। छिन्दवाड़ा में जिला आचार्यकुल की बैठक की थी ग० उ० पाटणकर ने सम्बोधित किया। वहाँ ११८ सदस्य नये बने हैं। विलासपुर में श्री नमदा प्रसाद शर्मा ने रामपुर में डा० सरयूबात शा ने और जबलपुर में श्री गणेश प्रसाद नायक ने तथा श्री रामकुमार शर्मा ने विविधा सागर और छिन्दवाड़ा में आचार्यकुल के काम को विस्तार दिया। आचार्यकुल की ओर से सर्वोदय विचार प्रारम्भिक परीक्षा के काम ग्वालियर से भराये गये हैं।

- वर्ष ७३ ७४ के बजट पर चर्चा हुई और तय किया गया कि चूँकि अभी तक तदर्थ समिति काम कर रही थी और सगठन की शुद्धता ही थी इसलिए कम बजट में काम चला लेकिन वर्ष ७३ ७४ का बजट ६० दस हजार की मर्यादा में बनाया जाय। इसके लिए सयोजक को अधिकृत किया गया कि वह मध्य प्रदेश सर्वोदय मण्डल के मंत्री से पत्र-व्यवहार करके इस वर्ष जिन ग्रामस्वराज्य समितियों से १०० रु० की वर्ष ७२ ७३ की धनराशि नहीं आयी है वह पुन लिखकर भेगाई जाय और आगामी वर्ष श्री वर्ष ७३ ७४ में इस प्रकार का सहयोग प्राप्त किया जाय।

यह भी तय हुआ कि मध्य प्रदेश सर्वोदय मण्डल अभी तक जो ₹० १००० ₹० वार्षिक की सहायता देता था, वह आचार्यकुल के वार्षिक के विस्तार को देखते हुए ₹० ३००० ₹० की वार्षिक सहायता स्वीकार करे।

- प्रादेशिक स्वाध्याय योजना में योगदान देने की दृष्टि से प्रत्येक आचार्यकुल केन्द्र पर एक स्वाध्याय केन्द्र की स्थापना की जाय और वर्ष १९७३ में दूसरी बार सर्वोदय-विचार प्रारम्भिक परीक्षा के आयोजन में मदद की जाय। इस सन्दर्भ में प्रादेशिक स्वाध्याय समिति ने सयोजक तथा मध्य प्रदेश सेवक संघ के मंत्री श्री बनवारी लाल चौधरी ने सुझाव दिया कि प्रत्येक आचार्यकुल-केन्द्र तथा प्रत्येक आचार्यकुल सदस्य को ₹० ६० में ₹० ६० मूल्य का सर्वोदय साहित्य और ₹० ६० में ₹० ६० मूल्य की सर्वोदय-विचार पत्रिकाएँ मध्य प्रदेश सेवक संघ, ग्राम १०० रंसलपुर, होशंगाबाद (म० प्र०) के पते पर लिखकर प्राप्त की जा सकती हैं।
- जिन जिलों में अभी आचार्यकुल के काम की शुरुआत नहीं हुई है उनमें उस क्षेत्र के सम्मागोय प्रतिनिधि, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, विशेष प्रयत्न करें और सम्मागोय प्रतिनिधिगण वर्ष १९७३ में प्रत्येक काम-से-काम १००० सदस्य बनवायें।
- श्री रामकुमार वर्मा ने सुझाव रखा कि प्रदेश की अशासकीय शिक्षण-संस्थाओं की समस्याओं का सर्वेक्षण करके उसकी विस्तृत रिपोर्ट अगले मध्य प्रदेश आचार्यकुल सम्मेलन के अवसर पर रखी जाय और यह प्रयत्न किया जाय कि अशासकीय शिक्षण-संस्थाएँ अपनी प्रभुसत्ता को कायम रखकर नयी तालीम की दिशा में अपना योग दे सकें।
- डाइरेक्टरी मध्य प्रदेश आचार्यकुल १९७३ का प्रकाशन मध्य प्रदेश आचार्यकुल १९७३ की डाइरेक्टरी में प्रकाशनाय सभी जिलों से ३१ दिसम्बर, '७२ तक बने सदस्यों के नाम और पते पिछले माह माँगे गये थे। डाइरेक्टरी में आचार्यकुल सदस्यों के नाम जित्तवार रहेंगे और यह नि शुल्क सदस्यों को प्राप्त होगी।

गुदमरण,

सयोजक,

मध्य प्रदेश आचार्यकुल

‘नयी तालीम’

मासिक का प्रकाशन चकत्तव्य

समाचार पत्र पञ्जीकरण अधिकरण (धार्म नं० ४, नियम ८) के अनुसार हर एक पत्रिका के प्रकाशक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के साथ-साथ अपनी पत्रिका में भी यह प्रकाशित करना पड़ता है । तदनुसार यह प्रति-निधि यहाँ दी जा रही है ।

—सम्पादक

- | | |
|---------------------|--|
| १. प्रकाशन का स्थान | वाराणसी |
| २. प्रकाशन का समय | माह में एक बार |
| ३. मुद्रक का नाम : | श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| पता . | नयी तालीम, मासिक, राजघाट,
वाराणसी-१ |
| ४. प्रकाशक का नाम | श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट |
| राष्ट्रीयता : | भारतीय |
| पता | नयी तालीम, मासिक, राजघाट,
वाराणसी-१ |
| ५. सम्पादक का नाम | (I) श्री धीरेन्द्र मरूपशर |
| | (II) श्री बंशीधर श्रीवास्तव |
| | (III) आचार्य राममूर्ति |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| पता . | नयी तालीम, मासिक, राजघाट,
वाराणसी-१ |
| ६. समाचार पत्र के | सर्व सेवा सच, गोपुरी, बर्धा (महाराष्ट्र) |
| संवालों का नाम | (सन् १८६० के सीसण्टी रजिस्ट्रेशन |
| व पता : | एक्ट २१ के अनुसार रजिस्टर्ड मार्बजनिक् |
| | संस्था) रजिस्टर्ड नं० ५२ |

मैं, श्रीकृष्णदत्त भट्ट, यह स्वीकार करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है ।

वाराणसी,
२८-२-७३

श्रीकृष्णदत्त भट्ट
प्रकाशक

सम्पादक गण्डल :

श्री घीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक

श्री वंशीधर श्रीवास्तव

आचार्य राममूर्ति

वर्ष : २१

अंक : ७

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

नयी तालीम और पुराना समाज

घूरेवाली बिद्या ?

२८९ सम्पादकीय

बिहार में राजकीय घनाम अराजकीय

माध्यमिक शिक्षक

२९१ रामचरित्र

तीसरी दुनिया की करुण कहानी

२९४ नरेन्द्र दुबे

युवा आक्रोश भविष्य क्या है ?

२९८ सतोप भारतीय

हिन्दुस्तान की सब भाषाओं के लिए

नागरी लिपि भाग्य हो

३०० विनोबा

सर्पोदय-शिक्षा-दर्शन

३०२ तिलोकचन्द्र

लोक-भारती ग्राम-उच्च विद्या का प्रयोग

३०५ मनुमाई पञ्चोली

ईसवी सन् २००० में शिक्षा

३१५ प्रेमनारायण कसिया

सामुदायिक विकास और शिक्षा

३२२ डॉ० दामोदर शर्मा

राष्ट्रीय शिक्षा

३२९

आचार्यकुल की गतिविधि

३३३

फरवरी, '७३

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्द्रा आठ रुपये हैं और एक अंक के ७० पैसे ।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट, द्वारा सर्व सेवा सम के लिए प्रकाशित;

पनोहर प्रेस, छतनगर, वाराणसी में मुद्रित

मयी तांसीम ३ फरवरी, '७३

एहिने मे शक-अवय दिवें भेजने की स्वीकृति प्राप्त

लाइसेंस नं० ४६

रजि० सं० एत० १७२३

श्री गांधी आश्रम द्वारा

महोदय-साहित्य-सेट रियायत-अवधि बढ़ी

अब यह रियायत ३१ मार्च '७३ तक मिलेगी

श्री गांधी आश्रम, उत्तर प्रदेश की ओर से सर्व सेवा संघ-प्रकाशन के सर्वोदय-साहित्य-सेटों पर बिना खादी खरीदे भी रियायत दी जाती रही है। अब तक रियायत २२ फरवरी '७३ तक थी। अभी अकबरपुर की श्री गांधी आश्रम की बैठक में तय हुआ है कि यह रियायत अब ३१ मार्च १९७३ तक दी जायगी।

पाठकों से अनुरोध है कि इस सुविधा का लाभ उठाकर सर्वोदय-साहित्य-सेट खरीदकर अपने घर की लायब्रेरी की शोभा बढ़ायें। गांधी आश्रमों के खादी भण्डारों पर :

११ रुपये का साहित्य-सेट

११ रुपये में

१५ रुपये

६ रुपये में

२५ रुपये

११ रुपये में

एतद् मेरुद, एतद् प्रकाशन, एतद् एतद् की ओर से प्रसारित

नयी तालीम

सर्व सेवा-मण की शक्ति

वर्ष : २१

अंक : ८

- सत्य ही शिक्षक की सत्ता
- शिक्षा-पद्धति कैसी है ? कैसी होनी चाहिए ?
- सरकारी नौकरियों से डिग्री का सम्बन्ध-विच्छेद हो
- अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए नये तरीके

मार्च १९७३

शिक्षा की स्वायत्तता—एक अविभाज्य इकाई है

बर्ट्रैंड रसेल ने अपनी “विस्डम ऑफ़ दी वेस्ट” नाम की पुस्तक में एक जगह लिखा है— “स्वतंत्र चिंतन का जहाँ अन्त हो जाता है, इसका कारण साहस की कमी हो अथवा अनुशासन का बंधन, अनुचित प्रचार और सत्तावाद के अंकुर यही मुक्तभाव से बनपने लगते हैं।” अतः शिक्षक को स्वतन्त्रापूर्वक मुक्त भाव से अपने को व्यक्त करने का अवसर मिलना ही चाहिए। शिक्षक की स्वतन्त्रता का अर्थ इतना ही है कि वह स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचारों को व्यक्त कर सके। किसी अध्यापक से न तो यह अपेक्षा की जा सके और न उसे यह आदेश दिया जा सके कि वह छात्रों को ऐसी कोई बात पढ़ाये जो उसकी अन्तरात्मा के प्रतिकूल हो। शिक्षक की स्वतन्त्रता का अर्थ है कि वह अपने विचारों पर दृढ़ भी रह सकता है यद्यपि कि यह शिक्षण को अपने विशिष्ट विचारों के प्रचार का या पक्षपोषण का साधन न बनाकर किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल दे। इस प्रकार की स्वतन्त्रता तब तक सम्भव नहीं है जब तक शिक्षा-संस्थाएँ स्वायत्त नहीं होती। “यह निश्चित है कि दल अथवा सत्ता के दबाव से मुक्त रहनेवाली स्वायत्त शिक्षा-संस्थाएँ ही निर्भयतापूर्वक सत्य का सन्धान कर सकती हैं और अपने अध्यापकों और छात्रों में स्वतंत्र चिंतन और जिज्ञासा की भावना पैदा कर सकती हैं। अतः यह निश्चय कर

वर्ष : २१

अंक : ८

लेना चाहिए कि विश्वविद्यालयों पर शासन अथवा प्रशासकों का प्रभुत्व न हो पावे । और यदि प्रभुत्व होना ही है तो शैक्षिक वर्ग का हो हो ।” (कोठारी कमीशन १३-९-२२)

कोठारी कमीशन ने जहाँ विश्वविद्यालयों के लिए स्वायत्तता की यह वकालत की है वहीं उसने यह भी कहा है कि “शाश्वत चौकसी स्वायत्तता का मूल्य है ।” उसने स्पष्ट घोषणा की है कि निर्भयतापूर्वक सत्य-सधान में बौद्धिक सत्यनिष्ठा बनाये रखनेवाले स्वायत्त विश्व-विद्यालय लोकतंत्र और स्वाधीनता के अडिग स्तम्भ हैं परन्तु प्रभावी स्वायत्तता वरदान स्वरूप नहीं प्राप्त होती । उसे सतत अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए । विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता का अधिकार सत्य के सधान और उसकी सतत साधना के फलस्वरूप प्राप्त होता है । अतः स्वायत्तता के प्रति किये जानेवाले विरोधों के प्रतिकार की उनकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी जितनी अधिक साधना से वे अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे ।” (कोठारी कमीशन—१३-१५-१)

हमें खेद इस बात का है कि हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा-संस्थाओं की स्वायत्तता के लिए सतत चौकसी का मूल्य अदा नहीं कर पाये हैं । यदि वे चौकस रहते तो उस समय चुप नहीं रहते जब इस प्रदेश (और दूसरे प्रदेशों) की सरकारें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्वायत्तता का अपहरण कर रही थीं । यात यह है कि शिक्षा की स्वायत्तता एक मधिमाज्य इकाई है—एक इन्डिविजुल होत है । ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा सरकार के हाथ में हो, माध्यमिक स्तर पर उसके सरकारीकरण का प्रयास हो रहा हो और उच्च स्तर पर स्वायत्त बनी रहे । परन्तु आज उत्तर प्रदेश में और भारत में यही हो रहा है ।

गत वर्ष जब उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के सरकारीकरण का विधेयक बना (विधेयक बनाने के पहले तो उसे गवर्नर के आर्डिनेन्स के रूप में लागू किया गया था) तब सरकार के इस कदम का विलकुल विरोध नहा हुआ । जो शिक्षा अभिज्ञों के जमाने में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के हाथ में दी गयी थी उसका भी जब अपनी सरकार ने अपहरण किया तो सब चुप रहे । हमारे विश्वविद्यालयों से इस अपहरण के विरुद्ध किसी प्रकार की आवाज नहीं उठायी गयी । हमारे

विश्वविद्यालय शिक्षा की स्वायत्तता के सजग प्रहरी नहीं रह सके। और आज माध्यमिक शिक्षा के सरकारीकरण के लिए जो आन्दोलन हो रहा है, भले ही यह आन्दोलन स्वयं माध्यमिक शिक्षक सघ द्वारा ही हो रहा हो, तो उसका भी विरोध हमारे विश्वविद्यालय, जो हमारी श्रेष्ठतम बौद्धिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, नहीं कर रहे हैं। बड़े मजे की बात यह है कि अगर कोई विरोध कर रहा है और माध्यमिक शिक्षा का सरकारीकरण टल रहा है तो इसलिए कि स्वयं सरकार उसे यह कहकर टाल रही है—‘माध्यमिक शिक्षा के सरकारीकरण से जो आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ेगा उसे सरकार उठा नहीं सकता।’ परन्तु सिद्धांततः यह गलत हो रहा है, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। शिक्षा की स्वायत्तता के सबसे प्रबल रक्षक विश्वविद्यालयों से तो इसके विरुद्ध क्षीणतम आवाज भी नहीं उठी है, परन्तु जयसे उत्तर-प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक लाने की बात हो रही है तब से अचानक विश्वविद्यालय के शिक्षक मुत्तर हो उठे हैं। जगह-जगह सेमिनार और गोष्ठियाँ की जा रही हैं और चिल्ला चिल्ला कर कहा जा रहा है कि यह विधेयक अप्रजातान्त्रिक ही नहीं, शिक्षकों के हित में भी नहीं है। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का अपहरण हुआ तो विचारों का ‘रेजिमेन्टेशन’ होगा और देश में पकाधिपत्यवादी राजनीति पनपेगी, और अन्ततोगत्वा लोकतंत्र का नाश हो जायगा।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डाक्टर रघुवश ने तो यहाँ तक कह डाला है—(और मैं नहीं समझता कि उन्होंने गलत कहा है) कि “प्रस्तावित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक के पीछे सरकार की अपनी पचीस वर्ष की असफलताओं को, अपनी झूठी कयनी-करनी के अन्तर को, और अपने भ्रष्टाचार की दुर्गन्ध को छिपाने का प्रयास है। केन्द्र हो या प्रदेश, शिक्षा क्षेत्र की सरकारी नीतियाँ पूरी तरह असफल सिद्ध हो चुकी हैं और सरकार का एक ही काम रह गया है—अपनी असफलताओं पर पर्दा डालना।” इसी लेख में लेखक ने लिखा है कि ‘स्वराज्य प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालय एकटों में जितने भी सुधार हुए हैं सरकारी प्रभागों को बढ़ाने के लिए ही हुए हैं। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के सम्बन्ध में ब्रिटिश नीति अधिक उदार थी। वहाँ विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को आर्थिक अनुदान

के नाम पर छीना नहीं जाता था । हमारे यहाँ तो सरकार जनता के प्रतिनिधित्व और आर्थिक अनुदान की दुहाई देकर सरकारीकरण की प्रक्रिया चला रही है—जिससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त होती जा रही है ।”

उत्तर प्रदेश का प्रस्तावित विश्वविद्यालय विधेयक विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को समाप्त करने का एक कुचक्र है और यदि यह विधेयक पारित हो गया तो शिक्षा का पूर्णतः सरकारीकरण हो जायेगा । पूर्णतः इसलिए कि प्राथमिक शिक्षा का सरकारीकरण तो हो ही चुका है और माध्यमिक शिक्षा के सरकारीकरण के लिए तीव्र आन्दोलन हो रहा है—जिसका विरोध कोई नहीं कर रहा है ।

इस प्रस्तावित विधेयक को प्रमुख सत्तुतियों को देखा जाय तो इस तर्क की पुष्टि हो जायेगी

१—इसके अनुसार विश्वविद्यालय के कुलपति का चुनाव कुलाधिपति पर निर्भर करेगा । कुलाधिपति गवर्नर होता है जिसकी नियुक्ति सत्तारूढ़ दल द्वारा की जाती है । अभी तक कार्यकारिणी द्वारा तीन नाम भेजे जाते थे जिनमे से कुलाधिपति किसी एक को चुनवा था परन्तु वर्तमान विधेयक में कुलाधिपति आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार कुलपति चुनेगा । प्रस्तावित एक्ट में विशेषाधिकार कुलपति के स्थान पर कुलाधिपति को प्राप्त हो गये हैं, और कुलाधिपति की शक्ति का अर्थ है मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री की शक्ति ।

२—कुलाधिपति विशेष स्थिति में पूरी कार्यकारिणी को निरस्त कर सकते हैं और वर्ष दो वर्ष के लिए नामनद सदस्यों की कार्यकारिणी घोषित कर सकते हैं ।

३—सरकार ने विश्वविद्यालयों के निरीक्षण का अधिकार ले लिया है ।

४—विधेयक में अपील का एक मात्र अधिकारी कुलाधिपति ही है—न्यायालयों की शरण की मनाही है ।

५—प्रस्तावित विधेयक के अनुसार लेखाधिकारी और कुल सचिव (सहायक सचिव भी) सरकार के सहारा केवल नियुक्त नहीं होंगे, वे एक प्रकार से सरकारी आदमी होंगे । विश्वविद्यालय के प्रति उनका

कोई प्रतिश्रुति (कमिटमेण्ट) नहीं होगा। लेखाधिकारी आर्थिक मामलों की ही देख-रेख नहीं करेगा वरन् हर मामले में निर्णायक होगा। आर्थिक समिति में एक भी सदस्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं रखा गया है।

६—संकायों के डीन का कार्यकाल एक वर्ष का ही कर दिया गया है। विभागीय अध्यापकों की स्थिति स्थायी है और उन्हें कुलपति के व्यक्ति के रूप में स्थायी कर दिया गया है।

७—विद्यार्थी-सहयोग के नाम पर कोट में दो विद्यार्थी प्रति-निधि रहेंगे।

८—नियुक्तियों में चयन समिति और कार्यकारिणी में मतभेद होने पर कुलाधिपति का निर्णय सर्वोपरी होगा।

यह है संक्षेप में विश्वविद्यालय विधेयक। इस विधेयक के पारित हो जाने पर विश्वविद्यालयीन जीवन प्रजातांत्रिक नहीं रह जायेगा। और इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगी। विचारों का रेजिमेण्टेशन लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा है और इस विधेयक के अधिनियम बन जाने से यह खतरा बढ़ता है। इसलिए इस विधेयक का विरोध होना चाहिए। परन्तु यह भी समझ लेना चाहिए कि विरोध अगर इस सरकारीकरण की प्रकृति का शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर नहीं हुआ, तो विरोध का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। शिक्षा की स्वायत्तता एक पवित्र वस्तु है और वह विश्वविद्यालय के क्षेत्र में जितनी पवित्र है उतनी ही पवित्र प्रारम्भिक और माध्यमिक क्षेत्र में भी है। वह एक ऐसी पावन धारा है जिसे उद्गम स्थल से समुद्र-मिलन-स्थल तक अजस्र प्रवाहित होना चाहिए, यह दूसरी बात है कि कहीं यह धारा क्षीण हो और कहीं मिशाल अथवा कहीं इसकी गति धीमी और कहीं वेगवती!

—चंशोधर धीवास्तव

राममूर्ति

सत्य ही शिक्षक की सत्ता

[२८, २९ अक्टूबर '७२ को पवनार में महाराष्ट्र आचार्यकुल परिषद के प्रथम अधिवेशन में पण्यद के प्रमुख अनिवार्य आचार्य राममूर्ति के प्रारंभ भाषण का एक अंश नयी तासीम के पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है ।—स०]

मैं साब रहा था कि किस अधिकार से आपका समय लूँ। पूज्य विनोबाजी का अधिकार मेरे पास नहीं। दादा घर्माधिकारी का मामा क्षीर-सागर का भी नहीं। अध्यक्ष महोदय उमाशंकर जोशी का अधिकार भी मेरे पास नहीं। अगर कोई अधिकार हो सकता है तो सिर्फ इतना ही कि कई वर्ष पहले मैं भी एक शिक्षक था। तेरह वर्षों तक शिक्षण का काम करने के बाद ही सावजनिक क्षेत्र में आया हूँ। या यों कहिए कि सर्वनाश से सर्वोदय की तरफ आ गया। इतिहास पढ़ता था, पढ़ाता था, लेकिन ऐसा लगा कि लोकनय और विनाय के इस जमाने में बस्ता में बैठकर इतिहास पढ़ना या पढ़ाना पर्याप्त नहीं। अपनी थोड़ी सी शक्ति से ही सही इतिहास बनाने में योगदान देना चाहिए।

मेरे इतिहास के अध्ययन ने मुझे बताया कि मानव का विकास अनेक अवसरों पर ऐसे बिन्दु पर पहुँचता है जिसकी सत्यता के मोड़ का बिंदु कह सकते हैं। और आज भी ऐसी बात दिखायी देती कि जिन मूल्यों की विद्वान की और सोचतंत्र की बदौलत मनुष्य ने प्राप्ति किया है उन्हें वह अपने पास रख भी सकता है, गवाँ भी सकता है। इसलिए इस मोड़ के बिंदु पर पढ़ने और पढ़ाने से कुछ ज्यादा करने की भी जरूरत है।

हम यह अस्वीकार तो नहीं कर सकते कि आज का युग विज्ञान का है। और, किसी सत्ता में विज्ञान का विश्वास नहीं, सिवा कि बुद्धि की। आज जिस सत्य को विज्ञान मान रहा है, उसे कन छोड़ सकता है और वल तक जो सत्य माना गया था उसे आज छोड़ सकता है। बहुत पुराना एक प्रसंग है गैलिलीयो के जीवन का। यूरोप में प्रथम गैलिलीयो ने आविष्कार किया कि पृथ्वी चलती है, सूर्य नहीं। यहाँ, हमारे देश में तो यह प्राचीन काल से मान्य था, पश्चिम की तरफ मान्य नहीं था। गैलिलीयो ने यह जब कहा, तब जितने सत्तापति थे, धर्मगुरु थे, उस जमाने के बड़े बड़े विद्वान और पंडित थे उन्होंने कहा कि यह ईश्वर के खिलाफ है, यह आदमी भगवान को चुनौती दे रहा है, पृथ्वी को चाहता है, सूर्य को नहीं। विद्वानों और सत्तापतियों कि सभा हुई और उसमें गैलिलीयो से पूछा गया कि क्या तुम्हारा कहना है कि पृथ्वी चलती है और सूर्य चलता नहीं? तब गैलिलीयो ने कहा, मैं नही कहता पृथ्वी चलती है, वह चल रही है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ मेरे प्रयोगों ने सिद्ध किया है कि पृथ्वी चलती है।" तब माराम हो गये विशिष्ट लोग और उन्होंने कहा तुम अपना कहना वापस लेते हो कि दण्ड के भागी होते हो।' वह बेचारा वैज्ञानिक, उसने सोचा, भले पृथ्वी न चले, सूर्य ही चले अपनी जान सतरे में है क्यों मैं इसके पीछे पड़ूँ। इसलिए वह तैयार हो गया सिख देवे कि लिए कि सूर्य चलता है, पृथ्वी नहीं। उसे बागज दिया गया और वह सिखने लगा तब उसके हाथ काँपने लगे। क्योंकि सारी निदानी भर का प्रयोग था उसकी साधना थी। लोग देख रहे थे और वह बोल उठा सिखते निखते—“बट स्ट्राट मैं आई हूँ इट इज दी वय दीन मून्ड... मैं क्या करूँ”, पृथ्वी है, जो चल रही है। इसलिए सत्य की अपनी मता है। वह अपनी जगह रहती है। बुद्धि की अपनी सत्ता है। और इतिहास के अवसर थे जब धर्म की सत्ता को सत्य की सत्ता ने चुनौती दी और इस चुनौती को बुद्धि की सत्ता ने स्वीकार दिया है। और उस स्वीकृति में से मानव के विकास का रास्ता निकला है।

अंग्रेजों के जमाने से, जब से शिष्य का विभाग सरकारी विभागों में से एक विभाग हुआ, शिक्षक नौकर हो गया—सरकारी नौकर। हम भी काम करते थे, हमारा भी एमोसिएशन था, हम भी वेतन सिविल क्लर्क आदि के लिए लड़ते थे। और ठीक था वैसा करना। लेकिन हम लोग भी बार-बार सोचते थे कि अगर किसी दिन शिला-मन्त्रालय से सर्वमुत्तर निकल आये कि भारत का गणित आज से बदल गया है $2 \times 2 = 4$ नहीं होगा, $2 \times 2 = 4\frac{1}{2}$ होगा, तो हम क्या करेंगे? यह सब जाचियों की मजदूरी है, वह क्या करेंगी?

गैलिलीओ की स्थिति होगी हमारी, “वट ब्लाट वैन धी डू, दू इन्टू दू इज इक्वल दू फोर ।” यह इतना सत्य है कि हम उसका अस्वीकार नहीं कर सकते । यही चीज शिक्षकों को दूसरे नागरिकों से अलग करती है । राज-नैतिक नेता कितना भ्रष्ट होगा, व्यापारी कितनी मिलावट करेगा, इसकी सीमा नहीं । लेकिन शिक्षक कितना असत्यवादी हो सकता है इसकी सीमा है । हम गलत काम नहीं करते ऐसा दम धावद कोई शिक्षक नहीं करेगा, फिर भी शिक्षकों को नीचे गिरने की सीमा होती है । और जहाँ गिरते-गिरते हम सीमा पर गिर जाते हैं, वहीं हमारे आगे बढ़ने का प्रारम्भ हो जाता है ।

एक पहलू शिक्षक के जीवन का यह है कि वह गृहस्थ है । गृहस्थ के नाते उसका परिवार है, जिसका पालन-पोषण करना उसकी जिम्मेदारी है । इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि ‘ट्रेंड यूनियन थे जैसे अनेक भागों का वह उपयोग करता है वह गलत करता है । उस पहलू की जो माँग है, उसकी माँग उसी तरह से हो सकती है । इसलिए शिक्षक कहता है कि ‘यह क्या आपने आचार्य-कुल का तमाशा खड़ा कर दिया है ? जब आपने देखा कि शिक्षकों की शक्ति बढ़ रही है, तब आचार्यकुल का सचिन बोर्ड लेकर निकल आये ।’ लेकिन, हमने दूसरे कुछ अपराध किये हमें, पर यह कभी नहीं किया, न करना चाहते हैं कि यनी हुई शक्ति को तोड़ दें । हम सरकार की आर से नहीं आये, न हम भारतीय सी आई ए हैं । हम भी शिक्षकों की ताकत बनाना चाहते हैं ।

लेकिन, हमने यह देखा है कि दलबंदी ने, राजनीति ने मजदूर आन्दोलन को खतम कर दिया है । आज कहाँ है श्रमशक्ति—मजदूरों की संगठन शक्ति ? आज क्या दिखेगा मिलों में ? एक दल का एक मजदूर, दूसरे दल का दूसरा मजदूर । एक-एक कारखाने में मजदूर एक-दूसरे के दुश्मन जैसे हैं । विरोधी पक्षों में बँट गये हैं । इस दलबंदी ने विद्यार्थियों की शक्ति को खतम कर दिया । एक एक पार्टी में एक-एक विद्यार्थी । जिसकी हत्या होती है, वह भी विद्यार्थी और जो हत्या करता है वह भी विद्यार्थी । क्यों ? क्योंकि एक एक पार्टी में, दूसरा दूसरी पार्टी में, और दोनों भूल गये कि दोनों विद्यार्थी हैं । एक ही कक्षा में बैठनेवाले विद्यार्थी राजनीति में बँट जाते हैं और उनकी एकता समाप्त हो जाती है । एक विद्यालय में एक पक्ष का बोलवाला, दूसरे में दूसरे का । विद्यालय भी पक्षों में बँट गये हैं । कुछ शिक्षक एक एसोसिएशन में बैठते हैं, कुछ शिक्षक दूसरे एसोसिएशन में बैठते हैं । शिक्षक शिक्षक की हैसियत खो बैठता है । थमिक थमिक की

हैसियत हो बैठा है। क्या खो बैठा है ? पार्ली-पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स। इससे सदेह और अविश्वास की दीवार इतनी ऊँची बन जाती है कि टूट नहा सकती। अगर शिपक अपनी शक्ति बनाना चाहत हैं तो इतना तो करिये कि सगठन को तोड़नेवाली जो शक्ति है उससे जलम रहिये। सगठन ठोस होना चाहिए। किसी तरह सगठन में दरार पड़ती है और वह राजनीति के कारण पड़ती है तो वह सगठन दरार का सहन नहा कर सकता।

हम नागरिक भी हैं। आज नागरिक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को अपना महसूस नहीं करता। सामाजिक उत्तरदायित्व से वह जलम रहता है। लेकिन शिक्षक कितना भी दृढ़ यूनिवर्सिटी (मजदूर संघवादो) बने, उसका पंशा इस तरह का है कि समाज ने जबरदस्ती विद्यार्थी को उसके भत्ते पर बैठाया है। वह यह कह दे कि क्यों जबरदस्ती यह बोझ मेरे भत्ते पर दिया है कह दे वह एस। तो क्या होगा ? विद्यार्थी चले जायेंगे तो फिर वह शिपक ही नहीं रहेगा। विद्यार्थी नहीं, शिक्षक भी नहीं और दृढ़ यूनिवर्सिटी भी नहीं। इसलिए सामाजिक उत्तरदायित्व से वह हट नहीं सकता।

हमने शिक्षक की क्या क्या हैसियत हो सकती है देखा। एक इस देश में नागरिक की हैसियत। दूसरी गृहस्थ के नाते, एक विशिष्ट पग के कारण दृढ़ यूनिवर्सिटी की हैसियत और तीसरी शिक्षक के नाते शिक्षक की हैसियत जिसका उल्लेख मैंने आरम्भ में किया कि दो गुना दो बराबर चार होते हैं साढ़े चार नहा। ऐसे कुछ तथ्य और मूल्य हैं जिनसे हम छोड़ नहीं सकते। और उन मूल्यों को खुद हम ही नहीं मानते बल्कि हमारे द्वारा समाज भी मानता और समझता है।

आज सारी शक्ति पॉलिटिक्स (राजनीति) और बिजिनेस (व्यापार) के हाथ में है। सरकार पॉलिटिक्स के हाथ में और समाज बिजिनेस के हाथ में है क्योंकि बाजार उसके हाथ में है। या यो कहिए पॉलिटिक्स और बिजिनेस का ज्वाइंट सेक्टर (संयुक्त क्षेत्र) है। शिपक को कहा जाता है कि तुम भविष्य में निर्माता हो इसलिए वर्तमान की चिन्ता मत करो। मगर आज अगर समाज का और हमारे देश का भविष्य भी पॉलिटिक्स और बिजिनेस के हाथ में जा रहा है तो शिक्षक किस भविष्य का निर्माण करेगा ? शिक्षक का भविष्य के निर्माण में कोई स्थान हो इसके पहले यह तो तथ्य हो कि जैसे पॉलिटिक्स एन पावर (शक्ति) है और बिजिनेस एन पावर है वैसे शिक्षण भी एक पावर है। शिक्षण भी एक शक्ति बने।

आज विश्वविद्यालय अपने को पाठ जितना स्वागत समझ ले, लेकिन शिक्षण सरकार द्वारा संचालित एक विभाग ही है। यानी जब हमसे यह कहा जाता है कि हम भविष्य के निर्माता हैं, तब उसका अर्थ यह है कि हम पन-पाप्पुनर गवर्नमेण्ट (लोक-अग्रिय सरकार) के पाप्पुनर एजेण्ट (लोकिय प्रतिनिधि) हैं। यह बात आज शिक्षकों को सीना गया है। एक एक विद्यालय एक एक पक्ष का। प्राथमिक शिक्षा चुनाव में बच्चों को से बर नारे लगाना फिरता है। ऐसी विवशता बर दी है पक्षों में कि शिक्षा उनके हाथ का खिलौना बन गया है। जैसे जमींदारी होती है, वैसे विद्यालय जमींदारी होने लगे हैं पक्षों की। बोल्ट पोलिटिकल सिमिन वॉर ! एर चीनयुद्ध राजनीति को से बर शिक्षण-संस्था तक में चलता है।

आज शिक्षक माँग रहा है कि शिक्षा का सरकारीकरण हो। जो गैर-सरकारी शिक्षण-संस्थाएँ हैं वे आज किसी-न-किसी सेठ या ताहूदार के हाथ में हैं। वे विद्यालय का सेठ, साहूकार की मालमत्ता का गये हैं। बिहार में तो विद्यालयों की खरीदी-बिक्री भी चलती है। उससे तब आकर शिक्षक सरकारीकरण की माँग कर रहे हैं, शासन की बरण जानने की तैयार हैं। लेकिन व यह समझते नहीं कि शासन में भी वे ही सेठ और वे ही नेता होते हैं।

और एक बात बहुत सोचने की है। सरकारीकरण से हम करना क्या बना भी लें समाज में, लेकिन हमारे बच्चों का क्या क्या होगा ? यह सोचना जरूरी है। और उनकी माँग तो हमारी माँगों से कई गुना ज्यादा होगी। सहवा की समस्या और जीवनस्तर की समस्या, ये दो चीजें ऐसी हैं, जो इस देश का भविष्य बनायेंगी या बिगाड़ेंगी। आज पुराना आसान, सरल जीवन नहीं रहा, आज जीवन में जटिलता है।

आज इस देश में शक्ति है एक ही, सरकार की। और वह भी कितनी शक्ति है उसका अनुमान लग सकता है। जब देश की रक्षा करनी होती है, शिक्षा का प्रचार करना होता है, अण्डाधार का निर्मूलन करना होता है, जब-ये प्रश्न सामने आते हैं, तब हर बख्त कहा जाता है कि यह प्रश्न एक पक्ष का नहीं है, यह राष्ट्रीय प्रश्न है। ये सारे प्रश्न अगर राष्ट्रीय हैं, तो फिर पार्टी पालिटिक्स (पक्ष-राजनीति) किसका प्रश्न है ? किसी ने कहा है, सम्प्रदाय, भाषा, जाति, अनेक प्रकार के लोभ हैं भारत में, उनका गुणन यानी भारतीय राजनीति होगी। जब तक लोभ उभाड़ेंगे नहीं, तब तक जनता का समर्थन

मिलेगा नहीं। वास्तव में यह दलबन्दी है और इसी को हम लोकशाही कहते हैं। हर दल का एक घोषणा-पत्र होता है। और दल अपने घोषणा-पत्र को राष्ट्रीय सत्य कहता है—नेशनल ट्रूथ। हर पक्ष के पास सत्य है, लेकिन देश के पास भी कोई सत्य है? जो है वह पार्टी-सत्य है।

विज्ञान 'पार्टी-सत्य' को नहीं मानता। विज्ञान राष्ट्रीय सत्य को भी नहीं मानता। यह केवल सत्य मानता है। विश्वव्यापी सत्य मानता है, क्योंकि वह विश्वव्यापी है। शिक्षकों को भी 'पार्टी-सत्य' मानना नहीं चाहिए, राष्ट्रीय सत्य भी मानना नहीं चाहिए। विज्ञान के सत्य का 'फ्रांटियर' (क्षितिज) विश्व-व्यापी है, वैसे शिक्षक के सत्य का फ्रांटियर भी विश्वव्यापी है। शिक्षक अपने को अक्षित महसूस करता है, तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। यानी सरकार का शिक्षा के लिए साधन देना चाहिए। परन्तु इसके बाद क्या हमारी यह माँग होगी कि जिस सत्य को हम सिखाते हैं वह सत्य भी सरकार के हाथ में सुरक्षित रहे? इसलिए सत्य हमारा और साधन सरकार का, यह माँग हो सकती है। इंग्लैण्ड में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की सरकार मदद करती है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करती। सरकार और समाज में कोई डिवाइडिंग लाइन—विभाजक रेखा है या नहीं? यह सारा समाज सरकार के पेट में समा जायेगा? इतना बड़ा पेट किसी समय फूट गया तो क्या हालत होगी? दूसरे देशों में जो परिणाम हुए हैं वे यहाँ भी होंगे। आज सरकार ने प्रजातंत्र की घोषणा कर अपना पेट हमना बड़ाया है कि मारा समाज उसमें समा लिया है। इसलिए शिक्षक सुरक्षा की माँग करे, लेकिन शिक्षण सरकारी तंत्र से मुक्त रहे। प्रत्येक विद्यालय का अंतर्गत जीवन स्वायत्त चाहिए। निर्णय का अधिकार हमारे हाथ में चाहिए। अगर यह नहीं होगा तो विद्यालय सरकार और राजनीति में फँस जायेंगे और गलत्य तक पहुँच नहीं पायेंगे। ●

❊	अ० मा० शान्तिसेना-रैली	❊
❊	शान्तिसेना की अखिल भारत रैली २१ वें सर्वोदय सम्मेलन	❊
❊	के अवसर पर कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में दिनांक १३ अप्रैल	❊
❊	१९७३ को सवेरे ७ बजे होगी।	❊
❊	सब शान्ति सैनिकों, शान्ति सेवकों, तरुण-शान्तिसेना के	❊
❊	सदस्यों तथा सहयोगियों को गणवेश के साथ रैली में भाग लेने	❊
❊	का निवेदन है।	❊
❊	—कार्यालय	❊
❊	अ० मा० शान्तिसेना महल	❊

सरकारी नौकरियों से डिग्री का सम्बन्ध-विच्छेद हो

१—१४-१५ अक्टूबर १९७१ को वर्धा (महाराष्ट्र) में हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ने यह सस्तुति की है कि “सावजनिक व निजी, इन दोनों ही क्षेत्रों के लिए भर्ती करते समय नौकरी के साथ डिग्री की अनिवार्यता समाप्त करने की पूरी कोशिश होगी चाहिए ।” सरकारी नौकरियों के लिए डिग्रियों की अनिवार्यता समाप्त करने की बात पहले भी उठ चुकी है और भारत सरकार को यह सस्तुति दी जा चुकी है कि आई० ए० एस० (भारतीय प्रशासन सेवा) जैसी कुछ अखिल भारतीय नौकरियों को छोड़कर बाकी सरकारी नौकरियों के लिए सरकारी विभाग अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करें और डिग्रियों का आग्रह रखे बिना योग्य प्रत्याशियों के चुनाव के लिए इस्तेहान लें ।

२—चूँकि ज्यादातर मामलों में यह माना जाता है कि डिग्रियाँ बेकार होती हैं, और यह भी अनुभव किया जाता है कि बिना खास काम के लिए योग्य व्यक्ति के चुनाव में सिर्फ डिग्री कोई ठोस मापदण्ड नहीं बनती, फिर भी सरकारी नौकरियों के लिए डिग्रियों की अनिवार्यता खत्म करने की दृष्टि से कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं । इस निबन्ध का उद्देश्य यह सुझाना है कि इस समस्या का विगणेषण हो प्रत्याशियों के चुनाव के तरीका और उसकी आवश्यकताओं का परीक्षण हो और यह विचार किया जाय कि सरकारी और निजी नौकरियों के लिए डिग्रियों की अनिवार्यता कहाँ तक खत्म की जा सकती है ।

३—जैसा कि सभी जानते हैं हिन्दुस्तान की शिक्षा-प्रणाली विदेशियों की देन है । अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था पढ़े लिखे ऐसे लड़के-लड़कियों को तैयार करना, जो प्रशासकीय ढाँचे में क्लर्कों तथा दूसरी नीचे स्तर की नौकरियों के लिए इस्तेमाल किये जा सकें । इस प्रणाली से बीते जमाने में उद्देश्य की प्राप्ति चाहे हुई हो लेकिन आजागी के बाद के जमाने में देखने से ही इसका विरोधाभास नजर आ जाता है । अब यह प्रतीति बढ रही है कि इस प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाय और करीब-करीब इस बात की भी सर्वसम्मति बन गयी है कि परिवर्तन किस तरह किया जाय । शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय विकास के सम्पूर्ण कार्यक्रम में शिक्षा के वर्तुत्व के पुनर्भूल्यावन और यदि शिक्षा को अपना सही रोल अदा करना है तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन का सही स्वरूप निश्चित करने और उन पर आधारित शैक्षिक विकास का एक

कार्यक्रम तैयार करने और इस कार्यक्रम को दृढ़ निश्चय और शक्ति से पूरा करने पर जो जोर दिया है वह ठीक ही है। आयोग ने जो सस्तुतियाँ की हैं उनका मूल अर्थ यही है कि शिक्षा को विकास और सामाजिक न्याय से जोड़ा जाय। इस विचार और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उसके प्रचारों की विशद व्याख्या श्री श्रीमन्नारायण ने अपने “विकास और सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा का अनुबन्ध” शीर्षक निबन्ध में अच्छी तरह किया है। उम निबन्ध में विभिन्न निष्कर्ष निकाले गये हैं उन्हें यहाँ दुहराना जरूरी नहीं है। वास्तव में उस निबन्ध में दिये सारे निष्कर्षों का अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के “मर्दानुमति सम्बन्धी प्रतिवेदन” में समावेश कर लिया गया है।

४—सारी समस्या है मूल्य व दृष्टि परिवर्तन की। ज्ञान के किसी क्षेत्र-विशेष में डिग्री के साथ प्रतीक रूप में योग्यता का जो मूल जुड़ा हुआ है और यह दृष्टि कि डिग्री सफेदपोश नौकरी का साधन है, इन दोनों को एकदम बदल देना है। यह एक बड़ी समस्या है जो शिक्षा-प्रणाली, परीक्षा व नौकरी-व्यवस्था पर छाई हुई है।

५—कभी भी यह नहीं माना गया है कि शिक्षा जोविरा की माधन मात्र है। दुर्भाग्य से शिक्षा का अब तक जो प्रणाली रही है उसने सिर्फ ऐसे मैट्रिकुलेटो व प्रेजुएटो की ही सख्या बढ़ाने में मदद की है जो रोजगार, विशेषकर सरकारी नौकरियों के पीछे भारे-भारे फिरते हैं। शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के तीव्रगामी प्रसार से यह समस्या और बड़ी है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि शिक्षा में गुणात्मक तो कम लेकिन सख्यात्मक वृद्धि काफी हुई है। शिक्षित बेकारों के प्रश्न ने राजनीतिक-सामाजिक व आर्थिक, गम्भीर समस्याओं को जन्म दिया है। शिक्षा व रोजगार के बीच अनुबन्ध स्थापित करने के लिए बड़ी तेजी से मुझाव दिये जा रहे हैं। हालाँकि शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से शिक्षित बेकारों के लिए थोड़ा दिनों के रोजगारपरक पाठ्यक्रम के रूप में कुछ अल्पकालिन हल जरूर सुझाये जा रहे हैं। फिर भी शिक्षा व रोजगार के बीच विधायक व निपेधात्मक दोनों प्रकार के अनुबन्ध बैठकर समस्या का और गम्भीर हल निकालना चाहिए।

६—शिक्षा व रोजगारी के बीच जो विधायक बड़ी है वह है शिक्षा का उत्पादक रोजगार से समवाय। इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की यह सस्तुति कि ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी स्तरों पर शिक्षा सामाजिक रूप से उपादेय व उत्पादक, ऐसी क्रियाओं के माध्यम से दी

जाय, आर्थिक उन्नति व विरासत के साथ अनुवर्धित हो, ऐसे प्रशासक व शिक्षाविदों, बाना के ध्यान देने योग्य है जिनका ध्येय शिक्षा में परिवर्तन करना है। प्राइमरी स्कूलों के बच्चा या सजनात्मक क्रियाओं के माध्यम से सामाजिक शिक्षा दी जाय और साथ ही उन्हें सामाजिक व प्राकृतिक परिवेश का निरन्तर परिचय प्रदान किया जाय और जहाँ तक माध्यमिक स्कूलों के शिक्षार्थियों का सम्बन्ध है उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं व श्रमशक्ति की दृष्टि से ऐसा क्रियात्मक प्रशिक्षण देना चाहिए जो कोई-न कोई राजगार तो देवाना हो, साथ ही सामाजिक दृष्टि से उपयोगी व क्रियात्मक भी हो। उच्च माध्यमिक स्तर पर जर्मनी तथा अन्य पश्चिमी देशों के नमूने पर पानिटेक्निक (वहुशिल्प शिक्षणालय) प्रशिक्षण में प्रयुक्त होनेवाले अनेक विषयों में क्रियात्मक व पूरी सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करनेवाली शिक्षा की एक बहुमुखी प्रणाली को तात्कालिक आवश्यकता के रूप में लागू किया जाना चाहिए। शिक्षण का सारा ढाँचा ऐसा हो कि प्रत्येक लड़के या लड़की का शिक्षा दत्तक व केवल कोई-न कोई खास काम करने योग्य बनाया जाय बल्कि उसे ऐसे उपयोगी नागरिक के रूप में भी तैयार किया जाय जो किसी भी उत्पादक कार्य में लगाया जा सकें और जो राष्ट्रीय विकास-नायक में भा प्रभावोत्पादन ढंग से हिस्सा ले सकें। शिक्षा की विषय-वस्तु में सुधार से आज की शिक्षा का दिये गये मूल्य में भी निश्चित ही अभिवृद्धि होगी और यदि सैद्धान्तिक विषय वस्तुओं के बजाय व्यावहारिक एवं सामाजिक समस्या समाधानमूलक शिक्षा पर जोर दिया जाने लगेगा तो सिर्फ डिग्री को जो महत्त्व दिया जाता है वह खत्म हो जायगा।

७—एक दूसरा पहलू यह है कि शिक्षा व रोजगार के बीच आज जो सम्बन्ध है उसका विस्लेषण हो और डिग्री व सरकारी नौकरियाँ के बीच जो अवाञ्छित सम्बन्ध स्थापित हो जाता है उसका विच्छेद किया जाय। तब परिवर्तित हो रही शिक्षा व्यवस्था के सदृश में रोजगार व्यवस्था का प्रश्न सामने आता है और तभी सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों प्रकार की नौकरियाँ जो डिग्री के सम्बन्ध-विच्छेद की भी समस्या सामने आती है। इसे दूर करने की जरूरत नहीं है कि यदि एक बार शिक्षा व डिग्री का सम्बन्ध विच्छेद हो जाय या यों कहिये नि रोजगार का डिग्री से सम्बन्ध विच्छेद हो जाय तो आज डिग्री के साथ जो एक झूठी प्रतिष्ठा जुड़ जाती है वह सय हो जाय। ज्यादातर यही होता है कि डिग्री से जो प्रतिष्ठा जुड़ जाती है उससे लड़के-लड़कियों को यह धारणा बन जाती है कि शिक्षा के जरिये ज्ञान प्राप्ति नहीं बल्कि डिग्री की प्राप्ति कहा

ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे होता यह है कि डिग्री पाने के लिए किसी भी तरह इम्तहान पास करने की मनोवृत्ति को बढ़ाया जाता है। नतीजा यह होता है कि इस उपायवित्त बाहरी इम्तहान को न केवल एक झूठा महत्व मिला है बल्कि परीक्षा की पूरी प्रणाली ही भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए रोजगार के माध्यम डिग्री का सम्बन्ध-विच्छेद करना ज्यादा मौलिक सुधार है। जिससे वर्तमान शिक्षा-प्रणाली की कई बुराइयों पर प्रहार होगा और इससे भर्ती व परीक्षाओं में सुधार के जरिये शिक्षा की गुणात्मकता बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक सुधार का भी रास्ता साफ हो जाएगा। सवाल यही है कि सुधार कैसे हो। इस सम्बन्ध में सरकार, शैक्षिक-संस्थाओं और रोजगार देनेवाले माध्यमों द्वारा कई कदम उठाने पड़ेंगे। समुदाय से कड़ी बैठाना एक उपाय होगा। शिक्षित युवकों की बेरोजगारी की आज की समस्या और सकेद-पोंग नीकरियों के लिए इस अन्धाधुन्ध दौड़ का कारण है एक तरफ शैक्षिक-संस्थाओं द्वारा तैयार किये गये विभिन्न पाठ्याभ्यास व कृतकताओंवाले शिक्षाविद्यों तथा दूसरी ओर समाज के विभिन्न जाति-वर्गों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार से प्रतिदिन लोगों के बीच की दूरी। यह दूरी परम्परागत शैक्षिक-प्रणाली व समाज के बदलते स्वरूप के बीच की है। यह शिक्षा-अवस्था व रोजगार-अवस्था के बीच एक अंगुलबन्ध सम्बन्ध है। शिक्षा-प्रणाली के लिए सुझाये गये विभिन्न उपाय यह दूरी हटाने में कारगर हों सकते हैं। लेकिन उपयुक्त महत्त्वपूर्ण व जैविक सम्बन्ध-स्थापन के लिए नीकरी-अवस्था में सुधार का काम भी साथ-ही-साथ हाथ में लेना है। वैसे ऐसा वातावरण बन गया है जिसमें शिक्षा-सम्बन्धी सुधार के लिए शिक्षा आयोग द्वारा की गयी महत्त्वपूर्ण सन्तुष्टियाँ और सर्वानुमति सम्बन्धी प्रतिवेदन में दी गयी अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की भी सन्तुष्टियाँ केन्द्र, राज्य सरकारों, विश्व-विद्यालयों व शैक्षिक-संस्थाओं द्वारा स्वीकार कर ली जायगी, फिर भी जब तक रोजगार-अवस्था के सुधार के लिए भी वैसे ही कदम नहीं उठाये जाते, तब तक कोई काम फल नहीं होगा।

८—रोजगार-अवस्था के फिर से संयोजन के लिए कुछ उपाय निम्न-लिखित हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए :

(१) सरकारी विभागों की भर्ती के सम्बन्ध में लागू नियमों में प्रभावशाली परिवर्तन किया जाय।

(२) सचिवालय एकाउन्ट, प्रशासन और भवनालय सम्बन्धी नीतियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाये जायें।

(३) नौकरी देनेवालों व नौकरी में आनेवाले लोगों की दूरी कम करने के लिए रोजगार दफ्तरो को और अधिक क्रियाशील बनाया जाय । इन दफ्तरो को पने व रोजगार दोनों के स्वरूप का व्यवस्थित अध्ययन करना चाहिए ।

(४) डिग्रियो पर अनावश्यक जोर और उन कामों के लिए भी जहाँ कम योग्यताएँ भी काम दे सकती हों ज्यादा योग्यतावाले व्यक्तियों पर जोर देने का प्रोत्साहन न दिया जाय ।

(५) केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर पेशों के विश्लेषण व वर्गीकरण आवश्यक खास रोजगार की परख व उसकी छाँज रोजगार-व्यवस्था में व्यावहारिक प्रशिक्षण के समावेश व विभिन्न शिष्टो एव पेशों से सम्बन्धित प्रशिक्षण के आयोजन के लिए घटकों का निर्माण होना चाहिए ।

१. भर्तियों के नियम-उपनियम

सरकारी तमाम विभागों के भर्तियों के चालू नियम उपनियम अब पुराने पड़ गये हैं । नारीय-करीब सभी कामों के लिए कम से कम योग्यता स्नातकीय स्तर से थोड़ा ही कम है । कुछ खास पने सम्बन्धी जैसे डाक्टरों इंजीनियरों या औद्योगिक कार्यों के लिए किसी कम-से-कम डिग्री की मांग ठीक कही जा सकती है लेकिन मजालयी या उससे कम के प्रशासकीय ज्यादातर कामों के लिए डिग्री पर जोर देना जरूरी नहीं भी हो सकती है । क्लर्कों की जगहों के लिए तो भर्ती उन लोगों के लिए खुली होनी चाहिए जिन्होंने माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी कर ली । इसके लिए डिग्री पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए । ऐसी जगहों की भर्तियों के लिए जो भी प्रशिक्षण या अनुभव जरूरी हो वह नौकरी में आ जाने पर भी दिया जा सकता है । दफ्तर काय प्रणाली प्रशासकीय रीति-रम्परवादी मजालयी रिवाजों व हिताव किताब व्यवस्था के प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक स्कूलों व आई० टी० आई० (भारतीय औद्योगिक संस्थाओं) में सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए । यही नहीं कि ऐसी नौकरियों के लिए डिग्री की अनिवार्यता खत्म कर दी जाय बल्कि यह एक निश्चित नियम बना दिया जाय कि ऐसे कामों के लिए डिग्री को अयोग्यता में शुमार दिया जायगा । डाक्टरों इंजीनियरों कृषि और दूसरे क्षेत्रों के पने सम्बन्धी विशेष कामों के लिए किसी कम-से-कम डिग्री पर आपस रखे जा सकता है लेकिन यहाँ भी भर्ती व चुनाव के नियमों में काफी संशोधन की जरूरत है । डिप्लोमा स्तर के प्रशिक्षण औद्योगिक शिक्षा और व्यवसाय के अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए

भी अब काफी सुविधाएँ हो गयी हैं, और जहाँ भी स्नातकीय योग्यताओं की जरूरत न हो, वहाँ आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए। एक ही काम के लिए डिप्लोमा रखनेवालों व डिग्री रखनेवालों के बीच जो वशमकश होनी है उसे खतम किया जाना चाहिए। जिन कामों के लिए ऊँचे किस्म की जिम्मेदारी की जरूरत हो वे डिग्रीधारियों को दिये जा सकते हैं लेकिन औसत स्तर की देखभाल की जिम्मेदारीवाली जगहों तो डिप्लोमा रखनेवालों को ही दी जायें। अब विशेष प्रकार के प्रशिक्षण व बहुमुखी पाठ्यक्रम के लिए भी प्रशिक्षण की सुविधाएँ हो गयी हैं। ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए भर्ती के नियम अक्सर सामान्य प्रकार के ही होते हैं। उदाहरण के लिए मोटर-विज्ञान, वातानुकूल और रेफ्रिजेशन, यन्त्र-उपकरण और उत्पादन तकनीक आदि के लिए आवश्यक योग्यता के तौर पर यानिक-इंजीनियरी की मोटी-मोटी बातों की जानकारी रखी गयी है। भर्ती के वर्तमान नियमों-उपनियमों को कार्य की आवश्यकतानुसार ज्यादा वास्तविक बनाने की दृष्टि से यह जरूरी है कि उनकी बारीकी से परख की जाय। भर्ती के नियमों को भी समय-समय पर जाँच होती रहे ताकि वे बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप रहें।

२. व्यावसायिक और वृत्ति-सम्बन्धी प्रशिक्षण

दूसरा उपाय है व्यावसायिक और वृत्ति-सम्बन्धी प्रशिक्षण को बहुमुखी बनाया जाय। व्यावसायिकीकरण के बारे में काफी चर्चा की गयी है लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं। व्यावसायिक शिक्षा या वृत्ति-सम्बन्धी प्रशिक्षण के सम्बन्ध में शुष्कात्मक आयोजन करते समय बाह्य लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए। देश की अर्थ-अवस्था व सामाजिक-आर्थिक ढाँचे में जिन प्रशिक्षितों को उपयुक्त पार्ट अदा करना है उनके लिए जो हुनर, ज्ञान व वैयक्तिक गुण वांछित हैं उनका विश्लेषण व विकास करना आवश्यक है। निरिष्ट व्यवसायों के लिए जो छात्र या काम जरूरी है उनका ठीक से विश्लेषण होना चाहिए। छात्रों व व्यवसायों के सम्बन्ध में विशिष्ट आवश्यकताएँ तय की जायें और काम सम्बन्धी निरिष्टताओं के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा और छात्रों से प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए नया-नया कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए। यहाँ रोकगार देनेवाले माध्यमों के रोल पर जोर देना आवश्यक है। नये भर्ती हुए लोगों के लिए काम के साथ-साथ दिये जानेवाले प्रशिक्षण को अच्छा बनाने की दृष्टि तथा स्वच्छता शिक्षा-वृत्ति की एक प्रणाली अपनाने के लिए

भी रोजगार देनेवाले माध्यमों को, जैसा कि कई विनसित देशों में होता है, आगे आना चाहिए ।

३. रोजगार दफ्तरों को क्रियाशील बनाना

रोजगार-दफ्तर रोजी की तलाश करनेवालों व रोजी देनेवालों के बीच की कड़ी है । आज जैसा हो रहा है वाम चाहनेवाले रोजगार-दफ्तरों की शरण-जाते हैं । लेकिन नौकरियों की काफी बढ़ी सख्या के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनके बारे में रोजगार-दफ्तरों को बताया ही जाय और और न वाम देनेवालों के लिए यह जरूरी है कि वे रोजगार-दफ्तरों द्वारा सुझाये नाम स्वीकार ही करें । रोजगार-दफ्तरों की यह एक मौलिक कमजोरी है और जब तक इस कमजोरी को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाये जाते, रोजगार-दफ्तर वाम देने के कोई सशक्त माध्यम नहीं बन सकते । पंजीकरण की प्रणाली में भी परिवर्तन की जरूरत है । वर्गीकरण के हिमाय से जो पंजीकरण कराया जाता है उसमें न पूरी तौर से शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं का ध्यान लिया जाता है न खास उपलब्धियों का और न अनुभव का ही । परिणाम यह होता है कि मालिकों के लिए सही ढंग के उम्मीदवारों के चुनाव में रोजगार-दफ्तर एक बड़े ही कमजोर माध्यम बनकर रह जाते हैं । रोजगार-दफ्तर को ध्यावसायिक मार्गदर्शन देना चाहिए । काम मिल सकने के मौकों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, सलाह-मशविरा देना चाहिए और कुछ प्रशिक्षण भी । रोजगार-दफ्तर एक माध्यम है, श्रमशक्ति आँकड़ों के बारे में शायद एकमात्र माध्यम । लेकिन यह माध्यम सर्वांगीण सही आँकड़े प्रदान करने में शायद ही सक्षम है । रोजगार-दफ्तर शिल्प सम्बन्धी सर्वेक्षण कराते रहते हैं लेकिन इन सर्वेक्षणों में विस्तृत वर्गीकरण, वर्णन, पर्याप्त सम्पर्क और अनेक प्रभाव सम्बन्धी आँकड़े नहीं रहते । अगर यह व्यवस्था सुधारी जा सकती हो, जरूरत पड़ने पर कानून के जरिये भी, तो श्रम-शक्ति और वैश्विक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए रोजगार-दफ्तर सही और उपयोगी आँकड़ों के माध्यम बन सकते हैं । पेशेवरों व तबन्तीकी कामगारों का ही वर्गीकरण कर देना काफी नहीं है । विभिन्न पेशेवरों-जैसे इंजीनियरों, इमारत बनानेवालों, पैमाइश करनेवालों, नर्सों, दवाफरोशों, केमिस्टों, डाक्टरों, वैज्ञानिकों, नक्शा बनानेवालों, इंजीनियरी सम्बन्धी टेक्नीशियनों, पशु-चिकित्सकों तथा कृषि-विशेषज्ञों आदि का विस्तृत वर्गीकरण उपयोगी होगा । इसी तरह, बलकी सम्बन्धी कामों, पुस्तक-संरक्षण, कंशियर, बिक्रेता, ट्रकान-

सहायकों, सकेतलिपिकों, टाइपिस्टों, इश्योरेन्स क्लर्कों, बैंक-क्लर्कों, प्रूफ पढ़ने-वालों आदि के बारे में विशेषज्ञ और उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। नयी विवक्षित होती हुई अर्थ-व्यवस्था में नये नये कामों को स्पष्ट रूप से जानने और तेजी से बदलती हुई आर्थिक स्थितिवाले क्षेत्रों में विस्तार से वर्गीकरण की बहुत जरूरत है। उदाहरण के लिए कृषि-क्षेत्र में हम किसानों, खेत पर काम करनेवाले मजदूरों, ट्रैक्टर ड्राइवरा, ग्रामीण मिस्त्रियों, फार्म-व्यवस्थापकों, गोदाम की व्यवस्था करनेवालों, पशु-चिकित्सकों और विजनी मिस्त्रियों का अलग-अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। ऐसा वर्गीकरण करने से शिक्षा व प्रशिक्षण के उपयुक्त कार्यक्रम बनाने के मौके मिलेंगे और हम सीमा तक किसी खास डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं रहेगी। नौकरी और डिग्री का सम्बन्ध-विच्छेद रोजगार-दर्शनरी के माध्यम से रोजी देकर सबसे अच्छी प्रकार किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ तो वे मातृशिक्षा की विविध आवश्यकताओं की ठीक-ठीक जानकारी कराने और दूसरी तरफ ज्यादातर मामलों में बिना किसी चालू डिग्री या डिप्लोमा की अनिवार्यता मानत हुए उपयुक्त योग्यतावाले प्रत्याशियों का काम दिलाकर एक सक्रिय रोल अदा कर सकते हैं।

४. ऊँची शैक्षिक योग्यता का अनावश्यक महत्त्व

नौकरी व डिग्री का सम्बन्ध विच्छेद करने के लिए अहाँ भर्ती के नियमों में व्यवस्थित सुधार की जरूरत है वही मौजूदा नियमों-उपनियमों के अन्तर्गत भी यह निश्चित कर देने की जरूरत है कि जिन कामों के लिए कम योग्यता वाले लोगों से काम चल सकता है उसके लिए ऊँची योग्यता के व्यक्तियों को प्राथमिकता न दी जाय। इसके विपरीत, किसी खास काम के लिए ऊँची डिग्रीवाले लोगों को निश्चित ही अनग रहना चाहिए। किसी काम के लिए जो कम-से-कम योग्यता निश्चित रहती है उनके बजाय ऊँची योग्यता के व्यक्तियों के चुनाव की प्रवृत्ति से ऊँची योग्यता की प्राप्ति को अनावश्यक महत्त्व मिल जाता है। यह एक राष्ट्रीय बरबादी है। यह सामाजिक भ्रष्टाचार भी है। विभिन्न देशों में, जहाँ शिना सम्बन्धी सुविधाएँ काफी सुलभ हैं और ऊँची योग्यता के प्रमाण भी सुलभ होते हैं, काम देनेवालों में यह चेतना रहती है कि वह काम कम-से-कम योग्यता या अनुभव वाले व्यक्ति से भी हो सकता है तो किसी ऊँची योग्यतावाले व्यक्ति से बराबर उसकी शक्ति बरबाद न की जाय। अगर ऊँची योग्यतावाले व्यक्ति की जरूरत है तो उसे भी नौकरी दी जा सकती है। लेकिन उन लोगों की कीमत पर नहीं जो अपनी

योग्यता के अनुस्यू कामों पर लगाये जा सकते हैं। इस दिशा में तुरन्त एक कदम यह नियम बनाने उठाया जा जाना है कि वार्तों के कामों के लिए उनकी भर्तों की जायगी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा की अन्तिम सावजनिक परीक्षा पास कर ली है। ऐसे कामों के लिए ऊँचे योग्यतावाने व्यक्तियों की दरिस्त पर विचार नहीं होगा। अगर वार्तों के कामों के लिए रगी गयी कम-से-कम उम्र पाँच और कम कर दी जाय तो ऊँची योग्यतावाने लोग अपने आप छँट जायेंगे।

५. केन्द्रीय व राज्यस्तरीय के घटक

अन्ततः यह जरूरी लगता है कि केन्द्रीय व राज्य सरकारों के सामान्य प्रशासन विभागों व नौकरिया से सम्बन्धित विभागों में एक घटक पाना जाय। ऐसे घटक का काम होगा भर्तों के चालू नियमों का मूक निरीक्षण और उनमें समय-समय पर सुधार। यह घटक कुछ ऐसा अध्ययन भी कराता रहगा जिससे शिक्षा-प्रणाली व नौकरी-व्यवस्था व बीच की कड़ी बनी रह। यह रोजगार दफ्तरो से भी सम्पर्क रखेगा और व्यावसायिक नमूने व व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण भी करेगा। विश्लेषण, जानकारी प्रदान व सशोधन की प्रक्रिया ऐसे घटक की विशेष जिम्मेदारी हानी चाहिए।

९—ऊपर कुछ सुझाव दिये गये हैं। इस निवध की अपनी सीमाएँ हैं। फिर भी आज सामाजिक-आर्थिक दशा में अनुदिक परिवर्तन और सामाजिक ढाँचो व आर्थिक संगठनों के पुनिर्माण की आज की प्रक्रिया और उसके परिणाम स्वरूप पाताकरण में हो रहे परिवर्तन की शिक्षा के लिए चुनौती बनने को अच्छी तरह प्रकाश में लाना है। साथ ही समुदाय से कबो स्थापित करने की जरूरत और शिक्षा प्रणाली तथा नौकरी-व्यवस्था में सुधारों की आवश्यकता का भी लोगों के सामने लाना है। यदि लोगों की भर्तों व चुनाव सम्बन्धी हमारी नीतियों में इस निवध से नये-नये सर्जनात्मक सुधारों को प्रोत्साहन मिलता है और साथ ही शिक्षा-प्रणाली तथा नौकरी-व्यवस्था के बीच सामन्य बैठाने में मदद मिलती है तो उद्देश्य की काफी सीमा तक प्राप्ति हो जायगी।

उपकुलपति, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय

चाडली फिटूरी

अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए नये तरीके

[पढ़ने का आदत कला में ही बननी और मिटनी है। हाल ही में द्यूनिश के शैक्षणिक विद्वान-संस्थान के विरोधियों ने द्यूनीशिया के स्कूलों के लिए अध्ययन प्रेरक प्रणाली विकसित की है। इसके द्वारा न केवल जीवन पर्यन्त अध्ययन की आदत डाली जाती है बल्कि बालकों की लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति को भी भाँजा जाता है।—स०]

बहुतों युवकों के भावाभिव्यक्ति के ढंग के प्रति आश्चर्य कुछ अधिक ही आलोचनात्मक रख अपनाये हुए प्रतीत होते हैं। उनकी दृष्टि में आधुनिक युवक भूक, अनिश्चयी और यहाँ तक कि एकदम गूढ़ है और बहुतों लोग इस भूकना को आधुनिक युवकों द्वारा नये जा रहे अपने जीवन का ही प्रतिबिम्ब मानते हैं। उनके कोनाहलपूर्ण प्रदर्शनों, गीतों और संगीत पर उनकी कला और मॉड अभिव्यक्तियों पर हमेशा ही पिछोकि (कनीचे) नारा और अन्वजीवी विचार हावी रहता है।

ऐसा लगता है कि शिक्षकों के पास अभिव्यक्ति के स्तर में आयी इस गिरावट की केवल एव ही सफाई है और यह है अध्ययन में युवकों की रुचि।

क्या हमें यह स्थिति अपने समय का अग्रिहार्य रोग समझना चाहिए? युवकों में आयी अभिव्यक्ति के स्तर की गिरावट के लिए क्या हमें एकमात्र लोक माध्यमों को उत्तरदायी ठहराना चाहिए? यह एक आवश्यकता से अधिक सरल सफाई होगी। और न ही हमें आधुनिक युवक के सम्बन्ध में बुजुर्गों की राय को फोड़ियों की साई का एव और पहनू नहकर टाल देना चाहिए। सम्भवतः यह अपेक्षाकृत एक अधिक यथार्थवादी तर्क होगा कि स्वयं को अभिव्यक्त करने में युवकों की क्षमता में हुए ह्रास शिक्षा के स्तर में आयी गिरावट के कारण है।

सचाई यह है कि जब बहुतों लोग अपनी पीढ़ी के स्कूली छात्रों की तुलना आज के स्कूली छात्रों से करते हैं तो सम्भव है यह भूत जाने हैं कि अनेक देशों

में बल और परसा के स्कूल आज की तुलना में बड़ा अधिक चयनात्मक थे। आज के अधिकांश छात्र एवं ऐसे सुविधाजनक सामाजिक वय से आते हैं जिनके पास सांस्कृतिक परम्परा के नाम पर मौलिक 'लोक' परम्परा ही होती है।

यह कहना कि एवं सुविधाजनक परिवेश के वस्त्रा को अध्ययन पसंद नहीं होता है किसी भी प्रकार से एवं मूल्यात्मक निष्पत्ति नहीं है बल्कि यह तो एक सीधा सादा तथ्य वचन है। अगर वे पढ़ते नहीं हैं अगर उन्हें अध्ययन करना पसंद नहीं है तो इसका कारण यह है कि उनके परिवेश ने उन्हें पढ़ने के लिए कभी प्रोत्साहित ही नहीं किया है।

उदाहरणार्थ द्यूनीशिया में १९६६-६८ में किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला था कि स्कूलों के पुस्तकालयों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, (यहाँ तक कि नये-नये खुले स्कूलों में तो उनका अस्तित्व तक न था) या फिर वे एकदम बेकार हूँ, शिक्षाशास्त्रीय या शैक्षणिक मापदण्ड के अनुसार नहीं छाड़ी गयी थी।

छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि की कमियों को दूर करना तो अलग रहा मे स्कूल तो अध्ययन को पाठ्यक्रम का एक भाग बनाकर उनमें आमदौर पर और भी अधिक वृद्धि करत प्रतीत होते हैं। छात्रों और अध्यापक दोनों को ही पाशक सेन्सेट लैक्चर या अध्ययन का घण्टा समान रूप से अवरोधक कृत्रिम और उबाऊ लगते हैं।

फिर भी अभिव्यक्ति की सुविधा केवल लिखित रचनाओं में पाए जाते नमूनों की परख के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सशम और सार्थक लेखकों की रचनाओं से परिचित होना अपूर्व मानवाय अनुभव को अनुभूत करने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन इससे भी अधिक पाठक प्रत्येक पृष्ठ पर यह देख सकता है कि एक कुशल लेखक एक ऐसे ढंग से मनोभाव या विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कितनी कुशलता से शब्दों और मुहावरों का प्रयोग करता है कि मनोभाव या विचार न केवल स्पष्ट हो जाते हैं बल्कि वे अधिकतम गहनता और प्रभावशालिता से सम्पन्न भी हो जाते हैं।

जब अध्ययन आरंभ वन जाता है तो किसी भी लेखक की रचनाओं से घनिष्ठता पाठक को सहभागिता अध्ययन की ओर ले जाती है। यही वह सह भागिता है जो उस समय हैनरी मिलर के मस्तिष्क में थी जब उसने यह कहा था कि जब भी कोई व्यक्ति पुस्तक उठाता है तो उसे यही आशा होती है कि वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा है जो स्वयं उसके अपने दिल की बात बहेगा जिसके साथ वह उन श्रद्धादियों और आनंदों का अनुभव कर सकेगा।

जिन्हें स्वयं प्रकाश में लाने के मामले में हम अत्यधिक मरुंधी और भीरु होत हैं, वे अपने सपने देख सकेगा जो जीवन को वही अधिक मोहर बना देने हैं और सम्भवतः एक ऐसा जीवन-दर्शन मिल जायेगा जो हमारे मुँह बाये ग़ड्डी परीक्षाओं और समस्याओं का सामना करने में हमें और अधिक मशम व समर्थ बना देगा । इस प्रकार की सहभागिता कभी भी निष्क्रिय नहीं होती है ।

किशोरावस्था स्वच्छता और उत्साह की अवस्था होती है । सबसे अधिक तो वह अध्ययन की अवस्था होनी है । कुछ परिष्कृत बुरा उस सबकी सुस्पष्ट स्मृति जीवित नहीं रख पाते हैं जो कुछ उन्होंने अपनी किशोरावस्था में पढ़ा होता है । किसी भी व्यक्ति का जीवन—यहाँ तक कि उसका समूचा व्यक्तिव—बहुत हद तक प्रायः उस अध्ययन से निर्धारित होता जो उसने अपने जीवन के इस काल-खण्ड में किया होता है ।

एक ऐसे समय में जबकि दैनंदिन जीवन में मानवीय तत्व का क्षय किया जा रहा है, यह अपने आप में एक असाधारण दुःखदायक बात है कि वे ही स्कूल, जिनका मूल कार्य सीखने और जीने के लिए उनकी पूर्ण मानवीय क्षमताओं के विकास में छात्रों की सहायता करना है, आज भी उस समृद्धि की अपेक्षा कर रहे हैं जोकि एक गम्भीर अध्ययन प्रदान करती है और मिलन-स्थल का भी, जो वह अध्ययन, छात्र और शिक्षक के लिए उपलब्ध कराती है ।

अध्ययन मात्र एक साधन है, साध्य नहीं और छात्रों को अध्ययन की ओर प्रेरित करने के लिए सबनीयें खोज निकालने में तीन भ्रम प्रश्नों ने हमारा दिशा-निर्देश किया था—हमें क्या पढ़ना चाहिए ? हमें क्यों पढ़ना चाहिए ? हमें कैसे पढ़ना चाहिए ?

दूसरी शिवा में हमारी अध्ययन अभिप्रेरणा परियोजना ने इन तीनों की ही अपेक्षा कर दी थी । हमने स्वयं से प्रश्न किया था कि क्या वह सम्भव नहीं है कि छात्रों में अध्ययन की सतक पैदा करने के लिए वे ही दूसरे अथवा माध्यम प्रयोग किये जायें जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे अध्ययन के प्रति युवकों को हतोत्साहित करते हैं ? दूसरे शब्दों में, एक ऐसी चीज के आधार पर, जिसकी ओर युवक अत्यधिक अभिप्रेरित हैं, क्या हम उन्हें दूसरी गति-विधियों की ओर—विशेष कर अच्छे साहित्य के अध्ययन की ओर—अभिप्रेरित नहीं कर सकते हैं ? यह पहला कदम था ।

अगली अवस्था युवकों को पढ़े हुए साहित्य के बारे में चिन्तन, मनन, अनुसंधान, विचार-विमर्श और विचारों के आदान-प्रदान के लिए प्रेरित करने

और इस प्रकार अध्ययन में स्वयं नये आयाम खोजने में समर्थ बनाने के लिए उन्हीं माध्यमों का प्रयोग करने की थी। १९६८ में हमने अपनी यह धार्य-परिवर्त्यता द्यूनीक्षिया के शिक्षा अधिवारियों, स्कूल निरीक्षकों और शिक्षक परामर्शदाताओं को पेश करने का फैसला किया। शैक्षिक समस्याओं की अपेक्षा-कृत सुनिश्चित रूप में निरूपित करने के लिए हमने अपनी सिफारिशों उपरोक्त तीन प्रश्नों पर आधारित की थी।

क्यों पढ़ें ? यह जरूरी नहीं है कि किसी पाठ्यक्रम को सिफारिश करने का अर्थ यह भी हो कि छात्र उसका अनुसरण करेंगे—फिर भले ही वह सिफारिश एक आदेश के रूप में हो या कि मात्र एक गैनीपूर्ण परामर्श। यहाँ तक कि परीक्षाओं की धमकी इस बात की कोई गारण्टी नहीं देती। इसलिए हमने यह फैसला किया कि हमें स्कूली परम्परा से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना होगा, जिससे कि छात्र को यह महसूस कराया जा सके कि उसने स्वयं चुनाव किया है और वह निमी कृति विशेष को पढ़ने की सच्ची और निजी आवश्यकता से प्रेरित है। हम बेहतरीन शुरुआत की कल्पना लेकर चले थे अर्थात् हमने अपने दिमाग में एक ऐसा नगजोर और आनसी छात्र रखकर यह धार्यविधि तैयार की थी जिसने १५०-२०० पृष्ठ की विताव कभी भी अतः तब पढ़ी ही न थी। जहाँ तक भी सम्भव हो, पाठ्याभ्यास को पारस्परिक स्कूली पृष्ठभूमि से दूर रखा जाय। हम तो उसे स्कूल से एकदम अलग चलाने की तैयार थे लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण हमें यह विचार छोड़ देना पड़ा। अतः में हमने एक कक्षा में काम करने का फैसला किया लेकिन डेस्क के स्थान पर स्टूल और कुर्सियाँ रख कर, जो कि आवश्यकतानुसार इधर-उधर खिसवाई जा सकती थी, कमरे की व्यवस्था बदल दी थी। कमरे में एक प्रदर्शन पलक, एक प्रोजेक्टर, एक इधर से उधर जाया जा सकनेवाला चित्रपट और एक टैपरिकार्डर भी था।

सत्र में उपस्थिति पूर्णतः ऐच्छिक थी। एक मात्र शर्त यह थी कि छात्र एक ही शिक्षा स्तर और इस प्रकार कमीवेश एक ही आयु के होने चाहिए। यह अध्ययन प्रेरणा-सून स्कूली घण्टों से अलग लगाये गये थे और तब तक चलते रहे थे जब तक कि छात्रों की बहुसंख्या ने चाहा था। एक ग्रुप में २५-३० से अधिक छात्र नहीं होने दिये थे।

क्या पढ़ें ? शुरुआत हमने प्रस्तुतीकरण के स्तर (इस मामले में सेकेण्ड्री की तृतीय वर्ष की कक्षा) और पुस्तक का चयन करने के लिए समिति की स्थापना से की। हमें यह कामनसाऊ तरीका इसलिए अपनाना पड़ा था, क्योंकि

द्यूनीशिया में स्कूनी बच्चों की वास्तविक अध्ययन अभिरूचियों के बारे में इससे पहले कभी कोई अन्वेषण या जाँच-पड़ताल की ही नहीं गयी थी। बाद में 'द डायरी ऑफ़ ऐन फ्रांक' जैसी पुस्तकों का प्रयोग करते हुए हमने अपने परीक्षण जारी रखे तो हमें स्वरं यह पता चरना शुरू हो गया कि छात्रों की दिलचस्पी निम्नमें है।

तब से लेकर अब तक द्यूनिस् स्थित शैक्षणिक अध्ययन तथा स्कूनी बच्चों के अध्ययन के सम्बन्ध में अनेक सर्वेक्षण कर चुका है और बच्चों के अध्ययन के लिए पुस्तकों का चयन करने में निष्कर्षों को पर्य-प्रदर्शक की तरह इस्तेमाल कर चुका है। बयोटि यही यह चयन है जो बच्चों को न केवल अध्ययन के लिए वास्तविक प्रेरणा देना है बल्कि उनकी समूची बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक बनावट भी निर्धारित करना है।

कैसे पढ़ें ? हेनरी मिनर ने ठीक ही कहा है कि अन्य किसी भी वस्तु की तरह पुस्तक भी उस चीज को ह्राने के लिए एक बहाने के रूप में प्रायः इस्तेमाल की जाती है जिसकी हम वास्तव में तलाश में होते हैं। इस प्रकार अध्ययन मनोरंजन का मात्र एव एव हो सरता है। (पत्रिकाएँ और जासूसी कहानियाँ) या जल्दी से मूचनाएँ समावेशित करने का एक साधन (समाचार पत्र और किसी की रचना से सम्बद्ध लोकप्रिय किये या चुके उद्धरण) या सीखने, स्वशिक्षा और सर्कसगत विवेचन का एक सुअवसर।

अध्ययन-दोस्ताहन को तबनीन प्रसारयोजना के लिए आविष्कृत सभी गति-विधियाँ अध्ययन के अन्तिम प्रकार से सम्बद्ध हैं।

पूरे सूत्र के दो चरण होते हैं और दोनों चरणों के बीच एक या दो सप्ताह का मध्यान्तर होता है जिससे कि छात्रों को प्रस्तावित पुस्तक पढ़ने के लिए समय मिल जाय।

पुस्तक छाँट लेने के बाद हम यह काम शुरू करते हैं जिसे हम चयन और संग्रहण कहते हैं। चयन के अतर्गत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लेखाश छाँट लेता होता है जो शैली और वर्य की दृष्टि से विशिष्ट हो और जिनके प्रति सम्बद्ध आयु एवं शैक्षणिक स्तर के छात्र सर्वाधिक ग्रहणशील हो।

इसके बाद हम पुस्तक से अनेक पुरुषों और महिलाओं के स्वरों में पढ़े गये लेखाशों की टेपरिकार्डिंग के स्वर-ग्रथन तैयार करते हैं, हालांकि यह जरूरी नहीं होता है कि वे अश उसी क्रम में पढ़े गये हो जिस क्रम में वे पुस्तक में आये हैं। स्वर-संग्रथन का प्रयोग मात्र एक ऐसा परिवेश तैयार करने के लिए किया

जाता है जो रचना का भार उद्घाटित किये बिना ही दिलचस्पी पैदा कर सके। पुस्तक का सारांश प्रस्तुत करना उन उद्देश्यों का प्रतिवाद करना होगा जो हमने परियोजना के प्रारम्भ में ही निर्धारित किये थे। हमारा उद्देश्य थोड़ा ही रसिक को बड़ाना भर है।

हमने यह पैमाना दिया कि अगर हम उच्चरित अंशों की पुस्तक की विषय-वस्तु के उन्मुख भाषात्रीय समूहों के छोटे-छोटे टुकड़ों से सम्बद्ध कर दें तो स्वर संप्रयन वही अधिक प्रभावशाली होगा और कि यह बच्चों को मूल पाठ को समझने में भी सहायक होगा। चूंकि मगन कुछ मनोभावों का मनेगों को सम्प्रयुक्त कर सकता है, इसलिए वह ऐसी चीजें उद्घाटित कर दे सकता है जिन्हें एक निम्न भाषा भाषात्रीय क्षमता का बच्चा बिलिख पाठ से उनको जल्दी नहीं समझ पायेगा।

हमारे छात्र द्वि-भाषाभाषी (अरबी और फ्रेंच) हैं। वे प्रायः पाठशाला के तीसरे वर्ष में फ्रेंच पढ़ना शुरू करते हैं और उनका अभिगमन स्वर फ्रेंच और अरबी दोनों में ही समान रूप से नीचा है। इसलिए हमारी अध्ययन-प्रोत्साहन की तरनीय परियोजना में दोनों भाषाओं में अध्ययन समाविष्ट है। दीर्घकालिक विज्ञानों के सत्यान द्वारा इस परियोजना पर प्रकाशित की जानेवाली विशेष रिपोर्ट में परीक्षणों में प्रयुक्त अरबी और फ्रेंच लेखकों व रचनाओं की पूरी सूची और संकलित वैज्ञानिक व दृश्य-श्रव्य चित्रा सम्बन्धी आँकड़े सम्मिलित होंगे।

स्वर संप्रयन के प्रभाव की जानकारी देने और उस प्रभाव को बड़ाने के लिए हम प्रदर्शन फनक और स्लाइड जैसे दृश्य सहायक भी प्रयोग करते हैं। फनकों का प्रयोग लेखक और उनके जीवन के बिना, पुस्तक में प्रयुक्त चित्रों व स्वयं पुस्तक की प्रतिमों के दर्शन के लिए किया जाता है।

सत्र प्रारम्भ होने पर युव का नेना (जो प्रायः दीर्घकालिक विज्ञानों के सत्यान का सदस्य या फिर इस सत्यान द्वारा प्रशिक्षित कोई अध्यापन होता है) छात्रों का स्वागत करता है और उन्हें प्रदर्शित वस्तुओं का निरीक्षण करने का सुताव देता है। इसके बाद वह लगभग पाँच मिनट में पुस्तक का संक्षिप्त परिचय देता है, पुस्तक (शीर्षक, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करता है और लेखक के सम्बन्ध में अनेक स्लाइडें दिखायी जाती हैं। इसके बाद टेपरिकॉर्डिंग संप्रयन बजाया जाता है।

टेप बजने के दौरान, जिसकी अवधि २५ या ३० मिनट होती है, अतिरिक्त अभिकृति पैदा करने के लिए अन्य स्लाइडें बिताई जाती हैं। जिस सत्र में

विवेच्य पुस्तक पोल डी करोटे (प्रचलित ज्यू रीति द्वारा अने ही वचन का बटु उपयोग चित्रण सम्पादक) को उसमें हमने जहाँ एक और चित्रपट पर अबना करने की मन्त्रिणी वाले एक किशोर की तसवीर लिखी वहाँ दूसरी ओर बच्चे अन्तिम अध्याय— रिवोल (विद्रोह) का एक अंग सुन रहे थे ।

रिवोल की समाप्ति पर बच्चों के बीच एक वाद विवाद शुरू करने के लिए ग्रुप का नेता प्रश्न उत्तर का तरीका प्रयोग करता है । यदि विवाद के दौरान उमरा काम यह होता है कि वह पुस्तक की विषयवस्तु का पता नहीं चलने दे बल्कि पुस्तक का स्वयं पढ़ने की बच्चों को उकता का बढ़ाने में सहायक हो । यह प्रथम चरण समाप्त होने पर बच्चों से कहा जाता है कि वे चाहें तो पुस्तक की एक प्रति न जा सकते हैं और ग्रुप के नेता के साथ पुस्तक के मूल विषय के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के लिए एक तारीख निर्धारित कर दी जाती है ।

दूसरा चरण एक या दो सप्ताह बाद शुरू होता है । इस बार वे स्वयं वाद विवाद को चलाने ह । इसके लिए उन्हें अपने में से ही अध्यक्ष सचिव और उनके प्रसक्त चुन लेते होते हैं । जैसे-जैसे परीक्षण आगे बढ़ता जाता है ग्रुप के नेता द्वारा अंग की जानेवानी भूमिका महत्व की दृष्टि से कम होती चली जाती है । क्योंकि बच्चे आम-अनुशासन लोकतन्त्र और उत्तरदायित्व के नियमों का पालन करना सीख लेते हैं ।

उत्तरदायित्व दिन दिनों पाइल डी करोटे और डायरी आव एन फाक क अध्ययन ग्रुप चल रहे थे तब बच्चों ने किशोरावस्था युद्ध और शान्ति सह शिन्ना, विवाह तलाक घन डायरी रखना आदि से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन एवं संवर्धन के लिए स्वच्छता से ही विभिन्न ग्रुप बना लिये थे । इस प्रकार अध्ययन एवं एडवोकेट (साहसिक क्रिय) बन जाता है ।

बच्चे स्वयं ही यह निर्णय करते हैं कि कोई वाद विवाद कितनी देर चलना चाहिए । ये वाद विवाद और अध्ययन दल द्विभाषी बच्चों को (जो मुख्यतः अरबी धरो के होते हैं) उच्चारित और लिखित फल का अभ्यास करने का एक अच्छा सुझावसर प्रदान करते हैं ।

लेकिन परियोजना द्वारा खोली गयी सम्भवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्भावना उन वाद विवादों और अध्ययनों के माध्यम से खुली है जो नयी अध्ययन आवश्यकताएँ पदा करने हैं और बच्चों को नयी पुस्तकों के अध्ययन की दिशा में

अभिमुख करते हैं। इस प्रकार अध्ययन की एक क्रिया दूसरी क्रिया को जन्म देती है और प्रत्येक पुस्तक-अध्ययनों, जीवंत वाद-विवादों, नये सम्पर्कों और सृजनात्मक गतिविधियों का प्रारम्भ करनेवाली बन जाती है।

मुझे प्राथमिक पाठशाला के पाँचवें वर्ष के बच्चों का एक वाद-विवाद याद है जिसमें मैं उपस्थित था। वाद-विवाद विक्टर ह्यूगो के लॉ मिजरेबुल कोसोले की वरुण कथा के एक अंश पर हो रहा था। लगातार डेढ़ घण्टे तक उन बच्चों के बीच एक प्रखर वाद-विवाद चलता रहा था, जिन्हें दो वर्ष से भी कम समय से फ्रेंच पढ़ाई जा रही थी। इससे पता चला कि जब दस-ग्यारह वर्ष के बच्चों के पास पर्याप्त प्रयोजन होता है तो वे न केवल एक घण्टे से भी अधिक समय तक एकाग्र रह सकते हैं, बल्कि स्वयं को एक ऐसी भाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं जो उन्होंने अभी-अभी बोलना सीखी है।

पुस्तकों का पढ़ना कुछ बच्चों को किती-न-किती चरित्र या स्थिति को चित्रित करने के लिए चित्रकला की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है; क्योंकि उस चरित्र या स्थिति ने अध्ययन या वाद-विवाद के दौरान उन्हें प्रभावित किया था। हाथ कितों में ऐसे अनेक चित्र जुड़ चुके हैं और वे दूसरे बच्चों के साधारण प्रदर्शन फचकों को अत्यधिक सम्पन्न कर चुके हैं।

हम यह महसूस करते हैं कि इस उवाक वातावरण और नीरस परिवेश से बहुत आगे निकल आये हैं। जिसमें हमें अपने शुरुआतकाल में रहना पड़ा था, और दुर्भाग्य से आज के भी अनेक बच्चों को रहना पड़ रहा है जो 'आदेशानुसार अध्ययन' और सरकारी पाठ्यक्रमों की पुस्तक-रिपोर्टों का परिवेश था।

अध्ययन के लिए किस प्रकार के प्रोत्साहन का हमने उल्लेख किया है वह अध्ययन कार्यक्रमों को निर्जीव और प्रभावहीन बनने की बजाय (जैसा कि प्रायः होता है), सजीव और प्रभावशाली अध्यापन विधि में रूपांतरित हो सकने में सक्षम कर सकेगा।

('यूनेस्को क्यूरियर' : अगस्त '७२ के अंक
से सामान्य पुनर्मुद्रित)

सपुस्तक परीक्षा

[राजस्थीय सेन्ट्रल पेडागॉजिकल इन्स्टीच्यूट इलाहाबाद (३० प्र०) में परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में चलायी हुई एक परियोजना ।—सम्पादक]

१—परियोजना की आवश्यकता : वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारे छात्रों की सामर्थ्य तथा योग्यताओं अथवा उपलब्धियों को उचित रूप से निर्धारित करने में सहायक सिद्ध नहीं हुई है । इसका अभिप्राय केवल उनकी स्मरण शक्ति को आँकना ही है । इस भाँति विद्यार्थियों अध्यापकों और अभिभावकों के समस्त प्रयास छात्रों की रटन्ट विद्या की ओर लगे रहते हैं । उसमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए सम्प्रत्ययात्मक (कान्सेप्चुअल) ज्ञानार्जन और सर्जनात्मक चिन्तन के विकास की ओर कम बल दिया जाता है ।

अध्यापन के दैक्षिक पक्ष की ओर जो बच्चे के समुचित विकास में सहायक होता है हमारे अध्यापकों और विद्यार्थियों का ध्यान आरपित करने की दृष्टि से यह निश्चित किया गया कि इस प्रकार के प्रश्न-पत्रों की रचना की जाय जिससे छात्रों और अध्यापकों में स्वतः चिन्तन करने की रुचि उत्पन्न हो । उन्हें रट-रट विद्या के सर्वांग माँगों में सीमित न रहना पड़े ।

यह भी निश्चित किया गया कि प्रश्न-पत्र इस प्रकार के हों कि यदि छात्रों को पुस्तकों के प्रयोग करने की छूट प्रदान कर भी दी जाय तो उनकी उपलब्धियाँ में किसी प्रकार का प्रभाव न पड़ेगा । इस प्रसंग में यह आशा की कि प्रश्न-पत्रों के स्वरूप और शिथिल में इस प्रकार के परिवर्तन से परीक्षा भवनों में गुप्त रूप से अनुचित साधन प्रयोग करने अथवा अपने साम्य पुस्तकें, टिप्पणियाँ आदि सजाने की ओर बच्चों का ध्यान कम जायगा ।

२—लक्ष्य : पर्यायानता कं निम्नांकित लक्ष्य थे

इस प्रकार के प्रश्न पत्रों की रचना करना जिससे—

(क) छात्रों को वर्तमान समय में प्रचलित रट-रट अभ्यास से रोका जा सक ।

(ख) सम्प्रत्ययात्मक (कान्सेप्चुअल) ज्ञानार्जन और रचनात्मक चिन्तन की क्षमता को विकसित किया जा सके और

(ग) छात्रों को परीक्षा-भवन में पुस्तकों, टिप्पणियों आदि से नक़ज़ करने के रूप में अनुचित साधन के प्रयोग को रोका जा सके ।

३—परियोजना की सीमाएँ : (अ) वर्तमान अध्ययन को इस संस्थान में संलग्न राजकीय इण्टर कालेज की कक्षा ८ के दोनों वर्गों में परिसीमित किया गया ।

(आ) इस परियोजना के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेज़ी, गणित और सामान्य-विज्ञान विषयों को लिया गया ।

४—शोध के उपकरण : निम्नलिखित उपकरण प्रयोग में लाये गये :

(क) सशोधित प्रकार के प्रश्न-पत्र ।

(ख) इण्टरमीडिएट कालेज द्वारा संचालित पन्मासिक परीक्षा का समेकित परीक्षाफल ।

५—कार्य-विधि : सितम्बर १९६९ की मासिक परीक्षा के लिए कक्षा ८ के दोनों वर्गों के १०२ छात्रों को ६ छोटे-छोटे समूहों में विभाजित किया गया । प्रत्येक छोटे समूह में १५ से २० तक छात्र सम्मिलित थे और प्रत्येक समूह संस्थान के एक छात्राध्यापक के सरक्षण में था । प्रत्येक प्रश्न-पत्र में पूर्णतः २० थे और प्रत्येक प्रश्न-पत्र की समयावधि ३५ मिनट थी । छात्राध्यापकों ने छात्रों की परीक्षा का संचालन और मूल्यांकन किया । संस्थान के सम्बन्धित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन के परिणामों की अन्तिम रूप से जाँच की गयी ।

जनवरी, १९७० की परीक्षा के लिए छात्र छ. कमरों में बैठाये गये । इण्टरमीडिएट कालेज के अध्यापकों ने गिरीक्षकों का कार्य किया ।

६—प्रस्तुतीकरण और प्रदत्तों (डेटा) का विश्लेषण : सितम्बर और जनवरी मास की परीक्षाओं के प्रश्न मुख्यतः कुछ सम्प्रत्ययों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के प्रयोग पर आधारित थे । पाठ्यसामग्री के रटन्त विद्या पर आधारित तथ्यों की पुनरावृत्ति सम्बन्धी प्रश्न नहीं थे । इस कारण पहले से कण्ठस्थ किये हुए ज्ञान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने का छात्रों को कोई अवसर नहीं रह गया । प्रश्नों के उत्तरों को प्रस्तुत करने के लिए सर्जनात्मक चिन्तन और वास्तविक बोध की आवश्यकता थी । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कण्ठस्थ करने और रटन्त विद्या के दूषित अभ्यास को ख़त्म करने का लक्ष्य प्राप्त किया गया । इसके अतिरिक्त, संशोधित रूप के प्रश्न-पत्रों के द्वारा, जिनका सितम्बर और जनवरी की परीक्षाओं में प्रयोग किया गया था,

परीक्षा की यह प्रणाली छात्रों के मन्वत्नात्मक ज्ञान और सर्जनात्मक चिन्तन पर बल देती थी, जिससे उन्हें परीक्षा में सफलता प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में यह प्रणाली वास्तविक ज्ञानार्जन के लिए सम्प्रत्ययात्मक ज्ञान और रचनात्मक चिन्तन की क्षमता का विकास करती है। प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में कुछ शब्द उपर्युक्त कथन को और अधिक स्पष्ट कर देंगे।

हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के प्रश्न-पत्रों में ऐसे प्रश्न दिये गये थे जिनमें पूर्वार्जन ज्ञान को भी परिस्थितियों में प्रयोग करने की आवश्यकता थी। उनमें उन परम्परागत प्रश्नों को नहीं रखा गया था जो केवल रटन्त विद्या का मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार सशोधित प्रश्नों द्वारा यह मूल्यांकन हो जाता था कि छात्रों को समस्त विषय का कहीं तक बोध हुआ है और उनके मस्तिष्क में समग्र वस्तु की स्पष्ट सकल्पना कहीं तक अंकित हुई है।

गणित में भी, सूत्र अथवा समीकरण अथवा प्रमेय प्रत्यक्ष रूप में नहीं पूछे गये थे। इसके स्थान पर बोध और प्रयोग पर आधारित प्रश्न पूछे गये थे। जब कोई परिभाषा दी गयी तो उसके अनन्त प्रश्न का दूसरा भाग भी सन्निविष्ट किया गया, जिससे यह विदिष्ट हो सका कि छात्र परिभाषा के वास्तविक अर्थ को समझने में कहीं तक समर्थ हुआ।

इसी प्रकार सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसमें पाठ्य-सामग्री से प्रत्यक्ष रूप में कोई वैज्ञानिक तथ्य पूछा गया हो। इसके स्थान पर प्रश्न पाठ्यक्रम में सम्मिलित सकल्पनाओं के द्वारा प्राप्त ज्ञान के प्रयोग पर आधारित थे। किसी विशेष प्रश्न का सफलता के साथ उत्तर देने के लिए छात्रों में सकल्पना के स्पष्ट परिज्ञान और बोध की आवश्यकता थी।

परीक्षा-भवन में पाठ्य पुस्तकों तथा सहायक-पुस्तकों, टीकाओं आदि से नज़र करने के रूप में अनुचित साधन प्रयोग को समाप्त करने का इस परियोजना का तीव्र लक्ष्य है, जिसके लिए निम्नांकित बातों के विनिर्देश की आवश्यकता है:—

सितम्बर की परीक्षा, जनवरी की परीक्षा और छमाही परीक्षा में सफलता प्राप्त करनेवाले परीक्षार्थियों के प्रतिशत का बाट

विषय	सशोधित प्रश्न-पत्र के आधार पर सितम्बर की परीक्षा	सशोधित प्रश्न-पत्र के आधार पर जनवरी की परीक्षा	परम्परागत प्रश्न-पत्र के आधार पर छमाही परीक्षा
हिन्दी	३०	२३	९२
अंग्रेजी	२७	५६	८७
गणित	२०	१९	८५
सामान्य विज्ञान	१०-५	१६	८६

उक्त चाट से स्पष्ट है कि छात्रों ने सशोधित प्रश्न-पत्रों पर आधारित परीक्षाओं में उतना उत्तम कार्य नहीं किया जितना परम्परागत परीक्षा में किया। परम्परागत परीक्षा के प्रत्येक विषय में छात्रों की सफ़लता का प्रतिशत बहुत ऊँचा था। इसके अतिरिक्त सितम्बर की परीक्षा में अंग्रेजी को छोड़ कर दोष विषयों में उत्तम परीक्षार्थियों के प्रतिशत जनवरी परीक्षा के प्रतिशत से अधिक ऊँचे थे।

यह स्वीकार करना पड़ा कि सितम्बर की परीक्षा छात्रों के लिए प्रथम अनुभव की थी। इस कारण यह उचित ही था कि छात्रों को जनवरी की परीक्षा में अधिक उत्तम परीक्षाफल दिखाना चाहिए था। किन्तु वास्तव में बात बिल्कुल ही विपरीत रही। इसके लिए केवल यही सम्भावित व्याख्या है कि सितम्बर-परीक्षा केवल एक मासिक परीक्षा थी और इस कारण पाठ्यक्रम सीमित था। सितम्बर मास में जो विषय सामग्री पढ़ाई गयी थी उसी पर प्रश्न आधारित थे। परन्तु इसके विपरीत जनवरी की परीक्षा में अधिक विस्तृत पाठ्यक्रम अर्थात् जो कुछ जुलाई से दिसम्बर तक पढ़ाया गया था सम्मिलित था। अतएव परीक्षा फल में अवनति स्वाभाविक है।

छमाही परीक्षा के परीक्षा फल से सितम्बर और जनवरी की परीक्षाओं के परीक्षा फलों की तुलना करने पर यह स्पष्टतः विदित हो जाता है कि यद्यपि छात्रों को सितम्बर और जनवरी की परीक्षाओं में हर प्रकार की सामग्री प्रयोग करने की सुविधा थी तथापि उन्होंने छमाही परीक्षा में, जिसमें उक्त सुविधा नहीं प्रदान की गयी थी अत्यधिक उत्तम परीक्षा फल दिखाये। इससे सिद्ध होता है कि सशोधित रूप के प्रश्न-पत्रों से छात्रों में परीक्षा भयन में पाठ्य-पुस्तकों अथवा सहायक पुस्तकों अथवा टिप्पणियों आदि से नकल करने के रूप में अनुचित साधन के प्रयोग की प्रवृत्ति कम होती है।

सितम्बर, जनवरी और छमाही परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के प्रतिशत को दिखानेवाला चार्ट

विषय	सशोधित प्रश्न-पत्र पर आधारित सितम्बर की परीक्षा	सशोधित प्रश्न-पत्र पर आधारित जनवरी की परीक्षा	परम्परागत प्रश्न पत्र पर आधारित छमाही परीक्षा
हिंदी	५	१	३०
अंग्रेजी	१४	१८	४१
गणित	५	२	५०
सामान्य विज्ञान	८	४	२६

जब हम उन छात्रों की सख्या के सम्बन्ध में विचार करते हैं जिन्होंने सितम्बर और जनवरी की परीक्षाओं और छमाही परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किये तब हम उसी प्रकार की स्थिति पाते हैं जा सफ़्त छात्रों के प्रतिशत के सम्बन्ध में पायी गयी थी। परम्परागत प्रश्न-पत्रों पर आधारित परीक्षा के समस्त विषयों में प्रथम श्रेणी प्राप्त करनेवाले छात्रों का प्रतिशत बहुत ऊँचा है। किन्तु सितम्बर और जनवरी की परीक्षाओं के प्रत्येक विषय में प्रथम श्रेणी प्राप्त करनेवाले छात्रों का प्रतिशत बहुत कम है। इसके अतिरिक्त जनवरी की परीक्षा का परीक्षा फल सितम्बर की परीक्षा के परीक्षा फल से निम्नकोटि का रहा है जैसा कि उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रतिशत के अन्तर्गत भी विवेचन किया जा चुका है। वास्तव में यहाँ भी सितम्बर की परीक्षा के समान अग्रजी एक अपवाद है। वही सम्भावित व्याख्या जा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रतिशत के अधीन दी गया है वहाँ भी ठीक उतरती है। इसमें यह अर्थ निकलता है कि अच्छे छात्र ही सितम्बर और जनवरी की परीक्षा में अच्छा परीक्षा फल लिया सके।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्रथम श्रेणी के छात्र भी सितम्बर और जनवरी की परीक्षाओं में छमाही परीक्षा की अपेक्षा अच्छा परीक्षा फल न दिखा सके। उनके परीक्षा-फल इस तथ्य को स्पष्ट प्रमाणित करते हैं कि छात्रों में प्ररणा की भावना का अभाव निम्न प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है। वास्तव में छात्रों में प्ररणा की भावना का अभाव वनमान परियोजना के सम्पादन में एक स्वाभाविक कठिनाई थी क्योंकि छात्र यह जानते थे कि इसका उनकी कक्षेत्रति पर कोई प्रभाव नही पडगा।

सितम्बर और जनवरी की परीक्षाओं में शोचनीय परीक्षा-फल का कारण यह तथ्य ठहराया जा सकता है कि संशोधित रूप के प्रश्न-पत्रों में केवल ज्ञान के प्रयोग पर आधारित प्रश्नों का समावेश था। सूचना-स्तर पर ज्ञान की परीक्षा करनेवाले प्रश्नों को पूरणरूप हटा दिया गया था।

यहाँ यह उल्लेख कर देना भी अप्रासंगिक न होगा कि संशोधित प्रश्न-पत्रों पर आधारित नवीन परीक्षा प्रणाली विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति बढ़ाने को समझा तथा प्रत्यक्षमक जानाजब पर तो बल देती है किन्तु शिक्षा का अथवा विद्यार्थी के विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि उसे कुछ सूचना स्तर तथा स्मृति पर आधारित ज्ञान प्राप्त हो। उनके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न या इन पर आधारित प्रश्न-पत्र उपयोगी हो सकते हैं।

७-परियोजना के निष्कर्ष सशोधित प्रश्न-पत्रों पर आधारित परीक्षा-प्रणाली शिक्षा के उन लक्ष्यों की पूर्ति करती है जिनमें मौलिक तथा तर्कयुक्त चिन्तन का विशेष स्थान है। इस परीक्षा-प्रणाली को प्रारम्भ करना एक क्रान्तिकारी बदल होगा और यह विश्वास किया जा सकता है कि यदि इस प्रकार के प्रश्न-पत्र परीक्षा में दिये जायें तो शिक्षकों को अपनी शिक्षण-विधि में भी परिवर्तन करना होगा, क्योंकि जब शिक्षक अपने विद्यार्थियों को मौलिक तथा तर्कयुक्त चिन्तन का अभ्यास करावेंगे तभी उस प्रकार के प्रश्न-पत्रों के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। उपलब्ध आँकड़ों से स्पष्ट है कि गणित में लगभग २० प्रतिशत विद्यार्थी नवीन परीक्षा-प्रणाली में सफल हो सके हैं। अन्य विषयों में भी उत्तीर्ण होनेवालों का प्रतिशत परम्परागत परीक्षा-प्रणाली की अपेक्षा बहुत कम है। प्रश्न यह उठता है कि विद्यार्थियों के लिए कक्षाक्षति प्राप्त करने में नवीन परीक्षा-प्रणाली द्वारा मूल्यांकन का क्या स्थान होगा? वस्तु-स्थिति यह है कि हम नवीन परीक्षा-प्रणाली के आधार पर मूल्यांकन परके केवल २० प्रतिशत को कक्षाक्षति देंगे तो अभिभावकों में बड़ा असंतोष होगा। इसलिए सुझाव यह है कि प्रारम्भ में हर विषय के विभिन्न क्षेत्रों पर ऐसे प्रश्नों का संकलन किया जाय जो मौलिक चिन्तन और तर्कना शक्ति के विकास को प्रेरणा देते हों और प्रश्नों के इस संकलन को हर स्तर के विद्यालयों में प्रसारित कर दिया जाय। इससे शिक्षकों को एक नयी दिशा मिलेगी और वे न केवल इन प्रश्नों का प्रयोग अपने प्रश्न-पत्र बनाते समय कर सकेंगे, प्रत्युत अपनी शिक्षण-विधि को भी उनसे अनुसार बदलने का प्रयास करेंगे।

नवीन परीक्षा-प्रणाली के प्रश्न-पत्रों को तैयार करने के प्रसंग में यह भी निष्कर्ष निकला कि गणित, विज्ञान और भाषा में इस प्रकार के प्रश्न बनाने में अधिक कठिनाई नहीं है बल्कि इतिहास जैसे विषय में इस प्रकार के प्रश्न तैयार करने में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि इतिहास के अध्ययन में तथ्यों का प्राचुर्य है और मौलिक चिन्तन की आवश्यकता कम-से-कम विद्यार्थी शिक्षा में कम पड़ती है। अतएव यह भी परिणाम निकलता है कि नवीन परीक्षा-प्रणाली का प्रयोग अभी विज्ञान, गणित तथा भाषा तक ही सीमित रखा जाय। इन विषयों में जो प्रश्न-पत्र बनाये जायें, उनमें प्रश्नों की संख्या अधिक-से-अधिक रखी जाय जिससे पाठ्यक्रम का अधिक-से-अधिक समावेश हो सके, छात्रों को बातचीत का अवसर न मिले और वही छात्र पुस्तक का लाभ उठा सकें जिन्होंने पुस्तक को अच्छी तरह पढ़ा है।

परीक्षा-प्रणाली में परिवर्तन करने से सम्बन्धित प्रयाग करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि विद्यालयों में शिक्षण का कार्य पुराने ढंग से चलता है। नये ढंग से परीक्षा लेने के लिए कक्षा-शिक्षण भी नये ढंग से चलाना होगा और उसी के आधार पर उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करने के मापदण्ड भी निर्धारित करने होंगे। वर्तमान नियमों की व्यवस्था में कक्षाशक्ति के सिद्धान्त को बदलना सम्भव नहीं हो पाता। निश्चय ही पाठ्य-क्रम का संशोधन भी बदलना आवश्यक होगा। ऐसा स्थिति में जब तक विद्यालयों को पूर्ण स्वतंत्रता न मिले, तब तक परीक्षा-प्रणाली को बदलने का प्रयाग सफल होना असम्भव रहा तो दुःसाध्य अवस्था है।

अन्त में यह उम्मेद करना है कि एक या दो वर्ष के अन्त में एक भारी-भरतम परीक्षा लेकर विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना अत्यन्त अनुचित है। वास्तव में मूल्यांकन दैनिक, मात्साहिक तथा मासिक होना चाहिए और बालक के विकास के सभी पक्षों शैक्षिक, सवैसात्मिक, चारित्रिक तथा कौशल, अभिवृत्ति, आदि से सम्बन्धित होना चाहिए और इसके लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि बालक के बहुमुखी विकास का मारन करने के लिए कोई एक ही विधि कदापि पर्याप्त नहीं हो सकती। इसलिये विद्यालयों को यह सुझाव दिया जाय कि वे बालकों के बहुमुखी विकास के मूल्यांकन की आन्तरिक व्यवस्था करें और उसका ऐसा अभिलेख रखें जिससे देखनेवाले को बालक की हर प्रकार की क्षमता का ठीक-ठीक ज्ञान हो सके। जब तक किसी बाह्य संशोधन द्वारा विद्यार्थियों के विकास का मूल्यांकन चलता रहगा तब तक बालक के व्यक्तित्व का व्यापक मूल्यांकन सम्भव न हो सकेगा। जहाँ तक स्तर में एकत्पना रखने की बात है, इसके लिए पाठ्यक्रम का निरूपण ठीक प्रकार होना चाहिए। प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा, जिनका शिक्षण से कोई सम्बन्ध नहीं होगा, शिक्षकों के कार्य का निरीक्षण करना अनुचित है और ऐसी व्यवस्था कहीं भी प्रगतिशील देशों में नहीं है। शिक्षकों के कार्य का निरीक्षण करना प्रधानाचार्य अथवा विषय के विशेषज्ञों का कर्तव्य होना चाहिए।

—राजकीय सेन्ट्रल पेडागॉजिकल इन्स्टीट्यूट,
इलाहाबाद

शिक्षा-पद्धति कैसी है ? कैसी होनी चाहिए ?

यज्जागवली गुप्त

प्रायः समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं एवं भाषणों इत्यादि में शिक्षा पद्धति के दूषित होने की चर्चा तथा उसके आमूल परिवर्तन का आह्वान देखने तथा सुनने को मिलता है। किन्तु कोई ठोस विचार या कार्यक्रम सम्मुख नहीं आते। प्रत्येक विचारक प्रश्न सूचक चिह्न के साथ ही साथ विस्मयादिबोधक चिह्न भी बना कर मीन हो जाता दीख रहा है। ऐसा विश्वास नहीं होता कि यह कोई बहुत गम्भीर समस्या है जिसका कोई समाधान न हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिक्षा-पद्धति तथा उसके दोषों की रूपरेखा एवं उसका विकल्प तथा निदान भी उन विचारकों के भस्तिष्क में है किन्तु कुछ व्यावसायिक प्रवृत्ति स्वार्थपरता विफलता अथवा उपहास के भय के कारण समस्या केवल समस्या ही रह जा रही है जैसे डालडा घी में रंग मिटाने की समस्या। अथवा शिक्षा पद्धति का अभिप्राय ही मनन में नहीं आता। शिक्षा-पद्धति से हमारा क्या अभिप्राय है ? यह स्पष्ट रूप से व्यक्त होना चाहिए अर्थात् इसका अभिप्राय अध्यापन शैली तथा विषय से है या शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था से है। मेरे व्यक्तिगत विचार से इसका अभिप्राय संस्थाओं की आंतरिक तथा बाह्य व्यवस्था से होना चाहिए।

शिक्षा की वर्तमान स्थिति तथा उसका परिणाम प्रत्यक्ष है। इसके विषय में कुछ कहना नही है। मुझे इसमें निम्न कतिपय मूल दोष बीख पड़ते हैं

(१) शिक्षा का व्यावसायिक रूप से लेना। (२) शिक्षा का उद्देश्य जीविका अर्जन की क्षमता प्राप्त करना मानना। (३) शिक्षकों में नीचरी

की श्रुति होना । (४) शिक्षा-संस्थाओं का वेरोजगारी की समस्या के हल के रूप में प्रयोग करना । (५) शिक्षा पर सरकारी अधिकार तथा उसमें सरकारी हस्तक्षेप । (६) साईं मेराने के अनुसार विषयों का विभाजन ।

अनुमानतः यदि शिक्षा, शिक्षक, शिष्य एवं शिक्षा-संस्था को उपरोक्त दोषों से मुक्त कर दिया जाय तो शिक्षा स्वतः करवट बदल देगी और एक प्रभावशाली क्रांति होगी जो देश में व्याप्त व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक सभी समस्याओं का समाधान कर देगी ।

उपरोक्त दोषों से मुक्ति की युक्तियाँ

1. शिक्षा-क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप एवं अधिकार का वहिष्कार ।
2. शिक्षा-संस्थाएँ पुण्य-प्राप्ति के उद्देश्य से, व्यक्तिगत प्रवास से आश्रम के रूप में स्थापित की जायें । इसकी स्थापना मयवा संचालन हेतु किसी प्रकार के दान-अनुदान इत्यादि स्वीकार्य न हो ।
3. शिक्षकों की नियुक्ति उनके प्रति सहानुभूति अथवा आर्थिक सहायता (नीकरी) देने की दृष्टि से न होकर उनके प्रति श्रद्धा एवं आस्था तथा उनसे बौद्धिक सहायता लेकर आभार प्रदर्शन के भाव से प्रेरित होनी चाहिए ।
4. शिक्षा-संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था की जाय कि शिक्षा की पूर्ण अवधि तक शिष्य-गृह परिवार के अतिरिक्त किसी भी अन्य परिवार से सम्बद्ध न हो सकें । अभिभावकों को यदा-कदा उनसे मिलने मात्र की अनुमति दी जाय ।
5. अध्ययन तथा अध्यापन में सरलता एवं सुविधा (प्रभाव) के विपरीत तप की भावना भरी जाय । सार्विक जीवन के लिए अनिवार्य सभी विषयों (ज्ञान तथा धर्म) का विश्लेषणात्मक अध्ययन कराया जाय अर्थात् प्रत्येक शिष्य को विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, कला, भूगोल एवं इतिहास इत्यादि का पूर्ण तथा समान ज्ञान दिया जाय ।
6. किसी भी विषय में विशेष शिक्षा देने के लिए सर्वप्रथम उस विषय में भारतीय प्राचीन विद्वानों के विचार से उन्हें अवगत कराया जाय, तत्पश्चात् वर्तमान तथा विदेशी मतों से अवगत कराया जाय, जिससे उनमें अपनी संस्कृति के प्रति आस्था उत्पन्न हो ।
7. धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन दैविक काल से ही कराया जाना चाहिए । प्रत्येक शिष्य को भारत में प्रचलित सभी सम्प्रदाय के धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन निष्पक्ष भाव से तथा समान रूप से कराया जाय ।

८. सभ्यता में व्यवस्था देने (कानून बनाने) का अधिकार गुरुओं को ही प्राप्त होना चाहिए । यहाँ सरकारी कानून नहीं लागू होना चाहिए ।
९. सस्थाएँ स्वावलम्बी होनी चाहिए अर्थात् शिष्य के शिक्षा-काल तक तथा गुरु परिवार के उनके जीवन पर्यन्त अथवा विद्यादान-काल तक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उनके परस्पर सहयोग तथा अवकाश के समय में सस्था की भूमि से उत्पन्न की गयी उपज अथवा कला तथा विज्ञान के क्रियात्मक अभ्यास से प्राप्त साधनों से ही होनी चाहिए । इनका कोई वेतन निश्चित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विद्या दान के भाव से प्रेरित महात्माओं का अपमान है ।

साधारणतः ये विचार देखने में असम्भव से प्रतीत होते हैं । इस विषय में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जामूल परिवर्तन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं किन्तु सुधार एवं संशोधन के लिए ये अनुपयुक्त हैं । वर्तमान से चिपके रहने का मोह इसे असम्भव का ही रूप देगा ।

इन योजना को क्रियान्वित करने की पहली कड़ी के रूप में सरकार को एक प्रलोभन, आश्वासन के रूप में देना होगा । सरकार आज शिक्षा पर प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि व्यय करती है । उससे यह आग्रह किया जाय कि वह शिक्षा-संस्थाओं की व्यवस्था स्वावलम्बी बनाने के लिए यदि पर्याप्त मात्रा में भूमि की व्यवस्था कर दे तो वह प्रतिवर्ष किये जानेवाले व्यय की राशि बचा सकेगी । इस प्रकार की सस्थाएँ वर्तमान विश्वविद्यालय, विद्यालय आदि को परिवर्तित करके भी स्थापित की जा सकती हैं ।

सरकार को यह भी आश्वासन दिया जा सकता है उपरोक्त व्यवस्था हो जाने पर भारत की प्रायः सभी समस्याएँ स्वतः हल हो जाएँगी । यहाँ तक कि जाट-समस्या, जनसंख्या-समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य-रक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक भेदभाव, साम्प्रदायिक समस्याएँ भा स्वतः हल हो जाएँगी और सरकार देश की भीतरी व्यवस्था में वर्तमान बिन्दु से स्वतः अन्तर्देशीय प्रगति में अग्रसर हो सकेगी ।

आचार्यकुल का संगठन

पृष्ठभूमि

यत्र मुक्ति और निधि-भुक्ति के विषय में विनोद के विचार कुछ भी रहे हों जहाँ तक आचार्यकुल का सम्बन्ध है प्रारम्भ से हाँ वे इस बात के रहे हों कि आचार्यकुल का एक संगठन बनना चाहिए नहीं तो आचार्यकुल हमारे ही रहेगा। कहलगाँव (भागलपुर) में आचार्यकुल का स्थापना के समय उ होने लगा हम यहाँ दो अपक्षाएँ निकल आये हैं। पहली बिहारदान की अपेक्षा और दूसरी यह कि शिष्यो की एक स्वतन्त्र मता छड़ी की जाय। शिष्यो का एक संगठन हो जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक के सभी शिष्य हों। इसमें एक निर्णायक समिति होगी जिसमें चुनाव और निष्पक्ष स्वतन्त्रता से होंगे। मानव के शिष्य बनने के लिए एक प्रतिभा इस संगठन के लिए दोगे। नीचे के शिष्यो की यदि यह अधिक मालूम हो तो १०० रुपये में से ५० पैसे दें। (आचार्यकुल पृष्ठ ६९)

यह उस दिन की बात है जिस दिन विनोदजी ने कहलगाँव में आचार्य कुल नाम का उच्चारण किया। परन्तु उसके भी एक दिन पहले भागलपुर में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था—एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ। आचार्यकुल की स्थापना के लिए आपको थोड़ा धन इकट्ठा करना होगा। आफिस बनाना होगा। कुछ कायकर्ता उसमें रखने होंगे। सारे बिहार में सम्पर्क करने के लिए जगह जगह मीटिंग बुनानी होगी। यह सब करने के लिए थोड़ा पैसे की जरूरत होगी। इसलिए मैंने मुझसे रखा है कि आचार्यकुल के सन्तान पर पर हस्ताक्षर करनेवाले जितने सन्तान होंगे वे अपनी तनहाह का एक प्रतिशत चन्दे के रूप में देंगे।

आचार्यकुल का एक संगठन बने, इस आन्धी बात को विनोय बारबार दोहराते रह रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बोनत हुए उन्होंने कहा—“काम को बढ़ाने के लिए पत्र-व्यवहार एक प्रोपेगण्ड का पूरे समय का खर्च, काफ़ी में सवरा भोजन मग जगह जाकर विचार समझाना, नये हस्ताक्षर लेना, आदि अनेक काम रह्यो। बिना पैसे के नही चलेगा। आचार्यकुल हवा में रहेगा।” दूसरी जगह एक प्रकार का व्यंग सा करते हुए वे कहते हैं ‘उत्तर प्रदेश में आचार्यकुल हुआ है महाराष्ट्र में भी आचार्यकुल स्थापित-स्थापित करने की बात चल रही है। यह अलग बात है कि अभी कुछ हुआ नहीं। ब्रह्म का वर्णन आना है कि यह निष्क्रिय शांत व्यवहारातीत है। हम ऐसे हो जायें तब तो ठीक है। लेपिन * ।’

वे एक दूसरे भाषण में फिर कहते हैं—“बिना पैसे के आचार्यकुल का प्रचार हो तो बिना काबज के यह सब हुआ यह सोचकर बाबा तो नाचेगा। परन्तु बिना पैसे के संगठन नहीं बनेगा।’ और लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। एक प्रतिशत तो बहुत भारी है आधा प्रतिशत भी नहीं दे रहे हैं। यह बात उन्हें बराबर छटकती रही है।

लेकिन बाबा की इतनी व्यग्रता के बावजूद, १९६९ तक अर्थात् आचार्यकुल की स्थापना के डेढ़ वर्ष बाद तक, और बावजूद इसके कि आचार्यकुल की स्थापना के शुरुआत बाद मुगेर (बिहार) गलेज के अध्यापको ने आचार्यकुल के लिए एक संगठन और कार्यक्रम की रूपरेखा बनायी थी और उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया था कि आचार्यकुल की इकाई के प्रत्येक सदस्य को अपने निर्धारित वेतन का एक प्रतिशत संगठन के संचालन के लिए अनिवार्य देना होगा, जिससे पूरा समय देनेवाले का वेतन दिया जा सके और अन्य दूसरी व्यवस्थाओं पर व्यय किया जा सके ऐसा नहीं हो पाया।

मेरी समझ में इसका एक बड़ा कारण यह था कि मुजफ्फरपुर के अध्यापको ने आचार्यकुल की सदस्यता का जो संकल्प-पत्र तैयार किया था उसमें उन्होंने पक्ष-मुक्तता और दण्ड शक्ति का प्रयोग न करने की दो धारों तो रखी थी परन्तु सदस्यता शुल्क की कोई धारा नहीं रखी थी। फलस्वरूप बिहार के जिन शिक्षकों ने आचार्यकुल के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किये, उन्होंने भी कोई सदस्यता शुल्क नहीं दिया जिससे बिहार में आचार्यकुल का कोई संगठन आज भी नहीं बन सका है। बिहार में ही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी आचार्यकुल के विचार का जले ही प्रचार हुआ लेकिन धन के अभाव में कहीं भी कोई संगठन

नहीं बन सता है, भले ही किसी प्रकार चन्दा बाँटि एकत्र कर कोई आयोजन-समारोह कर लिया गया हो ।

अतः सगठन बनाने के लिए अक्तूबर १९६९ के राजगीर सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर विनोबाजी की प्रेरणा से सब सेवा सघ ने केन्द्रीय आचार्यकुल समिति का निर्माण किया । सगठन बनाने की दृष्टि से हम केन्द्रीय समिति का सबसे पहला काम था आचार्यकुल का सदस्यता के सक्ल्प-पत्र में परिवर्तन । इस परिवर्तन के अनुसार सदस्यता शुल्क की धारा को भी सक्ल्प-पत्र में शामिल किया गया और यह आशा की गयी कि आचार्यकुल का सदस्य जिस प्रकार पञ्च-सुवर्ण झोकर राजनीति के तमस से परे रह कर अहिंसा और हृदय परिवर्तन के सिद्धान्तों को अपनावेगा—वैसे ही वह नियमपूर्वक सदस्यता शुल्क भी देगा । परन्तु यह अपेक्षा पूरी नहीं हुई है और सक्ल्प-पत्र पर हस्ताक्षर करके भी सदस्यों ने नियमपूर्वक सदस्यता शुल्क नहीं दिया है । ग्राहिर है कि सगठन की दृष्टि से सबसे पहली आवश्यकता यही है कि आचार्यकुल का सम्पूर्ण नियमपूर्वक शुल्क देता रहे । यह आश्चर्य है कि अभी यत्न १९७२ में जब पवनार में विनोबा के सानिध्य में आचार्यकुल की मीटिंग हुई तब भी महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया था कि क्या आचार्यकुल भी सम्स्यता के लिए सदस्यता-शुल्क की शर्त अनिवार्य मानी जाय ? विनोबा ने फिर एक बार दोहराया कि सदस्यता शुल्क दिये बिना आचार्यकुल का नाम हवा में रहगा ।

आचार्यकुल का विधान

सगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से आचार्यकुल की केन्द्राय समिति ने दूमरा काम किया है आचार्यकुल का एक विधान बनाना । यद्यपि हम विधान का सम्पद यही है कि आचार्यकुल का एक राष्ट्रीय सगठन बने और राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक इकाइयों का सम्बन्ध दृढ़ हो । फिर भी आचार्यकुल का यह विधान काफी सचीला है और आचार्यकुल की संस्थागत इकाइयों को कार्यक्रम बनाने और निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है । विधान में यह भी प्राविधान है कि सदस्यता शुल्क का ७५ प्रतिशत स्थानीय इकाइयाँ अपनी संस्थाओं में ही खर्च करें । विधान बनाते समय चेष्टा यही रही है कि आचार्यकुल सगठन से अधिक एक विरादरी ही रहे । परन्तु प्राइमरी स्तर से ऊपर उठते हुए राष्ट्रीय स्तर तक हमारी यह विरादरी संगठित विरादरी रहे, यह चेष्टा की गयी है । विरादरी ऐच्छित होगी परन्तु असंगठित नहीं होगी । अगर हमें अन्याय और अनैतिक्ता का प्रतिकार करना है तो हमारी विरादरी में प्रतिकार का सामर्थ्य होना चाहिए,

हमारी राष्ट्रीय आवाज होनी चाहिए। अगर हमारी जोरदार आवाज नहीं हुई तो हमारी बात कौन सुनेगा ? हमें अपनी आवाज को प्रभावशाली बनाना होगा। सहनार शक्ति के विनाश के लिए प्रतिवार शक्ति के विकास के लिए इस विरादरी को इतनी ताज़ा तो पंदा करनी ही होगी कि ज़रूरत पड़ने पर वह बोल सके और कुछ कर सके। उतनी ताज़ा की रक्षा करते हुए इस विरादरी के सगठन को जितना भी ढीलाढाला रखा जा सकता है रखा गया है। सगठन शब्द में बठोरता की छवि है। इस बठोरता की पहचान यह ही है कि हमारे ऊपर किसी दूसरे का आदेश लागू आ रहा है। आचार्यकुल के विधान में इससे बचा गया है। इसमें किसी भी ऊपर की इकाई का आदेश नीचे की इकाई पर नहीं है।

इस विधान में भी सदस्यता शुल्क की धारा को सार्वजनिक की दूसरी धाराओं के साथ ही रखा गया है और प्रायना की गयी है कि प्रादेशिक आचार्यकुल सदस्यता शुल्क १० प्रतिशत केन्द्रीय आचार्यकुल को दें। परन्तु अब भी मध्यप्रदेश के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रदेश से इस प्रकार का धन प्राप्त नहीं हुआ है।

सर्व सेवा सघ और आचार्यकुल

केन्द्रीय आचार्यकुल समिति की स्थापना के बाद और सार्वजनिक में सदस्यता शुल्क की धारा रखने के बावजूद भी जब सदस्यों के नियमपूर्वक जवाब नहीं दिया और धन के अभाव में आचार्यकुल आन्दोलन का नाम रखने लगा तो सर्व सेवा सघ ने केन्द्रीय समिति की धन से सहायता की जिससे पूरा समय देने वाले एक सगठक की नियुक्ति सम्भव हुई और एक आफिस भी रखा जा सका। इसी पैसे से आचार्यकुल-सम्बन्धी पम्फलेट आदि का प्रकाशन होता है और प्रदेशों को एक मुक्त पाँच सौ रुपये की सहायता भी दी जाती है।

आचार्यकुल की स्वायत्तता

सर्व सेवा सघ की इस आर्थिक सहायता के बाद सगठन के सम्बन्ध में एक प्रश्न बहुधा केन्द्रीय और प्रादेशिक समितियों की बैठकों में पूछा जाता रहा है कि जब सर्व सेवा सघ को ओर से ही आचार्यकुल आन्दोलन चलाया जा रहा है तब आचार्यकुल को स्वायत्त सगठन कहना कहाँ तक उचित होगा ? इस सम्बन्ध में विनोबाजी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर आचार्यकुल चाहता है कि सर्व सेवा सघ उसकी आर्थिक सहायता करे परन्तु बिल्कुल दखल न दे तो वैसा सम्भव रहे। परन्तु आचार्यकुल की स्वायत्तता में किसी प्रकार का

हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और आज स्थिति यही है कि सर्व सेवा सघ से पूरी आर्थिक सहायता लेता हुआ भी आचार्यकुल पूर्णतः स्वायत्त है और सर्व सेवा सघ ने उसके काम में कभी किसी प्रकार दखल नहीं दिया है तथा आचार्यकुल जिस प्रकार का सम्बन्ध चाहे सर्व सेवा सघ या सर्वोदय आन्दोलन से रख सकता है। उसे यह भी छूट है कि अगर वह किसी वक्त यह महसूस करे कि सर्वोदय आन्दोलन से देश का अहित हो रहा है तो अपनी राष्ट्रीय इकाई से विचार करके उसे देश के नाम यह घोषणा करनी चाहिए कि देश में सर्वोदय नाम का जो यह आन्दोलन चल रहा है, उससे देश को नुकसान हो रहा है और उससे देश की जनता को हानिग्रस्त रखना चाहिए। इससे बड़कर स्वायत्तता का आश्वासन और बना हो सकता है? यह आश्वासन आचार्यकुल को मिला हुआ है। सर्वोदय-आन्दोलन ने माना है कि आचार्यकुल सत्य की वाणी है। जिसे वह सत्य समझेगा, कहेगा। आचार्यकुल किसी का 'मास्टर' वापस नहीं है। वह अपने कर्षों की बात खुलकर कहेगा—कहना चाहिए।

इम समय तक यह स्थिति है, परन्तु यह स्वायत्तता कायम रहे, इसके लिए यह अनिवार्य है कि आचार्यकुल का आन्दोलन अपने पैरों पर खड़ा हो और सर्व सेवा सघ से आर्थिक सहायता लेना बन्द करे। 'धन बव बन्धन हो जायगा, यह कहा नहीं जा सकता।

केन्द्रीय और प्रादेशिक आचार्यकुल का सम्बन्ध

संगठन के सम्बन्ध में तीसरी बात, जो बहुत महत्व की है वह है केन्द्रीय आचार्यकुल का प्रादेशिक आचार्यकुलों से सम्बन्ध। इस सम्बन्ध में संगठन की दृष्टि से सस्थागत और प्रादेशिक इकाइयों की स्वायत्तता का निश्चान्त ही सर्वमान्य होना चाहिए। जैसा पहले कहा चुका है आचार्यकुल को विरादरी संगठित विरादरी बने, असंगठित विरादरी न बन जाय, इतना ही प्रयास करना चाहिए। आचार्यकुल 'सत्ता के लिए नहीं सेवा' के लिए है, और जब तक आचार्यकुल ॥ सामने यह लक्ष्य स्पष्ट रहेगा तब तक किसी प्रकार केन्द्रीयकरण की नीति ॥ बचना आसान होगा। फिर भी अगर आचार्यकुल को एक राष्ट्रीय नीति बननी है, उसकी आवाज को राष्ट्रीय आवाज बननी है—ऐसी आवाज, जिसकी राष्ट्र में प्रतिष्ठा हो, तो उसकी सस्थागत, जनपदीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय इकाइया को आपस में बँधकर रहना चाहिए। संगठन की दृष्टि से सबसे महत्व का प्रश्न वही है कि जब न होता हुआ भी यह सम्बन्ध सिधिल न पड़े। साल भर में कम-से-कम एकबार ही प्रदेशों की सब इकाइयाँ प्रदेश में एक जगह इकट्ठी हो और स्थानीय अथवा प्रादेशिक समस्याओं पर निष्पक्ष

होकर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें और अपनी राय समाज के सामने प्रस्तुत करें। इसी प्रकार सब प्रदेशों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय स्तर पर मिलें। यह तभी सम्भव होगा जब प्रादेशिक आचार्यकुल केन्द्रीय आचार्यकुल को नियमपूर्वक विधान के अनुसार सदस्यता शुल्क का अशदान देता रहेगा। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त और कहीं से अब तक यह अशदान नहीं प्राप्त हुआ है। यद्यपि प्रादेशिक स्तरीय आचार्यकुल एक से अधिक प्रदेशों में स्थापित हुए हैं। किसी प्रकार के केन्द्रीयकरण की प्रोत्साहन दिये बिना प्रादेशिक और केन्द्रीय आचार्यकुल के सम्बन्ध में दृढ़ता कैसे हो, इस विषय पर चिन्तन होना चाहिए।

आचार्यकुल का अन्य शिक्षक संघों से सम्बन्ध

आचार्यकुल का दूसरे शिक्षक संघों से क्या सम्बन्ध हो, सगठन की दृष्टि से यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज सभी राज्यों में शिक्षक संघ हैं जो अपने सदस्य अंगणिका के अधिकारों के लिए सरकार से अपवा मैनेजरो से लड़ते हैं। चूँकि आचार्यकुल अधिकारों की प्रमुखता न देकर कर्तव्य की जागृति पर जोर देता है अतः कुछ लोग आचार्यकुल को एक विरोधी मंच स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखते हैं। उनसे कहना है कि आचार्यकुल प्रोफेशनल एकता को तोड़ने का नहीं उसकी नागरिक हैसियत को बढ़ाने का कार्यक्रम है। शिक्षक संघों की एकता अगर टूटी तो दसवत राजनीति के प्रवेश से टूटेगी। आचार्यकुल तो इससे रक्षा का कार्यक्रम है।

जहाँ तक अधिकारों का प्रश्न है आचार्यकुल अधिकारों की माँग के लिए नहीं, कर्तव्य की जागृति के लिए है। परन्तु अगर किसी समस्या के समाधान के लिए शिक्षक संघों की माँग न्यायपूर्ण है और उनका मार्ग शान्ति और अहिंसा का है तो आचार्यकुल उनका समर्थन करेगा। आचार्यकुल का लक्ष्य शान्तिपूर्ण ढंग से अत्याचार का प्रतिकार है, और जो भी शान्तिपूर्ण तरीकों से अत्याचार के विरुद्ध लड़ेंगे, आचार्यकुल उनके साथ रहेगा। लेकिन आचार्यकुल यह समझता है कि शिक्षक-संघ ने जो लड़ाई छेड़ी है वह उचित नहीं है, तो समर्थन नहीं करेगा।

अक्सर दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या एक शिक्षक अपने संघ के साथ आचार्यकुल का भी सदस्य हो सकता है? मेरे विचार में अगर कोई आचार्यकुल की निष्ठाओं में विश्वास रखता है तो वह आचार्यकुल का सदस्य हो सकता है और जब किसी विशेष परिस्थिति में दोनों संघों में संघर्ष हो तो वह निर्णय करे कि उसे किम्को छोड़ना चाहिए।

—बशीर धीयास्त

केरल में आचार्यकुल का प्रारंभिक कार्य :

एक प्रतिवेदन

केरल सर्वोदय मण्डल की कोचीन में ५-११-७२ को हुई बैठक में ही यह तय किया गया कि केरल में श्री आचार्यकुल का काम किया जाय। श्री ई० नारायण पिल्लई से जो केरल सर्वोदय मण्डल के एक सदस्य हैं और गांधी शान्ति प्रतिष्ठान केन्द्र त्रिवेन्द्रम के सेक्रेटरी भी यह अनुरोध किया गया कि वे इस कार्य की जिम्मेदारी लें। केरल के विभिन्न क्षेत्रों के आठ सन्स्यों की एक अस्थायी समिति इस कार्य के लिए बनायी गयी और श्री पिल्लई को उसका संयोजक नियुक्त किया गया।

इस अस्थायी समिति की कोचीन में २० दिसम्बर १९७२ को एक बैठक बुलाई गयी, लेकिन संयोजक को मिलाकर कुल चार व्यक्ति ही बैठक में शामिल हुए। अतः बैठक आगे के लिए टाल दी गयी। बाद में सब सेवा सच की केलपननगर में हुई छ माही बैठक के अवसर पर ३१ दिसम्बर १९७२ को आचार्य राममूर्ति व श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा की उपस्थिति में संयोजक ने दो अनौपचारिक बैठकें बुलाई। सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये आए हुए शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन दोनों बैठकों में भाग लिया। इस बैठक में यह निश्चय किया गया कि १४ जनवरी १९७३ को राज्य-स्तर की एक बैठक त्रिचूर में बुलाई जाय।

आचार्यकुल के काम में रुचि रखनेवाले शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक पूर्व निश्चय के अनुसार त्रिचूर के निकट १४ जनवरी १९७३ को बुलाई गयी। इस बैठक में केरल के ११ जिलों में से ८ जिलों के २५ शिक्षकों

ने भाग लिया। इनके अतिरिक्त १० सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया, जिनमें श्री मनमथन व अस्थायी समिति के संयोजक भी सम्मिलित थे। बैठक में निचले प्राइमरी स्कूलों, हाई स्कूलों व कालेजों के शिक्षक शामिल थे, जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बैठक में गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि व केरल सर्वोदय सघ का प्रतिनिधित्व किया। बैठक ११ बजे सुबह शुरू हुई और तीसरे पहर साढ़े तीन बजे तक चली। श्री एम०पी० मनमथन ने बैठक की अध्यक्षता की। विचार-विमर्श काफी अच्छा रहा। सर्वानुमति इस पक्ष में थी कि केरल में आचार्यकुल कार्यक्रम का संगठन किया जाय। बैठक में निम्नलिखित निर्णय हुए :

(१) केन्द्रीय आचार्यकुल समिति ने जिस नमूने का सुझाव दिया है वैसे आचार्यकुल का केरल में संगठन हो। आचार्यकुल का संविधान सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया।

(२) बैठक में सभी जिलों के जो सदस्य आये थे उन्हीं में से कुछ लोगों को लेकर अस्थायी समिति का पुनर्निर्माण हुआ। पुनर्निर्मित इस अस्थायी समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :

- | | |
|--|--------------------|
| १. श्री के० के० नारायणन् नायर | |
| २. श्री पी० एम० कुमारन् नायर | त्रिवेन्द्रम् जिला |
| ३. एन० एस० पनिकर | विजयन ,, |
| ४. श्री सी० जी० नारायण पनिकर | |
| ५. श्री ए० नटराजन् | |
| ६. श्री प्रो० प्रिकोडियनम् गोपीनाथन नायर | |
| ७. श्री एन० शिवरमण नायर | कोट्टायम |
| ८. श्री नीलेश्वरम् रमनकुंजी | |
| ९. एन० पी० अब्दुलसेदर | |
| १०. प्रो० एम० वी० आगस्टिन | अर्नाकुलम् |
| ११. श्रीमती एम० के० इल्लिअम्मा | |
| १२. श्री ईवी० छट्टुदुट्टी | चिचूर |
| १३. श्री एम० नारायणन् | |
| १४. श्री प्रो० एन० चन्द्रोत्तरन् नायर | |
| १५. श्री के० भीमन नायर | पालघाट |
| १६. श्री प्रो० पी० के० वी० नायर | इडिक्कि |

१७ श्री एम० पी० मनमथन्

अध्यक्ष, केरल सर्वोदय मण्डल

१८ श्री ई० नारायण पिल्लई

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान सेक्टर, त्रिवेन्द्रम्

रोप वत्ते तीन जिलो में से शीघ्र ही प्रत्येक में से दो-दो सदस्य शामिल किये जायेंगे । इसी तरह क्विलन और इडिक्की जिलो से भी एक एक शिक्षक शामिल किया जायगा ।

(३) ग्रामस्वराज्य विद्यालय नटथारा के प्रिंसिपल श्री के० भीमन नायर तदर्थ समिति के समान्य सयोजक मनोनीत किये गये । गवर्नमेण्ट हाई स्कूल की श्रीमती रमन कुजी और त्रिवेन्द्रम् गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के श्री ई० नारायण पिल्लई सयुक्त सयोजक चुने गये । श्रीमती रमन कुजी उत्तरी जिलो का संगठन कार्य देखेंगी और श्री नारायण पिल्लई दक्षिणी जिलो का । साथ ही ये दोनों इस तदर्थ समिति के कार्यालय का भी काम देखेंगे ।

(४) आनेवाले महीनो में शिक्षको की जिला स्तरीय बैठक बुनायी जायगी और जैसा कि सविधान में निर्दिष्ट है निचले स्तर की इकाइयो व राज्य स्तरीय समिति का भी निर्माण होगा । राज्य स्तरीय मण्डल अप्रैल तक पूरा हो सकता है और कई महीने में राज्य स्तर की एक बैठक बुलायी जा सकती है ।

(५) सदस्यता फार्म मलयालम् भाषा में तुरत छपा लिये जाय तथा फरवरी व मार्च महीनो में सदस्य बनाने का अभियान रखा जाय ।

(६) पत्रिकाएँ तथा अन्य आवश्यक साहित्य मलयालम में तैयार हो जिनका अंग्रेजी और हिन्दी में भी अनुवाद हो ।

(७) तदर्थ समिति की फरवरी में बैठक बुनायी जाय और भविष्य का कार्य क्रम विस्तार से तय किया जाय । बैठक में शामिल सदस्यों में श्री भीमन नायर, उनके सहयोगियो और विद्यालय के विद्यार्थियो के प्रति भोजन व आतिथ्य के लिए धन्यवाद प्रकाश किया गया ।

यह बैठक ३ ३० बजे समाप्त हुई । १४ तारीख को ही ४ बजे राज्य स्तरीय बैठक के बाद तदर्थ समिति की बैठक हुई । तब हुआ कि दूसरी बैठक १२ फरवरी १९७३ को यित्तवाया में हो ।

त्रिवेन्द्रम्, २५-१-१९७३

ई० नारायण पिल्लई

सयुक्त सयोजक

केरल आचार्यकुल अस्थायी समिति

सम्पादक मण्डल :

श्री धीरेन्द्र मजूमदार : प्रधान सम्पादक

श्री यशीधर श्रीवास्तव

आचार्य राममूर्ति

वर्ष : २१

अंक ८

मूल्य : ७० पैसे

अनुक्रम

शिक्षा की स्वायत्तता —

एक अविभाज्य इकाई है

सत्य ही शिक्षक की सत्ता

सरकारी नीतियों से डिग्री का

सम्बन्ध-विच्छेद हो

अध्ययन की प्रीतिताह्न देने के लिए

नये तरीके

सपुस्तक परीक्षा

शिक्षा-पद्धति कैसी है ?

कैसी होनी चाहिए ?

आचार्यशुल का संगठन

केरल में आचार्यकुल का प्रारम्भिक कार्य

एक प्रतिवेदन

३३७ सम्पादकीय

३४२ राममूर्ति

३४८ बी० आर० मेहता

३५७ बाबूजी फिरोजी

३६५

३७२ अज्ञानवली गुप्त

३७५ अशीधर श्रीवास्तव

२८१ ई० नारायण पिल्लई

मार्च, '७३

● 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता ।

● 'नयी तालीम' का वार्षिक चढ़ा आठ रुपये हैं और एक अंक के ७० पैसे ।

● पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सख्या का उल्लेख अवश्य करें ।

● रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त मट्ट, द्वारा सर्व सेवा सघ के लिए प्रकाशित,

मनोहर प्रेस, जतनबर, धाराणसी में मुद्रित

नयी तालीम

नवी सेवा-संघ की मासिकी

वर्ष ॥ २१

अंक : ६

- सोवियत रूस के विद्यार्थी
- शिक्षा का सरकारीकरण
- शिक्षा-समस्या
- शिक्षा-सुधार की एक योजना
- दुनियादी शिक्षा—आनेवाले कल की शिक्षा-पद्धति

अप्रैल १९७३

सोवियत रूस के विद्यार्थी

देश की शिक्षा प्रणाली में जो भी आमूल परिवर्तन किये जायें उसमें सबसे पहला परिवर्तन यह करना है कि इस देश के विद्यार्थियों में ऐसी क्षमता उत्पन्न की जाय जिससे कि वे समाज की एक उत्पादक इकाई बन सकें। जो शिक्षा उन्हें केवल परोपजीवी बनाती है, ऐसी शिक्षा एक स्वतंत्र समाजवादी देश को नहीं चाहिए। प्रकृति अथवा समाज में जो उपादान उपलब्ध है, समाजवाद में उनके समान उपभोग की और उस उपभोग द्वारा सबसे समान विकास के लिए समान अवसर की कल्पना है। और यह कल्पना तब तक चरितार्थ नहीं होती जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज की उत्पादक इकाई नहीं बन जाता।

वर्ष : २१

अंक : ९

और फिर आज की दुनिया में जिसमें विज्ञान और टेक्नालॉजी प्रतिक्षण नये नये परिवर्तन कर रहे हैं—उत्पादक इकाई का अर्थ है विज्ञान और टेक्नालॉजी की वर्तमान उत्पादन प्रकृति की समझदारी मात्र ही नहीं, भविष्य में वह प्रकृति क्या रूप ले लेगी उसकी भी समझदारी। इसका अर्थ हुआ कि आज के तकनीकी युग में उत्पादक इकाई वही हो सकेगा जिसमें आज की टेक्नालॉजी को समझने की ही क्षमता नहीं है। कल के तकनीकी परिवर्तन के अपेक्षित संभावनाओं को समझने और उसके परिवर्तन के अनुसार अपने को ढाल सकने की योग्यता भी है। दूसरे शब्दों में, कल तक के उत्पादन के लिए केवल इंजीनियर की आवश्यकता थी। आज इंजीनियर के साथ-साथ अनुसंधानकर्ता भी हो। इसने साथ-साथ यह भी सीखना है कि जो टेक्नीकल ज्ञान उसे प्राप्त

हुआ है उसका संगठन वह इस प्रकार करे कि आज समाज में उत्पादन की जो पद्धतियाँ चल रही हैं, उनमें वांछित सुधार करके वह उन्हें अधिक उत्पादक बना सके। इसके लिए इतना ही आवश्यक नहीं है कि वह कक्षा के भीतर विज्ञान और टेक्नालॉजी का अद्यतन ज्ञान प्राप्त करे, बल्कि यह भी आवश्यक है कि कक्षा के बाहर जो व्यक्ति उत्पादन की क्रिया-प्रक्रिया में लगे हैं वह उनके साथ काम करता हुआ पद्धतियों के रहस्यों का प्रायोगिक ढंग से समझे। ऐसा करेगा तभी उसका अनुसंधान अधिक व्यावहारिक होगा और तभी उसे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। और तभी वह भविष्य का मुकाबला करने के लिए सश्रम भी हो सकेगा। इस दिशा में सोवियत रूस की शिक्षा-प्रणाली अनुकरणीय है, और हमें अगर अपनी शिक्षा को उत्पादक बनाना है तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा।

सोवियत रूस के उच्च शिक्षा के कालेजों के 6 लाख विद्यार्थी जो देश की कुल सख्या के लगभग चौथाई हैं, उन "छात्र-वैज्ञानिक-सोसाइटियों" के सदस्य हैं जो अनुसंधान का काम करती हैं। दूसरे शब्दों में ये विद्यार्थी कक्षा में टेक्नालॉजी का ज्ञान ही नहीं प्राप्त करते बल्कि उत्पादन-पद्धति में गम्भीरतापूर्वक अनुसंधान भी करते हैं। दो सौ से अधिक ऐसे छात्र डिजाइनिंग-ब्यूरो (शालाएँ) हैं जो उद्योग, कृषि, भवन-निर्माण आदि औद्योगिक संस्थाओं से ठीके के आधार पर विभिन्न प्रकार की योजना चलाते हैं।

छात्रों के ये सभी संगठन स्वतंत्र संस्थाएँ हैं और इनका प्रबंध छात्र ही करते हैं। यह दूसरी बात है कि अध्यापक थोड़ी वैज्ञानिक अथवा दूसरी टेक्नीकल सहायता कर देते हों। परन्तु प्रबंध पूर्णतः छात्रों के हाथ में ही रहता है और इस प्रकार रूस में छात्र-स्वतंत्रता की प्रवृत्ति रचनात्मक और पाजिटिव हो जाती है। इस स्वतंत्र छात्र-अनुसंधान-संगठनों के प्रयासों का परिणाम बहुत उत्साहप्रद है। १९६९-७० में इन संगठनों के ३ सौ अनुसंधान-कार्य पेटेन्ट कराये गये और लगभग ४ हजार अनुसंधान-कार्यों को उत्पादन के लिए सख्त किया गया और सात हजार शोध-लेख प्रकाशित हुए। १९७० में लेनिन शती के अवसर पर आयोजित समाज-विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान-स्पर्धाओं में लगभग ८ लाख छात्रों ने भाग लिया।

इस प्रकार देश के छात्रों में उत्पादक काम के प्रति स्वतंत्र रचनात्मक अनुसंधानिक दृष्टिकोण के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। किसी भी प्रगतिशील समाजवादी देश के विद्यार्थियों में इस भावना का विकास आवश्यक है। सोवियत रूस का विद्यार्थी अपने देश का नागरिक है और सोवियत संविधान में दिये गये सारे अधिकारों को भोगता है एवं सारे कर्तव्यों का पालन भी करता है। इस समय १३ विद्यार्थी सुप्रीम सोवियत के, जो सोवियत रिपब्लिक की पार्लियामेण्ट है, डिप्टी हैं। १९७१ में एक हजार से अधिक विद्यार्थी सुप्रीम सोवियत और इसके स्थानीय भागों के सदस्य हुए थे।

१९६९-७० में २ लाख से अधिक छात्रों ने रूस के सैम्बों गाँवों और कस्बों की यात्राएँ की जहाँ उन्होंने ४ लाख व्याख्यान दिये और १ लाख से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये। १९७१ के प्रोफ़ेसरावकाश में ४ लाख छात्रों ने पावर स्टेशन बनाने, मरफान बनाने, रेलवे-लाइन तथा रिहायश के लिए भवन एवं कृषि-भवन के निर्माण के काम किये।

इतना ही नहीं सोवियत रूस के उच्चतर विद्यालयों के प्रशासन के लिये जो कानून बनाये गये हैं वे विद्यार्थियों को अनेक महत्त्वपूर्ण कालेन संगठना में व्यापक स्तर पर भाग लेने का अधिकार प्रदान करते हैं—जैसे कालेन की उस कौंसिल में जो छात्रों के प्रवेश और रोजगार का प्रयत्न करती है। (सोवियत रूस में प्रत्येक स्नातक को रोजगार की गारण्टी रहती है) अथवा उस कौंसिल में जो छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम करती है, भाग लेना।

सोवियत रूस में कालेन के विद्यार्थी, अध्यापक और दूसरे कर्मी, एक ही ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं। उदाहरणार्थ मास्को विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी, अध्यापक और कर्मी "वर्कर्स ऑव एजुकेशन हायर स्कूल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रेड यूनियन" के सदस्य हैं। इसका अर्थ यह होता है कि अपने वरिष्ठ साथियों (अध्यापकों) के साथ समानता के स्तर पर विद्यार्थी अपने हितों की सुरक्षा स्वयं करते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन जो श्रम सम्बन्धी कानून अथवा विद्यार्थियों

के प्रतिदिन के जीवन से सम्बन्धित जो नियम बनाते हैं उन पर नियंत्रण रखने में विद्यार्थियों का हाथ रहता है ।

इस प्रकार सोवियत रूस के कालेजों में विद्यार्थियों को जन-जीवन के उत्पादक कामों में भाग लेने का और दूसरे प्रशासनिक कामों में हिस्सा लेने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है । भारत की शिक्षा में अगर इस प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन करने हैं जिससे शिक्षा जन-जीवन के साथ जुड़े तो विद्यार्थियों को अधिक अवसर इस बात का देना चाहिए कि समाज की उत्पादक क्रियाओं का वैज्ञानिक ढंग से संचालन करना ही न सीखें, वे कक्षा के बाहर निकलकर उनके साथ काम करें जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के काम में लगे हैं । इससे दोहरा लाभ होगा । समाज में काम करनेवाले उत्पादक श्रमिकों की वैज्ञानिक दृष्टि मिलेगी और विद्यार्थियों के कामों को जीवन का ठोस आधार प्राप्त होगा ।

—बशीर धीवान

शिक्षा का सरकारीकरण

[आचार्यकुल सम्मेलन मुर्शीदाबाद, बिहार) में दादा धर्माधिकारी द्वारा दिये गये भाषण का सार :—सम्पादक]

सरकारीकरण से बचने का एक ही उपाय

जमी जो कुछ मैंने बिहार प्रदेश आचार्यकुल के संयोजक डाक्टर रामजी सिंह से सुना उसके मुझे ऐसा भाम हुआ कि हमारे प्रान्तों की तरह यहां भी शिक्षकों ने वह मांग की है कि हमारे वेतन देने की जिम्मेवारी सरकार पर हो। इसका मतलब यह है कि परिस्थिति से विवश होकर ध्यान शिक्षण भी राजस्वनिष्ठ अधिक हो रहा है और उसकी लोकनिष्ठा कम हो रही है। दूसरा लोकतन्त्र की एक मांग यह है कि सत्ता का विदेशीकरण हो। दूसरी तरफ वस्तुस्थिति यह है कि हमारा एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। अब इस परिस्थिति का थोड़ा विश्लेषण आप कीजिए। साग-सन्नी बचनेवाले कुछ से लेकर देश के प्रतिष्ठित-से-प्रतिष्ठित विद्वान और धनी यही कहन पाये जाते हैं कि यह सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है। यह भ्रष्ट है तो फिर उजले कौन हैं? वह कौन हैं जो निरन्त्रे नहीं हैं? जब तो जो समीकरण हा रहा है वह यह हो रहा है न कि सरकार निरन्त्रे है और हमारे लोग अधिक निरन्त्रे हैं। तो अब बतलाइये कि इस देश के लिए कौन-सी काना है? सरकार निरन्त्रे है इसकी बदनाम चाहिए। लेकिन जो बदलेंगे वे लोग अधिक निरन्त्रे हैं। तो फिर क्या हो? समस्या का हल क्या है?

मेरे पास समस्या का कोई जवाब नहीं है और जिनके पास जवाब है उनमें मेरा कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि वे जवाब देते हैं साधुन की तरह।

केरल में एक शिबिर हुआ, उसमें शिक्षक थे। उन शिक्षकों में पूछा, "आप कम्युनिस्ट सत्ता के हिमायती, पक्षपाती क्यों हैं, समर्थक क्यों हैं?" उन्होंने यही कारण बताया कि हमको हमारी तनखाह नहीं मिलती है, वेतन नहीं मिलता है। इसलिए इसे हम सरकार को सौंप देना चाहते हैं। और यह भूमिका सिर्फ कम्युनिस्ट सरकार की है, कम्युनिस्ट पार्टी की है इसलिए हम कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हैं। आज भी वह आन्दोलन चल ही रहा था। दुबारा जब मैं १९७२ की मई या जून महीने में गया तो यह आन्दोलन चल रहा था

कि यहाँ के सारे के सारे शिक्षण का सरकारीकरण हो। वहाँ केवल की सरकार का भी यही विचार है। अब आप शर्त क्या लगा रहे हैं कि राजकीकरण तो हो लेकिन राज्य का शासन शिक्षण पर न हो। तो इसका मतलब यह हुआ न कि आप में इतनी शक्ति चाहिए कि आप सरकार से पैसा भी ले लें और ऊपर से अपनी अरुढ़ दिखायें। यह तो है नहीं। आज तो परिस्थिति यह है न कि आप विवश होकर सरकार के दरवाजे पर भीख माँगने जा रहे हैं। यह तुम ले सो तो हम बचेंगे। तो एक न्याय है पुराना “ही वॉल्ट कि ट्यून दू पेज दि पाइवर।” यानी जो गहनाईवाने को पैसा देता है वह राग फर्माता है कि कौन-सा राग बजाया जाय। इससे हमका अगर बचना है तो एक ही उपाय है और वह उपाय यह है कि हममें से मुट्ठी भर शिक्षकों को (मैं नहीं कहता कि अधिवाश) यह निश्चय करना होगा कि अब समाज की केन्द्रीय सस्था बाजार नहीं होगी। आज मनुष्य की स्वतंत्रता है मालिक चुनने की और अपने आपको बेचने की भी। ये दो दाप हैं। लोक-सत्ता उत्तम-से-उत्तम अधिनायक राज्य से बेहतर है। और यह क्यों है ? रही-से-रही लोकसत्ता में भी अगर मैं पालियामेण्ट में चुना जाऊँ तो पालियामेण्ट के सदन में खड़ा होकर प्रधानमंत्री की आँखों से आँख मिलाकर यह कह सकता हूँ कि शासन मूर्खों का है। लेकिन जहाँ उत्तम-से-उत्तम अधिनायक सत्ता होगी वहाँ घर में अपनी पत्नी के कान में भी कहूँ कि यह सत्ता मूर्खों की है तो मेरी जीभ काट ली जायगी। यह शिक्षक का सत्त्व है लोकतंत्र में, शिक्षक को यह कहने का अधिकार है। आप इस अधिवार को क्यों छोड़ते हैं ? क्या शिक्षा के सरकारीकरण के बाद आपका यह अधिकार रह जायगा ? तो इस अधिकार के लिए कुछ लोग लड़ें। भले इस लड़ाई में उन्हें बिप का प्याला पीना पड़े।

जब सुगरात के होठों से बिप का प्याला दबाया जाता है, होठों से उसका स्पर्श होता है, तो उसमें विजय की तारीर आ जाती है। उसमें मानव विजय घोल दी जाती है। कुछ शिक्षकों को यह जहर का प्याला पीना होगा। इसमें कोई आचार सहिता आपकी सहायता नहीं करनेवाली है। इस प्रकार के जो मनुष्य होते हैं वे आउट साइडर कहलाते हैं। आउट साइडर से मतलब जिन पर परिस्थिति और परम्परा का कोई असर नहीं होता। वर्तमान परिस्थिति और परम्परा इन दोनों से जो ऊपर उठ सकते हैं, वे आउट साइडर हैं, क्रान्तिकारी हैं। वे प्रतिलिपि नहीं होते। यह ही सच्चा है और यह हुआ है।

आपने वहाँ धीरे-धीरे हैं। मैं उनको पूज्यनीय मानता हूँ। ये इसी प्रकार के आउट साइडर हैं।

मनुष्य स्वनिर्मित होना चाहिए

मैं आपसे सुनाना यह चाहता हूँ कि कृपा कीजिए और जा आपकी आदर्श शिक्षण-संस्थाएँ बननेवाली हैं, उन आदर्श संस्थाओं में अपने विद्यार्थियों पर अपने व्यक्तिगत की छाया न डालें न पहनें दोजिए। आपके जैसे विद्यार्थी हमें तो आपसे नादान होंगे। ईश्वर के बनाये हुए हम ऐसे हैं कि किसी की नाक एभी और किसी की आँखें ऐसी हैं, तो हमारे बनाये हुए क्या हमें भगवान जानें। मनुष्य का निर्माण मनुष्य का काम नहीं। मनुष्य स्वनिर्मित होना चाहिए। सेनेण्ड हैण्ड नहीं। किसी का बनाया हुआ नहीं। मनुष्य का बनाया हुआ मनुष्य नहीं। ऐसा होगा तब दूसरी पीढ़ी में शायद यह बोध जागृत हो कि बाजार केन्द्रीय संस्था नहीं रहनी चाहिए। अब तक बाजार केन्द्रीय संस्था रहनी आप खूब याद रखिए, गाँठ बाँध लीजिए कि विद्या भी विक्रेणी, विद्यार्थी भी विक्रेणी और शिक्षक तो विक्री ही रहा है। अब ये सभी बाजार में बैठे हैं। गांधीजी ने किसी दूसरे सदर्भ में कहा था कि सोरमता बाजार में बैठी है। इसलिए गणिका है—वेश्या है। तो यह मुनवर एव स्त्री ने लिखा कि गांधी तुम चौ सत कहलाने हो, तुम्हारी भाषा मृदु होनी चाहिए। तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, धनन कर रहा हूँ। और वणन निरपेक्ष होता है। वह कठोर या मृदु नहीं होना, यथावत होता है। विद्या भी अपनी मर्यादा को छोड़कर अब बाजार में आकर बैठती है तो वह गणिका होती है। बन कचनी हो जाती है। तो क्या हम विद्या को बाजार से उठा सकते हैं? अब तक बाजार में रहनी तब तक सौदा रहेगा। तब तक आप सौ रुपये पर हस्ताक्षर करेंगे और साठ रुपये मिलेंगे। यह बिहार में ही नहीं, सार प्रांतों में है।

शिक्षा के मूल्यों में परिवर्तन कीजिए

प्रतिकूल परिस्थिति में से अनुकूल काम की सोच क्रांति का बीज मग है। निःशस्त्र देश था, निहत्थों का। निहत्थों का देश, शस्त्र निरपेक्ष बीरता का विकास करे तो स्वतंत्र होगा। यह पक्क की बात गांधी के (आउट साइडर) मन में आयी। इतिहासवेत्ता तो कहना कि शस्त्र के बिना स्वतंत्रता नहीं। परम्परा को देखता तो मानता कि राम, कृष्ण सभी शस्त्र हथ में लिये, शिवाजी, राणा प्रताप सभी। लेकिन इतिहास और परम्परा दोनों से ऊपर उठ गया गांधी

क्योकि, वस्तु को देख रहा था बाँस खोलकर । वस्तुस्थिति यह थी कि देश निहत्थों का और नि शस्त्र होने के कारण यहाँ मनुष्य अहिंसक नहीं बना, हतवीर्य बना, हतबल बना । तो जो नि शस्त्र था, हतवीर्य था, हतबल था उसकी इस नि शस्त्र अवस्था में से क्या कोई शक्ति जागृत हो सकती है ? शिक्षण भी आज ऐसी ही अग्रहाय स्थिति में है । शिक्षण का पेट खाती है । भूख कोई सस्कृति नहीं जानती, कोई धर्म नहीं जानती, कोई अध्यात्म नहीं जानती । सारा धर्म, सारी सस्कृति, सारा अध्यात्म सारी सम्भवा जठराग्नि में भस्मसात हो जाती है । वह सहानु-भूति का पात्र है । लेकिन सहानुभूति का पात्र है तो क्या हम उससे यह कहेंगे कि दूसरा खिनायेगा तब तेरा पट भरेगा ? तब तो हम उससे परोपजीवी बनायेंगे । आज जितना विवश हैं उससे अधिक विवश उससे बनायेंगे । इसका तो मतलब इतना ही हुआ न कि एक जजमान खाने को नहीं दे रहा है तो दूसरे जजमान को खोजें । और दूसरे जजमान को खोजें तो उसकी प्रशंसा भी हमसे करनी पड़ेगी । प्रार्थना मेरी इतनी ही है कि आप मुद्दोभर सोच ही क्यों न निकालें, लेकिन प्रण यह होना चाहिए कि अब नये जजमान नहीं खोजना है । प्रण यह करना है कि शिक्षा बाजार का अन्त होगा । मनुष्य नहीं बिकेगा । उसकी विद्या नहीं बिकेगी । और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए । शिक्षण को भी उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए । इसके लिए सघर्ष करना पड़ तो सघर्ष कोजिए । लेकिन मेहरबानी कीजिए कि परिस्थिति का परिवर्तन, सन्दर्भ का परिवर्तन जब हम करते हैं तब यह न भूलें कि मूल्यों का परिवर्तन भी करना है । आज समाज में मूल्य नहीं है । समाज में आज जिसे कीमत कहते हैं 'प्राइज' 'दाम' वह है, मूल्य नहीं है । मूल्य से मतलब है महत्व, जीवन में उपयोगिता । और बाग बाजार में जो तप होता है, निश्चित होता है उसका नाम है दाम । तो आज हर चीज की प्राइज है, हर चीज के दाम हैं, हर चीज की कीमत है, लेकिन कितनी चीज का मूल्य नहीं है और गही कारण है कि इस शिक्षा को हम कोस रहे हैं ।

जॉव ओरियेण्टेड शिक्षा

एक मैने विरोध आपके सामने रख दिया, विरोधाभास नहीं प्रत्यक्ष विरोध । दूसरा विरोध आपके सामने रख रहा हूँ । राष्ट्रपति से लेकर प्राइमरी शिक्षक तक सब कह रहे हैं कि यह शिक्षण-पद्धति ही गलत है । यह निरुम्मी है, अनर्थकारक है । तब मैं पूछता हूँ कि अपने लड़कों को इसमें इतने प्रयत्न से क्यों भेजते हैं ? सोच कहते हैं, सरकार भी कहती है कि शिक्षा-पद्धति निरुम्मी

है तो फिर इसको बदलने में सरकार को किसने रोका है ? मैं कहता हूँ अभी भावकों को किसने रोका है ? ये तो बहुत अधिक सत्या में हैं और इन शिक्षकों को किसने रोका है ? ये तो अभी बनने भी वेदों को वहीं भेजते हैं और सिफारिश करते हैं उसके लिए । और ये विद्यार्थी रोज़ मुनिवसिटी का मकान जलाते हैं और रोज़ माँग करते हैं कि हमारे यहाँ एक नयी मुनिवसिटी खोल दी जाय, नहा सोलेंगे तो रेल की पटरियाँ उखाड़ेंगे । किसलिए मुनिवसिटी खोलिए ? उसे जलाने के लिए । मरी समझ में यह बात नहा आती है । अब जब लोग यह कहने हैं कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए तो मैं कहता हूँ कि माम ही नहीं है तो क्या दर्शन करें । मैं कहता हूँ कि क्या सबमुझ इस शिक्षण-पद्धति को हम दुरा समझते हैं । मैं इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि इस देश में इस शिक्षण-पद्धति को बिल से कोई भी दुरा नहीं समझता । हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आज जो समाज है, वर्तमान समाज उसमें सिर्फ हमको प्रतिष्ठा मिले । वर्तमान समाज के मूँचा का परिवर्तन हम नहीं चाहते । इतना ही हम चाहते हैं कि समाज में सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले और सम्पत्ति मिले यह एक दूसरी चीज है । हमारे देश में अंग्रेजों के आने से पहले ५ प्रतिशत आदमियों को अधिक-से-अधिक शिक्षण मिलता हो, इससे अधिक नहीं । कुछ ज्यादा ही कह रहा हूँ ।

केरल में सारे ब्राह्मण साक्षर हैं उत्तर-पूर्व में तो सारे साक्षर भी नहीं हैं । और ये जो कुछ कायस्थ हुये, मुसी, ये मुसलमानों के आने के बाद हुये । लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में शिक्षण सावत्रिक तो था ही नहीं । १० प्रतिशत भी शिक्षित नहीं थे । तब जो समाज शिक्षित नहीं था उसमें जो आकाशा है वह बाबूगिरी के शिक्षण की है । वे यह चाहते हैं कि हमारे बेटे शिक्षण पायें हाईकोर्ट के जज बनें वकील बों, डाक्टर बनें, बाबू बनें, प्रोफेसर बनें । आज तक जिस समाज में उनका स्थान नहीं था उस समाज में स्थान पाना चाहते हैं । इसलिए इस शिक्षण की तरफ से उनका जितनी घृणा होनी चाहिए उतनी घृणा नहीं है, विरस्कार नहीं है । शिवायव इतनी ही है कि शिक्षण के बाद हमको बेकार रहना पड़ता है हमको काम नहीं मिलता है । अब इस माँग को भी थोड़ा समझने की कोशिश करें । यह हर मनुष्य की माँग है, “हमको पढ़ने के बाद काम दो ।” क्या आप यह चाहते हैं कि यह देश सारा का सारा सरकारी नौकरों का बन जाय ?

जिस तरह चीन के युद्ध या पाकिस्तान के युद्ध में सिपाही जान हथेली पर लेकर गया होगा वैसे ही शिक्षक को जान हथेली पर लेकर आने आपको इसमें

होम देना होगा। फिर तो चाहे भुट्टी भर ही क्यों न हों उनका यह बाना होगा। समाज में आज जो मूल्य हैं वह नहीं रहेंगे। हम हृदय-परिवर्तन करेंगे और हृदय-परिवर्तन से मतलब आज बालक का हृदय, बालक का जो मन है उसे अपना हृदय, अपना मन देंगे ऐसा हविज नहीं। यह दुनिया मनुष्य के नाम की बनेगी और उसमें बालक का हृदय और बुद्धि मनुष्य की होगी, हमारा नहीं। हमारा तो विकृत है, संस्कारों से अशुद्ध है। संस्कार कचुपित हमारा चित्त है। उसका चित्त और उसका हृदय शुद्ध होगा। यह हृदय-परिवर्तन है। मैं आश्वासन दिला सकता हूँ कि जिस पर कोई संस्कार नहीं होगा, ऐसा संस्कार-निरपेक्ष मनुष्य का हृदय शुद्ध होगा। अस्तु, तीनों प्रेरणाएँ हमारी साथ-साथ चलनी चाहिए। मार्क्स की प्रक्रिया, सन्दर्भ-परिवर्तन की, चेंज ऑव कान्टेस्ट, समाज-वादियों की प्रक्रिया, चेंज ऑव वैल्यूज—मूल्य-परिवर्तन, और गांधी की प्रक्रिया हृदय-परिवर्तन की। ये तीनों एक के बाद एक अगर नहीं होंगे तो कोई क्रान्ति सफल नहीं होगी और समग्र नहीं होगी। तीनों एक साथ होगी तो क्रान्ति समग्र होगी और सफल होगी। तो इसका जो मूल्य-परिवर्तन का, हृदय-परिवर्तन का अंश है यह सांस्कृतिक क्रान्ति का अंश है और इसमें आपकी भूमिका है। इसमें शिक्षक की भूमिका अन्यतम है। वह अद्वितीय है इस विषय में।

आचार्यकुल का संकल्प

आपका यह बिशेष गौरव है कि आप विद्या को बाजार से उबारें और निवेदन मेरा यह है कि विद्या को दरबार से उबारें। बाजार और दरबार दोनों जगह विद्या नहीं जानी चाहिए। अगर दरबार में विद्या बैठी रहेगी तो खूब याद रखिए, वह राज्य की रखैली रहेगी और बाजार में बैठी रहेगी तो गणिका रहेगी। हमारे सारे के सारे विश्वविद्यालय, हमारे मस्जिद, हमारे गुरु-द्वारे, हमारे गिरजाघर ये सारे बाजार में बैठे हैं। मनुष्य विकता है, देवता विकता। अब जहाँ मनुष्य भी विकता है, देवता भी विकता है, वहाँ पर मनुष्य की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। संकल्प हमारा यह रहे कि मनुष्य नहीं विकेगा। किसी परिस्थिति में नहीं विकेगा। क्रांति में कंटेण्डर नहीं होते। क्रांति काल-निरपेक्ष होती है। इसलिए जब हम पूछते हैं लोगों से कि इसमें कितना समय लगेगा तो यह कोई रेलगाड़ी है, यह कोई मोटर गाड़ी है, कोई हिसाब है दमका। एक दण भी नहीं लगना चाहिए। हमारी तो इच्छा यह होगी। वह दण जब आयेगा जब आप साथेंगे।

शिक्षा-समस्या

मेरे विचार वर्षों के सोच विचार और प्रयोग के बाद निश्चित हुए । फिर भी मैं यह अपेक्षा नहीं करता कि वे सब विचार सरकार को मान्य होंगे या विचारदों को मान्य होंगे अथवा जनता ही उन्हें पसंद करेगी । अगर विचार लोगों को जैसे और लोग उस पर अमल करें तो अच्छी बात है । अगर नहीं जैसे और वे उस पर अमल न करें तो भी कोई खास दुःख की बात नहीं है । 'शापक शास्त्र न तु कारकम्' शास्त्रीय वृत्ति रखनेवाला शापक होता है कारक नहीं होता, यानी करानेवाला नहीं होता ।

भारत का शिक्षा शास्त्र

इन दिनों यूरोप और अमरीका में अनेक नये शास्त्रों की खोज हुई है और वहाँ से हमको बहुत सीखना है—इसमें कोई शक नहीं । खास करके अनेक-विध विज्ञान का विकास इन पाँच-पचास सालों में वहाँ बहुत ज्यादा हुआ है । वह तो हमको सीखना ही चाहिए । लेकिन फिर भी भारत की अपनी भी कुछ विद्याएँ हैं और कुछ शास्त्र वहाँ पर पुराने काल से विकसित हैं । उन शास्त्रों में शिक्षा शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसका भारत में काफी विकास हुआ था । इसमें कोई शक नहीं कि हमकी बहुत सेना है लेकिन अपने पास जो है उसे ही पहचानना चाहिए और यह इसलिए जरूरी होता है कि जो जहाँ का होता है वहाँ की परिस्थिति और चारित्र्य के लिए अनुकूल होता है । यहाँ का बच्चा हुआ जो शिक्षा शास्त्र है वह हमारे प्रभाव से अनुकूल होने के कारण हमको काफी मदद दे सकता है । शिक्षा शास्त्र के जो ग्रन्थ संस्कृत भाषा में हैं उन सब में शिरोमणि ग्रन्थ है पतञ्जलि का योगशास्त्र । उसमें शिक्षा के विषय में मावस और अति-मानस दोनों दृष्टियों से विचार किया गया है । पतञ्जलि ने योगशास्त्र में वृत्तियों का परीक्षण करके वृत्तियों के अनुकूल कैसे बढ़ा जाय और वृत्तियों से परे कैसे हुआ जाय, ये दोनों बातें बतायी हैं । यदि वृत्तियों के अनुकूल नहीं बरतते तो हम ससार में कोई कार्य नहीं कर सकते हैं । वृत्तियों से परे होकर अगर नहीं सोचते तो एतस्य दर्शन नहीं होता । और इसलिए नजदीक ही छोटे विन्तन में हम गिरपजार रहते हैं और दूर दृष्टि का अभाव हो जाता है । दोनों दृष्टियों को ध्यान में रखकर पतञ्जलि ने बहुत थोड़े में योगशास्त्र में यह बात रखी है ।

राजनीति और शिक्षा

पतञ्जलि परमात्मा को गुरु रूप में देखते हैं। 'स एष पूर्वेषामपि गुरु'— यह परमात्मा की बात है? हमारे जो प्राचीन ज्ञानी हो गये हैं, उनका भी गुरु। मुझे बहुत-सी भाषाएँ पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन किसी धर्मग्रन्थ में या परमात्मा को गुरु रूप में देखा गया हो—एसा मैंने नहीं देखा। परमात्मा को पिता के रूप में देखा ही जाता है। 'पितामि लोकस्य' इत्यादि। क्रिश्चियानिटी में तो परमात्मा के लिए 'फादर' आता ही है। माता के रूप में भी वह देखा गया किन्तु योगशास्त्र में उसे गुरु के रूप में देखा गया है। परमात्मा गुरु रूप तो है ही, वह परम गुरु है। वह हम सबको शिक्षा देता है, देता ही हमको उठका अनुराग करके सीखना सिखाना है। वह अखण्ड तटस्थ होकर सिखाता है। इसके सिखाने की विधि जो है वह तटस्थता की है। वह कोई चीज लावता नहीं। परन्तु इन दिनों हमारे यहाँ या दूसरे देशों में सरकारी तौर पर जो कुछ भी प्रयत्न हो रहे हैं वे इतनी बात के हो रहे हैं कि जिन-जिन विचारों की सरकारें बनी हुई होती हैं वे अपने विचारों का विद्यालयों पर असर डालना चाहती हैं। और विद्यालयों को उसकी पकड़ में रखना चाहती हैं। वे विद्यालयों को अपने सौंपों में डालना चाहती हैं। अगर कम्युनिज्म हुआ तो कम्युनिज्म की आइडियासों की सिखायी जायेगी। अगर फासिज्म हुआ तो सारे विद्यालयों को फासिज्म सिखाया जायेगा। और इसी प्रकार से भिन्न भिन्न राज्यों व्यवस्थाएँ आती हैं, और अपने बने-बनाये विचारों में विद्यालयों के दिमाग को डालने की कोशिश होती है। यह सबकुछ डेमोक्रेसी पर बहुत बड़ा खतरा है। मत का अधिकार देते ही तो मनन स्वातन्त्र्य भी तो होना चाहिए। अगर मनन स्वातन्त्र्य नहीं है तो एक हाथ से वोट का अधिकार दिया और दूसरे हाथ से उसे निराम लिया, इतना ही होता है। यह बहुत बड़ा खतरा सब देशों में मौजूद है और अपने देश में भी है।

शिक्षक के तीन गुण

शिक्षक में कम से-कम तीन गुणों की आवश्यकता है, एक गुण यह कि विद्यालयों पर प्रेम होना चाहिए, वास्तव्य होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। इससे बिना शिक्षक बन ही नहीं सकता। शिक्षक का दूसरा बड़ा गुण है निरन्तर अध्ययनशील होना। रोज नया-नया अध्ययन जारी रह और ज्ञान की वृद्धि सतत होती चली जाय। इस प्रकार से उसे ज्ञान का समुद्र बनना है। उसको ज्ञान की उपायना करनी है।

एक तीसरा मुल और होना चाहिए जिसका बोझ-सा उल्लेख मैं कर चुका हूँ। मैंने कहा कि इन दिनों विचारपियों के दिमाग पर पोलिटिक्स बहुत लादा जाता है और वे विचार्यों शिक्षकों के हाथ में हैं। अगर शिक्षक राजनीति में पड़े हुए हैं तो समझना चाहिए कि शिक्षक का व्यवसाय बेकार हो गया। तब वे कर्त्ता नहीं रहे, कर्म हो गये। उनकी करनेवाले दूसरे हैं कर्त्ता और वे उनके कर्म हैं। उनके हाथ में कृतत्व नहीं है। वह कर्मणि प्रयोग है, कर्त्तरि प्रयोग नहीं। धरने यहाँ जो कुछ विचार या उसमें राज्य सत्ता की सत्ता गुरु पर नहीं थी। गुरु उससे परे था। ग्राम विभाग को शासन की तरफ से तनहावह मिलती है लेकिन फिर भी उस पर शासन का अकुस नहीं है। जिस तरह यह बात इंडियन के बारे में मान्य हो गयी है, इसी तरह शिक्षा के बारे में भी मान्य होनी चाहिए। तब शिक्षा पढ़ना। आइए हम पोलिटिक्सिपन्स की पकड़ में हैं, उस पकड़ से छोटे बिना शिक्षा का कोई मसला हल नहीं होगा।

स्वतंत्र देश की तालीम

पुरानी बात है, १९४७ पंद्रह अगस्त स्वातंत्र्य दिन की। लोग ने मुझको आश्वासन देने के लिए पवनार से वर्षा सुनाया। मैंने उनसे पूछा, 'देखो भाई, स्वराज्य मिल गया तो क्या पुराना झण्डा एक दिन के लिए भी स्वीकार करोगे?' वे बोले, 'नहीं।' अगर पुराना झण्डा चले तो उसका अर्थ होगा पुराना राज्य हो चला रहा है। इसी तरह अगर पुरानी ही तालीम चली तो समझना चाहिए कि पुराने राज्य का ही एक्स्प्लेन चल रहा है, नया राज्य नहीं आया। गांधीजी ने दूर-दृष्टि से नयी तालीम नाम को एक पद्धति सुनाई—और वह गांधीजी ने सुनाई इन वास्तव माय करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं है कि उनकी बात हमें जैसी की तैसी माननी चाहिए और न गांधीजी स्वयं ऐसा मानते थे कि उनकी चीज जैसी की तैसी मानी जाय। अगर एक पञ्चायिक, दो पञ्चायिक, तीन पञ्चायिक, चार पञ्चायिक योद्धाएँ चली और तालीम का झंडा पुराना का पुराना ही रहा। कोई बदलाव नहीं हुआ। आजकल की सरकार कहती है कि शिक्षा के बारे में बड़ बड़े प्रश्न हैं। भारत में शिक्षा का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है और इसलिए नयी-नयी समस्याएँ हमारे सामने आकर खड़ी हो गयी हैं। भूलतः यह है कि अगर आप तालीम नहीं बढ़ाते तो लोग बेवकूफ रहेंगे और अगर तालीम बढ़ाते हैं तो बेकार बनेंगे। अर्थात् बेवकूफ बनो या बेकार रहो। कहा जाता है कि भारत में शिक्षा की यह एक बड़ी समस्या है। मैं कहता हूँ कि शिक्षा वह चीज है

जिससे समस्याओं का हल होता है तो फिर वह शिक्षा भी समस्या हो गयी ? जिससे तमाम समस्याओं का परिहार होता है वह समस्या क्यों हो गयी ? इसलिए कि शिक्षा राज्य के हाथ में चली गयी ।

जो अधिकार आपने शकराचार्य को नहीं दिया, जो अधिकार आपने तुलसीदास को नहीं दिया, वह अधिकार आपने एजुकेशन टायरेक्टर को दे दिया । जो किताब उन्होंने तय कर दी, पास कर दी, उसको पढ़ानी पड़ेगी । यह अधिकार तुलसीदास ने लिया नहीं और आपने दिया नहीं । काफी लोग रामायण पढ़ते हैं किन्तु अपनी स्वेच्छा से पढ़ते हैं । सार यह है कि हरेक का अपना स्थान होता है । शिक्षा का सारा का सारा क्षेत्र शासनभूत होना चाहिए । इसे मुक्त रखना आपके अधिकार में है । उसके पजे से आप स्वयं मुक्त हो जायें तो शिक्षा मुक्त हो जाये ।

ज्ञान और कर्म का योग

गांधीजी ने, कृष्ण ने, पतञ्जलि ने सबने सिखाया कि ज्ञान और कर्म इकट्ठा होना चाहिए । ज्ञान और कर्म के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए । ज्ञान कर्म से अलग बही होना चाहिए । अगर ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के पास ज्ञान और कुछ लोगों के पास कर्म तो राहु-केतु का समाज बनेगा । देहात ■ सारे लोग केतु बनेंगे और शहर के लोग राहु । काम करने की शक्ति किसान के हाथ में और ज्ञान की शक्ति शहरवालों के हाथ में, तो वह इसको क्या देगा और यह उसको क्या देगा ? इस वास्ते अगर उत्पादन बढ़ाना है, पराक्रम का प्राम करना है, विकास करना है, तो ज्ञान और कर्म को इकट्ठा होना चाहिए ।

आरच्य की बात है कि गांधीजी ने कहा और चीन ने सुना । उन लोगों ने सारे देश के तमाम लोगों को एक ही तरह के स्कूलों में रखा है । उसमें तीन घण्टे काम करना पड़ता है और तीन घण्टे पढ़ना पड़ता है । यह और बात है कि उनका कम्युनिज्म बाला, सोशलिज्म बाला ज्ञान रम्यो होता है । उनका रंग बढ़ा दिया जाता है, यह बलव बात है । परन्तु सबको ज्ञान, सबको काम, दोनों आधा-आधा—यह चीनवालों ने की । यहाँ पर भी हमको इस बात का आयोजन करना होगा कि हमारे सब बच्चों को काम और ज्ञान समान रूप से मिले :

अध्यात्म और विज्ञान

एक और बात मैंने जाहिर की है । राजनीति और धर्म पुराने पड़ गये ।

धर्मपथो के दिन लद गये। भिन्न-भिन्न धर्मों की जगह अध्यात्म जाना चाहिए और राजनीति की जगह विज्ञान जाना चाहिए सब काम होगा। व्यापक साक्ष-स और व्यापक अध्यात्म स्वीकार करना होगा, तभी बुनियादी मसले हल होंगे। पुराने जो विचारक हो गये हैं, उनके विचारों को जैसा का तैसा धर्म के नाम पर स्वीकार कर लेने में सार नहीं है। इसमें अध्यात्म का आधार लेना चाहिए। सर्वोत्तम अध्यात्म विद्या जो भारत में थी उसका अध्ययन अध्यापन स्कूलों में होना चाहिए और उसके साथ माइन साक्ष-स का भी अध्ययन होना चाहिए।

माध्यम का सवाल

अगर आठ साल की शिक्षा बच्चों को देनी है और उस आठ साल की शिक्षा के अन्दर हमने अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन एसे कोई 'विन्डो' रखी तो यह बेकार है। उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि वह लोग अंग्रेजी या फ्रेंच सीखेंगे, और ऐसे थोड़े-से ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि यह तो आठ साल की परीक्षा देकर चले जायेंगे। कोई खेती में जायेगा, अपना खरना काम करेंगे। उन सब लोगों पर दूसरी भाषा लादना ठीक नहीं है। अभी तो अपनी भाषा का भी ठीक से ज्ञान नहीं हाता। अगर वे मातृभाषा का अध्ययन करेंगे तो उनके जीवन में उसका कुछ उपयोग होगा। मातृभाषा के द्वारा शिक्षा देनी है या नहीं, यह बड़ा विलक्षण प्रश्न है। इसमें दो रायें तो होती ही नहीं चाहिए। दो रायें कैसे बनती हायी, हमारी समझ में नहीं आता। गधे के बच्चे से पूछा जाय, 'गुहे गधे की भाषा में ज्ञान देना चाहिए या सिंह की भाषा में?' तो वह कहेगा, 'सिंह की भाषा चाहे जितनी भी अच्छी हो मुझे तो गधे की भाषा समझ में आयेगी, सिंह की नहीं।' तो यह जाहिर बात है कि मनुष्य के हृदय की ग्रहण करनेवाली भी मातृभाषा है, शिक्षा उसी के द्वारा होनी चाहिए।

अब सवाल उठता है कि इस तालीम के लिए कितना समय दिया जाय? कमोमन की रिपोर्ट है दस साल से ज्यादा न हो। उन्होंने जो निर्णय दिया है वह काफी अच्छा है। मेरी अपनी राय है कि अगर पूरा प्रयत्न किया जाय तो पाँच साल में भी हो सकता है। ऐसा आस नहीं है, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए। मातृभाषा के द्वारा ही शुरू से आखिर तक की पूरी तालीम दी जानी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ●

डा० डी० एन० कौल

बुनियादी शिक्षा—आनेवाले कल की शिक्षा-पद्धति

हिंदुस्तानी शिक्षा-शास्त्री अंग्रेजों पर जमाने से यह बोधोपपन्न करते रहे हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान में विदेशी शिक्षा-प्रणाली चलायी। आज भी कुछ शिक्षा-शास्त्रियों की धृष्टि कहने में कोई हिचक नहीं होती। सचबाई यह है कि अंग्रेजों ने हमें जो शिक्षा-पद्धति दी वह उस ब्रि-दश के रयास से सबसे अच्छी थी जिसमें वे खुद पलकर बड़े हुए थे, और यह बिलकुल स्वाभाविक था कि वे हमें यही शिक्षा पद्धति देते। शिक्षा के सम्बन्ध में अगर हमारे पास अपने विचार होते तो हम निश्चित ही अपनी इच्छानुसार उसे स्वीकार या अस्वीकार कर देते। लेकिन अपना शिक्षा-पद्धति क्या है यह न हम उस समय जानते थे न आज, यह निहायत अकसोस की बात है। यह सही ही कहा गया है कि लोग जिस गान्य होते हैं शिक्षा की वही पद्धति उन्हें मिलती भी है। सुजन की अवधि में कोई राष्ट्र परीक्षण व विश्लेषण करता है। देश में जैसे ही इस सजवात्मक प्रेरणा ने जन्म लिया हमने शिक्षा प्रणाली की जाँच पड़ताल शुरू कर दी और यह प्रश्न भी शुरू कर दिया कि अंग्रेजों की हमारे ऊपर यह शिक्षा-पद्धति लादने का हक क्या है? राष्ट्र के लोच पर हमने एक शिक्षा-पद्धति निकाली भी जिसे धामतीर पर सिद्धा का बुनियादी तरीका कहते हैं।

इस प्रणाली को समझने के लिए यह जरूरी है कि भारतीय चिन्तनधारा का सामान्य और विशेषकर शिक्षा के विकास का अध्ययन किया जाय।

अंग्रेजों के सम्पर्क से हिंदुस्तान के लोग पश्चिमी विचारों व शिक्षा के निवट धामे और इससे देश के प्रबुद्ध लोगों पर बड़ा असर पड़ा। कुछ समय

बाद देश ने विचारको, सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज सुधारका, धार्मिक सुधारकों तथा अन्य लोगों की एक अच्छी खासी मस्या पैदा की जिन्होंने भारतीय विचार व चिंतन को उसके पूरे विस्तार में फिर से परखना शुरू किया। इन लोगों ने विदेशों नेससको, नेससो, विचारों व उनकी प्राप्तियों को परखा और साथ ही इन्होंने दुनिया की स्थिति तथा पूर्व व पश्चिम में चिंतन की उन धाराओं की भी परख की। इसका नतीजा वही निकला जिसे हम भारतीय चिंतन व विचार की जागृति या रिनेसा कहते हैं। उन लोगों में से जिनके कारण यह रिनेसा सम्भव हो सका, धार्मिक क्षेत्र के कुछ बड़े नाम ये हैं : राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी यदुनन्द, स्वामी रामतीर्थ। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र के प्रमुख नाम हैं बाल गंगाधर तिलक, सात्य सात्रपतराय, चितरजनदास, आगरकर तथा विज्ञान एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख नाम हैं सो० बी० रमण और टैगोर। शुरू-शुरू में यह जागृति साहित्य-रचना, सम्मेलन आयोजित करने, भाषण देने और नम्र प्रस्तावों के रूप में ही प्रकट हुई, जो ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर सही भी लगता है, क्योंकि क्रिया सम्बन्धी किसी भी कार्यक्रम के लिए यह जरूरी है कि सामान्य चेतना और असतोष की भावना उसकी पूर्ववर्ती रह चुकी हो। भारतीय राजनीति में जब गांधीजी का पदार्पण हुआ तभी काग्रेस में नवीनता आयी और क्रिया सम्बन्धी कोई भी कार्यक्रम जरूरी समझा गया। वास्तव में, बुद्धिवादियों, यहाँ तक की नेहरू की नजर में भी गांधीजी की खास देन यही रही कि उन्होंने देश के सामने कोई कार्यक्रम रखा।

क्रिया सम्बन्धी इस कार्यक्रम के पीछे विचार क्या था और औचित्य क्या था ? हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति धर्म, कला, विज्ञान, दर्शन, सामाजिक रीति-रिवाज तथा उसकी सुराहियों व अच्छाईयों को समझने व उनकी व्यवस्था के लिए काफी कोशिश की गयी थी। पश्चात्य विचार-प्रणाली, अंग्रेजी पार्लियामेंटरी व्यवस्था, अमेरिकी स्वातन्त्र्य युद्ध, फ्रांससी राज्य क्रांति, रूसी क्रांति तथा अन्य आन्दोलनों को समझने के लिए भी काफी ध्यान दिया गया। साथ ही साथ पश्चिम में औद्योगिक क्रांति के कारण हुए परिवर्तन, उनके सर्वसाधारण, धार्मिक व पूँजीपति पर पड़े प्रभाव, लोगों का जीवनमान बढ़ाने के सदर्भ में औद्योगिक उत्पादन का नया दर्शन और उसकी प्रतिस्वरूप बच्चे माल की शरीर और बने माल को बिक्री के लिए बाजारों की खोज और इसी तरह की अन्य बातों में अध्ययन के लिए भी काफी कोशिश की

गयी। विचार के इन विविध क्षेत्रों की तरफ भारतीय भी अपनी प्रतिक्रिया विभिन्न रूपों से व्यक्त कर रहे थे। कुछ लोग प्राचीन भारतीय गौरव को फिर से लाने की बात कर रहे थे। कुछ चाहते थे कि भारतीय अपने कर्म को फिर से ऊँचा उठावें और इन सबसे अलग कुछ बुद्धिवादी भी थे जो कोई बात तब तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जब तक कि वह विचार या तर्क पर न आधारित हो। वे न पुनरोद्धार सम्बन्धी नारों से प्रभावित थे न धर्म सम्बन्धी। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो सार-सग्रह में आस्था रखते थे या जो मध्यम मार्गों कहे जा सकते थे अर्थात् जो इनमें से प्रत्येक में सत्याश की खोज करते थे।

यह कहा जा सकता है कि गांधीजी इसी श्रेणी के व्यक्ति थे। दूसरों की तरह उन्होंने भी अपने मानस में उस समाज का एक चित्र बना लिया जो वह लाना चाहते थे। और यह चित्र उनकी क्रियाओं व उनके कार्यों का वैचारिक आधार बन गया। उन्होंने जिस किसी भी कार्यक्रम की रचना की वह उनकी समाज-निर्माण सम्बन्धी कल्पना से परिचालित था।

आइये हम देखें कि गांधीजी की समाज सम्बन्धी कल्पना क्या थी और उस यह जानने की कोशिश करें कि इस कल्पना से एक क्रियाशील दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई। "गांधी के आदर्श समाज में कोई ऊँचा या नीचा वर्ग नहीं होगा, सभी मिलकर एक ऐसे भारत के लिए काम करेंगे जिसमें कोई ऊँचा या नीचा नहीं होगा, ऐसा भारत जिसमें सभी प्रेम और सद्भाव से रहेंगे। ऐसे भारत में छुआछूत, दारु-मंदिरा या नशीली वस्तुओं के लिए कोई स्थान नहीं होगा। स्त्रियों के भी वही अधिकार होंगे जो पुरुषों के। चूंकि बाकी दुनिया के साथ हमारा सम्बन्ध प्रेम और सद्भावपूर्ण होगा, यानी न हम किसी का शोषण करेंगे न शोषित होंगे, अतः हमारी सेना छोटी-से-छोटी होगी। सभी स्त्रियाँ व बच्चे देशी हों या विदेशी, यदि वे देश के लाखों-लाख निरीह लोगों के विरुद्ध न हुई हों तो उनका जरूर सम्मान किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से मैं देशी या विदेशी जैसे फर्क से घृणा करता हूँ। यही मेरे सपनों का भारत है—इससे कम किसी चीज से सन्तुष्ट नहीं होऊँगा।"¹ यह चित्र कितना सरल है, फिर भी हिन्दुस्तान जिस हालत में था और आज भी है उसके सदर्भ में विचार करने पर बहुत क्रान्तिकारी भी। हर आदमी, स्त्री

१ एसेन्शल गांधी में उद्धृत-सुई फिगर, पृष्ठ १९६, जार्ज एलेन एण्ड अनविन लिमिटेड सदन।

व पुरुष तथा समुदाय, समुदाय की बराबरी पर फिर से जोर देता है। यह एक ऐसी दुनिया चाहता है जहाँ एक दूसरे का शोषण नहीं करता, यह देशी विदेशी का फर्क भी स्वीकार नहीं करता। इस चित्र में एक सास बीज यह है कि इसमें अधिक उत्पादन या समाज के लोगों के लिए ऊँचा या उच्चतर जीवन स्तर की बात नहीं है, इसके विपरीत, पृथ्वी पर वैसे सभी मनुष्यों की बराबरी की बात जरूर है। अब गांधीजी अमोर या ताकतवर हिन्दुस्तान नहीं बल्कि अच्छे हिन्दुस्तान के अर्थों में सोचते थे। उनका तुरन्त लक्ष्य था हिन्दुस्तान की आशाओं की प्राप्ति। उन्होंने महान शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से परम्परागत पारिवर्तक शक्तियों द्वारा नहीं बल्कि उसका मनुष्य के सीधे-भादे व भवै विचार द्वारा सामना करने का निश्चय किया। परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान में मनुष्य की गुण-वृद्धि ही उनका दर्शन बन गया। उन्होंने जो भी कार्यक्रम चलाये वे मनुष्य के विकास के लिए थे। ये रचनात्मक कार्यक्रम हरिजन व आदिवासी, पिछड़े लोगों, स्त्रियों के उद्धार व नगीली चीजों के बहिष्कार के लिए थे। वास्तव में वह कई मोर्चों से एक साथ हमला था जिसमें कई प्रकार के लोग जैसे राजनीतिक, समाज सेवा, धर्म सुधारक व शिक्षाविद लगे हुए थे।

डा० जाकिरहुसेन के नेतृत्व में जो बाद में हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति हुए, शिक्षाविदों ने गांधी का यह कार्यक्रम स्वीकार किया। कांग्रेस द्वारा मन्त्रिमंडल बनाने से इसको देश भर में फैलाने में सहायता मिली। इससे कई समस्याएँ उठ खड़ी हुईं। इसलिए यह जरूरी समझा गया कि एक केन्द्रीय मण्डल हो जो बसिक शिक्षा में अनुसंधान करे, विभिन्न राज्यों के कार्यों में समन्वय स्थापित करे, बसिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के लिए सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करे और इस क्षेत्र में नये तरीकों का विकास करे, परिणामस्वरूप भारत सरकार ने बसिक शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान ने अपने क्षेत्र में कुछ मूल्यवान काम किया और बाद में, जब शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण की राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई तो यह संस्थान "नसर्ट" का एक अन्तरंग भाग बन गया। बाद में यह "पाठ्यक्रम व मूल्यांकन" विभाग में मिला दिया गया।

प्रारम्भिक स्तरों में इस बात से बड़ा बल मिला कि यह सारी योजना देश के सामने एक विचारक द्वारा रखी गयी जो मूलतः राजनीतिक व एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। राजनीतिज्ञों ने इस विचार को उसके सामान्य रूप में ग्रहण किया और वे बड़े उत्साह के साथ उसके प्रसार में लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि स्वयं गति प्रणाली से बड़ी अधिक महत्वपूर्ण बन बैठी।

बेसिक शिक्षा ने प्रति वैसे हमेला ही प्रतिरोध रहा है। यह प्रणाली फंकी जल्द लेविन नाम अच्छी तरह चला नहीं। पाठ्यक्रम के कुछ पहलुओं, शिक्षा के तरीके, प्रशासकीय व शिक्षकों के दस व कुछ समय बाद बेसिक स्कूलों से निकले बच्चों के प्रति सामान्यतः असंतोष हो ध्वस्त हुआ। बेसिक शिक्षा के समर्थकों का यह दृष्टिकोण रहा कि योजना वैसे अच्छी तो है लेकिन उस पर अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया। इस प्रणाली के निर्माताओं में से एक डा० आकिर हुसेन ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह प्रणाली वैसे चलाई जा रही है वह एक धोखा ही है। परम्परावादियों ने कहा कि यह योजना, जैसा कि इनका रुझान था, चल नहीं सकती। १९६४-६६ के शिक्षा आयोग के माध्यम से इस प्रतिरोध को अपना जोर और भी सशक्त रूप से प्रकट करने का मौका मिला। आयोग ने बेसिक शिक्षा की उन्मुखता की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उसने कहा, "बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्त यानी उत्पादक क्रिया, वातावरण व स्थानीय समुदाय से सम्पर्क, इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें शिक्षा का सभी स्तरों पर मार्गदर्शन व उसका रूप निश्चित करना चाहिए और इन सत्सुति में जो सुझाव दिये गये हैं उनका यही भर्त्ता है। शिक्षा का कोई एक स्तर बेसिक शिक्षा के नाम से नहीं चलाया जाना चाहिए।" किसी भी राष्ट्रीय प्रलेख में दर्ज किया हुआ यह एक ऐतिहासिक विरोधाभास है। धोपना तो यह की गयी कि प्राथमिक ही या विश्वविद्यालयी, बेसिक शिक्षा किसे भी स्तर के लिए अच्छी व उन्मुख है लेकिन ऐसी नहीं है कि उसका नाम बनाये रखा जाय। असल बात यह है कि परम्परावादियों को बेसिक शिक्षा के दर्शन से कभी भी संतोष नहीं हुआ। वे यह नहीं चाहते थे कि यह चले। लेकिन उससे यथायथ, उसकी तर्कसंगतता का वह विरोध भी नहीं कर सके। लेकिन धूर्ति के ऊँची जगहों पर गदासीन थे इसलिए उन्होंने उसे एक अच्छा-सा नाम देकर उसे पक्की फाँसी दे दी। उस समय जो सामाजिक मूल्य थे उनके होते तो ऐसा होना ठीक ही था। लेकिन यह हुआ यह दुःख की ही बात है। शिक्षा की वर्तमान प्रणाली २०० वर्षों से चली आ रही है और ५४ विश्वविद्यालयों, २०० से ऊपर शिक्षक-प्रशिक्षण पालेजों व १२०० प्रशिक्षक स्कूलों के बावजूद हम विचार का कोई एक प्रणाली, कोई एक विशिष्ट तरीका, मनोविज्ञान या दर्शन की आभा-समान ही सही लेकिन कोई एक प्रणाली, शिक्षण का कोई भी तरीका या एक अच्छी किताब भी पैदा नहीं कर सके हैं। सामान्य तरीका यही चला आ रहा है कि पाँच किताबें देकर छठी किताब गढ़ दी जाय। हममें से दस में

म नौ को अपने अनुभव या अपने प्रयोग के आधार पर कुछ भी कहना नहीं रहता । और सब पूछिये तो हमने पैदा भी कुछ नहीं किया है । हमारा गुल्मवाक्यपन-केन्द्र अभी हिन्दुस्तान के बाहर ही चल रहा है । परिणाम स्वप्न हम स्थापित नहीं हैं वलिक प्रणय, सहारा व निभरता के लिए पवित्र विचारों को ओर देखने रहना चाहते हैं । शैक्षिक अनुसंधान, प्रयोग व नवीनीकरण के इस दुःखद अभाव की स्थिति में गांधीजी की देन ही आशा की किरण है जो यह बता रही है कि देश की आत्मा मर नहीं गयी है । इस बीरान शैक्षिक दुनिया को शिष्टा आयोग ने बड़ा ही महत्वपूर्ण सेवा की होती यदि उसने एक तरफ तो विदेशी विचारों व विरोधों पर निभर रहने की हमारी प्रवृत्ति का विरोध किया होता और दूसरी तरफ साधारण ही सही लेकिन स्थानीय कोशिशों को प्रोत्साहित कर वैश्व शिक्षा को गर्व से अपनाया व स्वाकार किया होता । उसे इसे सिद्ध करने, इसमें सुधार करने का पूरा हक था । लेकिन दुर्भाग्यवश उसने ऐसा किया नहा । उसमें तो इसके नाम को ही एकदम छोड़ दिया और इसकी आत्मा का स्वीकार नहीं किया ।

वैश्व शिक्षा क प्रति विराघ या इस प्रणाली की असफलता के कारणों की खोजबीन रुचिकर होगी । बात रुचिकर जरूर है लेकिन निदिष्ट जगह में यह सम्भव नहीं है । फिर भी, स्पष्ट और प्रमुखतम कारणों पर विचार-विमर्श टालना भी सम्भव नहीं है । इस प्रणाली को सत्ताह्वय ने बड़े ज़रसाह से अपनाया व लागू किया था । इसके कारण यश व शक्ति प्राप्त करने के भी काफी मौक मिल सकते थे । इसलिए बड़ी ऐसे लोग जो सत्ता व यश को ज्यादा महत्व देते हैं इसे क्रियान्वित करने के बजाय इसे सफल होते दिखाने में जुट गये । इसलिए जिस यथार्थ व जिन वास्तविकताओं की वजह से इसका जन्म हुआ था उनसे यह अलग हट गयी ।

वैश्व शिक्षा प्रणाली की यह कृत्रिम समृद्धि उम्मी शिक्षकों, प्रशासकों तथा अन्य लोगों द्वारा सायी गयी जिन्हें इसमें कोई आस्था नहीं थी । उनकी समझ से यह बाहर था कि उद्योग केन्द्रित शिक्षा व शिक्षण की समवाई पक्षीको राष्ट्र की सर्जनात्मक वृत्ति को कैसे प्ररित या अध्ययन में विविध विषयों की व्यवस्थित व अनुशासित समझ प्रदान कर सकती थी ।

यह प्रणाली इसलिए चलायी गयी ताकि एक नये प्रकार के नागरिक उत्पन्न हों और कुछ स्कूलों ने इस प्रकार के नागरिक उत्पन्न भी किये । लेकिन सामयिक, सामाजिक मुद्दों को इनकी जरूरत नहीं थी । सरकारी व गैर-

सरकारी विभिन्न संस्थाओं यानी विश्वविद्यालयों, परीक्षा के विभिन्न सगठनों, राजकीय नियुक्ति अधिकारियों और लोक सेवा आयोग को ऐसे विद्यार्थियों की जरूरत थी जो सूचनाएँ इकट्ठी करने व स्मरणशक्ति के नमूने पेश कर सकते हैं कि विकसित एवं सतुलित व्यक्तित्व। वैसिक प्रणाली से जिस प्रकार के लोगों के निकलने की आशा की जा सकती थी वैसे लोगों की इन सगठनों की जरूरत ही नहीं थी। इन्होंने एक अच्छे नागरिक या अच्छे व्यक्ति के व्यक्तित्व सम्बन्धी गुणों के निर्धारण का कोई मापदण्ड आज तक तय नहीं किया है। इसलिए वैसिक शिक्षा से निकले लोगों को एक निश्चित हानि उठावी पड़ी। उनका निर्माण ऐसी समाज-व्यवस्था के लिए किया गया था जो अभी था नहीं। अतः उन्हें उसी पुराने समाज में खरना पड़ा जहाँ वे फिट नहीं हो सकते थे। स्वाभाविक था कि शोर-शरावा होता। परम्परावादियों ने वैसिक स्कूलों को निम्नस्तरीय उत्पादक के लिए सुरा-भला कहा। अभिभावकों ने उसे बन्द कर देने की बात कही, क्योंकि वह समझ नहीं सके कि सार्वजनिक नीति-रिक्तों में उनका लड़का क्यों सफल नहीं हो सका। उदाहरण के लिए, दिल्ली के प्रामाणिक लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि अगर वैसिक शिक्षा प्रामाणिक लोगों के लिए अच्छी है तो बाहरी लोगों के लिए क्यों नहीं?

वैसिक शिक्षा योजना के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के लिए जब मूल्यांकन समिति के लोग विभिन्न राज्यों में घूमे तो उन्हें पता चला कि जो लोग वैसिक स्कूलों को चला रहे थे उनमें उनके प्रति कोई आस्था नहीं थी। उन लोगों ने कहा “हमें अच्छे प्रशासक दीजिए, हम आप को अच्छी वैसिक शिक्षा देंगे।” सामान्यतः यह बात निराशाजनक रूप से देखने में आयी कि जैसे काफ़ी लोग जो वैसिक स्कूलों में पढ़ा रहे थे या इसके प्रशासन से सम्बद्ध थे या वे लोग भी जो इसके पक्ष में बोलते थे स्वयं अपने बच्चों को गैरवैसिक स्कूलों में ही भेजते थे। एक परम्परावादी ने वैसिक शिक्षा की जो परिभाषा की उसमें इस लोग का सबसे अच्छा वर्णन निहित है। उसने कहा, “वैसिक शिक्षा वह शिक्षा है जो दूसरों के बच्चों के लिए अच्छी है।”

परम्परागत और वैसिक प्रणाली के बीच जैसे-जैसे फर्क बढ़ने लगा तो लोगों व कुछ शिक्षावादियों ने यह जानना चाहा कि यह प्रणाली क्यों असफल हो रही है या असफल हो भी रही है या नहीं। विभिन्न स्तरों पर कई अध्ययन किये गये। लेकिन सामान्यतः यही हुआ कि वैसिक शिक्षा का मूल्यांकन वैसिक शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि परम्परागत,

शिक्षा के उद्देश्यों और सदस्यों के परिप्रेक्ष्य में किया गया। कारण यह था कि अनुसंधान या सर्वेक्षण करने या उसका मार्गदर्शन करनेवाले ज्यादातर विश्व-विद्यालयों के ही लोग थे जिन्हें वैसिक प्रणाली की कोई जानकारी नहीं थी या यदि थी भी तो बहुत थोड़ी। इनमें से ज्यादातर लोग गांधीजी की बौद्धिकता का विरोधी मानने थे यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी स्थिति में नहीं था कि विश्वविद्यालयों के साथ-से-साथ बुद्धिवाले लोग तैयार कर सकता।

ऊपर जो कारण दिये गये हैं वे काफी उपयुक्त हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है जिसे अभी पूरी तौर से न जाना ही गया है और न उसे स्वीकार ही किया गया है। वास्तव में, जितने भी कारण ऊपर बताये गये हैं या जिनका जिक्र नहीं भी किया गया है वे सभी इस एक कारण में आ जाते हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, गांधीजी एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, जहाँ शोषण न हो, देशी-विदेशी का भेद न हो, और जहाँ मनुष्य सारी दुनिया के साथ शांतिपूर्वक रह सके। ऐसे समाज में व्यक्ति सदैव बढ़ते रहनेवाले जीवन स्तर पर जीवन के सुखों के लिए वस्तुओं के निरन्तर बढ़नेवाले उत्पादन का आकांक्षी नहीं होगा। ये मूलतः क्लेशों परिकल्पनाएँ हैं जिनका उनके लिए कोई मूल्य न था। वह जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए अपनी शक्ति खर्च करने में बढ़ते-चढ़ते शारीरिक विघटन, खादी बुनने व पहनने और अपनी शारीरिक व मानसिक आवश्यकताओं के अनुसार ही भोजन ग्रहण करना अधिक अच्छा मानते थे। उन्हें सुविधा सम्पन्न थोड़े से लोगों की नहीं बल्कि लाखों लाख भूख व विभिन्न लोगों की परवाह थी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे गरीबों के पोषक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों की भयंकर गरीबी के विरुद्ध लड़ने में लगाया। कहा करते थे, "पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की मासरहित पसलियोंवाली थोड़ी मेरे दिमाग में नाचा करती है।" पुनः "किसी ने कभी यह नहीं कहा कि भयंकर गरीबी का परिणाम नैतिक पतन के अभाव और कुछ होगा।" उन्होंने आगे फिर कहा, "ऐसे लोगों के सामने जो मूल में भर रहा हों और बेकार हो, भगवान भी काम व भोजन तथा धनदूरी की हा शक्ति में आने की हिम्मत करेंगे।" लेकिन इतना तो निश्चित है कि वे किसी ऐसे जीवन-दर्शन के पक्ष में नहीं थे जिसमें मनुष्य मरने पर संकुश न रहे। जीवनमान की उनकी कल्पना उस मापदण्ड के अनुरूप नहीं थी जिसमें "मुख्यतः भौतिक वस्तु-आधिक्य या भोगवादिता पर जोर दिया जाता है

वल्कि उन व्यक्तियों में निहित थी जिनमें मनुष्य की पवित्रता, सत्य, अहिंसा और धृष्टार्थ को महत्त्व दिया जाता है।" म्योर सेण्ट्रल कालेज के विद्यार्थियों के समक्ष बोलते हुए उन्होंने कहा था, "महाराष्ट्र सचमुच अध्यात्मिक तभी बनेगा जब हम स्वर्ण की मुखाबिन्दु अधिक सत्य और आत्मप्रेम के मुकाबिले अधिक त्याग व दान भावना प्रदर्शित करेंगे। अगर हम अपने भनानो, महलो और मदिरों में धन के उपादानों को नहीं बल्कि नैतिकता के उपादानों का प्रदर्शन करें तो एक बड़ी सेना रखने का भार उठाये बिना हम बित्तनी भी विरोधी शक्तियों के गठवधन का मुकाबिला कर सकते हैं। आइये हम पहले ईश्वर का राज्य और उसकी करणा की सलाह करें और इसका अवश्यम्भावी परिणाम यही होगा कि हमें बाकी प्रत्येक वस्तु मिल जायगी। यही वास्तविक अर्थशास्त्र है। ईश्वर आरको तथा हम इनका सुरक्षित रखने और जीवन में उतारने सायक बनाये।" २ अतः गांधीजी का अर्थशास्त्र यद्वा सरल था। उनका विश्वास आवश्यकता से कम से कम रखने में था। लेकिन ये आवश्यकताएँ इतनी जल्द रह ताकि शरीर व मन अच्छी तरह काम करने सायक सक्षम बना रह। उनका विश्वास ऐसे दर्शन में नहीं था जिसमें उद्योग व तकनीक अनिवार्य बन जायें आवश्यकताओं में वृद्धि हो जाय आपूर्ति और बढ जाय और घर व बाहर और अधिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगे। उनकी यह धारणा थी कि उद्योगों के अकुशल रहित उपयोग से शोषण और बढगा। उन्होंने घोषणा की, मुझे डर है औद्योगीकरण दुनिया के लिए एक अभिशाप बनने जा रहा है। ३

गांधीवादी अर्थशास्त्र की नैतिकता की देश के बुद्धिवादियों ने स्वीकार नहीं किया। उनके शिष्य जवाहरलाल नेहरू तक को भी उनसे इस बात में सहमती नहीं थी। नेहरू ने कहा, 'यह सही है कि जीवन के प्रति उनके सामान्य दृष्टि की और आधुनिक दृष्टिकोण में मौलिक अंतर है। वे निरंतर बढ़ते जीवन स्तर आध्यात्मिक मूल्यों की दबाकर वह भोग विलास बढाने की कायल नहीं है। उन्हें आरामतलबों की जिदगी पसंद नहीं है। उनके लिए सीधे रास्ते का अर्थ है कठोर रास्ता जबकि सुख सुविधाओं के प्रति प्रेम बढ-

२ म्योर कालेज इलाहाबाद की अर्थशास्त्र समिति ■ समक्ष २२ दिसम्बर १९१६ को दिये गये भाषण से।

३ मग इण्डिया १९१९ १९२२ १२ ११-२१, २६५।

नीयती खाना व सद्गुणों का विनाश करना ।” गांधीजी ॥ ग्रामस्वालयन या ग्रामीण सर्वशास्त्र या बड़े उद्योग धर्मों के प्रति उनके विरोध को भी बुद्धिवादियों ने स्वीकार नहीं किया । इसे कई आधारों पर अस्वीकृत कर दिया गया । पहला, “सादा जीवन उच्च विचार” या “आत्म निग्रह” ॥ जीवन को “अभाव की सृष्टि” से उत्पन्न माना गया । दूसरे, कुटीर उद्योगों व धातमनिर्भरता सम्बन्धी विचारों को मशीनों की उत्पादकता के सामने ठहरते लायक नहीं समझा गया । बुद्धिवादियों ने सर्वोपरि रूप से मशीनीकरण व अच्छे जीवन के आदर्शों में कोई विरोधाभास नहीं देखा ।

और जब कांग्रेस सत्ता में आयी और उसने देश का भाग्य धनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली तो विनय लेने की जिम्मेदारी भी वास्तविकों और जैसे बुद्धिवादियों की एक बड़ी सहाय पर आ पड़ी जो सत्ताह्वय दल के प्रति निष्ठा के हामी थे या जिन्होंने अपनी निष्ठा उसके पक्ष में कर ली थी । अतः स्वाभाविक ही था कि बुद्धिवादियों का अदरनी जो वास्तविक बितन या उसे कार्यक्षेत्र में परिणत किया जाता । जैसे बुद्धिवादियों के बितन का उद्गमस्थल पश्चिम की सृष्टि और बितनप्रणाली में था । अनुकूलत देश के औद्योगिकरण और उसी बितन को कृषि तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में उतारने की गम्भीर चेष्टा की गयी । जो तक दिया गया वह सरल था । हिन्दुस्तानी भी वैसी ही आराम की शिथिल बिताने लायक क्यों न बनें जैसा कि किसी भी विकसित देश में कोई व्यक्ति बिताता है । ‘जीवन स्तर’ व जी० एन० पी० (कुल राष्ट्रीय उत्पादन) की परिकल्पना का यहाँ भी यही अर्थ लिया जावे लगा जो पश्चिम में देश का सारा प्रयास इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति बन गया और “पञ्चवर्षीय योजनाओं” की परिकल्पना, निर्माण व क्रिया-व्ययन भी इन्हीं आधारों पर किया गया । आज हमारा देश दुनिया के अच्छे से विकसित व औद्योगिकरण सम्पन्न देशों में से एक है । अपनी अन्य आवश्यकताओं के सन्दर्भ में औद्योगिकरण की सीमा पर विचार-विमर्श करने का यहाँ अवसर नहीं है । अधिकारी विद्वानों ने कहा है कि हमारी पञ्चवर्षीय योजनाएँ—समेरित और रूसी नमूने से अधिक प्रभावित हैं जबकि इन देशों का सांस्कृतिक व जनसंख्या सम्बन्धी आधार हम से बहुत भिन्न है ।

यह भी कहा गया है कि ये योजनाएँ भारतीय वास्तविकताओं पर आधारित नहीं हैं और उन्होंने कुछ आधारभूत सम्पत्तियों को ध्यान में नहीं रखा

है। एक तथ्य यह है कि हमारी ८२ प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है। और विकास की कोई बात जनसंख्या के इन बड़े हिस्सों को ध्यान में रखकर सोचनी चाहिए थी। दूसरा तथ्य यह है कि ऐसे देश का औद्योगीकरण जिसमें थमशक्ति की बहुलता हो, एक विशेष प्रकार का होगा। यह स्वरूप वैसा ही नहीं होगा जैसा कि सीमित थमशक्तिवाले देशों का होता है। तीसरा तथ्य यह है कि यह औद्योगीकरण किस सीमा तक या लोगों के किस धरा को रोजगारी दे सकेगा। यह भी कहा गया है कि हमारी योजनाएँ हमारे साधनों के संदर्भ में विशाल जरूर हैं लेकिन हमारी आवश्यकताओं के संदर्भ में नहीं। फिर भी हम अच्छे-खासे तौर पर औद्योगीकरण के रास्ते पर हैं। अतः यह देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन औद्योगीकरण का अब तक क्या जबर रहा है और आगे की दशा क्या है ?

पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ है कि देश के लिए गांधीजी द्वारा सोचे गये कठोर किन्तु अच्छे जीवन-दर्शन से हटकर उस सुखकर सांसारिक जीवन को महत्व मिल गया जो बुद्धिवादी देश में लाना चाहते थे। एक औसत भारतीय बड़प्पन व अच्छाई को सांसारिक सुख व कल्याण की दृष्टि से नापने लगा। अभिकार्यकर्ता, क्लर्क, डाक्टर, इंजीनियर, राजनीतिज्ञ, सभी मानवीय बड़प्पन व मूल्य को अभिकार्य या डाक्टर की दुनिया की हैसियत की दृष्टि से नापने लगे, उनके अच्छे बनने या अच्छा करने की योग्यता की दृष्टि से नहीं। इस दृष्टि का परिणाम यह हुआ कि साधन सम्पत्तियों और साधनविहानों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया, थम व पूँजी के सगड़ों व मनभेदों को शुद्धमान हा गया, थम या ट्रेड यूनियनों या पूँजीपति-यूनियनों को स्थापना में सहायता मिली। और इस तरह आदमी से आदमी अलग हो गया। थमिक ने कम काम करना और अधिक दाम माँगना शुरू कर दिया, अधिक पूँजीपति अधिक काम लेने और कम दाम देने की तलाश में रहने लगा। इन दृष्टि के कारण दूसरे स्तर पर पानी प हवा के दूषण की शुरुआत हो गयी, और जहाँ एक समय सहलहाते हरे क्षेत्र थे वहाँ गंदी यस्त्रियों का निर्माण शुरू हो गया। इससे घोरबाजार की भी शुरुआत हुई और हाल ही में वित्त मंत्रालय ने पालियामेण्ट में कहा है कि बाजार में छुग काता धन बराब-करोब समानान्तर अर्थव्यवस्था चला रहा है। एर दूसरे स्तर पर औद्योगीकरण का विस्तार नयी-नयी आदतें जैसे मारक द्रव्यों व नगोनी वस्तुओं का सेवन पंदा कर रहा है। १९६३ से ६८ के पाँच

वर्षों में हो करत में ३० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस तथ्य पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चूंकि हम हिन्दुस्तान की धरती पर पश्चिम का जीवन दुहरा रहे हैं इसलिए दुनिया के इन हिस्से में भी हम मनुष्य के इस विकास और पतन का इतिहास दुहरा रहे हैं। जीवन के निरंतर बढ़ते स्तर व जी० एन० पी० यानी कुल राष्ट्रीय उत्पादन पर जोर देने की वृत्ति दुनिया के औद्योगीकरण प्राप्त देशों में सफल हुई। उनसे ऐसी भौतिक समृद्धि आयी जो मनुष्य ने कभी देखा नहीं था। आज औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में एक औसत आदमी भी जो चाहे पा सकता या पाने की आशा रख सकता है। भौतिक विकास में तो आदमी ने चोटी छू ली है। बौद्धिक विकास में भी उसने बहुत ऊँचा स्तर पा लिया है। उसने चाँद पर कदम रख दिया है, और दूसरे ग्रहों, नक्षत्रों पर भी ऐसा ही करने की सोच रहा है।

फिर भी, यह चित्र का सिर्फ एक पहलू है। घन-दोलत की इस विपुलता ने समाज की बीमार बना दिया है। समाज सब अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता। विनाश की जिन शक्तियों के निर्माण के लिए उसने इतनी बड़ी मेहनत की उन्हीं के आगे अब वह असहाय होता जा रहा है। उसने जीवन का एक ऐसा प्रकार विकसित कर दिया है जो अब उसकी मजबूरी बन गया है, और जहाँ से वापस लौटने की कोई गुज़ारिश नहीं है। धरती माता के पेट में जो सीमित साधन पड़े हैं वह उन्हें बड़ी तेज़ी से खतम कर रहा है। उसने पानी और वायु को दूषित किया है और आगे भी करता जा रहा है। उसने धरती व जल कई चीज़ों की जगहें ही खतम कर दी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस जीवन-वृद्धि ने मानसिक व शारीरिक एक बीमारी पैदा कर दी है, जिस पर नियंत्रण कर पाना कठिन होता जा रहा है। मानसिक बीमारियाँ तो बड़ी-छोटी पर हैं ही, यही दशा अपराध व किशोर-अपराध की भी है। यहाँ तक की स्त्रियों द्वारा किये गये अपराध भी बढ़ रहे हैं। इस सनातन स्थिति ने सबको चौंका दिया है और दुनिया भर के विचारक यह सोचने में लगे हैं कि मनुष्य को निकट विनाश से कैसे बचाया जाय। निरंतर बढ़ते जानेवाले उत्पादन व जी० एन० पी० के इस दर्शन के विरुद्ध जैसा कि स्वामाजिक है, दुनिया के समृद्ध देशों से ही आवाज़ उठ रही है।

प्रचुरता और उसके परिणामों के विरुद्ध विद्रोह उठ खड़ा हुआ है। विचार व व्यवहार के कट्टरपन के विरुद्ध भी विद्रोह है। सब पूछा जाय तो स्वयं वैज्ञानिकों की तरफ से दर्शन के खिलाफ विद्रोह है। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध

जीव वैज्ञानिक प्रोफेसर लडविग यान वरटेन लंडेन पनाई कहते हैं, "बीमारी का निदान यह है कि वह मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं को तो कम-बेश रूप में पूरा करती भी है लेकिन आत्मिक आवश्यकताओं को एकदम सुरक्षा देती है।" इसके अलावा कुछ प्रमुख वैज्ञानिक निरन्तर बढ़नेवाले उत्पादन और जी० एन० पी० जैसी परिकल्पनाओं की बुद्धिमत्ता में सदेह प्रकट करने लगे हैं। वे यह सीधा प्रश्न पूछने लगे हैं 'क्या पृथ्वी के सीमित साधनों से इस दशक की निरन्तर बढ़ती रहनेवाली भागों की पूर्ति हमेशा हो सकती है?'^४ इस समस्या पर सोचने विचारनेवाले विद्वान वैज्ञानिक इस अनिवार्य विष्णु पर आये हैं कि जी० एन० पी० बढ़ाने के पीछे हमारा जो पागलपन भरा मोह है उसे अब उलट देना चाहिए और प्राकृतिक साधना का इस्तेमाल न केवल थोड़े समय के पैसे सन्व धी मतलबों की पूर्ति के लिए बल्कि वातावरण के दूरगामी परत के आधार पर भी होना चाहिए। हाल ही में ३५ प्रमुख वैज्ञानिकों, विद्वानों मंगोलजों, पत्रकारी और इंगलंड के कुछ पार्लियामेण्ट सदस्यों ने दुनिया को अथ-अवस्था में ब्राह्मिकारी उलट फेर की मांग की, क्योंकि "आर्थिक प्रगति मनुष्य जाति के लिए बरबादी जा सकती है।" उन्होंने कहा "सरकारें वास्तविक हल प्रस्तुत करने में अक्षम रहो हैं, वे समस्या का आकार भी निर्धारित करने में अक्षम रहो हैं। हमारा लक्ष्य स्थायी अथ-अवस्था होना चाहिए। इसे उस स्तर पर स्थायी होना चाहिए जिसे पृथ्वी अनिश्चित काल तक बर्दाश्त कर सके। हमारी आज की व्यवस्था घन, स्वाध, अज्ञानता व सीमित साधनों के बतहाशा शीघ्र पर आधारित है। विशेषरूप से, वस्तुएँ ऐसी बनें जो निर्दिष्ट समय तक चल सकें न कि ऐसी जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी जायें।"

इन दूरदृष्टी विद्वानों के अनुसार दुनिया को आज जिस बीज की जड़स्त है वह न तो जीवन का निरन्तर बढ़नेवाला स्तर है व तो निरन्तर बढ़नेवाला जी० एन० पी० बल्कि एक स्थायी अथ-अवस्था है। इन विद्वानों की 'स्थायी अथ-अवस्था' का अर्थ गांधीजी के 'आत्म सयम' में अलावा और कुछ नहीं है। यानी मनुष्य के गुणों न कि उसके सुखों के दशक का ही दूसरा नाम है। यह सुखमय जीवन के मुकाबिले अच्छे जीवन को महत्त्व देता है। यह आत्मा के सत्कार व विज्ञान तथा तकनीकी को दुनिया ने बीच रास्ताने स्थापित करना

४ प्रायलमस एण्ड इसुज इन कान्टेम्पोरेरीज एजुकेशन एण्ड एथानॉजी, पृष्ठ २४८, स्वाट, फोरमैन एण्ड क०, यू० एस० ए०

है इस दृष्टि से, यदि मनुष्य जाति को आदमियों का जीवन जीना है तो वैदिक शिक्षा का दर्शन ही वह अनिवार्य दर्शन है जिसे मनुष्य या अपनाता ही होगा। आज दोड़ ज्ञान और अज्ञान के बीच नहीं बल्कि ज्ञान और अज्ञान के बीच है। आवश्यकता इस बात की कि ज्ञान इस प्रकार प्रयुक्त हो ताकि उससे अज्ञान उद्भूत हो न कि और अधिक ज्ञान और इन्द्रियसुख और गांधीजी वैदिक शिक्षा की प्रणाली द्वारा यही लाना चाहते थे। जहाँ तक कुछ कार्यप्रणालियों और तकनीकों का सम्बन्ध है हम गांधीजी से अमहमन हो सकते हैं लेकिन वैदिक शिक्षा द्वारा प्रणिपादित दर्शन से हम किसी भी हालत में असहमत नहीं हो सकते और यदि यह सत्य है तो हिन्दुस्तान ही नहीं सारी दुनिया के लिए दुनियादी स्कूल आनेवाले बल का स्कूल है।

ई शिक्षाशास्त्री जो अपने का मानवमात्र से सम्बद्ध महसूस करते हैं, एक ऐसा स्कूल विकसित करने में लगे हुए हैं जिसे अब 'मनुष्यजाति का स्कूल' कहा जा रहा है। यह आशा की जा रही है कि इस स्कूल से एक ऐसी प्रणाली विकसित होगी जिससे विभिन्न राष्ट्रों को अपने आत्म-प्रेम के पात्र से बाहर आकर सारी दुनिया के मानव को भ्रातृभाव के एक विस्तृत दायरे में गले से लगाने और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षण की प्रक्रिया विकसित करने में मदद मिलेगी। यह प्रणाली शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करने की ओर उन्मुख रहेगी ताकि दोनों जीना सीखने के लिए पर्याप्त रूप से स्वतंत्र रहे।

इसका सत्य एक नयी दुनिया का निर्माण है जहाँ मनुष्य जागतिक होगा, ऐसा मनुष्य जिसका वास्तविक व्यक्तित्व, जाति, मत, वर्ण, धर्म, भाषा, भौगोलिक व राष्ट्रीय व्यवधारों को पार कर जायगा। ऐसी आशा है कि यह सत्य मनुष्य जाति की शक्तियों को पदार्थ व आत्मा के ससार की अवाधित रूप में नष्ट करने से विमुक्त करके मनुष्य के उस व्यक्तित्व-निर्माण में सहायक होगा जो दोष जगत् के साथ भेद बैठा सकेगा। गांधीजी ने हमें जो शिक्षा प्रणाली दी उसके द्वारा भी वह यही प्राप्त करना चाहते थे। आज सामान्य-तौर से हम उन्हें भले ही अस्वीकृत कर दें लेकिन विश्वशक्तियों जल्दी ही इस प्रणाली की अनिवार्यता समझ जायगी, क्योंकि यह निश्चित ही आनेवाले बल की प्रणाली है।

मूल अंग्रेजी से,
भावानुवाद : रामभूषण

शिक्षा-सुधार की एक योजना

१ कोई भी समाज, उसकी शिक्षानीति और कार्यक्रम के माध्यम से ही अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। उसे यो भी कह सकते हैं कि शिक्षानीति और कार्यक्रम ही किसी समाज को उसका लक्ष्य प्रदान करता है। अतः शिक्षा और समाज का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानन्द जैसे कई विचारकों ने भी इसी बात पर जोर दिया है कि शिक्षा को ही सामाजिक परिवर्तन और विकास का माध्यम बनना है। आज विनोबाजी जैसे महान आचार्य भी यही कर रहे हैं। अभी गत अक्टूबर '७२ में सेबाग्राम में हुए राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में ही उन्होंने शिक्षा के तीन महान सूत्र दिये हैं। वे हैं योग, उद्योग और सहयोग। इन सूत्रों में ही सारा शिक्षा-सिद्धान्त आ जाता है। इसके आधार पर ही हम व्यक्ति-शिक्षा-समाज के सम्पर्क त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं।

२ किन्तु हमारी आज की शिक्षानीति और कार्यक्रम व तो शिक्षा के इन सूत्रों का ही पोषण कर पा रहे हैं और न हमारी राष्ट्रीय आकाशमो की ही पूर्ति कर पा रहे हैं। हमने भारत में समाजवादी समाज-रचना का संकल्प किया है किन्तु यह शिक्षा अक्षमता, शोषण और हिंसा को पोषण दे रही है। शिक्षा में आज कुछ घाटे-से विधायक मूल्य हैं भी तो हमारी राजनैतिक और आर्थिक नीतियाँ और कार्यक्रम उनके ठीक विपरीत हैं। विद्यालयों में पाठ्यक्रमों का देश की आर्थिक और राजनैतिक नीतियों तथा कार्यक्रमों से कोई विधायक सम्बन्ध नहीं रह गया है। हमको आज भी यह बात साफ नहीं हो सकी है कि विद्यालयों में पढ़ाये जानेवाले ऋषट को देश की आर्थिक और औद्योगिक कार्यनीति से मिलाकर बनाना होगा। यही कारण है कि आज हमारे विद्यालय दमन, शोषण, हिंसा और उद्देश्यहीन उत्पत्तों के स्थल बन गये हैं। छात्र, शिक्षक और समाज आमने-सामने की स्थिति में आ गये हैं और हमारे इन जीवनरुपे त्रिभुज को तीनों भुजा एक दूसरे के विपरीत जा रही है।

३ अतः उत्तरोत्तर दोनों ही दृष्टियों से आज की शिक्षा में आमूल परिवर्तन अतिरिक्त है। शिक्षा में परिवर्तन समाज में परिवर्तन के बिना सम्भव नहीं है। और ये दोनों काम हथे साथ-साथ हाथ में लेने होंगे। यही हमारा आज का

संभव होना चाहिए। इस प्रकार का एक समग्र परिवर्तन का राष्ट्रीय प्रयोग पिछले दो साल से बिहार के कुछ क्षेत्रों में आरम्भ हुआ है जिसका नेतृत्व देश के महान नेता और विचारक श्री जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं। यह प्रयोग मुजरुमपुर जिले के मुमहरी प्रखण्ड में, पूर्णिया जिले के रणौली और भवानोपुर प्रखण्ड में, तथा सहरसा जिले के कुछ हिस्सों में चल रहा है। इस प्रयोग में दो तरफा काम हो रहा है। एक तरफ तो ग्राम-समुदायों को स्वायत्त और स्वावलम्बी घरानल प्रदान कर उन्हें राष्ट्रीय एकता और विकास को बुनियादी कठिनों के रूप में संगठित करने का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी तरफ देश की शिक्षा नीति और कार्यक्रम में तदर्थ परिवर्तन के लिए परिस्थितियाँ पैदा कर शिक्षा को विधायक सामाजिक परिवर्तन और विकास का माध्यम बनाने का प्रयास हो रहा है।

४. अब यह विचार आया है कि शिक्षा में इस प्रकार की समग्र क्रान्ति के सम्बन्ध होने तक भी हम चुन न बैठें बल्कि उसके लिए आज से ही कुछ विधायक क्रिया आरम्भ करें, और यह हमारे वर्तमान शिक्षाक्रम की लेकर किया जाय। बिहार का वर्तमान माध्यमिक शिक्षाक्रम देश के कुछ उत्तम शिक्षाक्रमों में से माना जाता है। किन्तु हम इस पर भी अभी तक सही और पूरे अर्थ से अमल नहीं कर पाये हैं। यदि यह भी हो जाता तो भी शिक्षा और शिक्षकों के स्तर में काफी बड़े सुधार होने की पूरी सम्भावना है। अब यह सोचा गया है कि यह काम हाथ में लिया जाय। यह आचार्यकुल के माध्यम से चने यह भी निश्चय किया गया है, क्योंकि इसका सम्बन्ध एक व्यापक रचनात्मक सन्दर्भ से है जिस सन्दर्भ के बिना हम शिक्षा में कोई भी विधायक परिवर्तन नहीं कर सकते। हमारा आशय यह है कि आचार्यकुल में शिक्षा और समाज पर एक साथ विचार होता है और यह एक ऐसे राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का भाग है जो शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन में विश्वास करता है।

५. गत दो सालों में इन क्षेत्रों में काम करते हुए आचार्यकुल ने एक द्विविध-कार्यक्रम का विकास किया है। उसमें यही समग्र दृष्टिकोण है कि शिक्षा, शिक्षक और समाज को एक साथ ही परिवर्तन की दिशा में लगाया जाय। इस त्रिविध-कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम है आचार्यत्व-दीक्षा का कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत शिक्षकों के लिए एक आधार संहिता का विकास किया गया है। इसका दूसरा कार्यक्रम है शिक्षा में क्रांति-कार्य, जिसमें दस तरह के सुधार-कार्य भी शामिल हैं। और तीसरा कार्यक्रम है लोक-स्वराज्य की, स्थापना की, जिसमें स्वायत्तम्बी और

कार्य सम्पादित करना और इसे गाँव के विकास के साथ समन्वित करने का प्रयास करना ।

(४) छात्रों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना का विकास हो इसके लिए उन्हें फीस के बदले काम करने के लिए प्रोत्साहित करना और विद्यालयों में तदर्थ योजनाएँ बनाना और क्रियान्वित करना ।

(५) समाज सेवा और लोक-शक्ति-निर्माण की दिशा में सतत जागरूक कार्यक्रम हाथ में लेना । उसके लिए समाज-शिक्षण (रात्रि शालाएँ) की योजना चलाना । इस कार्य में छात्रों को आगे किया जाय और शिक्षक केवल उन्हें मार्गदर्शन करें । छात्रों के मूल्यांकन में उनके इस कार्य को भी शामिल किया जाय । ग्राम-सफाई और स्वच्छता के संस्कार स्थायी बनाने के लिए साप्ताहिक या मासिक अभियान चलाना, विद्यालय में और गाँव में कम्पोस्ट बनाने की योजना क्रियान्वित करना । लोक-शक्ति का जागरण और संगठन हो इसके लिए समाज में अन्याय-प्रतिकार का छात्रों को प्रशिक्षण देना, स्वयं अन्याय से विरत रहना और समाज में अन्याय के अवसर आये तो उसका निराकरण करने का प्रयास करना ।

(६) अशांति शमन के लिए सतत जागरूक रहना और अशांति के अवसर आने पर उसका निराकरण करने का सक्रिय प्रयास करना । इसके लिए विद्यालय की शांतिसेना का गठन करना ।

(७) परीक्षा-पद्धति को सतत मूल्यांकन-पद्धति में बदलने का प्रयास और क्रियान्वयन, विद्यालय के दैनिक काम में छात्रों का प्रत्यक्ष सहकार का आयोजन और क्रियान्वयन करना । इसके लिए छात्र-शिक्षक समितियों का गठन हो सकता है । सामूहिक छात्र-दुकानें भी कायम की जा सकती हैं ।

(८) लोक-शिक्षण के अन्य कार्य ।

शिक्षकों के लिए आचार संहिता

(१) विद्यालय और सामान्य जीवन में समय की पाबंदी ।

(२) निर्य नियमित स्वाध्याय ।

(३) सादगी और मिश्रव्ययिता के साथ व्यसन-मुक्ति । शराब से पूर्ण मुक्ति व कम से-कम विद्यालय में छात्रों के साथ एवं उनके माध्यम से पाव-सम्बाकू का सेवन न करना ।

(४) वर्ग-प्रेम एवं छात्रों के साथ पढ़ाई, परीक्षा तथा अन्य प्रकार की प्रामाणिकता । वात्सल्यपूर्ण वर्तन एवं सहाय्य की स्थापना का प्रयास ।

(५) पाठ की सम्यक् पूर्वं तैयारी ।

(६) विद्यालय उत्थवन और समाज सेवा का दैनिक प्रत्यक्ष कार्य ।

(७) श्रम-प्रतिष्ठा, नित्य किसी-न-किसी उदात्तक शरीर-श्रम का कार्य ।

(८) जाति, सम्प्रदाय और राजनैतिक दलबाजी से मुक्ति ।

शासन से अपेक्षा

(१) शासन इस योजना को मान्य करे और कम-से-कम एक ऐसा आदर्श विद्यालय कायम करे ।

(२) विभाग इन विद्यालयों के लिए बने स्वायत्त समितियों की सलाह पर विद्यालयों के लिए योग्य शिक्षकों को व्यवस्था करे और विना समिति की सलाह और स्वीकृति से कम-से-कम साठ साल तक उनका तबादला न करे ।

(३) यह विद्यालयों को भवन, छात्रावास और अन्य उपकरणों के लिए पर्याप्त धन दे । यह धन अनुदान या लम्बी अवधि का बिना व्याज का ऋण हो जिसकी बसुली को किस्में उधार हो । साथ ही वह साठ साल तक विद्यालयों को म० वि० को कुल व्यय का ७५ प्रतिशत और उ० वि० को कुल व्यय का ६५ से ७० प्रतिशत तक धन दे । आगामी तीन सालों में यह रकम घटकर क्रमशः ५० और २५ प्रतिशत हो जाय । दस साल के बाद शासन शिक्षकों के वेतन को छोड़कर अन्य कोई रकम विद्यालयों को न दे ।

(४) विभाग इन विद्यालयों के सामान्य निरीक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार रहे किन्तु वह हस्तक्षेपीय न होकर सलाहकार स्तर का हो । वह स्वायत्त समिति की सर्वसम्मति राय को स्वीकार और क्रियान्वित करे ।

संचालन और नियंत्रण

इस योजना का संचालन और नियंत्रण आज की सामान्य परम्परा से कुछ भिन्न होगा । वह इस तरह का ही कि ऐसे सभी विद्यालयों के संचालन और नियंत्रण के लिए शिक्षक, छात्र, शिक्षाविद, अभिभावक और शासन के प्रतिनिधियों की लेकर एक जिला स्तरीय स्वायत्त समिति बनायी जाय । इसका कोई भी सदस्य किसी भी राजनैतिक पक्ष का सदस्य न हो यह रोक रहे । शिक्षकों की समिति के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षक संघ और व्याचार्यकुल मिलकर करेगा और बाकी को सरकार नियुक्त करेगी । विभाग के लोगों का बाहुल्य न हो यह रहे । इस समिति के सभी निर्णय सर्वसम्मति या कम-से-कम ८० प्रतिशत बहुमत के आधार पर हो और इसके निर्णयों को सभी शिक्षक, विद्यालय, समाज तथा विभाग मान्य और क्रियान्वित करे । इन

स्वायत्त सामुदायिक संगठन की प्रणाली पर आधारित समाज व्यवस्था कायम करने का प्रयास हो रहा है। इस कार्यक्रम का विकास मुसहरी, हपोली और भवानीपुर तथा सहरसा में हुई अनेक चर्चा गोष्ठियों के फलस्वरूप हुआ। मुसहरी में श्री जयप्रकाश नारायण के मागदर्शन में गांधी विद्यापीठ, वेङ्गछी, गुजरात के श्री ज्योति भाई द्वारा संचालित शिक्षा-सुधार की एक योजना भी बिहार सरकार ने मान्य की है। इस योजना-संचालन में नयी तालीम के सम्पादक और केन्द्रीय आचार्यकुल के संयोजक श्री वशीधर श्रीवास्तव का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। हपोली और सहरसा में भी हम वह करने का प्रयास कर रहे हैं। हपोली में बिहार के प्रसिद्ध सर्वोदय नेता श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी ने नेतृत्व में इस पर विचार चल रहा है। सहरसा में जिला आचार्यकुल समिति ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के संयोजकत्व में एक शिक्षा सुधार उपसमिति का गठन किया है जो श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा के मार्गदर्शन में काम कर रही है। सहरसा में हमें सीमावर्ती से देश के विख्यात शिक्षा शास्त्री श्री धीरेन्द्र मजूमदार का भी मागवणन प्राप्त है और उनसे भी इस पर चर्चा हुई है। उनकी स्वीकृति इसे प्राप्त है। हमारे लिए यह भी संतोष की बात है कि इस योजना में भागलपुर मंडल के क्षेत्रीय शिक्षा-पनिदेशक श्री उमा प्रसाद सिंह भी इसमें गहरी रुचि ले रहे हैं। उन्होंने इसमें हमें कई मुख्य सुझाव दिये हैं तथा विभाग की ओर से हर तरह के सहयोग का आश्वासन भी दिया है। इसमें बिहार के एक अग्रणी शिक्षाशास्त्री खासकर बुनियादी शिक्षानीति के निर्धारक श्री द्वारिका सिंह से भी इस बारे में चर्चा हुई है और उनकी भी इसमें सहमति है। योजना संक्षेप में इस प्रकार है

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य बिहार के वर्तमान माध्यमिक शिक्षालय को आधार मानकर शिक्षा और शिक्षक के स्तर में इन प्रकार का सुधार करना है ताकि -

- (१) शिक्षा समाज के दैनिक जीवन के साथ सामुदायिक सम्बंध कायम कर सके और वह सामाजिक विकास और निर्माण की चाहिका बन सके।
- (२) शिक्षकों को ऐसा व्यावहारिक परिवेश प्राप्त हो सके ताकि वे समाज में उचित सम्मान व सुरक्षा प्राप्त कर सकें।
- (३) शिक्षा स्वायत्त हो सके।

रूपरेखा

अब तक हुई चर्चाओं के आधार पर इसकी रूपरेखा इस प्रकार है

- (१) इसके अंतर्गत आनेवाले विद्यालय आदर्श विद्यालय कहलाये जायें।

(२) ऐसे सभी विद्यालयों के लिए एक सामान्य कार्य-प्रणाली और विद्यालय योजना का एक सामान्य ढाँचा हो।

(३) ऐसे सभी विद्यालय पूर्णतः व्यावसायीक हों और यदि आरम्भ में ही यह सम्भव न हो तो कम-से-कम ३० प्रतिशत से आरम्भ कर तीसरे साल तक ७५ प्रतिशत तक पहुँचाया जाय।

(४) ऐसे सभी विद्यालय कक्षा १ से कक्षा ३ तक या कक्षा १० तक की सम्पूर्ण प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध करें।

(५) ऐसे सभी विद्यालयों के सञ्चालन और नियन्त्रण के लिए आज की परम्परागत व्यवस्था से भिन्न ऐसी व्यवस्था हो चाकि ये स्वराज्य का उपयोग कर सकें।

विद्यालय खर्च की कसौटी

(१) ऐसे सभी विद्यालय इस योजना को स्वेच्छा से स्वीकार करें।

(२) उनके शिक्षक आचार संहिता का पूर्ण पालन करते हों।

(३) विद्यालय के पास म० वि० कम से-कम १० एकड़ और उ० वि० २० एकड़ भूमि रखते हों, या प्राप्त करें।

(४) विद्यालय अपने व्यय में कम-से-कम म० वि० २० से २५ प्रतिशत और उ० वि० ३० प्रतिशत से ३५ प्रतिशत का स्वयं पैदा करें। यह सात सालों में हो। फिर आगामी तीन साल में यह प्रतिशत म० वि० को ५० और उ० वि० को ८५ प्रतिशत हो और दस साल के या वे शिक्षकों के वेतन को छोड़कर अन्य कोई रकम सरकार से न लें।

(५) विद्यालय में शिक्षा किसी उत्पादक हूनर के माध्यम से देने का प्रयास हो। यह उद्योग, खेती, पशुपालन या शहरी में कोई अन्य उद्योग हो सकता है।

विद्यालयों के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

(१) विद्यालय उन्नयन का पूर्ण प्रयास। आँगन, फूलबारी, मकान आदि की स्वच्छता और सौन्दर्य को बनाये रखने का सतत प्रयास।

(२) प्रातः सायं सर्वधर्म प्रार्थनाएँ, सत्साहित्य का वाचन, धार्मिक और सामाजिक व्यवहारों पर विद्यालय के नेतृत्व में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करना और त्योहारों को सांस्कृतिक परिवेश प्रदान करने का प्रयास करना।

(३) स्वावलम्बन की दिशा में हर सम्भव प्रयास करना। इसमें खाद, बीज आदि का उत्पादन एवं वितरण से लेकर अन्य प्रकार के विकास और उत्पादन-

समिति की प्रखण्ड स्तरीय शाखाएँ हो जो प्रखण्ड स्तर पर समिति की ओर से सामान्य देखरेख करे किन्तु विद्यालय के सामान्य काम में हस्तक्षेप न करे। यह माना जाय कि विद्यालय अपने कार्यक्रम में सामान्यतः स्वतंत्र हो किन्तु वह समिति के द्वारा दो गयी निर्देश परम्परा का पालन करे। हर विद्यालय की भी इस तरह की अपनी समिति हो और उसके सर्वसम्मति निर्णयों को ऊपर की सभी समितियाँ मान्य करें। किन्तु शिक्षकों की निष्पक्षता, विमुक्तियाँ और अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ आदि जैसी बातों में विद्यालय समिति की राय ली जाय लेकिन प्रखण्ड के लिए अंतिम निर्णय का अधिकार प्रखण्ड समिति का हो और जिले के लिए जिला समिति का। प्रखण्ड समिति के निर्णय से कोई पक्ष असन्तुष्ट हो तो जिला समिति का निर्णय अंतिम माना जाय और उसके भी निर्णय से कोई असन्तुष्ट हो तो फिर सरकार का निर्णय अंतिम माना जाय। किन्तु साथ ही जिला समितियों को यह अधिकार रहे कि वे कभी आवश्यक माने तो सर्वसम्मति या सर्वानुमति के आधार पर सरकार (केन्द्र या राज्य) के किसी भी आदेश को अमान्य कर दें।

योजना का क्रियान्वयन

इसके तीन कारण होने

(१) विद्यालय चयन करना।

(२) शिक्षकों का प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण स्थानीय ग्रामसभाओं के पदाधिकारियों या उनके प्रतिनिधियों को भी दिया जाय। अतः वे भी इसमें शामिल किये जायेंगे। ऐसे प्रशिक्षण के लिए पहले तीन से लेकर पाँच दिन का शिविर लगे और आवश्यक माना जाय तो फिर अधिक दिन के लिए भी व्यवस्था की जायेगी। शिक्षकों को ऐसे प्रशिक्षण के लिए सुविधा देने का दायित्व विभाग को होगा और ग्रामसभाओं को तैयार करने का काम सामाजिक कार्यकर्ता करेंगे। जो विद्यालय इस योजना के लिए अपनी सहमति देंगे उनके गाँवों को इसके लिए अप्रोच करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान एक विद्यालय को अन्दाष्ट विद्यालय के रूप में लेकर काम करेंगे।

(३) फिर इसे विद्यालय में लागू कर क्रियान्वित किया जायेगा।

यह सक्षिप्त योजना है। क्रियान्वयन होने के क्रम में इसमें अनेक सुधार होने की पूरी पूरी सम्भावनाएँ हैं और हमारे साक्षर को निमग्न है। शिक्षा विभाग और शिक्षण तथा समाज को मिलाकर यह साक्षर करना होगा। यह हो सभा तो हमारा पूरा विश्वास है कि हम शिक्षा को उसके वर्तमान सन्दर्भ में ही आमूल मोड़ दे सकने में समर्थ हो सकेंगे।

सहरसा जिला आचार्यकुल सम्मेलन

सहरसा जिला आचार्यकुल का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन दिनांक १३-१४ फरवरी को सुपौल (सहरसा) में सम्पन्न हुआ । सम्मेलन में जिले भर से आये हुए ५०-५५ प्रतिनिधि और इतने ही अन्य शिक्षकों ने भाग लिया । सम्मेलन का उद्घाटन और समापनवर्तन प्रसिद्ध सर्वोदय विचारक आचार्य श्री दादा धर्माधिकारी के हाथों सम्पन्न हुआ । सम्मेलन में केन्द्रीय आचार्य-कुल समिति के सदस्य श्री कामेश्वर प्र० बहुगुणा, बिहार प्रदेश आचार्यकुल के संयोजक डा० रामजी सिंह, सर्वोदय नेता श्री कृष्णराज मेहता और श्री चिरंजीव झा सदस्य सदस्य विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे । उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता सदस्य श्री चिरंजीव झा और समापन समारोह की अध्यक्षता जिला आचार्यकुल के अध्यक्ष श्री लाला सुरेंद्र प्र० ने की ।

स्वायत्त समिति की ओर से स्वागतार्थ्यता श्री गुणानन्द पाठक, प्राचार्य, विलियम बहुदेसीय उच्च विद्यालय, सुपौल से सम्मेलन में आये विशिष्ट अतिथियों और प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा, “आज ज्ञान शक्ति कुठित और तेजहीन होकर सत्ता की दासी हो गयी है । इस स्थिति में न तो लोक-तन्त्र पनप सकता है, न मनुष्य का विकास ही हो सकता है । हमारी आज की सारी समस्याओं की जड़ यह है कि हम समाज को दण्ड दान के सहारे चलाना चाहते हैं, जबकि आकांक्षाएँ स्वतन्त्रता की हैं । इस अन्तर्विरोध को विवेकपूर्ण आचरण एवं समाज रचना करके ही दूर किया जा सकता है । यह काम सत्ता ही नहीं हो सकता है । इसलिए ज्ञान शक्ति पर आस्था रखनेवाले ज्ञानी आचारवान आचार्य ही यह काम कर सकते हैं । आचार्यकुल ऐसे ही आचार्यों का एक परिवार है । इस परिवार को यह दायित्व प्रद्वन करना ही होगा कि यह ज्ञान की शाश्वत वाणी के रूप में सगठित होकर तटस्थता और निष्पक्षता से वैयक्तिक और सामाजिक मुक्ति के लिए काम करे । ”

स्वागत भाषण के बाद जिला आचार्यकुल के संयोजक डा० जयदेव ने वापिक प्रगति का विवरण देते हुए कहा, ‘यद्यपि सगठन की दिशा में हम को अभी बहुत कुछ करना बाकी है, किंतु वैचारिक दृष्टि से आचार्यकुल का

विचार सारे जिले में फैलाने में हम सफल हो सके हैं। आज हम आचार्यकुल के विचार और कार्यक्रम के बारे में काफी स्पष्ट हैं और इस जिले में ग्राम-स्वराज्य का जो राष्ट्रीय प्रयोग चल रहा है, आचार्यकुल का उसमें अपना सहयोग रहा है। आचार्यकुल ने पिछले एक डेढ़ वर्ष में एक त्रिविध-कार्यक्रम— (१) आचार्यत्व दांता (२) शिक्षा में क्रान्ति और (३) लोक स्वराज्य की स्थापना का विकास किया है। यह सतोष की बात है कि इस त्रिविध कार्यक्रम पर आचार्यकुल की अनेक जिलों में हुई गोष्ठियों में भी चर्चा हुई और सर्वत्र इस पर सहमति जाहिर की गयी। पूज्य विनोबाजी ने भी इसे सराहा है। इस कार्यक्रम पर जिला आचार्यकुल अमल करने का प्रयास कर रहा है और ग्रामस्वराज्य में सहयोग देने के साथ साथ बिहार के वर्तमान मा० पाठ्यक्रम के आधार पर एक शिक्षा-सुधार-योजना बनायी गयी है। अनेक विद्यालयों ने इसे स्वीकार किया है और अब सरकार के सहयोग से इस पर अमल करने की तैयारियाँ चल रही हैं।”

सम्मेलन में आचार्यकुल सगठन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। श्री कान्हे श्वर प्रसाद बहुगुणा और डा० रामजी सिंह दोनों ने अपने-अपने भाषणों में सगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। श्रद्धेय दादा वर्माधिकारी ने अपने दो भाषणों में मुख्य विचार की आवश्यकता बताई। सरदार सदस्य श्री चिर-जीव झा ने अपने भाषण में कहा, “आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम राजनीतिक सत्ता को नागरिक सत्ता पर हावी होने से रोकें और आचार्यकुल यह काम कर सकने में समर्थ हो।”

सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण निश्चय यह भी किया गया कि आगामी जून माह में, जब बिहार के विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश रहता है, आचार्यकुल द्वारा ग्रामस्वराज्य का एक सप्ताह अभिमान चलाया जाय। इसका प्रस्ताव गत २६ जनवरी को गया जिला आचार्यकुल सम्मेलन की ओर से आया था।

अंत में स्वागत समिति के संयोजक श्री दीनेशकुमार सिंह अधिवक्ता, सुपौल की ओर से श्री गुणानन्द पाठक ने धन्यवाद ज्ञापन किया। संयोजक कार्य व्यस्तता के कारण अपना भाषण नहीं कर पाये। इस सम्मेलन की सही व्यवस्था सुपौल प्रखण्ड आचार्यकुल समिति के मंत्री श्री चन्द्रसेखरजी के संयोजकत्व में स्थानीय शिक्षकों और नागरिकों ने मिलकर की। सम्मेलन में सुपौल अनुमण्डल के शिक्षा अधिकारी अपने सहयोगियों के साथ उपस्थित रहे। ●

२१ वाँ सर्वोदय सम्मेलन : कुरुक्षेत्र

आकलन तथा उद्योधन

[अभी हाल में ही ११ से १४ अप्रैल ७३ को सम्पन्न हुए २१ वाँ सर्वोदय सम्मेलन, कुरुक्षेत्र की एक झांकी पाठकों, विशेषतः नयी तालीम के पाठकों के लिए प्रस्तुत की जा रही है जो किसी कारणवश सम्मेलन में जा सके हो ।-सं०]

“अगर देश की प्रगति का उल्लेख हम करें तो देखने में आयेगा कि अन्तिम वर्ग को लाभ सबसे कम हुआ है। सबसे ज्यादा लाभ ऊँच वर्ग को हुआ है। जितना लाभ हुआ उससे ज्यादा लाभ छोटी छोटी योजनाओं से राष्ट्र को हो सकता था। इस मूल को नेहरूजी ने भी महसूस किया लेकिन बाद में। अगर हम इस तरह बहे कि शुद्ध से ही गांधीजी के अनुसार देहातो में उत्पादन बढ़ाने का काम हुआ होता तो आज देश का नक्शा ही कुछ दूसरा होता। इन विचारों के साथ २१ वें सर्वोदय समाज सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष श्री रामकृष्ण पाटिल ने अपना (लिखित भाषण के अतिरिक्त) अध्यक्षीय भाषण किया। यह अध्यक्षीय भाषण हुआ कुरुक्षेत्र में जो इस वर्ष सर्वोदय सम्मेलन का स्थान था। ११ वें १४ अप्रैल '७३ तक चलनेवाला यह चतुर्दिवसीय सम्मेलन हर वर्ष की ही तरह लोगों के आकषण का केंद्र रहा और देश के कोने कोने से आये प्रतिनिधियों तथा लोगों का मिलन स्थल भी। श्री पाटिल साहब ने आगे अपने भाषण में आज की नाशुक स्थिति का मूल्यांकन किया तथा लोगों को एकगुट होकर अपना कर्तव्य मनसते हुए जनसाधारण के बीच काम करने की प्रेरणा दी। सर्वोदय के पाँच महारथियों—विनोबा जयप्रकाश शंकरराव धीरेन्द्र तथा दादाधर्माधिकारी—के सम्मेलन में न आ सकने पर उन्होंने खेद भी प्रकट किया।

नवोदित हरियाणा प्रदेश की होनेवाली राजधानी कुरुक्षेत्र की अपनी खास ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं जिसकी धर्चा हम आगे करेंगे। इसी कुरुक्षेत्र में विभिन्न स्थलों से आये तथा सर्वोदय आन्दोलन में लगे करीब पाँच हजार स्त्री-पुरुषों ने एक सप्ताह तक विचार मयन किया। लोगों के सामने साल भर के काम का लेखा-जोखा तथा काम के दौरान रास्ते में आनेवाली बाधाएँ रखी गयी। आपस में एक दूसरे को देखते एवं समझने की लोगों की कोशिश रही। सभी के मन में बराबर यह प्रतीति रही कि हमारे रास्ते भले ही भिन्न

हो, पर हम सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक ही मजिल के राही हैं। अतः विचारों के उतार-चढ़ाव के बावजूद लोग सर्वसम्मति से एक निर्णय पर पहुँचे।

सम्मेलन का पहला दिन

दिनांक ११-४-७३ से १४-४-७३ तक सम्मेलन का कार्यक्रम चलाता रहा। सम्मेलन के उद्घाटन कर्त्ता ईश्वर भवत, नयन बिहीन, बाल ब्रह्मचारी, सत स्वामी शरणानन्दजी का परिचय श्री जैनेन्द्र कुमार ने दिया। वैसे ही सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष श्री आर० के० पाटिल का परिचय सुश्री निर्मला बहन ने दिया। श्री पाटिल साहब बचपन से बुद्धि के प्रसरण एवं कुशाग्र रहे हैं। आई० सी० एस० करने के बाद जिलाघाश एवं कमिश्नर रह चुके हैं। इतने बड़े गौरवपूर्ण औहदे की गाँधीजी के आवाहन पर तिलाञ्जलि देकर वह राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन में कूद पड़े। उनका पूरा जीवन सेवापरायण, सादगी एवं त्याग का है। आजादी के बाद विचार की परिपक्वता देखकर तत्कालीन प्रधान मंत्री प० जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में उन्हें योजना आयोग का सदस्य बनाया। वहाँ तब राजनीति में रहने के बाद भी राजनीति के दलदल से बेदाग निकल कर पाटिल साहब सर्वोदय आन्दोलन में जुटे हुए हैं। ऐसी बेदाग तथा ऊँची जिन्दगी कितनी की है ?

दूसरा दिन : समस्याएँ

दिनांक १२-४-७३ को हरिजन समस्या पर श्री जीवनलालजी ने अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "आज भारत में ९ करोड़ हरिजन हैं। अगर ये किसी खास जगह पर होते तो इनकी सख्या दुनिया के ७ वें देश में होती। लेकिन पूरे देश में ये इस बँदर बिखरे हुए हैं जैसे इनकी कोई सख्या ही न हो। यही कारण है कि इनका सामाजिक तथा शैक्षणिक विकास जिस अनुपात में होना चाहिए नहीं हो रहा है। शैक्षिक आँकड़ों की तरफ ध्यान खींचते हुए उन्होंने बताया कि १९४७ में हरिजन विद्यापियों की सख्या कालेजी में १६ हजार थी, आज २५ लाख है। इनकी समस्या सिर्फ नौकरियों में कुछ प्रतिशत स्थान आरक्षित कर देने मात्र से हल नहीं होगी, इनकी गरीबी तथा अस्पृश्यता पर ध्यान देते हुए कोई दूसरा रास्ता ढूँढना होगा।"

इसी तरह श्री चिन्तामणिजी ने भगी-भुक्ति के प्रति अपनी वेदना एवं बेचैनी प्रकट करते हुए हरिजनों को समाज में स्थान तथा उनका अधिकार दिलाने का सवान पेश किया। उनका कहना था कि भगी-नार्य में कुछ सुधार कर देने

मात्र से ही हरिजनो की समस्या नहीं सुलझ जायेगी। इसके लिए उन्हें समाज में आदमी का दर्जा देना होगा।

नशाबन्दी समस्या पर बोलते हुए डा० सुशीला नंयर ने सर्वोदय-कार्य में लगे साधियों का ध्यान इस जागतिक समस्या की ओर आकृष्ट किया और कहा कि जब तक हम सर्वोदय कार्यकर्ता अपना-अपना राग अलग-अलग बनापते रहेंगे, अपनी-अपनी खिन्नी अलग-अलग फँकाते रहेंगे तब तक यह ज्वलंत समस्या असंगठित शक्ति से हल नहीं होगी। इसके लिए संगठित अहिंसक शक्ति चाहिए जो इसका मुकाबला खटकर कर सके।

पूर्वाह्न के बाद पूर्ण रोजगारी पर अपना विचार व्यक्त करते हुए श्री श्रीमन्नारायण ने कहा कि आज देश में ३ करोड़ हरिजन तथा आदिवासी ऐसे हैं जो बिनकुल बेतार हैं। देश की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना बन रही है। इसमें ऐसा विधान किया जा रहा है कि जो काम चाहेगा उसे सबसे पहले काम दिया जायगा। देश भर में फैनी मारी रचनात्मक संस्थाओं को चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास कोई काम न हो उसे कम से-कम दो तफुएँ का चरखा दिया जाय। चरखा एक ऐसा साधन है जिससे आदमी भूखा नहीं मर सकता। भारतीय सर्व-व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि है। अतः कृषि में अधिराशि सुधार लाकर अनाज उत्पान मात्र में वृद्धि करनी होगी।

तीसरा दिन : ग्रामस्वराज्य

सम्मेलन के तीसरे दिन १३-४-७३ को ग्रामस्वराज्य विषय पर देश के कोने-कोने में ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य आन्दोलन में कार्य कर रहे साधियों ने अपनी प्रगति एवं रास्ते में आ रही रुकावटों का ब्योरा दिया। अन्त में ग्रामस्वराज्य समिति के अध्यक्ष आचार्य रामभूति ने इस विषय पर उठाये गये प्रश्नों एवं प्राप्ति-मुष्टि में आ रही कठिनाइयों का सरल तरीके से समाधान किया। उन्होंने कहा कि आज देश के ३१ क्षेत्रों में ग्रामदान का कार्य हो रहा है। इनमें अभी सक्रिय भी नहीं हैं। अगर हम संपान पैदा करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो क्रान्ति नहीं आयेगी। आज हम वास्तविकता से हट गये हैं। कुछ मित्रों के सुपाओं का सफ़ा करना करते हुए उन्होंने कहा कि मिफं राजनीति में प्रवेश करने मात्र से ही हमारे आन्दोलन पर प्रभाव नहीं होगा। इसके लिए जनता की संगठित एवं सत्पात्र शक्ति को विकसित करना होगा। २२ वर्ष पहले हमने चौसरी राह पर चलने का, तीसरी शक्ति पैदा करने का तय किया। वहाँ है

वह तीसरी शक्ति ? तीसरी शक्ति का मतलब है लोक-शक्ति का निर्माण । पर अभी तक हम इस काम में सफल नहीं हो सके । हमारी क्रान्ति में तेज आवे इसके लिए आवश्यक है हम अपने सामने का चित्र, एक निश्चित उद्देश्य सामने रखें । तभी क्रान्ति होगी । ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य को गति देने के लिए हमारा विचार-प्रचार हो । आम लोगों की रूढ़िवादी धारणा को बदल कर लोक-शक्ति विकसित करने की आवश्यकता है । इसके लिए आवश्यक है हमारा साहस रावल, सरल और सस्ता हो ।

११ अप्रैल को रात्रि में भोजनोपरान्त आचार्यकुल में रुचि रखनेवाले मित्रों की एक अनौपचारिक बैठक कानपुर विश्वविद्यालय के भू० पू० कुलपति श्री राधा-कृष्ण अप्पवाल की अध्यक्षता में हुई जिसमें ३९ साथियों ने भाग लिया । केन्द्रीय आचार्यकुल समिति के सयोजक श्री बशीधर श्रीवास्तव अपनी अस्वस्थता एवं बड़े लड़के की बीमारी के कारण सम्मेलन में उपस्थित न हो सके । अबतक देश के भीतर ११ प्रदेशों में हुए आचार्यकुल का संगठन भाषा सर्व सेवा संघ की मदद तथा सयोजक श्रीबशीधर श्रीवास्तव के पुरोधार्य एवं प्रयासों की परिणति है ।

बैठक में अब तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए विभिन्न सदस्यों ने भागे के लिए कई सुझाव दिये जिनमें कुछ मुख्य ये हैं :

(१) सभी प्रदेश सर्वोदय मंडल आचार्यकुल को अपने कार्य का अंग मानकर इसमें रुचि लेनेवाले शिक्षकों से सम्पर्क एवं उन्हें संगठित करें । (२) आचार्यकुल को गति देने के लिए नागरी लिपि की सक्रिय बनाया जाय । (३) आचार्यकुल सर्वोदय आन्दोलन में भाग लेने या न लेने के लिए स्वतंत्र है । इसका कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक तथा सामाजिक विषयों पर तटस्थ राय व्यक्त करना है । (४) आचार्यकुल चुनाव में भाग ले या न ले यह स्वयं तय करे । (५) आचार्यकुल अपने दैनिक जीवन में न्यूनतम व निश्चित कोई काम अवश्य करे । (६) वही आवश्यक हो एवं सुविधा हो तो आचार्यकुल शिक्षा के नये प्रयोग एवं क्षेत्र भी कायम कर सकता है ।

शांतिसेना रैली इस बार के सम्मेलन में लोगों के लिए आकर्षण रही । वेतरिया रमान बांधे हजारों लोगों की कमबद्ध गंकिनियाँ ध्यान तो आकर्षित करती ही थीं, शांतिसेना के प्रति लोगों की बढ़ती निष्ठा की परिचायक भी थी ।

महिला सम्मेलन इस बार के सम्मेलन का एक प्रमुख अंग था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की उड़ीमा की प्रमुख समाजसेवी महिला श्रीमती रमा-देवी ने। गुजरात के भूतपूर्व राज्यपाल श्री श्रीमन्नारायण की पत्नी श्रीमती मदालसा नारायण ने अपने सारगर्भित भाषण में नारी-जागृति की महत्ता पर प्रकाश डाला और स्त्रियों को सर्वोदय क्रान्ति के लिए आह्वान किया। गांधीजी ने आजादी की लड़ाई के माध्यम से स्त्रियों की स्वतंत्रता और उनकी जागृति का द्वार खोल दिया था। सर्वोदय आन्दोलन भी स्त्री-शक्ति में पूर्ण विकास की तरफ सतत सचेष्ट है। विनोबाजी की नारी को विधायिका शक्ति में बड़ी श्रद्धा है।

सर्वोदय सम्मेलन में जनता के लिए सर्वाधिक आर्पण का केन्द्र रही खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी। हाथ एवं बुटोर उद्योग द्वारा वेग की गरीबी तथा बेकारी का काफी सीमा तक निराकरण और आजादी के पचीस वर्षों में हरियाणा राज्य की प्रगति के कीर्तिमान प्रदर्शनी, ये दो प्रमुख प्रतिपाद्य थे। रात्रि को प्रदर्शित होनेवाली सिनेमा स्लाइड संगो का आकर्षण और भी बड़ा देती थी। ये सभी चीजें एक सप्ताह तक कुश्नोद के अपेक्षाकृत शान्त जीवन को बहल-पहल से भरे रही।

चौथा दिन : सामयिक प्रश्न

सम्मेलन के अन्तिम दिन १४-४-७३ को चार विषय लिये गये। नागरील्लिपि, तरुण-शांतिसेना, गीताई मिशन तथा आध्र की समस्या। समय के अभाव के कारण इन विषयों पर बक्तारों ने अपना विचार संक्षेप में रखा। श्रीकृष्णराज भाई ने आगे सम्मेलन का स्वरूप बँसा हो, दिखाया हो, इनको सरस ढंग से श्रोताओं के सामने रखा।

अन्त में सर्वोदय साधियों को सदेश देते हुए सुश्री निर्मला बहन ने कहा कि हम एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति और बिखरी हुई शक्ति को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह गंगा की धारा में पाँच सौ नदियाँ आकर मिलती हैं उसी तरह सर्वोदय विचारधारा में अन्य विचार मिलते जा रहे हैं। लेकिन सागर तक जाने में गंगा की जो धारा है—ग्रामस्वराज्य की धारा—उसे हमें नाफी मजबूत बना कर आगे की दिशा में ले जाना होगा। ग्रामस्वराज्य जनता एवं बुद्धिजीवियों का विचार बने यह हमारी आवश्यकता होनी चाहिए।

आन्दोलन की प्राप्ति, उसकी दिशा

दो शब्द, सर्वोदय आन्दोलन की प्राप्ति और उसकी दिशा के सम्बन्ध में। यों सरसरी तौर पर देखा जाए तो साफ है आन्दोलन का जनजीवन पर कोई

व्यापक असर नहीं हुआ है। ग्रामस्वराज्य आन्दोलन के चरण बढ जलर रहे हैं लेकिन देश सर्वोदय से उल्टी दिशा में भी उसी तरह तेजी से बढ रहा है। देश में सिर्फ हिंसा में ही वृद्धि नहा हुई है बल्कि हिंसा में आस्था में भी वृद्धि हुई है। आर्थिक और जिन चीजों में वृद्धि हुई वे है आर्थिक विपमता महिलाओं आदिवासियों तथा हरिजनों की दुदशा भ्रष्टाचार बेकारी पश्चिम का अधा सुकरण और राजनीतिक आकांक्षा। इसके लिए हमें अपनी स्ट्रैटजी में जो परिवर्तन करना हो हम कर। जनता में यह भावना बढ रही है कि आज की शक्तियों के पास अब उसकी मूल समस्याओं का समाध न नहीं है। जनता की इस भावना को और विस्तृत कर हम सर्वोन्म विचार को अधिकाधिक ग्राह्य बना सकते हैं। इसके लिए विचार तथा भावनाशील—थोड ही सही किंतु हठमती साधियों की जरूरत है। जब तक यह नहा होता है तब तक सर्वोन्म आन्दोलन व्यापक घरातल पर नहा आ सकेगा।

सम्मेलन में आये अय राज्या की अपक्षा हरियाणा प्रदेश के भाई बहनों की सत्ता ज्यादा रही। स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री बनारसीदास गुप्ता तथा मंत्री श्री सामभाई के जवन परियम से पाँच हजार लोगों के रहने खाने-पीने गहाने घोंने तथा गीच आदि की व्यवस्था बडी ही व्यवस्थित ढग से की गयी था। प्रदेश भर की विभिन्न रचना मय एव सर्वोन्म विचार में आस्था रखने वाली गैलिन-रास्याभा के स्त्री पुरुष वायवर्ताओं ने बाहर से आये भतिषियों की और इस तरह वे सबके भद्धा के पास बने। रात दिन एक्जुट होकर भोजन नाश्ता तथा समा स्थन में पूरी व्यवस्था रख इन लोगों ने अपनी वाय बुशानता का परिचय दिया।

सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

बुद्धधर्म का हम जब एतिहासिक एव सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो लगता है यह नवनिर्मित प्रदेश हरियाणा देश के सांस्कृतिक धर्म में अपना प्रमुख स्थान रखता है। यह प्रदेश आरम्भ से ही भारतीय संस्कृति का आदि स्रोत रहा है। हरियाणा शब्द का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रन्थों तथा शिला लेखों में मिलता है। इस ग्रन्थ के नती नाना पवलो तथा भूखण्डातक के नाम भी वैदिक शब्दों के आधार पर रखे गये प्रतीत होते हैं। इस पवित्र भूमि पर ही सरस्वती के तट पर ऋषियों ने वैदिक ऋचाओं का गान किया। यह प्रदेश वीर योद्धाओं की जननी रही है। वीर हेमू वीर चूडामणि नाहर सिंह तथा राववृष्ण गोसले भाति महान योद्धाओं का नाम स्वर्ण अंगारों में लिखा जायेगा।

गीता जैसी अमर ग्रंथ की रचना यही हुई। इसी अमर ग्रंथ में भगवान् कृष्ण ने जीवन का मर्म समझाया है। कर्म में लगने के गीता के उसी प्राचीन उपदेश की आज नये परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है। यही धानेश्वर में १३ सौ वर्ष पूर्ण सम्राट् हर्षवर्द्धन ने अपना गौरवमय साम्राज्य स्थापित किया था। यही पर महाकवि बाणभट्ट ने वादम्बरी की रचना की। पानीपत का वह ऐतिहासिक मैदान यही है जहाँ एक बार नही तीन-तीन बार भारत के भाग्य का फैसला हुआ है।

कुरुक्षेत्र में आप आज भी जाइए तो वहाँ आपको हरियाणु जीवन की पूरी झलक मिल जायेगी। कुरुक्षेत्र शहर में सिक्ख तथा गुजर जाति के लोगों की प्रधानता है। दोनों जातियों के लोग काफी मेहनती, बलवान्, कर्मठ एवं पुरुषार्थी होते हैं। इनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है। नये तरीके की खेती, नये वैज्ञानिक औजार, रासायनिक खाद का सतुलित रूप में प्रयोग, ये अच्छी तरह करते हैं। कुरुक्षेत्र के गाँवों में शायद ही कोई ऐसा दरवाजा मिलता था जहाँ ट्रेंक्टर या बूमर न हो। खेतों में गेहूँ की फसल के टाक लगे हुए दिखे। यहाँ की मुख्य फसल गेहूँ तथा उरद है। यहाँ के पशु, खासकर गाय तथा बैल तो भारत में अपनी अच्छी नस्ल के लिए मशहूर हैं। कुरुक्षेत्र निवासी अपनी सत्कृति के प्रति बड़े कट्टर होते हैं। अभी इनके रहन-सहन, इनकी पोगाक पर अन्य लोगों की छाप नहीं पड़ी है।

सर्वोदय सम्मेलन मंच की हरियाणा के लोगों ने जैसी साज-सज्जा की थी वह उनकी सत्कृति का ही प्रतीक थी। एक मीटर ऊँच, दस मीटर लम्बे, ६ मीटर चौड़े मंच की चारों तरफ नक्काशी तथा फूल-पत्तियों को देखकर हरियाणा की सदिया। पुरानी सत्कृति एवं कला की वरवस याद आ जाती थी। मंच पर चढ़ने के लिए तीन तरफ से दो-दो सीढ़ियाँ बनी थी। सीढ़ी के दोनों तरफ कला से ओतप्रोत सुन्दर तथा आवर्णित कर लेनेवाले घड़ों की सजावट थी। मंच के अगले हिस्से के ठीक बीचों-बीच थी आर० के० पाटिल की मेढ़ थी। मंच के पिछले हिस्से पर सर्वोदय विचार माननेवाले, राजनीतिक तथा स्थानीय प्रतिष्ठित परिवारों के लोग बैठे थे। मंच के पीछे दीवाल पर टंगे गाड़ी, विनोबा तथा बुद्ध की तस्वीरों के नीचे प्रेरणादायी सुभाषित एवं बड़े-बड़े अक्षरों में सूक्तियाँ लिखी हुई थी।

आगे की दृष्टि

कुरुक्षेत्र की भावी योजना भी अपने आप में अनोखी योजना है। हर गाँव

मे विजली, पक्की सड़क, सिंचाई के लिए नदी-तालाब पूर्ति की योजना चल रही है। अभी-अभी रोहतक से २ हजार किलो मीटर लम्बी नहर निकालने की योजना बनी है, जो हरियाणा की सूखी करीब ढाई लाख एकड़ भूमि को सिंचाई करेगी। विजली तो हरियाणा के हर गांव तक पहुँच ही गयी है। खास कुरुक्षेत्र में ही जल परियोजनार्थ करोड़ों रुपये की लागत से एक बहुत बड़े तालाब का निर्माण हो रहा है।

बशीराल सरकार के प्रति लोगों की कोई खास आलोचना या दिष्णो सुनने को नहीं मिली। अब जब चंडीगढ़ को नये राज्य हरियाणा की राजधानी बनाने में हरियाणावासी सफल नहीं हुए, तब कुरुक्षेत्र को ही उन्होंने हरियाणा की राजधानी बनाने का तय किया है। ऐसा निर्णय होते ही सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र में ६ शराब की दूकानों को साइसेन्स मिल गया जिसमें तीन दूकानें खुल भी गयी। इस पवित्र भूमि में शराब का व्यापार हो और सरकारी आमदनी हेतु लोगों को शराब का आदी बनाया जाय, यह कुरुक्षेत्रवासियों के लिए असहनीय है। इसकी प्रतिक्रिया युवा वर्ग से लेकर बुजुर्गों तक में सुनने को मिली।

कुरुक्षेत्र में दो कुण्ड हैं। एक सूर्य कुण्ड तथा दूसरा वाणगंगा। हर पूर्णिमा को सूर्य कुण्ड में स्नान करनेवालों की संख्या हजारों में होती है। राज्य भर से स्त्री-पुरुष-बच्चे ट्रक, बस, जीप तथा अन्य सवारियों में स्नान करने प्रचापच भरे आते हैं। सड़क के किनारे मेसा लग जाता है। सूर्य कुण्ड की खास विशेषता यह है कि उसमें एक करोड़ पन्नी पर रामनाम लिखकर डाला गया है। उसी तरह वाणगंगा उस समय की याद दिलाती है जब शरद्व्या पर सोये भीष्मपितामह की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने तीर द्वारा पाताल से पानी खींचा था। कुरुक्षेत्र में रेगिस्तान की झलक भी मिलती है पर अब सिंचाई योजना के दौरान सारी ऊसर भूमि को ऊर्वर बना दिया गया है।

सामान्य लोगों पर सम्मेलन का कोई खास असर पड़ा हो ऐसा महसूस नहीं हुआ। सम्मेलन के प्रति सामान्य लोगों में उदासिनता ही दिखी। लेकिन कुछ युवा मित्रों से चर्चा के दौरान यह जाभास हुआ कि उनका मानस सर्वोदय की ओर झुका है। अच्छे वक्ताओं के भाषण भी अच्छे लगे। जब कुछ युवा मित्रों के सामने ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य की तसवीर रखी गयी तो उनका उत्साह और आगे बढ़ता मालूम हुआ। उन्होंने सर्वोदय आन्दोलन में हिस्सा लेने तथा सम्पर्क बनाये रखने की अपनी इच्छा भी बाहिर की।

अगला सर्वोदय समाज सम्मेलन पश्चिम बंगाल सर्वोदय मंडल के साथियों के अनुरोध पर पश्चिम बंगाल में, गुरुदेव रवीन्द्र के आश्रम, शांति निवेदन में होने का तय हुआ। सम्मेलन में आये लोक सेवना तथा प्रतिनिधियों की अल्प संख्या एवं समापन के पूर्व ही लोगों के भागने पर रोक लगाने हेतु यह निर्णय लिया गया कि सम्मेलन में आने पर प्रवेश पत्र के साथ वापसी टिकट भी जमा करा दिया जायेगा ताकि सम्मेलन से पूर्व कोई न जाय।

प्रतीति जग चुकी है

आज देश जिस विषम परिस्थिति से गुजर रहा है उसके लिए लाजिमी है कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागकर राष्ट्रहित की भावना का विकास करें। आज देश की सबसे बड़ी ज्वलत समस्या सूखे की है। हमारी अधिक-से-अधिक मदद सूखा पीड़ितों को मिल सके ऐसा प्रयास हम करें। सर्वोदय सम्मेलन के पूरे वातावरण में यह भावना बराबर गूँजती रही।

आज दुनिया के किसी भी राष्ट्र में चाहे वह साम्यवादी हो या समाजवादी — जनता का सर्वांगीण विकास इदापि सम्भव नहीं। सर्वोदय ही एक ऐसा विनल्प है जिनमें छोटे-बड़ा धनी-गरीब छूत-अछूत आदि का भेदभाव मिटा कर एक आदर्श परिवार, समाज तथा राष्ट्र की स्थापना हो सकती है। भले ही आज की परिस्थिति में सर्वोदय की महत्ता को लोग अंगीकार नहीं करें लेकिन आने वाले दिनों में सर्वोदय ही एक ऐसा विचार है जो टिक पायेगा। जैसे गांधी को जीनेकी मनकी ही समझा गया लेकिन आज सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में गांधी-विचार के प्रति लोगों की रसान बढ रही है। इस अनुभूति की शलक सम्मेलन में आई भीठ के किमी-न- किस्ती भाग में मिल ही जाती थी कि आनेवाले दिनों में जनता की रुचि सर्वोदय आन्दोलन की तरफ ही होगी। मनुष्य की बढती महत्वाकांक्षा का जीवन की परिस्थिति से मेन बैठानेवाला आज सर्वोदय से बढकर अन्य कोई विचार नहीं है। प्रश्न है आज की परिस्थिति में सम्मिलित और अथक प्रयास की। कुदधन सर्वोदय सम्मेलन लोगा में यह प्रतीति जगा सका है ऐसी आशा है। ●

सम्पादक मण्डल :

श्री धीरेन्द्र मजूमदार : प्रधान सम्पादक

श्री यशोधर श्रीवास्तव

आचार्य राममूर्ति

वर्ष २१

अंक ९

मूल्य ७० पैसे

अनुक्रम

सोवियत रूस के विद्यार्थी	३८५ सम्पादकीय
शिक्षा का सरकारीकरण	३८९ दादाधर्माधिकारी
शिक्षा समस्या	३९५ विनोबा
युनियावी शिक्षा—आनेवाले कल की	
शिक्षा पद्धति	४०० डा० डी० एन० कौल
शिक्षा-सुधार की एक योजना	४१४ कामेश्वर प्र० बहुगुणा
राहरसा गिला आचार्यकुल सम्मेलन	४२१
२१ वाँ सर्वोदय सम्मेलन कुरुक्षेत्र	४२३ श्रीनाथ सहाय

अप्रैल, '७३

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक खर्चा आठ रुपये हैं और एक अंक के ७० पैसे।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री श्रीगुरुदेवस्य मठ, द्वारा सय सेवा सय के लिए प्रकाशित
बनोहर प्रेस, जलमबर, वाराणसी में मुद्रित

सम्पादक मण्डल :

श्री धीरेन्द्र मजूमदार : प्रधान सम्पादक

श्री यशोधर श्रीवास्तव

आचार्य राममूर्ति

वर्ष : २१

अंक ९

मूल्य : ७० पैसे

अनुक्रम

सोवियत रूस के विद्यार्थी	३८५ सम्पादकीय
शिक्षा का सरकारीकरण	३८९ दादाधर्माधिकारी
शिक्षा-समस्या	३९५ विनोबा
बुनियादी शिक्षा—आनेवाले कल की	
शिक्षा-पद्धति	४०० डा० डी० एन० कील
शिक्षा-सुधार की एक योजना	४१४ कामेश्वर प्र० बहुगुणा
सहरसा जिला आचार्यकुल सम्मेलन	४२१
२१ वाँ सर्वोदय सम्मेलन कुतुबेन	४२३ धत्रीनाथ सहाय

अप्रैल, '७३

- 'नयी सालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- 'नयी सालीम' का वार्षिक चन्द्रा आठ रुपये हैं और एक अंक के ७० पैसे।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक संख्या का जल्दसे अवश्य करें।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों को पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट, द्वारा सर्व सेवा सघ के लिए प्रकाशित,
मनोहर प्रेस, जतनबर, यादगढी में मुद्रित

नयी तालीम

वर्ष : २१

अंक : १०

महाराष्ट्र एवं बिहार
आचार्यकुल
सम्मेलन विशेषांक

मई १९७३

यह आचार्यकुल विशेषांक

विगत चार वर्षों में आचार्यकुल आन्दोलन की इतनी प्रगति हुई है कि शिक्षा सत्र १९७२-७३ में तीन प्रदेशों में—मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में, प्रादेशिक स्तर के सम्मेलन हुए हैं। प्रादेशिक स्तर के सम्मेलन अर्थात् ऐसे सम्मेलन जिनमें प्रदेश के अधिकांश जिले अथवा सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया हो। महाराष्ट्र सम्मेलन हुआ तो उसमें महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले से कुल मिलाकर ३६५ प्रतिनिधि सदस्य आये और बिहार तथा मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों से कुल मिलाकर क्रमशः १५० और २०० प्रतिनिधि आये। मतलब यह कि आचार्यकुल की निष्ठाओं में विश्वास रखनेवाले और उसकी शिक्षा-नीति में रुचि रखनेवाले शिक्षकों की एक विरादरी बनी है। ऐसे लोग साथ मिलकर बैठे हैं, अपने लिए आधार सहित बनायी है, और शिक्षा की समस्याओं पर धितन मनन कर यह विचार किया है कि शिक्षा वारक शक्ति कैसे बने।

आज शिक्षा जगत की सबसे बड़ी समस्या है—शिक्षा की स्वायत्तता। आचार्यकुल मानता है कि लोकसत्र में शिक्षा को सरकार मुक्त होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो दलीय लोकसत्र में जिस दल की सरकार होगी वह शिक्षा का अपने दल की नीति सिखाने का माध्यम बनावेगा और शिक्षा इन्डाक्ट्रिनेशन का जरिया बनेगा, जो लोकसत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। लेकिन स्वातन्त्र्योत्तर काल में शिक्षा के सरकारीकरण की

वर्ष : २१

अंक : १०

मोंग बढ़ी है और स्वयं शिक्षक-संगठनों ने शिक्षा के सरकारीकरण की मोंग की है, उसके लिए आंदोलन भी किये हैं। कई प्रदेशों में उच्च शिक्षा को सरकार के प्रतिबन्धों से अधिकाधिक जकड़ने की चेष्टा हो रही है। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। आचार्यकुल ने शिक्षा की स्वायत्तता, उसके स्वरूप, व्यवहार और उसकी मर्यादा पर विचार किया है। महाराष्ट्र और बिहार दोनों ही सम्मेलनों में इस पर लाभप्रद चर्चाएँ हुई हैं।

इसी प्रकार यह अनुभव किया गया है कि देश की शिक्षा में अगर क्रांति नहीं हुई, और शिक्षा देशवासियों और विकास के साथ न जुड़ो, तो देश की किसी भी समस्या का हल नहीं होगा। शिक्षा की क्रांति का सबसे महत्त्वपूर्ण घटक है—शिक्षक। जब तक शिक्षक योग्य और अच्छा नहीं बनता, तब तक शिक्षा की कोई क्रांतिकारी योजना सफल नहीं होगी। आज के शिक्षक में बड़ी कमजोरियाँ हैं। वे कैसे दूर होंगी इस विषय पर भी चिंतन मनन हुआ है। और, इसके लिए बिहार आचार्यकुल सम्मेलन में शिक्षकों की एक आचार-सहिता भी बनी है।

यह सयोग ही कहा जायगा कि बिहार और महाराष्ट्र के दोनों ही आचार्यकुल सम्मेलन का उद्घाटन प्रसिद्ध सर्वोदय विचारक पू० दादा धर्माधिकारी द्वारा हुआ। दादा के विचार मौलिक होते हैं और उनको प्रकट करने की शैली उत्तेजक होती है। उनका मार्गदर्शन आचार्यकुल का सौभाग्य है। अपने भाषणों में आज की शिक्षा की अनेक समस्याओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है। महाराष्ट्र आचार्यकुल सम्मेलन में पू० विनोबाजी का मार्गदर्शन और प्रसिद्ध सर्वोदय नेता आचार्य राममूर्तिजी का सहयोग प्राप्त हुआ। (उनके भाषण को हम मार्च के अंक में प्रकाशित कर चुके हैं।) महाराष्ट्र सम्मेलन को गुनराव के उपकुलपति और साहित्यिक श्रो उमाशंकर जोशी का भी सहयोग प्राप्त हुआ।

ये सम्मेलन आचार्यकुल आंदोलन की प्रगति की दृष्टि से नहीं, आज की शिक्षा-जगत की समस्याओं की दृष्टि से भी इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि हम चाहते हैं कि नयी तालीम के पाठक इन सम्मेलनों की चर्चाओं से लाभान्वित हों। यही कारण है यह विशेषांक निकालने का।

—बघोघर धोबास्तव

महाराष्ट्र आचार्यकुल सम्मेलन

उद्घाटन भाषण

शिक्षा और शिक्षक कैसे हों ?

दादा धर्माधिकारी

[आचार्य दादा धर्माधिकारी ने महाराष्ट्र आचार्यकुल सम्मेलन के अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में जो विचार व्यक्त किये वह आज की परिस्थिति में शिक्षण, शिक्षक तथा शिक्षार्थी—तीनों के लिए एक नया मागदर्शन है। आशा है नयी तालीम के पाठक इससे ज्यादा लाभान्वित होंगे। —सम्पादक]

शिक्षक का कर्तव्य

आरको थी उमाशकर भाई जैसे विद्वत्ता भाषना सत्ता आदि विविध अधिकारी से सम्पन्न अध्यक्ष मिले हैं। साहित्य, शिक्षा और अब छहर राजनीति—इन तीनों क्षेत्रों में उनका प्रवेश है। मैं सब ओर से निवृत्त हो गया हूँ ओर मुझे सूझ में आने की सुविधा नहीं है। अतएव मुझे जो कुछ कहना है वह संक्षेप में कहनेवाला हूँ। आरम्भ में करनेवाला हूँ शिक्षक के शीर्ष से। पहली बात आपसे मुझे यह बहनी है कि नया समाज और नया मानव निर्माण करने

की आसुरी महत्वाकांक्षा आप न रखें। यह भगवान का काम है और भगवान के काम को जो भगवान से छीन लेता है उसका नाम शैतान है। विश्वामित्र ने यह बेकार का श्रम करके देख लिया। फजीहत हो गयी उसकी। अरे भगवान के बनाये हुए हम मनुष्य कैसे हैं यह आइने में देखो तो। और हम शिक्षक जब मनुष्यों का निर्माण करने लगे तब उनकी क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना कीजिए। मैं तो कल्पना तक नहीं कर सकता। अब शिक्षक को पहली बात यह ध्यान में रखनी है कि जगत में उत्पन्न होनेवाला प्रत्येक बालक द्वितीय होता है वह एक विभूति है। उसको गढ़नेवाले हम नहीं हैं। उस विभूति के विकास में जो बाधाएँ हमारे सत्कारों की हमारी सामाजिक परिस्थिति की आती हैं उन्हें दूर करना और उसके विकास का अवसर प्रदान करना ही शिक्षक का कर्तव्य है।

शासन का हास

दूसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि जैसे-जैसे शिक्षण का विकास होगा वैसे-वैसे शासन का हास होना चाहिए। जहाँ शिक्षण होता है वहाँ शासन नहीं हो सकता। शासन सर्वाधिक हो जाय तो शिक्षण समाप्त हो जायेगा। इतना ही नहीं इस विश्व में चम्पाभर जगह भी शिक्षण के लिए नहीं मिलेगी। लड़के का और शिक्षक का—दोनों का कर्तव्य एक ही है। कहीं भी उसकी बुद्धि बधक नहीं रहनी चाहिए। गुप्त प्रथम संस्था समाज राष्ट्र वहीं भी शिक्षक की सुबुद्धि बधक नहीं रहेगी। कहीं भी वह कुठिन नहीं होगी। बौद्धिक स्वतंत्रता शिक्षक का बाना है और बुद्धि की शक्ति उपकरण शस्त्र सम्पत्ति और सत्ता की अपेक्षा सौगुनी अधिक है। इस पर उसकी श्रद्धा चाहिए।

शिक्षक का मिशन नहीं

तीसरी बात यह है कि शिक्षक को उपदेशक अथवा प्रचारक नहा होना चाहिए। उसका कोई मिशन नहीं है। उसका कोई संदेश नहा होना चाहिए और उसे अपने व्यक्तित्व का कोई संदेश विद्यार्थियों तक पहुँचाने का आकांक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। यह आसुरी आकांक्षा है। शिक्षकों को सत्यनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता के आधार पर सत्य का शोध यह उसका प्रयोग है और इसीलिए वह विद्यार्थियों का सहपाठी है।

समान शिक्षण

स्वायत्त शिक्षण के विषय में मुझे एक छोटी-सी बात आपसे कहनी है। सरकार नियंत्रित शिक्षण न हो लेकिन वह राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। भारत

आपी ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी। इसलिए उसमें एक समानत्व की पैठ होनी चाहिए। असम से लेकर गुजरात-छोटाछाड़ तक और कश्मीर से बंगाल-कुमारी तक प्रत्येक विद्यार्थी को समान शिक्षण मिलना चाहिए। विशिष्ट शिक्षण अलग, सामान्य शिक्षण समान होना चाहिए, तभी वह सार्वजनिक हो सकेगा। इसे कौन साकार करेगा? इसका विचार हमें करना है। यह मैं कह नहीं सकता। सरकार को अगर यह नहीं करना है तो किसी को यह तय करना होगा। डेड-महार लडके-नटकी को और ब्राह्मण के नटकी को मराठी, कन्नड बोलनेवाले लडके को एक ही शिक्षण, समान सामान्य शिक्षण मिलना चाहिए, यह एक सार्वजनिक नीति तय करना अत्यंत आवश्यक है। न्याय-विभाग की तरह शिक्षण-विभाग को भी स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा मैं समझता हूँ। न्याय-विभाग जिन कानूनों को कार्यान्वित करता है वे सार्वजनिक होते हैं। इसी तरह शिक्षण की नीति सार्वजनिक होनी चाहिए। शिक्षण को इन्डाकिन्वैशन का, अपने विचारों को विद्यार्थियों के दिमाग में दूंसने का अथवा किसी भी सरकार के प्रचार का साधन नहीं बनना चाहिए। इसलिए जब हम कहते हैं कि सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, तब इसका अर्थ यह है कि यह शिक्षण सत्ता समान रूप से बराबर मिलना चाहिए। यदि यह बात हम ध्यान में नहीं रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में साम्प्रदायिक शिक्षण तेजी से फैलगा। बौद्धों को मालाएँ, जैनो को मालाएँ, सातमा मिशनरी कालेज बौद्ध कालेज और ऐसे ही दूसरे कालेज यदि निकलने लगे तो एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के जैसा कुछ नहीं होगा। एक की भाषा दूसरे नहीं समझेंगे और बराबरका फैलेगी। अब इसका विचार करना बहुत आवश्यक है।

साम्प्रदायिकता का स्तर

मित्रा, मुझे अभी ऐसा नहीं लगा कि जो शिक्षण मुझे मिला है वह न मिला होता तो बहुत अच्छा होता। अब तक तथा भगवान की कृपा से आगे भी अभी लगेगा नहीं। यह अमेज अगर इस देश में नहीं आया होता तो आपकी सामान्य शिक्षण का दर्शन भी नहीं हुआ होता। आप कहेंगे कि यह तो वाइप्रॉडकट है आदि। वह चाह जो हो। परन्तु अमेज के आने के कारण इस देश में सामान्य शिक्षण इतना व्यापक हुआ, यह हम देख रहे हैं। और सम्प्रदायों के विषय में उमक तटस्थ होने से डामिनेशन एजुकेशन, साम्प्रदायिक शिक्षण का प्रादुर्भाव हमारे देश में नहीं हुआ। वाइबिल भी सिखायी गयी है। कुरान भी सिखाया जाता है। नीता-उपनिषद् की शिक्षा का तो पार ही नहीं है, फिर भी

साम्प्रदायिक भावना या हमारे शिक्षण में जो कुछ प्रचार हुआ, यह बहुत कम प्रमाण में हुआ है। यह सेकुलरिज्म आदि की बात में नहीं कह रहा हूँ। सामान्य मान्यता, सामान्य आस्तित्वता, सार्वजनिक आस्तित्वता, मानवनिष्ठा और ईश्वर-निष्ठा की शिक्षण व साथ जोड़ना ही तो अवश्य जोड़िए, लेकिन डामिनेशनल शिक्षण नहीं होगा, साम्प्रदायिक-शिक्षण नहीं होगा।

प्रचलित शिक्षण

अन्त में एक प्रश्न मैं स्वयं अपने से पूछता हूँ और आप भी अपने से पूछें—औरकारण दृष्टि से नहीं, सचमुच पूछिए, यह प्रश्न। आज जो शिक्षण इस देश में प्रचलित है क्या उसे लोग सचमुच नहीं चाहते हैं? वास्तव में क्या वह उर्ध्व रेखी और निरम्मा लगता है। मामा क्षीरगागर ने मेरा नाम लिया, मेरा लड़का का भी नाम लिया। बानेज गुलते ही एक महीना तो प्रवेश पाने में बीत जाता है और परसा ही एक सज्जन ने मुझसे कहा कि मेडिकल कलेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए उसको १० हजार रुपये देनेवाला हूँ। बाद में लड़के का १० हजार दाना देकर खूना। उनका पास हिसाब तैयार था। क्या यह शिक्षण लोग नहीं चाहते? यह निरम्मा मान्यता है? सन् १९१५ के संडलर कमीशन से लेकर अब तक शिक्षा के लिए जितने कमीशन नियुक्त किये गये और उनके जो विवरण प्रकाशित हुए उनका उपयोग मेरी समझ में नहीं आता। हम नये बालक चाहते हैं। और एक सज्जन ने नये बानेज के लिए ५ लाख रुपये दिये। दानवीर। उससे किमा ने कहा कहा कि आपने बाहिदात शिक्षण के लिए दान दिया है। दान-भ-भूर भाई कहा कहता। बल्कि ऐसे लोगों का नाम लिया जाता है और स्मारक खड़ा किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में मन से तुम ऐसा शिक्षण नहीं चाहते, इस बात में मेरा विश्वास नहीं है। अब तक तो विश्वास नहीं है।

अंग्रेजी परकीय नहीं

अंत में एक बात और कहनी है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में साम्प्रदायिकता नहीं रहनी चाहिए वैसे ही अब उसमें भाषाभिमान नहीं रहना चाहिए। यह बात मैं हमेशा से कहता आया हूँ और मैं निरन्तर एक के अल्पमत (मायनोटीटी आदिक) में हूँ। अब इस देश में, २०-२५ वर्षों में सभी भी हो शिक्षा का माध्यम एक ही बनना चाहिए और उस दिशा में प्रगति होनी चाहिए। हिन्दी, अंग्रेजी कोई भाषा रहे, मुझे किसी भी भाषा का रोग नहीं है। मैंने अंग्रेजी को परकीय भाषा नहीं माना है। मनुष्य की भाषा परकीय होती ही नहीं। शत्रु की ही तो भी उससे झगड़ने के लिए सोचना होगा। लेकिन हमारे देश में

शीलावनी करकर नलिनी सेनगुप्ता—इन बहनो को भापा ही अग्रजी थी । अब क्या आप यह कहते कि यह विशेष भापा है ? उसका परीक्षण अब दृष्टियों से कीजिए । लेकिन हिन्दी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का झगडा मुझे नहीं करना है । आचन पत्राकर इतनी ही प्रार्थना है कि जैसे उमागवर भाई और दादा धर्माधिकारी एर चास पाठ पर बैठ सके हैं वैसे ही आने की पोड़ी में ए० के० गणालन का लडका और कर्णोविह का लडका एत्र बैठ सकने चाहिए ।

मातृभाषा नहीं होती

एक पृष्ठना मैंने और की है । यहाँ सब शिक्षा शास्त्री आदि बैठे हुए हैं । मैंने कहा कि अपनी लेख साफ कर लीजिए इसलिए मैं पुन उच्चारण करने का साहम करता हूँ । मनुष्य की मातृभाषा होती है । इस पर मेरा विश्वास नहीं है । प्रत्येक भाषा मनुष्य को सिखानी ही पड़ती है । मैं कहना तक सिखाना पड़ता है । जिस परिस्थिति में बच्चा पैदा होता है उस परिस्थिति की जो भाषा होना है उसे वह बच्चा सीखता है । मेरे शिक्षा शास्त्रियों से मेरी प्रार्थना है कि बच्चा के नाम की परिस्थिति बाल झालिए । मारामण देसाई (जिससे यह परिवार परिचित है) उसका सास बगरी । उसका समुर उगाया । तो उसकी पत्नी ? बगाडिया । लडकी गुजबगोडिया । क्योंकि यह नारायण देसाई गुजराती है । पत्नी का पति ? महाराष्ट्रीयन साहण । अब उसकी सतति ? अखिल भारतीय । ऐसे अवसर शिन्ना के क्षण में प्रयत्नपूर्वक उपस्थित करने चाहिए ।

आवश्यक सूचना

[नयी तालीम के पाठकों को सूचित किया जाता है कि गत अप्रैल माह में कुल्चेत्र में हुए सर्वोदय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि जुलाई ७३ से नयी तालीम का प्रकाशन सेवाग्राम वर्धा (महाराष्ट्र) से होगा । अब नयी तालीम के प्रधान सम्पादक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री व गुजरात राज्य के मूलपूर्व राज्यपाल श्री धीमधारायण रहेगे । सहायक के रूप में काम देखने के लिए वाराणसी से श्री बद्रीनाथ सहाय सेवाग्राम जायगे ।

अब पाठकों से निवेदन है कि नयी तालीम सम्बन्धा पत्र व्यवहार जुलाई ७३ से सम्पादक नयी तालीम मासिक सेवाग्राम वर्धा (महाराष्ट्र) के पते से करें । —सम्पादक]

आचार्यों के प्रश्न—विनोबा के उत्तर

[महाराष्ट्र आचार्यकुल सम्मेलन के अवसर पर पूज्य विनोबा से पूछे गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर नयी तात्पीम के पाठकों की सेवा में प्रस्तुत हैं ।—स०]

प्रश्न शिक्षकों को राजनीतिक पार्टियों का सदस्य नहीं बनना चाहिए, यह आचार्यकुल के सदस्यत्व की शर्त है। यह शर्त रखने का प्रयोजन क्या है ?

उत्तर प्रयोजन स्पष्ट है। राजनीतिक पार्टी का जा सदस्य रहेगा, उस पर राजनीतिक पार्टी का अग्रह रहेगा। उस पर वह अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकेगी। इस बंधन से शिक्षक की मुक्त रहना ही ठीक है।

नागरिकत्व से आचार्यत्व महान है

प्रश्न शिक्षक नागरिक भी है, उसे मत का अधिकार है। उसे जो मत प्येच गया है उसका प्रचार प्राजनरूप में करने में क्या खराबी है ?

उत्तर खराबी कुछ नहीं है, अच्छा ही है। लेकिन अपने इस नागरिकत्व के अधिकार का एक ओर रखकर आचार्यत्व का अधिनार प्राप्त करने के लिए इस काय से अग्रिम रहना ज्यादा अच्छा है। पहला अच्छा है, दूसरा ज्यादा अच्छा है।

राजनीतिक प्रचार करने में हानि क्या है ?

प्रश्न शिक्षक को शिक्षक के रूप में व्यवहार करते हुए राजनीतिक पार्टी-वाजी से अलिप्त रहना चाहिए, यह ठीक है। लेकिन नागरिक के रूप में बर्ताव करते हुए शिक्षक राजनीतिक मत का प्रचार करे ता इसमें क्या हानि है ?

उत्तर उह जेचि हुए जो राजनीतिक मत हा, उनका व्यक्तिगत रूप से प्रचार करने की अपेक्षा समूह के रूप में एकत्र हो और सारे शिक्षक मिलकर अभिप्राय निश्चित करें तथा सबका जो एकत्र विचार हो, उसी का प्रचार करें। इससे ज्यादा ताकत पैदा होगी। प्रत्येक व्यक्ति अपना अलग-अलग विचार करने लगेगा, तो ससार के ऐसे अनेकों में यह भी शामिल हो जायेगा। अर्थात् शक्ति खड़ी नहीं रहेगी। शक्ति के लिए क्या करना होता है ? समूह को एकत्र

करना होता है। फिर सामूहिक रूप से सारे शिक्षक मिलकर जा तय करें, यह करना उचित है।

नदियों से सीख लें

प्रश्न शिक्षक मागरिक के रूप में दितचस्थी से राजनीति में भाग लेने लगे तो राजनीति के शुद्ध होने में क्या मदद नहीं होगी ?

उत्तर यह प्रयोग अनेक नदियों ने करके देखा है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, साप्ती, नमदा और अन्य सब नदियाँ मोठे पानी की हैं। उन्होंने समुद्र को मीठा बनाने का प्रयत्न किया। बड़ी तेजी से बेंग से समुद्र की ओर जाने लगी। लेकिन समुद्र थोड़ा भा मीठा नहीं बना। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि इन सब नदिया से शिक्षण प्राप्त करें।

राजनीति का अभ्यास करें

प्रश्न शिक्षक को राजनीति से अलग रहना चाहिए। तबिल उसे लोक-नाति का व्यवहार तो रसपूवक करना चाहिए। एसा आपरा कपन है। इस विषय में आपका क्या विचार है ?

उत्तर शिक्षक का राजनीति का उत्तम अभ्यास करना चाहिए समाज-नीति का भी करना चाहिए। उत्तम अभ्यास करके तटस्थ रूप से अपना विचार बनाना शिक्षक का कर्त्तव्य है। यदि वह राजनीति का अध्ययन नहीं करेगा, तो वह अपने आचार्य का एक अंग दुबल बना डालता है। उसे अध्ययन अवश्य करना चाहिए। लेकिन अध्ययन करके तटस्थ रूप से देखना चाहिए। राजनीति के 'जाल' में अपने को अलग रहकर लेकिन उसका अध्ययन करते रहकर जो मनुष्य अपना विचार बनावेगा वह तटस्थ रहेगा और उसका समाज पर अमर होगा।

आज की राजनीति निरुन्मी है

रम वास्ते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की यह राजनीति किसी काम की नहीं है। उनके नष्ट हुए बिना समाज सुखी नहीं होगा। आज १३० राष्ट्र हैं और ये राष्ट्र अपने मतभेद भी रखेंगे परस्पर भिन्न मामाएँ रखने, यह पक्की समझने और राजनानि चलायेंगे तब आपके ध्यान में आवेगा कि हमें आानि कनी रहेगी और वह कभी भी दूर नहीं वा ना सकेगी। इसलिए अब विश्व-भासाज्य बनना चाहिए। विश्व राज्य का मतलब हो है राजनीति का दूर होना और सासनीति का आना। सम्पूर्ण विश्व का राज्य। अब एसी

विशाल गल्पना करनी चाहिए, तभी जगत में शांति फैलेगी। क्योंकि साइस के कारण सब लोग निवृत्त आ गये हैं।

पहले क्या था ? पहल हिमालय हिन्दुस्तान की उत्तरी सीमा की रक्षा करता था। आज वायुयान द्वारा हिमालय की एक ओर से दूसरी ओर पाँच मिनट में पहुँच सकते हैं। मानलीजिए तिब्बत से निवृत्तकर इस ओर बम गिराना हो तो केवल सात मिनट लगेंगे। वह अब इतना निवृत्त आ गया है। वह सक्ता है कि वह इतना छोटा हो गया है। पहले जो प्रचण्ड सागर था, वह अब कुछ भी नहीं रह गया है। फार ईस्ट और फार वेस्ट। जापान और अमेरिका बिलकुल नजदीक आ गये हैं। पड़ोसी देश हो गये हैं। ऐसी स्थिति में सार देशों के निवृत्त आने के कारण आज की जो पुटुवर राजनीति है, यह मारवा है। अब उससे मुक्ति कैसे मिलेगी, यहाँ विचार समाज को सिखाना है।

शिक्षा का राष्ट्रीयकरण

प्रश्न कुछ शिक्षक-संगठनों ने प्रस्ताव किया है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और उसका पृष्ठपोषण भी कर रहे हैं। आचार्यकुल मानता है कि शिक्षा को सरकारभुक्त होना चाहिए। ये दोनों परस्पर-विरोधी सिरे हैं। तो क्या ऐसे संगठनों के पदाधिकारियों को और सदस्यों को आचार्यकुल की सश्रुता स्वीकार करनी चाहिए ? अथवा क्या वे स्वीकार कर सकते हैं ?

उत्तर शिक्षण के राष्ट्रीयकरण की जिन लोगों ने माग की है, वह इसलिए कि जा निजी विद्यालय चलते हैं, उनमें अधेरगर्दी चल रही है और सब प्रकार की अनुचित बातें वहाँ चलती हैं। इससे प्रस्ताव होकर अतः राष्ट्रीयकरण हो अर्थात् सारा शिक्षण सरकार के हाथ में जाय, यह माग की गयी है। लेकिन इसका भी उपाय है। यहाँ उमाशकर भाई बैठे हैं। इनके हाथ में उपाय है। ये एक युनिवर्सिटी के वाइसचांसलर हैं। देश भर में सत्तर युनिवर्सिटियाँ हैं, उनके सत्तर वाइसनाइलर हैं। ये अपनी एक मीटिंग करें, यह मेरा प्रयोजन है। वे सब मिलकर शिक्षण का एक ढाँचा तैयार करें। वे जो रचना तय करेंगे उस सब विद्यालयों को मानना चाहिए। फिर वे सब प्राइवट हो या सरकारी हा। सब उसे मान्य करें, यह मेरा प्रयोजन है। ऐसा न माना जाय कि वह अव्यावहारिक है। क्योंकि वे सब वाइसचांसलर हैं, जिनसे अधिक चिन्तनशील, अधिक विचारयुक्त मनुष्य बहुत कम मिलेंगे।

अब ऐसे कुछ लोग तथा इनके अविरुद्ध कुछ साहित्यिक, जो किसी का पक्ष लेनेवाले नहीं हैं, जैसे जैनेन्द्रजी, दादा धर्माधिकारी आदि कुछ साहित्यिक

मिलकर भी बर सन हैं। लेकिन मानलीजिए प्रारम्भ में सतर ने भी योजना की ता भी चनेगा और उसे सब मायता प्रदान कर। वह योजना इतनी ठोसी है कि उस योजना में प्राइवट आदि विद्यालयों को एक मर्यादा में अपनी बात चलाने की इजाजत रहे। इतना ही देखा जाय कि उनका उलघन न हो। शिक्षण विषयक कौन-सी पुस्तक रखी जाय क्या रखी जाय और अन्य बहुत सी बातों में उन्हें स्वतन्त्रता दी जा सकती है। नविन प्रत्येक पुस्तक जो चुनी जायगी उसकी सम्मति भी वाइसचांसलर के पास भेजकर प्राप्ति की जानी चाहिए। उन्हें उसमें कुछ विपरीत या विरोधी बातें लगे तो वे ध्यान में ला दगे और उचित अंग निकाल देना होगा। ऐसा यदि हम कर सकें तो यह जो प्राइवट विद्यालयों का अधेरागर्ने का प्रश्न है हम हल कर सकेंगे ऐसा मुझे लगता है।

नैतिक सामर्थ्य कैसे बढ़ेगी

प्रश्न शिक्षा की वैयक्तिक नैतिक सामर्थ्य कैसे बढ़ेगी ?

उत्तर एक उपाय है। हमारे भारत में परमात्मा की कृपा से विपुल सन्त-साहित्य है। उससे नैतिक सामर्थ्य की प्रेरणा मिलेगी। इसे कहना चाहिए स्वाध्याय। उनके साहित्य का अध्ययन। दूसरी बात है सत्संग अर्थात् आध्यात्मिक चर्चा के लिए जिसको के सम्मेलन हो। दूसरी चर्चाओं के लिए सभी-सभी हम एकत्र होते ही हैं। लेकिन आध्यात्मिक चर्चा के लिए मानलीजिए हम आध्यात्मिक महीने में एकत्र हो १०-१५ दिन बैठकर अध्ययन विचार चर्चा प्राप्ति की जाय।

अपना ही अवमान न करें

प्रश्न जिस स्वतन्त्रता का स्वायत्तता की मुक्तता की मांग हम कर रहे हैं उसके लिए हम आज के आचार्य मात्र हैं। योग्य आचार्य के शिक्षा-क्षेत्र में आने के लिए क्या उपाय करने चाहिए ?

उत्तर हम उत्तम पात्र हैं यह मान बैठना गलत है और यह कल्पना भी छोड़ देनी चाहिए कि हम अपात्र हैं। हमें अब तक यश नहीं मिला इसलिए अपना अवमान न कर। भगवान् मनु ने एक आना दी है— न आमानाम् अवमन्येत्। पहले हमें समृद्धि मिली नही यश मिला नही इसलिए हम अपात्र हैं ऐसा भास जिसको हुआ उम्मी क्षण वह पात्र बन गया। यह बहुत महत्त्वपूर्ण विचार है। हम अपात्र हैं यह बात अज्ञानता समझते ही नहीं। अपात्र का मुख्य लक्षण ही यह है और जिसे महसूस होता है कि हम अपात्र हैं वह अपात्रता का समझी बन गया अपात्रता में अलग हो गया।

एक बार सुकरात से प्रश्न किया गया था। सुकरात को उस जमाने के लोग सबसे समाना समझते थे। लोगो ने उनसे पूछा, “आपको सबसे ज्ञानी क्यो कहा जाता है ?” तब उन्होंने कहा, “यह बात लोगो से ही पूछनी चाहिए कि मुझे सबसे ज्ञानी क्यो कहा जाता है। मुझसे क्यो पूछते हैं ? फिर भी पूछते हैं तो कहता हूँ। लोगो में जितना अज्ञान है, मेरे पास भी उतना ही अज्ञान है और मेरे पास अज्ञान का ज्ञान है इसीलिए लोग मुझे ज्ञानी कहते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ और लोगो को यह मालूम ही नहीं कि वे अज्ञानी हैं।”

शिक्षक सञ्जन

मुझे महाराष्ट्र के शिक्षको का अनुभव कम है। क्योंकि पिछले १५ वर्ष का समय महाराष्ट्र के बाहर ही बिता है। बिहार का अनुभव मुझे उगाड़ा है। उधर के आचार्यों ने जितनी सहानुभूति सर्वोदय के लिए दिखाई, उतनी दूसरे किसी भी वर्ग ने नहीं दिखाई, और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि आचार्य उनमें अधिक समरस हैं। मैं शान्ता के सामान्य शिक्षको के बिषय में नहीं कह सकता। क्योंकि जो सामान्य शिक्षक हैं, वे अन्य नीचरियाँ देखते हैं। और नीचरी न मिलने पर ही शिक्षक बनते हैं, ऐसी उनकी स्थिति है। उनकी सनस्वाह भी कम ही होती है। उनकी बात मैं नहीं करता, परन्तु सामान्यतः हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और प्रिन्सिपल के आचार्य-प्राचार्य आदि लोगो में पर्याप्त सञ्जनता है, ऐसा मेरा अनुभव है।

उपमा एकांगी हो होती है

प्रश्न न्यायविभाग की स्वतन्त्रता की जो उपमा आपने शिक्षण स्वातंत्र्य का विषय समझाने हुए दी है, वह कोई उत्तम उपाय नहीं है ।

उत्तर : वह मुझे स्वीकार है, क्योंकि उपमा सर्वांगीण नहीं हो सकती, एकांगी हो होती है ।

गाय का दूध कैसा है ? राजहंस की तरह सफेद । तो उन्होंने कहा 'दूध की चोख होती है क्या ? अरे भलेमानुष दूध के लिए यह जो उपमा दी गयी है, वह चोख के लिए नहीं दी गयी है । इसी प्रकार न्याय विभाग की जो उपमा दी गयी वह बिलकुल छोटी उपमा है । शिक्षकों के हाथ में भरपूर स्वतन्त्रता होनी चाहिए । न्याय-विभाग को जो स्वतन्त्रता है वह बहुत ही मर्यादित है । यह उपमा केवल समझने के लिए ही दी गयी है । वावा भो हो आलसी हो तो भी घड़ी आलसी नहीं है । ग्यारह बजे शुरूआत की थी अब बारह बज गये हैं । काटा आगे सरक गया है ।

जय तक मस्कार है तब तक

प्रश्न आज की परिस्थिति में सामान्य जनता तक शासन शिक्षा को पहुँचाता है । अर्थात् शासन ने इतनी व्यापक योजना बनायी है कि वह गाँव-गाँव में शालाएँ खोलता है । यानी शिक्षण का प्रसार शासन ने किया है । यह कहते हैं कि शासन की मदद के बिना शिक्षण स्वयं कैसे पहुँचाया जा सकता है ? अर्थात् स्वतन्त्र शिक्षण कैसे सम्भव है ? इतनी व्यापक योजना सरकार को एक ओर रखकर कैसे बनायी जा सकती है ?

उत्तर इसीलिए मैंने आप से कहा कि हमें वृक्ष की छाया का उपयोग उसे तोड़ने के लिए करना है । पेड़ की छाया में खड़ा रखकर उसे तोड़ना है । ठीकते समय वह छिर पर न गिरे इसलिए थोड़ा सरक जाना है । लेकिन वह टूटते समय । वैसे ही सरकारी शासन को जो मदद हमें मिलती रहेगी उसे लेने में कोई हर्ज नहीं । वे भी मदद दें । वह इसी वृत्ति से दी जाये कि हमारी वह छोटी-सी अल्प मदद है, मुख्य कार्य आपका ही है । यह पूरी योजना आपकी हो, बुद्धि आपकी लेकिन बाह्य योजना हमारी ओर से मदद के रूप में है, ऐसा उन्हें स्वीकार करना चाहिए और आपको भी उसे मान्य करना चाहिए । इस समय मानी क्या तक ? जब तक शासन-संस्था कायम है तब तक ।

मुख्य उद्देश्य

प्रश्न शिक्षण में सुधार लाने के लिए सशोधन, प्रयोग, निष्कर्ष निकालने की योजना क्या आचार्यकुल को तैयार करनी चाहिए ?

उत्तर आचार्यकुल को जगत में और भारत में जो घटनाएँ हो रही हैं उनका परिणाम जगत पर और सर्वत्र मनुष्यों पर होनेवाला है। उन महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में अपना अभिप्राय जो सर्वानुमति से तय हो उसे प्रकट करना चाहिए और उसकी शक्ति जगत में प्रकट करनी चाहिए, ऐसी कल्पना है। आचार्यकुल का मुख्य उद्देश्य नहीं है। उदाहरण देता हूँ—मान लीजिए इधर सरकार के माफ़त जुआ चल रहा है उसका नाम लाटरी है। अब यह लाटरी अनेक राज्यों में चल रही है।

गुजरात राज्य लाटरी मुक्त है। शेष सभी प्रान्तों में है। अब इस लाटरी के विषय में आचार्यकुल के लोगो ने एकत्र होकर—जैसाकि मेरा कहना है वाइसचांसलर आदि विद्वानों तथा आचार्यों ने एकत्र होकर—अपना निणय लिया। मानलीजिए अपना मत अनुकूल हो गया तो उन्हें अनुमूल प्रस्ताव करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि बाबा के कहे अनुसार ही प्रस्ताव करना चाहिए। उन सबका मत प्रतिकूल हो जाय कि यह बात अच्छी नहीं है इससे पोरुष की हानि होती है मनुष्यत्व की हानि होती है पैसे कमाने का वह एक उद्योग है—ऐसा मत उन्होंने व्यक्ति किया तो उसका सारे भारत पर असर होगा। यह एक उदाहरण है। ऐसी और भी बातें हैं।

नीचे की कक्षाओं के लिए हेडमास्टर

मेरी एक योजना है। वह यदि जेंच जाय तो शिक्षक सुधरेगा। वह क्या है ? बाला का हेडमास्टर किस कक्षा को पढ़ायेगा ? मेट्रिक आदि। मेरा कहना यह है कि जो हेडमास्टर होगा वह सबसे विद्वान होगा। उसे पहली कक्षा को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि पहली कक्षा को पढ़ाने में बुद्धि की अधिक आवश्यकता है। उसरी अपक्षा ऊपर के शिक्षक को जानकारी रही तो बस है। जानकारी के बन पर वह पढ़ा सकेगा। उसे शिक्षण की उत्तम कला अवगत रहनी चाहिए ऐसी बात नहीं, लेकिन नीचे की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए सबसे उत्तम शिक्षक आवश्यक है। मानलीजिए मैं शिक्षक बना तो ऐसे सबको को एकत्र करूँगा जो बहुत पढ़ हुए नहीं हैं। उनको सिखाने में मेरी बुद्धि का विकास होगा। मुझे मालूम होगा कि कैसे सिखाया जाता है। इसलिए सबसे अधिक कलावन्त शिक्षक नीचे की कक्षाओं को चाहिए। मेरी यह धान अगर कार्यावित्त की जा सके तो काफी सुधार होगा।

अच्छे सरकार

प्रश्न बच्चा पर अच्छे सम्कार डालने के लिए आप कौन-से उपक्रम सुझाते हैं ?

उत्तर यदि हममें अच्छा संस्कार होंगे तो वे बच्चों को सहज ही मिलेंगे। गुलाब में यदि सुगंध होगी तो सहज में वह सागो को नाक में धुस जायेगी। बच्चा पर अच्छा संस्कार डालने के लिए माता को भक्त होना चाहिए। पिता को योगी होना चाहिए। माता भक्त पिता योगी और आचार्य नानी। अर्थात् यदि माता भक्त है तो उसकी भक्ति का संस्कार बच्चा को सहज रूप से मिलना है। और भक्ति के अभाव और किसी भी चीज में इतनी शक्ति नहीं है। बच्चों पर संस्कार डालने के लिए भक्ति ही माता है। पिता समस्त ब्रह्म चित्त से संसार शायं करे। यह पिता का कर्तव्य है। और गृह को में नानी कहती हैं। यानि उसमें माता की भक्ति पिता के योग (समस्तब्रह्म चित्त) के अतिरिक्त गान होता है। इसलिए बच्चों पर अच्छा संस्कार डालने की पहली जवाबदारी माता पिता पर है ऐसा समझना चाहिए। हम क्या करते हैं? माता पिता की कल्पना न करके सारी जवाबदारी अपने सिर पर ले लेते हैं।

मैंने देखा है कि इधर बहुत से माँ-बाप बच्चों से परेशान रहते हैं। और ब छोटे-छोटे बच्चे घर पर तंग करते हैं। उनके लिए काफी समय देना पड़ता है। इसलिए उन छोटे बच्चों की शानाएँ खोली गयी हैं। ३-४ ५ वर्षों के सारे बच्चे किसी महिला के पास जाते हैं। यानी माँ की ५ फुट पन्पट मिटी। ऐसी जो माताएँ हैं जिन्हें बच्चा का पशु मालूम होती है उनको कभी माँ कहें? इसलिए गृह जीवन पर मुख्य बात अवलंबित है। और शिक्षक के पास भी बच्चों के आने पर उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि वे सीख रहे हैं। बच्चे खेलते हैं तब उनका व्यायाम होता रहता है। लेकिन इसका उन्हें पता नहीं चलता। ऐसे ही शिक्षक के साथ हम काम कर रहे हैं बात कर रहे हैं भजन करते हैं शिक्षकों के साथ बगीचे में काम करते हैं ऐसा प्रतीत होना चाहिए और कुछ सिखाया जा रहा है यह बच्चा को महसूस नहीं होना चाहिए। शिक्षण-काम चल रहा है ऐसा जितना भास होगा उतना ही वह शिक्षण निम्न दर्जा का समझना चाहिए।

शिक्षा-क्षेत्र की स्वायत्तता का स्वरूप, व्यवहार और मर्यादा

स्वायत्तता का स्वरूप

१. सरकार हमारा मार्गदर्शन स्वीकार करे, इतनी सामर्थ्य जन-शक्ति के आधार पर शिक्षकों को अर्जित करनी चाहिए।

२. सम्पूर्ण शिक्षा-क्षेत्र का उत्तरदायित्व स्वायत्त शिक्षा-परिषदों को सौंपना, यह स्वायत्तता का स्वरूप रहे। सम्पूर्ण शिक्षा-क्षेत्र का अर्थ शिक्षा से सम्बंधित सारे विषय।

सम्पूर्ण स्वायत्तता—अर्जन-मार्ग के प्राथमिक तीन कदम

१. शिक्षा-संस्थाओं की व्यवस्था केवल शिक्षा के हित की अपेक्षा अन्य हित-साधन करने की नीति से चलानेवाले व्यवस्थापकों के हाथ से तत्काल निशाल लेना और शिक्षा-हितैषी स्वायत्त परिषदों के अधीन करना।

२. स्वयं शिक्षकों को राष्ट्रीय प्रगति के मार्ग की अपनी भूमिका समझाकर आचार्यकुल की अपेक्षा के अनुसार शिक्षक का कार्य करना।

३. शिक्षकों को भारतीय तथा राज्य-स्तर पर जो प्रशस्ति पत्र दिये जाते हैं, उनमें लिए शिक्षकों की परिषद नियुक्त करना।

शिक्षा-क्षेत्र की स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए ये तीन बातें लोकशक्ति के भारोत्ते पर साध्य करनी चाहिए।

शिक्षक की गानुवित् भूमिका

समाज-जीवन सदा ही गतिमान रहा है। स्वाभाविक रूप से परिवर्तन ही समाज का प्राण है। इसीलिए समय-समय पर परिवर्तन का उचित दिशा दिखानेवाले मार्गदर्शकों की समाज को आवश्यकता पड़ती है। यह दिशा दिखानेवाला कौन है? इस प्रश्न का उत्तर वेद में शिक्षकों को गानुवित् अर्थात् मार्ग खोजनेवाला सम्बोधित किया है। 'गानु यानी गगनमार्ग और विद् यानी रोज निरामोवाला।' इस पर से गानुवित् के कार्य का उद्देश्य भी स्पष्ट हो गया है। निम्न समाज-जीवन अधिनाधिन उन्नत अवस्था को पहुँच, गगन-मार्ग बने, ऐसा ही मार्गदर्शन जिम्मे अपेक्षा है वह है गानुवित्। जिसे यह उँची जवाबदारी निम्नी है जगते अध्ययन-अध्यापन पर तथा विचार-प्रचार की स्तनत्रया पर विद्यों की भी कोई मगाम नहीं रहनी चाहिए—यह स्पष्ट है।

जिसे समाज का नेतृत्व करना है, उसका जियो भी बंधन में रहना ठीक नहीं। इस दृष्टि से शिक्षा-क्षेत्र की स्वायत्तता की तथा शिक्षक की प्रतिष्ठा की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है।

मानव-समाज के इतिहास में अनेक आचार्यों ने समाज का मार्गदर्शन किया है, तो भी समाज-जीवन का प्रत्यक्ष नियंत्रण शासन-संस्था करती आयी है। ऐसा हम देखते हैं कि शासन-संस्था साधारणतः (स्टेट्स-को) यथास्थिति को बनाये रखना चाहती है।

लेकिन, यथास्थितिवाद कुल मिलाकर समाज-जीवन के प्रवाह की—विरोधी होने से समाज के बहुविध जीवन के स्थित्यान्तर में हस्तक्षेप शासन-संस्था को समय पर ही करना चाहिए। समाज में अज्ञाति उत्पन्न न हो, इनके लिए शिक्षा को शासन-संस्था का मार्गदर्शन करना चाहिए। लेकिन यह मार्गदर्शन शासन के स्वोन्मत्त करने पर ही समाज-जीवन का प्रवाह मरलतापूर्वक चलेगा। इस दृष्टि से शिक्षा-क्षेत्र की स्वायत्तता की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के विषय में शासन की शिक्षा-युगत की ही बात माननी चाहिए।

शासन की यथास्थितिवाद प्रकृति के कारण और शिक्षक की दृष्टि भविष्य निर्माण की ओर होने के कारण, समाज-जीवन में शिक्षक को अपना यह उच्च-स्थान पहचानना चाहिए। यह दृष्टि प्राप्त होने पर वह इस पात्रता को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। शिक्षण की स्वायत्तता प्राप्त होने के लिए शिक्षक को यह भूमिका स्वीकारनी चाहिए।

विनोबाजी की छटपटाहट

आज दुर्भाग्य से विपरीत स्थिति हो गयी है। इसीलिए शिक्षा का क्षेत्र स्वायत्त हो और शिक्षक को समान-मार्गदर्शन की प्रतिष्ठा प्राप्त हो, इसकी छटपटाहट विनोबाजी की है। लोचनत्र होते हुए भी उस पद्धति के लिए आज आवश्यक बनी हुई पञ्चनिष्ठ राजनीति और शिक्षा-क्षेत्र पर उसके परिणाम को देखते हुए, विनोबाजी की यह छटपटाहट और भी तीव्र हो गयी है।

विनोबाजी की मिसाल

इस बारे में अपने मन का प्रतिपादन करते हुए पूज्य विनोबाजी ने न्याय-विभाग की स्वायत्तता और न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा की मिसाल दी है। वे कहते हैं, 'न्याय विभाग का जितनी स्वतंत्रता है, दुर्भाग्य से उतनी स्वतंत्रता भी शिक्षा-विभाग की नहीं है। न्याय-विभाग का शासन पर एक विशिष्ट प्रकार का वजन होता है। वह शासन के विरुद्ध निर्णय तक दे सकता है और शासन को वह मानना पड़ता है। शासन से बेजबन केरूर भी न्याय-विभाग शासन के अधीन नहीं

रहता। इसी प्रकार शिक्षा-विभाग का भी होना चाहिए। वेतन भले ही शासन की ओर से मिले लेकिन विचार-स्वातन्त्र्य उस विभाग को होना चाहिए।'

मिसाल की उपयुक्तता के विषय में शका

सम्पूर्ण शिक्षा-क्षेत्र की स्वायत्तता होनी चाहिए और शिक्षण शासन-मुक्त होना चाहिए, यह ठीक है। लेकिन इस क्षेत्र की स्वायत्तता के समर्थन में पूज्य विनोबाजी द्वारा रखी गयी अमर की मिसाल भी उपयुक्तता के विषय में भेरे मन में शका है। उसे पूज्य विनोबाजी के अधिकृत मार्गदर्शन के लिए उनके आगे रखना मैं अपना वर्तमान समझता हूँ।

एक जमाने में न्याय-विभाग शासन-संस्था में अलग और स्वतंत्र नहीं था। जिस समय कानून से प्राप्त स्वतंत्रता तो नागरिकों को उपलब्ध होनी चाहिए ऐसा समाज को लगने लगा, तब शासन-संस्था की तीन स्वतंत्र शाखाएँ बनीं— कानून बनानेवाली, कार्यकारी और न्यायिक (पार्लियामेंट, लोकसभा, विधान-सभा आदि)। पहली दो शाखाओं के पारस्परिक सम्बन्धों से हमारा निकट का सम्बन्ध नहीं है। लेकिन जो न्यायिक शाखा स्वतंत्र मानी जाती है उसकी स्वतंत्रता का स्वरूप मुझे केवल सार्वजनिक डम का और अल्पजीवी प्रतीत होता है। न्याय-विभाग स्वतंत्र है, इसका अर्थ शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा किये गये या न किये गये कृत्य कानून के अन्तर्गत शब्द और अर्थ की दृष्टि से ठीक है या नहीं इतना ही तय करने का अधिकार न्याय-विभाग को है। यह स्वातन्त्र्य बहुत हुआ तो कार्यकारी विभाग पर न्याय-विभाग का आतंक जमाता है, लेकिन विधि-विभाग (विधानसभा-लोकसभा) पर न्याय-विभाग का नियंत्रण बिलकुल नहीं रहता। क्योंकि कानून के शब्दों का अर्थ अपेक्षा से भिन्न होता है, ऐसा विधि-विभाग को प्रतीत हुआ तो कानून और उसके शब्दों को बदलने का उस विभाग का अधिकार अबाधित रहता है और है।

स्वायत्तता का औपचारिक पद्धति में व्यवहार कैसा हो ?

भारत ने लोकतंत्र को जीवन-पद्धति के रूप में पूरी तरह प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार नहीं किया है। इस पद्धति के अनुसार जनता के हित के लिए परिधान की दिना बोननी हो, यह तय करना विधि-विभाग के लिए अपरिहार्य है। अनेक अध्ययन के भरोसे पर और दृष्टान्त की सामर्थ्य पर आधारित अधिक-से-अधिक विधि विभाग का मार्गदर्शन कर सकेगा। लेकिन लोकतांत्रिक शासन-पद्धति में सम्पूर्ण स्वायत्तता केवल विधिभारता को ही रह सकती है। अन्य शक्ति भी जीवनशासक न्याय-विभाग तक—सम्पूर्णतया स्वायत्त नहीं रह सकती। यह हमें

मान्य करना ही होगा। इसलिए इस शासन-व्यवस्था में शिक्षा जगत को सम्पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होना और भाग करना मुझे जरा कठिन लगता है।

अन्य शिक्षा-क्षेत्र को और आचार्य को मार्गदर्शन वा अपना कार्य विधि-विभाग वा मार्गदर्शन करके उसे अपनी सामर्थ्य से ही मान्य करना होगा, यह स्पष्ट है।

विनोबाजी को जन-शक्ति का सहारा स्वीकार

पूज्य विनोबाजी को भी लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था वा यह गृहीत कृत्य पूरी तरह मान्य है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पक्षनिष्ठ राजनीति से आचार्यों को दूर रहना चाहिए। ऐसा वे कहते हैं। उनका कहना है कि शिक्षकों को जन-शक्ति पर आधारित लोकनीति अंगीकार करनी चाहिए और जन-सम्पर्क के बिना राजनीति पर प्रभाव पड़ना असम्भव है। इसका मतलब यह हुआ कि लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था में शिक्षकों को पक्षनिष्ठ राजनीति से दूर रहकर जन शक्ति जागृत करना चाहिए, ऐसा पूज्य विनोबाजी को अभिप्रेत है।

इस मार्ग को अपनाना है तो सर्वसाधारण शिक्षकों पर अपनी क्षमता बढ़ाने की बहुत बड़ी जवाबदारी आ जाती है। उसका कार्यक्षेत्र कक्षा मर्यादित नहीं रह जाता। वह लोक-शिक्षक बन जाता है। प्रत्यक्ष सत्ता को न स्वीकारते हुए जन-शिक्षक रहना हो धी शिक्षकों को अपनी सामर्थ्य जन-शक्ति के भरोसे पर बढ़ाना शिक्षा-क्षेत्र को स्वायत्त करने का और स्वायत्तता बनाये रखने का एकमेव मार्ग है।

स्वायत्तता की माँग क्यों ?

शिक्षा-क्षेत्र की स्वायत्तता का विचार करना जिन अनेक कारणों से आज आवश्यक हो गया है उनमें से सबसे प्रमुख कारण यह है कि शिक्षा-शास्त्रियों के विचार आज का विधि-विभाग तुरन्त स्वीकार नहीं करता। स्वीकार करने में हस्तक्षेप करता है। और स्वीकार करने के बाद उनको दुर्दत्तापूर्वक कार्यान्वित नहीं करता।

केन्द्रीय और राज्य स्तर पर स्वायत्त शिक्षा-परिषदों की स्थापना पिछले २५ वर्षों में अनेक शिक्षण-आयोग स्थापित हुए हैं। उन्होंने शिक्षा-क्षेत्र में परिवर्तन के अनेक सुझाव दिये लेकिन उनमें से एक भी सुझाव का भारतीय स्तर पर सतत, दीर्घकाल तक अमल नहीं हुआ है। कुछ सुझावों की ओर तो शासन ने बिलकुल ध्यान ही नहीं दिया।

लोकतांत्रिक-व्यवस्था में विधि-शाखा का प्रमुख मान्य करके भी, और आज सामान्य शिक्षक की क्षमता गणतन्त्र को नहीं है, यह मान्य करने पर भी जिन

उद्देश्यो से शिक्षा की स्वायत्तता माय करनी है, उन उद्देश्यों की सफलता की दृष्टि से भारतीय स्तर पर एक स्वायत्त शिक्षण-महामंडल की ओर सब राश्यों में राज्यस्तर पर स्वायत्त शिक्षण-मंडलों की स्थापना करके, उनको शिक्षा क्षेत्र का सम्पूर्ण संचालन सौंप देना आवश्यक है। आज के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस योजना का कुछ अंशों में प्रतीक माना जा सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वायत्त है, उसे भारत सरकार विशिष्ट धनराशि देती है और आयोग उस धनराशि का विनियोग अपने निणयानुसार करता है। उपरोक्त शिक्षा मंडलों को शासन इसी प्रकार धनराशि दे और उसका विनियोग मंडल अपनी योजनानुसार करे ऐसी योजना होनी चाहिए।

विचारणीय मुद्दे

इस शिक्षण मंडल में केवल शिक्षक ही रहने चाहिए यह सामान्य तत्त्व मान्य होने जैसा है। फिर भी इस मंडल की रचना कसी हो, सदस्यों का चयन हो या निर्वाचन हो सभी मंडलों के ध्येयों और नीतियों में सुसूत्रीकरण कैसे रखा जायगा इस बारे में सूक्ष्म विचार करना होगा। केन्द्र तथा राज्य सरकारें कितनी धनराशि इन मंडलों को दें—यह प्रश्न सदैव विवादास्पद रहेगा। लेकिन इन सबके पूर्व निम्नलिखित दो बातों पर निणय होगा अत्यन्त आवश्यक है।

१ पहली बात यह कि इन स्वायत्त मंडलों में शिक्षा क्षेत्र से सम्बद्धित विविध विषयों में भर्तव्य होना चाहिए। भर्तव्य न हो तो बहुमत का निणय मान्य करना चाहिए, सबमत का आग्रह न रखा जाय।

२ दूसरी बात यह कि इस क्षेत्र तक ही सही, भारत में शासन व्यवस्था के समानांतर एक ऐसा संगठन रहेगा और इसे चलाने के लिए शासन द्वारा धन दिये जाने पर भी उस पर शासन करने का अधिकार शासन (राज्य सत्ता) को नहा रहेगा। तुरही (वाद्य-यंत्र) के लिए हम भले ही पंसा दें, ता भी वह कैसे और कब बजायी जाय, इसका हमें तनिक भी अधिकार नहीं है, वह कड़ुवी घूंट शासन को पीनी पड़ेगी।

स्वायत्तता के मार्ग पर दूसरा कदम

शिक्षा क्षेत्र की स्वायत्तता का विचार करना पड़ता है, इसका दूसरा प्रमुख कारण है अनेक स्तरों पर शिक्षा-संस्था, सारे स्तरों के विद्यालय, महा-विद्यालय, विश्वविद्यालय—की व्यवस्था पर उन लोगों की पकड़, जिनका प्रत्यक्ष शिगा की गुणवत्ता से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस पकड़ के कारण ही शिक्षा-क्षेत्र का नाश हो रहा है।

अप्रेजा वे जमाने में शासन की शिक्षा के प्रचार, ध्येय-नीति और व्यव-

स्थापन की कोई चिन्ता नहीं थी। अगर भी तो इतनी ही कि उनकी व्यवस्था ब्रिटिश अनुकूलन-जन ही करें। इसलिए उस जमाने में समाजसेवा के बहुत बड़े साधन के रूप में अनेक समाजसेवक इस क्षेत्र में आये और उन्होंने ऐसा नि स्वार्थ प्रयत्न किया कि इन्होंने सस्थाओं से भारत का प्रिय नागरिक बाहर निकले। स्वतन्त्रोत्तर काल में स्वयं शासन की शिक्षा-प्रसार करना तथा शिक्षा की नीति-रीति सविधान में स्पष्ट की गयी नीति-रीति के अनुसार हो, ऐसा अपना कर्तव्य प्रतीत हुआ। उन उद्देश्यों के अनुसार स्वयं शासन शिक्षा-प्रसार का और पाठ्यक्रम तैयार करने का कार्य करने लगा तो भी समाजसेवक शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित करें और चलायें, यह नीति कायम रही है। शिक्षा की ओर देखने की शासन की दृष्टि पूरी तरह बदल गयी है। तो भी यह नीति मूलभूत रूप से न बदलने के कारण आज भारत की सारी शिक्षा-संस्थाएँ अनेकानेक व्यक्तियों के लिए सत्ता और सम्पत्ति की उत्पादन स्थल बन गयी हैं। उनमें राजनीति ही नहीं, अनेक नीतियाँ धूम गयी हैं। ये संस्थाएँ सत्ताशुद्ध दल के व्यक्तियों की हो सत्ता और सम्पत्ति-स्थल बन गये हैं, ऐसी बात नहीं है। सब दलों के, धर्मों के, सम्प्रदायों के और समाज के व्यक्तियों के अथवा व्यक्तिसमूहों के ये सत्ता सम्पत्ति स्थल बन गये हैं। शिक्षा की स्वायत्तता का और शिक्षक का शिक्षण-कार्य में स्वतन्त्रता देने की दृष्टि से आज अत्यन्त शोघ्रता इस बात में होनी चाहिए कि इन सबके शिकजे से भारी शिक्षाएँ मुक्त हो जायें। विविध स्तरों पर विभिन्न क्षेत्र की शिक्षण-संस्थाओं की अपेक्षा केवल उत्कृष्ट शिक्षण-संस्था, संशालन स्वयत्त-मंडल स्थापित करना आज की परिस्थिति में शिक्षा-क्षेत्र की स्वायत्तता की दृष्टि से पहला और शोघ्रता का कदम है।

सौभाग्य से महाराष्ट्र में तो भारतीय सविधान के घोषणा पत्र से सुसंगत प्रेरणा देनेवाले पाठ्यक्रम की शुरुआत हो गयी है। अभी-अभी आचार्यकुल की केन्द्रीय समिति ने शिक्षा-विषयक नीति और कार्यक्रम प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र की शिक्षा-नीति और पाठ्यक्रम उससे मिलता-जुलता है। निकट भविष्य में इस नये पाठ्यक्रम में विशेष फर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता अथवा ऐसी व्यवस्था करने की है कि पाठ्यक्रम जिस मस्या में कार्यान्वित होनेवाला हो, उस मस्या की व्यवस्था उसी उद्देश्य से चले और अपनी सत्ता तथा सम्पत्ति बनी रहे, ऐसी व्यवस्था के ह्रास में मस्या की जा पकड़ है, वह नष्ट हो। इस पकड़ के नष्ट होने पर तो वे शिक्षण ऐसी व्यवस्था के शिकजे से मुक्त हो जायेंगे जिसको शिक्षा में कोई रम नहीं है। और फिर सही अर्थ में उसे शिक्षक होने का अवसर प्राप्त होगा।

दूसरा कदम : शिक्षक द्वारा अपने कार्य की भूमिका

शिक्षक को स्व-प्रयत्न से अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए। इसके लिए उसे पाठ्यक्रम की पुष्टिया बांधकर उन्हें विद्यार्थियों के आगे स्मरण-शक्ति में ठूसने की पद्धति छोड़ देनी चाहिए। हमें ऐसा विद्यार्थी निर्माण करना है जो गतिमान विश्व का समय-समय पर मार्गदर्शन करने की योग्यता रखे, ऐसी निष्ठा शिक्षक को रखनी चाहिए। भविष्य में शिक्षा का क्षेत्र स्वायत्त बने और स्वयं शिक्षक को ऊँची प्रतिष्ठा प्राप्त होने की दृष्टि से शिक्षक के ही मन में अपनी कार्य-विषयक भूमिका में ही ऐसी क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना आवश्यक है। स्वायत्तता के मार्ग पर यह दूसरा महत्वपूर्ण कदम है।

तीसरा कदम : शिक्षकों का सम्मान

जब डा० राधाकृष्णन् राष्ट्रपति थे, तब शिक्षकों का सम्मान करने की पद्धति प्रारम्भ हुई। इसके लिए शासन ही शिक्षकों का चुनाव करता है। यह चुनाव उचित ही होता है, ऐसी बात नहीं। चुनाव करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षिनी (टीचर्स एकादमी) स्थापित की जाय। यह ऐसे ही शिक्षकों का चयन करेगी जिससे मार्गदर्शन शिक्षण सस्या और समाज स्वीकार करेगा। इस तरह सामान्य शिक्षक स्वयं समझेंगे कि उन्हें अपने में बंसी क्षमता पैदा करनी है।

मर्यादा नहीं, मार्ग

इस प्रतिपादन से शिक्षा-क्षेत्र की आवश्यकता, स्वरूप और व्यवहार को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। सखी स्वायत्तता की मर्यादाएँ मर्यादित प्रमाण में स्पष्ट की गयी हैं। अय नहीं की गयी है, लेकिन स्वायत्तता की प्राप्ति का उपाय बनाने का प्रयत्न किया गया है।

कार्यक्रम

सारी शिक्षा-संस्थाओं की व्यवस्था शिक्षा-हितैषी लोगों के स्वायत्त मंडलों को उत्काल सौचना और शिक्षक को अपनी 'गानुबि' भूमिका सदा जागृत रखकर कार्य करना, इस मार्ग पर हम तत्काल धन पड़ें, यही शिक्षा-क्षेत्र की स्वायत्तता-प्राप्ति का उपाय है। यही हमारा कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसी मेरी धारणा है।

विनोबा

आचार्यकुल कार्य की सही दिशा

मीन परम् सत्यतम्

आनन्द शंकराचार्य के एक वचन की याद आती है। हम उन्हें अद्वैतवादी मानते हैं। गानेश्वर को द्वैताद्वैत विवर्जित समरसवादी कह सकते हैं। गानेश्वर समरमाधस्या माननेवाले हैं। शास्त्र में मीन सर्वसम्मत होता है। फिर भी बोलने से जो कहा जाना है वह ऐसा ही कि वह मीनप्राय रहे। सब भाषाओं का समन्वय मीन में होना है। जब भाषा शुरू होती है तब मराठी हिन्दी नाम देने पड़ते हैं। आज टालस्टाय की पुण्यतिथि है। निन्सी की जयन्ती और पुण्य-तिथि मनाती हो तो मैं वर्ष के ३६५ दिन का कार्यक्रम (सत्पुरुषों की जयन्ती-पुण्यतिथि के निमित्त) देने में समर्थ हूँ। इसके कारण शिस्तों को पढ़ाना नहीं पढ़ाया और विद्यापियों को पनाई नहीं करनी पड़ेगी। टालस्टाय मार्क्स इस युग के प्रेरक थे। टालस्टाय प्रेरक भी हैं और तारक भी। इस देश में प्रेरक और तारक शक्ति इसके पहले ही महात्मा गौतमबुद्ध और महात्मागांधी में दिखायी दी। इनके पहले मैंने सेवाश्रम की शिक्षा-परिपद में बहुत कुछ कहा है। अब वचन करने का वाक्य सचा है। मैंने उस परिपद में तीन शब्दा पर जोर दिया था—योग उग्राम और सहयोग। अब तक शिक्षा के लिए बुनियादी तालीम मौनिक शिक्षा और वर्क-ओरियण्टेड आदि शब्द प्रयुक्त किये जाने थे। मैं उसे त्रिसूत्री शिक्षा-पद्धति कहूँगा।

आज कुछ शिक्षक मुझसे मिलने आये थे। उनसे मैंने पूछा कि इस समय स्वाति नक्षत्र चल रहा है। इस समय वर्षा हो जाय तो उनके मोती बनते हैं। आपके खेत में प्यार बोयी हो तो उसनी भी बढ़िया फल होगी। फिर हमारे आचार्यकुन के शिविर के लिए दो दिन वर्षा न हो तो भी चलेगा या वर्षा का होना आवश्यक है, इस दृष्टि से आपकी क्या दृष्टा है? उन्होंने कहा, 'खूब वर्षा होनी चाहिए। मैंने उह ३३ प्रतिशत अक देकर उत्तीर्ण किया। क्योंकि किसानों के प्रति उन्हें अपनत्व प्रतीत हुआ और उह लगा कि इस सम्मेलन की अपेक्षा कृषि का महत्व अधिक है। तब भी उह ३३ प्रतिशत अक ही दिये थे। इतने कम अक देने का कारण बताते हुए मैंने उनसे कहा, 'किसानों से अगर हम पूछें कि स्वाति नक्षत्र या पानी अगर बरसे तो दिन चाहिए या रात।' तो वे कहेंगे, 'रात की वर्षा श्रेयस्कर है, क्योंकि दिन में काम किया जा सकेगा।' अर्थात् हमारे और किसानों के हित में वैसे कोई फर्क नहीं है। दोनों ही वर्षा चाहते हैं। किसान धमनिष्ठ के नाते श्रम-परायणता का विचार करता है। हम आचार्य के नाते ज्ञाननिष्ठा से ज्ञानपरायणता का विचार करते हैं। इन दोनों शक्तियों का समन्वय हमारे लिए उपकारक है। वस्तुतः इन दोनों में विरोध नहीं है। जीवन में इन दोनों शक्तियों का उत्तम समन्वय निर्माण होना चाहिए। इससे शिक्षण उत्कृष्ट होगा और खेती भी उत्कृष्ट होगी। (आपके कथन में यह सामंजस्य नहीं था इसलिए ३३ प्रतिशत अक दिया)।

अगस्त्य का आदर्श रखें

ज्ञाननिष्ठा और श्रमनिष्ठा का समन्वय नया नहीं है। प्राचीन काल से यह आदर्श है ही। वेदों में अगस्त्य का वर्णन इस प्रकार है

“अगस्त्य क्षममान रयनित्र
उभी वारणो ऋषिह्य पुषोप”

कुदाल लेकर अगस्त्य छोड़ता था। इस उग्र ऋषि ने कृषि-कार्य के साथ-साथ ज्ञानोपासना भी जारी रखी थी। और दोनों वर्णों का पोषण किया था। वे द्रष्टा थे, ऋषि थे, परन्तु उनका स्वभाव उग्र प्रवृत्तिमय था। कुन्हाडी और कुदाल लेकर जंगल साफ करके उन्होंने दक्षिण भारत को बसाया। उनकी इस लगन के कारण सामंजस्य या समन्वय इन उभयविध वर्णों में हो गया था। ठीक-ठीक यही कार्य हमें करना है। सबसे पहले स्वयं अपने ही आचार्यों को यह क्रांति करनी होगी। समाज के श्रम-विभाग की दृष्टि से एक

वर्ग ज्ञानप्रधान होना चाहिए और दूसरा श्रमप्रधान । किन्तु ज्ञानप्रधान वर्ग को ६ घण्टे अध्ययन, अध्यापन करना चाहिए और दो घण्टे श्रम । इसी तरह श्रमप्रधान वर्ग को ६ घण्टे श्रम करके २ घण्टे ज्ञानोपासना करनी चाहिए । परमेश्वर ने मनुष्य को दस अंगुलियाँ दी हैं । लेखन की शिक्षा केवल तीन अंगुलियों में समानी है । हमें तो दस अंगुलियों की शिक्षा चाहिए । दस अंगुलियों—हाथों से श्रम करने की । तीन अंगुलीवानों के मन में विचार गुरु हुआ है कि पाँच अंगुलिवा पर ममज्ञाना करने में हज नहीं । ऐसा कोई समझोता इसमें न हा ।

महाराष्ट्र आचार्यकुल : प्रगति विवरण

गत अक्तूबर के आखिरी हफ्ते में पवनार आश्रम में महाराष्ट्र प्रदेश की आचार्यकुल परिषद सम्पन्न हुई। इस परिषद के फलस्वरूप आचार्यकुल संगठन को एक विशेष रचनात्मक आकार प्राप्त हुआ है। पवनार परिषद में आचार्यकुल का एक समिधान बना जो व्यवस्थापन और संयोजन की दृष्टि से एक ठोस कदम समझा जाना है। इस परिषद की प्रमुख फलश्रुति यह है कि समूचे महाराष्ट्र का एक प्रादेशिक स्तर का महामण्डल स्थापित हुआ, जिसके लगभग पचहत्तर सदस्य हैं। गत फरवरी की १०।११ तारीख की बोर्डी में महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल का जो सम्मेलन सम्पन्न हुआ उसके अंतर्गत आचार्यकुल की भी एक छोटी-सी बैठक हुई, जिसमें एक नयी कार्यकारिणी भी चुनाव हुआ। इस प्रदेश में आचार्यकुल की नीति और कार्य चलाने की पूरी ज़िम्मेदारी अब इस कार्यकारिणी के नथे पर है। गत चार साल से महि ज़िम्मेदारी अकेले मामा खोरसागर प्रमुख संयोजक की हैसियत से हल कर रहे थे। अब इस काम को एक ऐसा रचनात्मक और संस्थानुकूल स्वरूप प्राप्त हुआ है जिसके फलस्वरूप भविष्य में महाराष्ट्र के आचार्यकुल का कार्य संगठनात्मक व्यवस्था की पद्धति से जारी रहेगा।

आगामी वर्ष का आयोजन

इस नयी रचना के अनुसार गत मार्च महीने की ११ तारीख को जलगांव जिले के चासीसगांव नगर में नयी कार्यकारिणी की प्रथम बैठक हुई जिसमें

आगामी एक वर्ष की भुक्त के एक विधायक कार्यक्रम का सयाजन निर्धारित किया गया। इन कार्यक्रम के कुछ विषय पहले इस प्रकार हैं

(१) आचार्यकुल के संस्कार प्रसार के लिए शिक्षा संस्थाओं तक पहुँचाने का एक स्वाक्षरी अभियान निर्धारित हुआ है। आचार्यकुल की ज्ञाननिष्ठा, यमनिष्ठा और विद्यार्थी निष्ठा इन तीन निष्ठाओं के अभियान के माध्यम से समाज में शिक्षकों की नैतिकता की ओर कृतव्यनिष्ठा की जागृति का प्रसार महाराष्ट्र में किया जायेगा।

(२) इस वर्ष की धूमनास की छुट्टियों में अकाल की परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए चासीसर्गाव के मजदीक के एक दहात में २५ दिव का एक थन शिविर आयोजित हुआ है। इस शिविर में अकाल पीडित दहातो में मुश्किल पानी के दुर्भिक्ष को हटाने के लिए नये कुए खोदने का कार्यक्रम क्रियान्वित होगा।

(३) आचार्यकुल का जितना सम्पद सामान्यतः महाविद्यालयीय तथा माध्यमिक शिक्षकों के साथ रहता है उसकी तुलना में बहुत ही कम सम्पद प्राथमिक शिक्षकों के साथ होता है। आचार्यकुल का शिक्षक समानता का जो सिद्धान्त है उसके विपरीत यह स्थिति है। इस विषयता को दूर करने के लिए महाराष्ट्र के महामण्डल ने और कार्यकारिणी ने आगामी वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के सम्पद का क्षेत्र विस्तार करने का कार्यक्रम मजूर किया है।

कुछ नये उपक्रम

इन बहुलवर्ण प्रस्तावों के साथ आचार्यकुल के विकास के उद्देश्य से विषय महत्त्व के कुछ अन्य निर्णय भी मजूर किये हैं। उनका श्रोता नीचे लखे अनुसार है

(१) पवनार परिषद के आदेश के अनुसार कार्यकारिणी महाराष्ट्र के लिए आचार्यकुल का एक स्वतंत्र संकल्पपत्रक बना लिया है जिसमें केन्द्रीय संकल्प पत्रक के साथ मेल रखते हुए कुछ अन्य विचारों का भी जिक्र किया है।

(२) इस संकल्प पत्रक के अतिरिक्त दूसरा भी एक संकल्प पत्रक आचार्यकुल सहयोगी मित्रों के लिए बना है। सहयोगी मित्र वे कहलाते हैं जो आचार्यकुल के लिए मन में रुचि रखते हैं और अपना सहयोग भी देना चाहते हैं। किंतु राजनैतिक पक्ष के सदस्य रहने के कारण मूल संकल्प पत्रक की पशुमुक्ति की प्रतिष्ठा सेने के बारे में वे लाचार हैं।

(३) महाराष्ट्र में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का हामर सेवेण्डरी के साथ जोड़ रखनेवाला एक नया सुधारित पाठ्यक्रम १९७२ से निर्धारित हुआ है । यह पाठ्यक्रम अध्यापकों को समझाकर और उसका कुशलता से अध्यापन करने के लिए प्रेरणा देकर अने कर्तव्य के प्रति वफादारी की भावना बढ़ाने के लिए उद्बोधन शिविर चलाने का काम आचार्यकुल के एक निवृत्त मित्र नागपुर के श्री दि० ह० सहस्रबुद्ध बहुत लगन से कर रहे हैं । महाराष्ट्र के आचार्यकुल ने श्री सहस्रबुद्धजी को इस सेवा का आदरभाव से पुरस्कार किया है ।

(४) दिल्ली के गांधी स्मारक निधि द्वारा सर्वोदय विचार-परीक्षा का एक नया आयोजन फरवरी १९७३ से आरम्भ हुआ है । अन्य परीक्षा की तुलना में इस परीक्षा-पद्धति का स्वरूप केवल स्मरणशक्ति की परीक्षा का नहीं है । इस परीक्षा-पद्धति का स्वरूप भी के विलकुल-भाषुनिक ढंग का है । इसमें परीक्षा गीण है, विचार प्रधान है । अपनी पिछली बैठक में केन्द्रीय आचार्यकुल ने भी इस परीक्षा का आचार्यकुल के लिए पुरस्कार किया है । अतएव महाराष्ट्र आचार्यकुल कार्यकारिणी के सामने भी यह विषय विचाराधीन है । महाराष्ट्र में इस परीक्षा के ५ केन्द्र चालू हैं जिसमें नासिक का केन्द्र प्रयोग के तौर पर आचार्यकुल द्वारा चलाया जा रहा है ।

(५) शिक्षा-क्षेत्र में हमेशा सरकारी और गैर-सरकारी समस्याएँ अचानक उत्पन्न होती रहती हैं । इन समस्याओं के बारे में आचार्यकुल का भी एक स्वतन्त्र दृष्टिकोण होता है । महाराष्ट्र आचार्यकुल की कार्यकारिणी ने ऐसी समस्याओं के बारे में समय-समय पर अपना दृष्टिकोण निर्भयतापूर्वक प्रकट करने के लिए एक छांटो-सो समिति नियुक्त की है । यह समिति समस्याओं का संशोधन करेगी और अपना स्पष्ट अभिप्राय शासन और समाज तक पहुँचाने का प्रयास करेगी ।

व्यावहारिक कठिनाइयों

महाराष्ट्र के आचार्यकुल की तरफ़ी के इस कार्यक्रम में महामंडल और कार्यकारिणी को कुछ विरोध कठिनाइयाँ भी पेश आती हैं । इन कठिनाइयों का स्वरूप आर्थिक और व्यावहारिक है । कार्य के विस्तार के साथ योग्य कार्यकर्ताओं की कमी तीव्रता से महसूस हो रही है । लेकिन महाराष्ट्र में इन कठिनाइयों के निवारण का भी विचार हो रहा है ।

—ड० द० बेदरकर

शिक्षा पर सामाजिक नियंत्रण हो उमाशंकर जोशी

परिषद के अध्यक्ष श्री उमाशंकर जोशी ने प्रतिनिधियों से प्रिदाते हुए कहा 'शिक्षा मंत्र की छाया के विषय में आज जितना कहा जाता है वानावरण उतना बिगड़ा हुआ नहा है। अमा भी मुघर के लिए काफी अशरारत है। कोई क्या करे और क्या न करे यह विवाद का विषय हा मकान है तो भा हम वही न कहा कम पड रहे हैं हमने इनकार नहा दिया जा सकता। उन्होंने आगे कहा शिक्षा शासनमुक्त हो यह बात तोरदार शब्दों में कही गया। शासनमन्त्रि का यह कहना उतना ठीक नही है। कुछ-न-कुछ बचन रहते हो। वे हाने हा चाहिए। सुविन के इस माहौल में दो एन ने विरोध किया सब मुने लगा रि शासनमुक्ति का विचार सामाजिक नियंत्रण के विचार जितना ही महत्वपूर्ण है। हमने तोरनत्र स्वीकार किया है इसलिए शासन से कोई भी इकाई छुट्टी नही ल मरनी। लेकिन शिक्षण के राष्ट्रीयकरण की अपक्षा उस पर सामाजिक नियंत्रण रहना आवश्यक है। इस नियंत्रण में शिक्षक की भागीदारी रहनी चाहिए।

विद्यापीठों में राजनीति

आपने आगे कहा आज हमारे विद्यापीठों में राजनीति घुस गयी है। नेता बाहर हैं ऐसा लगता है। उह भीतर मन आने दो, ऐसा भी प्रतिपादित किया जाता है। नकिन बन्तुस्थिति यह है कि ये सब नेता भीतर घुस गये ह। प्रश्न यही है कि उह बाहर कैसे निकाला जाय ?

राजनीति छोडी नहीं जा सकती

शिक्षकों को राजनीति से अलग रहना चाहिए। विनोदानी के इस विचार से सहमति व्यक्त करते हुए उमाशंकरजी ने कहा शिक्षक ही क्या आज समाज का कोई भी वर्ग राजनीति नहा छोड सकता। दशिय राजनीति का हम जितना ही तिरस्कार करें ता भी दल रहने ही वाले हैं। लोकनत्र में यह अतिरहाय है। राजनीति दलदल ही होगी बहुत कुछ है भी लेकिन हम इस दलदल से अविष्ट रह भी नही सकते।

अन्त में उन्होंने कहा 'गुरु की इस भूमि में आज शिक्षक आया है। विद्यापियों से उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध टूट गया है। वह उसे जोडना चाहिए। इस जवाबदारी को वह स्वीकार कर ले तो शिक्षक के गौरव के दिन दूर नही।

बिहार आचार्यकुल सम्मेलन

स्वागत भाषण

आचार्यकुल में आचार्यप्रवर

आचार्य कपिल

सम्मान्य बधुजो !

आचार्य विनोबाजी द्वारा स्थापित अपने इस आचार्यकुल के अधिवेशन में हम आपका सादर स्वागत करते हैं। आज जब सोचने तक का अवकाश निकाल पाना कठिन हो गया है तो कुछ करने का सवाल तो और भी मुश्किल है। सोचते कुछ लाग हैं, विचारते और भी कम लोग हैं और इससे भी कम संख्या कुछ करनेवालों की है। कहते हैं कि महाकवि अकबर सरसैयद अहमद खाँ के समर्थन या पक्ष में कभी नहीं लिख सके। सर सैयद ने भी उनके समर्थन की कभी ज़रूरत नहीं समझी। वे जो भी काम करते थे, करते रहे। पर जब सर सैयद का इंतकाल हो गया तो उन्हो अकबर साहब ने लिखा—

‘हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था,
न भूयो फर्क जो है कहनेवाले करनेवाले में।’

इसलिए चिन्तनशील आचार्यगण आपका कष्ट करके यहाँ पधरना हमें अच्छा लग रहा है और यह भी लग रहा है कि आप कुछ सोचना, विचारना और करना भी चाहते हैं। तभी तो आपने यहाँ आने की कृपा की। हम आपका महसान मानते हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हैं।

आज जहाँ हम मिल रहे हैं यही सन् १९६८ में विनोबाजी भी पधारे थे। हमने ‘जा दिन सत पाहुने आवत’ गाकर उनका स्वागत किया था। इसी प्रांगण में उन्होंने दस दिनों का प्रवासकाल बिताया था। विनोबा कॉलेज में आये और यहाँ रहे, इसका भी एक विस्सा है।

विनोबा का कार्यक्रम जब मुगेर ने लिए बना तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वे किसी विद्यालय के प्राणन में ही ठहरेंगे। ठहरने के लिए पढाव के लिए कोई नेता अधिनेता सेनापति या सन सभासी किसी विद्यालय को क्यों चुनेगा ? उसे तो परिमदन चाहिए वगला चाहिए या मठ चाहिए। पर आचार्य विनोबा ने विद्यालय की ही खोज की और उन्होंने निस्संकोच भाव से पूरी आत्मीयता के साथ इस प्राणन में प्रवेश किया। दस दिनों तक हमें अपने साहचर्य का सौभाग्य मिया। वे दस दिन कालज की चिन्गी की तबारीस में अच्छे-से-अच्छे दिनों की गिनता में रह। दस दिनों में जानेज की रुटीन और उनकी अपनी रुटीन में एक ऐसा सामंजस्य उनके पावन व्यक्तित्व ने स्थापित कर दिया कि हम सब एक हैं ऐसा बोध होता रहा। उह छाना से भी बहुत कुछ कहता था। उन्होंने उनसे कहा भी। वे उनके साथ एन०सी०सी०की परेड तक मैं शामिल हुए। छात्रा बासा की कोठरी-कोठरी में जाकर टगे हुए कैंलेंडरो को भी हटवाया—ओ या तो उनक अधीनको को करना या या मुझे। कनिज का घटा एक दिन जब नहीं बजा तो सौम्य विनोबा को बिता हो गयी। दूसरे ही दिन आचार्यकुल की परिवर्तना को अभिव्यक्ति दी और कहा आचार्यों तुम अपनी हैमियत का अगर उठाओ। उन्होंने शिक्षा की स्वायत्तता का प्रश्न उठाया और उसका समर्पण करते हुए कहा कि यह सभी सम्भव है जब आचार्य आचार्यत्व के धर्म को निभायें।

इसलिए आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी के सदस्य मैं हम फिर आपका स्वागत करने हैं। पूसा में आचार्यों की एक सभा मैं बोलते हुए एक बार विनोबा ने कहा वे इस सभा में स्वास्थ्य की दृष्टि से आने की नहा साध रहे थे। पर आ इसलिए गये कि यह आचार्यों की सभा है पडितो का सभा है। ये तो किसी बिन्दु पर एकमत होते नहीं हैं। इसलिए यलो एक बिन्दु उनक विचार विमर्श के लिए दें। विचार का वही बिन्दु आचार्यकुल का मूल है उसकी जड़ है। हम वैमर्ष के लिए गहो पाडित्य के प्रभाव के प्रदर्शन के लिए भी नहा धर्तिक क्रिया की एकता के लिए एकमत होना चाहते हैं। एक क्रिय भवेमित्र —एक क्रियावाले स्वत मित्र हो जाते हैं और मित्रो की राय भी एक होती है। देशकान का यह तकाजा स्वीकारना चाहिए—इनकारने का खतरा हमें नहीं लेना है। इस देश में आचार्यों ने ही जीवन के सूत्र लिखे हैं दिम्भ्रमिओ को दिशा दी है और जन-मानस को तमस से ज्योति में लाया है।

विहार की विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी रही है कि यहाँ के लोग काम शुरू जरूर कर देते हैं। थोड़ा कर थोड़े पर सुस्ताना चाहते हैं और अगर

सुस्ताने का सुअवसर उह मिल जाता है तो वे सो जाना चाहते हैं। आचार्यकुल की भी यही स्थिति रही। हम छिटपुट डग से ही अभी तक कुछ कर सके हैं। केन्द्रित होकर राज्य स्तर पर खड़े होकर फैलने की वह चेष्टा हम नहीं कर सके जिसकी अपेक्षा थी। आज यह पहला दिन है कि हम सारे राज्य से आकर इकट्ठे हुए हैं। हम आशा करना चाहते हैं कि अब फिर जीत गही होगी। बिना सहाय के कोई आन्दोलन चल नहा सकता है। इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। आचार्यकुल विचार भी है और बिनारा का आन्दोलन भी।

हमने आपका बुला लिया है। आप आ भी गये। पर यह सब कुछ बात की बात में ही हो गया है। रामजी बाबू ने रामनारायण बाबू से बातचीत की और फिर इसमें महादेवजी शामिल हो गये। तब हुआ कि यह अधिवेशन यही हो। मैंने अपने सहयोगियों से भी राय-मशविरा लिया। करना तो सब कुछ उहा का था पर वे भी र जी हो गये। फिर हाँ और नहीं के बीच की जा मेरी मन स्थिति की वह निष्पत्ति पर आ गया और अधिवेशन आज हो रहा है। इसे हम स्वागत समिति के सन्सों तथा अपने शुभचिन्तकों के साथ अपना सौभाग्य मानते हैं। भीड़ चाहें छोटी हो या बड़ी खोड़ी असुविधा होगी ही, तकलीफ हागी ही पर आप आचार्यगण निश्चय ही क्षमाशील होंगे। सारे दोषों का, दुर्नियों का ख्याल नहीं करेंगे ऐसी आशा है।

हम अपने विशिष्ट अतिथियों का भी अभिनन्दन-वन्दन के साथ स्वागत करते हैं। सम्मान्य दादा जा आचार्यों में भी घमाँघिकारी हैं उनके पधारने से हमें बड़ा सतोप हुआ। अपनी इस अवस्था में भी वे हमें नसीहत देत रह रहे हैं और आज भी हम उनके आशीर्वाद के आकाक्षी हैं। सम्मान्य महादेवीजी अपने स्वास्थ्य के कारण नहा आ सकी हैं इसका हमें खेद है। बिहार आचार्यकुल के संयोजक डा० रामजी सिंह तो हमारी स्वागत समिति के भी सदस्य हैं और हमारे परम प्रिय छात्रों में से एक विशिष्ट छात्र हैं। इन्होंने हा अपने महाविद्यालय की यह सुयश देना चाहा इसलिए अपने घर में ही उनका स्वागत करते हमें हर्ष हो रहा है। भाई बशीरजी अभी कुछ जिनो से प्रतिकूल परिस्थितियाँ में पड़ गये हैं। वे हमारे केन्द्रीय कुल का संयोजक हैं। वह भी अपनी विपत्ति के कारण नहीं आ सके हैं इसका हमें दुःख है। हम उनके साथी श्री बहुगुणाजी का स्वागत करते हैं।

अन्त में फिर अपनी नृत्तियों के लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं और स्वस्तिनोस्तु प्रियेभ्य बहते हुए आपके कल्याण-मंगल की कामना करते हैं।

समग्र क्रान्ति की खोज लक्ष्य बने

दादा धर्माधिकारी

मैं स्वायत्ताध्यक्ष महोदय का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि थोड़े-से शब्दों में वह कुछ कह देने की बजाय उनको शामिल है। उनका भाषण इतना संक्षिप्त किन्तु इतना सारगर्भित है कि मेरे जैसे चौराहे पर भाषण करनेवाले के लिए वह कठिन काम है। वे सचमुच धर्मवाद के पात्र हैं, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मैं भी उसी तरह संक्षिप्त भाषण करूँगा। मुझे सदाप में भाषण करना आता नहीं है, किन्तु फिर भी आपके बीच आ गया। संयोजकजी के प्रतिवेदन को सुन कर मुझे न्यूटन का स्मरण हुआ। उसने कहा है कि ज्यों-ज्यों हमें यह भान होता है कि हम कितना कर पाये हैं उतना ही प्रतीत होता है कि हम कितना नहीं कर पाये हैं।

जीविता और जीवन का अनुबन्ध

मैं इधर कई वर्षों से एक बात के विषय में सोचता रहा हूँ। आज हम जिस समाज में रहते हैं उसमें दो वर्ग हैं। मैं वर्ग कोई मार्क्स की परिभाषा में नहीं कह रहा हूँ बल्कि मेरा आशय यह है कि आज समाज में दो तरह के लोग हैं। एक तो वे हैं जिनके पेट में भूख है, जो भूख के और किसी तरह का विचार ही नहीं कर पाते। यह वर्ग कभी भूख की भाषा बोलता है तो कभी अत्याचार की भाषा बोलता है। किन्तु इन दोनों में से किसी प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तन की बात नहीं हो पाती है। अठारहवीं की ज्वाला में सारी सांस्कृतिक

विरासतें, धर्म आदि सब स्वाहा हो जाता है। दूसरा वर्ग वह है जो पेट है। इसे सत्तार की हर चीज पेट में भरने की लालसा रहती है। यह एक प्रकार का व्यापारवाद या सौदेबाजी है। मनुष्य के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह बाजार में न रखता हो। आज बाजार में रखे गये सौदे ही सौदे हैं। धर्म, विज्ञान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर सभी आज बाजार में बैठ गये हैं और इनसे हमने आशा रखी है कि इसमें से सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होगा। यानी हम जहर के बीज बोकर अमृत प्राप्त करना चाहते हैं। किन्तु यह हो नहीं सकता। भूख मनुष्यता का हनन करती है तो पेटपन ने सत्तार की हर वस्तु को और मनुष्य को भी वस्तु बना दिया है, सौदे के बाजार में रख दिया है। इसमें से कोई सस्कृति नहीं पनप सकती। अब प्रश्न यह है कि क्या आज कहीं कोई ऐसा समूह है जो पेट के साथ और भी कुछ रखता है जिसके पास पेट के साथ वृद्धि भी है? क्या आप आचार्यों का ऐसा वर्ग (समूह) हो सकता है जो पेट के साथ वृद्धि भी रखता हो? यह एक ऐसा समूह है जो जीविका के साथ जीवन भी रखता है। जीविका एवं जीवन के अनुबन्ध से ही सस्कृति का सृजन होगा है। अध्यापकों का वर्ग ऐसा है जो पेट के साथ वृद्धि था, जीविका के साथ जीवन का परिपोष कर सकता है। मनुष्य का जीवन उसकी आदिम स्वतन्त्रता में है। आज दो छावनियाँ हैं। एक छावनी में राजनैतिक स्वतन्त्रता और कुछ हद तक आर्थिक सुस्थिति है, वैचारिक स्वतन्त्रता कुछ है किन्तु समानता नहीं है। आर्थिक सुस्थिति होते हुये भी असमानता हो तो भी जीवन विषम हो जाता है। दूसरी छावनी है जहाँ किसी मर्यादा तक आर्थिक समानता है किन्तु वहाँ राजनैतिक और वैचारिक स्वतन्त्रता का अभाव है। वहाँ मनुष्य एक मुसीब पशु है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम अन्धुदय के साथ प्राप्ति कर सकते हैं? क्या दुनिया में ऐसा पुरुषार्थ नहीं हो सकता जहाँ मनुष्य की इन दोनों आनाझाजों की पूर्ति साथ साथ हो सके? इसे मैं सांस्कृतिक समस्या मानता हूँ।

पैन अमरीका का क्रान्तिद्रष्टा है। उसने 'राइट्स ऑव मैन' पुस्तक लिखी है। मुंबरात ने मनुष्य की बौद्धिक स्वतन्त्रता के लिए ही आत्मबलिदान स्वीकार किया। फ्रांस की सामाजिक क्रान्ति सांस्कृतिक क्रान्ति नहीं थी। रूस, चीन में भी राजनैतिक एवं आर्थिक क्रान्ति सांस्कृतिक क्रान्ति से अलग हो हुई है। किन्तु यदि क्रान्तियाँ इस प्रकार अलग अलग हों तो फिर ये क्रान्तियाँ समग्र नहीं होतीं। इनमें से कोई भी क्रान्ति समग्र नहीं था। हमें इसे समझना होगा कि हमें इस देश में समग्र क्रान्ति की सोच करनी है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी

नाथि राजनैतिक और आर्थिक क्रान्ति के बाद अलग से फिर सांस्कृतिक क्रान्ति की आवश्यकता न रहे। इसी खोज के लिए आचार्यों की विशिष्टता है। मनुष्यता की यह एक बड़ी सेवा होगी।

बुद्धि पर लेबुल न रहे

मनुष्य की स्वतन्त्रता का अर्थ विचार की स्वतन्त्रता नहीं, विचार करने की स्वतन्त्रता से है। इसलिए हम विचार का प्रचार न करें, विचार करना सिखायें। हम विचार न दें। मनुष्य को विचार देना उस पर प्रभाव डालना, उसकी आत्मा के साथ बलात्कार करना है। आज तब मानवात्मा पर ऐसे ही बलात्कार किये गये हैं। धर्माग्र्यक्षो पैगम्बरों अवतारों एवं धर्मों ने मनुष्य के विचारों का इस कदर सैनिकीकरण किया है जिनका सेना ने भी नहीं किया। धर्म ने कहा है कि धर्म प्रथी के अनुचाल अनी बुद्धि करलो। यानी बुद्धि धर्म प्रथ की अनुगामिनी, अनुचरी बन गयी। किन्तु बुद्धि का स्थान कोई नहीं ले सकता। क्या मानव की अन्तरात्मा का कोई स्थान ले सकता है? यह स्थान धर्म, ग्रन्थ, पीर या पैगम्बर, अवतार, राजा, गुरु या नेता कोई नहीं ले सकता। यदि हम यह होने दते हैं तो अपने को मूल अधिकारों से वंचित कर देते हैं। विचार के सम्बन्ध में दो बातें हैं। विचार जब संगठित हो जाता है तो वह सम्प्रदाय बन जाता है। उसमें से फिर विचार का प्रवाह रुक हो जाता है। सम्प्रदाय यानी जमा हुआ विचार। इस प्रकार का विचार आक्रामक और अतृप्तिपूर्ण होता है। अपने विचार का दुनिया में दूसरे विचारों को परास्त करने में लगाने का, यानी वैचारिक दिग्विजय करने का विचार यही से पैदा होता है। ये विचार जब राजनैतिक रूप ग्रहण करते हैं तो साम्राज्यवाद और तानाशाही को जन्म देते हैं। इस प्रकार का संगठित और आक्रामक विचार ही पार्टी बन जाता है। इस हालत में विचार रहता है किन्तु विचार की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए आज हम जब कहते हैं कि विद्या सत्ता-निरपेक्ष होनी चाहिए, तो मुझे यही डर है कि कहा हमारी विद्या साम्प्रदायिक न बन जाय। इस प्रकार का अवसर सत्ता है। लाला लाजपत राय ने 'राष्ट्रीय शिक्षा' नामक अपने ग्रन्थ में कहा है, "हम जो राष्ट्रीय शिक्षण दें उसे साम्प्रदायिक होने से बचायें। साम्प्रदायिक शिक्षण में शिक्षण प्रधान हो जाता है मनुष्य गौण बन जाता है।" आज तो शिक्षा में भी लवुली का बाजार गर्म है। किन्तु तब यह सत्ता-निरपेक्ष शिक्षण क्या हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन या पारसी शिक्षण होगा? आज सनातन धर्म कालेज, जैन कालेज, मुस्लिम कालेज आदि होते हैं, किन्तु इन कालेजों में शिक्षण तब पूर्णतः डिनामिनेशनल बन जाता है। किन्तु

मनुष्य की बुद्धि पर कोई सेतुन नहीं लगना चाहिए। शिक्षण को मनुष्य की अंतरात्मा की आवाज बनने दो। बौद्धिक स्वतंत्रता का अर्थ ही है नरक में भी जाने की स्वतंत्रता। मनुष्य का मनोविज्ञान हमेशा सस्वार से मुक्त होना चाहिए। टेरिच ने अपनी पुस्तक में यही कहा है कि मानव मन को सस्वार-मुक्त होना चाहिए। सा विद्या या विमुक्तये का यही अर्थ है न। यही मनुष्य की प्रतिष्ठा है। उसकी अंतरात्मा की आवाज भी यही है। इस आवाज का गुंजने दो। मनुष्य की अंतरात्मा की आवाज गुंजने दो। शब्द आकाश का गुण है तो इस गुण का विकास होने दो। पेंन ने कहा, "मैं मनुष्य के अधिकारों की घोषणा करूँगा।" किंतु बाद को मोहनदास कर्मचंद गांधी नाम के मनुष्य ने कहा, 'मैं अधिकार और कर्तव्य का ऐसा समझस्य करूँगा कि दोनों में फर्क ही न रह जाय।'

आचार्यदुरु दिल-दिमाग मुक्त रखे

जमशेदपुर में मजदूरों ने वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल की। वे मेरे पास आये और कहने लगे कि मैं उनकी कुछ मदद करूँ। तो मैंने कहा, 'आपसी सुनियत यह घोषणा करे कि कामचोर मजदूरों को सजा मिलेगी।' तो उन्होंने कहा "इससे तो हम बरबाद हो जायेंगे। न हमारी सुनियत रहेगी और न हमारी लीडरशिप ही रहेगी।' आज तो लीडरशिप की सड़ाई चबती है न। आज तो भीड़ होती है। भीड़ यानी एमोर्फिक ब्लॉक ऑव पॉपुलेशन, जिनमें कुछ दिमाग नहीं होना। मानवना को ऐसी गिनती को भीड़ कहते हैं। भीड़ में शिर तो बहुत हात हैं किंतु दिमाग एक भी नहीं होना। आज का नेता चाहे धार्मिक, सामाजिक या राजनैतिक कैता भी हो उसे प्रचार की पद्धति और मनो-विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। आज के शिक्षण में कोई केश स्टडी नहीं होती। किसी आशुभी ने कहा कि एबरेस्ट २९ हजार फुट ऊँचा है तो दूसरे ने कहा कि हम तो इस पर कई बार चढ़ चुके हैं। केश स्टडी मनुष्य की नहीं मनुष्यता की होनी चाहिए। यही बात टिर्कनिक ने अपनी 'मारेनिटी एण्ड बिगान्ड' (नैतिकता और उससे आगे) में लिखा है कि मनुष्य के मन का भी शुद्धिकरण होना चाहिए। उसकी अन्तरात्मा का जागरण होना चाहिए। यह काम भीड़ में नहीं हो सकता, न यह किसी धर्म, गुरु, राजा, नेता, धीर, पंगम्बर अथवा धर्मगुरु या अनुसरण करने से ही हो सकता है। मनुष्य की प्रतिष्ठा, उसका ईमान, उसकी अपनी चीज है। इसलिए आचार्यदुरु का अपना दिल-दिमाग मुक्त रखना चाहिए। उसे गांधी, विनोबा, गाँडो-बाँडो किसी के पास नहीं रखना चाहिए। मैं कहूँगा कि उसे केवल कैपिटल आई के पास ही रखना

है। मैं हिन्दी व्याकरण का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ कि उसमें प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष बना दिया है। एक तरफ मनुष्य की अन्तरात्मा की आवाज और दूसरी तरफ मानवीय अन्तरात्मा का आवाहन होना चाहिए। आज इसी की आवश्यकता है। आज विश्व विद्यालयों में यह नहीं हो रहा है। आज तो वहाँ न विश्व है न विद्या ही है। वह सुद्ध धर्मवाद और मानववाद के अग बग गये हैं। अब इसमें से जो आदमी निकलेंगे वे निम नाप के होंगे ? उनका नाप उस कूमद्रूप का होगा, किन्तु वेडोंगे अखिल भारतीय कुर्मी पर। उसमें से क्या होगा ? हमने बचपन में एक कविता पढ़ी थी। पूसी बिल्बी लदन गयी तो उसे रानी के महल में रानी की कुर्सी के नीचे एक चूने के अनाया और कुछ नहा दिखाई दिया। यही आज के विश्व विद्यालय का दर्शन है। इसी दर्शन को लेकर जन वह नाँद पर गया तो उसने झडा अमेरिका का ही लगाया। आज का मनुष्य नक़्के पर जीनेवाला है। हमें योनगर में कहा गया कि आप नीचे (निवेन्द्रम्) से आये हैं। अब जमीन पर तो कोई उत्तर-दक्षिण नहा होता, नक़्के पर होता है। क्या हम इस नक़्के की दृष्टि से ऊपर उठ सकते हैं ? क्या वह हा सकता है कि हमारे विश्व विद्यालय विश्व की प्रतिबुद्धि बन सकें ? ऐसी प्रतिकृति जिसमें कहीं कोई गतिविधि नहीं है। यदि मानव आत्मा बिश्वरूपा है तो ज्ञान भी विश्व व्यापी है और मानव आत्मा ज्ञान से उत्तम है।

विज्ञान और अध्यात्म का केवल सामंजस्य नहीं बरन् दाना का एक समन्वय होगा। विज्ञान यानी वस्तुनिष्ठा, ऑब्जेक्टिविटी। जैसा है वैसा देखना, यह नहीं कि जैसा आप देखना चाहते हैं। बड़े पुरुषाने हमें चरम दिये हैं पर हमारी आँखें छीन भी हैं। हमें हमारी आँखें मिलनी चाहिए। इसके लिए जिस अजन की आवश्यकता हो वह मिलना ही चाहिए। यदि हम भी विचार उधार ही लें तो फिर निराशा ही होगी। एक शिक्षण शास्त्री है जो कहते हैं कि प्रतिभाशाली लोग बनाये जा सकते हैं। अतः प्रतिभाशाली लोगों की ओलाख बढ़ाओ। ध्यवहारवादियों ने कहा कि हम लोगों को लेकर तो जो चाहे बना लें मल्लाह, सिपाही, मजदारी या भिखारी, किन्तु बाइबिल में कहा गया है कि भगवान ने मनुष्य को अपनी शक्त में बनाया है। पर यदि उसे भगवान ने अपनी शक्ति में बनाया है तो वह कहीं भी भीतर होगी। वह सभी प्रकट होगी जब मंदिर, मस्जिद, गिरजा आदि में बैठा भगवान भी एक ही होगा। जहाँ भगवान दो हुए, वहाँ उसके दावेदार भी दो होंगे ही। भगवान को गद्दी के दावेदार का नाम ही शीतल है। जिसकी बुद्धि स्वतंत्र होगी वह वस्तुनिष्ठ होगी। यह है विज्ञान।

दूसरी चीज है मानव-निष्ठा, जिसका शिक्तिज कही नहीं है। आज का यह विज्ञान तो सम्प्रदाय का अनुचर है। आज भाषिक युनिवर्सिटी का झगडा, लिपि का झगडा हो गया है। विनोबा कहते हैं कि लिपि तो एक करो। शिक्षण सरकार निरपेक्ष हो, किंतु सार्वभौम हो। त्रिवेन्द्रम् एव श्रीनगर का छात्र, द्वारका एव कोहिमा का स्नातक एक साथ बढ सके। इसमें केवल एकरूपता ही नहीं, रिस्तेदारी हो। अतः शिक्षण का माध्यम एक ही होना चाहिए। भाषा अपने लिए नहीं दूसरों के लिए होता है, अभिव्यक्ति के लिए होती है। मनुष्य की तीन विशेषताएँ हैं—यह अपनी भाषा भी सीखता है, दूसरे की भाषा सीख सकता है और उसकी भाषा का अनुवाद हो सकता है। विश्व विद्यालय तब बनेंगे जब मनुष्य के साथ मनुष्य का सम्पर्क—यानी सीधा सम्पर्क हो। यदि कहीं दुभाषिया मूल्य हुआ तो क्या होगा ? पर आज विश्वविद्यालय ही भाषिक विवाद में उलझे हैं। पर बात बन्द को जा सकती है खत्म नहीं की जा सकती। आज का सत्ताधीश और आज का सम्पत्तिशाली मनुष्य के विश्व पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। सुद्धिवादी वाद के नाम पर सारे विश्व को पदाङ्गान्त करना चाहता है। इसमें हमें अपने आप को उधारना है। यही मनुष्य की बौद्धिक स्वतन्त्रता है। आत्मवान् पुरुष में ही सामर्थ्य होता है। सामान्य मनुष्य के हाथ में हथियार नहीं, दीलत नहीं, हुकूमत नहीं, जो हमारी जिन्दगी को सुखी करता है वही हमारे सुख का आधार होगा। हमें मनुष्य-मनुष्य के बीच से हर प्रकार के बिचौलियों, पड़े, पुजारी, भौलवी आदि को हटाना होगा। बाजार में बिचौलिया है, भ्यापारी है, मन्दिर में पुरोहित, नागरिक जीवन में नेता, यह सब बिचौलिये हैं। इन सबको हटाना होगा। तीसरी चीज यह है कि शिक्षा पर सरकार का नियन्त्रण नहीं हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी कौन-सी सत्ता होगी जो सारा-का-सारा शिक्षण भारत में समान कर सके, तानि आगे आनेवाला बच्चा केवल मुक्त हो ? तो इसके लिए मेहरबानी करने अपनी छाया इन पर मत डालिए। यह षडाल की छाया है। उससे गभयनी की भी बचाइये। विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वय हो इसके लिए और हमारे लिए कोई भाषा पराई नहीं है। अंग्रेजों राज पराया था दोस्तपियर पराया नहीं है। बम्बूसिंघस भी पश्चिम में जाय, गोर्की भी भारत का नहीं किन्तु ये सब हमारे अपने ही हैं। समाज-परिवर्तन के लिए नैतिकता की खोज की जानी चाहिए।

बिहार आचार्यकुल : प्रगति विवरण

डा० रामजी सिंह

आदरणीय अध्यक्षजी, पूज्य धादा, गुरुजनों एम बन्धुओं,

॥ दिसम्बर १९६७ को पूसा रोड में बिहार के शिक्षाविदों की गम्भीर परिपद के समक्ष शिक्षा की समस्या पर जो चिन्तन प्रस्तुत किया गया उसे हम शिक्षा-शास्त्र के क्षेत्र में एक बिस्फोट कह सकते हैं। ज्ञान एवं कर्म के पार्यवय के कारण शिक्षा की शकुलता रो रही है। इसीलिए एक ओर तो उन्होंने आचार्यों के लिए ज्ञान-निष्ठा, विद्यार्थियों के लिए वात्सल्य एवं तटस्थ वृत्ति पर जोर दिया तो दूसरी ओर राजनीति को शिक्षा के लिए खतरा बताते हुए न्यायालय की भांति शिक्षा-विभाग को भी शासन से ऊपर रखने की बात को समाज में मान्य

करने का विचार रखा। उस सभा में भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डा० त्रिगुणसेन एवं केन्द्रीय शिक्षा सचिव श्री नाइक भी थे। बिहार सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री कर्पूरीजी ने तो यह बैठक ही आहूत की थी। दूसरे दिन ८ दिसम्बर को उसी गोष्ठी के समापन भाषण में विनोबाजी ने शिक्षा में अहिंसक क्रांति का विचार रखते हुए यह अफमोस प्रकट किया कि उन्होंने शिक्षा एवं शिक्षकों का काम पहले नहीं उठाया। ९ जनवरी '६८ को जब वे बिहार विश्वविद्यालय के अगान भूखण्ड, मुजफ्फरपुर में आचार्यों के बीच पहुँचे और शिक्षा के प्राप्ति में पुलिस के प्रवेश का दुःखद दृश्य देखा तो शिक्षकों से अनील की कि व करना नैतिक असर डाल कर समाज में अशान्ति-शान्त का सामाजिक दायित्व सम्भालें। इसके लिए उन्होंने केवल शिक्षा में अहिंसक क्रांति की योजना ही नहीं रखी बल्कि इसके लिए शिक्षकों को सकीर्ण साम्प्रदायिक और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोक-नीति से जुड़ने को कहा। इसके लिए बहो सबल्य पत्र का भी निर्माण हुआ। पटना में भी उन्होंने इसी विषय पर शिक्षाविदों से चर्चा की।

अब तो बाबा जहाँ जाते किसी-न-किसी शिक्षण-संस्था में ही अपना प्रवास रखते। फरवरी १९६८ में लगभग दस दिनों तक बाबा मुंगेर के आर०डी० एण्ड डी० जे० कालेज में रहे और शिक्षकों से व्यक्तिगत एवं सामूहिक चर्चा कर १६-२-६८ को उन्होंने समाज का मार्गदर्शक बनने के लिए आह्वान करते हुए अध्यापकों के लिए एक भाईचारा बनाने का भी सुझाव दिया। मुंगेर से फिर बाबा ६-३-६८ को भागलपुर विश्वविद्यालय पहुँचे और उसी दिन बड़ी आनुरता से पहले कुलपति, कुलसचिव एवं कुछ बरिष्ठ अध्यापकों के साथ इस विषय पर चर्चा की, जिसे उन्होंने उपनिषद की सत्ता दी। फिर ७-३-६८ को भागलपुर विश्वविद्यालय के लगभग ५०० से शिक्षकों के बीच टी० एन० डी० कालेज हाल में उन्होंने सर्वप्रथम आचार्यकुल शब्द का उच्चारण किया। शिक्षकों का धर्मारम्भ जो आज नीचे गिर गया है उसे देखकर उन्होंने अपनी अन्तर्वेदना व्यक्त की और शिक्षकों से अपने और अपने ही कर्तव्य को पहचान कर सामान्य स्तर से ऊपर उठने की अपील की। दूसरे दिन ८-३-६८ को प्राचीन पहीन मुनि के आश्रम एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पार्ष्वभूमि, आधुनिक महनगाँव में विनोबाजी ने आचार्यकुल की स्थापना की। इसके बाद आचार्यकुल की भावना फैली गयी और बाबा की जिज्ञासी को यह आखिरी लेखन सप्ताह घेहवरीन सनक बन गयी। उन्होंने आचार्यकुल में योगदान देने के लिए सरस्वती के समस्त करद पुत्रों का आह्वान किया। प्रसिद्ध साहित्यकार जेनेन्द्रजी ने

अप्रैल '६९ में बिहार में एक सप्ताह का ममय दिया और उनका कार्यक्रम पूर्णगढा, भागलपुर, बेगूसराय, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, पटना एवं गिरीडीह में रखा गया । विद्वत वर्ग ने इस विचार का सर्वत्र आदर दिया ।

३० दिसम्बर '६९ को ख० अ० शिक्षा सम्मेलन के अवसर पर आचार्यकुल मंच से एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें डा० घमाधिकागी, जयप्रकाश नारायण, बंशीधर श्रीवास्तव, आचार्य कपिल आदि ने लगभग १० हजार शिक्षकों के समक्ष आचार्यकुल का विचार रखा । ३१ दिसम्बर '६९ को पटना में केन्द्रीय आचार्यकुल के संयोजक बंशीधरजी एवं जैनेन्द्रजी आदि के सामने बिहार आचार्यकुल का नवगठन हुआ, जिसमें पटना विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुनरति श्री महेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, आचार्य कपिल उपाध्यक्ष, डा० रामजी सिंह संयोजक एवं आचार्य राममूर्ति सदस्य हुए । इसी समिति को भार दिया गया कि सम्मेलन तक के लिए एक संघर्ष समिति बना ले । तदनुसार २१ व्यक्तियों की एक समिति गठित की गयी । लेकिन हमारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सम्पूर्ण समय देकर आचार्यों के बीच घूम कर इस विचार का संगठन करे । परन्तु इसी समय केन्द्रीय आचार्यकुल ने श्री० कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा को सहरसा में आचार्यकुल का संगठन करने के लिए भेजा । चूंकि सहरसा रामस्वराज का अखिल भारतीय मोर्चा है इसलिये बहुगुणाजी ने सहरसा में ही सघन रूप में आचार्यकुल का काम किया । परन्तु बिहार के दूसरे स्थानों पर काम करने के लिए भी उनका सहयोग प्राप्त हुआ । १७ १८, १९ अप्रैल, १९७१ को मधेपुरा में सहरसा जिला आचार्यकुल का प्रथम शिविर तथा सम्मेलन हुआ । फिर तो जिले के २१ प्रखंडों में प्रखंड आचार्यकुल समितियाँ बनी और ७०२ सदस्यों ने निष्ठापत्र भरे । अभी सहरसा जिला आचार्यकुल का दूसरा सम्मेलन १३ नवम्बर, १९७३ को सुपौल में हुआ । वहाँ सादा सुरेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष एवं डा० जयदेव मंत्री हैं । सहरसा में पुष्टि-अभियान में शिक्षकों ने अभूतपूर्व योगदान दिया । सहरसा के बाद सघन काम पूर्णिया जिले के रूपौना एवं भवानीपुर प्रखंडों में हुआ । दिसम्बर '७१ के अन्त में वहाँ के २०० शिक्षकों का एक त्रिविधस्रोत शिविर हुआ । उन प्रखंडों में आचार्यकुल ने अपने लिए आचार संहिता बनायी । विशाल-विकास के ठोस कार्यक्रम बनाये तथा शिक्षा की स्वायत्तता के विषय में व्यावहारिक योजना बनी । यहाँ वसोवृद्ध नेता श्री बैठनाथ प्र० चौधरी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है । भागलपुर प्रमंडल के शिरोपनिदेशक श्री उमाप्रसाद सिंह ने आचार्यकुल द्वारा चलनेवाली इस योजना को सब प्रकार का सहयोग देने का वचन दिया । पूर्णिया जिला आचार्यकुल के संयोजक डा० अरुण शास्त्री हैं और वहाँ आचार्य-

कुल की एक जिला स्तरीय समिति है किन्तु भवानीपुर, रूपौली के अतिरिक्त और कहीं उल्लेखनीय काम नहीं हुआ है। पूर्णिया के बाद गया का स्थान आता है। गया में आचार्यकुल की स्थापना म भाई केशव प्रसादजी ने बड़ा प्रयास किया है। वहाँ के आचार्यगण शुरू से ही सजग एवं सतर्क हैं। वहाँ समय-समय पर आचार्यकुल के सदस्यों ने जगह-जगह एवं दो दिनों के लिए इकट्ठे होकर अपनी अपनी समस्याओं पर चर्चा की है। ऐसी गोष्ठियाँ सोखोदेवरा, बजीरगज, गया, बेला एवं टेकारी में हुई। गया कालेज के भूतपूर्व एवं दिवंगत प्राचार्य डा० भुनेश्वर नाथ मिश्र माधव हमारे साथ रहे। डा० कुबेर चन्द्र प्रकाशजी के सहयोग से हमने मगध विश्वविद्यालय में भी प्रवेश किया। गया जिला आचार्यकुल का प्रथम सम्मेलन वैनागज में '७१ में हुआ जहाँ दिनकरजी मुखर्ज्य अतिथि थे। इसका दूसरा सम्मेलन अभी-अभी २६ २७ जनवरी '७३ को टेकारी राज हामर रोकेट्टी स्कूल पर हुआ। इस अवसर पर डा० रामतत्वका शर्मा, डा० यचनदेव कुमार, श्री नानेश्वर बहुगुणा विशेष अतिथि थे। जिला आचार्यकुल के अध्यक्ष श्री राजेन्द्रप्रसाद सिंह एवं मंत्री श्री गिरिजानन्द मिश्र हैं। गया के बाद हम मुंगेर का स्मरण कर सकते हैं। असल में मुंगेर इसका घर ही है। साथ-साथ सुगन्धा में श्री महादेव झा सुदैव खडगपुर में प्रो० रामचरित्र सिंह एवं मुंगेर कालेज में प्रो० जाविर हुसैन, बेगूसराय में प्रो० गोरेश्वर प्रसाद सिंह धर्मपुरी, श्री हेमनाथ सिंह एवं श्री लक्ष्मी कान्ताजी इसके मुख्य प्राण थे। मुंगेर का सारा सर्वोदय परिवार आचार्यकुल का अपना परिवार है। आखिर लोक शिक्षक होने के नाते वे भी तो आचार्यकुल के सदस्य हैं ही। मुंगेर के बाद भागलपुर आता है जहाँ आचार्यकुल शब्द का प्रथम उच्चारण हुआ और जहाँ इसका जग भो हुआ। जिले में शुरू में तो घड़ले से २२०० सदस्य बन गये लेकिन पीछे लगा कि यह भीड़ भाड़ ठीक नहीं। तो भी आचार्यकुल का विचार फँसाने के लिए लगभग ५० शिक्षकों की कई गोष्ठियाँ की गयी। उत्तर भागलपुर में अधिक गोष्ठियाँ हुईं। इसमें शिक्षा विभाग का योगदान अधिक रहा। भागलपुर शहर में आचार्यकुल, तरुण शांतिसेना एवं गांधी शांति प्रतिष्ठान के संयुक्त वस्त्रावधान में प्रत्येक सप्ताह एवं विचार-गोष्ठा पिछले चार वर्षों से निर्वाह रूप से हो रही है।

भागलपुर में आचार्यकुल का विचार फँसाने के लिए जैनेन्द्रजी, प० रामानन्द मिश्र, संयोजक बंगीधर श्रीवास्तव, बहुगुणाजी आदि आये। प्रिंसिपल कपिल ने विश्वविद्यालय का विद्वत परिषद के समक्ष भी एक बार इसका विचार रखा। भागलपुर के साथ हम मुजफ्फरपुर को नहीं भूल सकते। वहाँ

यद्यपि पुराने सात सदस्य हैं फिर भी प्रिंसिपल गौड ने यदावदा विचार गोष्ठियों का आयोजन किया। जे० पी० ने भी शिक्षकों को कई बार सम्बोधित किया। ग्रामस्वराज्य की प्रयोगशाला मुमहरी में गुजरात के शिक्षाशास्त्री ज्योति भाई ने मुमहरी प्रखण्ड के शिक्षकों के सहयोग से वहाँ की एक शिक्षा योजना बनायी और उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। वहाँ बशीधरजी एवं बहुगुणाजी भी जाकर कुछ दिन रहे। मुसहरी प्रखण्ड में प्रखण्डस्तरिय आचार्यकुल की तदर्थ समिति भी बनी, साथ-साथ प्रखण्ड की एक योजना भी तैयार हुई है। दरभंगा में एक बार जेनेट्रजी के कार्यक्रम एवं शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित कुछ विचार-गोष्ठियों के अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर पाये। यद्यपि दरभंगा दो विश्वविद्यालयों का मुख्यालय है। राजी में भी प्रिंसिपल एम० आर० चौरसिया एवं श्री कुल्लानन्द गिरि तथा क्षेत्रीय शिक्षोपनिवेशक के सहयोग से आचार्यकुल का विचार यदावदा शिक्षक-समाज के सामने रखा जाना रहा है। जमशेदपुर में भी मुहम्मद अयूब एवं डा० सत्यदेव ओझा तथा अन्य मित्रों के सहयोग से शिक्षकों की कई गोष्ठियाँ की लेकिन रुग्ण विधिवत नहीं हो पाया है। सपाल परगना में भी बिनोबाजी के प्रवास के समय साहेबगंज कासेज एवं देवघर में आचार्यकुल की सभा हुई।

दरभंगा—नवम्बर १९७१ में जिला पदाधिकारी श्री नन्दजी सिंह ने बिहीन प्रखण्ड के शिक्षकों को एक गोष्ठी बुलायी। इसी अवसर पर बिहीन प्रखण्ड आचार्यकुल की स्थापना की गयी जिसके अध्यक्ष प्रभवलाल हुए। ५० शिक्षकों ने निष्ठा व्यक्त की थी।

आरा—२० अप्रैल एवं १ मई '७२ को शाहाबाद जिला प्राध्यापक सम्मेलन के समय बहुगुणाजी ने आचार्यकुल का बीज रखा एवं अवधविहारीजी जिला सयोजक चुने गये। अबतक ३२ सदस्य हैं। कभी कभी विचार-वर्षा होती रहती है। इन सम्मेलन में आरा से ७ प्रतिनिधि आये हैं।

पलामू—७-१२-७२ को पलामू जिला आचार्यकुल को विचार देने के लिए एक बैठक हुई जिसमें बहुगुणाजी ने आचार्यकुल का विचार रखा। २७ सदस्यों की एक सदस्य समिति बनी जिसका सयोजक श्री नागेश्वर तिवारी हुए। फिर अनुमंडल स्तर पर बैठकें हुईं। १०-२-७३ को गडवा अनुमंडल की बैठक में जनार्दन द्विवेदी सयोजक हुए। इस समय दो सदस्यों ने निष्ठा पत्र भरे।

शिक्षा में क्रान्ति के विचार को आचार्यकुल ने लक्ष्म शातिषेना के साथ मिल-कर राज्य भर में फैलाने का प्रयास किया और इन सम्मेलन में गया, सहरसा एवं

पटना में एक बड़ी रैली हुई। इसके अलावे भागलपुर जमशेदपुर गया एवं मुजफ्फरपुर में गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के विनोद सहयोग से शिक्षा में क्रान्ति विपयक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आचार्यकुल तरुण शान्तिसेना साथ मिलकर काम करता है। वस्तुतः शिक्षक एवं विद्यार्थी एक ही मित्रके के दो पहलू हैं। इसलिए हम यह अपेक्षा भी रखते हैं कि युवान और विद्वान का समन्वित शक्ति से समाज को एक नयी दिशा मिले।

सदस्यता शुल्क के अभी तक जो पैसे हुए भा तो स्थानीय इकाइयों की महायता के लिए या केन्द्रीय आचार्यकुल के पास। प्रान्तीय आचार्यकुल को ग्रामस्वराज्य कीप से मात्र ५०० मिले थे जिसमें १५२-७३ तक ३४२७५ खर्च हुए और अभी भी १५७२५ बाकी है। यहाँ हम कह देना चाहते हैं कि हमारे काम में अनेक व्यक्तियों ने सहयोग दिया एवं राज्य के गांधी शान्ति प्रतिष्ठान केन्द्रो सर्वोदय मंडलों तरुण शान्तिसेना ने विनोद सहयोग दिया। सबसे सौभाग्य की बात है कि बिहार के शिक्षक संघ ने भी आचार्यकुल का अपनी ही सस्था मानकर हमें यह विश्वास और बल दिया है कि आचार्यकुल का यह बीज एक दिन बर बृष्ण होकर भारत भर के २५३० लाख शिक्षकों साहित्यकारों लोक शिक्षकों का यह विश्व आतुस्व बन सके।

हमारा यह सम्मेलन कब से टनता आ रहा था। हमने प्रयास की कि जितने साथी और मित्र इस सिलसिले में अपने सम्पर्क में आये हैं वे एकवार कहीं मिलें ताकि इस सगठन को एक नयी दिशा एवं एक नया आयाम दिया जा सके। यह सुनकर भार मुगैर के मित्रों ने ही उठाया इसके लिए यहां के सभी मित्रों के प्रति मेरा रोम रोम कृतज्ञ है।

जो यहाँ के कायबाल में यदि समर्थ मित्र भेरी जगह रहते तो शायद आचार्यकुल का सगठन और भी अधिक व्यापक होता। आशा है हमारे नये मित्र हमारे इस अभाव को पूरण करगे और श्रुष्टसे जो श्रुटियाँ हुई हो उन्हें दामा करेंगे।

शिक्षा की स्वायत्तता का स्वरूप क्या हो ?

[दिनांक १७-३-७३ को सात बजे साय से नौ बजे रात तक प्राचार्य कपिलजी की अध्यक्षता में "शिक्षा में स्वायत्तता" विषय पर हुई विचार-गोष्ठी में भाग लेनेवाले आचार्यों ने काफी मनोयोगपूर्वक विचार-विमर्श किया। चर्चा में प्रस्तुत विषय-वर्षा सकेतो के हर बिन्दु पर विस्तार से मनन के बाद सौगो ने जिन तीन बिन्दुओं पर निर्णय लिये वे निम्न हैं।—स०]

(१) क्यों ? (२) क्या ? (३) कैसे ?

क्यों ?

स्वायत्तता की सीमा निर्धारण पर चिन्तन हुआ। शिक्षा जीवन जीने की एक कला है सम्बन्धित ज्ञानार्जन की प्रक्रिया है। अतः इस समस्या को किसी खास वर्ग या वर्गीय निहित स्वार्थ रखनेवाली सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखकर मनुष्य को शिक्षा मिले, तभी शिक्षा में वास्तविक पूर्णता आ सकेगी। शिक्षा "मा विद्या या विमुक्तये" के तत्त्व चिन्तन को साकार कर पायेगी। एतदर्थ निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लिये गये :

१. शिक्षा-सिद्धान्त के अनुसार शिक्षा में स्वायत्तता जरूरी है। जो समस्या स्वयं स्वतंत्र नहीं होगी उससे स्वतंत्र जीवन-कला का विकास-प्रसार कहाँ से होगा ?

२. भारत में परम्परा रही है कि शिक्षा-संचालन में शिक्षण-कार्य करनेवाले और विद्यार्थी ही उसका नियंत्रण, संचालन और पोषण करते रहे हैं। राज्य धन-दान जरूर देता रहा है परन्तु गुरुकुल की स्वायत्तता अक्षुण्ण थी। अतः परम्परा में अनुकूल आचरण देश की प्रतिभा में भी अनुकूल होगा।

३ समाज शास्त्रीय दृष्टि में भी समाज में सामाजिक-नीति एवं सामाजिक मत के निर्धारण को बान आनी है। इस लोकनीति एवं लोकमत पर विचारते हुए तय पाया गया कि राजनीति लोकनीति को बनाती है। लोकनीति दिशा एवं निर्देश देती है। अतः भूमिका में लोक शिक्षा या जीवन-शिक्षा काम करती है। जब तक वह स्वायत्तता नहीं रहेगी तब तक सुनीति पर बल नहीं पड़ेगा। अतः समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी शिक्षा स्वायत्त रहनी चाहिए।

४ सत्ता की दृतीय राजनीति से शिक्षा को अप्रभावित रहना अपेक्षित है। यह तभी होगा जब शिक्षा सत्ता से अलग रहे और स्वायत्त हो।

क्या ?

स्वायत्तता में क्या हो ? इस तत्त्व पर चिन्तन किया गया और निम्न बिन्दुओं पर नियम हुए

१ जिस प्रकार राजसत्ता जब की व्यवस्था करते हुए भी माप-विभाग को माप निर्णय में पूर्णतः स्वायत्त किये हुए है, उसी तरह वह शिक्षा अधिकांशों के लिए भी अनुदान दे और शिक्षा को शिक्षा सम्बन्धी हर नियम के लिए स्वायत्तता दे।

२ शिक्षा-स्वायत्तता में न्यूनतम सीमा

(क) शिक्षा-नीति-निर्धारण की स्वायत्तता।

(ख) छात्र चयन की स्वायत्तता।

(ग) शिक्षकों की नियुक्त, प्रोत्ति एवं विभूक्ति की स्वायत्तता शिक्षा-नीति निर्धारण समिति की ही हो, जिसके सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि, राजकीय प्रतिनिधि तथा विधायक प्रतिनिधि हो। परन्तु समिति में ५१० के अनुपात में शिक्षक ही रहें।

(घ) पाठ्यक्रम निर्धारण तथा पाठ्यविधि निर्धारण की स्वायत्तता,

(ङ) शिक्षा के माध्यम निर्णय की स्वायत्तता,

(च) शिक्षकों की सेवा-संहिता के निर्धारण की स्वायत्तता।

३ शिक्षा और सरकार

(क) केन्द्रीय सरकार

१ यू० जी० सी० के कार्यालयों में भी स्वायत्तता हो और इस संस्था का गठन भा शिक्षकों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ छात्रों के प्रतिनिधि, अभिभावकों के प्रतिनिधि सरकार के प्रतिनिधि तथा विधायकों के प्रतिनिधि सदस्यों द्वारा हो। लेकिन ५१० के अनुपात में शिक्षक-प्रतिनिधि हो इसमें रहें।

२ शिक्षा-अनुष्ठान का वितरण भी समिति के स्वायत्त निणय से हो, न कि राजनेता एवं मंत्री आदि के निर्देश से ।

३ केन्द्रीय सरकार के अधिनस्थ विश्वविद्यालयों में भी, संचालन कार्य में स्वायत्तता हो ।

(स) राज्य सरकार और शिक्षा

१ राज्य सरकारों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता हो ।

२ विश्वविद्यालयों के कुलपति के चुनाव में भी अधिष्ठान (शिक्षा) को ही स्वायत्तता रहे ।

३ राज्य सरकार से मिलानेवाले अनुदानों के व्यवस्थापन में शिक्षा अधिष्ठानों के प्रतिनिधि मंडल को ही स्वायत्तता मिले ।

४ शिक्षकों को नियुक्ति, प्रोन्नति एवं विमुक्ति के कार्यों में भी स्वायत्तता रहे ।

कैसे ?

शिक्षा में स्वायत्तता कैसे हो ? इस बिंदु पर भी चिंतन हुआ और निम्न निर्णय लिये गये

१ शिक्षकों को इतना योग्य और परिणवान होना है जिससे समाज उस पर पूरा पूरा विश्वास करता रहे ।

२ शिक्षक सम्प्रदाय एवं दल आदि की सीमा से अपने जानको ऊपर रहें ।

३ शिक्षकगण अपनी अचार-संहिताओं का अक्षरशः पालन करें ।

४ प्रांतीय एवं केन्द्रीय स्तरों पर शिक्षा को कम से-कम न्याय विभागीय स्तर की स्वायत्तता मिले—इस पर परिसवाद गोठो हुआ करे और तथ्य बिंदुओं पर चिंतन प्रस्तुत हो ।

५ जिसने भी शिक्षक संगठन हैं उन सबों की माँग सूची में सर्वप्रथम शिक्षा में स्वायत्तता की रखी जाय ।

६ केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से कहा जाय कि वह केन्द्रीय राज्य स्तरी तथा सत्रीय शिक्षा-परामर्शदातृ समिति गठित करे और उस समिति के सभी परामर्शों को वह माने ।

७ सभी राजनैतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाकर उसमें ' शिक्षा-स्वायत्तता ' पर अनुकूल चिंतन किया जाय । तब बने मानावरण के अनुकूल विधानसभा में तदनुसार विधान पारित हो ।

विहार आचार्यकुल सम्मेलन में प्रस्तावित शिक्षकों की आचार संहिता

भारतीय आचार्यकुल के सदस्य जिस निष्ठा-मन पर हस्ताक्षर द्वारा सकल प्रगट करते हैं उसमें सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अहिंसात्मक उपाय का अवलम्बन और राजनीति के तमस से दूर रहने की बात है। शिक्षा की स्वायत्तता के लिए दल वर्ग, जाति, सम्प्रदाय तथा निरपेक्ष स्वातंत्र्य चिन्तन की अपेक्षा है। शिक्षा समाज-निर्माण की एक विधायक प्रक्रिया है। भारत में जिस शोषण-विहीन अहिंसात्मक समाज रचना का कार्य लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य रखकर करना है, उसके अनुरूप शिक्षा-संस्थान का संचालन शिक्षक-समाज तभी कर सकता है जब उसके जीवन में स्वतः आदर्शों की निष्ठा प्रकट हो। वर्तमान शिक्षा की यथार्थस्थिति के प्रति विद्रोह का विधायक स्वरूप देना आचार्य-कुल का कार्य होगा। इस दृष्टि से आचार्यकुल की आचार संहिता के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें विचाराय प्रस्तुत हैं

(क) छात्रों के प्रति

(१) स्वाध्याय और समर्पण आचार्यकुल के अस्तित्व की नैतिक घोषणा है। आत्मविश्वास, नियमित पाठ और तत्संग द्वारा ज्ञानार्जन से क्षमता का विकास और सम्पूर्ण पूर्व सैयारा के बाद ही अध्यापन का कार्य किया जाय।

(२) छात्रों के हित और कल्याण को प्राथमिकता दी जाय। छात्रों की स्वाभाविक श्रद्धा, जिज्ञासा और निष्ठा को आत्मतृप्तता से भेदभावविहीन होकर प्राप्तोत्तम दिया जाय। छात्र सहज स्नेह के अधिकारी हैं।

(३) छात्रों के लक्ष्य निर्धारण और समाज से स्वीकृत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न के सम्वन्ध में अभिभावकों के मार्गदर्शन के लिए उनसे सम्पर्क और विचार-विनिमय आवश्यक है ।

(४) आचार्यों के जीवन की सादगी, धर्मनिष्ठा और समय की पाबन्दी से ही छात्रों के जीवन में चरित्र निर्माण का आदर्श प्राप्त होगा । इसलिए विद्यालय के अन्दर और बाहर आचार्यों का आचार अनुकरणीय हो ।

(२) समाज-निर्माण

लोकतांत्रिक अहिंसक समाज-रचना की दृष्टि से यह आवश्यक है कि

(१) निष्पक्ष और तटस्थ वृत्ति से विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विभेद अथवा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सम्प्रदायिक समूह को आशाओं-आकांक्षाओं के प्रति समन्वयात्मक दृष्टि को अपनाना पड़ेगा ।

(२) सहकारी प्रयत्न और सामूहिक चिन्तन की प्रक्रिया में विश्वास के साथ समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय और विद्यालय के बाहर भी छात्रों की समता का विकास किया जाय ।

(३) छात्रों की विधायक वृत्ति के निर्माण के लिए अवसर प्रदान किये जायें, जिससे उन्हें साहस, उत्साह, सेवा, सहिष्णुता, सामाजिक न्याय स्वातन्त्र्य-प्रियता के लिए प्रेरणा प्राप्त हो ।

(४) समाज के सांस्कृतिक स्तर के उन्नयन के लिए रचनात्मक प्रवृत्तियों एवं कला कौशल की अभिवृद्धि के लिए प्रोत्साहन दिया जाय । धर्म-निष्ठा और प्रत्यक्ष उत्साहन में सहयोग का अम्याम स्वदेशी वृत्ति का विकास हो ।

(५) विद्यालय का कार्य भवन के कमरों में सीमित न होकर उस सम्पूर्ण क्षेत्र में माना जाय जिसकी आवादी के लिए उसका अस्तित्व स्वीकार किया गया हो ।

(३) अध्यापन पेशे के प्रति

(१) सेवाभाव से उत्साह और अविनपूर्वक अनुप्यमात्र के कल्याण के लिए अध्यापन-व्यवसाय को अनायास जाय ।

(२) स्वाध्याय, अनुसन्धान, व्यावसायिक साहित्य का अध्ययन, समा-संगठितियों, सम्मेलनों में उपस्थिति, यात्रा एवं सम्बन्ध अवकाशों में आयोजित विशेष वर्गों में सम्मिलित होकर समता का विकास किया जाय ।

(३) सक्षम व्यक्तियों को शिक्षण पथों में आकर्षित किया जाय ।

(४) शिक्षण सयोजना में सक्रिय सहयोग दिया जाय तथा उसकी कार्य-
विवृति के यथासम्भव प्रयास हों ।

(५) शैक्षणिक विकास के लिए सगठित संस्थाओं की सक्रिय सदस्यता
नामम रखी जाय तथा शिक्षकों के सामाजिक उत्पादन का प्रयास किया जाय ।

(घ) इन उद्देश्यों एवं आदर्शों के सफल कार्यान्वयन के लिए समाज की
ओर से निम्नलिखित अधिकार स्वीकृत किये जायें -

(१) व्यावसायिक गौरव, सामाजिक स्थिति और योग्यता के अनुकूल
वेतनक्रम का अधिकार, जिससे वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए
सपरिवार सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें ।

(२) ऐसे हीन व्यक्तियों से सुरक्षा जो कम वेतन पर व्यवसाय में प्रवेश
के लिए प्रगतिशील हों ।

(३) विद्यालय सगठन से बाहर के राजनीतिक, आर्थिक, साम्प्रदायिक
तत्वों के अनैतिक आक्रमण से सुरक्षा ।

(४) शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण, उचित प्रसाधन और उपकरण
प्राप्त करने का अधिकार ।

(५) व्यावसायिक विकास, पारिवारिक कार्य तथा ससुचित विध्राम
लिए उचित अवकाश प्राप्ति का अधिकार ।

(६) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी बातों और
समस्या के सम्बन्ध में ।

(७) सेवा निवृत्ति के बाद अवकाश ग्रहण की स्थिति में जीवन-यापन की
सुविधा एवं पेंशन की व्यवस्था ।

(८) सेवा काल में कामकारी वर्ष में प्रशिक्षण की सुविधा के लिए
सेमिनार, सम्मेलन तथा शिक्षण-संस्थाओं का निरीक्षण ।

(९) योग्यता और क्षमता वृद्धि की स्थिति में स्तरोन्नति द्वारा प्रोत्साहन ।

(ङ) शिक्षकों के सामाजिक दायित्व

(१) सोशनीय निर्माण, (२) लोक शक्ति निर्माण, (३) अशान्ति
शमन, (४) अन्याय प्रतिकार, (५) सांस्कृतिक पुनर्जागरण, (६) सामाजिक
क्रान्ति, (७) शिक्षा में क्रांति, (८) विद्यालय विकास आदि ।

सम्मेलन का वक्तव्य

विहार आचार्यकुल का यह प्रथम सम्मेलन सम्पूर्ण देश में पर विशेषकर अपने राज्य में शिक्षा की यह दुरावस्था देखकर अपनी गम्भीर चिन्ता प्रकट करता है। एक ओर ता मामान्य रूप से हम अपने वक्तव्य में न्युत हो रहे हैं और दूसरी ओर सरकार का हस्तश्रेष्ठ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा यदि केवल बेतनभोगी अध्यापकों के हाथ में रहेगी तो उससे निष्पन्न शिक्षा भी मृत प्राय होगी। उसी तरह यदि शिक्षा मत्ता, सम्पत्ति या सम्प्रदाय की दासी रहेगी तो वह निरतेज एवं निर्जीव रहेगी। इसीलिए शिक्षा शासन-मुक्त और स्वायत्त होनी ही चाहिए। भारत की परम्परा में राज्य की सत्ता गुरु पर नहीं थी। गुरु उससे परे था। इसीलिए सम्मेलन पूरे समाज और अपनी सरकार से यह अपील करता है कि शिक्षा की स्वायत्तता का मूल्य स्वीकार करे। यह ठोक है कि शिक्षा-स्वायत्तता का सम्यन्ध स्वावलम्बन से है, शिक्षा का उत्पादक श्रम से जोड़ने में है। लेकिन अभी जब तक यह स्थिति नहीं है तब तक सरकार न्याय-विभाग की तरह शिक्षकों की आजीविका का भार ले, किन्तु उनके कार्यों में दखल न दे। स्वायत्तता को मूर्तरूप देने के लिए वर्षों (महाराष्ट्र) में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की अनुशंसाओं को जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने मान्य किया है आधार मान कर राज्य में भी शिक्षा परिषद का अविलम्ब निर्माण हो।

आचार्यकुल यह अनुभव करता है कि कर्तव्य बोध के बिना शिक्षा की स्वतंत्रता का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। फिर आचरण तो हमारा धर्म है, यह कोई प्रतिदान नहीं। इर्मलिन आचार्य के लिए जो आवश्यक आचार-सद्वर्तन हैं, उनको हम अपने जीवन-मृत्यु के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने अन्य शिक्षक सहो से भी हमारी प्रार्थना है कि वे भी इसको अंगीकार करने पर विचार करें। अपने इस कर्तव्य-बोध से हमें आत्म सतोष तो होगा ही साथ-साथ समाज का गौरव एवं सम्मान मिलेगा और समाज का उपकार भी होगा।

शिक्षा में क्रांति भी सामाजिक क्रांति के बिना असम्भव है। इसलिए हमें अपने सामाजिक दायित्व का भी भान होना चाहिए।

शिक्षा—सम्पत्ति, सत्ता एवं शस्त्र निरपेक्ष बने दादा धर्मोधिकारी

शिक्षक अपनी सत्ता स्वीकार करें

इस सम्मेलन का पुण्याहवाचन भी मैंने ही किया। इधर प्रया चल पड़ी है कि जिस अग्नि में जो दोष होता है लोग उसी को ग्रहण कर लेते हैं। आपने भी मेरे दोष का ग्रहण कर लिया कि मैं बहुत भाषण करता हूँ। तो आज भी मैं ही भाषण करूँ, शायद यह मेरी अधिक उम्र के कारण भी किया है, क्योंकि आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो वह कुछ सयाना हो जाता है। इसलिए मैं कुछ सावधानी को धातें करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के एक अग्रगण्य नाटककार हैं। उनके नाटक में राधोबा ने पेशवा की गद्दी छीननी चाही। इसलिए उसकी हत्या कराने की भी सोचा। न्यायाधीश से पूछा गया कि जिसने हत्या की हो उसके लिए कौन-सा दण्ड है? उस न्यायाधीश ने कहा, “जिसने मनुष्य की हत्या की हो उसको मृत्युदण्ड के अतिरिक्त कोई दूसरी सजा नहीं है। डर और लोभ के कारण उस न्यायाधीश ने अन्य कोई बात नहीं कही। शिक्षक का स्थान तो न्यायाधीश से भी ऊँचा है। राजसत्ता और धर्मसत्ता दोनों के सामने निष्पक्षता से अपने सिद्धान्त की बात कह सके, वही शिक्षक है। उसे लोकमत के अनुरूप नहीं होना है। उसका अनुगामी नहीं होना है। उन्हें समाज का नेता होना है। किन्तु आज तो नेता भी डेरापोंग हो गये हैं। नेता मनुष्यों की दुर्बलताओं और विचारों से लाभ उठाकर अपना काम करते हैं। जाति, वर्ग, सम्प्रदाय में जो अविश्वास होता है उससे वे लाभ उठाते हैं। भीड़ के साक्षर कुछ सधण होते हैं, उनसे लाभ उठाने से दमे हो सके हैं, विद्रोह हो सकते हैं, किन्तु समाज-परिवर्तन नहीं हो सकता है। समाज-परिवर्तन होना चाहिए। किन्तु मूल्य-परिवर्तन के लिए सन्दर्भ-परिवर्तन करना होता है और आज के शिक्षण से यह नहीं हो रहा है। हम किसी नेता के पीछे चलकर कुछ इधर-उधर के सामान्य परिवर्तन भले ही कर लें किन्तु उससे सन्दर्भ और मूल्य-परिवर्तन नहीं होगा। यह काम शिक्षक को करना है। हृदय-

परिवर्तन की आवश्यकता है यह काम बाहर से कोई नहीं कर सकता। धर्मसत्ता और राजसत्ता के खिलाफ उठाकर जो हुतात्माएँ बनीं उनसे भी आपका काम बठिन और ऊँचा है।

संस्थावाद से दूर रहें

आज शिक्षकों की भूमिका अलग है। बर्नार्ड शा ने कहा कि ईसा आया, मुकरान आया और उन्हें सजाएँ दी गयीं; क्योंकि वे मुँहफट थे। बात कहने का दग नहीं जानते थे। फावड़े को फावड़ा कहने के बजाय एक चतुष्कोणीय औजार कह सकते थे। मुकरान ने कहा, “मनुष्य तू सोया है, मुक्तिन घोड़ा है, मैं तुझे जगाने आया हूँ।” इसके लिए उसे जहर दिया गया। यही बात गैलिलियो के माथे हुई, जिसे केवल सत्य बोलने पर मर्जा दी गयी थी। अतः मर्यं ब्रूयात् त्रिय ब्रूयात्। नेवर वेन एन आरम्पूमेण्ट एण्ड सृज ए फ्रेण्ड (किसी विवाद के लिए मित्र नहीं खोजना चाहिए)। औपचारिक सण्डन में नियम गौण होता है, मनुष्य मुख्य होता है। आजकल बच्चे सोए बहुत क्रान्ति की बात करते हैं, कई बार कई चीजों को वे जना भी देते हैं। उन्हें आज की शिक्षा से भी शिकायत है। किन्तु प्रश्न यह है कि जो शिक्षा इतनी निरुम्मी है इसके लिए इतनी अजियाँ क्यों पढ़ती हैं ? इतना प्रमाद क्यों करते हैं ? छात्र बराबर नयी-नयी मुनिर्वसिटियाँ खोलने के लिए आन्दोलन करते हैं। यह क्या इसलिए करते हैं कि फिर उन मुनिर्वसिटियों को सका जैसा दहन किया जाय। अगर ऐसा नहीं तो और क्या कहा जायेगा ? असल बात यह है कि यदि मनुष्य की मनुष्यता को उबारना हो तो फिर सस्थावाद को समाप्त करना ही होगा। आज तो समाज में मनुष्य या तो किसी सस्था का सदस्य है या वस्तु की तरह से उसकी खरीद-बिक्री होती है। सस्थाएँ अक्सर मनुष्य को हजम कर जाती हैं। सस्था का मनुष्य पर कैसा प्रभाव होता है यह इससे पता लगेगा कि जब गांधीजी ने बहिष्कार-आन्दोलन आरम्भ किया और स्कूल-कालेज छोड़ने का आवाहन किया तो मालवीयजी ने मुझसे कहा कि तुम अब कालेज छोड़ दो, गांधीजी की बात मान लो। अपने बारे में उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ; क्योंकि मेरा इससे (हिन्दू विश्वविद्यालय से) अपत्य प्रेम है, सन्तान मोह है। सस्था के नाम पर मनुष्य जब अपनी आत्मा का हनन करता है तो उसका बही हस्त होता है।

सामाजिक और शैक्षणिक क्रान्ति का अनुबंध हो

आज हमारे देश में जे० कृष्णमूर्ति जैसे कुछ लोग हैं जो इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान दिला रहे हैं, पर बही अन्तिम नहीं हैं। हाँ, वे अब तक के

नवीनतम है। हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमें सत्य का अन्वेषी होना चाहिए और सत्य सभी दृक्को में नहीं प्रकट होता। दृक्का सभी सत्य हो ही नहीं सकता। यह संगठित भी नहीं हो सकता। सत्य जब संगठित होता है तो वह भयानक हो जाता है और दीनान की आवाज बन जाता है। तब मनुष्य पूरे तौर पर मौन और तिरोहित हो जाता है। आज हमारे मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में हम सब असत्य का पूजन ही तो कर रहे हैं। यहाँ पर मनुष्य की नहीं, भगवान की भी नहीं, पंथ की, संघित विचार की, संगठित विचार की पूजा होती है। किन्तु मैं और मेरा अंगोछा तो दो अलग अलग चीजें हैं न। तो मैं मेरे अंगोछे से बड़ा हुआ न। सत्य जब मेरा तेरा बनता है तो फिर वह सत्य रह नहीं जाता। सज्जनता संगठित हो, सांशनिष्ठ संगठित हो, किन्तु मनुष्य सर्वोपरि हो वही मेरा निवेदन है। मैं न इज द मेजर ऑफ़ मात पिम्स' मनुष्य ही सब चीजों का नाम है, उसका कोई नाम नहीं। वह स्वयं ही अपना नाम है। आज तो मनुष्य को, उसकी वक्ता, उसकी विद्या, उसकी प्रतिमा सबकी सब पैसे से नापी जाती है। किन्तु मनुष्य की कीमत मनुष्य का मूल्य नहीं है। हमें कीमत का नहीं, मूल्य का चिन्तन करना चाहिए। यह काम शिक्षण का है। अतः सामाजिक क्रांति और दैवगिर क्रांति का अनुबन्ध होना चाहिए और जब तक यह नहीं होता तब तक शिक्षण स्वायत्त नहीं हो सकता है। आज तो जो सबसे कम काम करता है वही सबसे अधिक पैसे लेता है। जिस बाजार में इनसान विकता है उस बाजार में भगवान भी विकता है। तो फिर ऐसे समाज में शिक्षक की क्या हैसियत हो सकती है ?

आज का समाज ही भ्रष्टाचारमूलक है। बाला बाजार बढ़ रहा है, किन्तु क्या बाजार भी बाला या गोरु होता है ? हमें बाजार एव दरबार में मनुष्य को उबारना होगा। इसलिए राज्यतन्त्र और अर्थतन्त्र से हमें मुक्त होना ही होगा। हम राज्य और अर्थ-निरपेक्ष नहीं, राज्यतन्त्र और अर्थतन्त्र से हमें मुक्त होना ही होगा। आज के समाज में तीन तत्व हैं—सोरा, सट्टा और लाटरी। सोरा यानी कम-से-कम जो देता है और ज्यादा-से-ज्यादा जो लेता है वही होशियार है। यह हुआ सोदा, लेना देना। दोनों फर्जों जहाँ है यह है सट्टा, और कुछ देना नहीं सबका लेना, यह है लाटरी। क्या हम मानते हैं कि इन मूल्यों से समाज चलेगा ? आज हम सब भ्रष्टाचार की बात करते हैं किन्तु उसमें स्वयं को छोड़कर शिकायत करते हैं। आप और हम सब आत्म विश्लेषण नहीं अन्तःप्रबोधन करें, केवल आत्म साक्षित्व नहीं अन्तःप्रबोधन करें।

मनुष्य का स्वत्व जिसी से प्रदान किया जानेवाला या जिसी से मान्यता पानेवाला नहा होता। वह तो हर आदमा की अपने लिये खोजना होता है। यही मनुष्य की अन्तिम प्रतिष्ठा है जिसका हमें आविष्कार करना होगा। यह काम प्रचार से नहा हागा। आज ता शिक्षण दरबार और बाजार के हाथ में पड़कर प्रचार का साधन बन गया है। उसे इससे हमें उबारना होगा। आज प्राथमिक से त्तर विश्वविद्यालय तक के शिक्षण की सुक्ति की बड़ी आवश्यकता है। दरबार कभी शास्त्र के साथ जाता है तो कभी शास्त्र के साथ। वह कभी सम्पत्ति के साथ जाता है तो कभी शास्त्र का प्रयोग करता है। किन्तु हमें समाज में से शास्त्र शास्त्र व सम्पत्ति इन तीनों से ही शिक्षण को बचाना होगा। आज शिक्षण के नाम पर जो प्रचार बन रहा है उससे यह नही होगा। आज देश में कम-से-कम १० हजार लोग ऐसे होंगे जो रोज अध्यात्म पर प्रवचन करते हैं। ३ हजार ऐसी सत्पाएँ होगी जिनका यह दावा है कि वे आध्यात्मिक उन्नयन का काम कर रही हैं और उनके अनुयायियों की संख्या तो बढ़ ही रहा है। फिर कम-से-कम ५० लाख शिक्षक और एक करोड़ छात्र होंगे ही। यह सब है तो फिर भ्रष्टाचार क्यों बढ रहा है? आप लोग अकसर इन भवोदयवानों को कहते हो कि ये भी भ्रष्टाचार नहीं रोक्ते बरन् कई बार स्वयं उसमें पड जाते हैं। किन्तु आपने कभी इस पर क्या नही सोचा कि देश में आध्यात्मिक शिक्षा देनेवाले इतने असंख्य प्रवचनकार और सत्पाएँ हैं उनके पास साधनों का भी बाहुल्य है तो वे क्यों नहीं भ्रष्टाचार रोकन?

आप सब तो बुद्धिवादी हैं न। किन्तु हमारे देश में बुद्धिवादी वह है जो बुद्धि से कम-से-कम काम नेता है। वह उसे बचाकर रखना चाहता है। यदि सत्य मूलवान है तो हम इसके खच में कजूसी क्यों करें? किन्तु आज तो हमारे विश्वविद्यालय ही कम-से-कम विद्या खर्च करते हैं। जिस देश की परम्परा ही धार्मिक और आध्यात्मिक रही है उसमें इतना भ्रष्टाचार क्यों है? इस पर आपने कभी सोचा है? आपने इस असंख्य पण्डे पुजारियों से कभी यह सवाल क्यों नहा पूछा? आपने उनसे इसलिए नहीं पूछा कि उनकी पाठ-पूजा के लिए मिठाई भी तो चोरवाग्राही से हो आती है न। इसमें नागरिक चारित्र्य कहाँ है? मनुष्य के जीवन की एक मर्यादा है उसका स्वीकार होना चाहिए। मैं मनुष्य की शान एवं जान नहीं नूँगा यह सत्य होना चाहिए। सम्पत्ति, सत्ता और शास्त्रधारियों को सरस्वती के मंदिरों में प्रवेश नहीं होना चाहिए।

सम्पादक मण्डल :

श्री धीरेन्द्र मजूमदार : प्रधान सम्पादक

श्री वंशीधर श्रीवास्तव

आचार्य राममूर्ति

वर्ष : २१

अंक : १०

मूल्य : ७० पैसे

अनुक्रम

यह आचार्यकुल विशेषांक	४३३ सम्पादकीय
शिक्षा और शिक्षक कैसे हो ?	४३५ दादा धर्माधिकारी
आचार्यों के प्रश्न विनोबा के उत्तर	४४० -
शिक्षा-क्षेत्र की स्वायत्तता का स्वरूप, व्यवहार और मर्यादा	४४८ सहस्रबुद्धे
आचार्यकुल कार्य की सही दिशा	४५५ विनोबा
महाराष्ट्र आचार्यकुल . प्रगति विवरण	४५८ कु० व० बेबरकर
शिक्षा पर सामाजिक नियंत्रण हो	४६१ उमाशंकर जोशी
आचार्यकुल में आचार्यप्रवर	४६२ आचार्य कपिल
समय क्रांति की खोज लक्ष्य बने	४६५ दादा धर्माधिकारी
बिहार आचार्यकुल . प्रगति विवरण	४७१ डा० रामजी सिंह
शिक्षा की स्वायत्तता का स्वरूप क्या हो ?	४७७
बिहार आचार्यकुल में प्रस्तावित शिक्षकों की आचार संहिता	४८०
सम्मेलन का व्यक्तव्य	४८३
शिक्षा—सम्पत्ति, सत्ता एवं शास्त्र निरपेक्ष बने	४८४ दादा धर्माधिकारी

मई, '७३

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्दा आठ रुपये हैं और एक अंक के ७० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट, द्वारा सर्वे सेवा सघ ॥ लिए प्रकाशित;
मनोहर प्रेस, छतनगर, पाराणसी में मुद्रित

शिक्षा में कोई नयी बात ?

शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति ने 'पंचवी योजना में शिक्षा-नीति' पर अपनी मुहर लगा दी है। योजना-अवधि में शिक्षा के लिए ३२ अरब की माँग की गयी थी, २२ अरब रुपये की ही स्वीकृति मिली है। इसमें से ११ अरब रुपये प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय होंगे—प्रारम्भिक शिक्षा में ६ से १४ वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा। शेष धन का उपयोग माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विकास के लिए किया जायगा।

इस विकास की रूप-रेखा भी सोची गयी है—सोचा गया है कि माध्यमिक शिक्षा अधिकाधिक व्यवसायीकरण और उच्च शिक्षा का नियमन किया जायगा। गुणात्मक विकास की तो प्रत्येक स्तर पर कोशिश की ही जायगी। चेष्टा की जायगी कि शिक्षा-व्यवस्था में सामाजिकन्याय का आकार तैयार किया जाय। गुणात्मक सुधार की ये बातें पहले भी कही जाती रही हैं, आज भी कही जा रही हैं और बावजूद इस कहने-सुनने के और बावजूद एक से अधिक शिक्षा-आयोगों की संस्तुतियों के शिक्षा का पुराना छगड़ा ज्यों का त्यों चलता जा रहा है।

एक नयी बात जो इस योजना में की जायगी वह है अनौपचारिक शिक्षा को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षण-प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में चलाना। शिक्षा-मंत्री का कहना है कि प्रस्तावित अनौपचारिक शिक्षा से शिक्षा-प्रणाली की अनेक घुटियों ठीक हो जायेंगी। शिक्षा अभी सभी स्तरों पर

वर्ष : २१

अंक : ११

हमारे नये प्रकाशन यत्र विश्व भवत्येक नोडम् नारायण न्याय

श्रीनारायण देसाई पिछले दिनों विश्व-शांति यात्रा पर यूरोप तथा अमेरिका गये थे। अनेक देशों के शांतिप्रिय लोगो से, युवक, युवतियों से मिले और उन्होंने देखा कि आज 'एक विश्व' की प्यास जोर से जागी है। सारा विश्व एक परिवार है, एक नोड है—यह सर्वोदय का आधारभूत विचार है।

पुस्तक यात्रा विवरण तो है ही, पर पढ़ने में प्रत्यक्ष अवलोकन का आनंद देती है। मूल्य : ३.००

मधुमेह

डॉ० चरण प्रसाद

इस पुस्तक में मधुमेह या डायबिटीज के विषय में लेखक ने प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से अच्छा विवेचन किया है। मूल्य १.५०

हृदय रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा

वमन द सरावगी

विषय नाम से स्पष्ट है।

मूल्य २.००

नेत्र रक्षा की कला

बोविंदभाई पटेल

आँख है तो जहान है। आँखों की रक्षा हमारे अपने हाथ में है। आँखों की सुरक्षा के प्रति हम सचमुच बहुत लापरवाह रहते हैं। यह पुस्तक हमें आँखों के विषय में अनेक बातों की जानकारी देती है। मूल्य - ३.००

सर्व सेवा सघ प्रकाशन, राजघाट, थाराणसो-१

आनंदन मन्दार कपूरनगर प्रेम भावसागर थाराणसो २२१००१

नयी तालीम

सर्व सेवा-संघ की मासिकी

घर : २१

अफ : ११

- शिक्षा में कोई नयी बात
- शिक्षा : जिसकी आवश्यकता है
- शिक्षा में परिवर्तन : एक यक्ष प्रश्न
- उच्चतर शिक्षा का माध्यम

जून १९५७

पूरी तरह सस्थागत थी। इस योजना-अनुधि में सस्थागत शिक्षा के अतिरिक्त आर्थिक सस्थागत शिक्षण और गैर-सस्थागत स्वाध्याय शिक्षण का शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर विकास करना है। अशकालीन और गैर-सस्थागत शिक्षण का बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया जायगा। सस्थागत शिक्षण के प्रारम्भिक स्तर पर बहुत बड़ा बेस्टेज होता है। इस नयी योजना से वह रुकेगा। माध्यमिक स्तर पर बड़े पैमाने पर अशकालीन और समाचार पाठ्यक्रम चालू किये जायेंगे। बोर्ड की सभी परीक्षाएँ प्राइवेट छात्रों के लिए खोल दी जायेंगी। विश्व-विद्यालय स्तर पर भी प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक खुला विश्व-विद्यालय स्थापित किया जायगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा ही एक खुला विश्वविद्यालय स्थापित होगा, जिसमें परीक्षा देने के लिए किसी प्रकार की उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सभी प्राइवेट छात्र शामिल होंगे।

यह सब होगा और इस प्रकार पढ़नेवालों की संख्या में खूब वृद्धि होगी। 'संख्या' पर 'सस्थागत शिक्षण' के कारण जो धन और नियमन या बड़ ढीला हो जायगा। तो निश्चय ही संख्या में वृद्धि होगी—परन्तु स्वाभाविक रूप में प्रश्न उठता है कि क्या पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई काम ऐसा होगा जो चार योजनाओं में अभी तक नहीं हुआ है—कम-से-कम शिक्षा के क्षेत्र में? अग्यारों में लम्बे विवरण निकलते हैं। उनमें बड़े-बड़े ऑर्डर होते हैं। वे यह बताने के लिए होते हैं कि हजारों नये स्कूल खुलेंगे जिनमें लाखों नये बच्चे भरती होंगे। कितने ही नये महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और संस्थान भी खुल जायेंगे।

हम मान लेते हैं कि यह सब होगा। प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जायगा। 'माटेल स्कूल', 'एक्सपेरिमेंटल स्कूल', 'कम्यूनिटी स्कूल' जैसे नये नाम प्रचलित होंगे। बड़े विद्यालय में नये नामों से नये विषय और नये विभाग शुरू किये जायेंगे। इमारतें बनैगी, वनरवाहें बढ़नी। लेकिन हम जानना यह चाहते हैं कि इन विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जायेगी वह कितनी बढ़ती हुई होगी, और जो शिक्षक होंगे वे कितने नये होंगे। संख्या

(पेज पृष्ठ १२६ पर देखें)

नारायण देसाई

पाओलो फ़ेरे का शिक्षण-विचार

पाओलो फ़ेरे का जन्म सन् १९२१ में उत्तर-पूर्व ब्राज़िल में रेसिफ में हुआ। "भूल के बारे में मुझे कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। मैं भूल के बीच ही पनपा था।" पाओलो के सारे विचार ही गरीबी और अत्याचार की परिस्थिति के खिलाफ़ एक मौलिक विचारक की प्रतिक्रिया-स्वरूप हैं। उसने पाया कि गरीबी का अज्ञान और आतस्य सारी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति के परिणाम-स्वरूप है और वर्तमान शिक्षा तो अत्याचारियों के अत्याचार को टिकाये रखने का एक प्रमुख साधन भर है। एक ओर से उसने अपने क्रांतिकारी विचारों में मार्क्स, सार्त्र, मुनीर, ऐरिक फ़्राम; माओ, माटिन लूथर किंग, चेचेवारा, उगातुनो और मरकुजे आदि विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों के विचारों से समर्पण पाया, तो दूसरी ओर से ब्राज़िल की गरीब वस्तियों में "मुक्ति के लिए शिक्षा" का प्रयोग किया। इस दर्शन और इस प्रयोग का परिणाम ही "पेंडेगोंज़ी ऑव द ओप्रेसड" में पाया जाता है। ब्राज़िल में सैनिक शासन आने के बाद पाओलो का देश-निर्वास किया गया। कुछ समय चिली में काम करने के बाद आज वह स्विट्ज़रलैंड के जिनोवा में 'बर्लैंड कौंसिल ऑव चर्चीज' में स्पेशल कन्सल्टन्ट के नाते काम कर रहा है। चण्डे कार्डन्सिल ऑव चर्चीज ने कई क्रांतिकारी विचारों का समर्पण किया है और सातकर दक्षिणी अमेरिका में उसके नई क्रांतिकारी आन्दोलनों को बल मिला है।

एक्यूमेनिकल क्रिश्चियन सेण्टर विभिन्न मतमतांतरवाले लोगों को इकट्ठा करनेवाला केन्द्र है। इस सेमिनार में भी विभिन्न प्रकार के मार्क्सवादी, विभिन्न सम्प्रदाय के ईसाई, युनिवर्सिटियों या सरकारी शिक्षा-विभाग में काम करनेवाले शिक्षाविद् लोग इकट्ठा हुए थे। मेरे लिए इतने सारे मार्क्सवादियों के बीच पांच दिन के लिए रहने का यह पहला मौका था। बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। ये लोग एक निश्चित भाषा में और निश्चित विचार-पद्धति ही से सोच सकते हैं। इनसे भिन्न सोचनेवालों के लिए उनके पास हमेशा कोई न कोई सेबल सैयार होता है—वृज्वा, पटीवृज्वा, रियेक्शनरी, रिविजनिस्ट इत्यादि-इत्यादि। अगर मार्क्सवादी लोग कुछ भी सोचें या कहें तो उसमें जरूर कुछ झूठा हेतु होगा, यह माननेवाले लोग भी सेमिनार में मौजूद थे। फिर भी सब एक-दूसरे के प्रति विनय-विदेह नहीं चूकते थे। इसलिए चर्चाओं में कभी गाली-गलौज नहीं हुआ। और चाहे जितना बद मन हो ता भी इस प्रकार के सामूहिक अनुभव का कुछ-न-कुछ असर होता ही है।

पाओलो फ़रे के विचारों को संक्षेप में बता दूँ। पाओलो का कहना है कि शिक्षा कभी तटस्थ नहीं हो सकती। या तो वह बचन के लिए होगी या मुक्ति के लिए। पूँजीवादी समाज में शिक्षा को चालू समाज-रचना को टिकाये रखने के एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उत्तम से उत्तम विद्यालय भी अगर गरीब जनता की मुक्ति के लिए न हो तो वह पूँजीवादी समाज-रचना को टिकाये रखने व मजबूत करने का ही काम करते हैं।

बचन की शिक्षा यह विश्वास रखती है कि गुरु में सारा ज्ञान है और शिष्य खाली है। गुरु शिष्य के दिमाग में ज्ञान उड़लता है। लेकिन यह सारी प्रक्रिया बचन की बढ़ानेवाली होती है, क्योंकि उसमें ज्ञान को एक वस्तु माना जाता है। और अपने मन के मुनासिब ज्ञान को उड़ला जाता है। वास्तव में ज्ञान तो एक निरन्तर विकास करनेवाली प्रक्रिया है। वह कभी एकतरफ़ा नहीं हो सकता। अतः मुक्ति की शिक्षा दमिता के बीच शुरू होती है। दलितों के आने प्रश्न मुलझाने की प्रक्रिया में ही शिक्षा है। निशर्मा और शिष्य साथ मिलकर प्रश्नों के बारे में विचार करते हैं। इस क्रिया से दोनों पक्षों को ज्ञान मिलता है। ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ हावा है वास्तविकता पर काम कर, और विचार कर उसमें से ज्ञान-सन्धि करना। इस प्रक्रिया में ज्ञान प्राप्त करनेवाला या प्रसितक दोनों ज्ञान-प्राप्ति के बाद वही पुराने के पुराने व्यक्ति नहीं रह जाते। दोनों पुराने व्यक्तियों की इस क्रिया में मृत्यु होती है और फिर पुनर्जन्म होता है,

इस माने में ज्ञान के कारण दोनों ही 'द्वित्र' बनने चाहिए। भुविन तो इतिहास के प्रवाह में प्राप्त करने की होती है। वह ऐसी प्रक्रिया से प्राप्त होती है, जिसमें ऐतिहासिक वास्तविकता पर लोग असर करते हैं, पूँजीवादी समाज-रचना ने अपने व्यापक प्रचार-साधनों द्वारा वास्तविकता के बारे में बहुत सारे भ्रम पैदा कर रखे होते हैं। उसे दूर करके जनता को जाग्रत करना यही शिक्षा का प्रमुख काम है। जाग्रत जनता अपने आप ही जाति करेगी। साधन-सुद्धि के विचार को पाओलो स्वीकार करता है। लेकिन उसका कहना है कि गरीब लोगों में जो अशांति दिखती है उसे हिंसा नहीं कहा जा सकता। करोड़ों लोगों की दबाये रखने में जो हिंसा है उस हिंसा के प्रवर्तक लोगों को इन गरीबों की "हिंसा" को भस्म करना करने का कोई अधिकार नहीं।

इन विचारों को पाओलो फेरे ने अपनी पुस्तकों में शास्त्रीय भाषा दी है। पहले ब्राजिल में तथा बाद में चिली में प्रौढ शिक्षा के व्यापक प्रयोग में उसने अपने इन विचारों को क्रम में रखने का प्रयत्न किया। प्रौढ शिक्षा के उसके वर्गों का वर्णन बड़ा दिलचस्प था। रिओडी जेनेरो के एक गरीब इलाके के प्रौढ शिक्षा-केन्द्र (जिसका पाओलो ने "सांस्कृतिक वर्तुन" नाम दिया था) में शामिल। मोचुगीज के १७ शब्द पाओलो के कार्यकर्ताओं ने सोच-विचार कर चुन लिये हैं। ये ऐसे भी शब्द हैं जिनसे कुछ पढ़ने-लिखने में आसान हैं और कुछ जटिल हैं। शहरी बस्ती है, इसलिए पहले एक स्लाइड दिखायी जाती है—गरीब बस्ती के बारे में। उसी स्लाइड में एक कोने में शीर्षक भी लिखा रहता है। फावेल्ला (FAVELA) यानी झुग्गी बस्ती। शिस्तक पूछता है कि इस चित्र में हम क्या देखते हैं? अलग-अलग लोग अलग-अलग जवाब देते हैं। सब इन विषय पर सहमत होते हैं कि यह झुग्गी बस्ती का चित्र है। पहले तो झुग्गी की अवस्था के बारे में चर्चा होती है—आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक। फिर दूसरी स्लाइड में सिर्फ "फावेल्ला" शब्द लिखा हुआ दिखाया जाता है। फिर सब लोग साथ मिलकर उस शब्द का उच्चारण कई बार करते हैं। फिर पूछा जाता है कि इसमें कितने उच्चारण हैं? तीसरी स्लाइड में फा, वे और ला को अलग-अलग लिखा हुआ दिखाया जाता है। फिर चौथी, पाँचवी, छठी स्लाइड में फा...फा...फा...पा...फा, वे...वे...वे...वे - वे...वे...ला...ला...सा...ला...ला दिखाया जाता है। फिर फा...फे...फि...फु फो, वा, वे, वि, वु, वो, ला, ले लि, लु, लो। इनको पढ़ने-लिखने से लोग कई सारे अक्षर सीख लेते हैं और कई नये शब्द। यहाँ तक कि दो-एक वाक्य भी बनाने लग जाते हैं। निरक्षरता-निवारण का यह एक शास्त्रीय तरीका है। पाओलो फेरे

की पद्धति में अगर कोई विशेषता है तो वह यह है कि वह लोगों से उत्तर निकालता है। उपनिषद् की पूर्णात् पूर्णम्" वाली प्रक्रिया को वह साकार करता है। उसके साथ सारी राष्ट्रीय परिस्थिति का समन्वय करता है।

दिन में एक बार पात्रोलो बोलता था और उस पर चर्चा होती थी। रोज किसी-न-किसी ओर एक वक्ता के विचार पेश होते थे। श्री जे० पी० नायक ने 'भारत में लोकशिक्षण' के बारे में, डा० बमरीक सिंह ने 'भारत में उच्च शिक्षा' के बारे में, और श्री विनायक पुरोहित ने 'कोठारी कमीशन की रिपोर्ट' की आलोचना करनेवाला भाषण किया। राधाकृष्ण 'गांधी के शिक्षा-विचार' पर बोलनेवाले थे, लेकिन वे सेमिनार में नहीं आ पाये थे। इसलिये यह विषय मुझे रखने के लिए कहा गया। श्री नवबाबू तो सेमिनार के लिए आये ही थे। वास्तव में यह विषय उन्हीं को रखना चाहिए था। चर्चा में उन्होंने ज़रूर हिस्सा लिया। पूरे सेमिनार में पात्रोलो के बाद किसी एक व्यक्ति का सबसे अधिक असर हुआ ही तो वह नवबाबू का। मेरे व्याख्यान के बाद दूसरे दिन पात्रोलो ने आकर मुझसे बहुत आग्रह किया कि I was Gandhi's educated इस विषय पर मैं एक पुस्तक लिखूँ। पात्रोलो स्वयं मार्क्स के विचार से प्रभावित हैं। लेकिन फिर भी उसका मन खुला है। इस बात का यह सूचक था।

(तब मन से साधार)

पूर्णचन्द्र जैन

शिक्षा में परिवर्तन : एक यक्ष प्रश्न

बालक वातावरण के वातावरण का प्रतिबिम्ब है ।

जन्म लेने के साथ चेतन पिण्डाश (शिशु) के शरीर, बुद्धि, मन, चित्त आदि द्वारा चारों ओर चल रही क्रिया-प्रक्रिया का आरम्भसात् किया जाना और उसके अनुसरण में प्रतिध्याया या प्रतिबिम्ब रूप ज्ञात-अज्ञात क्रिया होना, आरम्भ हो जाता है ।

भूख पीछा वगैरह की अभिव्यक्ति शिशु कराह, रुदन, मुख-मालिन्य द्वारा स्वतन्त्र रूप से भी करता है । किन्तु शिशु की भावना, उसकी इन्द्रियों की संवेदना और क्रिया, अधिकांशतः चारा ओर चल रहे क्रिया-कलाप एवं वन-विगड़ रहे वातावरण पर ही आधारित होती है ।

बालक वातावरण का प्रतिबिम्ब

इस प्रकार शिशु और बालक के सारे संस्कार, उसकी भावाभिव्यजना और उसके विभिन्न इन्द्रियों के संकेत-संचार, माता-पिता-परिजन के जीवन-व्यवहार, महल, घर, होपड़े के आनन्ददायी और उन्मुक्त, या पीछा भरे और छुटे-छुटे व सहने वातावरण के लगभग शत-प्रतिशत प्रतिबिम्ब होते हैं ।

यह अनुसरण, नकल या प्रतिबिम्बरूप की क्रिया-प्रक्रिया ही शिशु और बालक की पहली शिक्षा या ज्ञान घूट है ।

इसीलिए माँ, फिर पिता और फिर कुटुम्ब के अग्र सौग और बाद में पड़ोसी व समी-सामी शिशु के, बालक के, क्रमशः प्रथम व निकटतम या अभ्यक्त शिक्षक बहुलाते हैं ।

माता-पितादि से मिलनेवाला वातावरण वह नींव है जिस पर शिशु, बालक के भावी जीवन का, अर्थात् उसके व्यक्तित्व का महल खड़ा होता है ।

ऊपर की स्थापना को समझ लिया जाय तो शिक्षा में परिवर्तन कैसे, क्या, कब और कौन करे, इन प्रश्नों का ज्ञमेता बहुत सरल हो जा सकता है और

तब हा माता पिता, परिजन व समाज, शाला व शिक्षक, सरकार आदि के परस्पर सम्बन्ध तथा अपने हिस्से का काम करने के दायित्व का बंटवारा, एहसास और अमल बहुत सहज हो सकता है ।

इसी में से एक बात और निकलती है जो कम महत्व की नहा है । वह यह कि आदमी को जन्म से मृत्यु तक हर समय शिक्षण प्रशिक्षण सीखने, सिखाने की जरूरत है ।

ऊँची पढ़ाई करके अथवा अपनी आयु, अनुभव, जहवार आदि के आधार पर कौद् यह दावा करे कि उसे शानाजन की आवश्यकता नही, समाज से उसे कुछ नही सीखना-पिखाना है तो वह व्यक्ति शायद सबसे बडा मूख या अज्ञानी है ।

अच्छी शाला स्वयं परिवर्तन सक्षम

अच्छी शाला के कुछ लक्षण हं, होने चाहिए । चाहे वह शाला छोटे शिशुआ के लिए हो अथवा न्यूनतम प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा देनेवाली हो, उसकी सजीवता और सफलता के कुछ मापदण्ड होने चाहिए । शाला न सिर्फ प्रतिदिन पाठ्यक्रम क लिए सैली, विषय, आधारभूत पुस्तक, कथा व प्रदान करेह के चयन में नवीनता और मौलिकता भरे, बल्कि शाला के साथ शिक्षार्थी के मावा पिता व परिजन के चारो ओर के वातावरण को, उनस नियमित सम्पर्क रखते हुए, इतना स्वच्छ सजीव बनाये कि बालक को अच्छे स्वस्थ स्कार सहज मिलते जायें । इसके लिए शाला के प्रधानाध्यापक से लेकर चपरसी तक, सम्बन्धित अधिकारी या संचालकगण, बालक क अभिभावक या सरक्षक, पढोसी आदि को अपनी आखें खुली और सीखने के लिए तत्पर रखनी होगी, सस्कारी और घर-दुनिया की जानकारी में तरोताजा रखना होगा, ताकि बालक को अच्छे सत्पार मिलें, पढ़ने-गुनने की अच्छी सामग्री मिले और शाला में या घर पर शिक्षा पाने से बालक डरे या घागे नही ।

एकबार शिशु या बालक शाला में आ जाय, कक्षा के शिक्षक से चौ-नजर हो जाय, दिन भर शाला में गुजार दे, उसने पाद शाला से छुट्टी मिलने पर जात हुए वह कुछ खोया-खा महसूस न करे, दूसरे दिन शाला में आने को स्वतः जल्दी न करे, शाला न आने की वृत्ति दिखाये, तो यह स्थिति की पहली नाकामयावी का एक सर्टिफिकेट माना जायेगा ।

आज शालाएँ, खास जोर से शहरो के स्कूल, फंक्टरियां बनो हं । शिक्षार्थी दिन भर की पढ़ाई के बाद छुट्टी पाता है तो जेन से छुटने जैसा अनुभव करता है । क्योंकि शिक्षक स्वयं छुट्टी के लिए मानामित रहता तथा पढ़ाने से

अधिक मटरगश्त में खुशी अनुभव करता है। उधर माता-पिता या सरक्षक को भी अपनी सन्तान को प्रारम्भिक शिक्षा व सस्कार देने की पुर्मत नही है।

शाला जीवनदायी वातावरण बनस्ये

ऊपर मापदण्ड की सफ़जता के लिए शाला को मर्यादित बसाएँ और बसा में भी मर्यादित सख्या में शिक्षार्थी रखना चाहिये। कक्षा को शिक्षा के साथ शाला में चारो तरफ तया खेल-मैदान बगेरह में, जिशार्थी को जीवनदायी वातावरण देना चाहिये और शिक्षार्थी के माता-पिता, सरक्षक से सम्पर्क रख उससे घर-आगन व अभिभावक के दिल-दिमाग को अनुकूल बनाने में भी पर्याप्त समय-शक्ति लगानी चाहिए। शाला यह दायित्व माने इनका मतलब ही होगा कि शाला के शिक्षक, उसके सामान्य कर्मचारी, जिम्मेवार सञ्चालक, सब स्वयं अपने आपको शिक्षा ग्रहण करने की हर जिशार्थी व उसके माता-पिता के मानस स्वभाव बगेरह के समझने की वृत्ति रखेंगे।

गैर-सरकारी शिक्षण-सस्थाओं का दायित्व

इस दृष्टिकोण से गैर-सरकारी शिक्षण-सस्थाओं को, खास तौर से जो सस्थाएँ एक महत्वाकांक्षा इस क्षेत्र के प्रयोग की रखती हैं, उन्हें सरकार के ढाँचे व नियमों के रहने भी अपने यहाँ के शिक्षण को, आज और अभी दुस्त करने की बात मिलजुल कर सोचनी चाहिए। आज की सरकारें बहुत यान्त्रिक ढंग से बनने, चलनेवाली हो गयी हैं और जल्दी कुछ परिवर्तन इनके द्वारा शिक्षा या तो धन्य किसी क्षेत्र में हो सके यह सम्भव नही मानना चाहिए, क्योंकि इनका अस्तित्व लोक-शिक्षण, लोक-आवरण, लोक-सक्रियता से अधिक लोकजन या 'लोगों को घेन-केन-प्रकारेण धुग या तो मूक निष्क्रिय रखने (मनवान के आलावा) पर निर्भर करता है। सरकार चलानेवाले जन-प्रतिनिधि ऐसा न मानने हो तो बहुत ही अच्छा है, शिक्षायत का बवाल ही नही। जो भी हो, दोनो स्थितियों में सरकार शिक्षा की अत्यधिक गिरावट, कमी, स्वयं महसूस करती हो या नही करती हो अथवा वह अनुभव करते हुए भी कुछ परिवर्तन नही ला सक्ती हो, इन सब स्थितियों में, जनसेवी शिक्षण-सस्थाओं और शिक्षण-प्रेमियों को गम्भीरता से शिक्षा में परिवर्तन लाने की बात सोचनी, तय करनी व अमल में लानी चाहिए। सरकार स्वयं कभी अनुभव कर चढतीय परिवर्तन करने लगे, उसमें यदि साथ देने लगे तो सुन्दर, बलि सुन्दर। वह सोने में सुहागा होगा। ●

शिक्षक : आचार संहिता की सीमा में

राधेश्याम प्रसाद सिंह

विगत कुछ वर्षों से शिक्षकों के विषय में बातचीत करना एक फैशन जैसा हो गया है। राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, सरकारी अधिकारी सबके सब शिक्षकों को कुछ-न-कुछ नसीहत देना अपना वृत्तव्य समझते रहे हैं। इनके द्वारा व्यक्त किये गये बहुत सारे विचार अनगल होते हैं। आचार्यकुल वास्तव में एक ऐसा मंच है, जहाँ इस विषय पर गम्भीर विचार करना सम्भव तथा उचित है।

समाज के किसी वर्ग विशेष के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए प्रायः हम यह भूल जाते हैं कि वह वर्गविशेष भी समाज का ही एक अंग है और समाज के अन्य वर्गों के 'कारनामो' से वह अछूता नहीं रह सकता है। यदि समाज के विभिन्न अंग सड़ गये हों तो शिक्षकों की गतिविधि में भी सड़ाघ की सूं अवश्य आवेगी।

मूल प्रश्न : शिक्षक कौन हो ?

शिक्षक कौन हो, इसके विषय में बहुत सारे लोगो ने लम्बी दलीलें पेश की हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ शिक्षकों को कौता होना चाहिए, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि कौनसे लोगो को शिक्षक होना चाहिए। योग्यता के बंधन से मुक्त, सत्री तथा उच्च अधिकारियों की पंरबी पर शिक्षक की हैसियत हासिल करनेवाले सज्जन कदापि अच्छे शिक्षक नहीं हो सक्ते। ऐसे शिक्षक सामान्य शिक्षकों से बिलकुल भिन्न होंगे।

बेसे लोगों का ही शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हो, जिनको इस पेशे के प्रति स्वाभाविक रचि हो। आज बहुत सारे लोग बेरोजगारी की विवशता से मुक्त होने के लिए शिक्षण-संस्थाओं में प्रवेश कर जाते हैं। न उनका इस पेशे के प्रति रचि है और न इसके लिए स्वाभाविक गुण। आगे चलकर ऐसे लोग ही विद्या-मंदिर के सम्पूर्ण वातावरण को दूषित कर देते हैं। अभी ऐसे शिक्षकों की कमी नहीं, जो पैसे तो शिक्षा विभाग से प्राप्त करते हैं और काम करते हैं राजनीतिज्ञ के। प्रशासकीय तथा अन्य सरकारी सेवाओं के चुनाव की एक पद्धति है, लेकिन शिक्षकों के चुनाव की कोई पद्धति नहीं। शिक्षण-संस्थाएँ तो पोताला हैं, जहाँ निराश नवजवान और अवकाश प्राप्त अधिकारी दोनों का प्रवेश सम्भव है।

शिक्षकों को समाज के प्रति जागरूक होना है

किसी शिक्षण-संस्था के कार्यालय से नियुक्ति-पत्र प्राप्त कर लेने मात्र से कोई शिक्षक नहीं बन जाता। सही अर्थ में शिक्षक वही है जो अपने दायित्वों के प्रति जागरूक है। पिछले पचीस वर्षों से समाज में तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं। बहुत सारे गुलाम देश साम्राज्यवाद के जगल से मुक्ति पाकर राहत की सांस ले रहे हैं। एशिया में भारत जैसा शक्तिशाली गणतंत्र का उदय हुआ है। सदियों से पिछड़ी जातियाँ अब आधुनिक सभ्यता का स्वाद लेने लगी हैं। शिक्षण-संस्थाओं में नये धर्म की आवादी बढ़ रही है। पुराने मूल्य ढह गये हैं और नये मूल्यों की स्थापना नहीं हो सकी है। इस बदले हुए परिवेश में शिक्षक वर्ग सिर्फ ५० मिनटों का व्याख्यान देकर ही अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता। यह सचमुच चिन्ता का विषय है कि आज के छात्र पाठशाला से स्नातकोत्तर विभागों तक रास्ता तय कर लेते हैं, परन्तु सारी प्रारम्भिक बातों का भी उन्हें ज्ञान नहीं होता है। क्या इस त्रुटि के लिए शिक्षक दोषी नहीं हैं ?

अध्ययन-अभ्यापन एवं शोध-कार्य

शिक्षकों के हल्का होने का मूल कारण अध्ययन का अभाव है। जब तक अध्ययन हमारा मूल उद्देश्य नहीं होगा, हम अपने छात्रों से उचित प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते। अध्ययन के बिना प्रतिभा का विकास हरगिज सम्भव नहीं है। अत्यन्त खेद का विषय है कि शिक्षण-पद्धति का सीधा सम्बन्ध वार्षिक परीक्षा से हो गया है। पाठ्यक्रम से अलग होकर न हम सोचते हैं और न छात्रों को सोचने को प्रेरित करते हैं। हममें से कुछ लोगों की कृपा से छात्रों को ऐसे सल्ले नोट उपलब्ध हो रहे हैं, जिन्हें पढ़कर उनकी प्रतिभा कुठिल होती जा रही है। चिन्तन को प्रोत्साहित करने योग्य सामग्री को ध्यान अनावश्यक मान लिया गया है। जरूरत इस बात की है कि सन्ने अवकाश को शिक्षक अध्ययन-कार्य में ही लगायें। परिस्थितिवश, दो महीने के वीरमावकाश को हम परीक्षा को उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच में व्यतीत कर अपने को धन्य समझते हैं। आबिर परीक्षा का पारिश्रमिक ही तो वेतन का पूरक होता है ! सबसे दिलचस्प स्थिति तो शोध-कार्य की है। साधारणतः शिक्षकों के पास न दो इसके लिए समय है और न उचित प्रोत्साहन ही। शोध-कार्य के पुरस्कार से अधिक कीमती पुरस्कार तो दम्रगान और सल्ले नोट लेखन से ही सम्भव है। कुछ लोगों ने इतने गंदे और अपवित्र ढंग से शोध की उपाधि प्राप्त की है कि किसी भी स्वाधिमानी शिक्षक को उस रास्ते पर नदम बढ़ाना कठिन हो गया है। शोध की उपाधि वितरित

करनेवाले ऐसे महर्षी ने शिक्षण-संस्थाओं की गरिमा को नष्ट कर दिया है। इन सारी विवशनाओं के बावजूद शिक्षकों को अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। शिक्षक प्रायः वर्ग-नार्य में पूरी जापरवाही बरतते हैं। किसी भी मूल्य पर हमें पूरी तैयारी के बिना वर्ग में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह तैयारी उनके छात्र-काल के नोटों पर ही आधारित न होकर बयासम्भव मौलिक पुस्तकों के अध्ययन से ही हो। सुर्दा नोट छात्रों में स्वाभाविक उत्सुकता जागृत नहीं कर सकेंगे। यदि छात्रों में शिक्षकों के व्याख्यान से उत्सुकता नहीं जगी तो यह पूरा व्याख्यान समय और ऊर्जा का अपव्यय ही माना जायेगा।

राजनीति से तटस्थ

शिक्षकों के विरोध में एक आम शिष्यावृत्त है—राजनीतिज्ञों के पिछलग्नु बनने की। कुटिल राजनेताओं को शिक्षकों की प्रतिष्ठा कुचलने में आज चाहे जितना सुझाव का अनुभव हो रहा हो, परन्तु देश के भविष्य के साथ इस खेल की कीमत तो पुरानी ही पड़ेगी। इस परिस्थिति में हमारा यह कर्ज है कि राजनीति के प्रति अपना रुख तटस्थ रखें। इस सम्बन्ध में शिक्षकों के रुख के प्रति यह ठीक ही कहा गया है कि हमें राजनीति से दूर रहकर राजनीति पर प्रभाव डालना है। यह कैसे बिड़म्बना है कि पुराने पढ़े-लिखे शिक्षक आज राजसत्ता-विभूषित राजनीतिज्ञों के चरण रज निस्सकोच प्राप्त कर रहे हैं। पिछले पचीस वर्षों में इस देश में ऐसे शिक्षकों के प्रभाव से ही एक रीढ़-बिहीन पीढ़ी तैयार हो गयी है, जिसमें मात्र भौतिक उपलब्धि की भूख ही जग सकी है। दल के बलबल में फँसे शिक्षक सरस्वती के गुजारी होने का दावा नहीं कर सकते। अभी भी हम सम्भल जायें तो देश बिनाश से बच सकता है। राजनीति मिथ्या और कृत्रिम संगठन की ही जन्म देती है। ऐसे संगठन से हमारा उद्धार नहीं होगा।

समय-निष्ठा

शिक्षकों से एक महत्वपूर्ण अपेक्षा है—समयानुसार कार्य करने का, समय-निष्ठ होने का। आधुनिक शिक्षक समय के प्रति प्रायः उदार दृष्टिकोण रखते हैं। जरा ठहर कर सोचिए। १० मिनट के वर्ग में आप २० मिनट बाद पहुँचे, उस वर्ग में आप क्या न्याय कर सकेंगे? गाड़ी समय के बाद पहुँची, आपका मूड खराब हो गया। चाय देर से मिली, आपकी सिर दर्द हो गया। अखबार देर से आया, आप खफा हो गये और आप देर से पधारें और छात्र बूँ तक न

बोलें। वैसे पवित्र आकाशा है आपकी? समय पर आकर देखें, छात्रा का शरीर ही नहीं, आत्मा भी आपका अनुमरण करने लगेगी।

सादगी

अहंकार-विहीन सादगी शिक्षकों का दूसरा अभूषण है। सादगी का अर्थ वैतरणीव सिले हुए वस्त्र हरगिज नहीं है। यह तो सादगी का मजाक हुआ। मेरे एक मित्र हैं। एक घंटे उनके पास बैठ जाइए। अपने सस्ते और सादे वस्त्रों की चर्चा किये वगैर वे नहीं रह सकते। अपनी सादगी को इस तरह किसी पर थोपना अहंकार का खोतक है, और ऐसे आचरण से प्रतिक्रिया का ही जन्म होता है। कभी-कभी तो हमारे वस्त्र इतने आक्रामक होते हैं कि शिक्षण-संस्था के जिस रास्ते से हम गुजरते हैं, लोग आहन हो जाते हैं। सच्चा शिक्षक वही है, जिसमें स्वाभाविक सरलता और सादगी हो। आज ऐसे शिक्षकों का अभाव नहीं है जो छात्रों से मजिस्ट्रेट की तरह व्यवहार करते हैं। एक छोटी-सी घटना हुई और उबल पड़ते हैं। सहायता और देख-रेख की बात तो दूर है, सनकी मोठी बाणों सुनने को भी छात्र तरसते हैं। इन मानवीय व्यवहारों के अभाव में ही छात्र रास्ते से भटकते जा रहे हैं।

परीक्षा और शिक्षक

परीक्षा के सर्वभ में बहुत सारी तोहमत हम शिक्षकों पर लगायी गयी है। प्रश्न-चयन, निरीक्षण, परीक्षण, अक-निबन्धन—इन सारे कार्यों में हमारे खिलाफ अगुली उठाई जा रही है। ऐसे उदाहरण का अभाव नहीं, जब शिक्षक व्यापारियों की तरह प्रश्न बेचकर पैसे कमा रहे हैं, अक बेचकर यश पा रहे हैं। परीक्षा में ढिलाई के फलस्वरूप ही सरकार को विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता नष्ट करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और परीक्षा-निर्भरण में सफलता प्राप्त कर सरकार आज यश कमा रही है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक सिर्फ भय की भाषा समझते हैं। हममें से बहुसंख्यक अभी भी ठीक हैं और यदि चाहे तो इन अल्पसंख्यकों पर हावी होकर परीक्षा की पवित्रता को पुन स्थापित कर सकते हैं। इन परीक्षाओं को ठीक करने के लिए हमें वर्ग कार्य में घुस्त होना पड़ेगा। प्रायः छात्र इस घुस्ती के लिए बेचैन हैं।

अन्त में मेरा समर्पण है कि शिक्षकों के आचरण में तबतक सुधार सम्भव नहीं है, जबतक हम राजनीति के आकर्षण से चकाचौंध होना बन्द न कर दें। लोभी अधिभावक और छात्रों को ठग शिक्षक कभी सही रास्ते पर नहीं ला सकते। एवबार हम ईमानदारी और साहस से जीने का संकल्प तो लें, सफलता हमारी है।

शिक्षा : जिसकी आवश्यकता है

द्वारका सिंह

वर्तमान स्थिति

“हमारे समय का सबसे अधिक ज्वलन्त तथ्य यह है कि हम आज एक ऐसे सप्ताह में रह रहे हैं जो हममें अत्यधिक भय और चिन्ता उत्पन्न करता है। दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाजशास्त्री और दूसरे बुद्धिवादी बराबर मानव समाज के भविष्य पर चिन्ता कर रहे हैं और इस विषय में सका प्रवृत्ति की जाने लगी है कि क्या हम एक युग के अन्त में पहुँच गये हैं और जो सभ्यता हमने निर्मित की है वह नष्ट होने जा रही है ? विश्व वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था के प्रति असन्तोष, अनिश्चितता और बेवैनी के संकट से गुजर रहा है। अज्ञान के पुराने आधार कभी के टूट चुके हैं। नये अधिकारों और खोजों की तीव्र गति के कारण जन जीवन और समाज का नक्शा तेजी से बदल रहा है।

आज का संकट सभ्यता का संकट है। विज्ञान और तकनीकी की शानदार विजय ने भी इस सप्ताह में कोई कमी नहीं की है। इसके विपरीत इन विजयों ने उन सत्तरों की, मानवता आज जिनका सामना कर रही है, बुद्धि कर दी है।

राजनीतिक घरातल पर विश्व के लगभग प्रत्येक कोने में ‘गर्म’ और ‘शीत’ कोई बढ़ा युद्ध नहीं हो रहा है किन्तु हम निरन्तर युद्ध के कगार पर खड़े हैं। सभी मनुष्यों, जातियों और राष्ट्रों के लिए मानवाधिकारों की स्वीकृति का बावजूद हम देखते हैं कि राष्ट्र-धर्म-संघर्ष के संकीर्ण राष्ट्रवाद और जातिवाद के दल-दल में घँसते जा रहे हैं।

विज्ञान और तकनीकी के कारण राज्य-सत्ता के हाथों में इतनी शक्ति संचित हो गयी है कि उससे सारे संसार की सुरक्षा और शांति सठरे में पड़ गयी है। वैज्ञानिक भस्तिष्क ने अपनी सृजनात्मक योग्यता और प्रवीणता का उपयोग बिना किसी शक्तिशाली यंत्रों के अधिकार में किया है जिनसे मनुष्य के पूर्ण विनाश की हो सम्भावना उत्पन्न हो गयी है।

अस्थिरता और असुरक्षा की यह स्थिति निम्नो दोषी व्यवस्था का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक शक्तियों के साथ मनुष्य का असमंजस का परिणाम है। यह मानवदृष्ट और इस तकनीकी मानव की ही इस उदासीनता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आज के समाज की इन आर्थिक और राज-

नैतिक उत्तेजनाओं का एव ही इलाज है कि हम फिर नए समय का प्रतिपादन करनेवाले महान शक्तियों के सन्देश का स्मरण करें ।

यया शिक्षा नए पास व्यक्ति और समाज के लिए इस खतरे का कोई जवाब है ? यया शिक्षा विज्ञान और तकनीकी से समर्थित वर्तमान मूल्यों को, यह कह कर कि वे ऐतिहासिक और अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं, असाहाय होकर चुपचाप स्वीकार कर लेगी ? इसके विपरीत यया हम विश्व के महान पुरुषों की नेक सलाह, बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह, को स्वीकार कर विरासत में प्राप्त जीवन की बुनौती को साहमपूर्वक स्वीकार करके उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए आगे नहीं आयेगे ?

स्पष्ट है कि शिक्षा के वर्तमान ढाँचे ने देश में व्याप्त इस खतरा को समझ या कम करने में कोई योगदान नहीं किया है । वर्तमान शिक्षा-पद्धति के दोषों और कमियों पर पिछले छौ सालों में साहित्य का डेर लग गया है और प्रतिष्ठित शिक्षा-शास्त्रियों और दूसरे विद्वानों ने इसकी इसी स्पष्ट और ज़ोरदार शब्दों में निम्ना की है कि अब उसके विषय में और कुछ कहना भरे घोड़े को मारने के समान होगा ।

शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य में सहिष्णुता, सहकारिता और सामाजिक भाव-प्रवणता आदि गुणों का विकास करना है जो अपने पड़ोसियों और साथियों के साथ मेल और सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने के लिए आवश्यक है । सामाजिक न्याय के लिए अनुदाग विकसित करने की बुनियाद बनाने का केवल यही एक मार्ग है । इस प्रकार के कृतानों का विकास विद्यालय में रहकर वास्तविक अनुभव प्राप्त करके ही किया जा सकता है ।

बग़र शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना न तो यह आवश्यक है कि विद्यालय समुदाय शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में समाजसेवा के सार्थक कार्यक्रम में भाग लें । आज की शिक्षा में विद्यालय पड़ोस के समुदायों से अलग-अलग पड़ गये हैं । वे स्वयं के कार्यों, भावनाओं और विचारों के घेरे में अकेले और अलग रहते हैं । शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य यह है कि वह प्रत्येक बालक में अपने और सामाजिक परिवेश के बीच विश्वसनीय सम्बन्धकारी का विकास करे । इस प्रकार के सम्बन्ध सामरिक साहस के शैक्षणिक पाठ पढ़ा देने से नहीं बनेंगे । इस प्रकार के सम्बन्ध पड़ोसों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखने और उसके प्रति क्रियात्मक संवेदनशीलता का प्रतिफल होते हैं ।

हमारी वर्तमान शिक्षा-पद्धति ने हमारे बालक-व्यक्तियों को अपनी परम्परागत महान संस्कृति और धर्म से विमुख कर दिया है । शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो देश के नौनिहालों को उनकी ही धरती की संस्कृति में

पाले और उनके स्वस्थ विज्ञान के लिए उचित पोषण दे। हमारी शिक्षा ने अब तक भारत के अतीत की उपेक्षा की है और हमारे विद्यार्थियों को भारतीय सस्कृति की कोई जानकारी नहीं है। अपनी सस्कृति से अनभिज्ञ होना या उसके प्रति अवमानना की भावना रखना एक तरह की सांस्कृतिक आत्महत्या है। शिक्षा को किसी भी मुगठित व्यवस्था को अपने बालकों को न केवल उनके भव्य अतीत का ही ज्ञान देना चाहिए बल्कि इससे भी अधिक आवश्यक है उन्हें भविष्य के लिए उचित निर्देशन देने की दृष्टि से उसके प्रति रागात्मक प्रतीति कराना।

आज की शिक्षा के विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यही है कि उसने विद्यार्थियों में श्रद्धा का दृष्टिकोण नहीं पनपाया है। यदि शैक्षणिक प्रक्रिया में ऐसा ज्ञान शामिल नहीं है जिससे मस्तिष्क प्रकाश पा सके, तो वह पूर्ण शिक्षा नहीं है। मनुष्य की आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना पूर्ण माधव की शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है।

जीवन में मानव-मन को अज्ञान बना देवबाली अनिश्चितताओं और अत-विरोधी के कारण आज आध्यात्मिक शिक्षा की अतीव आवश्यकता है। सांस्कृतिक सबूट के काल से सही ढंग की आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा ही सुरक्षित आश्रय हो सकती है। आज परिवार, मन्दिर और अन्य सामाजिक संस्थाएँ मनुष्य में धार्मिक वृत्तियों का पोषण नहीं कर पा रही हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी सस्कृति सर्वव्यापक हो रही है।

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा केवल निर्देशन का नहीं, बल्कि शिक्षण का विषय है। विभिन्न विश्वासों की विरासत का प्रसार निस्सन्देह आवश्यक है। किन्तु यही अपने-आप में पर्याप्त नहीं है। आध्यात्मिक शिक्षा विश्वासों का हस्तान्तरण नहीं, बल्कि एक खोज है, एक शोध है। सही तरीके की आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्वानों को विश्व के भिन्न-भिन्न धर्मों के अध्ययन की श्रद्धाभाव से अपने पाठ्यक्रम में रखना होगा।

परीक्षाएँ जैसी आज चल रही हैं एक अभिशाप हैं। उन्हें जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। ये शिक्षा को गलत रास्ते पर ले गयी हैं। विद्यालयीय जीवन में सहभाग, वास्तविक कार्य, कार्य-विवरण और रिपोर्ट, कक्षा में उनके कार्य-निदान, व्याक्ति का मूल्यांकन, कार्य की दैनिक और सालाना रिपोर्ट, पुस्तकालय, सेमिनार, अभिलेख आदि के माध्यम से छात्रों के कार्यों का सतत मूल्यांकन होना चाहिए। आज दफ्तरो में मायूरी के पंनों के लिए पाठपोद्घ के तौर पर डिग्रियाँ, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्रों को

जो मान्यता प्राप्त है उसके अभाव में तो यह शिक्षा-वृद्धि कभी समाप्त हो गयी होती। फिर भी शिक्षा के पवित्र नाम पर चलनेवाले इस बेहूदेन को समाप्त करने का अब भी समय है।

शिक्षाशास्त्री न केवल हमारे देश में ही वरन् पश्चिमी देशों में भी इन विचारों पर जोर देते रहते हैं। विशिष्ट शिक्षा आयोगों ने भी समय समय पर इन कमियों को और हमारा ध्यान खींचा है और सुधार के लिए सुझाव दिये हैं। हमें माग्न और स्याही छर्च करके बुलेटीन, परिपत्र, सम्भावित योजनाएँ, शोध-अभ्यासों और शोधों के निष्कर्षों एवं रिपोर्टों का पक्षत जैसा ढेर वितरित किया जा चुका है। किन्तु परिणामस्वरूप शिक्षा के संगठन और प्रशासन में कुछ सामान्य सुधार, जैसे काम के घण्टों में परिवर्तन, छुट्टियाँ, टाइम-टेबल, परीक्षा-पद्धति में कुछ परिवर्तन अथवा कुछ नये पदाधिकारियों की नियुक्तियों के अतिरिक्त विचारों को शोध क्रिया में परिणत करने के लिए दुनियादी सिद्धान्तों में मौलिक और क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। हमें आज प्रशासन और संगठन-सम्बन्धी मामलों में छिटपुट सुधार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शिक्षा के आदर्श क्रिया-व्ययन में क्रांति की आवश्यकता है।

किये गये प्रयास

सन् १८५४ ई० के 'बुड हिसरीच' के बाद स्वतन्त्र भारत से अनेक आयोगों और समितियों का गठन किया जिनमें १९४८-४९ का विश्वविद्यालयीय शिक्षा आयोग, १९५२-५३ का माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा १९६५-६६ का भारतीय शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन) उल्लेखनीय हैं। इन आयोगों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये गये। नवीनतम शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन) की रिपोर्ट पर काफी चर्चा हुई और टिपणियाँ की गयीं। चर्चाओं के फलस्वरूप भारत सरकार ने १९६८ साल में अपने शिक्षा मन्त्रालय के द्वारा शिक्षा की राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जिसका प्रकाशन उसी साल किया गया।

सत्तरवात् १९७० की ९-१० फरवरी को डा० बी० के० आर० बी० राव तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की प्रेरणा से सेवाग्राम में देश के चुने हुए शिक्षा-विदों का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन का मुख्य सद्य यह था कि वह गांधीजी द्वारा निर्धारित मानव-मूल्यों की राष्ट्रीय शिक्षा-योजना में किस प्रकार शामिल किया जा सकता है, इस पर विचार करे।

उसके बाद १९७२ की ३ और ४ जून को शारदाग्राम (गुजरात) में सीमित सख्या III शिक्षाविदों का सम्मेलन हुआ जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के सम्बन्ध में काफी चर्चाएं हुईं। उक्त सम्मेलन के एक पारित प्रस्ताव हैं अनुसार १९७२ साल में ही सेवाग्राम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन १४, १५ और १६ अक्टूबर को किया गया जिसका उद्घाटन हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया। उक्त सम्मेलन के अवसर पर सम्मेलन के अध्यक्ष तथा गुजरात राज्य के तत्कालीन राज्यपाल श्री श्री भन्ना-रायण ने भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप का एक प्राकृत्य तैयार किया और सम्मेलन के सामने यह रखा गया। उक्त सम्मेलन में देश के अधिकांश मुख्य मंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों, उपकुलपतियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों तथा राष्ट्र-निर्माताओं ने भाग लिया और सर्वसम्मति से राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये जो निम्नांकित हैं — (१) शिक्षा हर स्तर पर सामाजिक दृष्टि से उपयोगी एवं उत्पादक क्रिया-कलापों द्वारा अधिक विकास की उपलब्धि से सम्बद्ध रहकर ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में प्रचलित हो।

(२) प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तरों के पाठ्यक्रमों में तीन मूल तत्वों पर धन दिया जाय .

(३) आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास तथा शैक्षणिकता की अविभाज्य अंग के रूप में कार्यों द्वारा श्रम-प्रतिष्ठा।

(४) सामुदायिक सेवा के सार्थक कार्यक्रमों में छात्रों और शिक्षकों के सहयोग से राष्ट्रीयता एवं सामाजिक दायित्व की भावना।

(५) नैतिक मूल्यों का सिक्नन तथा सर्वधर्म समभाव और उनके मूलभूत सिद्धान्तों की एकता।

(६) शैक्षणिक ढाँचे के विभिन्न स्तरों को १० + २ + ३ क्रम से अनुसार होना चाहिए।

(७) प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल सभी बच्चों के लिए समान स्तर पर खुले होना चाहिए।

(८) सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूलों की एक साथ पद्धति संघालित करना जरूरी है।

(९) विज्ञान संस्थाओं में भीड़-हल्लायों को हटाने के लिए भरपूर

प्रयत्न होने चाहिए । लेकिन प्रशासन को माध्यमिक स्तरीय और कॉलेजों को संचालित करने की समस्त जिम्मेवारी नहीं उठानी चाहिए ।

प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर सभी राज्यों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है, विश्वविद्यालय स्तर पर इस प्रकार के शिक्षा-माध्यम को जारी करने के लिए शीघ्र कदम उठाना चाहिए ।

(८) इस शैक्षणिक सुधार में शीघ्रता लाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि सिविल तथा मिलिट्री सेवाओं के लिए अखिल भारत प्रतियोगिता परीक्षाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में लिया जाय और सम्पीडवारों की प्रत्येक राज्य में लिए उर्कयुक्त आधार पर नियत कोटा के अनुसार चुना जाय । इन सेवाओं का अखिल भारतीय स्वरूप कायम रखने के लिए चुने गये नवयुवकों को हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान कराया जाय तथा उन्हें राष्ट्रीय इतिहास, संस्कृति, भारतीय संविधान और आर्थिक संयोजन की भी आवश्यक जानकारी दी जाय ।

(९) परीक्षा के वर्तमान ढंग से छात्रों की शारीरिक, मानसिक और नैतिक क्षमताओं पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है । इसलिए यह बहुत जरूरी है कि परीक्षा-पद्धति में अविलम्ब आमूल सुधार किये जायें ।

संक्षेप में, परीक्षा-पद्धति में केवल विद्यालयों की बौद्धिक सिद्धि की जांच करे, बल्कि उत्पादक और विकास प्रवृत्तियों, सह्योगी कार्यक्रमों, समाजसेवा, नियमित उपस्थिति तथा सामान्य व्यवहार पर भी ध्यान दे ।

(१०) छात्रजनिक एवं वित्री क्षेत्रों में नौकरियों के लिए डिग्रियों का सम्बन्ध विच्छेद कर देने के लिए भरसक प्रयत्न किये जाने चाहिए । इस उद्देश्य से नतीजों के नियमों में समुचित संशोधन किया जाय ।

(११) कोई भी शैक्षणिक विकास शिक्षकों का गुणवत्ता और प्रशिक्षण में सुधार लाये बिना सम्भव नहीं है । शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे छात्रों में प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का भरसक प्रयास करें । लेकिन सरकार का भी यह फर्ज है कि वह शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊँचा उठाये और उन्हें दैनिक आर्थिक चिन्ताओं से मुक्त करे ।

(१२) शैक्षणिक पुनर्रचना के महत्वपूर्ण कार्य में सभी स्तरों पर माता-पिता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है । इस उद्देश्य से विद्यालयों एवं कॉलेजों में पालक-शिक्षक मण्डल की स्थापना एक सामान्य व्यवस्था बन जानी चाहिए ।

(१३) शैक्षणिक सुधार की नीति-निर्धारण प्रक्रिया में छात्रों का सहकार लेना जरूरी है छात्र-समूहों का उपयोग विद्यापिया में आत्म-समय लागू करने की दृष्टि से किया जा सकता है ।

नवयुवका को यह बात भली-भाँति समझायी जाय कि हिंसा वर्तमान तरीको से अनिवार्यतः प्रति हिंसा उत्पन्न होगी जो हमारे लोकतांत्रिक ढाँचे को ही गम्भीर खतरे में डाल देगी ।

(१४) पिछले २५ वर्षों में लागू की गयी विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं के बावजूद हमारी आबादी का ७० प्रतिशत अब अभी भी निरक्षर बना हुआ है । इसलिए जनता में 'व्यावहारिक' साक्षरता लाने के लिए संगठित प्रयत्न किये जायें ताकि जनता में अपेक्षित नागरिक जागरूकता पैदा होने के अलावा उनकी कार्य कुशलताओं में अभिवृद्धि हो सके । इस राष्ट्रीय अभियान में सामाजिक सेवा की प्रवृत्ति के रूप में छात्रों और शिक्षकों का पूरा सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए ।

(१५) विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेल-कूद का बड़े पैमाने पर विकास किया जाय । प्रतिभाशील नवयुवकों का योग्यतानुसार चयन कर उन्हें प्रोत्साहित करना आवश्यक है ।

आगे की योजना

अब तक हमलोग शिक्षा की वर्तमान स्थिति को और अब तक किये गये प्रयासों के सम्बन्ध में चर्चा करते रहे । अब इन चर्चाओं के फलस्वरूप विहार आचार्यकुल आगे की नीति की योजना लेना इस पर विचार करना है ।

शिक्षा का उद्देश्य

- (१) शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है ।
- (२) शिक्षा को व्यक्ति को हर प्रकार के शोषण-भुक्त एक नयी समाज-रचना करने का उत्तरदायित्व, बुद्धिमत्ता और सक्रियता से स्वीकार करने के योग्य बनाना चाहिए ।
- (३) शिक्षा को व्यक्ति में बुद्धिमत्तापूर्ण समझदारी की भावना और उसकी आत्म निर्देशन की शक्तियों की वृद्धि के साथ-साथ उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए ।
- (४) शिक्षा को आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य मनवाने चाहिए ।
- (५) शिक्षा को पारस्परिक सहृदयता को पुनः व्याख्या में सहायता करनी चाहिए ।
- (६) शिक्षा को विज्ञान को सत्य के लिए खोज के रूप में और मानव मूल्यों को बढ़ावा देनेवाली तकनीकों को प्रोत्साहन देना चाहिए ।
- (७) शिक्षा को छात्रों में सृजनारम्भ और सौंदर्यात्मक अनुभवों के लिए प्रचुर अवसर प्रदान करने चाहिए ।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नांकित कार्यक्रम लाने होंगे

(१) चरित्र के वर्तमान ह्रास का हल केवल शिक्षा में सामान्य सुधारों से नहीं बरन् शैक्षिक उद्देश्यों और क्रियाओं में समग्र क्रांति के द्वारा ही निकल सकता है । (२) शिक्षा के हर स्तर पर मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए । (३) शिक्षा के सभी स्तरों पर उत्पादक और सार्थक शरीर-शिक्षा का अनिवार्य अंग होना चाहिए । (४) शिक्षण-संस्थाओं को कार्यकारी सोमवर्ग के रूप में विकसित होना चाहिए ।

तो हम क्या करें ।

सम्भवतः बिहार आचार्यकुल ही सर्वप्रथम आचार्यकुल है जो इस राज्य की नयी शिक्षा-नीति में मोड़ लाने के लिए आज विचार कर रहा है । इसलिए इस आचार्यकुल को नयी शिक्षा-नीति की कार्यान्विति के लिए निम्नांकित कदम उठाने होंगे

(व) आचार्यकुल की एक शिक्षा-समिति का गठन करना । (छ) शिक्षा के प्रत्येक स्तर के मिलेबस का मध्यक अध्ययन और उनके परिवर्तन के लिए ठोस सुझाव देना । (ग) प्रत्येक स्तर के विद्यालय और महाविद्यालय और महाविद्यालय के प्रांगण को सादमो के साथ आकर्षक और उपयोगी बनाना जिसमें समुदाय और छात्रों के वे प्रकाश-स्तम्भ बन सकें । (घ) आचार्यकुल के सभी सदस्यों की छादी वेश मूया में रहने का सकल्प लेना । (ङ) छात्र-समुदाय को किसी समाजोपयोगी उत्पादक काम की ओर प्रवृत्त करने के लिए संस्था के हाते में परिश्रमालय की स्थापना करना या निकट के सुसज्जित परिश्रमालय में कार्य की सुविधा प्रदान करना । (च) प्रत्येक संस्था का अपना सेवा-क्षेत्र होना चाहिए जहाँ वह सच्चा शिक्षा के माध्यम से सेवा के काम कर सके । (छ) लोकतंत्र के सफ़्त कार्यान्वयन के लिए नागरिक शिक्षा की व्यवस्था संस्था के सेवा क्षेत्र में करना । (ज) प्रत्येक आचार्य को आचार्यकुल के लिए निमित्त आचार्य संहिता के अनुसार अपने को निर्देशित करना । (झ) छात्रों की समस्याओं का स्नेहपूर्वक समाधान करना । (ट) प्रत्येक संस्था द्वारा अतिरिक्त समय में छात्रों के मार्गदर्शन के लिए अतिरिक्त समय में छात्रों के मार्गदर्शन के लिए अतिरिक्त यगों का संचालन करना ।

द्वारिका सिंह, शैक्षिक निबन्धक, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक

ब्रिटिश कारपोरेशन, पटना

शासनमुक्त शिक्षण : विनोबाजी के अधिकृत मार्गदर्शन

[महाराष्ट्र आचार्यकुल के प्रथम सम्मेलन के अवसर पर 'शासनमुक्त शिक्षण' विषय पर महाराष्ट्र आचार्यकुल के संयोजक श्री मामा क्षीरसागर, विदर्भ के सगठक श्री रामसेवालकर और श्री दि० ह० सहस्रबुद्धे ने विनोबाजी से कुछ प्रश्न पूछे थे। विनोबाजी द्वारा दिये गये प्रश्नों के उत्तर नयी तालीम के पाठकों के लिए दिया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपनी राय लिखें ऐसी प्रार्थना है।—सम्पादक]

प्रश्न शिक्षण क्रम की रचना कैसे हो, पाठ्यक्रम किन विषयों का हो, पाठ्यक्रम कैसे हो, परीक्षा प्रणाली कैसे हो, तथा ऐसे ही अन्य विषयों के बारे में शासन, भारत तथा राज्य स्तर पर शिक्षा-सम्बन्धित व्यक्तियों से शिक्षा-विरोध, शिक्षक, शिक्षा विभाग के कुछ उच्च अधिकारी आदि की समितियाँ गठित करके, उनसे सिफारिशें प्राप्त की जाती हैं और उन सिफारिशों पर शासन केवल निर्णय लेता है—आज ऐसी सामान्य स्थिति है। ऐसी स्थिति में शिक्षण शासन-मुक्त होना चाहिए या निश्चित रूप से क्या हो ?

विनोबा इंग्लैंड में क्या चल रहा है, जानते हैं ?

सहस्रबुद्धे—नहीं।

विनोबा—इंग्लैंड की तरह किया जाय। इंग्लैंड के सारे विश्वविद्यालय स्वतंत्र हैं। उन पर सरकार का कोई शासन नहीं है। शासन का हस्तक्षेप विश्वविद्यालय स्वीकार नहीं करता। शिक्षाक्रम, पाठ्यपुस्तकें आदि के बारे में सारा निर्णय विश्वविद्यालय ही करते हैं। सरकारी कुछ भी नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय का खर्च, प्राध्यापकों का वेतन आदि सब सरकार देती है। इस प्रकार इंग्लैंड में शिक्षण की पूरी स्वायत्तता है।

सहस्रमुखे—इंग्लैंड में विश्वविद्यालयों पर शासन के नियंत्रण के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन प्राथमिक और विशेषतः माध्यमिक शिक्षा पर शासन का काफी नियंत्रण रहता है। लड़का को किम उम्र तक अनिवार्य शिक्षण प्राप्त करना चाहिए, यह भी शासन तय करता है। वेगनमान तय करने के लिए जो बर्नहम कमेटी होती है उसमें शासन के प्रतिनिधि रहते हैं।

विनोबा—माध्यमिक शिक्षा तक इंग्लैंड में जैसी व्यवस्था है वैसी होनी चाहिए लेकिन लड़के को शाला में जाना चाहिए एसी सख्ती करने का अधिकार शासन को नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मेरा मन है कि प्रत्येक को पढ़ना चाहिए। सर्वत्र शाला में जाना ही चाहिए एसी सख्ती करना ठीक नहीं है। मेरे मन में बच्चे को खेती में लगाने का है और पढ़ाने का नहीं है अथवा पढ़ाना हो तो मैं अपना घर पर पढ़ा लूंगा शाला में भरती नहीं करूंगा। अपने लड़के को शाला में भरती न करके खेती में लगाने का अधिकार मुझे रहे, यह शासन-मुक्ति का पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है जो शाला में जायेगा उसकी माध्यमिक शिक्षा तक की व्यवस्था इंग्लैंड जैसी होनी चाहिए।*

आप विद्वान हैं, शिक्षक हैं। आपका एक लड़का है। आप उसे घर पर पढ़ाने हैं। फिर उसे स्कूल भेजने की जबरदस्ती क्यों होती चाहिए? आपके स्कूल में, मेरे घर में कुआँ है। फिर पानी पीने के लिए सार्वजनिक कुएँ पर जाना ही चाहिए, यह जबरदस्ती क्यों? मेरे घर में मेरे लड़के के लिए शिक्षण की योजना है। फिर मैं उन बच्चों को स्कूल में क्या भेजूँ? बहुत हुआ तो आप इतना दसिये कि उन लड़के को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। उससे लिखा सीखिए। प्रमाण क्या है? अँगूठे के बदले हस्ताक्षर करना। दूसरा क्या है? कम्प्लेक्सरी शिक्षण में क्या है? लड़के अँगूठा न करके सही कर सकते हैं—हो गयी पढ़ाई। शिक्षित हो गये। लेकिन ये लोग कहते हैं साक्षर हो गये। मैं कहता हूँ और लोग को साक्षर होना चाहिए। साक्षर होने का क्या उपयोग है? मुझे शासन मुक्त जनता चाहिए—शामन-मुक्त जनता शासन-मुक्त शिक्षण से ही आयेगी।

* विनोबा जी के शिक्षण सम्बन्धों के विचार आज के विश्व में अत्यन्त प्रगतिशील शिक्षाशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के अनुरूप हैं, जो मानते हैं कि स्कूली शिक्षा आज के युग के लिए अपर्याप्त ही नहीं हानिकार भी है। इन शिक्षा-शास्त्रियों में सैटिन अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री डॉ० इवान इल्लिय और 'प्यूब्लिक शाक' के लेखक एडविन टाफ्लर के नाम लिये जा सकते हैं।—सम्पादक

१—लड़ना वो स्कूल में भेजना चाहिए, यह आप्रह मुझे स्वीकार नहीं।

२—माध्यमिक शिक्षा तब शिक्षा-विभाग का नियमन मान्य है। लेकिन विभाग को विद्वानों की मनाहट से यह काम करना चाहिए। (आचार्यकुल ने अपनी शिक्षा-नीति में यह बात स्पष्ट की है।)

३—नालज और युनिवर्सिटियाँ सरकार के नियमन से पूरी तरह मुक्त रहे।

प्रश्न माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा विश्वविद्यालय तय करते हैं, परीक्षाएँ भी ही लेते हैं, पाठ्यक्रम स्वीकृत करते हैं। इधर विरोधज्ञा से पुस्तकें लिखाकर उनका प्रकाशन मंडल तथा विश्वविद्यालय ही करें, यह पद्धति चालू हो रही है। उक्त दोना वाला मैं शासन सहभा हस्तक्षेप नहीं करता। शिक्षण शासन-मुक्त हो, इस माँग के राक्षस में इस व्यवस्था में कंसा परिवर्तन होना चाहिए ?

उत्तर शिक्षा के विषय में सब कुछ युनिवर्सिटियों को भिनाकर करना चाहिए, यह मेरी सलाह है। लेकिन माध्यमिक स्तर तक, अगर ऐसा होता है तो मेरे द्वारा मान्य करने पर कोई कठिनाई नहीं रही।

प्रश्न भारत ने लोकशाही को जीवन-पद्धति के रूप में पूरी तरह प्रत्यक्षत मान्य नहीं किया है, तो भी शासन पद्धति के रूप में प्रत्यक्षत मान्य किया है। शिक्षण शासन-मुक्त होना चाहिए यह माँग करते समय शिक्षा क्षेत्र विषयक सारी बातों पर अन्तिम अधिकार प्रातिनिधिक विधि मंडल के हाथ में रहेगा। यह मानना ही पड़ेगा न ?

उत्तर प्रातिनिधिक विधि मंडल यानी लेजिस्लेटिव एसेम्बली का कोई अधिकार मैं मान्य नहीं करता। सदन के सदस्यों को जनता चुन देती है, इतना ही ज्ञान देकर उनका चुनाव नहीं किया जाता, इसलिए ज्ञान पर उनकी सत्ता नहीं हो सकती।

प्रश्न शिक्षा शासन-मुक्त हो और स्वायत्त हो, ये दो माँगें अलग-अलग मानी जायें या एक ही माँग के दो पहलू हैं ? दो स्वतंत्र माँगें मानने में क्या फर्क है ?

उत्तर फर्क मुझे भी समझ में नहीं आता।

प्रश्न शिक्षा शासन-मुक्त हो यह माँग आगे बढ़ाने में और उच्च समाज की ओर से स्वीकार कराने में आचार्यकुल के सदस्यों को कंसा बताव करना चाहिए ? कंसा प्रचार करे ? मतदाता नागरिकों को इस माँग की न्यायता कंसे समझाई जाय ?

उत्तर : आचार्यकुल को मतदाताओं के पास जाने का कोई कारण नहीं। आचार्यकुल को राजनीति स्तर से मुक्त होना चाहिए—विसी भी राजनीति पार्टी में न रहे।

१—विद्यार्थियों की शिक्षा की ओर तन्मयतापूर्वक ध्यान दिया जाय।

२—बने हुए समय में एक-एक गाँव का संगठन हाथ में लिया जाय। गाँव के लोगों की उनके वाम में मदद की जाय, सलाह दी जाय। इस तरह एक-एक गाँव की ओर लक्ष्य किया जाय। विशेष प्रश्नों के लिए वर्ष में दो-तीन बार सब एक जगह मिलें। वहाँ फार्म भरके अपना विचार जाहिर किया जाय। सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, आर्थिक प्रश्न, और जागतिक प्रश्नों का अध्ययन करके सबके सामने रखा जाय। सामूहिक निर्णय जाहिर किया जाय। जाहिर करने पर उसका जो प्रभाव पड़ेगा वह पड़ेगा। उसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं।

प्रश्न : आज शिक्षा-संस्थाओं की व्यवस्था प्रमुखतः शासन, निजी शिक्षा-संस्था या निजी मंडलों के हाथ में है। इन व्यवस्था मंडलों में व्यक्ति हित, जाति, भाषा, धर्म, राजनीतिक दल आदि का हित देखने की दृष्टि से विचार करनेवाले और उस दृष्टि से बर्ताव करनेवाले लोगों का प्राबल्य है। इस कारण शिक्षकों पर भी उस दृष्टि से बर्ताव करने का दबाव होता है। उस दबाव से मुक्त होना आवश्यक है। इसलिए शिक्षण को शासन-मुक्त करने के मार्ग पर एक कदम के रूप में सारी शिक्षा-संस्थाओं की व्यवस्था केवल शिक्षा-हितैषी लोगों को, जिन्होंने दूसरी नीतियों में भाग नहीं लिया और लेते भी नहीं उनको स्वायत्त मंडल स्थापित करके सौंप देना चाहिए। ऐसा एक सुझाव है, इस बारे में आपका विचार क्या है ?

उत्तर : सुझाव अच्छा है।

प्रश्न : आपने कहा है कि शिक्षा स्वायत्त कैसे हो ? यह तय करने के व्यावहारिक मार्ग के रूप में सारे कुलपुरुषों और साहित्यिकों को सही विचार में शिक्षा-योजना तैयार करनी चाहिए और वह सबको मान्य करनी चाहिए। कुलपुरुष चारित्र्य-सम्पन्न तथा चिन्तनशील होते हैं, ऐसा आपने कहा। वस्तु-स्थिति की जानकारी के आधार पर अनेक प्रतिनिधि आपके विचार से सहमत नहीं थे। इसके अतिरिक्त आज भी शिक्षण के स्वरूप के बारे में और व्यवस्था के बारे में इनमें से अनेक लोगों की सलाह ली जाती है। अतः दूसरा अधिक विश्वसनीय व्यावहारिक मार्ग आप सुझावें।

उत्तर : चारित्र्यहीन और चिन्तनहीन व्यक्ति सर्वत्र होते हैं। तब यह जो

कुलगुरु वर्ग है उसमें भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। परन्तु उनमें प्रमाण कम-से-कम होगा। किसी भी एक वर्ग में जिस प्रमाण में भ्रष्टाचारी व्यक्ति होंगे उस हिसाब से कुलगुरु वर्ग में कम-से-कम होंगे। कुल मिलाकर ७०-८० विश्व-विद्यालय हैं। वित्तों कुलगुरु हो गये ? एक विश्वविद्यालय के लिए एक कुलगुरु के हिसाब से अस्सी कुलगुरु हुए। इनमें कितने भ्रष्ट होंगे ? चार-पाँच होंगे। एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार का साँझ सगाने का आज़रल फैलान हो गया है। उम्मीद तरफ मैं ध्यान नहीं देता। लेकिन मैं सामान्यतः ऐसा समझता हूँ कि कुलगुरु है तो वह चारित्र्य-सम्पन्न होगा। इसके बिना वह इतना ऊपर नहीं चढ़ सकता।

प्रश्न : इस समय कुलगुरु पद के लिए पैनलस भेगाये जाते हैं और उन पैनलस में से एक की नियुक्ति सरकार करती है। कुलगुरु की नियुक्ति भी यह सर्वसाधारण पद्धति है। ऐसी स्थिति में उनका आचरण और वर्तन स्वतंत्र रहेगा यह कैसे माना जाय ?

उत्तर : सरकार की ओर से कुलगुरु नियुक्त किये जाते हैं, ऐसा आप कहते हैं, इसमें सुते आपत्ति नहीं। सरकार की ओर से न्यायपूर्ति नियुक्त किये जाते हैं लेकिन नियुक्त करने के बाद वे सरकार के अधीन नहीं रहते। कुलगुरु बनने के बाद उसे किसी भी प्रभाव में नहीं आना चाहिए।

प्रश्न : वर्तमान पद्धति के अनुसार एक पैनल सरकार की तरफ, राज्यपाल की तरफ जाता है और उस पैनलस में से एक की नियुक्ति होती है। जिनका चयन होता है वे प्रभाव में रहते हैं। पैनल में किसका चयन होगा यह कई बार तो पहले से बताया जा सकता है। इस पर से समझ में आता है कि यह चयन किस दृष्टि से किया जाता है।

उत्तर : कुलगुरु का वर्तक विधानमण्डल के स्पीकर जैसा होना चाहिए। इलेक्ट होते ही वह किसी भी पार्टी का नहीं रहता। स्पीकर बनने पर उस पर पार्टी का बंधन नहीं रहता। ऐसा ही इस विषय में होना चाहिए—इसी तरह कुलगुरुओं को वर्तना चाहिए।

प्रश्न—कोई भी एक योजना मान्य करने पर उसमें कार्यान्वयन के विषय में कुछ नार्म्स तय कर दिये जायें और दोष स्वातंत्र्य स्कूल, कालेजों को दिये जायें ऐसा विचार आगे व्यक्त किया है। इन नार्म्स का पालन किया जाता है, यह देखने के लिए एकाग्र कमेटी आवश्यक होगी। वह किसकी होगी ? कैसे होगी ?

उत्तर—योजना का पालन हो रहा है या नहीं, इसके लिए कमेटी चाहिए। वह प्रांतीय हो, अखिल भारतीय नहीं। और जो प्रांत के कुलगुरु होंगे, महाराष्ट्र

में सात युनिवर्सिटियाँ हैं। इसलिए उन ग़ात बुद्धबुद्धों को मिलाकर अपनी और से एक कमेटी इस काम के लिए नियुक्त करनी चाहिए और तो भी अपनी ओर से।

प्रश्न—शिक्षण को शासन-मुक्त करना है। ऐसा करने पर वह किसके हाथ में दिया जाय ? जिनके हाथ में दिया जाय उनके लिए कोई बसौटी होनी चाहिए ? कैसे ? उनका चयन, नियुक्ति और चुनाव कौन और कैसे करेगा ?

उत्तर—युनिवर्सिटियों के हाथ में।

प्रश्न—जिन मुद्दों पर मतैक्य होगा वे पुरोगामी स्वरूप के न रहें यह सम्भव है। ऐसी स्थिति में पुरोगामी (प्रोग्रेसिव) कदम शिक्षण-व्यवस्था की ओर से उठाना बटिन ही होगा। इन कारण शासन-मुक्त और स्वायत्त शिक्षण से उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहायता मिले—जातिपूण क्रांति हो—यह उद्देश्य साध्य होगा ऐसा नहीं लगता। आपकी प्रतिक्रिया क्या है ?

उत्तर—जिन मुद्दों पर एक मत होगा उन्हीं मुद्दों पर चला जाय। सारा समाज धीरे-धीरे ही आगे बढ़ेगा और क्रांति के लिए उपाय क्या है ?

१—जिन मुद्दों पर मतैक्य होगा उन मुद्दों पर अमल किया जाय। मतैक्य होने से अमल करने में कोई कठिनाई नहीं रहेगी।

२—जिन मुद्दों पर मतैक्य न हो उन मुद्दों पर चर्चा जारी रहे।

प्रश्न—शिक्षण को शासन-मुक्त होने से वह जातीयता, सम्प्रदाय भाषा-मिथान, विशिष्ट राजनीतिक दल, विशिष्ट अभिनिवेश आदि से वह सचमुच मुक्ति होगा क्या ? इनसे मुक्त न होने वाला हो और पुरोगामी न रहने वाला हो तो शासनमुक्ति की माँग क्यों की जाय ?

उत्तर—जातीयता, सम्प्रदाय, भाषाभिमान आदि बातें सर्वथा खुरी नहीं हैं। उनमें कुछ अच्छा अश्व है। अच्छा अश्व मिलेगा तब सुरा अश्व जायगा। तब तक हिन्दुस्तान के लिए आपको जरा धीरे धीरे बर्तना होगा। 'धीरे तो कारण साध्य होय नारायण', जरा धीरे-धीरे करना होगा।

जातीयता—जातीयता का हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा कारण है। वह कारण उसका समाधान होने पर दूर होगा। कौन-सा कारण है ? मासाहार-मुक्ति। कुछ जातियों ने मासाहार छोड़ दिया है। कुछ भी हो जाय तो भी हमारी लक्ष्मी मासाहारी कुल में न जाय, यह इच्छा रहती है और जातीयता मिटाने के लिए विवाह होने चाहिए। ऐसा होने पर ही जातीयता मिटेगी। उसके लिए दूसरी जाति का मनुष्य हो। लेकिन यदि उसने मासाहार छोड़ दिया हो तो विवाह करने में हर्ज नहीं। इस तरह जीवन को व्यापक बनाते जायें।

नया सम्प्रदाय—सम्प्रदाय को नष्ट होने की भूते आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। भारत जैसे बड़े देश में अनेक सम्प्रदायों का होना उचित ही है। निन्तु उन सम्प्रदायों के जो मुख्य लाग हैं उन्हें एकरा बैठार कामन पाइंट्स निवास्तना चाहिए और देश को आगे ले जाना चाहिए। भाषाभिमान अच्छी बात है लेकिन अय भाषा का विरोध न हो।

शिक्षण को शासनमुक्त करने से ये बातें सघ सवेंगी। चौथी बात है विशिष्ट राजनीतिज्ञ दल। वह विशिष्ट अभिनिवेश से मुक्त होना चाहिए। यह आज नहीं हागा यान्तर में हागा। तब तब राजनीतिक पक्ष भेद और दोरे कायम रहगे। उसमें शिक्षण सस्था भाग नहीं लेती। यह पर्याप्त है।

प्रश्न—आप जैसे दूरदृष्टिवाले लोग जा समझते हैं कि समाज-जीवन का प्रवाह मानवता की ओर जा रहा है तथा जो तदनुसार प्रत्यक्ष में बर्ताव करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा बहुत पाड़े होते हैं। तब शिक्षा-क्षेत्र विषय-अंतिम अधिकार लोगो को दे दिया ता निश्चित ही—बम खोला को दिया तो भी विविध प्रश्नों में मतभेद साकार होगा ही, ऐसा नहीं है। मतभेद न होना ही अधिक सम्भव है। ऐसी स्थिति में बहुमत या सर्वसम्मति से ?

उत्तर—जितने सुदो पर मतभेद होगा वह निणय। जिस पर नहीं होगा उस पर चर्चा जारी।

प्रश्न—शिक्षण शासन-मुक्त विषय की चर्चा में एक प्रतिनिधि ने यह सुझाव दिया कि राज्य विधान में ही जैसे कानूनी, कार्यकारी और न्याय ऐसे तीन विभाग होते हैं उसी तरह शिक्षण का भी एक चौथा विभाग रहे। यह सुझाव आप को कैसा लगता है ?

उत्तर—ठीक है यह सुझाव। ०

डा० नगेन्द्र

उच्चतर शिक्षा का माध्यम

शिक्षा के क्षेत्र में आज सबसे उच्चतम प्रश्न माध्यम का है उच्चतर ज्ञान-विज्ञान—उद्योग-विज्ञान आदि की शिक्षा का माध्यम क्या हो ? अंग्रेजी ही चलती रहे या भारतीय भाषाएँ हों और सार्वदेशिक स्तर पर हिन्दी का क्या उपयोग हो—ये कुछ प्रश्न अस्तुतः प्रसंग से सम्बन्ध हैं ।

शिक्षा-तन्त्र के चार प्रमुख अंग हैं । एक, आधारभूत ज्ञान । दो, प्रसारण की साधन-सामग्री । तीस, शिक्षक और चार, शिक्षा का अधिकारी छात्र-वर्ग । इनके अतिरिक्त समाज का भी इस तन्त्र से गहरा सम्बन्ध है, क्योंकि अन्ततः समाज का कल्याण ही ही शिक्षा का लक्ष्य है । शिक्षा-तन्त्र की सफलता इन सभी अंगों के उचित सामंजस्य में निहित है । इनमें से ज्ञान तो आत्मा या अन्तर्बोधना की क्रिया अथवा प्रकृति का वाग है जो अमूर्त है, धारणाओं के संघात से उसका निर्माण होता है । अतः ज्ञान का किसी जाति, देश या भाषा के साथ सहज सम्बन्ध नहीं माना जा सकता । यह ठीक ॥ कि विस्तृत जाति या भाषा अधिक ज्ञान सामग्री-सम्पन्न होती है, परन्तु ये सम्बन्ध मौलिक न होकर ऐतिहासिक ही हैं । आधुनिक विज्ञान के विकास में अनेक राष्ट्र योगदान कर रहे

है, उसको किसी जाति या भाषा तक सीमित कर देना मानव-आत्मा का अपमान करना होगा। प्रसारण की साधन सामग्री का सामान्य अर्थ है वाङ्-मय या ग्रन्थ समूह जिसका सम्बन्ध माध्यम, भाषा के साथ है। स्वभावतः जिन सम्पन्न देशों में ज्ञान-विज्ञान का प्रसार होता रहा है और हो रहा है अथवा जिसके पास अनुवाद आदि के लिए अधिक भौतिक साधन हैं उनकी भाषाओं से सब सामग्री अधिक उपलब्ध रहता है और व्यवहार एवं प्रयोग से उनकी शक्तियाँ इस प्रकार के ज्ञान का वाहन और सम्प्रेषण करने के लिए विकसित हो जाती हैं। जिन भाषाओं में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है उसके माध्यम से शिक्षा के लिए ज्ञान का अर्जन और विकास सरल होता है। नए शिक्षक-वर्ग के लिए ज्ञान के वितर्जन की भाषा भी प्रायः वही बन जाती है जो उसके अर्जन की भाषा होती है। जहाँ इस भाषा में और समाज की भाषा में या समाज के उन विशिष्ट अंग की भाषा में, जो विद्यार्जन करता है, ऐक्य है वहाँ तो लाभ है। परन्तु जहाँ समाज की भाषा भिन्न है, वहाँ समस्या पैदा होती है और शिक्षातन्त्र के विभिन्न अंगों का सम भय हो जाता है। हमारे देश के सबसे ऐतिहासिक कारणों से आज ठीक यही समस्या है। भौतिक विज्ञान और उद्योग-विज्ञान का विकास प्रायः पश्चिम के समृद्ध देशों में हुआ है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व यूरोप की तीस प्रमुख भाषाएँ—अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच ज्ञान-विज्ञान की सबसे समृद्ध माध्यम भाषाएँ थी। दूसरे महायुद्ध के बाद जर्मन और फ्रेंच पिछड़ गयीं। अमरीका के प्रभाव से अंग्रेजी का विस्तार और विकास होता रहा और उसने इसी भाषा का महत्त्व एकदम बढ़ा दिया। विज्ञान और उद्योग का भण्डार आज प्रायः इन दो भाषाओं में भरा हुआ है। हमारे देश का अंग्रेजी के साथ पिछले सौ वर्षों से घनिष्ठ सम्बन्ध है, नए इसी या यूरोप की किसी अन्य भाषा की अपेक्षा, ऐतिहासिक कारणों से भारतीय छात्र-समुदाय के लिए अंग्रेजी का माध्यम निश्चय ही सुख-साध्य है। जिस अंग्रेजी का धारों भारतीय समाज पर अंग्रेजी शासक ने अपनी स्वायत्तसिद्धि के लिए किया था, उसका सदुपयोग आज भारतीय अपने स्वार्थ के लिए क्यों न करें? देश के अनेक शिक्षाविदों का यह सोचा तर्क है और इसी के आधार पर शिक्षा-आयोग ने उच्चतम शिक्षा के लिए प्रादेशिक भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम का ग्रहण प्रायः अनिवार्य काल तक अवश्य माना है और इसी भाषा को केवल पुस्तकालय-भाषा के रूप में स्वीकार किया है।

इसमें सन्देह नहीं कि यह तर्क व्यावहारिक परिस्थितियों में से उद्भूत हुआ है और इसे मानसिक दासता या और कुछ कहकर तिरस्कृत करना समी-

चीन नहीं होगा। परन्तु इसमें भी अनेक दोष हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें शिक्षातंत्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग भारतीय छात्र-वर्ग और भारतीय समाज की, छात्र-वर्ग जिसका एक अंग है, उपेक्षा की जा रही है। भारतीय समाज का अंग्रेजी सम्पर्क परतंत्र भारत में भी कभी गहरा नहीं रहा, स्वतंत्र भारत में तो शासन की दुममुन नीति बावजूद वह और भी क्षीण हो गया है और तथाकथित उच्च या उच्चतर माध्यम वर्ग में भी, सत्कारों की बाधा होने पर भी, मातृभाषा के प्रति सम्मान की भावना बढती जा रही है। अतः जिस समाज के लिए उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, उसकी भाषा अंग्रेजी नहीं है। उधर माध्यमिक शिक्षा प्रायः भारतीय भाषाओं के द्वारा प्राप्त करने के कारण विद्यार्थी का अंग्रेजी के माध्यम से ज्ञान के ग्रहण एवं अभिव्यक्ति का अभ्यास भी एक प्रकार से छूट-सा गया है, और स्नातक स्तर पर भी अब यही हो रहा है। ऐसी स्थिति में अनभ्यास कारण एक साथ स्नातक-कौत्तर या उच्चतर स्तर पर सहसा अंग्रेजी की ग्रहण करना व्यावहारिक नहीं होगा। विद्यार्थी ज्ञान का अर्जन एक विशेष स्तर तक भारतीय भाषा में करता है और अतः में जिस समाज में उसे अपने ज्ञान का उपयोग करना है वहाँ भी मुख्यतः भारतीय भाषा का माध्यम ही ग्रहण करना होगा, तब फिर यह जाया करना गलत होगा कि बीच में वह अंग्रेजी का सम्यक् उपयोग कर सकेगा या अंग्रेजी के माध्यम से उसकी योग्यता में सहसा वृद्धि हो जायेगी। उदाहरण के लिए, विधि की शिक्षा को ही लीजिए। आरम्भ में वर्षों तक छात्र प्रादेशिक भाषा के माध्यम से इतिहास, नागरिक शास्त्र आदि का अध्ययन करता है, फिर अतः में भी उसे जिस वर्ग के लोगों के साथ काम करना है, उनके व्यवहार का माध्यम भी प्रादेशिक भाषा है। इसलिए उसे छोड़कर दूसरी भाषा का आचल पकड़ रहना कहाँ तक बुद्धिसम्मत है? एक विकल्प यह रखा जाता है कि भाविकी और सामाजिक विज्ञान आदि की शिक्षा भारतीय भाषाओं में हो, परन्तु भौतिक विज्ञान, उद्योग विज्ञान तथा विधि आदि तकनीकी विषयों की शिक्षा अंग्रेजी में हो होती रहनी चाहिए। इसके विषय में मैं अत्यन्त विनयपूर्वक यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि एक ही शिक्षातंत्र के भीतर क्या यह सम्भव हो सकेगा कि आधी शिक्षा भारतीय भाषाओं में हो और आधी अंग्रेजी में? राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन का माध्यम एक हो और वैज्ञानिक गतिविधि का माध्यम दूसरा। हम अनुभव करें हिन्दी, बंगला या तेलगु में और न्याय की भांग करें अंग्रेजी में?

वास्तव में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद बीस वर्षों में देश की परिस्थितियों ने प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अतः आज सवाल यह नहीं रहा कि माध्यम क्या हो—वरन् यह कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का सक्रिय प्रयोग किस प्रकार हो। जो लोग आज भी इस सवाल की छेड़ता चाहते हैं कि माध्यम क्या हो, वे या तो यथार्थ से अनभिज्ञ हैं, या जानबूझ कर मुख्य प्रश्न को टालना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बहस करना बेकार है, क्योंकि इससे अकारण ही राष्ट्र की उस सीमित शक्ति और समय का भी अपव्यय हो सकता है जो रचनात्मक कार्य के लिए अर्थात् माध्यम-परिवर्तन की योजनाओं की क्रियान्वित करने के लिए तत्काल अपेक्षित है। काम यह बड़ा है, पर बड़े से बड़ा काम भी सगठित प्रयत्न से शीघ्र ही पूरा हो सकता है। दुर्भाग्य यह है कि अभी तक इस प्रकार का प्रयत्न भी सही ढंग से आरम्भ नहीं हुआ है। इस प्रसंग में पहली आवश्यकता यह है कि हिन्दी-भाषी राज्य मिल-कर इस बात की जाँच-पड़ताल करें कि माध्यम-परिवर्तन के लिए कुल मिलाकर कितनी पुस्तकें अविवार्य रूप से अपेक्षित हैं। इनमें से उचित स्तर की कितनी पुस्तकें इस समय उपलब्ध हैं और शेष कितनी ऐसी हैं जिनका अनुवाद या स्वतः रूप से निर्माण होना है। तत्काल अपेक्षित आधारभूत सामग्री का मानचित्र तैयार हो जाने के बाद हिन्दी-राज्यों के विश्वविद्यालय आपस में कार्य-विभाजित करके इस लक्ष्य को शीघ्र ही पूरा कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षा के पाठ्यक्रम में छोटे-बड़े खगमन तीस विषय हैं। इनमें स्नातक कक्षाओं के ग्रन्थ प्रायः उपलब्ध हैं और शेष की पूर्ति अविलम्ब हो की जा सकती है। यह ठीक है कि इन ग्रन्थों का स्तर वैसा नहीं है जैसा अंग्रेजी में उपलब्ध मानक ग्रन्थों का है, परन्तु मैं पूछता हूँ कि छात्राचार्यों के मानक ग्रन्थ आजकल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? अधिकांश विश्वविद्यालयों में स्नातक-परीक्षा के लिए भारतीय लेखकों की पुस्तकें ही निर्धारित हैं जिनके अनुवाद प्रायः ही चुके हैं या माँग होते ही तीन महीने के भीतर प्रकाशक आपको छाप कर दे देंगे। यह भी ठीक है कि केवल व्यवसाय की दृष्टि से, जल्दी में या अनधिकारी न्यविजयों द्वारा प्रस्तुत ये अनुवाद सतोषप्रद नहीं हैं, किन्तु विश्वविद्यालयों की ओर से नियमित रूप से माँग होते ही इनका उचित संशोधन एवं पुनरीक्षण करने में कितना समय लगता है? स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी अनेक विषयों के ग्रन्थ उपलब्ध हैं। शेष का निर्माण विश्वविद्यालय अविलम्ब ही कर सकते हैं। हिन्दी राज्यों में पैंतीस विश्वविद्यालय हैं। आरम्भ से यदि सभी विषयों के लिए कुल डेढ़ हजार

नयी पुस्तकों की आवश्यकता है तो एक-एक विश्वविद्यालय के हिस्से में चालीस-पचास पुस्तकें आती हैं जो निष्ठा और सकल्प के साथ कार्य करने पर अधिक-से-अधिक पाँच वर्ष के भीतर, और जल्दी की जाय तो दो-तीन वर्षों में भीतर तैयार की जा सकती हैं। एक पुस्तक पर यदि औसत से बीस-पच्चीस हजार रुपया खर्च आया तो तीन करोड़ रुपये में आधाराभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तीन वर्ष के भीतर हो सकती है—और, यदि ईमानदारी से कोशिश की जाती तो अब तक यह लक्ष्य सात बार पूरा हो सकता था या सात गुना बाढ़ूमय प्रस्तुत किया जा सकता था।

इन ग्रन्थों के रचनातन्त्र के बारे में कुछ समस्याएँ सामने आ सकती हैं। उदाहरण के लिए एक मूल समस्या यह है कि साहित्येतर विषयों पर हिन्दी में लिखनेवालों की संख्या अभी बहुत कम है। विषय के पण्डित का भाषा-शैली पर अधिकार नहीं है और भाषा-प्रवीण को विषय का सम्यक् ज्ञान नहीं है। इसका हल बड़ा आसान है और जिन्हें आवश्यकता हुई है, उन्होंने खोज लिया है। यह कार्य वास्तव में दो सहयोगियों की अपेक्षा करता है—विषय का विशेषज्ञ और भाषा का अधिकारी, इनमें दोनों मिलकर काम करेंगे। विषय का विशेषज्ञ अपने भाषा-ज्ञान के अनुसार परिविष्टित हिन्दी में या लिखड़ी हिन्दी में प्रत्येक परिच्छेद का आरूप तैयार करता चलेगा और भाषाविद् साथ-साथ उसका सुस्कार करता चलेगा। यह तो हुआ स्वतन्त्र लेखन के प्रश्न का समाधान। प्रामाणिक ग्रन्थों के अनुवाद का कार्य अल्पसंख्यक लेखक कर सकते हैं और कर रहे हैं। इस प्रकार के अनुवाद में जो त्रुटियाँ रह जाती हैं, उनका कारण यह है कि इस अनुवाद का विषय-मर्मज्ञ और शैलीकार द्वारा उचित पुनरीक्षण नहीं किया जाता। वास्तव में अनुवाद-तन्त्र के तीन आवश्यक अंग हैं—एक : विषय का मर्मज्ञ और साथ ही भाषा का सामान्य अधिकारी अनुवादक, दो : विषय विशेषज्ञ और तीन : भाषा-सम्पादक। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने साधनों के अनुसार एक या दो चुनकर उपयुक्त तंत्र में आधार पर एक रचना-केन्द्र की स्थापना कर सकता है। जहाँ नियमित रूप से पूर्णकालिक तथा अर्धकालिक विशेषज्ञों की सहायता से, लक्ष्य बाँधकर, निर्माण-कार्य हो सकता है। इस प्रकार, उद्देश्य की पूर्ति सीधे ही की जा सकती है। शासन और विश्वविद्यालय दोनों की निरलस भाव से अविलम्ब ही इन संकल्पों की क्रियान्वित करना चाहिए। जो काम वृत्तव्य-निष्ठा से, सोचा के साथ होना चाहिए, उसके लिए धान्दोलनों के दबाव की प्रतीक्षा करना बुद्धिमत्ता नहीं। ●

शिक्षण किन बातों में स्वतंत्र और स्वायत्त रहे ?

[महाराष्ट्र आचार्यकुल की प्रश्नावली पर डा० चिन्तामण राव देशमुख, भूतपूर्व विल्ल मंत्री, भारत सरकार तथा श्री मा० गो० वेंकट से पूछे गये प्रश्नों के उत्तर । —स०]

प्रश्न : शिक्षण किन-किन बातों में स्वतंत्र और स्वायत्त रहे ?

देशमुख : शिक्षण के उद्देश्य जितने प्रमाण में अधिकाधिक साधे जा सकें उतने प्रमाण में शिक्षण-संस्था को स्वायत्तता और स्वतंत्रता रहे । किसी भी कार्य विभाग में विशेषतः शिक्षा-विभाग में निचली इकाइयों को निर्दिष्ट स्वायत्तता और स्वतंत्रता देना कार्यनिर्वाह के लिए आवश्यक है । तब संस्था किसी भी स्तर की हो, थोड़ी-सी स्वायत्तता और थोड़ा-सा स्वातंत्र्य प्रत्येक को देना ही पड़ता है ।

१—योजना की रूपरेखा और नियमावलियाँ केन्द्रीय शासन को ही तैयार करनी हानी ।

२—लेकिन तदन्तर्गत सविस्तार पाठ्यक्रम तैयार करने के बारे में स्वायत्तता और स्वतंत्रता का स्थान और उपयोग है—किन्तु इस शर्त पर कि यह 'योग' प्रशिक्षित व्यक्तियों के हाथ में हो ।

३—सार्वजनिक परीक्षा आदि सब हटा दी जायें । परिणामों पर प्रवेश-परीक्षा अपरिहार्य हो जायगी । यही हमारी पुरातन पद्धति है नालंदा विद्यापीठ इत्यादि में ।

मा०गो०वेंकट १—न्याय विभाग को शासन की दण्डशक्ति का सहारा (संवर्धन) अनिवार्य है । उसके बिना न्यायदान की कोई कीमत नहीं रहेगी । इस प्रकार का संवर्धन शिक्षा विभाग के लिए आवश्यक न रहे । शिक्षा विभाग को संवर्धन समाज का चाहिए । लेकिन वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा का सम्बन्ध केवल नीजरी से जुड़ा होने के कारण और सबसे बड़ा नीजरी दाता शासन होने से

उपाधि को शासन की मान्यता आवश्यक हो गयी है। उपाधि का नौकरी से सम्बन्ध तोड़ दिया जाय तो शासनाधिमुखता बहुत कम हो जायगी। जब तक यह नहीं होता तब तक शिक्षा पर शासन का अकुश और नियन्त्रण रहना अपरिहार्य है। न्यायदान के विषय में न्याय विभाग को शासन ने अपना 'सर्वशान' दिया और न्याय विभाग के 'फैमले' के अनुसार चलना मान्य करने पर अन्य विषयों में शासन हस्तक्षेप नहीं करता। न्यायाधीशों की नियुक्ति शासन करता है, लेकिन न्यायाधीश न्याय कानून के अनुसार देते हैं, शासन की इच्छा के अनुरूप नहीं। इसलिए कानून भले ही शासन बनाये और न्यायदान भी भले ही उस कानून के अनुरूप हो, तो भी न्यायदान स्वतन्त्र और स्वायत्त रहता है। शिक्षा विभाग की ऐसी रचना करना उचित नहीं। शिक्षण की व्यवस्था शिक्षा-संस्थाओं को सरकार के आदेश के अनुसार चलाने की अपेक्षा श्रेयस्वर नहीं है कि स्वयं सरकार ही सीधे-नोडि चलाये। यह नहीं चाहिए तो शिक्षण-संस्थाओं को पाठ्य-क्रम, नियन्त्रण और परीक्षण के विषय में स्वतन्त्रता रहनी चाहिए।

२—शिक्षण की स्वायत्तता का मतलब है सम्पूर्ण शिक्षण-व्यवस्था की स्वायत्तता।

३—शासकीय और अशासकीय का फर्क रहने में हर्ज नहीं है। अशासकीय शाखाओं को सरकार अनुदान देगी। परन्तु आज की अपेक्षा उसकी अलग से व्यवस्था करना आवश्यक है। आज सरकार पाठ्यक्रम तैयार करती है, पुस्तकें तैयार करती है, खर्च का ९७-९ प्रतिशत या ९९ प्रतिशत अनुदान देती है। फिर सरकार ढाई प्रतिशत या एक प्रतिशत खर्च के लिए संस्था चलाने की जिम्मेदारी क्यों ढालती है? मुझे लगता है कि ऐसी संस्थाओं को सरकार हाथ में ले ले तो आज का सारा भ्रष्टाचार रुक जायेगा। राजनैतिक स्वार्थपूर्ति के लिए शाखाएँ खोली और उस पूर्ति में हाथ का सहारा दे, इसलिए जिनको सरकार ने मान्यता दी, उनके चलने के लिए एकाध चरगाह ही तथा उनकी उपद्रव-शक्ति का कष्ट अपने को न हो, यह उद्देश्य होने से उनके लिए आज की व्यवस्था जितनी पोषक व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न ॥ १—शिक्षा के सारे घटकों का—शासन, शिक्षा-संस्था, संचालक, पाठक, शिक्षक और विद्यार्थी—अनुबन्ध छात्रों की योजना कौन तैयार करे? किस पद्धति से? यह पद्धति किस प्रकार तय की जाय?

२—स्थानीय राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं का स्थानीय संस्थाओं के संचालन में किस प्रकार का स्थान रहेगा? वह राजनीतिक दल का सदस्य रहे या न रहे? आज का सामाजिक कार्यकर्त्ता कल राजनैतिक दल का कार्यकर्त्ता हो सकता

है। सर्वोच्च पारदर्शिता को नैमित्तिक कार्य करता पड़ता है। क्या ऐसे कार्य-कर्ताओं को संचालन में स्थान दिया जाय ? क्यों ?

३—नारी शिक्षा-संस्थाओं के स्थापना होने पर उन्हें दो नयी शिक्षा-योजना की सामान्य कुररेखा एक ओर रखकर बचवा उसमें परिवर्तन करके उसे वे अंश में लाती होंगी तो उसरी देखरेख नीन, वैसे और क्यों रहे ?

४—शिक्षा-संस्था की सम्पूर्ण स्वायत्तता दी जाय अथवा मर्यादित स्वायत्तता दी जाय ? इसके कारण शिक्षा-संस्थाओं की प्रयोगक्षमता पर नीन-सा दृष्टान्तिष्ट परिणाम हो सकेगा ?

५—तात्कालिक समाजवादी समाज-रचना का ध्येय सामने रखकर भारतीय शासन ने कार्य करना तय किया है। शिक्षा के अनेक उद्देश्यों में से राष्ट्रीय लक्ष्य-नीति में सहायक होनेवाला शिक्षण दिया जायगा, ऐसी रूपरेखा संस्थाओं को दी जायगी। इस कारण स्वायत्तता की मर्यादा आयेगी या नहीं ? ऐसा होने पर उसका स्वरूप कैसा रहेगा ? वे आवश्यक हैं क्या ?

डा० देशमुख १—शासन, संस्था और संचालक के विषय में शासन और संचालक संस्था के प्रधान की स्वतन्त्रता है—पालकों की सहायता प्राप्त करवा संचालको का काम है। शिक्षा और विद्यार्थियों का अनुभव जोड़ना शिक्षा का धर्म होना चाहिए।

२—संस्था के स्तर पर—राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वैयक्तिक स्थान केवल उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रहे, अन्यथा उनकी शिक्षणकारी गाय के गले का भयकर घोषा हो जाने की सम्भावना है।

३—देखरेख उनकी होगी जिन्होंने स्वायत्तता दी। स्वायत्तता की मर्यादाएँ देने के पूर्व ही तय करनी होती है। वह कोई स्वयं-भू वात या स्थिति नहीं है। अनुभव के अनुसार बदल भी सकती है।

स्वायत्तता का प्रमाण समझदारों और शालीनता से तय करना होगा। "भाषा वारय प्रमाण" की सिरजोरी काम बिगाड़ेगी। राष्ट्रीय ध्येय के अनुरूप मर्यादा शिक्षा-पद्धति की और उसके तंत्र की अवश्य रहेगी।

किसी को भी स्वतन्त्र रूप से शिक्षा-संस्था शुरू करने का अधिकार है, लेकिन शासन उसकी सहायता नहीं करेगा।

४—अमर्यादित अनर्गल स्वायत्तता को बौद्धिक क्षेत्र में स्थान है, लेकिन शैक्षणिक क्षेत्र में नहीं।

५—देखरेख का कार्य मध्यवर्ती मंडल को करना चाहिए। लेकिन एक उदार चौखट में उस-उस शिक्षण-संस्था को परिवर्तन करने देने का मौका दिया जाय।

६—सम्पूर्ण स्वायत्तता कहीं वही होती। समानता और स्वायत्तता का मेल बैठना अशक्य नहीं है।

७—सोवियतवादी समाजवादी समाज-रचना का ध्येय हमारे संविधान में अंतर्भूत नहीं है। समाजवाद सर्वमान्य नहीं है। वह एक या कुछ विशिष्ट दलों का ध्येय है। इसके अलावा, समाजवाद के आशय के विषय में भी एक वाक्यता नहीं है। 'जीवन के सारे अंग सरकार के अधीन' यह समाजवाद का मोटा-मोटा अर्थ माना जाता है। उसे स्वीकार करने का तय कर लिया जाय तो स्वायत्तता की सारी चर्चा ही व्यर्थ हो जाती है। जो समाजवादी नहीं है, वह पूँजीवाद का पुरस्कर्ता है, ऐसा भी हमारे यहाँ अर्थ किया जाता है। इसलिए हर आदमी पूँजीवाद का पुरस्कर्ता साबित न होने के लिए अपने को समाजवादी कहता है। शिक्षण से व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह समाजशील बनना चाहिए, ऐसा ध्येय रखना ठूरा नहीं है। लेकिन व्यक्ति का समाजशील बनना अलग है और समाजवादी बनना अलग है। उसका समाजवादो बनने का मतलब विविध राज-नैतिक और आर्थिक व्यवस्था से उसे बाँधना। समाजशीलता में व्यक्ति के अहंकार का और विभक्त भावना का नियन्त्रण है। समाजवादित्व में व्यक्ति का विलयन है।

प्रश्न : स्वतंत्रता और स्वायत्तता मान्य करके भी शिक्षा-योजना के कुछ घटकों की ओर से लगायी गयी मर्यादाएँ व्यवहार के नाते आवश्यक होने पर, वे मर्यादाएँ कौन-सी हों ? वे मर्यादाएँ स्वीकार करने पर भी स्वायत्तता कैसे रखी जा सकेगी ? शिक्षा के विविध घटकों को शिक्षण स्वायत्त करने की दृष्टि से किस-किस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए ? उसमें शिक्षकों का—अभितगत और सघटन के द्वारा—कार्य क्या है ?

देशमुख : पहले किये गये विवेचन के अनुसार 'स्वायत्तता' बरिष्ठों की ओर से प्राप्त कार्यनिर्वाह-प्रवृत्ति है, जिसमें मर्यादा अभिप्रेत ही है। यह कोई नितर्गन्धर्व हक नहीं है। अनुमत स्वायत्तता के वर्तुल में कोई भी हस्तक्षेप न करे—यह स्वतंत्रता है। यह सम्पूर्ण हो और हस्तक्षेप न चले। कहीं जाकर रोका जाय यह प्रत्येक की सद्सद्-विवेकबुद्धि का प्रश्न है। भारत की वर्तमान परिस्थिति में यह सब मुझे मन का लड़कू लगता है। सिद्धान्त और सामग्रस्य रिक्त है और एकदम नीचे के स्तर के स्वार्थ में उन्माद आ गया है। इस प्रवृत्ति को नियन्त्रण में रखना व्यक्ति के लिए साध्य नहीं है। इसके लिए सगठन आवश्यक है और वह समीर चाहिए।

बढ़ना एक बात है, गुण बढ़ना विलकुल दूसरी । क्या संस्था के साथ-साथ गुण भी बढ़ेगा ?

अभी लखनऊ विद्वद्विद्यालय में जो झुठ हुआ उसे शिक्षा का 'वाटरगेट' मान लेना चाहिए । हमारी शिक्षा में जो सड़न और निम्नतापन है वह नया नहीं है, पुराना है । अगर इसी शिक्षा को चलाते रहना हो तो शिक्षा के नाम में कुशिक्षा का प्रचार करना होगा । कुशिक्षा का प्रचार करना देश का—उसके वर्तमान और भविष्य दोनों का—घोर अहित करना है । कुशिक्षा से अशिक्षा वही अधिक सहा है । कुशिक्षा का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह मनुष्य के सहज गुणों को भी हर लेती है । ऐसा मनुष्य समय की गति और समाज के जीवन से भी अच्छी बातें सीखने के अयोग्य हो जाता है । तब वह असामाजिक और समाज-विरोधी भी हो जाता है । हमारा तरुण समाज से हटता, फटता जा रहा है, इसका प्रमाण ढूँढ़ने की जरूरत नहीं है । परिवार, गाँव, स्कूल, बाज़ार हर जगह प्रमाण भरे पड़े हैं । समाज अपने तरुणों और तरुणियों के हाथों बहुत बड़ा नुकसान उठा रहा है । तोड़-फोड़ से कहीं बड़ी क्षति यह है कि समाज अपने तरुणों और तरुणियों की सही, सच्ची, विधायक शक्ति के लाभ से वंचित हो रहा है । तरुण की प्रतिभा से बड़ी कोई दौलत नहीं होती । आज हम उसी दौलत को खुले हाथों गँवा रहे हैं ।

क्या यह गँवाना पँचवीं पंचवर्षीय योजना में रतम होगा, या कम-से-कम रुकेगा ? अभी तक तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आयी है जिससे भरोसा हो कि ऐसा होगा । क्या शिक्षा स्कूल की चार दीवारों से बाहर भी निकलेगी ? क्या अभ्यास-क्रम बढ़ेगा ? परीक्षा-पद्धति में सुधार होगा ? उत्पादक श्रम हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होगा ? ज्ञान का अभ्यास वातावरण और समाज के वास्तविक जीवन के अनुबन्ध में कराया जायेगा ? क्या यह सब होगा, या विद्यालय डिग्री के बाज़ार ही बने रहेंगे ?

अब हमारे बच्चों के सामने इक्कीसवीं शताब्दी का जीवन है । कौन मानेगा कि आज की शिक्षा किसी भी अंश में उन्हें उस जीवन के लिए तैयार कर सकती है ? इसीलिए दुनिया में शिक्षा का नया

विचार अब यह नहीं मानता कि शिक्षा विद्यालय में बँध सकती है या कुछ वर्षों में किसी परीक्षा के साथ पूरी हो सकती है, या वास्तविक जीवन से अलग रहकर सार्थक रह सकती है। हमारे अगुआ क्या सोचते हैं ? स्वयं शिक्षक और विद्यार्थी क्या सोचते हैं ?

अगरेजों ने शिक्षा चलायी अपना शासन चलाने के लिए। आज की शिक्षा किसलिए चलायी जा रही है ? देश का सर्वनाश करने के लिए ?
—राममूर्ति

सूचना

[पाठकों को सूचित किया जाता है कि माह मई, अंक १० 'आचार्यकुल विशेषांक' निकालने के कारण सामान्य अंक से आठ पृष्ठ ज्यादा बढ़ाना पड़ा। सामान्य अंक ४८ पृष्ठ का प्रकाशित होता है।

अतः कागज का हिसाब पूरा करने की दृष्टि से यह अंक ४० पृष्ठ का ही प्रकाशित किया जा रहा है।—सम्पादक]

सम्पादक मण्डल :

श्री घोरेंद्र मजूमदार : प्रधान सम्पादक

वर्ष : २१

श्री वंशीधर श्रीवास्तव

अंक : ११

आचार्य राममूर्ति

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

शिक्षा में कोई नयी बात ?

४८९ सम्पादकीय

पाजोली फॉरे का शिक्षण-विचार

४९१ गारायण देसाई

शिक्षा में परिवर्तन . एक यश प्रण

४९५ पूर्णचन्द्र जैब

शिक्षक : आचार्य संहिता की सीमा में

४९८ राधेश्याम प्र० सिंह

शिक्षा : जिसकी आवश्यकता है

५०९ इरिकाल सिंह

शासनसुक्त शिक्षण : विनोबाजी के

अधिकृत मार्गदर्शन

५१०

सुख शिक्षा का माध्यम

५१७ डा० नगेन्द्र

शिक्षण किन बातों में स्वायत्त

और स्वतन्त्र रहे

५२२

जून, '७३

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्द्रा भाठ रुपये है और एक अंक के ७० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सख्या का जल्दसे अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट, द्वारा सर्वे सेवा सच के लिए प्रकाशित,
भनोहर प्रेस, जलनगर, धारागली में मुद्रित

नयी तालीम : जून, '७३

पहिले से शक-व्यय दिये बिना मेजने की स्वीकृति प्राप्त

साइसेंस न० ७४८५५५५

रजि० स० एल० १७२३

हमारे नये प्रकाशन

सूच्य

पत्र-विश्व-भवत्येक नोडम्

नारायण देसाई

श्री नारायण देसाई पिछले दिनों विश्व-शांति यात्रा पर यूरोप तथा अमेरिका गये थे। अनेक देशों के शांतिप्रिय लोगों से, युवक-युवतियों से मिले, और उन्होंने देखा कि आज 'एक विश्व' की प्यास जोर से लगी है। सारा विश्व एक परिवार है, एक नोड है-यह सर्वोदय का आधारभूत विचार है।

पुस्तक यात्रा-विवरण तो है ही, पर पढ़ने में प्रत्यक्ष अवलोकन का आनंद देती है।

मूल्य : ३.००

मधुमेह

डा० शरम प्रसाद

इस पुस्तक में मधुमेह या डायबिटीज के विषय में लेखक ने प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से अच्छा विवेचन किया है।

मूल्य १.५०

हृदय रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा

धनचंद सरावगी

विषय नाम से स्पष्ट है।

मूल्य २.००

नेत्र रक्षा की कला

गोविंदभाई पटेल

आँख है तो जहान है। आँखों की रक्षा हमारे अपने हाथ में है। आँखों की सुरक्षा के प्रति हम सचमुच बहुत लापरवाह रहते हैं। यह पुस्तक हमें आँखों के विषय में अनेक बातों की जानकारी देती है।

मूल्य - ३.००

सर्व सेवा सघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१